

नयी तालीम

“युवावस्था जीवन का स्वर्णकाल है जब कि (प्रत्येक) व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अनूद्य आदर्श अर्जित करता है और आन्तरिक शक्ति विकसित करता है। हमारी युवापीढी को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे यह देश की सस्कृति और उसकी उज्ज्वल परम्परा को समझ सें और उसके लिए जरूर गौरव सें ताकि वह देश के हित में ही उनका अपना हित सम्भावित है ऐसा समझ सके। देश को उनसे बहुत आशाएँ हैं।”

मोरारजी देसाई



अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

वर्ष : २६]

अगस्त-सितम्बर, १९७७

[संक : १]

सम्पादक-मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

श्री वज्रुभाई पटेल

श्रीमंती मदालसा नारायण

डॉ० मदनमोहन शर्मा

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

गौंव वालोंसे सम्बन्ध जोड़ें

बुनियादी तालीम

कार्य ताला

सरणाभिनन्दन एक राष्ट्रीय सत्कार

छठी योजना गांधीवादी हो

बुनियादी तालीम का एक प्रयोग

रचनात्मक कार्य की दिशा ,

स्वर-सत्कार

विज्ञान में सुधार

महात्मा गांधी

मोराजी देसाई

जाविर हुसैन

नादिक अली

श्रीमन्नारायण

राधाबहन

मदालसानारायण

अगस्त-सितम्बर '७७

- 'नई तालीम' का वर्ष अगस्त से शरम्भ होता है।
- 'नई ताली' का वार्षिक शुल्क वारह रुपए हैं और एक अंक का मुख्य दो व पत्र व्यवहार करते समय माहक अपनी सच्चा सिखना न भूलें।
- 'नई तालीम' में व्यक्ति विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा ज भा नई तालीम समिति सेवानामके लिए प्रकाशित
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन :

१० और ११ अगस्त को दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई ने किया। यह सम्मेलन कई दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि 'जनता पार्टी' की केंद्रीय सरकार गठित होने के बाद इसमें शिक्षा की नई नीति निर्धारित करना आवश्यक था। उत्तर भारत के लगभग सभी प्रदेशों में भी राज्य सरकारें जनता पार्टी की ही हैं।

अने उद्घाटन भाषण में श्री मोरारजी भाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि १०+२+३ के 'नए' शिक्षाक्रम को तभी सफल बनाया जा सकेगा जब वह महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धान्तों पर आधारित हो। इसके लिए यह जरूरी है कि हर स्तर पर शिक्षा का माध्यम समाज-उपयोगी उत्पादक थम हो। यह भी आवश्यक है कि शिक्षा का संबंध आस-पास की विकास योजनाओं से वैज्ञानिक ढंग से जोड़ा जाए और विद्यार्थी समाजसेवा के कार्य को अपनी शिक्षा का अविभाज्य अंग माने। प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि यदि हमारी शिक्षा पद्धति में इस प्रकार का कोई बुनियादी परिवर्तन न किया गया तो १०+२+३ का नया शिक्षाक्रम लगभग बेकार साबित होगा। हमारी समस्याएँ हल करने के बजाए उसको बजह से कुछ नई उलझने पैदा होंगी और शिक्षित बेकारों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी।

श्री मोरारजी भाई देसाई ने मातृभाषा माध्यम की हर स्तर पर व्यवस्थित ढंग से लागू करने पर भी बहुत जोर दिया। हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुसार इस समय हाईस्कूल तक तो शिक्षा का माध्यम सामान्यतः मातृभाषा ही है। कालेजों में मातृभाषा माध्यम ऐच्छिक रूप से चलाया जा रहा है। किन्तु मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की शिक्षा इस समय भी अंग्रेजी द्वारा ही अनिवार्य रूप में दी जा रही है। वर्धा में हमने कालेज स्तर पर मातृभाषा माध्यम का प्रारम्भ सन् १९४६ में ही किया था। इस अभिक्रम का उदघाटन स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। इस समय श्री हमारे वर्धा, नागपुर और जबलपुर कालेजों में एक काम तक सारी वाणिज्य शिक्षा हिन्दी और मराठी माध्यम द्वारा दी जा रही है। मातृभाषा माध्यम को सफल बनाने के लिए कामर्स के टेक्नीकल विषयों पर भी हिन्दी और मराठी में बहुत-सी सुन्दर और उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसलिए यह अनुभव से सिद्ध हो चका है कि हमारे देश में ऊँची से ऊँची शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं में दी जा सकती है।

किन्तु हमें खेद है कि शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई के विचारों और सुझावों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यही तर्क दिया कि नई शिक्षा प्रणाली को कुछ हेर-फेर के साथ सारे देश में लागू कर दिया जाए। कई प्रदेशों ने तो इसे प्रारम्भ कर भी दिया है। गैर राज्य इसे छोटी पचवर्षीय योजना के अन्त तक कार्यान्वित करें। सम्मेलन के प्रस्ताव में वृत्तियाँ दी शिक्षा के मिद्वान्ती का जिक्र भी नहीं है। मातृभाषा माध्यम को अनिवार्य बनाने में सम्बन्ध में भी कोई सिफारिश नहीं की गई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नागडवाला ने भी अपने सम्मेलन में यह बात माध्यम में इन विषयों का उल्लेख नहीं किया है। और न केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा. प्रतापचन्द्र चन्द्र ने प्रधानमंत्री के विचारों का समर्थन किया है। यह गन्तव्य बड़े आश्चर्य के दुःख का विषय है।

नई तालीम समिति की दिल्ली में तारीख १८ जुलाई को जो बैठक हुई थी उसकी सिफारिशें हम इस अंक में अलग प्रकाशित कर रहे हैं। हमारा निश्चित मत है कि यदि १०+२+३ के नए शिक्षा-धर्म में नई तालीम के मूलभूत सिद्धान्तों को ईमानदारी से लागू न किया गया तो वह एक महंगी निष्फलता साबित होगी। इस समय सारी दुनिया के शिक्षा शास्त्रियों का यह निश्चित मत है कि हमारी शिक्षा का आधार उत्पादक और समाजोपयोगी धर्म हो। यूनेस्को के अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा कमिशन ने भी इसी बात पर बल दिया है। हम आशा करते हैं कि केन्द्रीय और राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई के सुझावों पर एक बार फिर बहुत गहराई से विचार करनी और शीघ्र ही योग्य निर्णय लेंगी।

“पब्लिक” स्कूलों का भविष्य :

भारतीय संसद के पिछले अधिवेशन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केन्द्रीय शिक्षामंत्री डा. प्रतापचन्द्र चन्द्रन कहा था कि पब्लिक स्कूलों को बन्द करा देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वे अपने ढंग से उपयोगी कार्य कर रहे हैं। किन्तु जनता पार्टी के कई प्रमुख सदस्यों ने अपना स्पष्ट मत जाहिर किया है कि वर्तमान पब्लिक स्कूलों को अपना रंग-ढंग बदलना ही होगा और यदि वे ऐसा न कर तो उन्हें बन्द भी करना जरूरी हो जाएगा। नई तालीम समिति का यह निश्चित विचार है कि अब इन पब्लिक स्कूलों को अपनी वर्तमान पढ़ाई का ढाँचा और तौर-तरीका बदलना ही चाहिए। हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुसार पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। किन्तु इन पब्लिक स्कूलों में इस समय भी शुरू से ही बच्चों को अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षा दी जाती है। विभागा फॉर्मूले के अनुसार उनमें राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी उचित स्थान नहीं दिया जाता। उनका सारा वातावरण भी अंग्रेजी और ईसाई संस्कृति से भरा रहता है। यह सबदृष्टि से बहुत अनुचित है और इस सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य सरकारों को जल्द ही योग्य निर्णय लेना चाहिए।

य पब्लिक स्कूल मते ही चालू रख जाएँ क्योंकि उनमें कुछ बिभेपताएँ तो हैं ही। किंतु यह नितांत आवश्यक है कि उनका पढ़ाई का ढाँचा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीतिक अनुरूप हो। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि चूँकि वे सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं लते इसलिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में पूरी आजादी होनी चाहिए सरकारी सहायता न लत हुए भी उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अपना ढाँचा ढालना ही होगा। यदि वे ऐसा करने की तैयार न हों तो उन्हें चालू रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, तब आजाद देश के बच्चा और नवयुवकों का एक नया वर्ग खड़ा कर जायेंगे और इस कारण हमारे राष्ट्र में समानता के बजाय सामाजिक व आर्थिक विभेदताएँ और भी गहरी बनेंगी। यह सर्वथा अनुचित और अवांछनीय होगा।

गाँव वालों से संबंध जोड़े

महात्मा गांधी

[बुनियादी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से महात्मा गांधी ने धीमे-धीमे ग्रामों में नए नए स्कूलों में सन १९४५ में विस्तृत चर्चा की थी और सुझाया था कि स्वदेशीय के माध्यम से ग्रामीणों में साधारण सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। यह चर्चा नई तकनीक के पाठकों के लिए यहाँ दी जा रही है। यह कामगोपनीय भवन के प्रकाशित नहीं हुई है।]

गांधीजी — गाँव में बिखरकर रहना ठीक नहीं है। गाँव में काम करने के लिए यहाँ रहना है तो बाय वर्तकों का जीवन अलग होना जरूरी है यदि ऐसा नहीं रहेंगे तो हमारा खोला हो जाएगा। अलग रहने से अभिप्राय उनका हो कि हम से उनका जैसे धरा और वातावरण में न रहने से है। हमें अलग रहना है पर यहाँ रहते हुए हमारा हाड और हृदय एक होना है। स्वाभाविक की आवादी बढ़ रही है, दुगुनी हुई है इसीसे रोग बढ़त है। लोगो को जगह चाहिए, घर में हवा चाहिए खेतों में जाकर क्या नहीं रहते क्योंकि चोरों का डर है। इसलिए कैंसी भी गंदगी हो गाँव में ही रहें।

बाहर के लोग (बाय वर्तकों) गाँव में रहेंगे व गाँव के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। यहाँ नियंत्रण का अर्थ ठीक नहीं है तुम्हारा एक एक शब्द तोलकर होता है। बाहर के लोग जो गाँव में रहते हैं उन्हें गाँव के उसका और स्थिति आदि सामाजिक जीवन में हिस्सा लेना चाहिए, व हर चीज में हिस्सा नहीं ले सकते। व क्या चीज ले सकते हैं और क्या नहीं, यह उन्हें बताना चाहिए। देहात के लोग हमारी नकल करते हैं परंतु दूर से ही व समझ नहीं पाते कि उन्हें हमारे जीवन से क्या लेना है। देहातों की सारी शिक्षा में इतनी अधिक चीजें ग्रहण करना है। यह देखकर भागना नहीं, उनमें से अच्छी

चीजे ग्रहण करना है। कूड़े को सुधारना है। मैं चाहूँ तो कूड़े कचरे को बम से उड़ा दूँ और दूसरा गाँव बसा दूँ। मगर मैं यह काम नहीं चाहता हूँ। कि बम से उड़ा कर नया गाँव बसाऊँ। चाहे इस काममें (सुधारने) में दो पीढ़ी ही क्यों न लग जाए।

शान्ता बहन — गाँववालों से सम्बन्ध जोड़ने के लिए क्या करे ?

गाँधीजी — घर-घर जाकर बीमारों को देखो, जाकर उनके यहाँ सफाई भी करो, नई तालीम का यह हिस्सा है। जीवन का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो नई तालीम में नहीं आता, सब चीजों पर उसका कब्जा है। जहाँ तक हो सके तू ही (शान्ता) डाक्टर भी बनेगी। नैसर्गिक-उपचार पर मरोसा हो तो डाक्टर की जरूरत नहीं होगी। एक दिन ऐसा था कि मैं यह सब करता था। परन्तु आज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए दूसरों को भी नहीं रोक सकता। इसलिए मरीजों को देखना भी तेरा काम है।

शिक्षक के गुण य होने चाहिए कि उसका जो विश्वास हो वही करे, वह लोगों को जसा वह बंसा करे यह शक्ति उसमें आनी चाहिए उसके पास जितने बच्चे आएंगे, वे उसे लेकर उनके घर जाएंगे और उनकी माताओं का सिखाएगा।

शान्ता बहन — सेवाश्रम में अलग अलग संस्थाओं के काम चलेंगे। उनके सेवाश्रम में चलनेवाली अन्य संस्थाओं के कामों में कहीं तक मेरी जिम्मेदारी होगी? उनके प्रति मेरा क्या बर्तव्य होगा? सेवाश्रम में चलनेवाली अन्य संस्थाओं के कामोंमें कहीं तक मेरी जिम्मेदारी होगी?

गाँधीजी — गाँव में काम करनेवाला निश्चित जगह लेकर वह रहे क्योंकि तू तो इस काम को लेकर ही इस काम के लिए बैठेगा। मदद माँग सकती है। यदि दूसरे मदद दे सकें तो दे, नहीं तो बांग्र धूँए रहे सो रहे, परन्तु पसन्दगी तेरी ही रहेगी। तेरे में शक्ति होनी चाहिए, आत्म विश्वास होना चाहिए, कि काम होगा ही तू लाचार न हो, लाचार होगी तो पगु बनेगी। प्रौढ़-शिक्षा आता

नहीं। इन शिक्षिता से काम लेना ही है। देहातियों से काम लेना आसान है। वे अन्य कार्यकर्ता तो पढे लिखे हैं न।

नई तालीम का पूरा चित्र मेरे हृदय में बैठा है मैं ही नई तालीम का जन्म दाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह क्या चीज है। देहातियों को जागृत करना है। जिस शिक्षक में वह स्वभाव पैदा हो गया है वह ही जानेगा। मनुष्य स्वभाव को जीत लेना है।

विषय का विषय ज्ञान हो परन्तु शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों में साथ तो होना ही चाहिए। यदि यह सिद्ध नहीं होता है तो यह समझना होगा कि कही गलती है।

शान्ता बहन —सेवाप्रम के इर्द गिर्द की सस्थ ओ का सेवा-प्राम से क्या संबंध होगा ?

गांधीजी —सेवाप्रम की सब सस्थाएँ मेरा ही काम है। वे अहिंसा मार्ग के काम हैं। अंग्रेजी तरीको से चरने वाले एक के पीछे अनेक मन्न आए और उसी से यत्र-दास्त्र आया। इसका स्वरूप पश्चिम से आया। वैसी ही विश्व मूर्ति बनी। इसमें सामान्य काम भी हिंसासे करना होता है। यदि हम वैसे बने तो कैसे ठीक होगा ? इसके उल्टा हमें शान्ति से मार्ग निवातना है। इसी से हम शकट होती हैं।

सबको साथ रखना है शान्ति और महब्वत से काम लेना है। "सबको मिलाना" इसमें ही सारी नई तालीम की नींव डाली गई है। अहिंसा से सबको सिखाना चाहते हैं। सबको साथ लेकर काम करें इसके बाद अक्षर ज्ञान हो। इसलिए उद्योगों का अहिंसा के साथ गहरा तान्त्रिक है। इसमें आज व समाज में एक तरफ काम करनेकी वृत्ति है और दूसरा काम लेनेवाला है। लेकिन नये समाज में अब एव साथ सब काम करेंगे। य सस्थाएँ मेरी स्वेच्छा से हुआ काम है। अब वहाँ एक दुनिया पैठ गई है। इसलिए मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा काम यहाँ ही हो सकता है। अकला आदमी सब काम नहीं कर सकता। पहले दर्जे का काम सभी हो सकता है जब उसके साथ सबकी आकंक्ष काम लेनेकी "किन्" आजाए। हम, अलग-

अलग कंकरी जैसे है मगर हमें एक साथ मिलाकर ईंटकी तरह बनना होगा, फिर उनसे घर बनाता है। मेरा सहयोग का अर्थ अंग्रेजी को ज़ोर देना नहीं, वह तो मेरा अहिंसा का सहकार है। हमें गांधी के सामने एक आदर्श होकर दिखाना है। यहाँ की अनेक समस्याएँ एक के सदृश दिखाई दें। हम एक सौ पञ्चीस आदमी एक से ही नजर आएँ तो कुछ बताना नहीं होगा। गाँववाले देख सकेंगे। मकान को बोलने की जरूरत नहीं रखरख को कारी आवाज करते हैं।

बाहर के नए आदमी सेवाश्रम में रहने आएँ तो आएँ मगर तुम्हारी इजाजत से। गाँव के लोग भी इन नए आनेवालों से कहें कि शान्ता बहन की बिट्ठी लेकर आओ। नई तालीम का काम अवश्य है। किसी को पता नहीं चलेगा कि वह क्या चीज है लेकिन वह नई तालीम होती ही रहेगी। जैसे बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता नहीं कि वे क्या पढ़ते हैं मगर वह पढ़ाई तो दिल में बैठ जाती है, उसमें पीछे हटना नहीं है।

भय निवारण :

शान्ता बहन—देहात में काम करने के लिए गांववालों के भय को कैसे दूर करें ?

गांधीजी—यदि लोग कहें कि काम मत करो, हमें डर लगता है तो हमें (काम करने वालों को) बताना है कि आपको डर लगता है तो सिपाही से कहकर हमें पकड़वा दो। पर हम डटे रहेंगे। सफाई और काम करते रहेंगे। अगर हमसे डर बिल्कुल निवृत्त जाए और लोगों को इस पर विश्वास हो जाए कि हम निडर हैं तो अपने आप उनका डर निवृत्त जाएगा। लेकिन अभी हम में वह नहीं है। वह बात मेरे अनुभवसे बाहर है। “बेतिया के लोग डरपोक थे मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि वे चले जाओ वा हटो, ऐसा कहेंगे शान्ता बहन की बात बर लूँ। सेवाश्रम में वह स्वतंत्र काम चलाएंगे महाँ काम बड़ा है। इतनी समस्याएँ हैं परन्तु वह उसी चीज को देखेंगी जो नई तालीम के दायरे में आ सकती है।

जाजूजी —क्या वह गुड का काम भी देखेगी ?

गाँधीजी —मैं तो कह सकता हूँ कि यदि गुड वाला भी मेरे पास आए तो मैं यत्न दूँ कि वह कैसे हो सकता है। सब चीज का संशोधन मैं करने वाला हूँ। वह यह, यही नहीं कह सकती है। वह कहती है मैं स्वतंत्र रूपसे आपके मातहत काम करूँगी। आपसे पूछकर काम करूँगी क्योंकि यह आपका काम है। आपने कहा है कि सेवाग्राम तैयार हो जाए तो मैं समझूँगी कि सारा हिंदुस्तान तैयार हुआ है।

शांति वहन नई तालीम की दृष्टि से बैठेगी वह शिक्षण की दृष्टि से बैठेगी तो दूसरा काम बहुत कम रह जाएगा। दूसरा कोई काम करे तो वह उन्हें शिक्षिका की दृष्टिसे बताएगी कि ऐसा करो नहीं करेंगे तो जैसा मन चाहे वैसा चले।

नई तालीम अपने आप चलने वाली चीज है। स्वाश्रयी हो सकती है। गुडवाला अपने आप उसके पास पूछने के लिए आया—भाता वहन कैसे करूँ कि लड़का को भी साथ ले सकूँ। अगर वह स्वतंत्र मिजाज का आदमी है तो वह दुख शांति के लिए एक विषय बन जाता है। ओटनलट है न? उसे सोचना होगा कैसे मैं इसके साथ कैसे चलूँ कि वह मेरे साथ सीधे चले। स्वाश्रयी बनना है तो कोई चीज नई तालीम के बाहर रह नहीं सकती।

जो काम उस ढाँचे में नहीं आता वह उसे छोड़ देगी। उसने मेरा सहारा लिया है कि मैं हिसाब ले लूँ कि वह क्या कर सकती है और क्या-क्या नई तालीम में आता है क्या-क्या नहीं। दूसरे कार्य कर्ता के पास मैं नई तालीम की बात नहीं करूँगी। वह ग्राम उद्योग या चरखा ले ले। जितना कर सकते हो करो उस स्वाश्रयी बनाओ।

गाँधीजी —क्या करोगी? अंडल्ट एज्युकेशन से शुरु करोगी न?

शांति वहन —हाँ मैं तो पूर ममाज से सम्बन्ध होगा वहाँ वातावरण बनाना होगा और यह अस्वाभाविक भी न हो ऐसा लगता है इसलिए उनके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध कैसे बढ़ाया जाए? वहाँ पुरुष है स्त्रिया है, नवयुवक हैं वच्चे हैं। इनमें से कई कुटुम्ब सस्या से सम्बन्ध रखते हैं लेकिन सस्यावा जीवन उनका जीवन है ऐसा नहीं मानते हैं। उनमें यह भाव कैसे पैदा किया जाए? ग्राम पंचायत

का काम है। मालगुजार भी गाँव का एक प्रौढ़ है उसपर गाँव की जिम्मेदारी है। ऐसे कई प्रश्न हैं। इसलिए मुझे गाँव में जाकर ही रहना होगा। मैंने सोचा है एक एक मुहल्ले में १५ दिन रह कर लोगों से सम्बन्ध बढ़ाऊँ और उनमें मिल जाऊँ। वही ठीक होगा न? मेरे साथ यदि और कोई आएँ तो हम सब इसी तरह गाँव में फैल जाएँगे। शिक्षामें इतनी चीजें आती हैं उसे देखकर भागना नहीं उसमें से अच्छी चीजें ग्रहण करनी हैं। कूड़े को सुधारना है। यदि चाहें तो इस कूड़े कचरे को बम से उड़ा दें और दूसरा गाँव वसा दें मगर यह बात मैं नहीं चाहता हूँ चाहे उस सुधारके शिक्षा के काम में दो पीढ़ी ही क्यों न लग जाएँ।

शान्ता बहन :—फिर गाँव से सम्बन्ध बढ़ाना है तो किस तरह प्रवेश करें ?

गांधीजी :—घर-घर जाकर बीमारों को देख रेख और सफाई भी कर। यह नई तालीम का हिस्सा है जीवन का एक भी विभाग ऐसा नहीं है कि जो नई तालीम में नहीं आता हो। सब चीजों पर उसका कब्जा है। जहाँ तक हो सके तू डाक्टर भी बनेगी और नैसर्गिक उपचार पर भरौसा हो तो डाक्टरकी भी जरूरत नहीं होगी। एक दिन ऐसा था कि मैंने डाक्टर को नहीं बुलाया था। उस समय मेरा पदम आगे बढ़ा था। पर आज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए दूसरों को भी नहीं रोक सकता हूँ। मरीजों को देखना भी तेरा काम है परन्तु अभी तेरी यह हैसियत नहीं है। शिक्षक में यह गुण होना चाहिए कि जो बिदवास्त हो वही नरे। लोगों को हम बहें और वे वस्ता करें यह शक्ति हममें आनी चाहिए क्योंकि जितने बच्चे उसके पास आएँगे वे गुण लेकर घर जाएँगे और माँ बाप को सिखाएँगे।

शान्ता बहन :—मेवाग्राम देहात में अलग-अलग विधायक कार्य अलग-अलग समूहों के माफ़ेन चलेगा उनके बारे में मेरा क्या फर्क होगा जैसे ग्राम उद्योग, छादी बायें, दवा-शास्त्रा, इन संस्थाओं के कार्य में मेरी क्या जिम्मेदारी रहेगी ?

गांधीजी — घर लेकर रहे पर निश्चित जगह लेकर रहे क्योंकि जो इस काम को लेकर बैठे वह सारी जिम्मेदारी लेकर चले। तू मदद मांग सकती है। यदि मदद दे सके तो द नहीं तो काम अधूरा रहे परन्तु पसंदी तेरी ही रहेगी। तेरे में शक्ति होनी चाहिए। आत्म-विश्वास होना चाहिए कि काम होगा ही तू लाचार न हो लाचार होगी तो पगु बनगी।

अॅडल्ट एज्युकेशन आसान नहीं जब कि देहातियोसे काम लेना आसान है। लेकिन शिक्षितों से काम लेना आसान नहीं है, मगर तेरा आत्म-विश्वास हो कि काम लेना ही होगा। नई तालीम क्या चीज है वह तू अभी नहीं जानती लेकिन उसका पूरा चिन्म मेरे हृदय में बैठा है। मैं ही नई तालीम का जन्म दाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह क्या चीज है। देहातियों को जाग्रत करना है। जिस शिक्षक में यह स्वभाव पैदा हो गया है वह ही जानेगा कि सत्य मनुष्य स्वभाव को जीत लेना है। उनका साथ किस तरह वातें करनी, होगी वह पहचान लेता है। विषय का ज्ञान न हो परन्तु शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में साथ होना जरूरी है। यदि यह सिद्ध नहीं होगा तो कहीं-न-कहीं गलती है यह समझ ले।

शान्ता बहन — गाँव में पानीका इतना कम बँसा हो। पानी तो गंदा है और कुएँ भी बुरे हैं।

गांधीजी — बड़े परिश्रम से ही सही पर पानी तो उबाल कर पीना है। जो गन्दे कुएँ हैं उन्हें बंद कर दो। इस काम में पैस खर्च करेंगे क्योंकि ये बीमारी का घर हैं, ज्यादा कुएँ हैं, इतने कुआँ की जरूरत नहीं है बंद करके से पल्लों से पानी भी बनेगा। आम कुओंके साफ रखने का खर्च तो जनता को ही देना होगा। निजी कुएँ मालिक सुधारें नहीं तो मालकी छोड़ दो और उस पब्लिक फंड से सुधारें। इस तरह सब कुएँ हमारे हाथ आ जाएँ। देहात के लिए देहाती वाटर-वर्क बन जाए पर यह कैसे हो यह सोचने की बात है। काम ऐसा हो कि सारे हिन्दुस्तान के लिए हो सदा हो सस्ता हो। सनातन का आदर्श सबके लिए हो और खर्च भी हो और फिर वह सात लाख देहात के एक नमूना बने।

शान्ता बहन —गारनेखर भाई कहते हैं कि इनेक्ट्रिसिटी से यह काम आसान होगा।

गांधीजी —इनेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने कहा है कि मुझे वाँधो मत। पहले तो वह दो कि सारे हिन्दुस्तान में हो सकता है तब मुझे लगना इतनी पावर तो लेनी होगी फिर ऐसे कामों के लिए पब्लिक फंड जमा कर। पब्लिक भी हिस्सा रहे और उसमें आश्रम का हिस्सा भी रहे। आश्रम गाँव के किनारे है और हमें तो लोगों को तालीम देनी है।

शान्ता बहन —आपने कहा था गाँव में रहने जाए तो आश्रम से ही शुरू ही मगर आश्रम का खाना और रहन-सहन साविक है और गाँववालों से अलग है व देहान में कैसे रह सकेंगे?

गांधीजी —परिश्रम से ही सही पर पानी तो नाल कर पीना ही है। मैंने पहले सोचा था दहात में ही रहूँगा मगर चेचक का टीका आदि मुझ नहीं जना था। मुझे क्लेम रहना है ऐसा डाक्टर ने इसीलिए कहा था। प्लेगी डार्ड के विषय में यह बात है कि थोड़ा दूध तो लेना ही चाहिए प्राणीज प्रोटीन थोड़ा रा भी होनेसे दूसरी प्रोटीन अच्छी पचती है। अतएव थोड़ा प्रमाण दूध का रखें। १० तोला दूध और एक तोला घी मगर सच्चा घी हो।

आसादबी —बच्चोंको हम १ तोला तेल देते हैं।

गांधीजी —वह पूरा नहीं है, आज वह चलता है—क्याकि उन्हें घर में कुछ भी मिलता नहीं मगर अपना माप हम उसपर से न निकालें अपना शरीर ईश्वर का घर यानी जनता का है ऐसा मानते हैं, जनता के कारण हम ज़िन्दा रहना चाहते हैं तो शरीर अच्छा रखना है। आश्रम में तबीयत बिगड़ती है उसका कारण यह है कि ये लोग प्रमाण नहीं रखते, अब तबीयत बिगड़नी ही।

मुशीला बहन —यहाँ मसाला और न होने के कारण स्वादिष्ट खाना नहीं होता इसलिए प्रमाण नहीं रख सकते।

गांधीजी —स्वादिष्ट खाना नहीं है इसलिए प्रमाण नहीं है यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। दहात में जो खाना है वही

खाते हैं खाने में भी बला है। आश्रम-जीवन में शिक्षा देनी है। न तो ज्यादा नहीं और न छोड़ना ये बातें सीखने लायक हैं।

शान्ता बहन — खानेमें दूध होना जरूरी है और माँ बाप दूध के लिए पैसा दें ऐसा आपने कहा है, बच्चों को दूध देने के लिए उनके जेब में पैसे वहाँ हैं ?

गांधीजी — वही तो करना है। उसमें अंडल्ट एज्युमेजन्त है। उन्हें जिम्मेवारी समझना है। उनकी कमाने की शक्ति बढ़ाना है। उन्हें भिक्षुक नहीं बनाना है। आखिर उन्हें खान-पीना तो देना ही है। उनके ढंग दो हैं एक है रुस का। हमें वही चीज अपने ढंग में करनी है। यदि हम नहीं कर पाते तो कुछ कमी है। मैं मानता हूँ कि वह बनना चाहिए। वहाँ तो उन्होंने सारी दुनियाँ का नहीं सोचा। एक बड़ समाज का सोचा है। यहाँ तो एक सेनाग्राम लेता हूँ माने सारे दुनियाँको ही लेता हूँ। उनका समग्र जीवन लेकर एक सेनाग्राम देहात में कितना हो सकता है वह देखना है। एक बमाए और सौ खाए तो नहीं हो सकता है। हरेक बमाए और हरेक खाए तो हो सकता है। मुझे मरीज के मरने की परवाह नहीं है मगर मरीज होने से रोकूँ इतना बस है। अच्छे समाज में पगु बहुत बम रहते हैं। बच्चे को तो माँ-बाप खिलाते ही हैं अच्छे कुटुम्ब में बच्चे भी लम्बे अगसे (समय) तक भार नहीं होने। यदि ३-४ वर्ष का भी बच्चा बमाने लगे है तो हमारी तानीम है। कालेजवाले दरिद्री बनते हैं।

सेनाग्राम का आदमी हमारे यहाँ काम करता है। हम इसके बाल बच्चाका नहीं देखते हैं हमें उनके साथ के वर्तन में उनके और उनके बच्चों के साथ के व्यवहार में भिन्नता लानी है और रिस्तेदारीकी भावना निर्माण करनी है। वे उनका खाना अलग, कपड़े अलग रखते हैं। उसमें भी बला है। वे अपने को अलग समझते हैं मगर वे हमारे रिस्तेदार और सहकारी साथी हैं। हमें तो समझना होगा कि हम उनके साथ कैसे चलें अपने को अलग रखते हैं तो उसमें सुधार लाना होगा।

शान्ता बहन — यदि खाने में दूध न मिले तो क्या चीजें देनी होगी ?

गांधीजी — इसीलिए जो भूमिहारी हैं उनसे मैं चला हूँ कि यदि और कुछ न मिले तो भूमि, अण्डे याओ लेकिन आवाहारी को पहुँगा नाम न मिले तो मृत्यु मर जाओ। दक्षिण अफ्रीका में मृत्युप्रतियोगे आवाहारी के लिए जिस तरह तस्वारी जमा की थी वह समझने लायक है। आवाहारी को मनस्पति-शास्त्र जानना ही चाहिए। देहात के गरीबों को शिवा के मोषे जैसा बनाना है।

शांता बहन — भूमिहारी की आवादी बहुत बड़ गई है, नई आवादी बढ़ानी है तो घरों की व्यवस्था बंभी हो ?

गांधीजी — नया सेवास्यम अपना हो तो जगह हम देंगे। लोग घर अपने आप बनाएँ मगर जमीन पर उनका हक नहीं होगा। यदि घर बदलना पड़ा तो जो दूसरा आदमी जाएगा वह घर बनाने में जितना पैसा लगाया गया होगा उतना देकर घर ले सकेगा। लेकिन लोग घर के लिए जमीन माँगकर घर बसा लेंगे परन्तु पैसे की जगह परिश्रम देकर खाली रहने के लिए घर लेना पसंद नहीं करेंगे।

हमारे हाथ में राजस्व नहीं है और मैं आचार-विचार का भी जोर नहीं कर सकता हूँ। मैं जो सत्याग्रह करना चाहता हूँ वैसा हो तो जनता मुझे आप ही सहारा दे देगी। मगर लोग मुझे समझ लें। वे मुझे समझ लें तो फिर मेरा स्थान-स्थान नहीं रहेगा। हमारे खेतों को मैं उजाड़ दूँगा और लोगो को बसने के लिए जगह दे दूँगा। वे आज भी हमारे यहाँ आ जाएँगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे यह करने को तैयार नहीं हों। वे यह चाहेंगे कि जमीन मिल जाए उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं जमीन का मालिक नहीं यह वे नहीं मानेंगे। वे तो जमीन माँगेंगे।

शांता बहन — गाँव में दो विस्म के आदमी हैं। एक तो वे जिनके पास जमीन नहीं है और जमीन के मालिक नहीं बनोगे लेकिन पैसा और परिश्रम लगाकर मकान बनाना चाहते हैं। दूसरे वे हैं जिनके पास जमीन है पैसा नहीं है यदि वे अपनी जमीन पर घर बनाएँ तो विस्मो द्वारा पैसा अदा करेंगे पर तब तक वे घर पर कब्जा नहीं रखेंगे ऐसे लोगो को किस तरह मदद करनी होगी ?

गांधीजी — इसके लिए एक सहकारी गृह निर्माण समिति बनानी चाहिए। घर बनाने के लिए उन्हें पैसा उधार देना होगा और लोगो को सस्ती बरदास्त करनी पड़ेगी। जब तक भूरा पैसा अदा नहीं किया जाएगा तब तक घर, सोसायटी का रहेगा। हमें लोन निकालना होगा।

शान्ता बहन — पुराने घर चोरोके डर से बचे थे। वहाँ लोग पैसे गाड़कर रखते थे। इसलिए वे ऐसे थे। यदि कोऑपरेटिव्ह बैंक जैसी पब्लिक सायबरी हो तो घर अच्छे बनेंगे।

गांधीजी — यह पक्ष ना बदल नहीं है। वे लोग पैसे घरमें दबाकर रखन हों तो उसे तिक नवाना चाहिए। सोना तो सरकार ने सब खींच लिया। १ पौंड में १० शि दिए। अब जा रखने है उसका प्रबध करके फिर घर बनाना है। इसमें डर रहेगा ही नहीं।



संस्था कुल

गांधी स्मारक निधि का मासिक

सम्पादक — श्री पूर्णचन्द्र जैम

वार्षिक शुल्क—५ रुपये,

एक प्रति—५० पैसे

रचनात्मक प्रवृत्तियो, कार्यों सर्वोदय मगठन एवं

राष्ट्रीय हस्तकला की जागरूकी देनवाला

एक प्रभावशाली माध्यम

संपर्क करें—व्यवस्थापक, संस्थाकुल

गांधी स्मारक निधि,

राजघाट, नई दिल्ली-२

बुनियादी तालीम

मोरादजी देसाई

[१०-११ अगस्त की नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री श्री मोरादजी भाई देसाई ने बुनियादी तालीम की अनिवार्यता पर ध्रुव ज़ोर दिया था। उनके उद्घाटन भाषण के मुख्य अंश यहाँ प्रकाशित किए जा रहे हैं।]

यदि हमें अपनी सही हालत में आना है और देश को उन्नत बनाना है— जैसा कि हम उसे उन्नत बनाना चाहते हैं तो उचित शिक्षा को तथा हमारे सपनों और गांधीजी के स्वराज्य के सपनों को पूरा करने को मैं महत्त्व देता हूँ।

मेरी दृष्टि में कृषि और शिक्षा ये दो विषय अन्य सभी विषयों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। कृषि पर हमारी आर्थिक उन्नति निर्भर है। उसी के बिना और आर्थिक उन्नति गढ़ी जानी है। शिक्षा पर हमारे मानव एवं भावी नागरिकों की निर्भरता निर्भर है। हमारे हर एक बाल पर हमारी युवापीढ़ी को दी जाने वाली शिक्षा के गुणों का असर पड़ता है।

हम शिक्षा-पद्धति की उन खामियों के शिकार हैं जो पाश्चिमात्य विचारधारा द्वारा भारत के धर्म-परिधर्तार्थ हम पर आरोपित की गई थी और मेकॉले द्वारा अपने मूनाघार से पच-भ्रष्ट या च्युत कर दी गई थी। यह वही है जो अभी भी बटल है और यही वह दिशा है जिसे हमें बदलना है। मुझे खुशी है कि जाय सब इन दृष्टिकोणों पर विचार कर रहे हैं। किन्तु जब तक हम शिक्षा सबंधी अपनी वृत्ति एवं अंतर वस्तु में मूलमूल परिवर्तन नहीं करते तब तक मुझे भय है कि पैबन्द लगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है और यही हो रहा है।

१०+२+३ की शिक्षा संरचना को लीजिए। मैं नहीं जानता कि यह क्या है। मुझे नहीं मानूम कि यह कैसे कोई लाभ पहुँचाएगी। इसने और अधिक बुरे के लिए परेशान कर दिया है। मैं नहीं समझता कि उसने कुछ अधिक भला किया है। शिक्षा में इस तरह का परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है। मैं समझता हूँ कि अतः यह जनता को केवल दिग्भ्रमित करता है कि वह सोचने लगती है कि हम कुछ अधिक अच्छा कर रहे हैं।

शिक्षा का उद्देश्य यह देखना है कि उसने मानव को जिस बुद्धिमत्ता और क्षमता को दिया है वह उचित अनुपात में उसकी खुद की भी समझ में आती है या नहीं तथा आजीवन वह अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता को बढ़ाते हुए पूरी तरह से भलीभाँति उसका सदुपयोग करता है या नहीं। शिक्षा का यह सही उद्देश्य है और यदि उसकी उपलब्धि नहीं होती है तो शिक्षा अपनी उपयोगिता के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगी। अतः उसे उत्कृष्ट सारभूत चरित्र उत्पन्न करना चाहिए। वह निर्भयता और सत्य प्रदान करे। क्या ये गुण हममें हैं? हम तो दूसरों के लिए चिन्तन, हिम्मत, साहसिकता, भय-रहित प्रोत्साहन के अभाव में एकमेक भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता में पीड़ित हैं। यदि हममें उपर्युक्त गुण नहीं आते तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ तो हैं ही और रहेंगी किन्तु हम उन्हें और अधिक न बढ़ाएँ। यदि हमारे जीवन में सुलझाने के लिए और सामना करने के लिए कठिनाइयाँ नहीं हैं तो मचमुच में जीवन में आनन्द नहीं रहेगा। इसलिए उन्हें हमें ललकारना चाहिए। ऐसा करने में शिक्षा हमारी मदद करे और यही उसने नहीं किया है। महात्मा गाँधी ने इस देश के लोगों को सिखाया और उसे नई दिशा देने के लिए जो कुछ किया वही कुछ हद तक किया गया है। दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित लोगों ने जैसा उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए था वैसा नहीं बढ़ाया।

हमें भूत में नहीं जाना चाहिए, न उसकी चीर-फाड़ ही करनी है और न किसी व्यक्ति को दोष ही देना है। मैं सोचता हूँ कि हम सभी उसी तरह की शिक्षा की निष्पत्ति हैं अतः किसी को दोष न दें। यही कारण है कि हमें उससे हानि उठानी पड़ रही है। जो आज उस जगह पर

है उनमें से भी किसी की भूल नहीं है किन्तु अब यह हमारी भूल होगी। यह जानते हुए कि वमी कहाँ है और अब हमें क्या करना है, हम इन बाधाओं, बिम्बों को सही स्थिति पर आने की दृष्टि से यदि दूर न करें।

हमारे लिए यह भी कोई अच्छे भाव्य की बात नहीं है कि मुझे यहाँ अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा है और मैं नहीं जानता कि कितनी अधिक अवधि तक मुझे यह करते रहना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा से मेरी कोई लड़ाई नहीं है किन्तु उसे हम भारतीय भाषा तो नहीं कह सकते। मेरा तात्पर्य यह है कि क्या भाषायी दृष्टि से भ्रष्ट इतना गरीब है कि उसकी अपनी भाषा नहीं रह सकती? यहाँ भी हमारी शिक्षा का ही दुस्मानुभव है और कुछ क्षेत्रों में भय और बाधाएँ उत्पन्न की जा रही हैं। मैं किसी के भय को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं किसी की बाधाओं को, आपत्तियों को टालना या तरह नहीं देना चाहता। जनता पर जबरदस्ती कुछ लादा नहीं जा सकता। यह प्रजातन्त्र नहीं है। किसी पर कुछ जबरदस्ती लादने का तो सवाल ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या भारत का हित नहीं सोचना चाहिए? वह कौन परेगा? मैं सोचता हूँ कि वैद्यन शिक्षा अर्थात् शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए लोगों का ही यह कर्तव्य है किन्तु दूसरों को शिक्षित करने से पहले उन्हें अपने आप को शिक्षित करना है।

शिक्षा मंत्रियों का यही काम है जिसका आपको समझा बताया है। यदि आप मुझ से सहमत हैं तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा को बदलने और अच्छी अंतर्वस्तु देने में तथा अपने अनुरूप बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि पूरे घूम जाओ की पद्धति से शीघ्र ही कुछ कर सकना सम्भव नहीं है। यह न तो सक्षम तरीका ही है और न वांछनीय ही। लेकिन यदि हम तय करते हैं कि हमें क्या करना है कहाँ पहुँचना है तब हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं और हमें जल्दी से जल्दी गन्तव्य स्थान पर पहुँचना है तो हमें उसमें अपरिहार्य बिलम्ब न करना चाहिए। और न हमें अपनी क्षमता और पावन शक्ति से अधिक थम ही करना चाहिए। ये वे मापदण्ड हैं जिनपर हमें अपने कार्यक्रम आधारित करने चाहिए। यदि आप इन श्रृंखलाओं पर सोचें

तो मुझे विश्वास है कि आप भी उन्हीं निर्णयों पर पहुँचेंगे जिन पर मैं पहुँचा हूँ।

अब शिक्षा के माध्यम की बात। बालकों की शिक्षा का माध्यम आदि से अन्त तक मातृभाषा क्यों न हो? इसमें कहीं झगड़ा है? इसके बारे में किसे झगड़ना चाहिए? इसके बारे में कोई नहीं झगड़ेगा। धर्म शिक्षा रास्त्री भी कहने लगते हैं कि मातृभाषा की अपेक्षा अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाए, अपनी सर्वसाधारण भाषा को भी नहीं बल्कि अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाए। क्या यह दुर्बलता या कमजोरी नहीं है, जिससे हमें क्षति उठानी पड़ रही है? यदि आप इस कमजोरी का अनुभव करते हैं तो क्या हमें उसे हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? भारत के लिए होनिकारक हुए बिना उसे अधिक से अधिक सम्भाव्य हितावह रीति से हटाइए। और इसे किया जा सकता है। मैं नहीं कहना कि प्रत्येक प्रदेश में प्राथमिक से पीएच. डी. तक मातृभाषा में शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती? रास्ते में क्या रुकावट है? यह कहना कि हमारी भाषाएँ विकसित एवं समुन्नत नहीं हैं, केवल हीन भावना है और अपनी ही चीजों के प्रति सम्मानहीनता है। जब अंग्रेज यहाँ ये तब देश के सारे हिस्सों में देशी रियासतें थी जिनमें शासन का कार्य जनता की भाषा में चलता था। यदि वे उस कार्य के उपयुक्त नहीं थी तो उनमें कार्य कैसे होता था? यदि आप किसी भाषा का उपयोग न करते तो स्वभावतः पुस्तकें प्रकाशित नहीं होगी। पर यदि आप पुस्तकों के प्रकाशित होने तक ठहरेंगे और फिर कहें कि भाषा का प्रयोग हो सकता है तो आपको चिरतन काल तक रुकना पड़ेगा। यदि आप भाषा का उपयोग नहीं करते हैं तो वह समृद्धिशाली नहीं होती है। और हमें तो उसे समृद्धिशाली बनाना है। दुःख की बात तो यह है कि कृषि की शिक्षा भी अंग्रेजी में ही दी जाती है। कृषक उसे कैसे समझेंगे और वे उससे कैसे लाभान्वित होंगे तथा वे गाँवों में दूसरों तक कैसे सम्प्रेषित करेंगे? यही कारण है कि महाविद्यत्तर्यों में निकलकर आनेवाले अधिकांश लोग नौकरियाँ ही करना चाहते हैं और कृषि को समृद्ध नहीं करते जो कि उन्हें करना चाहिए। अतः मेरी दृष्टि में ये सब स्पष्ट बातें हैं जिनके

लिए अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं है। मैं इन पर अधिक नहीं कहूँगा। यह आवश्यक भी नहीं है।

आप सब शिक्षा मंत्री होने के कारण इसमें उत्तनी ही रुचि रखते हैं। मैं नहीं मानता कि आप मुझसे अधिक रुचि रखते हैं। वरन् आपकी भी समान रुचि है। मैं आशा करता हूँ कि आप समान रूप से इसलिए रुचि रखते हैं कि एवमान शिक्षा मंत्री हो जाना शिक्षा में बहुत रुचि उत्पन्न नहीं करता। वह तो पहले से ही वर्तमान रहनी चाहिए। दुर्भाग्य से अब तक शिक्षा मंत्री के पद इसी प्रकार दिए जाते रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि अब ये ऐसे नहीं होंगे।

हमें यह देखना है कि प्राथमिक स्तर से ही उचित ध्यान दिया जाए क्योंकि यही सब आधार रखा जाता है और हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। 'बच्चे को मनुष्य का गिता' कहा जाता है। क्योंकि वह मनुष्य बनता है, वह पिता बनता है और यदि वह ठीक नहीं है तो भावी पीढ़ी ठीक नहीं होती। जो लोग मेरी ओर आपकी तरह बूढ़े हो गए हैं, या अंधेड़ उम्र के हैं या तरुण हैं उनकी कुछ उन्नति कठिन है। चीनी मिट्टी के कप के टूटने के बाद उसमें सुधार सम्भव नहीं है। विन्तु जब वह कच्ची मिट्टी होती है तब उसे चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है। इसीलिए यदि हम स्वयं सावधान हैं तो ये बच्चे ही हैं जिनका इन आदर्शों के अनुसार संवर्धन सम्भव है। यदि मैं कहूँ तो कह सकता हूँ कि हमें उन्हें अपने उस साथे में नहीं ढालना है जो बहुत वांछनीय साँना नहीं है। और मैं यह प्रार्थना करूँगा कि यही हमें प्राथमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन शिक्षा के किस्म-संवर्धन की दृष्टि से विचार करना है।

हम सभी दृष्टियों से बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उनके शारीरिक गठन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं एक बार कुछ आँकड़े पढ़कर सचमुच चिंतित हुआ था कि भारतीयों की ऊँचाई घट रही है। जब कि अन्य देशों में वह बढ़ती जा रही है, वे ऊँचे होते जा रहे हैं। ऊँचा या नीचा होना उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं

है जितना कि ऊँच होना अथवा पिछड़ना। यदि आप गतिहीन या निश्चल रहने हैं तो आप पिछड़ते हैं या नीचे गिर पड़ते हैं। अतः प्रत्येक को प्रगति करनी है। किन्तु हम प्रगति नहीं कर रहे हैं वरन् हम तो पीछे जा रहे हैं। चर्चा के स्वास्थ्य की ओर जैसा कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए वैसा नहीं दिया जा रहा है। हम दापहर व भोजन तथा अन्य अनिवार्य कार्यभार मोचते हैं। व अपने में अच्छे हैं किन्तु एक भान व अपने में विनम्र अछ नहीं। व तो चर्चा व स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के साधन मात्र हैं। मृग इमम मन्द नहीं हैं कि इन विना भी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सकता है।

ईश्वर ने मनुष्य की आदर्शजनक सृष्टि की है। वह हर स्थिति में रह सकता है और हर प्रतिकूल परिस्थिति व बावजूद भी अपने को महान बना सकता है। मानव को यह क्षमता दी गई है और शिक्षा में हमें उस प्राप्त करने की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियाँ में रहना चाहिए। कुछ बाधाओं व कारणों तथा कठिन परिस्थितियों में हानि व कारण किसी को भी न ता चिल्ला-या मचानी चाहिए, न एकदम निराशावादी हो बनना चाहिए और न हताश हो होना चाहिए। आप दुनिया व अनेक उदाहरणों से देखें कि प्रत्येक व्यक्ति यदि चाह और दृढ़ निश्चयी हो तो बाधाओं को पार कर सकता है। असल में बहुत से महान व्यक्ति सुखी परिस्थितियों की नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों की उपज हैं। यह जीवन का सत्य है। अतएव पान्थों को बचपन से ही यह गुण सिखाया जाना आवश्यक है।

परन्तु यह केवल तभी सम्भव है जब हमारे पास उपयुक्त शिक्षक हों। अतएव शिक्षक हमारी शिक्षा है। पाठ्यक्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उपयुक्त शिक्षक। शिक्षक का व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार ही बालकों पर अपना प्रभाव डालता है। इसी पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। इस शिक्षा में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाली संस्थाओं को अधिक प्रभावगामी बनाया जाना है। व व्यापारिक संघों में रूपांतरित होने के कारण ह्रासशील हो रही हैं। क्या यदि

अति नाछनीय है? विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और फिर इसी कारण छात्रों और शिक्षकों के बीच जशान्ति दिखाई देती है। यह क्यों होना चाहिए? शिक्षकों, विद्यार्थियों और समाज के बीच क्या संघर्ष है? कोई संघर्ष नहीं हो सकता। दोनों के बीच मेल्याण की अनुरूपता है। फिर भी वे संघर्ष उत्पन्न करते हैं। इसमें केवल अधिक समझ की आवश्यकता है। इस विद्या में भी हमें सोचना और काम करना है।

इसलिए मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि बुनियादी शिक्षा को अपने सही रूप में और उपयुक्त शिक्षकों के सहित आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब कि शिक्षा मशीन प्रभावित हो जाएँ और ऐसा करने का दृढ़ निश्चय करे। फिर इसे कोई नहीं रोक् सकता। और इस पर आप सब को विचार करना है, आपस में चर्चा करनी है, एक निश्चय पर पहुँचना है। मैं आपको कुछ भी करने पर बाध्य नहीं कर सकता। मैं ऐसा करने का प्रयत्न भी नहीं करूँगा। मैं तो केवल आप लोगों को सब तक मनवाता, समझाता रह सकता हूँ जब तक कि मुझे सरलता नहीं मिल जाती। मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ। शिक्षा डंडे का ज्ञान नहीं है। यह तो और कुछ से मनवाने की प्रक्रिया और आत्मोद्धारण की ही प्रक्रिया अविवक्षित है। और इसमें इसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए।

यदि आप बुनियादी शिक्षा से प्रारम्भ करते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को हर स्तर पर उत्पादक काम देते हैं तो आप उसे एकदम भिन्न व्यक्ति बना देंगे। वह आत्मविश्वासी अधिक होगा और अपना इन्तजाम कैसे करे, इसमें वह जानेगा। प्रथम श्रेणी के एम एस सी, एम ए कुछ इंजीनियर डाक्टर मेरे पास आकर अपनी बेकारी की बात मुझसे कहें यह विचारा करणार्थक दृश्य है? कोई डाक्टर क्यों ऐसा अनुभव करे? कला का व्यक्ति कुछ हद तक अपने को असहाय अनुभव करे यह मैं समझ सकता हूँ, किन्तु यदि उसने उचित शिक्षा प्राप्त की है तो उसे भी ऐसा अनुभव करने का कोई कारण नहीं है। किन्तु ये भी अपने को असहाय अनुभव करते हैं। इसका क्या मतलब है? यह हमारी शिक्षा की कमी को ही बताता है। इसी को हमें ठीक करना है। किन्तु यह तभी हो

पाएगा जब कि हम उह चारित्रिक दृष्टिकोण देंगे जिसकी कि आज नितान्त कमी है। और चारित्रिक दृष्टिकोण अपने से अधिक दूसरो के बारे में सोचने से ही आता है। यह चारित्रिकता ही है जिसकी ओर मैं लौटना चाहता हूँ। यही चारित्रिकता इस देश की अपनी विपत्ति है। यह हमारी सस्रुति का मूल-तत्व है। यह मूल-धार है जिस हमने दृष्टि स ओझल कर दिया है। मैं उम्मीद दृष्टि स शिक्षाको जाँचना चाहूँगा और यही उसमें कमी पाई जाती है। हमें इस कमी की पूर्ति करनी होगी। यह आप ही सोचें कि इसे सर्वोत्तम रीति से आप किस प्रकार कर सकते हैं। उसका करन के नवन तरीके हो सकते हैं। किंतु वे सब सक्षम तरीके हो और वे हो सकते हैं यन् हमें जानना चाहिए। इस सम्बन्ध में गाँधीजी ने हमें बहुत-सी कल्पनाएँ दी हैं। वे कच्ची कल्पनाएँ ही नहीं हैं किंतु उन्होंने उदाहरण सहित समझाया है कि हम क्या करना हैं। वे एस व्यक्ति थे जो दूसरो को तब तक कोई सलाह नहीं देत थे जब तक कि वे स्वयं उसका सफल प्रयोग नहीं कर देत थे। वे वह कुछ कमी किसी स नहीं कहत थे जो वे स्वयं नहीं करत थे। सचमुच यही वह चारित्रिक दृष्टिकोण है और इसे को हम युवारीढी के मस्तिष्क में बैठाना है। इसीलिए इसका कोई उपयोग नहीं है कि मैं आपको यह विस्तार स कहूँ कि आप यह करिए वह करिए। ये वे कसौटी हैं जिन पर हमारा हर कार्यक्रम कस जाएँ और जाँच जाएँ।

हमारी विचित्र मनोवृत्ति तो देखिए। यदि हम अँग्रेजी बोलन में गलतियाँ करत हैं तो बहुत सज्जित होत हैं किंतु अपनी-अपनी मातृ भाषा में की जान वाली गलतियों की हन बिना तक नहीं करत। आप भी उनकी चिन्ता नहीं करत। यह किस प्रकार की शिक्षा है ?

आखिरकार सभी शिक्षा मन्त्रियों ने यह स्वीकार किया है कि शास्त्र अथवा छात्र अपनी मानभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। फिर भी हम उडबडान हैं क्योंकि हममें दृढ़ विश्वास नहीं है। और जिनमें विश्वास है उनमें अंग बढ़न की दृढ़ता नहीं है। यही ऊठिनाई आती है। इस समयजस में हमें और अधिक नहीं रहता है। उसकी कीमत चवान के लिए २० वर काफी लम्बी

अवधि है। अब बिना किसी की दोष दिए हम नए सिरे से ठीक से क्रमिक गति बनाएँ जिससे हम वास्तविक शिक्षा की प्रस्थापना कर सकें जो इस देश का भूतकालिक महान वैशिष्ट्य था। देश में पहले ऐसी ही शिक्षा थी। औप्रेजो के जमाने में यह छो गई और गलत चीज हम पर लाद दी गई। अब हमें यह देखना है कि वह बदल जाती है और उसके स्थान पर उपयुक्त व्यवस्था आती है। उसमें जितनी अच्छी चीजें हैं उन्हें हम अवश्य लेगे उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। जहाँ से जो भी कुछ अच्छा है सबका हम इसमें समावेश करेंगे। किन्तु यह समावेश तभी हो सकेगा जब कि आधार हमारा अपना हो। यदि आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तभी कुछ इधर से उधर ले जा सकेंगे। किन्तु यदि आप अपने पैरों को ही छो देते हैं तो फिर आप क्या ले जाएँगे? आप क्या पा सकते हैं? आप कैसे शक्ति प्राप्त करेंगे? अतः हम उस स्थिति और समय को लाना है और वह आस-पत्ता है क्योंकि इस देश ने सारे ससार के सामने अपनी यह कार्यशक्ति प्रदर्शित की है जिसको लोग आज प्रशंसा करते हैं। किन्तु हम उस प्रशंसा से प्रसन्न न हो और न यह मानने लगें कि हम एकदम ठीक हैं। अब तो हमें केवल यह बहने का बल देंगी कि हम सही दिशा में हैं और हम जागे बढ़ने जाना है। इसी के बारे में सोचने और आगे बढ़ने के अवध में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा।

मैं एक बात और कहना चाहूँगा। शिक्षा को मही शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकारी नियंत्रण के स्फोटक परिणामों से प्रस्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि सदुद्देश्य प्रवृत्त होने पर भी उदात्त प्रभाव स्फोटक है। वह और कुछ नहीं कर सकती। सरकार को शिक्षा का समर्थन करना और उसे आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि वह उस पर पूरा नियंत्रण रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी स्तर पर शिक्षा के साथ समुचित व्यवहार होता चाहिए। नियंत्रण का यही प्रयोग हो जहाँ कुछ भूलें होती हैं। जहाँ सरकार जो चाहती है वह नहीं होता है उसे गटबारेर, खींचिए। यदि कहीं हिस्सारी गडबडी है या पैसे का गबन है और गैरनिस्त है तो अवश्य ही उसके बारे में कहिए। किन्तु यह सब होने पर

भी गैरशिस्त कभी-कभी स्वाभाविक है। इस सबमें अब परिवर्तन होना आवश्यक है। अतः मैं यह चाहता हूँ कि शिक्षा और सहकार्य दोनों साथ साथ रहें। इनमें सरकार का उस तरह का गलाघोटू नियंत्रण न हो। यह आपको देखना है कि इसका अनुभव किया जाता है। मेरी दृष्टि में शिक्षा के क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण सच्चे अर्थों में होना अनिवार्य है।

मैं सोचता हूँ कि जिन भूलभूत बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता था उनके बारे में मैंने आपको कह दिया है। अब बातें उनके अनुरूप ही होंगी। व आपक लिए है क्योंकि आप उनका व्यवहार करेंगे। जहाँ जो आवश्यक हो वह विस्तार आप करेंगे। मैं तो इन प्रक्रिया में सहायता मान कर सकता हूँ इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। प्रत्यक्ष दिना मैं आपको हर सम्भव मदद करने के लिए तैयार हूँ किन्तु मैं उस आप पर लड़ना नहीं चाहता। उससे कोई लाभ नहीं। किन्तु यदि उसकी कोई भाग होगी तो यह आपके नियंत्रण में है। वस यही मैं आपसे कह सकता हूँ। आप से दो शब्द फेरकर मुझ खुशी है और मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे यह आशा है कि आप उपयोगी निष्पत्ति करण और दृढ़ता के साथ उन्हें यथा सम्भव गीघ्रातिरीघ्र उचित रूप में अमल में लाएँगे।



कार्य-शाला

जाकिर हुसैन

[दूसरे युगिवादी शिक्षा सम्मेलन, जामिया मिलिया, दिल्ली १९४१ के अवसरपर दिए गए उद्घाटन भाषणसे]

काम की शिक्षा का आवश्यक अंग बनाए जाने के सम्बन्ध में आज ही कुछ कहा जाता हो ऐसा नहीं है। लोग इसके सम्बन्ध में बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। कहने वालों में से प्रत्येक ने इसे अपने ढंग से कहा है। किसी के लिए 'काम' सिद्धान्त है तथा उसे पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में स्वीकृत किए बिना इसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्यो के लिए यह 'विषय' है तथा उसके लिए तासिका निर्धारित की जानी चाहिए और पणालिका तथा पाठ्यक्रम में आगे कोई परिवर्तन किए जाने आवश्यक नहीं है। तीसरे के लिए काम ऐसा होना चाहिए जिसका गुणवत्ता मिले और कुछ ऐसा कहते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाशीलता 'आशीर्वादात्मक' है। अतः कोई हर्ज नहीं यदि क्रियाशीलता कुछ उत्पादन नहीं, करती क्योंकि अच्छे कुछ मजदूर तो हैं नहीं। उनकी क्रियाशीलता ही उत्पादक है। जिनके ये विचार हैं उनमें मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं केवल अपनी बात कहना चाहता हूँ और मेरी राय यह है कि जब हम शिक्षा के सम्बन्ध में काम के बारे में कहते हैं तब हमें उसी काम को लेना है जो शरीर और मस्तिष्क के लिए सवर्गुण शिक्षाप्रद है। काम ऐसा हो जो मनुष्य को और अच्छा मनुष्य बनाए। मेरा विश्वास है कि अपने किए हुए काम के गुण-दोषों की परीक्षा करने पर मनुष्य उत्पन्न करता है। जब मनुष्य कोई शारीरिक या मानसिक काम हाथ में लेता है तब वह उसे अपने लिए सभी शिक्षाप्रद बना सकता है जब कि वह उससे प्रभावित हुआ हो और अपनाए गए काम के प्रति उसने पूरा ध्यान

किया हो तथा अपने काम के लिए आवश्यक शिस्त को अपने आप पर
 आरोपित करने के लिए वह राजी हो। प्रत्येक काम नहीं किन्तु सम्योजित
 काम ही शिक्षाप्रद हो सकता है। यत्र द्वारा किया जा सके वाला
 या यत्रवत् किया गया काम शिक्षाप्रद नहीं हो सकता। किए जाने वाले
 काम की योजना हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए। उद्देश्य की पूर्ति
 हेतु उचित उपाय योजना की मानसिक प्रक्रिया दूसरी सीढ़ी है। फिर
 सामग्री एवं चुने हुए यंत्रों से काम के क्रियान्वयन का क्रम आता है।
 तदनन्तर अन्तिम अवस्था में इस बात की जाँच होती है कि तैयार
 सामग्री मूल योजना के अनुसार है या नहीं। वह उन उचित माध्यमों
 द्वारा निमित्त है या नहीं जो योजना बनाते समय सोचे गए थे तथा, उसमें
 लगने वाली सामग्री और मजदूरी न्यायसंगत है या नहीं। ये कामकी
 प्रक्रिया की चार निर्धारित स्थितियाँ हैं जो उस शिक्षा प्रद बनाती हैं।
 किन्तु यही सब कुछ नहीं है। कोई भी काम सतत रूप से दोहराए जाने
 पर एक सीमा तक निपुणता उत्पन्न करता है। किन्तु शारीरिक, मानसिक
 या भाषा विषयक निपुण्य शिक्षात्मक गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है।
 शिक्षित मनुष्य सम्बन्धी हमारे मन में सामान्य विचार निपुण व्यक्ति के
 नहीं है। निपुणता तो चोरा द्वारा भी प्राप्त की जाती है। धोखेबाजी
 से पनपने वाले भी और सच को झूठ दिखा सके वाले भी इसे प्राप्त
 करते हैं। ऐसी निपुणता शिक्षा का सम्पन्न नहीं हो सकता। हम अपने
 विषय की और अधिक व्याख्या यह कहकर करनी हूँगी कि काम सचमुच
 शिक्षाप्रद तभी हो सकता है कि जब वह एकमात्र व्यक्तिगत उद्देश्यों से
 परे मूल्यों की दृष्टि से अधिक सार्थक हो। मूल्य हमसे भी परे हैं जिन्हें
 हम स्वीकार या अमीकर करते या मानते तथा सम्मान करते हैं।
 वह जो अपने लिए काम करता है निस्सन्देह निपुण हो जाता है किन्तु
 हम उसे सही रूप में या सचमुच शिक्षित नहीं मानेंगे। केवल वह जो
 उच्च मूल्यों का अमीकार करता है, सही रूप में अपने आप को शिक्षित
 बनाता है। इन उच्च उद्देश्यों के अमीकार करने की इच्छा में वह केवल
 अपना मनोरंजन या सतोष ही नहीं खोजता बल्कि अपनी सम्पूर्ण समता
 एवं शक्ति को वर्तव्य रूप में अपने काम की पूर्ति में लगाता है। यह उसके
 व्यक्तित्व की उन्नति में सहायक होता है एवं उसकी चारित्रिक प्रवृत्ति
 को ऊँचा उठाता है।

सन्तोष और आनन्द की सारी व्यक्तिगत इच्छा को मनुष्य उन मार मूल्या की सेवा हेतु रूपांतरित करनेका निश्चय करता है जिन्हें वह सेवा करने योग्य समझता है। उसे अपनी सेवाओं को उस उद्देश्य के अनुरूप बनाने में प्रयत्नशील होना चाहिए जिसके लिए वह समर्पित है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक शिक्षा और क्या है? शिल्प एवं श्रद्धा मानसिक कार्य दोनों इस प्रकार संचमुच शिक्षाप्रद बनाए जा सकते हैं तथा दोनों समान रूप से प्रेरणाहीन अथवा व्यर्थ भी हो सकते हैं। सही कर्मशाला वह है जहाँ काम शुरू करने से पहले अच्छे योजना की आदत अपनाते हैं, उपाया और प्रसाधना के बारे में सोचते हैं और उद्देश्य की शिक्षा में किए गए कार्य की उपलब्धियों के सम्बन्ध में आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं। इस प्रकार वे धीरे धीरे यह अनुभव करेंगे कि जो कुछ वे करना चाहते हैं उसके लिए यदि आवश्यक पूरी शक्ति और कुशलता नहीं लगती है, फिर से और ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं तो अपने कार्य के प्रति गैर ईमानदार और, गैर बफादार होंगे। जो काम की शिक्षाप्रद बनाना चाहते हैं उन्हें सतत ध्यान में रखना चाहिए कि बिना निश्चित उद्देश्यके कोई काम नहीं होता। उसके अपने आदर्श और नियम होते हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। केवल समय बिताने की दृष्टि से कुछ भी अपरिणामकारक कार्य करते रहना ग्राह्य एवं सतोपजनक नहीं होता। चीजों से खिलवाड़ करते रहकर मनोरंजन मात्र करते रहने की भी गुंजाइश नहीं है। किसी दृष्टि से गतिविधि प्राप्त प्रवृत्ति को 'काम' कहते हैं। इसमें आत्मालोचन टाला नहीं जा सकता एवं जो इसकी आवश्यकताओं की मांगों की पूर्ति करते हैं उन्हें एक अमूल्य आनन्द का अनुभव होता है जिससे अग्रणी और कुछ नहीं हो सकता। काम बठोर आत्मानुशासन है, काम प्रार्थना है।

किन्तु दिव्य कठोर तपस्या एवं प्रार्थना में भी आनन्द स्वार्थपरक हो सकते हैं। स्वर्ग में अपनी जगह की सुरक्षितता का भरोसा करके दूसरों को उनके भोग्य क भरोसा छोड़ देते हैं। संचमुच अपने आदर्शों के अनुरूप होने वाली कार्यशाला व्यक्ति को व्यक्तिपरक एवं स्वार्थी कभी नहीं होने देगी। वह तो सर्वसाधारण उद्देश्य के लिए अपने को एक समाज

के रूप में स्थापित कर देगी। इस समाज में पूर्ण सत्योद्योग वर्तमान रहेगा एवं प्रत्येक को सौंपी गई जिम्मेवारी की पूर्ति द्वारा सर्वसाधारण उद्देश्य की उपलब्धि होगी। प्रत्येक का श्रम सर्वसाधारण ढाँचे से इस प्रकार निर्गडित होगा कि एक की भूल सबके कार्यों को नष्ट कर देगी तथा तेज गति वाला धीमी गति वालेको पीछे न रहने दगा। इस प्रकार यह शाला अपने कार्य के द्वारा अत्यन्त निवृत्त का सम्बन्ध प्रस्थापित करेगी और स्वभावकी विभिन्नता के बावजूद सहकार्य की क्षमता तथा जिम्मेवारी की भावना आदि गुणों का सर्वांगीण करमी जिनकी दश को आज सचमुच आवश्यकता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओंकी पूर्ति की अपेक्षा सामाजिक कर्तव्या का निर्वाह अधिक महत्वपूर्ण है।

सच्ची कार्य शाला संगठित कार्य कलापा से अपने छात्रों को प्रशिक्षित करने मात्र से सतुष्ट नहीं होगी बल्कि इस संगठित कार्य-कलाप से एक ऐसी सहकारी समिति का गठन करेगी जिसमें प्रत्येक, केवल अपनी जिम्मेवारियों से ही अवगत नहीं है बल्कि अपना काम भी पूरा करता है।

मैं समझता हूँ कि सच्ची कार्यशाला अपनी छोटी सी सहकारी समितिको उच्चतर उद्देश्यका साधन बनाएगी बशर्ते कि उसके छात्र व्यक्तिगत लाभपर विजय पाकर सामूहिक दलदल तथा लोभलिप्सा के गड्ढे में न गिर पड़ें।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि कार्यशाला अपने छात्रों द्वारा स्वीकृत जिम्मेवारी को कार्य द्वारा पूरा करना सिखाएंगी—सहकारिता का आधार पर अपने सभी कार्योंका आयोजन करगी और इस विश्वास को पैदा करेगी कि शाला एक समाज है और उसका सारा काम समाज की सेवा है। अन्तमें यह इस आकांक्षा को विकसित करेगी कि समाज आदर्श की उस स्थिति तक पहुँच जाए कि जिसकी मानव मस्तिष्क कल्पना कर सकता है। इस प्रकार वह इस विश्वास की आधार शिला रखेगी कि निर्धारित काम का करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का काम है एवं उसका नैतिक कर्तव्य है कि व्यक्ति का काम और उसका जीवन हर तरह से अच्छा समाज बनाने में सहायक हो।



तरुणाभिनन्दन : एक राष्ट्रीय संस्कार

सादिक अली

[पिता मयाय ने १३ अगस्त को 'तरुण नागरिक दिवस' के रूप में मनाने का आग्रह कई वर्ष पहले किया था। उसने आठार दिन गांधी चौक वहाँ पर एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री शास्त्रि भली साहब ने किया था। उनके उद्घाटन भाषण का मुख्य अंग यहाँ दिया जा रहा है।]

वहाँ मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। यहाँ मैं अवसर आया हूँ लेकिन आजादी हासिल करने के पहले। जब आजादी के जग में हम लगे हुए थे तब अफसर वहाँ आने का मौका प्राप्त हुआ था। उस वक्त भी वहाँ सावजनिक महत्व की जगह थी और आज भी वैसे ही महत्व में जगह है। गुप्त रयार थे कि वहाँ न तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। लेकिन अगला हुआ कि वह मौका मुझे जल्दी ही मिल गया। मेरे पास अचाय श्री श्रीमन्नेजी और बहुत सदासजाजी ने यहाँ आने का निमन्त्रण भजा किसे मैंने खुशी से पसन्द किया। इस सभारोह का सबध नौजवानों से है और वे नौजवान जो आजाद हिन्दुस्तान में पैदा हुए। यह उन की खुशकिस्मती है। हमारी पीढी के लोग तो एक गुलाम हिन्दुस्तान में पैदा हुए थे। लेकिन हमारी भी खुशकिस्मती थी कि हमने आजादी के जग में हिस्सा लिया और पुरानी पीढी के बड़े बड़े इंसानों से मिलन का मौका मिला। हमारे पिछले ७०-८० बरस का इतिहास बड़ा दानदार इतिहास है। उसमें बड़े बड़े इंसान पैदा हुए और बड़े बड़े विचार उठे। उस जमाने में जो बड़े बड़े इंसान पैदा हुए उनका नाम लन की मुम जरूरत नहीं है। उनमें सबसे बड़े गांधीजी थे जो यहाँ बर्नो तक रहे। गांधीजी में बहुत सी खूबियाँ थी बहुत सी विशेषताएँ थी। लेकिन एक विशेषता यह भी थी कि वे हिन्दुस्तान को आजाद करने में लगे हुए थे। आजाद कराने के साथ-साथ उनकी यह भी चिन्ता

थी कि जब मुल्क आजाद हो जाएगा तब आजाद मुल्क कैसा होना चाहिए। गांधीजी का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से निकाल देने भर से पूरा नहीं होता था। वे जानते थे कि अंग्रेज को यहाँ से चला जाना पड़ेगा, लेकिन उनके जाने के बाद हिन्दुस्तान का नक्शा क्या होगा, किस किसका हिन्दुस्तान हम यहाँ बनाएँगे ? गांधीजी के विचारों के मुताबिक हिन्दुस्तान में हर कोम का इन्सान बसेगा। सब धर्मों को हिन्दुस्तान में बराबर का स्थान मिलेगा। हमारे देश का एक विधान है, कस्टोडियन है। गांधीजी ने हिन्दुस्तान का विधान बनाने के काम में कोई खास हिस्सा नहीं लिया। लेकिन हमारी जो कांग्रेस है उसने यह विधान बनाने में खासा हिस्सा लिया। जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, गांधीजी को छोड़कर; उन सब लोगों ने हिन्दुस्तान के विधान को बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया जितना भी दम दम था वह हमें लगाया। हमारा संविधान बना और लोग कहते हैं कि बड़ा कानदार संविधान है और हमने ज़्यादा अच्छा संविधान बनाना जरा मुश्किल है हमें अपने संविधान से प्रेरणा लेनी चाहिए।

आ। हम क्या करना चाहते हैं ? हमारे पास एक ही काम है— हिन्दुस्तान को बनाना। हिन्दुस्तान को बनाना कोई मामूली काम नहीं है। हिन्दुस्तान मामूली मुल्क नहीं है। एक विशाल—बहुत बड़ी आबादी वाला, मुल्क है। इसकी आबादी ३० करोड़ से शुरू होकर आज ६० करोड़ तक पहुँच गई है। ६० करोड़ लोगों की समस्याओं को हल करना जरा मुश्किल काम है। एक कुशल हिन्दुस्तान बनाना तान्त्रिकों के हिन्दुस्तान बनाना, शक्तिशाली हिन्दुस्तान बनाना यह गम्भीर उद्देश्य अपने सामने रखकर हमें हिन्दुस्तान को बनाना है तो ऐसा हिन्दुस्तान बनाने के लिए साफ रास्ता भी होना चाहिए। गांधीजी ने दिखाया है वह रास्ता जिस पर हमने आगे चलना है। आज जो नाजयान है पैदा होते हैं और अभी भी हमारे सामने बैठ हुए हैं जिन्होंने २१ बप पूरे कर लिए हैं और जिन्हें अभी मत्ता धिकार प्राप्त हो रहा है। वे हिन्दुस्तान के नागरिक हैं। उनको बोट देना अधिकार मिल रहा है। वे अच्छे नागरिक बनना चाहते

हैं। लेकिन अगर अच्छा नागरिक बनना है तो साफ रास्ता होना चाहिए। गांधीजी ने इस मुल्क को एक रचनात्मक कार्यक्रम दिया। सन १९२०-२१ में गांधीजी ने कहा कि हिन्दुस्तान को आजाद करना है तो इस मुल्क को सुन्दर तरीके से आजाद कराना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम, दोनों कौमों की एकता लाजिमी है, आवश्यक है। हमारे देश में जो गरीबी, बेकारी है वह दूर होनी चाहिए। इस तरह का रचनात्मक कार्यक्रम गांधीजी ने हमको दिया। आगे चलकर उन्होंने इन बातों पर अमल करनेको कहा। इस मुल्क के अन्दर बाईस कमजोरियाँ हैं, बाईस बीमारियाँ हैं। अगर हमें अपने मुल्कको स्वतंत्र करना है, ताकतवर बनाना है तो हमको इन बीमारियों को दूर करना चाहिए। चाहे वह गरीबी की समस्या हो, चाहे बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। हमारे आपस के जो झगड़े हैं वे सब खत्म होने चाहिए। हिन्दुस्तान को बनाने का पूरा तक्का सब सामने आएगा, इसमें पहले नहीं। वह नकशा जो गांधीजीने बताया जिसमें ऊपर बताई गई सभी छात्रियों, बीमारियों को दूर करना है। जब तक हम उनके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे सब तक एक कुशल हिन्दुस्तान, ताकतवर हिन्दुस्तान, आजाद हिन्दुस्तान नहीं बना सकेंगे।

हमारे संविधान में हर आदमी को स्वतंत्र होना चाहिए। आर्थिक सामाजिक न्याय होना चाहिए। प्रेस स्वतन्त्र होना चाहिए। हर आदमी को काम मिलना चाहिए। हिन्दुस्तान के अन्दर यह सब चीजें होनी चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा, दो रास्ते हैं—एक सरकार का रास्ता और दूसरा गांधीजी का रास्ता। दोनों एक रास्ते नहीं हैं, कुछ भिन्न हैं, लेकिन बहुत-सी बातों में समानता है। हम देखते हैं सरकार की तरफ; सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। देखते हैं भारत सरकार की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ। न्यायी हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिला मजिस्ट्रेट, एम.पी., एम.एल.ए. — इस सब का योगदान है एक कुशल सरकार बनाने में और चलाने में। अगर आप समझे कि सारा बोझ इनके ऊपर छोड़ दे एक ताकतवर हिन्दुस्तान, शक्तिशाली हिन्दुस्तान

बनाने के लिए तो यह जरा मुश्किल काम होगा। पार्टी पॉलिटिक्स की जरूरत है हिंदुस्तान में। क्याकि डेमोक्रेसी में किसी राजा-महाराजा का राज नहीं होता बल्कि जनता द्वारा बनाई गई पार्टियों—और उनमें से बहुमत वाली पार्टी का राज्य होता है। लोगों को यह हक है कि वे अच्छी से अच्छी पार्टी को वोट दें। जिस पार्टी को ज्यादा मत प्राप्त हो वह सरकार बना सकती है—यह राजनीति है। गांधीजी ने इसको स्वीकार किया कि प्रजातन्त्र प्रशासन में पार्टी पॉलिटिक्स की जगह है। लेकिन क्या हर चीज में पार्टी-पॉलिटिक्स घस जाए? बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें पॉलिटिक्स से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह बड़ा विशाल क्षेत्र है। वह बड़ा उम्रवा चौड़ा क्षेत्र है। पार्टी क्षेत्र के अंदर कुछ लोग हिस्सा लेंगे जब कि वोट देने का अधिकार—आजाद मूल्य बनाने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। इसमें हर आदमी हिस्सा ले सकता है। हर आदमी हक्दार है चाहे वह किसान हो मजदूर हो डाक्टर हो इंजीनियर हो छात्र विद्यार्थी हो टीचर हो—वे सब हमारा नागरिक हैं। आज जो एम पी चुनकर आते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। किसान मूल्य के लिए फसल उगाता है और डाक्टर लोगों की बीमारी दूर करता है और अपनी कमाई भी करता है। उसको अपनी कमाई भी करनी है घर का इतना काम भी करना है मूल्य की भी कुछ खिदमत करनी है। लेकिन सिर्फ हम अपनी भलाई के लिए जीने का काम करेंगे तो यह मूल्य के प्रति कफादारी नहीं होगी। हर आदमी को ८० फीसदी अपने तथा अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए और २० फीसदी देश के प्रति। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो कोई शक नहीं कि बहुत जल्द ही एक कुशल हिंदुस्तान गैरनिगाली हिंदुस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे।

कुछ लोग कहते हैं कि अहिंसा में ताकत नहीं होती। गांधीजी का कहना था कि अहिंसा में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत किसी में भी नहीं होती। इसका उदाहरण आप लोगों के सामने है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर मानी हुई फौज को हमारा यहाँ से हटना पड़ा, नष्टा जाना पड़ा। अपने मूल्य को आजाद करने के लिए हमें अपने यहाँ

से गरीबी, शिक्षा में सुधार तथा गाँवों और शहरों की दूरी को कम करना पड़ेगा औद्योगीकरण करना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि गाँधीजी औद्योगीकरण नहीं चाहते थे। उनका यह कहना बिलकुल गलत है। गाँधीजी औद्योगीकरण चाहते थे, देने को आगे ले जाना चाहते थे लेकिन वे शहरों या औद्योगीकरण नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि हर गाँव आगे बढ़े।

अभी मैंने आपसे पार्टी पॉलिटिक्स की बात कही थी। हमारे सिस्टम में पॉलिटिक्स का अपना क्षेत्र है अपनी जगह है और बहुत अच्छी जगह है, महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पॉलिटिक्स को आने की ज़रूरत नहीं है। एक पार्टी के अन्दर हर आदमी हिस्सा ले सकता है। लेकिन जिस मकसद के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं वह एक अच्छी चीज़ है नौजवानों के लिए। गुजरात में इसकी शुरुआत हुई और सम्माननीय मदनलालजी चाहती हैं कि यह चारों तरफ फैले। हमारे देश में आज भी बहुत से नौजवान हैं जो बेकार हैं परेशान हैं। हर नौजवान इज्जत के साथ अपना सिर ऊँचा करके जिन्दगी जी सके। हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

। गाँधीजी का ख्याल था—गरीबी की समस्या को आसानी से हल नहीं किया जा सकता। इनके बड़े मुल्क के अन्दर क्या हम सब लोगों को काम दे सकते हैं? हर आदमी को काम मिले—आजादी भी रहे, डेमोक्रेसी अच्छी तरह से चले। हमारे जो अधिकार हैं सुरक्षित रहें। हमारे जो कर्तव्य हैं उनका भी हम पालन करें। हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों बराबरी से हर नागरिक द्वारा अमल में लाए जाएँ। यह हिन्दुस्तान का एक नक्सा है। गाँधीजी से हम प्रेरणा ले सकते हैं और सगतिार लेते रहें। दुनिया उनसे प्रेरणा ले रही है। गाँधीजी का आखिरी मकसद दुनिया को बदलना था। गाँधीजी दुनिया को बदलना चाहते थे। दुनिया के समाज को बदलना चाहते थे। लेकिन हिन्दुस्तान का और उद्देश्य नामयाव हो गया तो वह मजबूत, ताकतवर बनेगा और

तभी यह दुनिया के ऊपर अपनी छाप डाल सकता है। अगर हम सही रास्ते पर चले, सही मायने में हमारी ताकत बनी तो एक न एक दिन हम दुनिया के ऊपर अच्छा असर डालेंगे। आज हर एक देश शांति की बात करता है। दुनिया की दो बड़ी फौजी ताकतें भी दुनिया में शांति स्थापित करना चाहती हैं। लेकिन जो रास्ता गाँधीजी ने बताया है जिस पर हम चलने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में अच्छा असर डाल सकेंगे।

मुझे बहुत खुशी है कि बहून मदालसा ने यह नई सस्था बनाई है। १५ बरस से अपने यहाँ चलाकर मजबूत करने के लिए उसे धीरे धीरे फैलाया, जिसका नौजवानों से ताल्लुक है। मेरी शुभकामनाएँ उसके साथ हैं। मेरी आशा है कि यह सस्था पनपती जाएगी और ज्यादासे ज्यादा लोगों का भला करेगी और मुल्क की भी भलाई करेगी। मैं श्रीमती मदालसाजी का शुक्रिया अदा करता हूँ।

अब हम सब यह प्रतिज्ञा करें।

- * भारत के प्रति कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति हम अफादार और निष्ठावान रहेंगे।
- * राष्ट्र के स्वातंत्र्य तथा उसकी एकता की रक्षा करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए हम समर्पण की भवना से कार्य करते रहेंगे।
- * किसी कार्य सिद्धि के लिए हम कभी हिंसा का आश्रय नहीं लेंगे।
- * प्रदेश, भाषा, धर्म और जाति सम्बन्धी सभी मतभेदों को तथा आर्थिक व राजकीय कठिनाइयों को हम शान्तिमय तरीकों से सुलझाने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

जय हिन्द !



छठी योजना गांधी वादी हो

श्रीमन्नारायण

अब तक महात्मा गांधी का नाम रस्सी तौर पर लिया जाता था, इसलिए पिछले चुनाव की जीत के बाद २३ मार्च को जब जनता-पार्टी के ससद सदस्यों ने राजघाट पर गांधीजी द्वारा शुरू किए गए काम की पूरे मनोयोग से आगे बढ़ाने की शपथ ली तो एक सुखद आश्चर्य हुआ। इससे पहले जनता-पार्टी के घोषणा-पत्र में यह वायदा किया गया था कि अगर वह सत्ता में आई तो अन्तपोष तथा आर्थिक व राज-नैतिक सत्ता के सब से निचले स्तर तक बिबेन्द्रीकरण के गांधीवादी सिद्धान्तों के आधार पर देश के विकास की कोशिश करेगी। हमें उम्मीद है कि जनता-पार्टी के लोग महात्मा गांधी की समाधि पर ली गई प्रतिज्ञा को सच्ची लगन से निमाएंगे।

गांधीजी के विचारों को लेकर बुद्धिजीवी तथा युवा पीढ़ी के कुछ लोगों के मन में कभी-कभी यह सन पैदा होता है कि विज्ञान तथा तन्मालाजी के आधुनिक युग में क्या गांधीजी के आदर्श और कार्य-पद्धति देश के विकास की दिशा में कोई सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। पर इधर पश्चिम में एक नई हवा देखने में आई है। अमरीका तथा यूरोप के देशों में ऐसे बहुत से लेख तथा पुस्तकें पिछले दिनों प्रकाशित हुई हैं जिनमें गांधीजी को न सिर्फ आज के लिए उपयोगी बताया गया है बल्कि कहा गया है कि उनके विचार हमारे समय से बहुत आगे हैं। जापान के 'मोज्यो विश्वविद्यालय' के प्रो मोरियोतो इन दिनों गांधीजी पर शोध कर रहे हैं। एक बातचीत में उन्होंने बताया, उनका यह दृढ़ विश्वास है कि गांधीजी अपने समय से सौ बरस आगे थे। इसी तरह अमरीकी पत्रिका 'न्यूजवीक' के स्तम्भकार थारेन्डा तारजी चित्ताची ने गांधीजी के विचारों पर लिखी एक प्रभावशाली लेखमाला में कहा है कि विभिन्न

मुहों पर गांधीजी के विचारों को अथ पश्चिमी बुद्धिजीवियों के बीच उत्तरोत्तर स्वीकृति प्राप्त होती जा रही है। वहाँ लोग यह स्वीकार करने लगे हैं कि पश्चिम की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का हल गांधीजी की इस उक्ति में निहित है कि हमारी जरूरतें तो पूरी हा पर उन जरूरतों को हम सीमित रखना चाहिए। यह सही है कि धरती पर हमारी जरूरत भर के लिए हमारा पर्याप्त साधन यह है और हम पर व हमारी लालच को कहीं तक पूरा करना ?

अजमेर में हुए संयुक्तराष्ट्र के पिछले सम्मेलन के दौरान इस बात की तरफ हमारा ध्यान खींचा गया था कि आने वाले कुछ ही दिनों में पानी की पूँद तक तेल के बराबर महंगी हो जाएगी। उन्नत देशों में ऊर्जा का संकट मुँह बाएँ है। यह सही है कि विश्वास के रास्ते में ऊर्जा आदि के भयंकर अभाव से भविष्य में आने वाली मुश्किलों की तरफ 'रोम क्लब' द्वारा दिए गए इशारे को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अग्रगण्य तथा वैज्ञानिकों द्वारा चुनौती दी जा रही है। 'हडसन' संस्थान के संस्थापक निर्देशक हरमन बॉन ने अपनी हाल में प्रकाशित एक किताब 'अगले दो सौ वर्ष' में दावा किया है कि मानव जातिका भविष्य बहुत सुन्दर है, आने वाले समय में सब तरफ से सम्पन्न हो जाएंगे और वे प्रकृति की क्षमता पर काबू पा लेंगे। परन्तु लोग भी मानते हैं कि धीरे धीरे कोयला तथा तेल से मिलने वाली ऊर्जा को सारे ऊर्जा तथा भूतल पर आधारित तबनालाजी से बदलना होगा।

कुछ महीने पहले टाइम्स पत्रिका में लिखे एक लम्बे मसूदे में कहा था कि आधुनिक विज्ञान और तबनालाजी को अब पहले की तरह 'गै-भाता' नहीं समझा जाता अब वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी लोग चक की नजर से देखने लग रहे हैं। आणविक शक्ति जिस अभी हाल तक विज्ञान को मानवता की एक महान् भेट समझा जाता था, अब आसका की नजर से देखी जाती है। लागू में यह एहसास बढ़ता जाता है कि जिस अणु में सम्पन्नता बढ़ाने में मदद मिल रही है उसी में बम भी बनाया जाता है और इससे दुनिया किसी भी समय तबाह हो सकती है। डा. शूमाखर ने अपनी ताजा किताब 'स्मॉल इज

बूटीफुल' में लिखा है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि विज्ञान और तकनालोंजी को एक नई समन्वित, सौम्य, महिम्न, श्रेष्ठ और सुन्दर दिशा दी जाए। अपनी किताब में उन्होंने गांधीजी के इस विचार की तरफ ध्यान खींचा है कि दुनिया को उत्पादन की वजाय बहुजन के लिए उत्पादन पर जोर देना चाहिए। आदमी लघु है और लघु ही सुन्दर होता है। प्रो. डायमण्ड ने 'मनस' के एक हात के ही अंक में प्रकाशित अपने लेख में 'नौकर-दाही की श्वेत्पूण समाप्ति', साझे-स्वामित्व और पैदावार के साधनों के विकेंद्रीकरण की यत्नात्मक को है। इसी तरह ग्राइन ईजली ने अपनी किताब 'सिबरेजन एंड द एम ऑफ साइन्स' में तकनालोंजी की तमाम महंगी योजनाओं को तत्काल ग्रस्त कर देने की सलाह दी है और कहा है कि 'विज्ञान का विकास उस सीमा के भीतर रहकर ही किया जाना चाहिए जिसमें मनुष्य के प्रति आदर और धार तथा प्रकृति से अनुराग बना रहता हो।'

ओ. ई. सी. डी. पेरिस के विकास केन्द्र ने इस वर्ष एक उल्लेखनीय शोध प्रकाशित किया है, उसका शीर्षक है 'टुथडेंस ए री-डिफिनीशन ऑफ डेवेलपमेंट' इस निताब के सम्पादक का कहना है कि 'विकास' एक भ्रामक विचार है। तेज विकास का एक अनिवार्य परिणाम यह होता है कि अमीर और गरीब तबकों के बीच तनाव बढ़ता चला जाता है और निर्माण की वजाय विध्वंस की तकनीक अधिक प्रभावी हो जाती है। इसके सम्पादक इस निश्चित राय के हैं कि ऐसा विकास जो एक आदमी को दूसरे के खिलाफ करता हो, मुखतापूर्ण है। उन्होंने इस धारणा को गलत बताया है कि पूरी दुनिया के विकास का कोई एक मॉडल हो सकता है। उनका कहना है कि हर समाज को अपना रास्ता खुद तय करना है। जरूरत इस बात की है कि पूंजी निर्माण और पैदावार के ढाँचे का पुनर्गठन किया जाए, उत्पादन के साधनों का पुनर्वितरण हो ताकि कुछ देशों के इस क्षेत्र में आर्थिक साम्राज्यवाद को समाप्त किया जा सके।

यूनेस्को प्रेस द्वारा प्रकाशित एक और पुस्तक 'कल्चर, सोसायटी एण्ड इकॉनामिक्स फॉर ए न्यू वर्ल्ड' में भी उसके सम्पादक ने तकनालोंजी

के साम्राज्यवाद के विरुद्ध चेतावनी दी है। 'जो देश अपनी तकनालोंजी का विकास नहीं कर पाए वे दूसरे देशों से तकनालोंजी उधार लेकर अपना नुकसान ही करते हैं, इस विचार के सम्पादक का कहना है कि हमें आदमी के श्रम के उपयोग के नए तरीके विकसित करने होंगे 'विविधता का सिर्फ सांस्कृतिक मूल्य ही नहीं है—उसके ठोस आर्थिक लाभ भी हैं। इसे विकास के रास्ते की रुकावट नहीं समझना चाहिए गांधीजी ने भी ठीक यही बातें कही थी।

विकास की तेज दर के प्रति दुनिया भर में अयंशाम्त्री अब सदाब हो उठे हैं। जापान जिसने पश्चिमी आर्थिक ढाँचे को अपनाकर पिछले दस सालों में अपनी पैदावार दुगुनी कर ली थी अब विकास की दर को कम करने की योजना बना रहा है ताकि प्राकृतिक साधना को चुक जाने से बचाया जा सके और राष्ट्रीय जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित किया जा सके।

पिछले वर्षों से विकसित देश हवा और पानी के सद्पण की गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सद्पणशाम्त्री और पर्यावरण वैज्ञानिक उन तरीकों की खोज में लगे हैं जिनसे इस जहरीले सद्पण को रोका जा सके।

यूरोप और अमरीका के लोगों में योग के प्रति असाधारण रूप से दिलचस्पी बढ़ी है। वे अपनी बीमारियों का इलाज मँहगी दवा और जटिल चिकित्सा पद्धति की बजाय आसान सस्ते और धरेनू उपायों से करना पसंद करते हैं। कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी विकासशील देशों को आसान और सस्ते देशी इलाजों को बढ़ावा देने की सलाह दी थी। पश्चिमी देशों में बड़ शहरों में जड़ी-बूटी की नई दुकानें तथा योग सिखाने के नए केन्द्र बढ रहे हैं। वहाँ अधिकाधिक योग प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ झुक रहे हैं।

भारत में पूर्ण शराबबन्दी किए जाने पर गांधीजी हमेशा जोर देते थे। आज पश्चिम के विकसित देशों में भी शराब की लत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। अमरीका और रूस की सरकारें शराब

प्राप्त लेखक सखरोव ने भी अहिंसा को एक श्रेष्ठ अम्य माना है। हमारी पिछली रूढ़ियों के इतिहास ने राजनैतिक उद्देश्यों को पाने के लिए हिंसा के प्रयोग की निरर्थकता को बिल्कुल पक्के तौर पर साबित कर दिया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि जनता पार्टी-गाँधीजी-के सपने के भारत को साकार करनेमें कोई कसर न उठा रखेगी। कई वर्षों पहले महान फ्रांसीसी दार्शनिक रोमा रोलाँ ने कहा था—'कुछ अर्थों में तो गाँधीजी आज के विज्ञान से भी आगे बढ़ गए थे, भविष्य की समस्याओं को उन्होंने भाँप लिया था। इस अर्थ में वे एक अत्याधुनिक व्यक्ति थे। मुझे जरा भी शक नहीं है कि गाँधीजी के विचार कभी पुराने नहीं पड़ेंगे, वे हमेशा हमें भविष्य का रास्ता खोजने में मददगार साबित होंगे।'

हमें उम्मीद करनी चाहिए कि छठवीं योजना का प्रारूप गाँधीवादी आदर्शों के अनुरूप होगा। गाँधीजी के समाजवाद की कल्पना राजनैतिक और आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर आधारित है। इसका अर्थ है हमारी विकास योजनाओं को इस तरह बनाया जाए कि वे नीचे गाँव तक पहुँच सकें। ये योजनाएँ लोगों के लिए हों और उन्हीं के सहारे चलाई जाएँ। सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनमें आत्मनिर्भरता बड़े और इस तरह सरकार का दखल कम से कम होता चला जाए ऐसी कोई गाँधीवादी योजना तभी सफल हो सकेगी जब राष्ट्रीय स्तर पर पूरी सादगी और कफायत बरती जाए।

जीवन कुटीर
बधा (महाराष्ट्र)



बुनियादी तालीम का एक प्रयोग

राधाबहन

सक्षमी आश्रम की गाँधीजी के आदीर्षादि के साथ पूज्य सरला बहनजी ने कुमाऊँ की महिलाओं के लिए बुनियादी तालीम की सस्था के रूप में वर्ष १९४६ में प्रारम्भ किया था। पूरे उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में सर्वोदय विचार का व नोवशक्ति जागरण की दिशा में जो कार्य हुआ है वह इस सस्था की दी गई प्रेरणा की एक उपलब्धि है। साथ ही इसके भीतर बुनियादी तालीम की दृष्टि से जो अनुभव आया, जो परिणाम निकला वह भी एक उपलब्धि है।

पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामों में आई बालिकाएँ ही हमारी छात्राएँ हैं और उन्हीं ग्रामों से आई हैं। हमारी शिक्षिकाएँ औसत में हमारी पारिवारिक पूर्ण भूमिका यह है कि हम श्रम प्रधान रहे हैं उसमें भी अकुशल श्रमही प्रधान रहा है शिक्षा अध्ययन अथवा चिंतन मनन की परम्परा नहीं रही है। न ही सिलाई कढ़ाई गृहकार्य कुशलता, बालसंगोपन गशीनों पर काम करने का कोई पारिवारिक संस्कार रहा है। इस प्रकार की हम छात्राएँ व शिक्षिकाएँ इस सस्था में एकत्र हुई हैं जहाँ हमारे ग्रामीण जीवन के अनुकूल गौशाला में गायें व भेंखें हैं जिनके लिए खेतों पहाड़ी ढलानों व पेड़ों से चारा काटकर सिर पर डोकर ले आती हैं छोटी सी खेती है जिसमें सागभाजी व फल पैदा करने के लिए कम्पोस्ट खाद तैयार करके उसे सिर पर डोकर खेतों को देती हैं। हाथ से चलाने वाले औजारों से खेत खोदने होते हैं और पहाड़ के सीमित पानी को बटोर-बटोर कर सिंचाई करनी होती है। साथ में एक उद्योग शाला है जहाँ यहाँ क पर्वतीय भोटिया लोगों के परम्परागत चर्खों बालीन अड्डों कतुओं तथा बागेश्वरी चर्खों पर कताई बुनाई का काम हम

सीखनी व करती है। हमारा छात्रावास जीवन में भी जंगल से लपेटो व बोयल आना मोटर सड़क से अपन भोजनालय क लिए अनाज को ढोकर ल आना जैसे सभी काय पूणत पर्वतीय ग्रामीण पद्धति पर होत है, सारांश कि माहोन पूणत पर्वतीय ग्राम का है।

विन्तु खती में खुदाई आदि व मुधर ओजार छात्रावास में साफ हव दार घर व फलश गौचालय उद्योग शाला में रुई कताई क ग्रामोद्योगी यत्र सिल इ मशीन एव स्वटर-बुनाई क हस्त यंत्र रसोई में विद्युत् खालित चक्की गोशाला में गोबर गैस सयन आदि साधन हमारी तालीम व इस परम्परागत माहोन को जीवन का वह विकास दना चाहत ह जो आज पर्वतीय ग्रामो को स्वावलम्बी व समृद्ध करन क लिए इस समाज की एक माँग है इस पर्वतीय जीवन की एक आवश्यकता है।

हमारा सामूहिक जीवन द्वारा शिक्षा का पहला आधार यह रहा है कि एक भोजनालय में शिक्षिकाएँ व छात्राएँ एक पक्ति में भोजन करती ह। हमारी पूरी सस्या क सदस्या क लिए एक ही रसोई है। और वह ह हमारा सामूहिक भोजनालय। उसी तरह एक छात्रावास की छत क नीचे छात्राओ व विभिन्न टोलियों क साथ शिक्षिकाएँ सोती है। और उसी तरह खत खतिलान, वनप्रांतर अथवा गौशाला व उद्योग शाला में छात्राएँ व शिक्षिकाएँ सही अर्थों में 'टु सव दि स्वीट' क लिए जुडती है अर्थात् जीवन व बुनियादी तीन कामा क लिए तीन सहज कार्यक्रम (१) सहभोजन (२) सहजीवन (३) सहकर्म।

इस सारी दिनचर्या में श्रम की प्रतिष्ठा व श्रम शिक्षण के लिए अलग से कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता होती ही नहीं। ना ही कोई औपचारिक कार्यक्रम या विशेष व्यवस्था का आयोजन करना पडता है परन्तु जीवन व जिन मूल्यों को हम दना चाहत ह उह आसानी से दे पात ह। इस सारी व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण ह कि शिक्षको की दृष्टि इस सम्बन्ध में साफ हो कि जीवन की दिशा क्या होगी? हम किस तरह क समाज की स्थापना करना चाहत ह? प्रत्यक्षत आज हमारा समाज रचना क्या है उसकी समस्याएँ क्या ह? उसकी गरिमाएँ क्या ह?

लक्ष्मी आश्रम को ऐसे शिक्षकों की एक पूरी सदस्य टीम आज तक नहीं मिली, यह एक दिक्कत रही है।

बच्चों के ऊपर बौद्धिक ज्ञान का बोझ बढ़ते जाने का प्रश्न हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से प्रचलित रहा है, याने बढ़ गया है। इस कारण पढ़ाई की किताबों कापियों का बोझ भी बढ़ा है और पढ़ने के घण्टों की संख्या भी परन्तु सह-कर्मयुक्त सहजीवन के अन्दर एक ऐसा संक्षिप्त आन्तःकरण बनता है जिसमें पूरा जीवन ही शिक्षा की एक खुली किताब होता है। यहाँ खाते समय भी भोजन के तत्वों पर साय-साध चर्चा होने लगती है, खेत में मिट्टी की रचना व उसके इतिहास का प्रसंग छिड़ सकता है, एक कमर में रहती हुई छात्राएँ अपनी शिक्षिका से हिन्दी, गणित, इतिहास भूगोल किसी भी विषय की जानकारी ले लेती हैं। इससे हमने पाया है कि बौद्धिक बर्ग व घण्टे ड़ाई या तीन घंटे बच्चों के लिए पर्याप्त है। हम उनका निजी अध्ययन, के लिए उन्हें एक या डेढ़ पढ़ाओर भी दत्त है इससे पुस्तकें व कापियाँ स्वतः अपेक्षाकृत कम हो जाती हैं पर बौद्धिक स्तर सामान्य विद्यालयों के बच्चों से कितनी ह्रासत में कम नहीं बरन् इन छात्राओं की लेखन व प्रगटन की मौखिकता विशेष होती है।

लोकतन्त्र में नागरिक के सही व्यक्तित्व के लिए हमने तीन पहलुओं पर प्रयोग किया है। पहला—छात्रावास में छात्राओं का मनीमण्डल और सामूहिक कार्य के लिए बनाई गई टोलियाँ, इसके कारण जुटकर काम करने के कर्तव्य व समाज को पहले देकर सब प्राय गए अधिकारा के उपयोग का गुण दिन प्रतिदिन छात्राओं व व्यक्तित्व में भजता जाता है। दूसरा—ग्रामी अथवा क्षेत्र की समस्याओं के हल में संप्रयत्न जुटाया व उनका अध्ययन करना, इसके लिए समय-समय पर अलग-अलग पहलू तथा जन-सुरक्षा इस प्रकार का या यह प्रत्यक्ष कार्य उनके मानस पर स्पष्ट छाप डालना है। तीसरा—अध्ययन प्रवास, जो छात्राओं के मस्तिष्क में अपने दबे वा-सजीव चित्र उजागर करता है।

शिक्षण आवश्यकता हमारा एक जानदार प्रोग्राम रहा है। आठवीं वक्षा के बाद याने १५ वर्ष की उम्र की छात्राओं अपनी शिक्षा ग्रहण

कापियां पुस्तकें आदि तथा अपने भोजन व वस्त्र पर आने वाला व्यय वदम प्रति वदम सहा बहन करने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसलिए छात्रा अपने अध्ययन से अतिरिक्त समय में कोई ऐसी उत्पादक या शैक्षणिक प्रवृत्ति की जिम्मेवारी लेती है जो उसकी आय का जरिया बनती है। एक मोटे अंदाज में प्रथम वर्ष में आय उसके खर्च की ३% द्वितीय वर्ष में १%, तृतीय वर्ष में ३% तथा चतुर्थ वर्ष में पूर्ण स्वावलम्बन-इस तरह रहती है। यह क्रम व्यक्तियों की अपनी व्यक्तिगत रुचि व शक्तियां तथा शिक्षिकाओं द्वारा दिए गए मार्गदर्शन व प्रेरणा पर भी निर्भर करता है। किन्तु १५ वर्ष से ऊपर के बच्चों की शिक्षा इत्यादि खर्च का भार न तो माँ बाप पर पड़ना चाहिए न ही वह समाज पर ही पड़े। साथ ही विद्यार्थी को उत्पादन करके सहा का सहयोगी बनना प्रारम्भ कर देना चाहिए जो एक पहाड़ी कृषक का सड़का १२-१३ वर्ष की उम्र से ही बन लगता है। हमारे इस विचार को शिक्षण स्वावलम्बन के इस प्रयोग ने पुष्टि दी है, हमारी कतई बुनाई की उद्योग-शाला, खेती गौनाला, विद्यालय एवं छात्रावास इन सभी को हमने शिक्षण स्वावलम्बन की प्रवृत्तियों का आधार बनाया है। किन्तु मुख्यतः उद्योग शाला उत्पादन कार्य देने का मुख्य रोल अदा करती है।

हमारी समस्याएँ — हमारी उपलब्धियाँ आपस में हैं किन्तु थोड़ी हैं। पर समस्याएँ कठिन व अधिक संख्या में हैं सर्वप्रथम समस्या है सरकार द्वारा नई तालीम की मान्यता नहीं होना, जिसके कारण हम छात्राओं को दो बारगा से शिक्षा बोर्ड की सामान्य फाइनल परीक्षाओं के लिए तैयार करना पड़ता है।

(१) परीक्षा के बाद प्राप्त होने वाले शिक्षा बोर्ड के सर्टिफिकेट में, जिसे सरकारी व गैर सरकारी तथा सामाजिक मान्यता प्राप्त है, भविष्य में बहना को आजीविका व अन्य अवसरों के लिए एक सुरक्षितता मिलती है।

(२) योग्यता व शक्तियाँ होते हुए भी अनात्मविश्वास व हीनता की गूथों से ग्रसित रहने की स्थिति से मुक्ति मिलती है।

दोन दोनो कारणो वा उन्मूलन हुआ है । किन्तु इससे नई तालीम की दिशा मे हमे बठिनाइयाँ आई हैं । परीक्षामूलक वातावरण को, जो कि शिक्षा या तालीम के वातावरण वा हनन करता है, मन्द करने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पडी है । साथ ही छात्राओं को कई व्यय के बौद्धिक विषया मे समय देना पडा है । जो कि परीक्षाओ के लिए अनिवार्य थे, किन्तु जीवन के लिए बेमेल हैं । आधुनिक परीक्षा पद्धति एवं परीक्षापूतकता शिक्षा ने सत्य को समाप्त कर देती है और जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोणको दबाकर एक अस्पष्ट वात्पनिवता ले आती है, जो व्यक्तिगत की समरसता व प्रभाव को छिन्न-भिन्न करती है ।

लेकिन आत्म विन्यासहीनता या हीन भावना की गूथी भी व्यक्तियों के लिए उतनी ही गतक चीजें हैं । आज हम इस दुराहे पर खडे हैं ।

मेरे विचार से इसका यह हल है जिसकी ओर सक्षमी आश्रम उत्सुकता से देख रहा है ।

(१) देश मे नई तालीम को कई स्वतन्त्र प्रयोग है । अपनी-अपनी क्षेत्रीयता को बनाए रखकर समग्र शिक्षा का स्वरूप उसमें परिलक्षित हो ।

(२) इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को शासन द्वारा स्वायत्तता प्राप्त हो ताकि आज के इस संक्रमण काल में डिग्री व सर्टिफिकेट आदि की मान्यता मूल्य-भेद न पैदा करे ।

(३) नई तालीम का शिक्षण गाँधी विचार मे चल रहे व उसके लिए काम कर रहे रचनात्मक कार्यकर्ता अपनी संस्थानों को दिलाएँ तब यह स्पष्ट होगा कि नई तालीम एक सक्षम मानव बनाने वाली क्रान्ति-कारी शिक्षा पद्धति है, न कि गाँधी का मात्र चित्र ।

आज तो नई तालीम को न सकारो से मान्यता मिली है और न ही उसका नाम लेने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले रचनात्मक कार्यकर्ताओ से, अतः ये दोनों पहलू बराबर महत्वपूर्ण हैं ।

आज देश का वातावरण ऐसा है कि इस दिशा में प्रयत्न किया जा सकता है, सरकारी मान्यता से भी आवश्यक पारिवारिक मान्यता है रचनात्मक परिवार की मान्यता, ये दोनों ही प्राप्त हो तो नई तालीम के सजीवन से देश को प्राण मिलेगा।

दूसरी समस्या इस दिशा में जुटकर प्रयोग करने वाली सक्षम टीम का अभाव भी है। जिन शिक्षिकाओं व कार्यकर्ताओं के बल पर हम यहाँ तक पहुँचे थे समाज में अपने जीवन का कार्य इस नहीं बना पाए हैं क्योंकि इसकी मान्यता न होना एक मुख्य दोष रहा है।

फिर भी हम आशाविन हैं कि देश व विश्व, आन ध्यान दिनों में बुनियादी शिक्षा के महत्त्व को अधिक म अधिक समयता जाएगा।



गांधी मार्ग

गांधी विचारक सृजनारमक साहित्य का मासिक
सारगर्भित लेख, लघु लेख, कहानी, नाटक, कविता,
सस्मरण एवं व्यक्ति-चित्रों से युक्त
विचारशील पाठकों एवं सर्वसाधारण पाठकों के लिए पठनीय
सम्पादक

श्री धीमन्नारायण, श्री भवानीप्रसाद मिश्र

वार्षिक शुल्क ₹ १२ द्विवाषिक ₹ २२

एक प्रतिका मूल्य ₹ ६

सम्पक करें व्यवस्थापक 'गांधीमार्ग' (हिन्दी मासिक)

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, २२१-२२

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली-२

रचनात्मक कार्य की दिशा

सर्वसम्मत निवेदन

[गांधी स्मारक निधि के १७ १८ १९ अगस्त को नई दिल्लीमें रचनात्मक कार्य संबंधी एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी। उस विचार गोष्ठी के अन्त में जो सर्व सम्मत निवेदन प्रकाशित किया गया था। उसे पाठकों को जानकारी के लिए यही दिया जा रहा है]

अखिल भारत रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन दिनांक १७ १८, और १९ जुलाई १९७७ को नई दिल्ली में हुआ। उसकी ओर से रचनात्मक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के संस्तु विचारों के लिए कई व्यापक सुझाव दिए गए थे। इनमें एक यह था कि रचनात्मक कार्य के अध्ययन के लिए एक केन्द्र होना चाहिए जो रचनात्मक संस्थाओं की सेवा उनके काम की पुनर्निरीक्षण और मूल्यांकन करके, प्रयोग करके, उनके क्रिया कलापों में अधिक सामंजस्य बिठाकर रचनात्मक कार्यकर्ताओं की दक्षता में उन्नति करके तथा क्षेत्रीय कार्य के लिए अधिक कारगर पद्धतियों को सुझाकर कर सके।

अखिल भारतीय सम्मेलन के सुझावों को त्रियात्मक रूप देने की दृष्टि से गांधी स्मारक निधि ने एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की। यह गोष्ठी राजघाट स्थित गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय में १७ १८, और १९ अगस्त १९७७ को हुई। इसमें देश के विभिन्न भागों की रचनात्मक संस्थाओं तथा स्वयंसेवी एजेंसियों से संबंधित ४० से अधिक प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चर्चा के आधारस्वरूप गोष्ठी के सम्मुख कई विचार पत्र (Papers) थे। जिनमें रचनात्मक कार्यको सफल बनाने के लिए तथा अध्ययन अनुसंधान और मूल्यांकनकी दृष्टि से रचनात्मक संगठनों की आवश्यकताओं को निश्चित करने के लिए सुझावों की रूपरेखा दी गई थी। गोष्ठी द्वारा विचार किए गए

मुख्य मुद्दों तथा चर्चा के अंत में किए गए सर्वसम्मति निर्णयों को निम्न-लिखित निवेदन के रूप में सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया —

१. रचनात्मक कार्य आन्दोलन

गोष्ठी यह मानती है कि, विशेष करके स्वतंत्रता के बाद, देश के विभिन्न भागों में रचनात्मक कार्य केवल उन्हीं लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है जो गांधीजी के विचार और आचार से प्रत्यक्ष प्रभावित हुए थे, बल्कि और भी विभिन्न मंचों के अंतर्गत हो रहा है जिनको सामाजिक कार्य, समाज-सुधार, स्वयंसेवी प्रयास जन सहयोग सामुदायिक कार्य जैसे नाम दिए गए हैं। विभिन्न नाम से किए जानेवाले इन सभी क्रिया कलाओं को रचनात्मक कार्य आन्दोलन माना चाहिए। यद्यपि सामाजिक और रचनात्मक इन एजेन्सिया की दृष्टि के आर्थिक और सामाजिक विकास में सम्पूर्ण देन निश्चित ही सीमित है किन्तु राष्ट्र को खुण्हाल बनाने की उन सबकी मिली जली क्षमता असाधारण है। इसलिए इस समय क्षेत्रीय काम में लगे रचनात्मक संगठनों को एक ऐसे राष्ट्रव्यापी विस्तृत आधारवाले आन्दोलन का बीजबिन्दु मानना चाहिए जो सतत विवसित होगा और अधिकाधिक रूप से ऐसी क्षमता प्राप्त करता जाएगा कि वह न केवल सरकारी कार्यक्रमों का पूरक बने या उनके कार्यान्वयन में सहायक हो बल्कि जनता के समीप काम करके भविष्य के लिए नए मार्ग और नमूने सुझानेवाला सिद्ध हो।

२. मूल उद्देश्य

अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका 'रचनात्मक कार्यक्रम उसका अर्थ और स्थान' (CONSTRUCTIVE PROGRAMME ITS MEANING AND PLACE) में गांधीजी ने रचनात्मक कार्य की विभिन्न १९ भदों के बारे में जो भाग-दर्जन दिया था उसको ध्यान में रखत हुए गोष्ठी को यह लगा कि इस समय, विशिष्ट विस्तार से भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि उस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में जो सिद्धान्त तथा मूल लक्ष्य थे उन पर ध्यान दिया जाए। यही नहीं, वर्तमान परिस्थितियों और जनसंख्या के विभिन्न भागों की

आवश्यकता के प्रकाश में इस कार्यक्रम की पुनः व्याख्या भी आवश्यक है। गांधीजी के सत्य और अहिंसा के बुनियादी मूल्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को अत्यन्त सजग और सतर्क रहना है। मानवीय परिस्थितियों और सामाजिक मूल्यों की भाषा में, इनमें यह निहित है कि नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों, लोकतांत्रिक कार्यात्मकता और मानवीय प्रतिष्ठा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता हो।

गांधीजी के लिए रचनात्मक कार्य, कुछ निश्चित मूल्यों और परिवर्तन पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए, समाज और अर्थव्यवस्था दोनों की पुनर्रचना का माध्यम था। इसलिए रचनात्मक कार्य सम्बन्धी दृष्टिकोण में समुदाय के अंदर सामान्य हित और कर्तव्य की भावना, आपसमें सहभागिता सामुदायिक कर्म तथा आत्म-निर्भरता, स्थानीय संसाधनों का अधिक उपयोग, सर्वोदय के लिए आवश्यक अंत्योदय, राजमन्दी और समझा-बुझाकर परिवर्तन पर आग्रह तथा अच्छे, ध्येयों के लिए अच्छे साधनों पर बल, अतर्निहित है। लोककल्याण, राहत तथा अन्य सहायता के परे, रचनात्मक कार्य का आवश्यक उद्देश्य समाज-आर्थिक परिवर्तन और पुनर्रचना तथा स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित सामाजिक और मानवीय संबंध है। अन्ततः उसकी आशा यही थी कि सर्वोदय के आदर्शों पर आधारित समाज का निर्माण होगा जिसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अहिंसात्मक और शोषणहीन होगी।

गौण्टी का यह विचार है कि देशभर में व्यापक रूप से रचनात्मक कार्य करने के बजाय, वह कुछ छोटे क्षेत्रों में साधन रूप से किया जाए। ऐसे क्षेत्रों में, जो कुछ ग्रामों के समूह हो सकते हैं या संपूर्ण विभाजित प्रखण्ड, विभिन्न क्रियाकलापों की, समुदाय के संपूर्ण संभयन और पहल पर, समग्र दृष्टि से करना है। हर घर में, विशेषरूप से उनमें जो पिछड़े गए हैं, पहुँचनेवाले काम के द्वारा रचनात्मक कार्यकर्ताओं को विकास के ऐसे नमूनों या प्रकार का सृजन करने का काम करना है जो महत्वपूर्ण जरूरतों का समाधान करे और जिनका संतत विस्तार अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में किया जा सके।

३. समाज को संगठित करना

गोष्ठी ने इस पर बल दिया कि रचनात्मक संगठनों और पचायत तथा सहकारी संस्थाओं की, जो बहुत सी विकासकीय गतिविधियों की प्राथमिक प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, सफलता में धनिएठ सबध है। इसलिए समाज में चेतनता और दिलचस्पी का स्तर उठ कर, उनके त्रियात्मक ढग में सुधार करके तथा उनके कार्यकर्ताओं की दक्षता को बढाकर, रचनात्मक कार्यकर्ताओं और संगठनों का यथासम्भव प्रयास, उन संस्थाओं को गतिशील बनाने का होना चाहिए।

स्थानीय लोकतन्त्र तथा आर्थिक, प्रशासनिक और नागरिक कार्यों के विकेन्द्रीकरण का आधार ऐसी ग्रामसभा है जिसका सदस्य ग्राम का प्रत्येक प्रौढ हो। इसलिए यह जरूरी है कि जहाँ भी पहले से कानूनी प्रावधान है, इसकी (ग्राम सभा की) बैठक बहुधा होती रहनी चाहिए और उनको इसका प्रयास करना चाहिए कि जनता की राय और उनकी आवश्यकताओं का असर ग्राम पचायतों और अन्य पचायती राजसंगठनों के निर्णयों पर पड़ता रहे। समुदाय के विभिन्न तरह के लोगों की शक्ति के उपयोग के लिए ग्रामसभा के अतर्गत स्त्रियों युवकों तथा बच्चों के विशेष संगठन होने चाहिए। ग्राम पचायत द्वारा विशेष कार्यों के लिए रचित समितियों में ग्रामसभा के त्रियाशील सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे गाँव के स्तर पर भागीदारी का क्षेत्र विस्तृत हो।

ग्राम समुदाय में दलबन्दी और विपक्षिताओं के अस्तित्व की ओर भी गोष्ठी का ध्यान गया। उसको लगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ एक आवश्यक अर्थ में सुदृढ बनेगी यदि कम-से-कम प्रखण्ड के स्तर तक राजनीतिक दल किसी ऐसी आचार-संहिता पर सहमत हो जाए जिसमें पदाधिकारियों के चयन और संस्था के निर्णयों में दलगत राजनीति की दृष्टि न होकर समूचे तौर पर जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति आदि की दृष्टि रहे। ग्राम और प्रखण्ड स्तर पर निर्णयों के लिए सर्वानुमति या कम-से-कम सामान्य निर्वाचकों के किसी विशाल

बहुमत, जैसे तीन-चौथाई, का आग्रह रखने से बहुत लाभ होगा। इस प्रकार आपसी समझौते की जो भावना निर्मित होगी उससे समुदाय में इसकी क्षमता बढ़ेगी कि वह अपने साधनों और जनशक्ति का उपयोग अधिक दुर्बल लोगों के हित से सवधित विकास में कर सके।

गोष्ठी ने यह मान्य किया कि अधिक समूहों की शक्ति तथा विकास को बढ़ाने तथा नीचे से अधिकाधिक दबाव डालने की उनकी क्षमता में वृद्धि के कदम उठाने की आवश्यकता तथा प्रासंगिकता है। यह लगा कि खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर और भाजिनल किसान जैसे लोगों को यथासंभव सामुदायिक संगठन के ढांचे में एकजुट करने के लिए विभिन्न तरीकों को आजमाना और विकसित करना चाहिए, जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सकें और उनकी बहुवृद्धि के लिए उठाए गए सामाजिक तथा आर्थिक कदमों और भूमि धारों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके। जनता के अधिक दुर्बल और प्रतिकूल स्थितिवाले विशेष समूहों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा और सुदृढ़ता के लिए बनाए जानेवाले संगठनों में, जाति-उपजाति तथा सामाजिक भेदाभेद का, गैर विचार किए प्रत्येक संबंधित व्यक्ति तथा परिवार को समानता तथा सार्वभौम सदस्यता के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिये। ग्रामीण निर्धनों को संगठित करने के प्रयासों के परिणाम सर्वोत्तम तभी निकलेगे जब कि वे प्रयास गांधी विचार पर आधारित होंगे, पृष्ठा और गनुता से बचा जाएगा और पूरे समुदाय में ही सामाजिक एकात्मता तथा एक-दूसरे के लिए चिंता की विस्तृत भावना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में तथा महान अग्यायो को दूर करने के लिए, अन्तिम विवरण के रूप में सत्याग्रह दिया जा सकता है।

देश के कई भागों में, भूदान तथा ग्रामदान के बड़े बड़े क्षेत्र हैं। जहाँ भी संभव हो, उपर्युक्त प्रस्तावित दिशा में भूदान-भूमि तथा उन्हीं लाभान्वित लोगों के विकास के प्रयास किए जाएँ और उनका उपयोग पूरे समुदाय के जीवन के पुनर्निर्माण में बीज केन्द्र के रूप में किया जाए।

सामुदायिक स्तर पर अधिक प्रभावी क्रिया तथा अधिक दुर्गल और निधन समूहों के संगठना के लिए उपर्युक्त सुझावों के कारगर क्रिया-व्ययन की दृष्टि से गोष्ठी को यह लगा कि पंचायती, सहकारी समस्याओं भूदान तथा ग्रामदान भूमि सुधार विषयक तथा अन्य संबंधित वर्तमान कानूनों का आज की आवश्यकताओं और पिछले १०-१५ वर्षों में होनेवाले परिवर्तन के प्रकाश में, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के साथ सहयोग करके पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए।

४. रचनात्मक कार्य क्षेत्र

गोष्ठी ने उन दिशाओं पर भी विचार किया जिनमें विकास के वर्तमान स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक कार्य को अधिक विस्तृत और व्यापक बनाने की जरूरत है। चुने हुए क्षेत्रों में सघन काम करने वाले रचनात्मक संगठनों को विभिन्न प्रवृत्तियों में समग्रता की पद्धति अपनाने स्थानीय समुदाय को अपने काम में साथ देने, स्थानीय प्रभावी नृत्वकों को आगे लाने तथा कार्यक्रमों के गुण विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गोष्ठी को यह लगा कि कृषि विकास ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और क्षेत्रीय समुदाय के स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी दक्षता जैसे मार्गजनिक नीति नीति के बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र के लिए रचनात्मक संगठनों के अपने भी स्रोत विकसित करने तथा ज्ञान बढ़ाने के विशेष प्रयास करने चाहिए। रचनात्मक संगठनों को रचनात्मक कार्य संबंधी धारणाओं और दायरे को व्यापक बनाना चाहिए। तथा राष्ट्रीय ऐक्य और सांस्कृतिक विकास, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य और सफाई, जल-प्रदाय तथा प्रौढ़ शिक्षा जैसे महत्व के क्षेत्रों में भी अपने अनुभव तथा स्रोतों का आवश्यक विकास करना चाहिए।

गोष्ठी ने यह बात स्वीकार की कि विगत वर्षों में विकास प्रशासन का एक सुसम्पन्न ढाँचा निमित्त हो गया है और ग्रामीण समाज की हित की दृष्टि से अनेक एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। नदी-हरणत जिलों और प्रखण्ड का विकास कर्मचारियों, पंचायती राज्य और सहकारी

संगठन, कृषि विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण तथा शोध में लगी अन्य सस्थाएँ मार्केटिंग बोर्ड्स और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हुए सार्वजनिक और निजी उद्योग कार्यक्रम। इन सभी एजेंसियों को परस्पर अपने प्रयासों का तालमेल बैठाना चाहिए, और साथ ही दूसरी ओर रचनात्मक संगठनों को, एक सामान्य हित के ऐसे कार्यक्रम में एकदूसरे को भागीदार मानकर उनको अपना निवृत्त सहयोग देना चाहिए।

गोष्ठी को यह अच्छा लगा कि सार्वजनिक रीतिनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केन्द्रीय और राज्य सरकारें, जैसा कि आवश्यक है, अधिनाधिक क्षेत्र विकास की दृष्टि, अन्तर्पचारिक पद्धतियों के प्रयोग, सामुदायिक क्रिया पर बल, अधिक दुर्बल वर्गों तथा अन्य लक्ष्यनिष्ठ समूहों की आवश्यकता की पूर्ति के प्रयास और रचनात्मक तथा स्वयंसेवी संगठनों के एक बड़े 'रोल' की दिशा में, प्रगति के साथ बढ़ती जा रही है। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों और स्वयंसेवी सस्थाओं दोनों से अब अपेक्षा है कि सारे कार्य में अधिक जोरदार पहल वे करें। अब यह विशेष रूप से आवश्यक है कि राजकीय विभाग उनको अन्य एजेंसियों अपनी गतिविधियों, दृष्टि और पद्धतियों से रचनात्मक संगठनों, पंचायतों, सहकारी सस्थाओं आदि को अवगत रखने के लिए विशेष योजनाएँ चलाएँ। व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से उनकी सहायता, प्रशिक्षण और फण्ड के बँटवारे की प्रक्रिया का विकास किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित की जानी चाहिए जिसमें रचनात्मक संगठन, सामुदायिक सस्थाएँ और सभी सरकारी तथा सकार-निर्मित एजेंसियाँ, लोगों की सेवा में लगातार भागीदार के रूप में काम कर सकें। प्रत्येक का 'रोल' क्या होगा यह स्पष्ट हो और हर एक उसका ध्यान रखे तथा साथ ही, सारी संरचना और सहायता की शैलियों में लचीलापन भी रहे।

५. कार्यकर्ता शक्ति खड़ी करना और उसका प्रशिक्षण।

गोष्ठी में भाग लेनेवालों को अपने-अपने क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर यह लगा कि रचनात्मक संगठनों की सफलता के लिए

सबसे महत्वपूर्ण शर्त कार्यकर्ताओं का गुण स्तर, योग्यता तथा उनकी समर्पित भावना और उनकी उपलब्धि है। जो भी कार्यक्रम हाथ में लेने है उनके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के सहकार की आवश्यकता है। इसलिए, अपने कार्य के फैलाव के अनुसार, रचनात्मक संगठनों के पास कार्यकर्ताओं का ऐसा एक छोटा समूह होना चाहिए जो स्थानीय समुदाय और सरकार तथा सङ्घित एजेंसियों सबके साथ काम करने की योग्यता रखते हों। ऐसे कार्यकर्ताओं के समाज में उनका समुचित स्थान मिलना चाहिए और उचित मानधन तथा अन्य सुविधाओं के लिए उनकी आवश्यकता किया जाना चाहिए। देश में कई ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-से युवा और योग्य व्यक्ति काम कर रहे हैं इस जानकारी से गोष्ठी को प्रोत्साहन मिला। यह भी जानकारी में आया कि बहुत से व्यक्ति जो सरकारी और गैर सरकारी पदों से सेवा निवृत्त हुए हैं जिन्हें पर्याप्त अनुभव है तथा जिनका स्वास्थ्य ठीक है, सेवाभावना में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं। सरकारी कर्मचारियों अध्यापक तथा दूसरों को अध्ययन-अवकाश की सुविधाएँ मिलनी चाहिए जिससे वे मध्य स्वयंसेवी संगठनों के साथ देहात में स्वयंसेवी कार्य कर सकें।

—जैसा कि पहले ऊपर कहा जा चुका है रचनात्मक संगठनों के कार्यकर्ताओं के पर्याप्त प्रशिक्षण को गोष्ठी बहुत महत्व देती है। उसका मुनाफा है कि सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं में वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं और उसकी सक्षमताओं का सर्वेक्षण किया जाए और उसको सफल बनाने के लिए कदम उठाए जाएँ। गोष्ठी ने यह आशा भी व्यक्त की कि केन्द्र और प्रादेशिक सरकारों की जो संस्थाएँ विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण में लगी हैं वे रचनात्मक संगठनों द्वारा मनोनीत कार्यकर्ताओं के लाभ के लिए विशेष प्रशिक्षण और नव संस्करण के कार्यक्रमों को प्रारम्भ करनी।

६. रचनात्मक कार्यके लिए साधन

गोष्ठी ने साधनों के प्रश्न पर बड़ी सावधानी से विचार किया जिसमें रचनात्मक संस्थाएँ प्रत्यक्ष सेवा करके और ठीक शैलियाँ तथा

पद्धतियाँ कायम कर विशाल जनता की, विशेष रूप से अधिक दुर्बल और प्रतिकूल अवस्थावाले समूहों की आर्थिक और सामाजिक बहुवृद्धि में उचित योगदान कर सके। इसको लगा कि जिस सीमा तक रचनात्मक संगठनों को विश्वास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा स्थानीय क्षेत्र और समुदायों की सेवा का स्पष्ट 'रोल' सौंपा जाएगा, उस सीमा तक केन्द्र तथा प्रादेशिक सरकारों के संबंधित विभागों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों में से वे वित्तीय सहायता ले सकेंगे। इसके बारे में केन्द्र और प्रादेशिक सरकारों द्वारा अपने विभिन्न विभागों और संगठनों को मोटे निदेश दिए जाने की जरूरत होगी।

निकट के वर्षों में, साथ और वृत्ति संगठन 'फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैम्पेन' के अतर्गत तथा अन्य विदेशी-स्वीच्छक सहायता के स्वीकृत स्रोतों से भारत सरकार की मारफत जो सहायता रचनात्मक संगठनों को प्राप्त हुई है, उसकी गोष्ठी ने सराहना की। इस सहायता से स्वयंसेवी संगठनों को काम बहुत अच्छी तरह करने में सुविधा हुई है। फिर भी, गोष्ठी को यह लगा कि विदेशी साधनों का 'रोल' नामूली और पूरक ही हो सकता है, मुख्य प्रयास तो देश के अपने सरकारी और गैर सरकारी साधनों से ही अधिक-से-अधिक सहायता जुटाने का होना चाहिए। गोष्ठी ने इस बात को सर्वोच्च महत्व दिया कि स्थानीय समुदाय का चेतना और प्रेरणा तथा समर्थ, विशेष-रूप से अधिक दुर्बल वर्गों के मंगल के प्रति अतिसह्य भावना में वृद्धि कर, उन समुदायों के साधनों को विकसित किया जाए और सहायता जुटाई जाए। संगोष्ठी ने इस पर ध्यान दिया कि निम्न केन्द्र सरकार ने व्यावसायिक उद्यम की इस दृष्टि से कर में महत्वपूर्ण रियायत दी है कि वे ग्रामीण विकास की योजनाओं में आर्थिक सहायता दें। गोष्ठी ने आशा व्यक्त की कि इन सुविधाओं का उपयोग ऐसे बड़े और सतत बढ़ने वाले विकास-क्षेत्रों के निर्माण में किया जाएगा जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों और रचनात्मक संगठनों के ग्रामीण क्रियाकलापों में सहायता देने का होगा। सार्वजनिक अधिकारियों ने और प्रतिनिधित्व के सहयोग से इसके लिए तरीके विकसित किए जाने चाहिए।

७. रचनात्मक कार्य अनुभव का विश्लेषण और मूल्यांकन

देश में विभिन्न परिस्थितियों के अतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को रचनात्मक कार्य-अनुभव के सतत विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता पर गोष्ठी ने गहराई से विचार किया। यह वाछनीय है कि रचनात्मक और स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा होनेवाले काम की नियमित जानकारी प्राप्त करने की तथा इस जानकारी और अनुभव की यथा-समय दूसरों को मुहैया कराने की पर्याप्त व्यवस्था हो। उनके द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों, उनकी सफलताओं तथा विफलताओं, का तटस्थ अध्ययन उनके सहयोग में किया जाना चाहिए। रचनात्मक संगठनों की इस बात में सहायता की जानी चाहिए कि जिन समस्याओं का हल अभी तक नहीं मिल सका है उनके सतोपजनक उत्तर की खोज की दृष्टि से वे मूजनात्मक सामाजिक प्रयोग कर सकें। सामाजिक आर्थिक और तकनीकी विकास के क्षेत्रों में जो बहुत सी समस्याएँ इस समय प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य में लगी हैं, उनके भी साधनों का इस्तेमाल, सामुदायिक स्तर की महत्वपूर्ण समस्याओं के हल में अधिकाधिक सहायता के लिए किया जाना चाहिए।

गोष्ठी का विचार रहा कि रचनात्मक कार्य के अध्ययन और मूल्यांकन के लिए किसी उपयुक्त केन्द्र के स्थापनायें शीघ्र कदम उठाए जाएँ तो इन विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास हो सकता है। यह केन्द्र एक ओर तो इसके लिए प्रयत्न करेगा कि रचनात्मक संगठनों से लगातार सूचना मिलती रहे और दूसरी ओर ऐसा ही प्रयत्न विश्वविद्यालयों और विभाग के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र से चलेगा। यह केन्द्र रचनात्मक कार्यकर्ताओं, विकास कर्मचारियों और समाज-वैज्ञानिकों को समय-समय पर अपने अनुभव और चिंतन के आदान प्रदान के लिए तथा अपने ज्ञान और पद्धतियों को, विशेषरूप से उनकी जो सफल सिद्ध हुई हों, जानकारी देने के लिए, एकत्रित करेगा।

प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना तथा अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुसंधान और प्रयोग के लिए, जिनका सवध, रचनात्मक कार्य से

और रचनात्मक तथा स्वयंसेवी कार्य-कर्ताओं के प्रशिक्षण की सुधरो पद्धतियों से होगा, एक विस्तृत योजना अधिव' सोच विचार के बाद तैयार की जानी चाहिए।

८. राष्ट्रीय और प्रादेशिक नीति

गोष्ठी ने यह आशा व्यक्त की कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार अपनी ओर से अपनी-अपनी नीति में इसका यथासम्भव प्रयास करेंगी कि रचनात्मक और स्वयंसेवी संगठनों की इसमें सहायता की जाए कि वे अ आवश्यक सेवाओं के लिए जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा जनता के निवृत्तम विकासकीय कार्यों के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमता और साधन का तथा स्वयंसेवी प्रयासों के सहज शाय्यताओं का इस्तेमाल कर सकें। ऐसी राष्ट्रीय और प्रादेशिक नीति के बिनासे तथा नियान्वयन में, रचनात्मक संस्थाएँ खुशी से उस समर्थन और सहायता को देने के लिए तैयार रहेंगी जिसके लिए उनसे इच्छा व्यक्त की जाएगी।

९. रचनात्मक कार्य पर समिति

गोष्ठी को लगा कि विकास के जिस स्तर पर हम पहुँच गए हैं, उस पर सगाज कार्य के कई क्षेत्रों में, जैसे आर्थिक और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, रोजगार का विस्तार, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, ग्रामीण औद्योगीकरण तथा गाँव और उद्योग के सवध में उत्पादन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण और आगक्षण तथा सार्वजनिक नीतियों की समीक्षा, तीव्र करने की जरूरत है।

गोष्ठी ने गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष से यह निवेदन किया कि इस सर्वेसम्मत वक्तव्य में दी गई सिफारिश पर आगे कार्यवाई करने के लिए रचनात्मक कार्य पर एक समिति बनाएँ। इस समितिकी रचनात्मक कार्य अध्ययन केन्द्र सवधी प्रस्तावों की तपसील में जाना और कुछ विशेष प्रकार की रचनात्मक प्रवृत्तियों का विशेषतया हरि जन और आदिवासियों सवधित कार्यों का, व्यवस्थित पुनर्निरीक्षण प्रारम्भ करना होगा।

राष्ट्रीय रचनात्मक कार्य विचार-गोष्ठी अध्यक्ष, गांधी स्मारक निधिद्वारा गठित कार्यान्वयन (फॉलो-अप) समिति

- १ डा श्रीमन्नारायण, अध्यक्ष, गांधी स्मारक निधि —अध्यक्ष
 - २ डा र रा दिगंबर, अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
 - ३ श्री सिद्धराज ढड्डा, अध्यक्ष, सर्व सेवा सघ, गोपुरी (वर्धा)
 - ४ श्री विचित्र नारायण शर्मा, अध्यक्ष भारतीय खादी ग्रामोद्योग सघ, लखनऊ
 - ५ श्री अण्णानाहेव महम्मदुल्ले, अध्यक्ष, गांधी सेवा सघ सेवाग्राम (वर्धा)
 - ६ श्री दयामलाल, अध्यक्ष, हरिजन सेवक सघ, नई दिल्ली
 - ७ डा सुशीला नंद्यर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय नानाबदी परिषद, नई दिल्ली
 - ८ श्री ल म श्रीकान्त, उपाध्यक्ष भारतीय आदिम जाति सेवक सघ, नई दिल्ली,
 - ९ श्री धरमसीभाई खटाऊ, अध्यक्ष, अ भा कृषि मोसवा सघ, वर्धा
 - १० श्रीमती लक्ष्मी एन मेनन, अध्यक्ष, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इंदौर
 - ११ डा मोहनसिंह मेहता, अध्यक्ष, सेवा मंदिर, उदयपुर
 - १२ श्री जे पी नायक, सचिव, इण्डियन काउंसिल आफ सोशल साइन्स रिसर्च, नई दिल्ली
 - १३ श्री सतीशचन्द्र आर-१२।१, राजनगर, गाजियाबाद
 - १४ श्री पूर्णचन्द्र जैन मंत्री, गांधी स्मारक निधि नई दिल्ली
 - १५ श्री तरलोक सिंह, ११० सुन्दर नगर, नई दिल्ली
- उक्त समिति को तीन तक अन्य सदस्य सहवर्ण करने का अधिकार होगा।



स्वर-संस्कार

[स्वर वर्णों की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें कविता के माध्यम से भरतापूर्वक याद किया जा सकता है । इसी दृष्टि से अ से झ तक १२ स्वरों पर आधारित कविताएँ यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं]

स्वर-संकेत :

अ आ इ ई उ ऊ ढम
ए ऐ ओ औ की ङम ङम
अं अंगूर हमें हैं माते
अः गीत हम हिल मिल गाते

स्वरावली :

अ

अनन्त है आनन्द अपार
घरती-माता का आधार
शिशु मंगलमय रूप उदार
मानव महिमा अपरंपार

इ

इला श्यामला घरती माता
गुमधुर फल फूलों की दाता
रंग विरंगी फूल अनेक
ले लूँ मैं उनसे से एक !

उ

उड़न खटोला उड़ता जाए
बैठे बालक मोव बनाए
हिमगिरि पर्वत पर उड़ जाए
'जय जय' करते हाथ हिलाए ।

आ

आभा फैल रही सुकुमार
पंछी कलरव करें उदार
सोता मैना चिड़िया रानी
बानी से हम सुनें कहानी

ई

ईश्वर की महिमा है प्यारी
भारत माता की बलिहारी
गंगा-जमना बहती धारा
धमक रहा है भाग्य-सितारा

ऊ

ऊपर से नीचे हम आते
भारत का गुण गौरव गाते
गुमधुर मीठे फल हम खाते
वर्षा में हम पूब मचाते

ए

एक बने हम, नेक बने हम
सगुण गुणी गुणवान बने हम
ज्ञानी ध्यानी धीर बने हम
देशभक्त बलवीर बने हम !

औ

औजस तेजस् दोनों भैया
बलि बलि जाए प्यारी भैया
साहसी अमित उदार
नैया तैर रही मँसधार

अ

अचल चंचल चाँव चाँव
कौधा करता काँव काँव
हम्मा हम्मा गोमाता की
जय बोली गंगा माता की

ऋ

ऋ से ऋषि हुए भारत में
अगणित ज्ञानी ध्यानी
आश्रमवासी बने तपस्वी
ज्ञानी वर विज्ञानी

जीवन कुटीर
वर्धा (महाराष्ट्र)

—मदालसा नारायण

ऐ

ऐतिहासिक देश प्यारा
हिंद वरदायक हमारा
गगन में चमका सितारा
धय धरती दिव्य धारा

औ

औजार गुणी गुणमय हैं नाम
आते हैं वे सब के काम
करामात हूँ वे बिछलाते
उनसे खेल खिलाते बनते

अ

अ मनोहर हैं गुलबस्ता
घर में बना पड़ा होसरता
दीदी ने हैं इसे बनाया
भैया ने हैं इसे सजाया !

~ ~



शिक्षा में सुधार

नई तालीम समिति के सुझाव

अखिल भारत नई तालीम समिति की एक आवश्यक बैठक नई दिल्ली में १७ जुलाई को केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि कॉलोनी में हुई थी। उसने शिक्षा सुधार सबंधी नीचे लिखे सुझाव शिक्षा मंत्री भारत सरकार को दिए हैं -

केन्द्र तथा अन्य कई राज्यों में अब जब कि जनता सरकार राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्र में महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने के लिए वचनबद्ध है, अखिल भारत नई तालीम समिति आशा करती है कि सरकार निम्नलिखित सुझावों पर गम्भीरतासे विचार करेगी।

१- सभी स्तरों पर शिक्षा सामाजिक रूप से लाभप्रद और उत्पादक गतिविधियों के द्वारा दी जाए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और विकास से सम्बद्ध हो। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम में कम से कम ५० प्रतिशत समय इन उत्पादक और रचनात्मक गतिविधियों को दिया जाए।

२- प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक पाठ्यक्रमों में तीन मूल बातों पर विशेष धन दिया जाए -

१- उत्पादक श्रम को शिक्षा का अभिन्न अंग मानकर स्वावलम्बन, आत्मविश्वास और श्रम का महत्व।

२- छात्रों और अध्यापकों को सार्वक समान सेवा के कार्यक्रमों से सम्बद्ध कर राष्ट्रीयता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना।

३- नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का निर्माण, एकताकी आवश्यकता तथा सभी धर्मों के प्रति समान आदर।

इन पाठ्यक्रमों में अपनी प्राचीन सांस्कृतिक देन का सामान्य ज्ञान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास, राष्ट्रीय एकता पर ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा अहिंसा, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता आदि विषयों को शामिल किया जाना चाहिए।

शिक्षा में उचित समय पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में 'गांधी विचार' का अध्ययन भी शुरू किया जाना चाहिए।

३- नई शिक्षा प्रणाली तब ही अर्थपूर्ण हो सकती है जब शिक्षा को नौकरी से सम्बन्ध न किया जाए। सरकारी विभाग तथा निजी

या सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में भर्ती के लिए उद्योग, वाणिज्य या सरकारी रोजगार में लगे लोगों के लिए बिना डिग्री के पाठ्यक्रमों की प्रणाली की स्थापना करना आवश्यक है।

४- विभिन्न चरणों में १०+२+३, वाले शिक्षा के ढांचे को अपनाया जाना चाहिए। दस वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद बड़ी सख्या में अनेक प्रकार के द्विवर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू किये जाएँ जो छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त करने और जीवन में स्थिर होने में सक्षम बनाएँ। उच्चस्तर माध्यमिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के आधार पर व्यावसायिक बनाया जाए। संज्ञात्मक और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त छात्रों में कोई अन्तर नही रखना चाहिए।

प्रथम दस वर्ष की स्कूली शिक्षा में "शारीरिक और उत्पादक कार्य पर बल दिया जाए तथा अन्य कार्यक्रमों का विकास किया जाए और यथा-सम्भव ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जो बच्चों के पर्यावरण के अनुकूल हो।

केन्द्रीय और पब्लिक स्कूलों समेत सभी स्कूल मातृ भाषा माध्यम और त्रिभाषा फार्मुले के सम्बन्ध में भी राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे के अनुसार हो तो भारत की विविधतापूर्ण सभ्यता का विस्तार करें।

५- स्कूली क्षेत्र में नए प्रयोगों को प्रोत्साहन देने के लिए "स्वायत्तता प्राप्त कॉलेज" के समान स्कूलों को भी चलाया जाए।

६- स्कूल और कॉलेज आस-पास के क्षेत्र में 'व्यावहारिक शिक्षा' के कार्यक्रम चलाएँ। संज्ञात्मक ज्ञान देने के साथ-साथ विभिन्न व्यवसायों में लोगों की कार्यकुशलता सुधारने तथा उसका स्तर बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया जाए।

७- शिक्षा मंत्रालय देश में बुनियादी शिक्षा की प्रगति की समीक्षा, अनुमान और मार्गदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा परिषद की स्थापना करे। राज्य सरकार भी अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी ही बुनियादी शिक्षा परिषदों की स्थापना करें।

८- देश के सम्मुख बुनियादी शिक्षा का अधिक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बुनियादी और उत्तर-बुनियादी शिक्षा संस्थाएँ अपने कार्य और अन्य सम्बन्धित शिक्षा में सुधार करने के लिए ठोस प्रयत्न करें।

९- बुनियादी शिक्षा के पक्ष में उचित वातावरण बनाने के लिए अखिल भारत नई तालीम समिति प्रत्येक राज्य में व्यापक आधार पर इकाइयों का गठन करे।

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee"

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

"यदि आपका प्रयत्न बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गोहाटी - न्यू बेहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

नई तालीम अगस्त-सितम्बर '७७

रजि० सं० WDA/1

लायसेंस नं० ११

हिन्दुस्थान शुगर मिल्स लिमिटेड का विभाग
मेरास उदयपुर सीमेंट वर्क्स
की
शुभ कामनाएँ

उच्च धेनी का 'शक्ति' छाप सीमेंट जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सब तरह के नवनिर्माण कार्य के लिए मजबूती तथा विश्वस्तता के साथ किया जाता है।

ध्यवस्था एवं विधी कार्यालय—

फैक्टरी,
पो. भो. बजाज नगर
(सी. एफ. ए.)
जि. उदयपुर (राजस्थान)
फोन : दशहरा : ३६ और ३७
उदयपुर २६०६

शहर कार्यालय,
६० नया पतेपुरा
उदयपुर ३१३००१
फोन ४४९, ग्राम 'बी'
उदयपुर

नयी तालीम

विद्यालय में परमेश्वर का आनन्दस्वरूप प्रगट होना चाहिए। ईश्वर के रूप तो अनन्त हैं, पर उसके तीन रूप बड़े प्रसिद्ध हैं। एक है सत्य, दूसरा है चित् याने ज्ञान और तीसरा है आनन्द। कर्मयोग में, संसार में, जीवन में सत्य प्रधान होता है। ज्ञानियों की गुहा में और विद्वानों के पुस्तकालय में ज्ञान प्रधान होता है। भक्ति-मार्ग में आनन्द प्रधान होता है। विद्यालय याने भक्ति-मार्ग, याने यहाँ हर चीज़ जो की जाएगी वह आनन्द के लिए ही की जाएगी।

— विनोबा



अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाश्रम

सम्पादक—मण्डल :

श्री धीमन्नारायण — प्रधान सम्पादक

श्री वज्रुभाई पटेल

श्रीमती मदालसा नारायण

डॉ० मदनमोहन शर्मा

वर्ष २६

अंक १

अनुक्रम

समाप्त दृष्टिकोण		
शक्ति पालेति सम्मन्ध जोडे	महात्मा गांधी	७१
शिक्षकों की स्वातन्त्रता चाहिए	बिनोबा	८९
देश की नई शिक्षा पद्धति	मोरारजी देसाई	९१
गांधीवादी योजना की रूपरेखा	श्रीमन्नारायण	९९
प्राकृतिक चिकित्सा का महत्त्व	...	१०७
एजुभाई	मदालसा नारायण	११९
सेवाप्रान्त-आयम-वृत्त	...	१२१

अक्टूबर—नवम्बर '७७

- * 'नई छातीम' का वर्ष अणुस से प्रारम्भ होता है।
- * 'नई छातीम' का वार्षिक दृष्टि बारह रूप है और एक एक का मुख्य दो है।
- * दृष्टि-संपादन करते समय छात्र अपनी सच्चा निष्ठा न भूलें।
- * 'नई छातीम' में अन्य विषयों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ या नई छातीम समिति सेवाप्रान्तों लिए प्रकाशित और
पत्रभाषा प्रेष, चर्चा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

१ अखिल भारत तथा अन्य शिक्षा सम्मेलन

जनता पार्टी का राज्य दिल्ली व उत्तरप्रदेश के कई प्रदेशों में करीब सात महीने से चल रहा है। इस बीच शासन की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रेस व भाषणों की स्वतंत्रता वापिस दी गई है और आपातकालीन आनक का वातावरण समाप्त किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि जनता सरकार गांधीजी के सपने के भारत का निर्माण करने के लिए कचन-बद्ध है। कृषि खादी ग्रामोद्योग मद्य-निषेध, गोसेवा, प्राकृतिक चिकित्सा, आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को अहमियत दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के सन्तुलित विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

किन्तु अभी तक शिक्षा सुधार की तरफ पर्याप्त चिन्तन नहीं हो सका है। केन्द्रीय शिक्षामंत्री डा प्रतापचन्द्र चन्दर काफी प्रयत्न कर रहे हैं कि देशकी शिक्षा पद्धति को नई दिशा दी जाए। प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई ने भी हाल ही में गुजरात विद्यापीठ के अपने दीक्षान्त भाषण में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनके भाषण के मुख्य अंग अन्यत्र इसी अंक में प्रकाशित किए गए हैं। लेकिन अब यह निहायत जरूरी है कि नई शिक्षा-मरजना के सम्बन्ध में ठोस निर्णय लिए जाएं और उन्हें व्यवस्थित ढंग से मारे देश में लागू किया जाए। *

इस दृष्टि से अखिल भारत नई तालीम समिति की ओर से दिल्ली में एक शिक्षा-सम्मेलन १८, १९, २० दिसम्बर को आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई करेंगे। डा चन्दर भी इसमें उपस्थित रहेंगे। सभी राज्यों के शिक्षा

मंत्रियो व प्रमुख विश्वविद्यालयोंके कुलपतियोंको आमन्त्रित किया गया है। देशभर के चुने हुए लगभग १५० शिक्षाशास्त्री व बुनियादी तालीमके कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। हम आशा करते हैं कि इस सम्मेलनमें कुछ निश्चित सर्वानुमति प्रकट होगी जिसके अनुसार भारत की शिक्षा-पद्धतिको ढाला जा सकेगा।

यह तो जाहिर ही है कि महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ही हमें अपनी सभी शिक्षण-संस्थाओं में हर स्तर पर समाज-उपयोगी उत्पादक श्रम को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। नटपि बिनोबा ने नई बाग समझाया है कि कर्म और ज्ञान का अद्वैत ही बुनियादी शिक्षा का मूल मंत्र है। विद्यार्थियों को यह पता ही नहीं लगना चाहिए कि उन्हें उत्पादक उद्योगों द्वारा कोई पाठ्यक्रम सम्बन्धी ज्ञान दिया जा रहा है। यह प्रक्रिया-अनुसंधान विसकुल सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। छात्र और शिक्षक मिलकर इस कर्म-ज्ञान-यज्ञ में भाग लें—“महवीर्यम् करवावहे।” यह यज्ञ निरन्तर आनन्द देनेवाला हो तभी वह सही शिक्षा का स्रोत बन सकेगा। यदि विद्यार्थियों को बाल मदिरा, स्कूल व कालिजों में अध्ययन द्वारा आनन्द की अनुभूति प्राप्त न होती रहे तो वह तालीम निकम्मी ही समझी जाएगी।

हमारी नई सरकार देश की बेकारी व गरीबी को अगले दस वर्षों में समाप्त करना चाहती है। ऐसा करने के लिए शहरों व गाँवों में छोटे उद्योगों व ग्राम-उद्योगों का व्यापक जाल बिछाना होगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की खास कोशिश करनी होगी। जाहिर है कि यह उद्देश्य आवश्यक शिक्षा-मुद्धार के बिना सफल नहीं हो सकेगा। शिक्षा और विकास-कार्यों के बीच अटूट सम्बन्ध जोड़ना होगा। यह तभी मुमकिन हो सकेगा अब हमारी शिक्षा-प्रणाली गांधीजी की “नई तालीम” योजना के अनुरूप श्रद्धापूर्वक पुनर्गठित की जाएगी।

२. प्राकृतिक चिकित्सा और शिक्षण-संस्थाएँ :

अखिल भारत प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् की ओर से १४, १५, १६ अप्रैलको गावगमती आश्रम, अहमदाबाद में गन्द्रहवाँ अधिवेशन,

सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया। सम्मेलन में देशभर के करीब ६०० प्राकृतिक चिकित्सक व कार्यकर्ता शामिल हुए। विस्तृत चर्चाओं के अन्त में जो प्रस्ताव पारित किए गए वे इसी अवसर में अलग दिए गए हैं। बंसर, हृदय रोग व बुद्ध-रोगों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा प्रयोगों पर विशेष पकड़ डाला गया। यह भी समझाया गया कि भारत के ग्रामीण-क्षेत्रों में जा स्वास्थ्य-योजना चालू की जा रही है उसमें प्राकृतिक जीवन चिकित्सा को प्रमुख स्थान देना अत्यन्त आवश्यक है।

लेकिन यह स्पष्ट है कि देश में प्राकृतिक जीवन दर्शन को तभी स्याई रूप से प्रतिष्ठित किया जा सकता है जब इसके बुनियादी सिद्धान्त हमारी शिक्षण-संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाएं और प्रारम्भ से ही बच्चों को प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व समझाया जाए। इस बारे में सम्मेलन ने एक प्रस्ताव भी प्रकाशित किया है। हम आशा करते हैं कि विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभाग इस ओर धीरे ध्यान देंगे।

३ देश की वर्तमान अवस्था

प्रतिवर्ष हम गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता का पुण्य-स्मरण करते हैं और उनके रचनात्मक कार्यक्रमों पर आवश्यक जोर देने रहते हैं। हममें से कुछ का ख्याल है कि खादी व ग्रामोद्योग ही महात्मा गांधी की विचारधारा के असली प्रतीक हैं। दूसरों का विचार है कि मद्य-निषेध हर्जित व आदिवासियों का कल्याण व नई तालीम कार्यक्रम विशेष महत्व रखते हैं। अन्य लोगों की धारणा है कि प्राकृतिक चिकित्सा व बुद्धराग निवारण की योजनाएँ गांधीजी के रचनात्मक काम की बुनियाद हैं। दरअसल इन सभी कार्यक्रमों की अपनी विशेष अहमियत है। किन्तु हम यह कभी न भूलें कि बापूकी विचारधारा और जीवन-मूल्यों का मत्व है 'साधन-शुद्धि'। उन्होंने हमें बार-बार समझाया था कि यदि हम अपने पवित्र साध्यों के लिए अपवित्र साधनों का इस्तेमाल करेंगे तो अमफल ही होंगे। विनोबाजी ने इसे 'गांधीजी के नए अद्वैत' की संज्ञा दी है। माध्य और साधना के बीच कोई दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। वे एक दूसरे के अविभाज्य अंग हैं। 'साधन शुद्धि'

का सिद्धान्त प्रकृति के नियमों की तरह अटन है, उसकी अनिवार्यता अवाट्य है। वह बोग आदर्शवाद नहीं, नितान्त व्यावहारिक भव्य है।

इस समय देश की अवस्था मनमुच चिन्तनीय है। रोज ही हड़तालें घराब व उपवासों के समाचार अखबारों में छपने रहते हैं। कानून की व्यवस्था ढीली व अस्त व्यस्त होती जा रही है। प्रत्येक वर्ग अधिक वेतन व महंगाई भत्ता मांगता है और यह भी चाहता है कि रोजमर्रा के उपयोग की चीजों के दाम कम हों। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि उत्पादन नहीं बढ़ेगा और मुद्रा की मात्रा निरन्तर बढ़ती जाएगी तो कीमतें नियंत्रण में लाना कैसे संभव होगा। अगर वर्तमान परिस्थिति पर धाबू पाना है तो जनता व विभिन्न वर्गों को अपना जीवन में आत्मनिष्ठा से तो लाना ही होगा न? महात्मा गांधी ने १९३१ में ही स्वराज्य भिन्न के पहले स्पष्ट शब्दों में कहा था— 'अनुशासन और विवेकयुक्त जनतन्त्र, दुनिया की सबसे सुन्दर वस्तु है।' हम इसी प्रकार का प्रजातन्त्र स्थापित करने का पूरा प्रयास करना है।

बापू ने एक और विचार हमें दिया था। वह था 'अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था— 'मैं तो एक ही अधिकार जानता हूँ— अपने कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार।' किन्तु इस समय तो हम सब अधिकारों की माँगों के चक्कर में पड़ गए हैं। जिम्मेदारियों का हमें बहुत कम भान है। यह दयनीय व चिंताजनक हानि हमारे राष्ट्र के लिए मनमुच बहुत खतरनाक है। भगवान् हमें सन्मति प्रदान करें।

४ 'वर्ग पक्ष' व गान सत्याग्रह

कुछ सप्ताह पहले भाई जयप्रकाशनारायणजी ने एक प्रसंगपर कह दिया था कि हरिजनो व अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए 'वर्ग पक्ष' अनिवार्य है। इस विचार को दक्षिण सभी समाचार पत्रों ने गहरापूर्ण ढंग से प्रकाशित किया और उसके कारण काफी गलतफहमी भी पैदा हुई। बाद में श्री जयप्रकाशजी ने कई दफा यह स्पष्ट कर दिया है कि यह 'वर्ग पक्ष' गांधीजी के आदर्श के अनुसार ही होना चाहिए। उसमें भावसंवादी हिंसा व वर्ग कलह का स्थान नहीं हो सकता। किन्तु

शब्दों के प्रयोग से भी अनावश्यक भ्रम व बुद्धि भेद पैदा हो जाना स्वाभाविक है। इसलिए अच्छा हो यदि हम 'वर्ग-सघर्ष' के स्थान पर 'सत्याग्रह' शब्द का प्रयोग करें। यह शब्द बापू ने दिया था और उनका नहीं अर्थ अब मारे ममार में व्यापक हो चुका है।

हाल ही में आचार्य कृपलानी ने विलुप्त सही कहा है कि हरिजनो का संरक्षण देने की जिम्मेदारी सवर्णों को सहर्ष उठा लेनी चाहिए। गरीब वर्गों को ही अपनी सुरक्षा के लिए नये संगठन बनाने के लिए मजबूर होना पड़े यह उचित नहीं है। गांधी के देश में इस प्रकार की परिस्थिति साम्या नहीं देनी। इसीलिए बापू ने हरिजन संघ के प्रमुख कार्यकर्ता वर्गों में से ही चुने थे। इस समय भी हम अभी का पावन कर्तव्य हो जाता है कि हरिजनो व गिरिजनो की हिफाजत की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि आए दिन होनेवाली धर्मनाक घटनाएँ बंद हों और भाग्य में एकता व भाईचारे का शुद्ध पातावरण प्रस्थापित हो सकें।

यह भी आवश्यक है कि हरिजनो की समस्याओं को दलगत राजनीति के नजरिए से न देखा जाए। सभी पार्टियों का यह कर्तव्य है कि मिलकर इस कलक का घाने का प्रयत्न करें।

५ 'घर का छत्ता'

समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि कन्द्रीय जनता सरकार के कुछ प्रमुख नेता उत्तरप्रदेश त्रिहार मध्यप्रदेश व राजस्थान जैसे विज्ञान प्रदेशों का विभाजन करके कई नए छोटे राज्य बनाने का विचार कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन समाचारों में कितना तथ्य है। किन्तु यदि इस तरह का थोड़ा भी विचार किया जा रहा हो तो यह समुचित चिन्ता नहीं है। जिस समय १९५६ में राज्य पुनर्गठन कमिशन की रिपोर्टों प्रकाशित हुई थी और उनका अनुसार भारत सरकार व राष्ट्रसंघ काय समिति द्वारा निर्णय लिए जा रहे थे मैं कांग्रेस का एक महामंत्री था। उस वक्त हमें देश के विभिन्न प्रदेशों के नेताओं व कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति का ओष्ठानुभव मिला वह अत्यन्त कटु व गौघनीय था। मुझे कई सप्ताह तक अखिल भारत कांग्रेस कमेटी व जतर मतर रोड के दफ्तर में सुबह तीन बजे तक बैठकर सभी तरह के प्रतिनिधि मण्डलों

के सुझावों को शान्ति व धीरज से सुनना पड़ा था। फिर भी कार्य-कतारों को पूरा रातोपूरा दिखाना बड़ी ही कठिन समस्या साबित हुई। मैंने स्पष्टतया अनुभव किया कि भाषावार प्रान्त रचना के प्रश्न पर तब-तब नेता भी अपना भावार्थक व मानसिक सतुलन खो बैठे थे। फिर भी किसी तरह यह मामला तय हुआ। किन्तु बाद में भी इस सिलसिले को बढ़ा करना संभव न हुआ और सन् १९६९ में बम्बई के बड़े प्रदेश को तोड़कर महाराष्ट्र व गुजरात के दो नए राज्य सगठित करने पड़े। तब भी यह चक्र नहीं रुक सका और १९६७ में छोटे पंजाब के भी तीन हिस्से करने पर केन्द्रीय शासन को बाध्य होना पड़ा।

अब फिर इस कठिन व जटिल प्रश्न को उठाना भारत की एकता के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। यह मामला सिर्फ उत्तर के हिन्दी प्रदेशों के पुनर्गठन में समाप्त नहीं होगा। यह पूरा देश के अन्य सभी राज्यों में फैलेगी और उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। न गालूम देश में कितने और नए राज्य बनाने पड़ेंगे।

जनता पार्टी न मभीर संकल्प जाहिर किया है कि यह दस वर्ष में देश की गरीबी व बफारी दूर करेगी। यह उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको प्राप्त करने के लिए बड़े परिश्रम व सम्वसित शक्ति की आवश्यकता होगी। इसी बीच अगर राज्यों के पुनर्गठन का पेचीदा मसला पड़ा कर दिया गया तो सभी बुनियादी व ठोस कार्य पिछड़ जाएंगे और राष्ट्र की सगठित शक्ति पूरी तरह बिखर जाएगी।

यह कुछ हद तक सही है कि छोटे राज्यों में अधिक विकास की गति अधिक तेज हो सकती है। किन्तु इस कार्य को गतिशील बनाने का एक और भी तरीका है। उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्यों में क्षेत्रीय विकास मण्डल गठित किए जा सकते हैं। जो हो, इस प्रकार राज्यों को फिर सगठित करने का विचार कम से कम दूर साल तक छोड़ देना ही सब दृष्टि में हितकर होगा। यह एक 'बुरा का छत्ता' है। इस समय उसे छोड़ना देश की एकता को गहरी टेढ़ा पड़ाना होगा।

गाँव वालों से संबंध जोड़ें

महात्मा गांधी

[बुनियादी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से महात्मा गांधी ने श्रीमती शान्ताबहन नाइमबर से सन् १९४५ में विस्तृत चर्चा की थी और सुझाया था कि सेवाग्राम के गाँववालों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। यह चर्चा गत अंक में प्रारम्भ की गई थी। यह किन्तु उसकी दूसरी और समापन किरत है।]

गांधीजी :—क्या करोगी, प्रौढ शिक्षा में ही शुरू करोगी क्या ?

शान्ता बहन —हाँ। सेवाग्राम देहात के नौजवानों को हाथ में लेना है उनसे सम्बन्ध बढाना है, उनमें जागृति पैदा करनी है तो क्या कहें ? कैसे सम्बन्ध बढाऊँ ?

गांधीजी :—यह समझ लो मैं अस्पताल नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ मुझे उन नव युवकों से काम लेना है वगैरह पैसे में। वे मुझे मदद देंगे फिर भी मेरे मन में आता है कि वही मुझे वह धोखा तो नहीं, देंगे ? लेकिन नव युवकों पर शिद्दाग करना है और उनमें काम तो लेना ही है।

उनमें यादवीत के जगिए परिचय होगा। जब एवाध-से परिचय हो तब उनके घर में ही शुरू करो (घर के बारे में पूछो कि क्या वह परिवार आश्रयालयवत्ता है। उनकी आयदादके बारे में पूछना। तैल आदि जानवरों की वह ठीक में देखभाल करना है या नहीं। उन्हें वह सामान खुराक क्या देता है। तुम्हें उसे बताना है कि उनसे वह प्रेम से व्यवहार करे। लाठी में आर नहीं लगाए। उनपर वे बताएंगे कि इनके बिना बेल चलते नहीं, पर मेरी नजरमें उनका यह जवाब ठीक नहीं है। जानवरों पर जैसी मस्तिष्क हिन्दुस्तान में होती है वंगी वही नहीं होती। उसे घरके बारे में कहो कि यदि छोटे भाई बहन है तो उसे पैमाने आदि की मफाई देखना है।

सेवाग्राम में दो चार जगह बगीचे, मंदिर आदि होना चाहिए। वही पहली तालीम होगी। वहाँ उमंगे बातें करें और नहें कि अपने साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी भी लेते आएँ। वातचीत में ही उन्हें इतिहास भूगोल का ज्ञान देना है। एक बोर्ड तो रखोगी। इच्छा है अक्षर ज्ञान भी दो। इकट्ठा होनेवालों के नाम का परिचय कर लो और थोड़ा मजाक भी करो। इस तरह परिचय बढ़ाओ उन्हें इकट्ठा करो। उन्हें सहयोगकी बात सिगानो है। जा नहीं आते उन्हें बलाना है।

मान लो तुम्हारे हाथ सत्ता और जमीन आ गई। सत्ता का अधिकार पाली पटेल और पटवारी के हाथ में रहता है। यदि जमीन हमारे हाथ में है और हम सब जानकार हैं और फिर हमने बीज बोया, सहयोग से सरकार का कर दे दिया तो हमारा वस्तु बच गया और पाम भी हुआ। हम सहयोग में ही खेती सिखाएंगे। खेती हाथ में आ जाए तो पैसों का भी सुधार हो सनता है। इस सब में गे अपनी सुविधा के अनुसार समय कर करो।

मान्ता — यहाँ तो गोसायन्ती गाँव वालों की होगी फिर क्या मतलब ?

बाबू — यहाँ जो होने वाला है यह गह है कि मुँडे ही पहले हमारे पास आएँगे। यज्जा बड़ी चीज होती है, फिर इनके पास पैसा भी है। पैसे वालों को मुँडे ही मानो।

गाँव के कुएँ

जा मुँडे कुएँ हो उन्हें बन्द कर दें, इस काम में पैसा खर्च करेंगे क्योंकि ये बीमारी के घर हैं। इतने कुओं की, जलरस नहीं है। इससे बन्द करने में लोगों ने मनोविनोद के लिए पब्लिश स्वचेयर भी धन्येंगे। जनता के कुओं का खर्चा जनता को ही देना होगा। निजी कुओं मालिक सुधारे, नहीं तो मालिकी छोड़ दे जिससे जनता के रूप में उसे सुधारा जा सके। इस तरह सब कुएँ हमारे हाथ आ जाएँगे। देहातो के लिए देहात के पात्र खर्च हो जाएँ, विन्तु वे कैसे हों यह गोबने की बात है। यह काम ऐसा सादा और सरल हो कि भागे हिन्दुस्तान में हो सके।

सेवाग्राम का आदर्श सबके लिए और कम खर्च का हो। वहाँ की खात लाख देहातों के लिए एक नमूना बने। बिजली के बारे में मैं कहूँगा कि मुझे बाँधो मत। पहले यह कह दो कि सारे हिंदुस्तान में बिजली हो सकती है तब मुझे लगेगा कि इतनी पावर तो होनी ही चाहिए। ऐसे काम के लिए जनता से घन इकट्ठा करे। जनता की निधि रह उसमें आश्रम का भी हिस्सा रहे। आश्रम भी जनता के ही रूप से चल रहा है और गाँव के किनारे बसा है। हमें तो लोगों को सालीम देनी है। ■

भोजन :

शाना —गाँव में रहने जाए तो आश्रम से ही वह काम शाह हो ऐसा आपने कहा है। आश्रम का खाना और रहन सहन सार्विक है और गाँववाला से अलग है वे देहात में कैसे रहेंगे और जिनका खान पान सब कुछ अलग है उनसे (गाँववालों से) कैसे मिलेंगे ?

बापू —बड़े परिश्रम से ही सही—पानी तो उबाल कर पीना है। जो यह नहीं करते वे देहात में कैसे रहते हैं। पहले मैंने सोचा था कि देहात में रहूँगा मगर बैक्सीनेशन (चेचक का टीका) इत्यादि मुझे नहीं लेना था। डाक्टर ने इसीलिए मुझे अलग ही रहने को कहा था। बिलेन्ड डाईट के विषय में यह बात है कि थोड़ासा दूध तो लेना ही चाहिए। प्राणीज प्रोटीन थोड़ा-सा भी लेनेसे दूसरी प्रोटीन—अच्छी पचती है अतः एक थोड़ा प्रमाण दूध का रखें। १० तोला दूध और ९ तोला घी—मगर मक्का घी हो।

आगा देवी —बच्चाको हम एक तोला तेल देते हैं।

बापू —यह बस नहीं। घर में (उनको) कुछ मिलता ही नहीं इसलिए आज वह चलता है। मगर अपना माप हम उमपर से न निकालें। अपने शरीर को ईश्वर का घर अर्थात् जनता की धरोहर मानते हैं। जनता के लिए हम जिंदा रहना चाहते हैं तो शरीर को अच्छा रखना ही है। उनके सामने घी खाओ और कहो तुम्हारा इसके बिना चलता है कि तुमरा चलना संभव नहीं अतः तुम घी लो। वहाँ आश्रम में तबियत

बिगड़ती है उसका कारण यह है कि यहाँ लोग मानते हैं कि जितना मिलता है उतना खाना ही चाहिए, ऐसे में तो तबियत बिगड़ेगी ही।

मुशौला बहन — यहाँ मसाला गैरा न होने के कारण खाना स्वाद नहीं होता इसलिए प्रमाण नहीं रख सकते।

बापू — खाना स्वाद नहीं है इसलिए बहुत खाया जाता है; मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। देहात में तो जितना खाना है वह लोग खाते ही हैं। खाने में भी कला है। आधम जीवन में हमें यह शिक्षा देनी है। ज्यादा न खेना तथा झूठ न छोड़ना इत्यादि बातें सीखने सायक है।

शान्ता — खाने में दूध होना जरूरी है और माँ-बाप दूध के लिए पैसा दें ऐसा आपने कहा है। किन्तु बच्चों को दूध देने को उनके पास पैसे कहाँ हैं?

बापू — वह तो करवाना ही है उसमें प्रौढ-शिक्षा है। उन्हें जिम्मेदारी समझानी है। उनकी बचाने की शक्ति बढ़ानी है। उन्हें शिक्षुक नहीं बनाना है। आखिर में तो उनको खाना पीना देना ही है। उसका दो ढग है—एकरुसका है। वे ही चीज अपने ढग से हमें करनी है। यदि हम उन्हें नहीं कर पाते तो समझ लो कि वही कुछ बर्बाद है। मैं मानता हूँ वह बनना चाहिए। वहाँ तो उन्होंने सारी दुनिया की बात नहीं सीखी उन्होंने तो एक बड़े समाज का सोचा है। मैं एक सेवाग्राम को लेता हूँ इसके माने सारी दुनिया को लेता हूँ। उनका समग्र जीवन लेकर एक देहात में बिठना हो सकता है, हमें यह देखना है। एक बच्चा और सौ खाएँ यह तो नहीं हो सकता। हरेक बच्चा और खाएँ तो हो सकता है। मुझे मरीज के मरने की परवा नहीं मगर मरीज होने से रोके इतना काफी है। अच्छे समाज में पग बहुत कम रहते हैं—बच्चे को तो माँ-बाप पिलाने ही हैं किसीको नहीं लगता कि बच्चा उनके सिर पर बोझ है। अच्छे कुटुम्ब में बच्चे भी अपने सपने तक भार नहीं होते। बच्चा ३-४ वर्ष का हुआ और बचाने लगता है। यह तो हमारी सामीप है। बानेज घाने दखिो बाने हैं।

सेवाग्राम का आदमी हमारे यहाँ वाम करता है, हम उसके बच्चों को नहीं देखते। हमें उनका साथ अपने बर्तन में तथा उनके बच्चों और उनके साथ व्यवहार में मित्रता और रिश्तेदारी की भावना का निर्माण करना है। उनके बपड़े अलग उनका खाना अलग और वे भी अपने को अलग रखते हैं उसमें भी सुधार करना है। वे अपने को हमसे अलग समझते हैं।

प्रश्न — यदि खाने में दूध न मिले तो कौन-कौन सी चीज देनी होगी ?

बापू — जो मासाहारी हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि यदि और कुछ न मिले तो मास अण्डे खाओ। लेकिन शाकाहारी को बहूँगा कि शाक न मिले तो भूखे मर जाओ। क्योंकि शाकाहारी को 'वनस्पति शास्त्र' जानना चाहिए। देहात के गरीबों को 'अंसा कि रक्षिया' बना ठीक वैसा ही बनाना है।

प्रार्थना :

शान्ता — प्रार्थना किस तरह चलाएँ ?

बापू — आम प्रार्थना में राजकर्ता का इल्जाम नहीं लग सकता मगर यह आम प्रार्थना शायद कठिन होगी। रामचन्द्र तो है—पर राम के सामने शिकायत हो तो हम सहन कर लेंगे, वह तो ईश्वर का नाम है। मैं तो सबका अप बदल देता हूँ। हिन्दू माइयाँ लॉजी में ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं मैं उन चीजों को नहीं छोड़ सकता हूँ। जो चीज जीवन में भरी हैं वह कैसे बदल सकती हैं ?

सेवाग्राम के मकान :

शान्ता बहन — सेवाग्राम की आबादी बढ़ गई है, नए बसनेवाले सेवाग्राम में घरों की व्यवस्था कैसी हो ?

बापू — नया सेवाग्राम बसाना हो तो जगह हम देंगे पर लोग अपने घर आप बनाएँ। यदि घर बदलना पड़ा तो जो दूसरा उमर में आया वह उसमें लगा हुआ पैसा देकर घर ल लगा। जमीन पर उनका (गाँव-वालों का) हक नहीं होगा। लोग घर के लिए जमीन माँगेंगे, और

घर बसा लेंगे परन्तु साली रहने के लिए ही वे पैसे की जगह परिश्रम देकर घर लेना पसन्द नहीं करेंगे ।

हमारे हाथ में राजसत्ता नहीं है और न तो—आचार-विचार का जोर ही डाल सकता हूँ । जो सत्याग्रह मैं करना चाहता हूँ यदि पैसा हो तो सरतनत आप ही मुझे सहारा दे देगी । मगर यदि लोग मुझे समय लेंगे तो मेरा स्वप्न, स्वप्न नहीं रहेगा । अपने खेतों को उजाड़ दूंगा और लोगों को बखन के लिए जगह दे दूंगा, वे आज ही हमारे यहाँ आ जाएँ । लेकिन वे यह करने को तैयार नहीं हैं । वे चाहेंगे जमीन हमें मिल जाए, लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ । मकान का मालिक मैं रहूँ (स्टेट रहे) वे यह नहीं मानेंगे—वे तो जमीन मांगेंगे ।

शान्ता बहन —गाँव में दो तरह के आदमी हैं एक तो वे जिनके पास जमीन नहीं है और जमीन के मालिक न बगते हुए भी पैसा और धर्म दोनों लगाकर मकान बनाना चाहते हैं और दूसरे वे लोग हैं जिनके पास जमीन है पर पैसा नहीं, यदि कोई घर बनाए तो वे किश्तों द्वारा उसका खपया देकर घर ले लें । ऐसे लोगों की मदद कैसे की जा सकती है ?

बापू —इसके लिए एक हाउसिंग सोसायटी (गृह-निर्माण संघ) बनानी चाहिए । घर बनाने के लिए उन्हें पैसा उधार देना होगा, लेकिन उन्हें सस्ती दरदास्त करनी पड़ेगी । जब तक पूरा पैसा अदा नहीं किया जाएगा तब तक घर सोसायटी का रहेगा । हमें उधार वसूल करना होगा ।

शान्ता बहन —पुराने ढंगके घर चोरो के डर से बने थे । लोग पैसे गाड़कर रखते थे । यदि को-ऑपरेटिव बैंक या किसी जनता के संजाने में पैसा रखा जाए तो घर अच्छे बनने लगेंगे ।

बापू —यह पहला बंदम नहीं । वे लोग पैसे घर में दबाकर रखते हैं । सोना सरकार ने खींच लिया है, अपना दिवाला निकाला है । एक फीट में १४ डि दिए । सोना तो इस प्रकार चला गया । अब जो धन रखते हैं वह सब निकलवाना चाहिए । उसका प्रबन्ध करना चाहिए । फिर घर बनाएंगे । तो उन्हें चोर डाकू चोते का डर रहेगा ही नहीं । वे घर तो ऐसे का ऐसा ही रखेंगे । हमें तो पहल

उनका डर निकालना चाहिए। जब तक लाठी बंदूक नहीं रहती तब तक लोगो में निर्भयता का वायुमण्डल होना चाहिए। अगर वे वहाँ से आकर जंगल में रहने को तैयार हैं तो मुझे आश्चर्य के साथ ही बड़ा आनन्द भी होगा। आनिंग करना तो आसान है। वी सी मेहता ने यह काम किया है।

शान्ता बहन — मजदूर कहते हैं हमें जमीन चाहिए।

बापू — वे लोग तैयार हैं तो हमें वर्ज लोन निकालना होगा हम ऐसा करेंगे और यदि वे सहकार को आपरेशन का महत्व समझ गए हैं तो जिनके पास पैसे हैं वे पैसे दें जिससे को आपरेटिव बैंक बनाएँ। नाम मात्र को सूद देना है। पैसे का उपयोग होना आवश्यक है जिससे वे बिना हमारे की मदद के केवल अपनी बुद्धि से दहात खड़ा कर दें और पीछे हम भी पैसा डालें। जब उन्हें पता चलेगा कि पैसा सूद सहित वापस मिलगा तो पैसा डाने वाल बहुत मिल जाएंगे। सोसाइटी को रजिस्टर कराएंगे जिसमें जप्त न हो सक। हम उन्हें तकलीफ में नहीं डालना चाहते। यदि वे सहयोग न दें तो यह काम शुरू ही नहीं करना चाहिए— नहीं तो सरकार जैसी बात होगी उनकी मालिकी नहीं रहेगी।

शान्ता बहन — मुना है कि सरकार न अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए ५०० रुपये देने की बात कही है।

बापू — समझ गया मेरे स्याल में यह बुरी बात है, सरकार अपना ही काम करना चाहती है, रैथ्यत का नहीं। गन्ने के बारे में ऐसा ही हुआ है इतना बोया गया कि जिसकी हद नहीं।

शान्ता — लोग यह बात समझ गए हैं कि उसमें फायदा नहीं है मगर वे यह नहीं जानते कि दूसरा रास्ता क्या है।

बापू — रास्ता घताना हमारा काम है। मकान इत्यादि का बताया मगर वह दूसरा बंदम है, उससे पहन तो उनसे (गाँववालो से) मिलें जुलें और देखें कि उनका स्त्री बच्चे साथ है या नहीं। वे ही मद आलसी बैठे हैं अथवा काम करते हैं या नहीं, यह देखें— उनमें प्रवेश करना है। आर्थिक स्वार्थ को छोड़कर नैतिक स्वार्थ रहे तो इससे उनका मन

साफ हो जाएगा और हमें भी पता लग जाएगा कि वहाँ तब लोग हमारा साथ देने वाले हैं। सच्ची मेहनत ही पैसा है।

शांता —पैसा लौटाना है तो फिर स्वार्थ क्या ?

बापू —पैसे का लेन देन जहाँ भी रहता है वहाँ स्वार्थ की व आ हो जाती है। गुंडे कहेंगे कर तो से पीछे हम गुंडागर्दी तो कर सकते हैं। अतएव ऐसा करेंगे तो पीछे हमें कठिनाइयाँ आएँगी। दक्षिण अफ्रीका में भी गुंडबाजी चलती थी मगर वहाँ दोनों तरफ गुंडे थे।

स्त्री-शिक्षा

प्रश्न —स्त्रियों की शिक्षा किस तरह शुरू करें ?

बापू —घर घर जाकर स्त्रियों को सुख दुख देखो। उन्हें पहिचानो और उनके दुखों को दूर करो। उन्हें समय का उपयोग करना सिखाना है। वे कुछ नहीं जानतीं—झाड़ू कैसे लगाना, घर कैसे रखना आदि भी बतलाना और सिखाना होगा। स्त्रियाँ पुरुषोंकी शिक्षिका हैं। मेरी ऐसी तालीम तो मौखिक होगी। स्त्री अपने पति के लिए ही नहीं देहात के लिए भी है यह बात घर-घर में पड़ोसियोंमें और फिर देहात में समझाना है। बाद में समझ से काम लेना। आर्थिक मदद में कम पड़े। व स्त्रियाँ स्वार्थ की बातें करेंगी, उनसे बचना होगा। जो भूखी मरते हैं उन्हें कमाई कैसे करना यह सिखाना होगा।

पहले सार्वारिख व्याघ्रियाँ आएँगी और फिर सफाई सम्बन्धी तथा आर्थिक, नैतिक और राजकीय कठिनाइयाँ भी आएँगी। मेरी निगाह में राजकारण तो आखिर में आएगा। खाली आर्थिक मदद से दंठन से नहीं चलगा। डाक्टर का काम अलग है खाली दवाई देना है परन्तु शिक्षिका का काम अलग है। वह जिम्मेदारी है। उनका बजट देखना और बनाना तथा उसमें से कितना कमाया और कितना खर्च किया आदि जो देखकर उनके आय-व्यय का अनुमान निकालना है। उन्हें दूगरे धन्ये भी सिपान है। वे तो हमारे रिस्तेदार, सहकारी और साथी हैं। हमें समझना होगा कि उनके साथ कैसे चलें।

प्रौढ-शिक्षा :

शान्ता — नौजवानों से सम्बन्ध बढ़ाने और उनमें जागृति पैदा करने के लिए क्या हम कैसे बढ़ाएँ?

बापू — यह समय तो कि तुम अस्पताल नहीं हो, वरन् शिक्षा हो। शिक्षक आध्यात्मिक है। समय तो कि मुझे बिना पैसे के, नवयुवकों से काम लेना है। नवयुवको को यह विश्वास दिला देना है कि उनसे मदद लेने में मेरा स्वार्थ नहीं है इस प्रकार उनसे काम लेना है।

गृह-परिषद — घर के बारे में उससे पूछना और देखना कि परिवार का क्या हाल रखता है या नहीं। जमीन जायदाद के बारे में पूछना— बैल धरारा की देख भाल करता है अथवा नहीं क्या खाना खुराक देता है और कैसा व्यवहार करता है। हमें उसे यह बताना है कि उनके साथ (बैल आदि) प्रेम का व्यवहार करें साठी में आर न लगाएँ। वह यदि बैल चलाता नहीं ऐसा कहता है तो उसे समझाना होगा। नौजवानों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए मैं (बापू) तो खेती और जानवरों की देख भाल के विषय में कहना चाहूँगा।

अंग्रेजों के जानवरों की देख भाल अच्छी होती है। जानवरों पर अत्याचार न करने के लिए यहाँ भी कानून (कौन्सिलेटी टू एनी मल्ट्स एक्ट) है लेकिन नाम मात्र के लिए। जानवरों पर जैसी सस्तिरियाँ हिन्दुस्तानमें होती हैं वैसी कहीं भी नहीं होती। गधा भी बहुत उपयोगी जानवर है काम बहुत देता है और खाता थोड़ा है परन्तु उसका जीवन दुःख का जीवन है। नौजवानों से इस प्रकार बातचीत के द्वारा सम्बन्ध बढ़ाकर उनके कुटुम्बों के साथ मेल बढ़ाना चाहिए। यदि उसकी (नौजवान भाई को) छोटी बहन हो तो उससे कहो कि उसे पाठशाला के लिए दे दें। उससे घर के बारे में पूछो कि वह पैखाना घर आदिकी देखभाल करता है और सफाई देखता है अथवा नहीं। यह देखो और फिर उससे अपने अड़ोसी-पड़ोसियों को भी साथ लाने को कहो। सेवा

धाम में बगीचे आदि जैसी दो-चार जगह होनी चाहिए। वही पहली तालीम होगी। उनके साथ बातचीत करें और बातचीत के द्वारा ही इतिहास भगोल का ज्ञान दें। एक नाला तस्ता रख दें। अधर ज्ञान की इच्छा है तो दे दें। इकट्ठा करके उन्हें सहयोग की बात सिखाना है। जो नहीं आते उन्हें बुलाना होगा। मानो कि हमारे हाथ में सत्ता आ गई—जमीन हमारे हाथ आ गई। सत्ता का अधिकार खाली पटेल और बलाटी के हाथ में है, व खाली दो ही हैं। मानो कि वे हमें मान लेंगे। जमीन हमारे हाथ में है, हम जानकार हैं। हम यदि सरकार से बीज बोएँ तो सरकार को कर भी दे दें और थोड़े समय में अधिक काम भी कर लें। हम खेती सिखाएँ तो सहयोग हो खेती एक साथ हो और सहयोग से हो। खेती हाथ में—आ जाने पर हम देखेंगे कि वहाँ की भी हम सुधार सकते हैं। मैं तो बदलता घना जाता हूँ इसमें मैं तुम जितना ल सकोगी सेना, तुम्हारे लिए यह ब्रह्म वाक्य नहीं है। मेरे लिए यह ब्रह्म वाक्य है। तुम सुविधा के अनुसार समझकर करो।

1. स्वाश्रयी शिक्षा

नई तालीम का अर्थ है उद्योग की मार्फत तालीम देना। यह मूल उद्योग भास-पाम के वातावरण उपज इत्यादि को देखकर चुनना होगा। उदाहरणार्थ जहाँ कपास नहीं उगती वहाँ बाहर से कपास लाकर खादी को तालीम का अरिथा बनाना ठीक न होगा। अगर खादी का उद्योग लेकर नई तालीम स्वाश्रयी सिद्ध की जा सके तो वही बीज दूसरे उद्योगों के भी लागू की जा सकती है। तालीम स्वाश्रयी बनाने का अर्थ यह है कि जैसे आज के सरकारी स्कूलों में लड़के अपने घर से खाना खाते हैं, कपड़ पहनते हैं उसी तरह नई तालीम के स्कूलों में भी लड़कों के खाने पहनने का भार माना पिता पर रहेगा। आज बल के स्कूलों में किताबों और फीस इत्यादि पर जो खर्च होता है वह बच जाएगा शिक्षक अगर आवश्यक वातावरण पैदा नहीं कर सकता तो नई तालीम स्वाश्रयी नहीं हो सकती। अगर वह वातावरण बनाने में और लड़कों की बुद्धि को ओजस्वी बनाने में सफल होता है तो शुरू से

लेकर बाहर तक की नई तालीम में सारा खर्च लड़कों के बनाए हुए कपड़े की कीमत के रूपों में से निकल आएगा।

नई तालीम में किताबों को तो स्थान ही नहीं। रुई, धुनकी, तकली इत्यादि सामान पर शुरू में थोड़ा खर्च करना पड़ेगा उसके बाद तो जो खर्च निकालना होगा वह केवल शिक्षक की तनखाह और आवश्यक स्टेशनरी तथा कोई चपरासी इत्यादि रखना पड़े तो उसका खर्च इतना ही होगा।

मानो कि एक स्कूल में ३० लड़के हैं वे खेत से कपास लाने से लेकर मूत निकालने और कपड़ा बनाने तक की सब क्रियाएँ अपने हाथों से करेंगे। हरेक क्रिया की माफ़त शिक्षक उन्हें ज्ञान देगा जिससे कि उनकी बुद्धि दिन प्रति दिन अधिक ओजस्वी होती जाएगी। परिणाम में वे लड़के खादी की क्रियाओं से नित्य नई मोध किया करेंगे जिससे कि खादी का उद्योग अधिक उत्पादक और मूल्यवान बनता जाएगा।

लड़कों का बनाया हुआ कपड़ा उनके माता पिता मुँह माँगे दाम पर ले जाएँगे। शिक्षक का यह काम होगा कि वह लड़कों के द्वारा उनके माता पिता में जागृनि पैदा करे जिससे कि वे विदेश और मिल के कपड़ों को छुएँ भी नहीं। वस्त्र-स्वावलम्बन और खादी का वातावरण पैदा हो। हमें अपना वातावरण पैदा करना ही होगा। आज जहाँ खादी पहुँची है उसके लिए भी हमें वातावरण पैदा ही करना पड़ा था। परिणाम में आज खादी को कोई उखाड़ फेंक नहीं सकता। वही चीज नई तालीम के बारे में भी कही जा सकती है।

लड़के, हमारे स्कूलों से निकलने के बाद कमाई करने के लायक होंगे हम उन्हें काम देनेका वचन नहीं देते। अगर सरकारी स्कूलों में बड़ा खर्च करके तालीम पाने वालों को भी सरकार नौकरी देनेका वचन देती। मगर हमारे लड़के सरकारी स्कूलों से निकले हुए लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजस्वी होंगे, और आमानी से अपने लिए धंधा ढूँढ़ लेंगे।

याद रखना है कि सरकारी मदद के लिए वातावरण पैदा करना पड़ा था। तब तो सत्ता होने हुए भी कुछ कष्ट हुआ था। हमें जो वातावरण

पंदा करना है वह पुनर्विचार है— जो मिटाया गया है उसको नए सिरे से और नए तरीके से उठाना है और हम उसको स्वराज्य पाने का शान्तिमय तरीका समझने हैं। इस तरह से करना हमें आसान होना चाहिए क्योंकि हमने ग्रामों में सही दृष्टि से तथा सच्चा प्रवेश ही नहीं किया अतएव यह आसान नहीं लगता है। अब नई तालीम चमत्कार ही है और उसमें यह शक्ति नहीं है तो और क्या है ?

बचपन से लड़का-लड़की हमारे हाथों में आए और सात वर्ष तक मानी उससे भी अधिक साल तक हमारी मार्फत शिक्षा पाए और फिर भी यदि उसमें स्वावलम्बन शक्ति न आए तो समझना चाहिए कि हम उसका अर्थ पूरा पूरा ग्रहण नहीं कर पाए। जो आधुनिक शिक्षा हमें दी जाती है वास्तव में उसी के कारण हमारे मन में दुविधा होती है कि शिक्षण स्वावलम्बी हो ही नहीं सकता। मेरा बड़ा विश्वास है कि यदि नई तालीम स्वावलम्बी न हो तो शिक्षक वर्ग उसे नहीं समझता। मेरे मजदीर नई तालीम के दूसरे लक्षणों में स्वावलम्बिता उसका एक बड़ा अंग या लक्षण है। अगर यह बात लड़के लड़कियों के लिए सही है तो प्रेरणा शिक्षण में तो स्वावलम्बिता होनी ही चाहिए। ऐसा मानना कि प्रौढ़ों को शिक्षण की बात ही समझाना मुश्किल है तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि यह पुराना भ्रम है। हमारी नई तालीम प्रौढ़ तालीम का तीन चार लक्षण सिखाना भी नहीं है। प्रौढ़ तालीम का अर्थ है कि प्रौढ़ों को जलकी भाषा की मार्फत हम उनको शुद्ध और सामाजिक जीवनका सब शिक्षण दें। अगर यह आसानी से स्वावलम्बी न बने तो मेरी दृष्टि में बड़ा दोष है। यह भूलना नहीं चाहिए कि नए शिक्षण में सम्पूर्ण सहयोग आरम्भ से ही अमल में आना चाहिए। सहयोग का पूरा अर्थ जो जानता है उसके मन में स्वावलम्बिता का प्रश्न उठ नहीं सकता।

1

वस्त्र स्वावलम्बन :

गुड़ियाँ देकर खादी मिलने की सुविधा करनी होगी। थोड़े सालों में खादी के अर्थशास्त्र को समझाना होगा— उद्योग तुम्हारा दाम है। स्वावलम्बन करते हारो तो हारो, करते रहो।

नायकम् ने कहा इन लडकों की मार्फत आसानी से हम खादी बना लेंगे। वह बहुत सस्ती होगी। उसमें सूबीदार ब्ला रहती है, कप्ट नहीं होता। उसके साथ जब प्रौढ़ शिक्षण आता है तो थोड़े सालों में सारे का सारा प्रश्न हल हो जाएगा। कोई खर्च नहीं। सो पहले तो हम उनका अयंगम्य हजम कर लें। इसमें हारने की कोई चीज नहीं है।

बच्चों की शिक्षा :

बापू - हमारा प्रयत्न तो यही होगा कि जितने सड़के हैं सब को हम खींच लें। जो नहीं आते हैं तो समझना चाहिए कि हमारी कोई कमी है। उन्हें या उनके बाप को कोई सालच होनी चाहिए कि हमारे लडके हैं उनका शरीर तगड़ा हो जाएगा। सम्यक् सीखेंगे। मैं नहीं मानता कि बच्चे तोड़ना फोड़ना सीखेंगे। मैंने बहुत लडकों को सिखाया है परन्तु किसी को तूफान करने नहीं दिया। मैं ऐसी तालीम दूंगा जिसमें विध्वंसक नहीं पर त्रियात्मक त्रिया हो।

इसमें बला होती है। बच्चे जन्म से अच्छे या बुरे नहीं होते। कुछ अलग तो रहता है मगर उसे अच्छा बनाना है। इससे बच्चा पैट में से ही तालीम पाता है। बच्चे के हाथ पैर भी चलते-और हिलते समय कुछ न कुछ करते हैं। वह नहीं जानता कि वह बच्चा क्या करता है लेकिन उसकी हालचाल त्रियात्मक होती है विध्वंसक नहीं। इसी पर प्रौढ़ शिक्षण आधारित है अथवा यही उसका आधार है। प्रौढ़ शिक्षण बाद में आता है। प्रौढ़ा के कारण बच्चा के सस्वार पड़ते हैं। बच्चे ठीक तालीम पाते हैं तो गुरु से ही रचनात्मक कार्य करते हैं।

२ या २॥ साल के लडके लडकियाँ गुरु से हमारे हाथ में आ जाएंगे। उनके हाथ पाँव हमारे बताएँ जैसे रास्ते इस्तेमाल करेंगे तो वे कहीं तक जाएंगे मैं तो बाँध नहीं सकता। मार से नहीं प्रेम से बढ़ाना है।

शिक्षा :

पहले रंगों की पहचान होगी। अक्षर ज्ञान चित्र से शुरू करें १, २ (गिन्ती) 'अ' 'आ' आदि वर्ण चित्ररूप से सीखें। अक्षर तो चित्र ही होते हैं। तीनों ओर बाद में आएंगे (लिखना पढ़ना इत्यादि)

मगर उस बताना नहीं होगा। एक के चित्र पहले आए तो फिर सब अक्षरचित्रमय हो जाएंगे। जेल में मैंने एक प्राइमरी रीडर लिखा था। आज की तरह में तीन चार बभी नहीं सिखाऊंगा। पहले तो पढ़ना ही हाथ में आएगा। लिखना चित्र से शुद्ध होगा—चित्र कोई तोतेका बनाएगा कोई सूतका बनाएगा। इसके साथ उसकी (बच्चेकी) बुद्धि भी जाती है और पैर भी चलते हैं। उसके लिए सब खेल है। वाम और खेल दो विभाग नहीं है। वह आगे जाता है तो इसी तरह उसकी जिन्दगी खेल या काम बन जाती है। मेरे पास चन्द घटा खेल और चन्द घटा काम में दो विभाग नहीं। मैं बरसों से ऐसा चला हूँ। मुझे बभी रयाल नहीं आता कि अब खलवा समय हुआ। मेरे लिए तो लिखना भी खेल है। बारह वर्ष से ऐसा चलता आ रहा है। आज मैं तो कोशिश करता हूँ कि दोनो लिपियाँ एक साथ सीख लूँगा। यह मेरे लिए कठिन सगे मगर बच्चे को बुरा से सीखना खेल होगा और आगे चला जाएगा तो सब खेल ही खेल होगा। पर लिए सच्ची नई ताजीम यही है कि सबके खेलते खेलते सीखें। पर भाषा सीखने में जितना समय दिया उसका एक हिस्सा समय में दूसरी दस्त लिपियाँ सीख सकत थे।

मॅडम मीटेसरी ने एक भाषा में मेरे लिए कहा था कि मैं जानती हूँ (जितना) उससे अधिक यह (गाधी) जानता है। वह बात सच्ची है।

ग्राम व्यवस्था .

सार्वजनिक कोष (पब्लिक फण्ड)

प्रश्न —सार्वजनिक कोष हैसियत के अनुसार या साधारण चन्दे के तौर पर जमा करना चाहिए ?

बापू —यह (सार्वजनिक कोष के लिए धन जमा करना) अडल्ट वनफ्रेज का सा होगा। उससे भी आगे जाएँ तो कम से कम चन्दा (मिनिमम कन्वेन्शन) रखें। लडके लडकियों को एक पैसा और बडोको एक आना दना है छीर दें। ज्यादा देनेवाले हो तो दें। हमारी शक्ति पैसे पर नहीं। एक एक पैसे की भी बहुत है। करोडो को मिला कर जो शक्ति होती है उसे कोई मार नहीं सकता। वहाँ तो सरकार ने

मकान जप्त कर लिए थे, मैंने कहा जंगल में बैठे रहेंगे। साना लोग देंगे तो ठीक है नहीं तो भूखे मर जाएंगे। नतीजा यह हुआ कि बड़ा कंप बन गया, उनमें सब बड़े आए पर बड़े डरते भी थे। बड़ों के साथ लड़ना भी होगा उन्हें मैंने कहा है कि जिन्दा रहना है तो गरीबों के ट्रस्टी बनकर रहें। उनके पास से सब धन छीन लूं तो जहर बढेगा। उनसे इसी लिए कहता हूँ ट्रस्टी बनो, कमीशन ज्यादा देता हूँ चाहे चौथाई ले लें। उसमें अभिमान है।

माता —बोप (फण्ड) के साथ प्रबन्ध भी होगा ?

बापू — हाँ। उसी में तुम्हारी कला आएगी। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों की तरह प्रबन्ध हो। वहाँ हमारा द्वारपाल ही तीन चौथाई खा जाता है। तुम्हारा प्रबन्ध इतना सादा होगा कि उसमें चोरी का मौका कम मिलेगा।



“शहर अपनी हिकाजत आप कर सकते हैं। हमें तो अपना ध्यान गाँवों की ओर लगाना चाहिए।” हमें उन्हें उनकी सकुचित दृष्टि, उनके पूर्वग्रहों और बहमों आदि से मुक्त करना है, और इसे करने के लिये हमका और कोई तरका नहीं कि हम उनके साथ उनके बीच में रहें, उनके सुख-दुख में हिस्सा लें और उनमें गिला का तथा उपयोगी ज्ञान का प्रचार करें।

—मो० क० गांधी

1

शिक्षकों को स्वतंत्रता चाहिए

विनोबा

[जबिल भारत नई तालीम समिति की ओरसे सेशनग्राम में तारीख १८-१९ और २० सितम्बर को 'शिक्षकों का प्रशिक्षण' विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता श्री ग्रामन्तरायण ने की थी। विचार गोष्ठी में शामिल हुए शिक्षकगण तारीख २० सितम्बर को ऋषि विनोबा से मिलने पटना आश्रम गए थे। उस अवसर पर पूज्य विनोबाजी ने जो विचार व्यक्त किए वे यहाँ दिए जा रहे हैं।]

विनोबाजी —अकराचार्य ने एक सुन्दर वाक्य लिखा है— 'गुरोस्तु मौन व्याख्यानम् । शिष्यास्तु छिन्न सञ्जया'—गुरु ते मौन व्याख्यान दिया और शिष्य छिन्न सञ्जय हो गए। गुरु मौन व्याख्यान नहीं बेंता और बोलता तो शिष्यो को शका उत्पन्न होती। लेकिन मौन व्याख्यान दिया तो सब शकएँ समाप्त हो गईं।

प्रश्न —संपूर्ण क्रांति के विषय में आप क्या सोचते हैं? शिक्षा का उसमें क्या सहयोग हो सकता है? शिक्षक उसमें क्या करें?

विनोबाजी —एक बार डा. जाकिर हुसैन से बाबा की बातें हो रही थी। बाबा न कहा आज हालत यह है कि आज जो तालीम चल रही है वह अगर हम लोगों को नहीं देते हैं तो लोग बेवकूफ हो जाते हैं और अगर वह तालीम देते हैं तो वे बेकार बन जाते हैं। तब उन्होंने कहा, आज की तालीम ऐसी है कि उससे लोग बेकार और बेवकूफ, दोनों हो जाते हैं। तालीम का यह वर्णन उन्होंने किया था।

तालीम के बारे में कहने का कुछ भी बाकी नहीं है। बहुत कुछ कहा है और वह सब प्रकाशित हुआ है, नितानें भी बनी है। जो कुछ बचा है वह करने का है। मेरा ख्याल है, आप सब करनेवाले लोग होंगे

या सुननेवाले हैं? सुनने की ऐसी मजा है कि एक कान से सुन सकते हैं, दूसरे कान से छोड़ सकते हैं। इस वास्ते मैं आशा करता हूँ कि आप सुननेवाले नहीं, करनेवाले भी होंगे।

आज कहा जाता है कि नई तालीम के लिए आज की सरकार अनुकूल है। भगवान जाने कौन अनुकूल है और कौन प्रतिकूल है। मुख्य बात यह है कि आपको सरकार की तरफ देखना नहीं चाहिए। सरकार आएगी और जाएगी। आचार्य रहेंगे। इस वास्ते आपको पॉसिटिविज्म की तरफ, सरकार की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। उसकी मदद की जरूरत नहीं है। उसकी मदद माँगनी भी नहीं चाहिए। शिक्षकों को स्वतंत्रता चाहिए। जो स्वतंत्र नहीं हैं वे शिक्षक ही नहीं हैं। वे तो गुलाम माने जाएंगे।

नवर एक में प्रतिष्ठा है माता की। नवर दो में प्रतिष्ठा है पिता की। और नवर तीन में आचार्य की। उपनिषद् ने कहा है—मातृ-देवो भव। पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। इसे आपने भी सुना होगा।

उसमें यह भी आया है कि आचार्य शिष्यों से कहते हैं कि हमारी जो अच्छी चीजें हैं वे लेनी चाहिए और जो अच्छी चीजें नहीं हैं वे नहीं लेनी चाहिए। ऐसा स्वातंत्र्य शिष्यों को, विद्यार्थियों को उपनिषद् ने दिया है। वेद में भी वर्णन है गातुविद्। शिक्षक को गातुविद् कहा है। गातु यानी मार्ग। मार्ग दिखानेवाला। शिक्षाज्ञीचेष्ट गातुविद्। है शिक्षक, तू उत्तम शक्तिशाली, तू मार्गदर्शक है। तू मार्ग दिखा। तो शिक्षक मार्ग दिखाएँ और लोग उस पर चले।

आज क्या होता है? आज सरकार शिक्षा देती है। सरकार सत्पाएँ बनाती है मार्ग दिखाती है। बिल्कुल पराधीन हो गए हैं शिक्षक। परिणाम यह हुआ है कि हम उत्तरोत्तर बेकार, गुलाम होते जा रहे हैं।

सम्पूर्ण क्रान्ति के बारे में सवाल पूछा है। सम्पूर्ण क्रान्ति का विचार मुझे अच्छा लगता है। सपर्यं क्रान्ति में जातिभेद मिटाने की बात है। जातिभेद मिट सक्ता है, उसकी एक शक्ति है। माताहार

बन्द होना चाहिए। मान लीजिए, कोई जैन है, जो जातिभेद मिटाना चाहता है और अपनी लडकी एक हरिजनको या गिरिजन को देना चाहता है। यह हरिजन या गिरिजन मांसाहारी हो तो जैन अपनी लडकी उसके घर नहीं देगा। इस वास्ते यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जातिभेद मिटाना हो तो मांसाहार बंद होना चाहिए। अन्यथा संपूर्ण शान्ति या समग्र क्रांति केवल बोलने की बात होगी और उससे कुछ होगा नहीं। मैं उम विचारको पसन्द करता हूँ।

प्रश्न — प्रजातंत्र में जनता और सरकार में तो कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रशासन से मदद न लेना किस हद तक सही है ?

विनोबाजी — प्रजातंत्र में, जनता और सरकार में बहुत अंतर है। होता क्या है ? एक एक पार्टी सामने आती है और कहती है कि हमें वोट दीजिए तो हम आपका उद्धार करेंगे। आजकी यह सरकार दस साल में गरीबी मिटा देगी, ऐसा कहा गया है। तो, आज जो गरीब है, उसे कहो कि संतुष्ट रहो, दस साल में तुम्हारी गरीबी मिटेगी। वह कहेंगा, मैं तो आज ही गरीब हूँ। यह सरकार यह करेगी, वह सरकार वह करेगी। गीता क्या कहती है ? उद्धरेत् आत्मनात्मानम् ॥ अपना उद्धार हमें खुद करना चाहिए। लेकिन आज तो जो आता है, वह कहता है, हमें वोट दो, हमें वोट दो। कोई जनता से यह नहीं कहता कि तुम्हारे उद्धार तुम्हारे हाथ में है। इसलिए गाँव-गाँव को मजबूत बनाना चाहिए। गाँव में सब लोग मिलजुल कर काम करें। गाँव व्यसनमुक्त, अदालतमुक्त हो। गाँव में कोई बेकार न हो। ये सब बातें गाँव में हो। इसलिए गाँव को समझाना चाहिए, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे हाथ में है।

प्रश्न — आज की शिक्षा में अध्यात्म को कैसे प्रतिष्ठित किया जा सकता है ?

विनोबाजी — एक सुन्दर उपाय है। लेकिन कोई करता नहीं, सब सुनते हैं। होली के दिन सब कचरा वगैरह जला देते हैं। वैसे तय करो कि हम सारे विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं। शिक्षक सारे बेकार बन रहे हैं, ऐसा होगा तो सोचने के लिए बाबा के पास आएंगे कि बाबा,

क्या करना है जर, सब स्कूल-कालेज खाली हो गए हैं। यह उपाय है। बाबा तो कहेंगे, छोटे दो स्कूल-कालेज। लेकिन आज बाबा को कौन पूछेगा? आज तो पूछेंगे शिक्षामंत्री को।

सब व्यवस्थाएँ गलत हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक दिन जाहिर कर के सब विद्यार्थी स्कूल छोड़ दें। तो फिर शिक्षा विभाग समाप्त होगा और शिक्षा में सुधार होगा। क्या यह हिम्मत है आप लोगों की? हिम्मत मर्दानों तो मदते खुदा।

प्रश्न —लेकिन क्या यह अनिवार्य है?

विनोबाजी —यह शिक्षा पद्धति सुधारने का एक उपाय है। अनिवार्य नहीं है। मुख्य बात यह है कि शिक्षा स्वतंत्र चाहिए। वृंसा आप रखिए शक्तिपूर्वक युक्तिपूर्वक सरकार के सामने कि शिक्षा स्वतंत्र हो, सरकार पर अवलंबित न हो।

प्रश्न —शिक्षा के द्वारा जागतिक शान्ति एक भारतीयके नाते इसे कैसे समझे?

विनोबाजी —भारत में पन्द्रह विकसित भाषाएँ हैं २०० अविकसित भाषाएँ हैं। जब मैं मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में घूमता था तब एक मभा में लोगों से पूछा, क्या गांधीजी का नाम आप लोगों ने सुना है? तो उन लोगों ने पूछा कौन गांधीजी? गांधीजी कौन उनको पता ही नहीं था। फिर पूछा जीजम आईस्ट का नाम सुना है? तो उन्होंने गुरन्त कहा सुना है। क्या कारण हुआ जीजस आईस्ट को जानने का? कारण उनको किताब मिली है। दो-सौ अविकसित भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद हो गया है। इतना पराक्रम उन लोगों ने किया। हम सारे शिक्षकों ने मिलकर कौन-सा पराक्रम किया है? सारे आदिवासियों के लिए आपने क्या दिया है? यह सारी सोचने की बात है। शिक्षकों का गाँव-गाँव में जाना चाहिए और गाँव गाँव को आजाद करना चाहिए। वहाँ गाँव की सभा बने, गाँव में कोई बेकार न रहे, गाँव की शिक्षा गाँव के हाथ में हो, गाँव व्यसनमुक्त हो, अदालतमुक्त हो। यह काम शिक्षक करें।

मैंने कहा था गाँव गाँव से जो टैक्स वसूल करते हैं, वह अनाज में वसूल हो। आज क्या होता है? अनाज गाँववालों के हाथ में पैसा व्यापारियों के हाथ में। व्यापारी सस्ता खरीदते हैं महंगा बेचते हैं। व्यापारियोंका घधा चलता है और सरकार को पैसा मिलता है। अगर सरकार गाँववालों से टैक्स के रूप में अनाज ले तो रेल्वे आदि बमंचारियों को तनखा का एक भाग अनाज में दे सकेंगी। सरकार चाहती है कि हम अनाज रखें तो चूहे खा जाएँगे। मैं कहा बिहिन्याँ रखो। टैक्स अनाज में लाने की बात अव्यवहार्य नहीं है। चीन में यह बात चल रही है। यहाँ आप करवाइए। बड़ी चीज है। इतना भी आप करेंगे तो बड़ी बात होगी। गाँव आजाद होंगे। गाँव के लिए सावा ने सदा दिया है यों मे— 'मक्खन खाओ पपड़ा बनाओ।'

×

बुद्ध के साथ बिप्लव रहने से ही गाँवाएँ सजीव बनी रह सकती हैं। बुद्ध हैं प्राचीन परम्परा और गाँवाएँ हैं नव सत्कार। हम नव सत्कार ग्रहण कर लंछित प्राचीन परम्परा से जुड़ रहे हैं। परिणामस्वरूप एक शास्ता भा बन रहा है और प्राचीन परम्परा भी खटित नहीं होगी।

—विनोबा

देश की नई शिक्षा पद्धति

मोरारजी देसाई

मैं देश की शिक्षा पद्धति को लेकर कुछ अनिवार्य परिवर्तन करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैंने प्रधान मंत्री का उत्तरदायित्व लेने के बाद 'राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्' और 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के प्रमुख अधिकारियों के साथ सलाह-मशविरा किया है। हम अपनी शिक्षा पद्धति में कुछ बुनियादी फेरफार करने पड़ेंगे और सौ भी एकाध वर्ष में ही। आज की हमारी शिक्षा-व्यवस्था का देश को गरीब लागो और गौबो में रहने वालो के साथ मेल नहीं बैठता इसे सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए कोई न कोई राष्ट्र-प्राप्ति-ध्यय सामन रखकर हमें अपनी व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा। जो पद्धति चली आ रही है, यदि उसमें बुनियादी परिवर्तन व प्रयत्नोमें ज्यादा देर होती है तो देश का बहुत नुकसान होगा। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि हमारी गिन्या-व्यवस्थाका परिणाम समाज की विपमताओं को बढ़ाना न बने। आज की पद्धति उन विद्यार्थियोंको ध्यान में रखकर रूढ़ हुई है जिन्हें अनेक सुविधाएँ प्राप्त हैं। आवश्यक है कि राष्ट्र के विकास के लिए गिन्या गुरु से अन्त तक सभी तबका व लोगो के लिए किसी न किसी उत्पादक प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो शिक्षा पद्धति में परिवर्तन भी नहीं हो सकता—गांधीजी ने इस विषय पर मौलिक चिंतन किया और दुनिया के सामन बुनियादी तानीमकी रूपरेखा रखी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, साबरमती, आश्रम, गुजरात विद्यापीठ सेवाग्राम आदि स्थानोमें इसके सफल प्रयोग किए और बाद में सारे देश के सामने इसे रखा। १९६५ में मैंने भी इस पद्धति पर जोर दिया था और शिक्षाविदोने उसे स्वीकार भी किया था। किन्तु सरकारी अथवा गैरसरकारी सस्थाओं ने उस पर जो अमल किया उस बहुत ढीला कहा जाएगा हमने संविधानकी

दृष्टिमें प्राथमिक शिक्षाको जिस तरह सब जगह फैलाना था उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। प्राथमिक शिक्षा की समस्या को किस तरह से हल किया जाए इसपर प्रजातंत्र की संप्रसत्ता का आधार है। हमन सात वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के सांख्यिक कार्यक्रम को सफल बनाने के बदल नहीं पद्धति के नाम से दस वर्ष की शिक्षा का विकास करने की कोशिश की ओर नतीजा यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा के पोषक के रूप में जिस तरह ग्रहण नहीं किया जा सकता उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा के पोषक रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसे अधिकांश विद्यार्थी जिन्हें आगे नहीं पढ़ना है उनका हित नहीं सधने पाता। प्राथमिक शिक्षा का काम देशवासियोंको अपनी-अपनी मातृभाषा में व्यापक रूप में नागरिक शिक्षण देना है। सात वर्षमें एवदम अनिवार्य, प्राथमिक शिक्षा सात वर्ष के पूर्व की जा सकती है। यह सबसे पहला काम है। इस दृष्टि से सार देश के पाठ्यक्रम को एक जैसा बनाना जरूरी नहीं है। प्राथमिक शिक्षा में मिश्रित स्कूल का जो भेद रखा गया है उसे भी हटा देना चाहिए और एक सात वर्ष की समूची शिक्षा को स्वरूप पर विचार किया जाना चाहिए जिसे हम सच्चे रूप में प्राथमिक कह सकें। देश के कुछ हिस्सों में आठ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा है जब कि कुछ जगह सात वर्ष की है। यह असंगति भी दूर की जानी चाहिए। यह काम करने के लिए कन्द्रीय सरकार का मुहताज रहना आवश्यक नहीं है। राज्य सरकारों और सांख्यिक संस्थाएँ अपने अपने स्थानीय साधनों की दृष्टि से इस प्रकार की पद्धति अपना सकती हैं। प्राथमिक शिक्षा के दौरान छुट्टियों की जो आज की प्रथा है उसे छोड़कर उराका मल जीवन को साथ बँटाया जाना चाहिए। जैसे छुट्टियाँ ऐसे समय पर ही दी जाएँ जब खेती का काम जोड़े पर चल रहा हो। उस समय विद्यार्थी अपने गाँवों में जाकर उत्पादक श्रम में हिस्सा बँटा सकते हैं और ऐसी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं जो शाला में दे सकना सहज ही सम्भव नहीं होता। यदि छुट्टियों की पद्धति में परिवर्तन हो जाए तो विद्यार्थी अपनी जीवन व्यवस्था से जुड़ रह सकते हैं।

— निरक्षरता हमारी दूमरी गम्भीर समस्या है। हमारे देश में चौदह से पैंतीस वर्ष तक की अवस्था के कोई तेईस करोड़ निरक्षर हैं। यो स्वीकार किया जाना चाहिए कि इन निरक्षर लोगों में पढ़े लिखे लोगों से समझ कम नहीं है, ज्यादा ही है। फिर भी निरक्षरता को दूर करना है और इसके लिए अधिक से अधिक दस वर्ष का समय लगना चाहिए। देश में लगभग साठे तीन लाख शिक्षक हैं और विद्यार्थियों की संख्या दस करोड़ है। सेना पर होने वाले खर्च के बाद शिक्षा पर होने वाले खर्च का मन्तर आता है। प्रतिवर्ष इस पर पच्चीस सौ करोड़ रुपये के लगभग खर्च किया जाता है— यह छोटा-मोटा खर्च नहीं है। यदि इतनी जवदस्त राष्ट्रीय सम्पत्तिका खर्च करनेवाला पढ़ा-लिखा तबका इसके बदले में कुछ भी देने लायक न बने तो राज्य या समाज की ओर से इस खर्च का समर्थन किस प्रकार किया जा सकता है ?

शिक्षा पद्धति को सामान्य लोगों के जीवन के साथ जोड़नेके लिए आवश्यक है कि उन्हें मूलमूल और मीघे-मादे जीवनशिक्षा देनी चाहिए। पूठे समृद्धि की लालसा पढ़े लिखे वर्ग को सामान्य जनता से अलग कर देनी है। इसलिए शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए आवश्यक चीजों का उत्पादन करने के योग्य बने। इसमें जीविका की अलगसे चिन्ता करना आवश्यक नहीं रहेगा और उत्पादन में वृद्धि के माय-माय सामाजिक रुमता भी बढ़ेगी।

जीवन व्यवस्था के साथ शिक्षा का मेल तभी बैठ सकता है जब हम उसे विकेंद्रित करें। सरकार उसमें कम से-कम दखल दे प्रदेश अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी शिक्षा पद्धति चलाए। इतना ही नहीं हर राज्य के अलग-अलग अंचल भी शिक्षा दते हुए अपनी आवश्यकताको दृष्टि में रखें।

गांधीजी ने जब यह कहा कि शिक्षा में उत्पादक श्रम का समावेश होना चाहिए तो उनका तात्पर्य स्थानीय समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकने वाली शिक्षा के विकास में था। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा हमारी चौथाई आबादी को छूती है। पचहत्तर प्रतिशत आबादी से तो उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं आता। आगामी दस वर्षों

में इस अनुपात की और कुछ नहीं तो उलट तो देना ही चाहिए। प्राथमिक शिक्षण और विद्वत् विद्यालय के स्नातक वत्तन्व्य दृष्टि से आगे आगे प्रौढ शिक्षण का काम आगे बढ़ाएँ। इस तरह वे प्रति वर्ष दो करोड़ निरक्षरों को साक्षर कर सकते हैं। उन्हें यह उत्तरदायित्व उठाना ही चाहिए। प्रौढ शिक्षा से विभिन्न व्यवसाय की कुशलता बढ़े इसे ही देगना है। इसी तरह जिन्होंने अपना पढ़ना बीच में ही बन्द कर दिया है उन्हें भी घर बैठे आगे पढ़ने की सुविधा जुटानी चाहिए, नहीं तो अनगढ़ लोग धीरे धीरे अपढ़ या निरक्षर हो जाते हैं। मुझे बताया गया है कि यदि चौदह वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षण दिया जाना हो तो १९८५ तक आज की साठे छह करोड़ विद्यार्थियों की सरया को बढ़ाकर साठे आठ करोड़ तक ले जाना है। इसमें ऊपर के वर्षों में आज डेढ़ करोड़ विद्यार्थी हैं। इसे अगले दस वर्षों में साठे चार करोड़ तक ले जाना है। इसका अर्थ यह हुआ कि आगामी दस वर्षों से हर वर्ष में ५२ लाख नए विद्यार्थी प्राथमिक शालाओं में आने चाहिए। आज पिछले तीस वर्षों की औसती २४ लाख से अधिक नहीं है। और पिछले तीस वर्षों में तो वह ११ लाख से भी कम हो गई है। ये आंकड़े हमारी प्राइमरी शिक्षा की गंभीर समस्याको सूचित करते हैं। यह स्पष्ट है कि इतनी जबरदस्त सरया के लिए स्कूलों का खोला जाना फठिन है, इसलिए जरूरी है कि खती और गृह उद्योग भाँति करते हुए बालिका को वास्तविक शिक्षण का लाभ भी दिया जाए। और इसी प्रकार हम अपनी विशाल जनसरया को निरक्षर बने रहने से बचाएँ। इस सन्दर्भ में लड़कियाँ के शिक्षण पर और भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

प्राथमिक शालाओं में पब्लिक स्कूल नाम से कुछ संस्थाएँ चल रही हैं। यह असल में मुट्ठीभर भद्र कह जाने वाले समाज की शालाएँ हैं। इसलिए गरीब माता-पिता भी इनके कारण एक निरर्थक होठ में पड़ जाते हैं। जरूरी है कि सात साल का प्राथमिक शिक्षण सच्चे अर्थ में पब्लिक अर्थात् सार्वत्रिक किया जाना चाहिए। डा. कोठारी आपोग ने कॉमन स्कूल पर अमल करने की बात नहीं है। नगरपालिकाएँ या पंचायतें अपनी पाठशालाओं में जिन साधनों से शिक्षा की व्यवस्था करती

हैं उनके मुकाबले में कई गुना समृद्धि माधनो के उपयोग के द्वारा पब्लिक स्कूल देश में सामाजिक विषमता को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए पब्लिक स्कूलोंकी व्यवस्था कम से कम प्राथमिक शिक्षण की हद तक समाप्त कर देनी चाहिए। १९६५ में मैंने यह बात शिक्षा आयोग के सामने कही थी। हमारा तथ्यांकित शिक्षित वर्ग इस भेदभाव को समाप्त करने का विरोध करता है। वह भूल जाता है कि शिक्षा की खूबी गुण-धत्ता पर आधारित है। शिक्षा देने के साधनों पर नहीं।

अलग से बालमन्दिर चलाने के बजाय प्राथमिक शालाओं में ही पूर्व प्राथमिक वर्ग चलाए जाने चाहिए। हमारा देश बाल मन्दिरों का खर्च अलग से उठाने की हालत में नहीं है। माध्यमिक शिक्षण की हद तक ग्यारहवें, बारहवें वर्गों में पाठ्यक्रम की विविधता और अलग-अलग व्यावसायिक विषयों को रखना जरूरी है। किन्तु यदि हम इस दृष्टि से ग्यारह बारह वर्ग बना डाल तो वह एक बड़ा बोझ बन जाएगा। माध्यमिक शिक्षण का उद्देश्य कोई एक व्यावसायिक शिक्षण होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग व्यवसाय की शिक्षा मस्याओं का खोलना जरूरी नहीं है। सामान्य शिक्षा चलाने वाली संस्थाओं में भी विभिन्न व्यवसायों का तत्व बढ़ाते चले जाएँ तो यह ध्येय साधा जा सकता है।

विश्वविद्यालय में पढ़ना सबके लिए जरूरी नहीं है। इसे ध्यान में रखकर नौकरियाँ देते समय विभिन्न कसौटियाँ सामने रखनी पड़गी। हर जवान कुछ इस तरह का काम कर सके कि वह अपने काम के द्वारा अपनी आवश्यकता के परिमाण में वेतन भी प्राप्त करे। बरोड़ो निरक्षरोंमें प्रौढ शिक्षण का फैलाव करते हुए हम उन्हें तीन वर्षों तक कोई व्यवसाय विशेष भी सिखाएँ। यदि इस बीच में उसे कोई छोटी-मोटी नौकरी भी मिल जाती है तो वह उसे स्वीकार कर सकता है। इस तरह तरुणों में बेकारी का भय समाप्त करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेकारी के भय में आज हमारी तरुण शक्ति निराशा के भंते में उतरती जा रही है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को चाहिए कि वे कम से कम छह महीने किसी धर्मिक समाज या गाँव में जाकर कोई काम सीखें। और वह भी अपने शिक्षण का अंग मान कर। राष्ट्रीय सेवा योजना के

द्वारा गरीब और पिछड़े हुए ग्राम-विकान के प्रयत्न चल रहे हैं। किन्तु वे पूरे नहीं पड़ते। वर्ष के अन्त में कोई पन्द्रह दिन का क्षिविर लगाकर राष्ट्रीय सेवा योजना मान लेती है कि अनिवार्य पूरा हो गया। इसमें देश के विकास की दिशा में कोई बड़ा परिणाम सामने नहीं आता। आवश्यक यह है कि अग्र विश्वविद्यालय का हरेक स्नातक जिस शहर में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो उस शहर के बांग्गानों में काम करता हुआ अपने विषयों का अध्ययन करे और आमजीवी वर्ग स्तरों आदि में मजदूरी करते हुए किसी उत्पादक प्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करे। और प्रौढ़ शिक्षण सार्वजनिक स्वास्थ्य, विभिन्न उद्योगों आदि के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता है। विश्वविद्यालय की शिक्षा को जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई है, यदि हम उसमें शारीरिक धर्म को जोड़कर बुनियादी परिवर्तन नहीं करते तो नीचे की पाठशालाओं में भी उस तत्व को दाबित करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा आज का शिक्षा जगत 'ऊर्ध्वमूलमधः शाखा' की स्थिति में है। विश्वविद्यालय की परम्परागत पोथी-पुराण शिक्षण व्यवस्था अविलम्ब बदल दी जानी चाहिए।

परिवर्तन की प्रक्रिया को तो तत्काल ही प्रारम्भ कर दिया जाना है। हमने १९६७ में स्वीकार कर लिया था कि सारी दुनिया में शिक्षा मातृ-भाषा में दी जाती है तब भी विश्वविद्यालय तब की शिक्षा मातृभाषा में देंगे और इन काम को १९७७ तक पूरा कर लेंगे। मुझे बताया गया है कि कोई सत्तर विश्वविद्यालयों ने इस मिश्रान्त पर अमल भी किया है, फिर भी उसकी गति मंद है जो तेज की जानी चाहिए। तद्विषयक सेवा को समाप्त करके एकाध बरस में ही माइंस टेक्नालाजी आदि शारीर विद्याशाखाओं पर इसे लागू कर दिया जाना चाहिए। यदि हम सामान्य जनता को साइंस और टेक्नोलॉजी का लाभ देना चाहते हैं तो यह मातृभाषा के माध्यम से हो सकता है। भारतीय धर्म परायण समाज में विज्ञान और धर्म परस्पर विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि विज्ञान को आध्यात्मिक शक्ति का सहारा नहीं मिलता तो वह मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं बनता। इसलिए गरीब और पिछड़े

हुए लोगों की दृष्टि से भी विज्ञान की खोज और उसे प्रसारित करने के तरीके महत्वपूर्ण गिने जाएँ। ग्राम विकास के अनुरूप टेक्नालाजी को विकसित करना प्राथमिक कर्तव्य बन जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का मैं शुरू से विरोधी रहा हूँ। राज्य को चाहिए कि वह विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करे किन्तु विश्वविद्यालयों को भी चाहिए कि वे इसका उपयोग पूरे संयम और उत्तरदायित्व से करें। यदि राज्य हस्तक्षेप करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। किन्तु स्वायत्तता के नाम पर विश्वविद्यालय भी राष्ट्र की जरूरतों की अनदेखी नहीं कर सकते। इसी प्रकार शिक्षकों को भी चाहिए कि वे अपने काम की ओर विशेष ध्यान दें। विश्वविद्यालयों को राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त रखने का यह मतलब नहीं है कि जिस व्यक्ति को राजनीति में दिलचस्पी हो और जो शिक्षा को भी सच्चे मन से अपना क्षेत्र मानता हो उसे विश्वविद्यालय के काम काज में हाथ बँटाने की गुंजाइश नहीं है। शिक्षित वर्ग में राजनीतिक और राजनीति-विहीन व्यक्ति जैसा कोई भेद नहीं है। मुख्य बात विश्वविद्यालय का सूत्र संचालन करने वाले लोग किसी राजकीय पक्ष में हैं या नहीं—न होकर यह है कि वे साधन-शुद्धि में विश्वास करते हैं या नहीं। प्रजातंत्र को अछूत मानना अवांछनीय है—इतना ही नहीं वह हानिकारक है। राजकीय पक्ष अपनी विचारधारा विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ, यह समझा जा सकता है। मुख्य बात कि विचारधारा किम पद्धति से मर्यादा में रहकर पहुँचाई जा रही है, इसी पर ध्यान रखना है। सत्तारूढ़ दलों को समझना चाहिए कि विश्वविद्यालयों के संचालक सर्व सामान्य नियमों का उल्लंघन किए बिना राजनीतिक विचारों का प्रचार होने दे सकते हैं। किन्तु वे किसी राजकीय आन्दोलन में नहीं पड़ सकते। नियमानुसार सत्पात्रह करने का अधिकार सबको है, किन्तु उसका मनमाना उपयोग नहीं होना चाहिए और न इस तरह से होना चाहिए कि वातावरण में दोष या हिंसा फैले।

मेरी स्वीकार करता हूँ कि शिक्षा संस्थाओं और शिक्षा के दैनंदिन कार्य में शिक्षकों का हाथ होना चाहिए। किन्तु सारा का सारा संचालन

उन्ही के हाथ में हो यह भी हितकारी नहीं है। समाज के नागरिक और शिक्षक इस दिशा में हाथ बँटाएँ। आज राज्य शिक्षकों के वेतन और सेवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। इसके बाद शिक्षकों का काम शिक्षा को तेजस्वी और उपयोगी बनाकर उसे अधिकाधिक इन्हीं दिशाओं में ले जाना है। जीवन की बुनियादी जरूरत पूरी हों, इतना तो वेतन हर शिक्षक को मिलना ही चाहिए। किन्तु अगर वे समृद्ध समाज से होड़ लेने लगे तो वह कैसे बनेगा। शिक्षकों के लिए विचार की स्वतन्त्रता आवश्यक है जिससे वे निभेंच होकर अपनी बात लोगों के सामने रख सकें। किन्तु अगर वे शिक्षा की संस्था को संसद या विधान सभा सरीखा प्रजातन्त्रीय रंगमंच बनाने का प्रयत्न करें तो उसे भी उचित नहीं माना जाएगा। हम प्रजातन्त्र के बाहरी स्वरूप को लेकर इतना उलझ गए हैं कि उसकी आत्मा हमारी आँखों के आगे से ओझल है। हमारे शिक्षण-संस्थान प्रजातन्त्र की आत्मा को समझने के संस्थान हैं। उसके बाहरी स्वरूप पर अटना अनावश्यक है।

आज हमारा अधिकाधिक ध्यान गाँवों की ओर रहे, हम निरक्षरता निवारण करें, नगाबन्दी के विचार को फेंकाएँ, आदिवासियों और ग्रामोद्योगों का विवास करें—यही हमारी आज की शिक्षा-दृष्टि होनी चाहिए। हम इसी प्रकार गांधीजी के स्वप्न के ग्राम स्वराज्य को संकल्प-पूर्वक सिद्ध करें।

[१८ अक्टूबर की गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में दिए हुए वीक्षात भाषण के कुछ अंश]



गांधीवादी योजना की रूपरेखा

श्रीमन्नारायण

यह बात साफ तौर पर स्वीकार कर ली जानी चाहिए कि हमारी आर्थिक योजना को अब तक गांधीवादी आधार पर एक बार भी तैयार नहीं किया गया। पिछले तीस वर्षों तक महात्मा को हम राष्ट्रपिता कहकर पुकारते रहे लेकिन उसके आदर्शों और विचारों को हमने योजनाबद्ध विकास के एक अंग के तौर पर कार्यक्रम में उतारने की कभी कोशिश नहीं की। जनता सरकार असल में पहली बार नये भारत के निर्माण में गांधीवादी सिद्धान्तों की मदद लेने के लिए कृत-संकल्प हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये लोग इस काम को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक मिशन के तौर पर करेंगे।

यहाँ पर राष्ट्रीय अथ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ दिशा निर्देशों का उल्लेख उपयोगी होगा जिन्हें छठी योजना बनते समय सरकार ध्यान में रख सके। यह ता स्पष्ट ही है कि गांधीजी के विचारों के अनुरूप बनी आर्थिक योजना में कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यद्यपि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के विकास की आर्थिक प्रगति का आधार बताया जाता रहा, लेकिन सचार्ई यह है कि कृषि, सिंचाई, पशु पालन, डेरी उद्योग तथा कृषि उद्योगों आदि को उनकी जरूरतों को देखते हुए बहुत कम पैसा मिला। भूमि सुधारों पर भी रुक-रुक कर और बड़े ब्रमन से अमल हुआ। और इसका नतीजा यह हुआ कि छोटे किसान और भूमिहीन मजदूरोंको विकास का पूरा फायदा नहीं मिल सका।

भोजन चूँकि जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है, अतः भारतीय कृषि को देश के विभिन्न भागों की पोषक आहार सम्बन्धी जरूरतों को

पूरा करने नायक पर्याप्त अन्न पैदा करना चाहिए। इस लिहाज से अन्न, दालों तथा मोटे अनाज के मामले में भी अन्तर-क्षेत्रीय विषमताओं को योजनाबद्ध तरीके से दूर करना होगा। पिछले दो दशक का अनुभव हमें बताता है कि इस सिलसिले में अन्तर-क्षेत्रीय व्यापार और परिवहन के विकास के बावजूद हर क्षेत्र या उपक्षेत्र की खाद्यान्नों की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सका। खाद्यान्नों के अलावा लोगों को सतुलित आहार उपलब्ध कराने के सवाल से दूध, फल और सब्जियों के उत्पादन की तरफ भी ध्यान देना होगा।

विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में छोटी सिंचाई योजना पर और अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है। इसके अलावा अगले पाँच सालों में भारत के सभी गाँवों में पीने के पानी को उपलब्ध करवा दिया जाना चाहिए। मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अत्यधिक खाद में रासायनिक खाद को ठीक तरह से मिलाया जाए। खेती में अति-मशीनीकरण के बजाय प्रति एक पैदावार बढ़ाने के लिए परम्परागत औजारों और विधि में आवश्यक सुधार के प्रयत्न किये जाने चाहिए। कृषि क्षेत्रों में सहकारिता आन्दोलन को और अधिक व्यापक बनाने के लिए छोटे तथा मध्यम किसानों को और बड़ी तादाद में उनमें शामिल किया जाना चाहिए। सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पर जमीन को सहकारी खेती के दायरे में लाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती न की जाए। खाद्यान्नों तथा पशुओं के हमारे उत्पादन में वृद्धि के लिए मिश्रित उपज की जानी चाहिए। लोगों की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के सवाल से हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाँव पंचायतों को पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए ताकि वे हर गाँव या गाँवों के समूहों में फसलों सम्बन्धी कोई योजना बना सकें।

भूमिहीन मजदूरों को ऐसे सहकारी श्रमिक संगठनों के रूप में संगठित किया जाना चाहिए जो अतिरिक्त श्रमशक्ति को खेती के अलावा गाँव में ही कृषि उद्योगों में तलाश सकें। स्थानीय जरूरत के आधार पर ईंधन और कृषि औजार बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी जुटाने की खातिर जंगलों की खेती का विश्वास किया जाना चाहिए। गाँवों में सार्व-

जनिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम के तौर पर आवश्यक जड़ी बूटी उगाए जाने के काम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, खाद रोशनी, ऊर्जा की पर्याप्त पूर्ति के ख्याल से बड़े पैमाने पर गोबरगैम के सयंत्र लगाए जाने चाहिए। जैसा कि विनोबाजी ने सुझाया है लगान को साधान्न की शक्ल में वसूल किया जाना चाहिए ताकि उनका एक भंडार बनाया जा सके। अलाम कर जोतो को लगान से छूट दे दी जानी चाहिए। जमीन की मिल्कियत के दस्तावेजों को सुधार कर उन्हें बिना जरा भी देर किए ठीक कर लिया जाए।

गाँवों के सम्पूर्ण विकास के ख्याल से पशुपालन और डयरी उद्योग के विकास की वैज्ञानिक याजना का होना अत्यन्त आवश्यक है। असल में कृषि भारतीय अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है और पशु पालन कृषि की रीढ़ है। सदियां तक गाय हमारे गाँवों की खुशहाली का मूलाधार रही हैं। उसकी वजह यही है कि वह न सिर्फ हमें दूध देती है बल्कि हमारी खेती के लिए मजबूत बल भी देती है। भारत के विभिन्न इलाकों में इसी तरह के दुहरे उपयोग के पशुधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमें सकार गायों के जरिए अधिक दूध पैदा करने की हडबडी में स्वस्थ बैलों को बढ़ाने की जरूरत को भूल नहीं जाना चाहिए। नई तथा ऊँच जमीन को तोड़ने लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जा सकता है पर अभी दसियों बरस तक छोटे किसानों को जो आबादी का काफी बड़ा हिस्सा है मजबूत बैलों और बहुत कृषि औजारों पर ही निर्भर रहना होगा। जापान तक में गाय तथा बैल तेजी से बड़ी मशीनों की जगह लेते जा रहे हैं।

कृषि और पशुपालन के अलावा गाँव की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने और लोगों को भरपूर रोजगार देने के लिहाज में कृषि से पैदा हुए कच्चे माल पर आधारित ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग भी बहुत जरूरी हैं। योजना आयोग की एक गणना के अनुसार अगर एक आदमी गाँव छोड़कर शहर में चला आए तो उसे सार्थक काम तथा रहने की साधारण सुविधाएँ देने में पचास गुना अधिक खर्च आता है। अतः यह जरूरी है कि गाँवों से शहरों की तरफ जाने की वृत्ति को रोका जाए।

यह काम निजी या सहकारी आधार पर कृषि उद्योगों को विकसित करके और उसमें उन्हें काम देकर ही किया जा सकता है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योगों के उत्पादन के क्षेत्र निश्चित करने की जो बात कही गई है उस आधार पर उन्हें बड़े उद्योगों की असीम प्रतियोगिता के विरुद्ध संरक्षण दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कपड़े के मामले में एक निश्चित किस्म से नीचे खादी का ही उत्पादन बढ़ाना चाहिए, खाने के तेल की पेराई, गाँव की पानी में ही होनी चाहिए, चप्पल तथा देशी जूते गाँव के मोची द्वारा ही बनवाए जाने चाहिए। गूड़, कपड़ा, घान-कुटाई, भूसा अलग करने तथा दाल बनाने के ग्रामोद्योगों को भी इसी तरह संरक्षण दिया जाना चाहिए। मकानों की सुविधा बढ़ाने के लिए गाँवों में ईंट और खपरैलों के उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करना चाहिए।

इसका मतलब यह नहीं है कि कृषि उद्योगों को पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। गांधीजी ग्रामीण कारीगरों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग के हिमायती थे। लेकिन वे यह जरूर चाहते थे कि पूँजीगत तकनीक और स्वचालित मशीन के देशों में अधिकतम उत्पादन और पूर्ण-रोजगार नहीं पैदा होने देना चाहिए। दुनिया के देशों में अधिकतम उत्पादन और पूर्ण रोजगार दोनों लक्ष्य पाने के लिए आज दुनिया भर के बड़े अर्थशास्त्री 'मध्य दरजे' या 'उपयुक्त टेक्नालाजी' की बात करते हैं। अतः यह नहीं समझना चाहिए, कि छोटी मशीन आर्थिक आयोजना के लिहाज से व्यावहारिक नहीं हैं। गांधीजी यात्रिव कुशलता और आर्थिक कुशलता में फर्क करते थे। यह हो सकता है कि बड़ी मशीन यांत्रिक रूप से अधिक कुशल हो पर वह आर्थिक रूप से अकुशल साबित होती है। चूंकि वह श्रमिकों की छुट्टी कर देती है और इस तरह समाज में बेरोजगारी या अर्द्ध बेरोजगारी जैसी घुराहियाँ पैदा हो जाती हैं; इसलिए सरकार का यह पहला कर्तव्य हो जाता है कि यह अपनी अर्थनीति के बुनियादी सिद्धान्त के रूप में खेती और कृषि उद्योगों को आवश्यक संरक्षण दे।

ऐसी बात नहीं है कि महात्मा गांधी बड़े उद्योगों या बुनियादी उद्योगों के बिल्कुल खिलाफ रहे हों। 'गांधी वादी आयोजना' में मैंने भारतीय अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने के स्याल से कुछ रक्षा तथा बुनियादी उद्योगों का प्रावधान किया था। गांधीजी इसके बारे में चाहते थे कि इस तरह के उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में हों। ताकि उनके माध्यम से उद्योगपतियों के सम्भावित शोषण से बचा जा सके। उनका कहना यह था कि साधारण लोगों की जरूरत की चीजें पैदा करने वाले कारखानों को विकेंद्रित आधार पर होना चाहिए।

भोजन और कपड़े के अलावा आदमी की ज़िन्दगी में सबसे ज़रूरी चीज होती है उपयुक्त निवास। पञ्चवर्षीय योजनाओं में शहरी क्षेत्रों में तो कम और मध्यम आमदनी वाले लोगों के मकान बनाने की व्यवस्था की गई है पर उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए छठी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते और मजबूत मकान बनाए जान की व्यवस्था हानी चाहिए। इस सन्दर्भ में यहाँ गांधी जी की कल्पना के आदर्श गाँव का उल्लेख उप योगी होगा —

'एक आदर्श भारतीय गाँव का इस तरह बनाया जाएगा कि उसमें सफाई का मुमुक्षित प्रबन्ध हो। उसके मकानों में रोशनी और ताज़ी हवा के आने जान की पर्याप्त व्यवस्था होगी। उन मकानों को पाँच मीन के घरे व भीतर मिलने वाले सामान से तैयार किया जाएगा। मकान के बाहर दानान होगे जहाँ घर के लोग अपनी जरूरत भर की सब्जियाँ उगा सकें तथा पशु बाँध सकें। गाँव की गलियाँ और सड़कें यथा सम्भव बड़े में मुक्त होगें गाँव में सब धर्मविलम्बियों के लिए पूजागृह होगा एक सभागृह होगा पशुओं का एक सम्मिलित चरागाह होगा, एक सहकारी दुग्धशाला होगी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय होंगे जिनमें मुख्य रूप से उद्योग घट्टों की शिक्षा दी जाएगी, आपसी बगडों के निपटारे के लिए पंचायत होगी। वह गाँव अपनी जरूरत भर का साधन, सब्जियाँ, फल और खादी खुद पैदा करेगा। यह है मोटे तौर पर एक आदर्श गाँव की मेरी कल्पना।'

जहाँ तक परिवहन का सवाल है हमारी योजना में सड़क और वच्चे रास्तों को ऊँची प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह उन्हें आने-जाने की सुविधाएँ उपलब्ध करवाए जाने के ख्याल से ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इससे सूदूर गाँवों तक में अधिक उत्पादन तथा व्यापार आदिको प्रोत्साहन मिलेगा। बेलगाड़ी जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन का एक महत्वपूर्ण आधार है उसे पर्याप्त खोज द्वारा सस्ती और अच्छी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय ने नई गाड़ी का एक डिजाइन विकसित करने के लिए एक अध्ययन दल गठित कर दिया है। देश के भीतर पानी के रास्ते परिवहन का भी विकास किया जाना चाहिए। इसे सस्ता और अधिक रोजगार प्रदान करने वाला होना चाहिए।

गांधीजी मजदूरों को खेती और कारखानों के स्वामित्व में सहभागी मानते थे। इस दृष्टि से मालिक और मजदूर के मौजूदा अन्तर को धीरे-धीरे मिटते जाना चाहिए। इसके साथ माय नौकरी के बजाय अपना स्वतन्त्र धन्धा करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। गांधीजी का ट्रस्टीशिप का मिद्धान्त सिर्फ पूँजी पर ही लागू नहीं होता। वह धर्म पर भी लागू होता है। अमल में जीवन के सभी क्षेत्रों पर वह लागू होता है। गांधीजी ने मजदूर और प्रबन्धकों के बीच के सम्बन्धों के सिलसिले में अधिकारों और वस्तुओं दोनों पर जोर दिया था। इस लिहाज से मजदूरों को उत्पादकता से जड़ा हुआ होना चाहिए। बड़ी आगदनों और घोनस का एक भाग शयर के रूप में दिया जाना चाहिए ताकि मजदूर धीरे-धीरे उस उद्योग या व्यवसाय में वास्तविक भागीदार बन जाएँ और वे अधिक उत्पादन के लक्ष्य में सच्ची दिलचस्पी लेना शुरू कर दें।

हमारी योजना में जनसंख्या पर नियंत्रण की समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा न हुआ तो बड़ा हुआ उत्पादन अधिक जनसंख्या में बँटकर रह जाएगा और लोगों को इसका कोई लाभ न मिल सकेगा। लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण की कोशिश को ऐच्छिक ही होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नोजवान लोग गर्म निरोध के तरीकों का उपयोग स्वेच्छाचार के लिए न करें।

राष्ट्रीय आयोजना में दामो पर नियंत्रण के काम को भी धरीयता देनी होगी। यह कोई आसान समस्या नहीं है और इसके लिए निश्चयपूर्वक बड़े बजट उठाने होंगे। हमारा यह पहला काम होता चाहिए कि हम आम आदमी की जरूरत के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दें। अमीर लोगों के ऐंग और आराम की वस्तुओं के उत्पादन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को बड़ाई में रोकना होगा। जरूरी चीजों के दामो पर नियंत्रण की दीर्घकालीन नीति के रूप में सायान्नो तेल चीनी कपड़ा सीमेंट तथा कागज के पर्याप्त भंडार बनाए जान चाहिए। गहर और गाँव सब जगह लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए एक ताकतवर उपभोक्ता सहकारी आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। खर्च को रोकने के लिए घरेलू बचत का एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए। अनावश्यक नियंत्रणों को हटा दिया जाना चाहिए। उनमें से सिर्फ आवश्यक नियंत्रण ही रहने दिए जाने चाहिए। सरकार की कर नीति में भी व्यापक परिवर्तन की जरूरत है। उदाहरण के लिए मद्रा प्रसार को रोकन के प्रयत्न दृढ़ता से किए जान चाहिए। अर्थ व्यवस्था के उच्चवरीयता वाले क्षेत्रों को ऋण की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध की जानी चाहिए। अनुत्पादक तथा फालत खर्च और प्रत्यक्ष उपभोग में कटौती की जानी चाहिए। इसके लिए कठिन फैसले ही नहीं लने होंगे बल्कि इसके लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा की भी जरूरत होगी।

हमें महात्मा गांधी की कल्पना का नया भारत बनाने के लिए उनके इन शब्दों को लगातार याद रखना होगा —

मैं एक ऐसा भारत के निर्माण की कोशिश करूँगा जिसमें गरीब-स गरीब आदमी को भी यह लग कि इसका निर्माण में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। वह ऐसा भारत होगा जिसमें न कोई उच्च वर्ग होगा और न निम्न वर्ग एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूरे सामंजस्य के साथ रहते हों। उस भारत में छत्रछाया के अभिगाप का नगीची चीजों या दवाओं के अभिगाप का कोई स्थान नहीं होगा। महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त होगा। चूंकि हम गेप पूरी

दुनिया के साथ शांतिपूर्वक रहेंगे, इसलिए बहुत छोटी सेना रखेंगे। हम एमे मव देशी और विदेशी हितों का पूरा ख्याल करेंगे जो देश के करोड़ों आम लोगों के हितों से नहीं टकराते। निजी तौर पर मैं देशी और विदेशी के फर्क को नापसन्द करता हूँ। यह है मर सपनों का भारत।”

अन्तमें, हमें अपनी योजनाओं को गांधीवादी आधार पर इसलिए नहीं बनाना कि इनके साथ उस महात्मा की स्मृति जुड़ी है, बल्कि इसलिए कि ये विचार समय के साथ पूरी तरह व्यावहारिक, वैज्ञानिक और उपयुक्त साबित हुए हैं। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि गांधीजी के विचार उनके जीवन में सार्थक थे, वे आज भी सार्थक हैं और आने वाले समय में भी सार्थक रहेंगे। गांधी अतीत की यादगार नहीं है। वे नो भविष्य को दृष्टा थे।



ज्ञान ओढ़ा जाता है, उतारा भी जा सकता है।
अनुभव जीने की प्रक्रिया में से समुद्र-मयन की
तरह उपजता है।

प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व

[अखिल भारत प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन का पंद्रहवाँ अधिवेशन १४, १५, १६ अक्टूबर को डॉ. श्रीमन्नारायण जी की अध्यक्षता में साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में सम्पन्न हुआ । उसका उद्घाटन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया । सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव पाठकों का जानकारी के लिए दिए जा रहे हैं ।]

- १- यह सम्मेलन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के इस आश्वासन का हृदयसे स्वागत करता है कि भारत सरकार प्राकृतिक चिकित्सा को एक स्वतंत्र पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान करनेवाली है । सम्मेलन आशा करता है कि जिन राज्य सरकारों ने अभी तक प्राकृतिक चिकित्सा को मान्य नहीं किया है वे भी शीघ्र ही इस पद्धति को मान्यता दे देगी ।
- २- सम्मेलन की राय में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा का मूल विचारों को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए ताकि गांधीजी के समय-प्रधान आदर्श को उनके जीवन में उतारा जा सकें । प्राकृतिक चिकित्सा के बुनियादी सिद्धान्तों के प्रचार के लिए रेडियो टेलीविजन व फिल्मों का भी उपयोग किया जाना चाहिए ।
- ३- प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को समय जीवन दर्शन के रूप में निरन्तर विकसित करते रहने की आवश्यकता है । इसके लिए यह जरूरी है कि भारत सरकार एक अखिल भारत प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्वतंत्र रूप से स्थापना करे । सम्मेलन की राय में इस केन्द्रीय संस्थान का केन्द्र सेवाग्राम हो । इसके क्षेत्रीय केन्द्र बलकटता, मोरखपुर, हैदराबाद व उरली काचन में रखे जाएँ ।
- ४- भारत सरकार ने जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना घोषित की हैं, उनके अभ्यासक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा को भी स्थान दिया

गया है यह सतोष का विषय है। वार्यवर्तियों के प्रशिक्षण के लिए देश भर के प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र सहायता देने को तैयार रहेंगे। किन्तु इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि सरकारी ग्राम स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अन्य पद्धतियों को अधिक महत्व न देकर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा ही गाँवों की जनता का स्वास्थ्य बच सचौले ढंग से सुधारने का पूरा प्रयास किया जाए।

५- अभी तक प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भारत सरकार ने केवल एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है। अब यह आवश्यक है कि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भी एक स्वतन्त्र अखिल भारतीय बोर्ड को गठित किया जाए। ताकि इस पद्धति का विकास गतिशील बन सके। इस कार्य के लिए समुचित धनराशि भी उपलब्ध करानी चाहिए।

६- यह सम्मेलन राज्य सरकारों से आग्रह करता है कि प्राकृतिक चिकित्सा के प्रसार के लिए प्रत्येक जिले में स्वतन्त्र रूप से कन्द्र स्थापित किए जाएँ जिनका संचालन प्रशिक्षित प्राकृतिक चिकित्सकों को सौंपा जाए।

अध्यापक-शिक्षा राष्ट्रीय विचार गोष्ठी सेवाग्राम,

१८, १९ और २० सितम्बर, १९७७

सर्वसम्मति निवेदन

अखिल भारत नई तालीम समिति तथा राष्ट्रीय संक्षिप्त अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा समुन्नत रूप से आयोजित की गई 'शिक्षक पाठ्यक्रम तैयारी की परिवर्तन' विषय पर विचार गोष्ठी १८, १९ और २० सितम्बर, १९७७ को सेवाग्राम में हुई। विचार गोष्ठी के सामने चर्चा का मुख्य विषय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद के लिए तैयार किए गए 'अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम' की रूपरेखा पर विस्तार से विचार करना था। इसका उद्घाटन अखिल भारतीय नई तालीम समिति के अध्यक्ष डा श्रीमन्नारायण द्वारा किया गया। इस विचार

गोष्ठी में सम्पूर्ण देश के जाने माने शिक्षाविदों ने भाग लिया। उसमें शिक्षा विभागों के अध्यक्षों शिक्षा वा नेजा के प्रिंसिपलों शिक्षकों प्राध्यापकों और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्यापक शिक्षा के तीन पहलुओं, यथा, "अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की परिवर्तना" समाज शिक्षा को अध्यापक शिक्षा के साथ जोड़ना" और अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन" पर विचार किया गया।

इस विचार गोष्ठी की चार बैठक हुईं तथा एक और बैठक थोड़े से समय के लिए पवनार आश्रम में आचार्य विनोबा भाव के साथ भी हुई, जिनमें 'पाठ्यक्रम की रूपरेखा' के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया और निम्नलिखित बातों पर मतंक्य हुआ —

१- देश में इस समय शिक्षा का जो वातावरण है वह यह अपेक्षा करता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सभी स्तरों पर गांधीय मूल्य तत्काल लागू किए जाएं। विचार गोष्ठी में यह अनुभव किया गया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा क्षेत्र में आज कार्य और समाज का नव निमाण करने की आवश्यकता है बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत शिक्षा के सभी स्तरों पर लागू होने चाहिए।

२- शिक्षा में गांधीय मूल्यों को सम्मिलित किए जान की अविलम्ब आवश्यकता के सदर्भ में अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रारूप में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा उपयुक्त सुधार करने की आवश्यकता है।

विचार गोष्ठी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से यह सिफारिश करती है कि एक छोटी समिति गठित की जाए जो अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रारूप पर विस्तार से विचार करे और शिक्षा सम्बन्धी गांधीय सिद्धांतों और मूल्यों के सदर्भ में उसमें अपेक्षित सुधारों के लिए सुझाव दे।

३- विचार गोष्ठी का मत है कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से देश में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए।

- ४- विचार गोष्ठी का यह निश्चित मत है कि उच्च शिक्षा देने वाले अध्यापकों को भी उचित प्रशिक्षण की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि स्कूल के अध्यापकों को।
- ५- विचार गोष्ठी सिफारिश करती है कि अध्यापक शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रथमतः ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जो देश की परिस्थितियों के अनुरूप देश में ही विकसित किए गए दृष्टिकोणों और तकनीकों पर आधारित हों। यहाँ, अन्य देशों में विकसित नई तकनीकों और पद्धतियों को भी आवश्यक सशोधनों और परिवर्तनों के साथ अपनाया जा सकता है।
- ६- विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने की नीति को सदर्भ में अनौपचारिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है। अतः विचार गोष्ठी सिफारिश करती है कि प्रत्येक अध्यापक को अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- ८- इस बात पर विचार गोष्ठी में भर्त्सक प्रकट किया गया कि सभी स्तरों पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में उत्पादक कार्य और सामुदायिक शिक्षा को अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित किया जाए।
- ७- सामुदायिक कार्य के कार्यक्रम में परिसर के भीतर की और परिसर के बाहर की सभी गतिविधियाँ सम्मिलित की जाएँ और उन्हें पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में सुनिश्चित रूप में लागू किया जाए।
- ९- सभी प्रशिक्षण सत्यापन स्वयं को स्वावलम्बन सहकारिता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक सुसम्बद्ध समुदाय के रूप में संगठित करें।
- १०- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करते समय छात्रों के परो और उनके माता-पिताओं के महत्वपूर्ण योगदान को पर्याप्त मान्यता दी जानी चाहिए।
- ११- नया पाठ्यक्रम अपनाए जाने के लिए अध्यापक शिक्षा सत्यापन को नया रूप देने के मागों में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई।

(अ) क्या एक अध्यापक शिक्षा संस्थान को अपनी निजी स्वाभाविक विशेषताएँ, अपना निजी संरचनात्मक वातावरण और अपनी नई कार्य-मदति विकसित करके अपना निजी पृथक् अस्तित्व विकसित करना चाहिए अथवा नहीं ?

(आ) क्या प्रत्येक ऐसे संस्थान को अपनी आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुसार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करने और उनका मूल्यांकन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए ?

इन दो विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और अनेक विकल्पों का सुझाव दिया गया। इस बारे में निम्नलिखित बातों पर मतभेद हुआ -

(अ) प्रत्येक अध्यापक शिक्षा संस्थान को राष्ट्रीय उद्देश्यों के दायरे में रहते हुए अपना निजी अस्तित्व विकसित करना चाहिए।

(आ) प्रत्येक संस्थान को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए कि वह पाठ्यक्रम कार्यक्रम में अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त संशोधन और प्रयोग कर सके। ऐसी स्वतंत्रता को प्रशासन से समर्थन मिलना चाहिए।

१२- विचार गोष्ठी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह आग्रह किया है कि वह अध्यापक शिक्षा और अध्यापक शिक्षकों की शिक्षा के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करे और अध्यापक शिक्षा संस्थानों को क्षमता के उम स्तर तक पहुँचने में सहायता दे जो स्तर में अपेक्षित सुधार लाने के लिए आवश्यक हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए और इस बात पर बल नहीं देना चाहिए कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय भी इसके लिए उतना ही धन दें। विचार गोष्ठी ने ऐसा ही आग्रह राज्य सरकारों से भी किया है कि वे भी अध्यापक शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आवश्यक धन दें। -



रहनुमाई

ऐ रहमदिल रहमान
 हमको राह दिखला दे,
 दुनिया में रहमदिल से भरा
 दरिया बहा दे !
 कैसा नजर आता जमाना
 देख तो लें आज,
 खिलमत पर मोहब्बत पर
 सच्चाई पर हमें है नाज !
 हैरान हैं कुर्बान हैं
 कानून पर तेरे,
 कुदरत के नजारे नजर हैं
 साज सवेरे !
 जगत् कहीं दोख कहीं
 पबंत कहीं पानी,
 बयो जग होती है कहीं
 होती है कुर्बानी !
 है खेल ये कैसा
 तमाशा देखते हो तुम,
 जरा कुछ नूर दिखला दो
 रहम से पेश आएँ हम !
 इस्मान दुनिया के सभी
 आवास मिलकर हम,
 भरे दिल में रहनुमाई
 लुटाएँ प्यार हम हर हम !

—मदालसा नारायण

सेवाग्राम-आश्रम-वृत्त

संकलक, श. प्र. पाडे

(माहे अक्टूबर १९७७)

“ गांधी जयंती ” के शुभ अवसर से इस माह का शुभारंभ हुआ । प्रातः फेरी, प्रायचना, अखंड सूत्र यज्ञ, गीताई पारायण, सामूहिक सूत्र यज्ञ, सर्व धर्म साथ प्रायचना तथा सर्व भाषीय भजन के कार्यक्रम से ‘बख्शी जयंती’ मनाई गई । विजया दशमी के अवसर पर बर्मशाला (बर्क-शाप) में आयुध पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ । सारे विभागों से कामों के औजार लाकर सजाए गए थे । भक्ति गीतों के साथ उनका पूजन तथा प्रसाद वितरण हुआ ।

इस माह में सेवाग्राम आश्रम के पुराने मित्र और आश्रमवासी, फ्रांसके गांधी श्री शान्तिदामजी सेवाग्राम आश्रम में आकर रहे । आस पास की मस्याबा के प्रतिनिधियों ने आकर उनके साथ भावी कार्यक्रम की चर्चा की । अहिंसा और शांति का विचार विश्वमें दृढ़ करने की दृष्टिसे भिन्न भिन्न स्थानोंपर व्यक्तिगत फुटकर प्रयत्न हो रहे ऐसा श्री शान्तिदासजी ने बताया । ऐसे प्रयत्न करने वाले इन चंद लोगों को एकत्रित करके सामूहिक रूपसे इस सम्बन्ध में विचार करने की दृष्टिसे १९७८ के दिसंबर में एक सगोष्ठी आमत्रित करने का विचार दृढ़ किया गया । तथा इस दृष्टि से प्रयत्न शुरू किए गए ।

गांधी के विकास की समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों का, जो कि एस वामा में प्रत्यक्ष सगे हैं, सम्मेलन २२ से २५ जनवरी १९७८ में सेवाग्राम आश्रम में सयोजित करल जा निश्चय किया गया है और उस दृष्टि से प्रयास भी आरंभ हो गए हैं ।

श्री जयप्रकाशजी के अमृत महोत्सव की कालावधि में सेवाग्राम के कार्यकर्ता आस-पास के देहातों में घूम और ग्रामवासियों से मिलकर खुल दिल से चर्चाएँ की ।

पूज्य अण्णा साहव सहस्रबुद्धे की ८१ वी वर्षगांठ दिनांक २३ अक्टूबर को मनाई गई। इस अवसर पर सेवाग्राम की संस्थाओं ने "वस्त्र स्वावलम्बन" की दृष्टि से प्रयास करने का संकल्प किया। इसके अनुसार २५-१०-७७ को कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी में एक बैठक पूज्य अण्णा साहव के उपस्थिति में हुई और "ग्राम वस्त्र स्वावलम्बन" समिति की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष श्री दत्तोबाजी को बनाया गया। पूनी के कार्य से आरम्भ करने की दृष्टि से गांधी सेवा सघ कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी तथा सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान इन संस्थाओं से प्रत्येकी प्रारम्भ में १००० रु लेने का निश्चित किया गया। इस कार्य की पूर्ण तैयारी आरम्भ हुई है।

आश्रम में इस माह में कुल दर्शनार्थी ३०८० आए। जिनमें कुल ८४ श्रुपत् भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया तथा जर्मनी के कुल ५ अतिथि आश्रम में रहे। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री सोनू सिंह पाटील ने आश्रम को भेंट दी।

आश्रम की स्मारक कुटियों की देखभाल पूर्ववत् की गई। बापू फुटी बम्पाउट के सड़ हुए खम्भे बदल दिए गए। शास्त्री फुटी का परिसर ठीक किया गया। सेवाग्राम में आकर बापू पहिली द्वार जहाँ ठहरे थे वहाँ प्रथम आदि निवास का स्थान अब ठीक किया गया।

आश्रम के दैनिक कार्यक्रम भी पूर्ववत् चले। सुबह के प्रायश्नाभा की कुल औ हाजरी २३ रही। इसमें सुबह ४-२० तथा ५-३० के प्रायश्नाभा का अंतर्भाव है। माय प्रायश्ना की औ हाजरी ११ रही। सुबह दान की प्रायश्नाओं में "गांधी विचार वाचन तथा जन्म व्रतों का प्रवचन" नित्य होता रहा।

आश्रम वासिनों में आश्रम प्रतिष्ठान मंत्री श्री प्रभाकरजी बाकी अस्वस्थ रहे। अन्य आश्रम वासिया का स्वास्थ्य अच्छा रहा। श्री बाबलजी मोनाशी ग्रहण के स्वास्थ्य उपचार के लिए बाहर गये गए। वे अब तक वापिस नहीं आए।

वार्यकर्त्ता का उत्पादन परिश्रम वार्य इस महीने में अच्छा चला।

गांधी मार्ग

गांधी-विचारके सृजनात्मक साहित्य वा मासिक
सारगर्भित लेख, लघु लेख, कहानी, नाटक, कविता,
संस्मरण एवं व्यक्ति-चित्रों से युक्त
विचारशील पाठकों एवं सर्वसाधारण पाठकों के लिए पठनीय
सम्पादक :

श्री श्रीमन्नारायण, श्री भवानोप्रसाद मिश्र

वार्षिक शुल्क : रु. १२ द्विवार्षिक : रु. २२

एक प्रतिका मूल्य १ रु.

सम्पर्क करें : व्यवस्थापक 'गांधीमार्ग' (हिन्दी-मासिक)

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, २२१-२२

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली-२

संस्था कुल

गांधी स्मारक निधि का मासिक

सम्पादक - श्री पूर्णचंद्र जैन

वार्षिक शुल्क-५ रुपये,

एक प्रति-५० पैसे

रचनात्मक प्रवृत्तियों, कार्यों, सर्वोदय संगठन एवं

राष्ट्रीय हलचलों की जानकारी देनेवाला

एक प्रभावशाली माध्यम

संपर्क करें-व्यवस्थापक, संस्थाकुल

गांधी स्मारक निधि,

राजघाट, नई दिल्ली-२

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee”

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta—Gauhati—New Delhi.

“यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।”

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गौहाटी - न्यू देहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

सम्पादक-मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

श्री ब्रह्ममार्द पटेल

श्रीमती मदातला नारायण

डॉ० मदनमोहन दामो

वर्ष २६

अंक ३

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

शिक्षा में आधुनिक परिवर्तन

—श्री मोरारजी देसाई ९

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली

—श्रीमन्नारायण १९

आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा—विचारणीय प्रश्न

—श्री रघुकुल तिलक ४८

शिक्षा की पुनर्रचना

—डॉ० सतीशचन्द्र ४४

भाषी कार्यक्रम पर सर्वसम्मति निवेदन

— ५९

सेनाप्रान्त वृत्त

— ६९

श्रद्धा गुमन

— ७१

दिसम्बर-जनवरी '७८

- 'नई तालीम' का कार्य अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- 'नई तालीम' का मासिक शुल्क बारह रुपए हैं और एक बच्चा का मूल्य दो रु है।
- तत्पश्चात्तर वाले समय प्राप्ति अपनी सक्षमता निखाना न भूलें।
- 'नई तालीम' में ध्येय विचारों की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है।

श्री प्रधानमंत्री द्वारा जे भा नई तालीम समिति, सेनाप्रान्तों लिए प्रकाशित श्री
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन :

अखिल भारत नई तालीम समिति के तत्वाधान में १८-१९-२० दिसम्बर १९७८ को नई दिल्ली में एक अखिल भारत राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। उसका उद्घाटन १८ दिसम्बर को प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया और २० दिसम्बर को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा. प्रतापचन्द्र खन्ना ने समापन भाषण दिया। इन सम्मेलन में राजस्थान के राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक, कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, लगभग ३० विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुछ सरकारी सदस्यों और लगभग १०० अनुभवी शिक्षा शास्त्रियों व बुनियादी तालीम के रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के उद्घाटन के सत्र में योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. लकड़ावाला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा. सतीशचन्द्र और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के निदेशक डा. मिश्रा ने भी भाग लिया। सम्मेलन के अन्त में जो सर्वानुमति का वक्तव्य पारित किया गया वह इसी अंक में अग्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

यह राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन शिक्षा सुधार की तथा अन्य कई दृष्टि से ऐतिहासिक रहा। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विश्वविद्यालय के कुलपतियों के सम्मेलन अलग-अलग होते रहते हैं। नई तालीम समिति की ओर से भी प्रतिवर्ष एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। किन्तु नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में सभी प्रकार के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्होंने चर्चाओं में सक्रिय भाग लिया। प्रधानमंत्री और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने भी उसको विशेष महत्व दिया और सम्मेलन में अपने विचार भी विस्तार से प्रगट किए। इस दृष्टि से सम्मेलन के अन्त में जो वक्तव्य जारी किया गया, उसकी अहमियत जाहिर ही है।

सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि भारत की नई शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुरूप और बुनियादी तालीम के आधार पर ढाली जानी चाहिए और उसका माध्यम समाज-उपयोगी उत्पादक श्रम होना जरूरी है। बुनियादी शिक्षा के सभी आदर्शों को वालमंदिर से लेकर विद्यविद्यालयों तक लागू करना भारत के लिए श्रेयस्कर होगा। अब तो गांधीजी के सिद्धान्तों को शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों के लगभग सभी शिक्षा और विद्या वास्तवी मान्य कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे देश में भी अब बुनियादी तालीम को बिना किसी मानसिक बंधनों के स्वीकार दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को उपयोगी शिक्षा प्राप्त हो सके और वे भारत के अच्छे नागरिक बन सकें।

सम्मेलन ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि शिक्षा का माध्यम हर स्तर पर मातृभाषा होना चाहिए और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं द्वारा सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने का उचित प्रयत्न करना चाहिए। भारतीय भाषाओं के माध्यम को सकलता के लिए यह आवश्यक है कि अखिल भारतीय सिविल तथा सैनिक सेवाओं में भरती के लिए जो परीक्षाएँ ली जाती हैं, उनका माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएँ ही रखी जाएँ। राष्ट्रीयकृत बैंक तथा सांख्यिक क्षेत्रों के उद्योगों की सेवाओं के लिए भी जो परीक्षाएँ ली जाती हैं उन्हें देशी भाषाओं में आयोजित दिया जाए। चुनाव के बाद जिन उम्मीदवारों को चुना जाए उन्हें बाद में हिन्दी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। किन्तु जब तक इन शासकीय सेवाओं में भरती होने के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य रहता जाएगा तब तक विश्वविद्यालयों में मातृभाषा माध्यम को सकलतापूर्वक संचालित करना मुमकिन नहीं होगा।

पब्लिक स्कूलों के सम्बन्ध में भी सम्मेलन में काफी चर्चा हुई। यह सभी ने स्वीकार किया कि इन पब्लिक स्कूलों को अपना काम-काज राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के अनुसार ही चलाया चाहिए और मातृभाषा माध्यम तथा विभाषा सूत्र को लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि इन शिक्षण संस्थाओं में ५० प्रतिशत स्थान समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिभा सन्त वच्चों के लिए सुरक्षित रखे जाएँ ताकि उनमें राष्ट्रीय वातावरण का मंचार हो सके।

नई शिक्षा संरचना के सम्बन्ध में सम्मेलन की राय रही कि १०+२+३ के बजाय ८+४+३ की योजना अधिक उपयोगी होगी। भारतीय संविधान के अनुसार १४ वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को ७ वर्ष की अनिवार्य और मुफ्त बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद ४ वर्ष की उत्तर बुनियादी या माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था होना जरूरी है। यह शिक्षा विद्यालयों में दी जाए, कालेजों में नहीं। माध्यमिक शिक्षण के बाद फिर ३ वर्ष की विश्वविद्यालयीय शिक्षा का प्रयत्न किया जाए। जो विद्यार्थी चाहें वे १० वर्ष की शिक्षा के बाद मॅट्रिकुलेशन परीक्षा दे सकते हैं। शेष विद्यार्थी १२ वर्ष की शिक्षा के बाद ही सार्व-जनिक परीक्षा में बैठेंगे।

लेकिन सम्मेलन ने यह स्पष्ट राय जाहिर की कि मावधानी के साथ विस्तृत चर्चाओं के उपरान्त जो नई शिक्षा संरचना स्वीकार की जाए उसमें फिर अगले १०-१५ वर्षों तक कोई फेर बदल नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा-नीति में बार-बार परिवर्तन करने से तरह-तरह की मानवीय समस्याएँ पैदा होती हैं और उनसे यथासम्भव बचना चाहिए।

इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया कि देश की राजनीतिक पार्टियाँ स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के कार्यों में किसी प्रकार का दखल न दें। इस सम्बन्ध में उन्हें एक आचारसंहिता बना लनी चाहिए ताकि शिक्षण संस्थाएँ दलगत राजनीति के चक्कर में न डाली जाएँ और उन्हें शान्तिपूर्वक अपना कार्य संचालन करने की सुविधा प्राप्त हो सके। हम आशा करते हैं कि सभी राजनैतिक दल इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

हमें पूरी आशा है कि सम्मेलन की सभी सिफारिशों पर भारत सरकार, राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय गम्भीरतापूर्वक निर्णय भी लेंगे ताकि अगले सत्र से ही हमारी शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार दालित किए जा सकें और नवयुवकों में नए उत्साह का वातावरण संचारित हो सके।

श्रीकाकुल हृदयसे :

‘नई तालीम’ का यह ‘राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन शिगेराव’ ऐसे दुःखद समयमें निाल रहा है जब इसकी प्रेरणास्थली डा श्रीमन्नारायणजी इहलोक लीला समाप्त कर हमसे विदा हो गए।

डा श्रीमन्नारायणजी ने इस सम्मेलन का आयोजन गत १८-१९-२० दिसम्बर को दिल्ली में किया था। भक्तों इस सम्मेलन में उपस्थित रहनेका अवसर मिला था। सम्मेलन अपने में अत्यन्त सकल एवं ऐतिहासिक रहा। स्वयं श्रीमन्जी इस आयोजन से अत्यन्त सतुष्ट थे और चाहते थे कि उसकी सिकारिशोपर भारत सरकार, राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय गभीरतापूर्वक निर्णय कर। इस कार्यको आगे बढ़ानेके लिए इसकी सदस्योंकी एक समिति भी गठित की गई थी। किन्तु दुःख है कि सम्मेलनकी उपलब्धियों को क्रियान्वित होते देखने से पहले ही वे हम से विदा हो गए।

इस सम्मेलन के आयोजन के लिए श्रीमन्नारायणजी ने अत्यन्त सगनपूर्वक काफी परिश्रम किया था। वैसे वे द्वारा से पीडित तो थे ही पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिश्रम का उनके स्वास्थ्यपर भीतरी असर पड़ा। सम्मेलन की समाप्ति के बाद वे जब दिनांक २ जनवरी को वर्धा लौट रहे थे तब ट्रेन में ही अस्वस्थ हो गए और आग्रामें तत्काल सामयिक लघु उपचारके बाद भी ग्वालियर पहुँचते तब अत्यधिक अस्वस्थ हो गए और अस्पताल पहुँचने से पहले ही इहलोक से विदा हो गए।

इस विशेषांक के लिए संपादकीय लिखकर उन्होंने मुझे दिल्लीमें ही दे दिया था। ‘नई तालीम’ पत्रिका के लिए यह उनका अंतिम संपादकीय होगा। अब म दी गई सारी सामग्री के सम्बन्ध में वे निर्देश दे गए थे और तदनुसार ही सामग्री दी गई है।

उनका यह असामयिक वियोग केवल ‘नई तालीम’ के परिवार के लिए ही भीषण आघात है ऐसा नहीं बरन पूरे देश के लिए असह्य।

है। उनके अवमानसे अनेक क्षेत्रों में एक रिक्तता उत्पन्न हो गई है जिसकी पूर्ति निकट भविष्यमें कठिन प्रतीत होती है। इसे विधिका विधान मानकर धैर्यपूर्वक सहन करनेके सिवा अब और चारा ही क्या है ?

उन्होंने जो विचारोंकी अमूल्य निधि हमें प्रदान की है वह हमें सदा प्रेरणा देती रहेगी और गांधी विचार तथा विनोबा-दर्शन से अभिभूत शिक्षा क्षेत्र के इस ज्योतिस्तंभ का प्रकाश उनके द्वारा छोड़े हुए कामोंको पूरा करने में हमारा मार्ग दर्शन करेगा। हम निष्ठापूर्वक उस पथपर अग्रसर होते रहें यही प्रभु से प्रार्थना है।

नई तासीरके इस अंकके प्रकाशनमें अथकी बार जो विलंब हुआ है उसके लिए सहृदय पाठक क्षमा करेंगे।

—मदनमोहन शर्मा

गांधी मार्ग

गांधी-विचारके, सृजनात्मक साहित्य का मासिक
सारगर्भित लेख, लघु लेख, कहानी, नाटक, कविता,
संस्मरण एवं व्यक्ति-चित्रों से युक्त
विचारशील पाठकों एवं सर्वसाधारण पाठकों के लिए पठनीय
: सम्पादक :

श्री श्रीमन्नारायण,

श्री भवानीप्रसाद मिश्र

वार्षिक शुल्क : रु. १२

द्विवायिक रु. २२

एक प्रतिका मूल्य १ रु.

सम्पर्क करें : व्यवस्थापक 'गांधीमार्ग' (हिन्दी मासिक)

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, २२१-२२

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली-२

शिक्षामें आमूल परिवर्तन

मोरारजी देसाई

[अखिल भारत नई तासीम समिति की ओरसे दिनांक १८, १९, २० दिसंबर को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री था मोरारजी देसाई द्वारा दिए गए भाषण का कुछ महत्वपूर्ण अंश]

• अध्यक्ष महोदय और मित्रों ?

मैं चाहता हूँ कि मैं किसी न किसी भारतीय भाषाओं में बोलूँ, किन्तु इस समय देश में जो गोरखघरे (घोटाखे) की स्थिति है उसी को प्रकट करने के लिए अपना भाषण अंग्रेजी में दे रहा हूँ। यदि मैं हिन्दी में भाषण देता हूँ तो २ प्रतिगत अंग्रेजीदाँ तथा देशका प्रतिनिधित्व करने की अहम्मन्यता वाले लोग 'अंग्रेजी विरोधी' कहकर मेरी आलोचना करेंगे। देशकी इस समय की इसी प्रकार की स्थिति में हम हैं। मेरी दृष्टि में इस स्थिति के लिए जिम्मेवार वे ही हैं। जब श्रीमनजी ने मुझसे कहा कि वे अखिल भारत नई तासीम समिति की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं तो मैंने इस विचारका स्वागत किया और उद्घाटन के समय आप के बीच आ गया। यहाँ आने में मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि मैं आपको यह बताऊँ कि मुझे जब भी अवसर मिला तब हम ९ महीने की अवधि में मैंने क्या किया ? शिक्षा प्रणाली के सबंध में हमें सोचने की सक्त जरूरत है जिससे हम कुछ ऐसे निश्चित निष्कर्षोंपर पहुँच सकें, जिन्हें कार्यान्वित किया जा सके। शिक्षा सबंधी मेरे कुछ स्पष्ट और निश्चित विचार हैं। शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है किन्तु यह बात तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसमें शिक्षकों और संस्था-संचालकोंका सहयोग प्राप्त न कर लिया जाए, उन्हें समझाया न

जाए। उन्हीं के सहयोग से यह परिवर्तन लाया जा सकता है। लोक-सभामें कानून पास कर लेने मात्र से यह संभव नहीं है। मैं उनको दोषी करार नहीं देना चाहता जो शिक्षा के संबन्ध में भ्रम राय रखते हैं, या शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संबन्ध में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। यदि किसी को दोष दिया जा सकता है तो वह अंग्रेज सरकार को ही दिया जा सकता है। और विशेष रूप से मेकॉल को। किन्तु उन्हें भी कैसे दोष दें? उनके कार्य सिद्धि के लिए तो यह आवश्यक ही था। वे तो यहाँ राज्य करना चाहते थे और जनसाधारण को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। भूलतः तो यह हमारा ही अपराध है कि हम उनके शासन में थे।

शिक्षा, मानवी विवासका प्रभावशाली माधन है। मानव की सभी कृतियाँ उसके द्वारा प्राप्त शिक्षा पर निर्भर हैं। इसीलिए शिक्षा हमारी मूलभूत समस्या है। यही कारण है कि जितनी शीघ्रता से शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाया जाना संभव हो उतनी शीघ्रता से परिवर्तन लाने को मैं उत्सुक हूँ। इस विषय में शिक्षा से सम्बद्ध अनेक लोगों से तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी घन और विचार देने वाली संस्थाओं से मैं बात कर चुका हूँ।

मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने घर में, शाला में उचित शिक्षा पाई है और महात्मा गांधी ने तो और भी अधिक शिक्षा पाई। यही कारण है कि इस संबन्ध में मुझे विचार पूर्वक एवं वस्तु परक दृष्टि से सोचने को बाध्य किया है। हम सभी बुद्धि लेकर जन्मे हैं फिर भी एक वर्ग-विरोध बुद्धिजीवी कहलाता है। मेरी समझमें नहीं आता कि केवल एक हिस्सा ही कैसे बुद्धिजीवी कहलाता है। इस प्रकार का वर्गीकरण हो गया है। मैं तो यही मानता हूँ कि इस प्रकार के वर्गीकरण का कारण यही है कि हम हमारी बुद्धि का समुचित उपयोग नहीं करते। मनुष्य अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग कर सके यही शिक्षा का सही उपयोग है। शिक्षा उसे इसमें सहायता पहुँचाती है। शिक्षा तो आजीवन चलनी चाहिए। आज प्रोफेसर और अध्यापक यह समझते हैं कि वे सब को

शिक्षा दे सकते हैं जब कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि विद्या-अर्जन कभी समाप्त नहीं होता । हम जितनी चाहे उतनी विद्या ग्रहण कर सकते हैं । यह तो एक भंडार है जो कभी खत्म नहीं होता ।

दुनिया में कुछ ही ऐसे महान लोग होते हैं जो अपने आपको शिक्षित कर लेते हैं और सब कुछ जान लेते हैं । रमण महर्षि और रामकृष्ण परमहंस जैसे महान व्यक्तियों ने अपने आपको शिक्षित किया । ऐसे शिक्षक भी थोड़े ही होंगे और व्यक्ति भी कम । रमण महर्षि ने यद्यपि स्कूली शिक्षा पाँचवे या छठे दर्जे तक ही पाई थी किन्तु ऐसा कोई विषय नहीं था कि जिस पर वे गम्भीर सलाह नहीं दे सकते थे । इतना ही नहीं उन्होंने तो पशु और पक्षियों की बोली को भी सीखा था । वे तो बिड़िया या गोरैया की भाषा भी जानते थे । किन्तु ऐसे लोग कम होते हैं । अतः शिक्षा और प्रशिक्षण की योजना बनानी पड़ती है जिससे शिक्षक और प्राध्यापक पहले स्वयं कुछ सीखें और फिर दूसरों को सिखाएँ ।

महार्मा गांधी हमें इसीलिए बहुत कुछ दे सके, सिखा सके कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था । उन्होंने हमें ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा जो उन्होंने अपने जीवन में खुद न किया हो । अन्य किसी देश को ऐसा शिक्षक मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है । इसी मूलभूत तथ्य को शिक्षकों और प्राध्यापकों को समझना है । मैं तो उन्हें केवल सूत्राय मात्र दे सकता हूँ । मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ क्योंकि वे भी तो उसी शिक्षा प्रणाली की उपज हैं । यही कारण है कि हमें शिक्षा पद्धति में दीर्घ परिवर्तन करने की बात सोचनी पड़ती है ।

मैं आपके सामने कुछ बुनियादी बातें रखना चाहता हूँ जिनपर आप विशेष ध्यान दें और कुछ निर्णय, निश्चित निर्णय पर पहुँच सकें । उसके पश्चात् सरकार देखेगी कि वह उन्हें कैसे कार्यान्वित कर पाती है । मैं रूपरेखा देकर और फिर जनतासे स्वीकृति प्राप्त करनेके पक्ष में नहीं हूँ । मेरी राय में यह उचित नहीं है । अतः वह निश्चयात्मक रूपरेखा मैं आपसे चाहता हूँ । मैं तब तक विश्राम नहीं लूँगा जब तक मैं इसे आपसे प्राप्त नहीं कर लेता हूँ । इसे आप मेरा आह्वान समझें । मैं स्वयं

चैन नहीं लूंगा और न आपको चैन लेने दूंगा, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। महात्मा गांधी ने स्वयं इम्पर दिचार किया था, इस दिशा में प्रयोग किए थे तथा हमें कुछ बुनियादी विचार दिए, दिशा दी और उनकी मोटी मोटी रूपरेखा भी दी। उन्होंने डॉ. झाकिर हुसेन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। झाकिर हुसेन, स्वयं शिक्षा में बहुत रुचि रखते थे और इसी समिति ने हमें बुनियादी तालीम दी। बुनियादी तालीम का अर्थ, मेरी समझ के अनुसार स्कूलों और कालेजों में प्राप्त होनेवाली वह शिक्षा है जो हमें अपनी जीवन प्रणाली से प्राप्त होती है। उसकी बुनियाद हमारा जीवन है अतः हमें मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में प्रारंभ करना चाहिए। मानव की मूलभूत आवश्यकता यह है कि वह अपनी इन्द्रियों को उपयोग में लाए। यदि आप उनका उपयोग नहीं करेंगे तो वे निष्क्रिय हो जाएंगी, यदि मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है तो वह जीवन में निरूपयोगी हो जाता है। यदि इन्द्रियों का उपयोग करना है तो उनका उचित उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आप उनका गलत उपयोग करेंगे तो वे गलत दिशा में जाएंगे। यही यथार्थ बुनियादी तालीम है। यही कारण है कि आरम्भ से ही उत्पादक थम हमारे पाठ्यक्रम का आवश्यक प्रमुख अंग माना गया था, अन्यथा वह थम की गलत व्याख्याएँ उत्पन्न करता है। प्रत्येक काम जो आप कर उत्पादक हो इसका अर्थ है कि वह करनेवाले के लिए और समाज के लिए मददगार हो। अन्यथा वह उत्पादक नहीं है।

अतः हमें यह सोचना है कि छात्रों को सिखाने साधक उत्पादक काम कौन-सा है—कनाई, बड़ईगिरी या कृषि। यह सब अपनी अपनी उपयोगिता पर, देश की आवश्यकता पर तथा लोगों की प्राहिका शक्ति पर निर्भर है। महात्मा गांधी को इसमें कोई शक नहीं थी। उन्होंने कताई में तथा कपड़े से अर्थात् कनाई में प्रारंभ किया और कहा कि भोजन के अतिरिक्त बपड़ा मनुष्य की महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकता है जिसके बिना वह कुछ नहीं कर सकता। ऋषियों ने भी कपड़े से बनी कम से कम सेंगोटी तो लगाई ही थी। अतः बपड़ा मानव की आवश्यकता है। इसकी ओर लक्ष्य दिए बिना हम जीवन में स्वतंत्र कैसे होंगे? पराव-

लम्बिता जीवन का सब से बड़ा अभिगाप है। इसीलिए बुनियादी तालीम का मूलभूत कार्य यह है कि वह शिक्षितों में स्वावलम्ब आत्म विश्वास, सत्य, निर्भयता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को देने का माध्यम बने। इन गुणों की उपलब्धि के बिना हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ कि विश्व विद्यालय के सर्वोत्तम छात्र आज कल निराश हैं, हताश हैं, विफल हैं। निराशा, हताशा, विफलता, आत्म संदेह का तथा संपूर्ण आत्म विश्वास हीनता का द्योतक है। किसी भी हालत में मनुष्य क्यों निराश होता है? सत्य और निर्भयता ही मनुष्यको उन्नति की उच्चतम स्थिति पर पहुँचा सकते हैं। अनेक उपलब्धियों के लिए हम पुरस्कार करते हैं किन्तु इन गुणों के लिए किसी को पुरस्कृत किए जाते नहीं देखा गया। तब हम शिक्षा के सही उद्देश्यको कैसे हस्तगत कर सकेंगे? मैं आशा करता हूँ कि आप अपने चिन्तन के दौरान इसपर भी विचार-मंथन करेंगे। यह मथन ऐसा हो जिससे उचित निर्णय पर पहुँचा जा सके।

दो तीनों बातें ऐसी हैं जिनपर मैं आपसे विचार करने के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा जिनमें शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है। देश में सभी स्तर पर शिक्षा का माध्यम बदलकर मातृभाषा करना आवश्यक है। सभी शिक्षा शास्त्रियों ने महसूस किया है कि छात्रों को उनकी मातृभाषाको माध्यम से शिक्षा देने पर वे विषय को गहरी भाँति ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि वयपन में वे उसी भाषा में सीखते हैं। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन है। वह छात्र पर एक भारी बोझ है। उनकी सभी खूबियों और विशेषताओं को समझने के लिए उसे उन्हें सीखना पड़ता है और इस प्रकार विषय को सीखने के स्थान पर उस भाषाको सीखने में उत्साह काफी समय और शक्ति खर्च हो जाती है। छोटे छोटे देशों की शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रों में कुशल लोगों को अधिक संख्या में दिया है। क्योंकि वहाँ शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है। यहाँ छात्र पर भाषाका बोझ अधिक है और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं है अतः

हमें शिक्षा का माध्यम परिवर्तित कर उसे प्राथमिक से उच्चतम स्तर तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कर देना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाएँ भी क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए। अँग्रेजी का म विरोधी नहीं हूँ। विदेशी भाषा हम सीखें। म अँग्रेजी में बोल रहा हूँ। हिंदी गुजराती या मराठी की अपेक्षा म अँग्रेजी में अधिक अच्छी तरह बोल सकता हूँ पर मैं आपको यह बता दूँ कि जब म अँग्रेजी बोलता हूँ तो मैं अधिक संतुष्ट रहता हूँ और अँग्रेजी में बोलना मेरे लिए श्रमनाशक भी है। जब मैं हिंदी मराठी या गुजराती में बोलता हूँ तो अधिक धरलूपन का अनुभव करता हूँ और अधिक तजी स तथा सक्षम में बोल सकता हूँ। अँग्रेजी न हमें ब्रिटिश मनी नरीका उपयुक्त पुर्जा बनाने वाला काम ही किया है और हममें उन्होंने आभासी सफलता प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी अँग्रेजी को अपनाकर हमने यह सिद्ध किया है कि हमने भौतिक स्वतंत्रता भल ही प्राप्त कर ली है किन्तु अँग्रेजियतकी मानसिक गुलामी से अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं। उमस अभी तक हम जकड़ हुए हैं। क्या हम हम नामना म मुक्त न हों?

हमारी संस्कृति में ही इतना कुछ है कि हम उमस बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें दूसरी भाषा या दूसरे राष्ट्र का महत्त्व की आवश्यकता नहीं है।

विदेशी भाषा हम सीखें हमें जाननी चाहिए और सम्भवतः अँग्रेजी क्योंकि उससे २०० वर्षों से हमारा संपर्क रहा है और उस हमने सीखा है पर विचारणीय यह है कि क्या वह हम आत्म सम्मान की ओर ले जाएगी? क्या यह कम आश्चर्य की बात है कि हम अँग्रेजी बोलने में तो गौरव का अनुभव करें किन्तु अपनी ही भाषा बोलने में गलतियाँ करें? अब इस पर आप सम्प्रीतिपूर्वक विचार करें और सोचें कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाने से अनिश्चित म तो और कोई रास्ता नहीं दखता।

अँग्रेजी न भी इतनी शक्ति नहीं है पाई? महज इसी से कि उमने अपना साम्राज्य स्थापित किया और हम पर लाद दी गई किन्तु हम

साम्राज्य स्थापित करना नहीं चाहते। हमारा अत्यंत विशाल देश है अतः हमें हीन भावना का अनुभव नहीं करना चाहिए और न हममें उच्च शक्ति या हीन शक्ति होनी चाहिए। हममें केवल इच्छा शक्ति हो अन्य कोई शक्ति न हो; अतः चली आ रही शिखा गद्दियों के परिवर्तन के प्रयत्नों में अधिक समय लगाया जाएगा तो देश का ही नुकसान होगा।

इस देश में भी प्रतिभाशाली लोग हैं जिनकी तुलना दुनिया के किन्हीं भी प्रतिभाशाली लोगों से की जा सकती है। विश्व भ्रमण के बाद मैं तो इस विचार का हूँ कि अन्य देशों की अपेक्षा इस देश में प्रतिभाशाली लोग अधिक हैं।

मैं जानता हूँ कि प्रचलित परीक्षा पद्धति के भी कारण हैं। छात्रों को बुराइयों से भी मे अवगत हैं। उन बुराइयों को हमें शीघ्र से शीघ्र दूर करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि सभी स्वर्द्धा-परीक्षाओं का माध्यम प्रादेशिक भाषाएँ हों। भाषा को प्रयोग का अवसर मिलने पर यह विवक्षित होता है अंग्रेजी में भी उचित इसी कारण आई है। अंग्रेजी साम्राज्य के कारण यह हम पर थोपी गई। मुक्त लोगों को यही यकीन दिलाना है, उनमें विश्वास पैदा करना है। मैं नहीं जानता कि हमें क्या हो गया है? भगवान के लिए इस पर विचार करिए और इस मलयकत सभी को सुधारने में हमारी मदद कीजिए। यह हमारे पूर्ण विकास में तथा हमारे देश के विकास में बाधक है। इस मुद्दे की अत्यधिक आवश्यकता है।

यह भी कहा जाता है कि उपाधियों को नियमितता से अलग कर दिया जाना चाहिए। यह भी गलत धारणा है। हमें जाँच के लिए कुछ न कुछ नियम तो निर्धारित करना ही होगा। यदि आप शिक्षा को वैज्ञानिक और युक्ति युक्त बना देते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं है। अन्यथा यदि आप उपाधियों की उपलब्धि को हटा देते हैं तो हर जगह प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यासी बन जाएगा और फिर उनमें से स्वयं के लिए योग्य व्यक्ति के चुनाव का कार्य बहुत मुश्किल हो जाएगा।

परीक्षाओं को हटा देने से हम कैसे जान पाएँगे कि छात्र ने कुछ पढ़ा है। मान लीजिए कि कोई छात्र तेरह वर्षों तक स्कूल या कॉलेज

में उपस्थित रहा और उसे इसी कारण पी एच डी की उपाधि दे दी गई तो क्या उसे उचित शिक्षा माना जाएगा ? किसी न किसी रूपमें परोक्षावा होना तो अनिवार्य है फिर चाहे वह मात्तात्मक हो मायिक हो या रायिक । हाँ, वह वैज्ञानिक एवं युक्ति-युक्त हो । आजकल नकल करने की मानी है और यह आज की शिक्षा पद्धति है जिनके हम धिक्कार है । इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना है । आज की शिक्षा हमें मग आत्म निर्भरता आत्म विश्वास एवं भय से मुक्तता नहीं देती । मानव-विकास के लिए ये गुण अत्यंत आवश्यक हैं जो शिक्षा द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं ।

आज के पाठ्यक्रम अत्यंत प्रोक्षित बना दिए गए हैं । यह भी एक परा ही है । मैंने देखा है कि ८ वें ९ वें दर्जों में मग विषय गव गग है । मैंने देखा कि छात्र को इतनी कितारें से जानी पडती है कि जिनको गग उठा नहीं पाता । मैं तो बी ए की कक्षा में इनसे आगे कितारें भी नहीं स जाता था । मैं नहीं जानता कि य छात्र हम लोग म भी कुछ अधिक सीखते हैं । एक बात यह और है कि शिक्षा में हर बार कुछ न कुछ जोड़ा जाता है, या तो सभी विषय या पुस्तकें जोड़ दी जाती हैं या फिर यप जोड़ दिए जाते हैं । शिक्षा सरचना म स्प अभी १० + २ + ३ है । मैं इस का जय नहीं ममन पा रहा हूँ । मेरी दृष्टि में तो तीन स्पष्ट श्रेणियाँ हैं—प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालयीन । मेरी दृष्टि में प्राथमिक ७ या ८ वर्ष होना चाहिए । मैं तो ७ वर्ष पमद करूँगा । जहाँ यह ७ वर्ष हो वहाँ ७ + १ + २ और जहाँ ८ हो वहाँ ८ + ४ + ३ हो सकता है । और फिर इस करने का क्या अर्थ है कि हायस्कूल की शिक्षा क बाद दो वर्षों म कुछ तभीकी या औद्योगिक शिक्षा दी जाएगी । यह एकदम तुरत देना कैसे सम्भव होगा ? इससे एक दूसरा अमतोप पैदा होगा ।

आज इस बात की आवश्यकता है कि राष्ट्र के विकास हेतु शिक्षा गुरु में अत तक सभी तबको के लोगो के लिए किसी न किसी उत्पादन प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हो जिस स के नौकरों की ओर न दोड़ें ।

आजकी हमारी शिक्षा-व्यवस्थाका देश के गरीब लोगों और गाँवों में रहनेवालों के साथ मेल नहीं बैठता इसलिए कोई न कोई ध्येय सामने रखकर हमें अपनी शिक्षा-पद्धति पर विचार करना होगा। हमारी शिक्षा कम खर्चीली हो। जरा महाविद्यालयों के छात्रों के जीवन की ओर तो देखिए विशेषतः आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के तथा इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों के जीवन को देखिए। वे जितना रुपया प्रतिमाह खर्च करते हैं यह केवल उनकी झक मात्र है। उनका यह खर्च हमारे जीवन के लिए यदापि उपयुक्त नहीं है। ऐसे लोग गाँवों में जाकर नहीं रह सकते। मेरी गय में शिक्षा-पद्धति को सामान्य लोगों के जीवन के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक है कि उन्हें मूलभूत और सीधे-न्मादे जीवन की शिक्षा दी जाए। विद्वत् विचारियों और स्कूलों के छात्रायासों में भी विद्यार्थियों का जीवन सादा रहना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए आवश्यक चीजोंका उत्पादन करने योग्य बने।

पब्लिक स्कूलों का उल्लेख करते हुए प्रधान मंत्रीजी ने कहा— जब अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग-अलग तरह के स्कूल हैं तो सभी को शिक्षा के समान अवसर कैसे दिए जा सकते हैं? यद्यपि पब्लिक स्कूलों को एकदम से बन्द नहीं किया जा सकता तथापि कोई ऐसा विकल्प ढूँढ़ना होगा जिससे सभी को समान रूप से शिक्षा दी जा सके।

देश में चल रहे पब्लिक स्कूल आज समाज में विषमता को बढ़ा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था को पनपने से रोकना चाहिए। यह व्यवस्था वर्ग भेद को जन्म देती है जो समाज के लिए घातक है। जब तक समानता के आधार पर सभी को एक जैसी शिक्षा नहीं मिलेगी, हम नए समाज की रचना नहीं कर सकेंगे। समानता हमारी संस्कृति की देन है। अतः इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों को समान महत्ता दी जाए। जो व्यक्ति अधिक सेवा करता है श्रेष्ठ है न कि वह जो अधिक व्यय करता है।

मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है और धक्का लगता है कि हमारे कुछ शिक्षित व्यक्ति कहते हैं कि जननत्र भाग्न के लिए उपयोगी नहीं है। भारत में तो जननत्र तब से है जब दुनिया इनके विषय में २५०० वर्ष पहले जानती तब न थी। जननत्र का उल्लेख पूरी तरह से ऋग्वेद में मिलता है। यही कारण है कि हम सब कुछ सीखने के लिए सब जगह जाते हैं। आपने जो सीखना है वह सीखें लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ है उसे भूँ नही। उसे हम पहले पूरी तरह सीखें और फिर अन्य बातें सीखें।

मैंने आपका काफी समय ले लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उपकुलपतियों के साथ शिक्षा पर मैं पुनः चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ भी मैं केवल उद्घाटन करने के लिए ही नहीं वरन् आपसे चर्चा करने और यह कहने आया हूँ कि आप सब कुछ ऐसे ठोस निर्णय करें गिनपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उपकुलपतियों के अधि-वेशनमें विचार किया जा सके तथा ससद में विचार किया जा सक।

अपनी इस अपील के साथ मैं इस सम्मेलन के उद्घाटनकी घोषणा करता हूँ।

संस्था कुल

गांधी स्मारक निधि का मासिक

सम्पादक - श्री पूर्णचन्द्र जैन

वार्षिक शुल्क-५ रुपये,

एक प्रति-५० पैसे

रचनात्मक प्रवृत्तियों, कामों सर्वोदय संगठन एवं

राष्ट्रीय हलधरों की जानकारी देनेवाला

एक प्रभावशाली माध्यम

संपर्क करें-ध्यवस्थापक, संस्थाकुल

गांधी स्मारक निधि,

राजघाट, नई दिल्ली-२

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली

कुछ रचनात्मक सुझाव

डॉ. श्रीमन्नारायण

[राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के अवसर पर प्रस्तुत सुझाव जो सम्मेलन की चर्चा के आधारभूत विषय थे]

आजादी के पहले और बाद के कई दशकों से भारत की शिक्षा-पद्धति की पुनर्रचना के सवाल पर बहस-मुवाहिरो होते रहे हैं और इस सबध में तरह-तरह के प्रयोग किए जाते रहे हैं। इस बीच अनेक समितियों और आयोगों ने केंद्र तथा राज्य सरकारों के मामले अपनी अपनी निकायिनी रखी है। इस मयके बानजूर हमारी शिक्षा-पद्धति अब भी जहाँ की नहीं पड़ी हुई है, और उसमें राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होने की कोई क्षमता दिखाई नहीं दे रही है। इस वर्ष के आम चुनावों के फलस्वरूप कई दिल्ली और कई राज्यों में भी नए दल की सरकार बनी है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि १९६८ में स्वीकृत शिक्षा सबधो राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में जनता पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसंधान आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई और केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री डा. प्रतापनन्द चंदर महात्मा गांधी के आदर्शों और आकांक्षाओं के अनुसार भारत में दीक्षणीय सुधार पर अपने सुर्चित विचारों का संकेत दे चुके हैं। अब प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयीन स्तर तक की नई शिक्षा-प्रणाली का अंतिम रूप और विषय तय करने और माय ही उसपर तत्काल अमल के स्पष्ट निर्देशों की व्यवस्था में देरी करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

सक्षिप्त इतिहास

हालीय वर्ष पूर्व, अक्टूबर १९३७ में, शिक्षा मंडल के रजत जयंती समारोह के अवसर पर, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का संयोजन किया गया

धा, उमकी अध्यक्षाता स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। इस परिपद की सिफारिश थी कि पूरे देश में सात माल की निगुलर और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और “इस अवधि में सारी शिक्षा गरीब-श्रम के द्वारा किसी न किसी उत्पादक काम के माध्यम से दी जानी चाहिए तथा जिन अन्य योग्यताओं का विकास या जो अन्य प्रशिक्षण देना आवश्यक हो, वह मग्न अभिन्न रूप से यथासंभव विद्यार्थी के परिवेश से जुड़ा हुआ हो।” बाद में जाकिर हुसैन समिति ने इस पद्धति पर एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया और इस तरह वह प्रणाली सामने आई जिसे हम बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से जानते हैं।

इस परिपद के दौरान और बाद में भी गांधीजी ने यह बात काफी स्पष्ट कर दी थी कि “बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य किसी दस्तकारी के माध्यम से बच्चे का शारीरिक बौद्धिक तथा नैतिक विकास है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “इस शिक्षा पद्धति की सफलता की कमौंटी इसका स्वावलम्बी रूप न होकर यह बात है कि शिक्षार्थी के संपूर्ण मानव-व्यक्तित्व को यात्रिक रीति से नहीं बरन शास्त्रीय ढंग से किसी दस्तकारी की शिक्षा द्वारा निम्नार दिया गया है।’ आगे चलकर आचार्य विनोबा भावे ने समझाया कि गांधीजी ने एक नए प्रकार के अद्वैत का—कर्म और ज्ञान के अद्वैत का—विकास किया है। इस तरह हर स्तर पर शिक्षा समाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक प्रवृत्तियों के जरिये दी जानी चाहिए और विभिन्न विषयों के ज्ञान का राष्ट्रीय आयोजना तथा विकास-कार्यों से ठीक तालमेल होना चाहिए। शिक्षण तथा रचनात्मक काम का यह पारस्परिक सामंजस्य बुनियादी शिक्षा का सार-सत्त्व है।

१९३८ में कई राज्यों की कांग्रेसी सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी उमंग और उत्साह के साथ बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को दाखिल किया। किन्तु १९३९ में द्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भ होते ही उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। फलतः बुनियादी शिक्षा को गंभीर

आघात पहुँचा और देश के आजाद होने के पूर्व १९४७ तक इस क्षेत्र में कोई उत्त्प्रेक्षणीय सफलता नहीं मिली। राधाकृष्णन् विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (१९४९) ने बुनियादी शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए देश में देहाती कानूनों और देहाती विश्वविद्यालयों की स्थापना की जोरदार सिफारिश की। आगे चलकर माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५३) ने भी माध्यमिक शिक्षा को एक ऐसा विराग-विद्रुमाना, जहाँ पहुँचकर विद्यार्थियों को जीवन में अपनी-अपनी पसन्द के काम धंधों में लगने के योग्य बन जाना चाहिए। इस आयोग की सिफारिश थी कि माध्यमिक शिक्षा बुनियादी शालाओं से घनिष्ठ रूप से जोड़ दी जाए। १९५७ में शिक्षा मंत्रालय ने 'द फ़ांन्सेप् ऑफ़ बैमिक एजुकेशन' (बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना) शीर्षक से एक बहुमूल्य पुस्तिका प्रकाशित की। उसमें इस बात को दोहराया गया था कि 'जिम बुनियादी शिक्षा की कल्पना और व्याख्या महात्मा गांधी ने की वह तत्त्वतः जीवनोपयोगी शिक्षा है, और जो इसमें भी बड़ी बात यह है कि वह जीवन के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है। इसका स्वयं अंतर्गत ऐसी समाज-व्यवस्था की रचना है जो शोषण और हिंसा से मुक्त होगी।' यही कारण है कि "उत्पादक, सृजनात्मक और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी ऐसे कार्य को बुनियादी शिक्षा में केन्द्रीय स्थान प्रदान किया गया है जिसमें सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लड़के-लड़कियाँ शामिल हो सकते हैं।" यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई कि "बुनियादी शिक्षा का मूलिक उद्देश्य साधारण नहीं है। उसका उद्देश्य बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा विकास है जिसमें उत्पादक कार्य-कुशलता का भी समावेश होगा।" विभिन्न स्तरों पर बुनियादी शिक्षा के अमल में, बिना किसी मानसिक संकोच के, आज भी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित इस महत्वपूर्ण पुस्तिका से मार्ग-दर्शन लेते रहना जरूरी है।

कोठारी शिक्षा आयोग (१९६६) ने गांधीजी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा :

बुनियादी शिक्षा के मुख्य सिद्धान्त इतने महत्वपूर्ण हैं कि सभी स्तरों की शिक्षा-पद्धति को अपना विषय और रूपाकार उनसे मार्ग-दर्शन लेकर निश्चित करना चाहिए। यह हमारे मुझाबों का सार है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी एक स्तर की शिक्षा को बुनियादी शिक्षा की संज्ञा देने के पक्ष में नहीं हैं।" आयोग ने बुनियादी शिक्षा के आवश्यक तत्वों का भी निर्देश किया और उन्हें इन शब्दों में परिभाषित किया " (१) शिक्षा में उत्पादक प्रवृत्ति, (२) उत्पादक प्रवृत्ति तथा भौतिक एवं सामाजिक परिवेश से पाठ्यक्रम का अनुबन्ध, और (३) शाला तथा स्थानीय जनसमुदाय के बीच अंतरंग सम्बन्ध।" फिर भी न जाने क्यों आयोग ने यह स्पष्ट कर देने के बाद भी कि यह परिकल्पना "बुनियादी शिक्षा की उत्पादक प्रवृत्ति की परिकल्पना के समान ही है," और इसलिए इसे प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्व-विद्यालयीन स्तरों की "शिक्षा का अभिन्न अंग" मानना चाहिए, इसके लिए 'कार्य-अनुभव' (वर्क एक्सपीरियन्स) शब्द का प्रयोग किया।

१९६८ में भारत सरकार के शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में इस बात को दोहराया गया कि "शिक्षा-पद्धति का काम राष्ट्रीय सेवा और विकास से प्रतिबद्ध आचारखान सुशोध्य युवक-युवतियाँ को तैयार करना है।" इसमें "शिक्षा-पद्धति को जन-जीवन से और भी घनिष्ठ बनाने के लिए उसके रूपान्तरण" की परिकल्पना थी, और "विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के विकास और नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के पोषण संवर्धन" पर जोर दिया गया था। प्रस्ताव में सुझाव दिया गया था कि "कार्य-अनुभव तथा राष्ट्रीय सेवा को, जिसमें राष्ट्रीय सेवा और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य और चुनौती-भरे कार्यक्रमों में योगदान करना भी शामिल हो, शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए।" साथ ही कोठारी आयोग द्वारा सुझाई १०+२+३ की शिक्षा पद्धति को अपनाने की भी सिफारिश की गई थी।

अक्टूबर १९७२ में शिवा मंडल और अगिल भारत नई तालीम समिति की ओर से सेवाग्राम में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का संयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था और उसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, कुलपति तथा देश-भर से अनेक शिक्षा-शास्त्री शामिल हुए थे। उनकी ओर से एक सर्वानुमती प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें यह सिफारिश की गई कि "सभी स्तरों की शिक्षा गाँवों और सहरो दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास के जुड़ी ऐसी उत्पादक प्रवृत्तियों के माध्यम से दी जानी चाहिए जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हों।" प्रस्ताव में तीन मूलभूत बातों पर भी जोर दिया गया था :

- (१) शैक्षणिक कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य-विशेष के उपयोग द्वारा स्वावलम्बन, आत्मविश्वास और श्रम की गरिमा की भावनाओं का पोषण;
- (२) विद्यार्थियों और अध्यापकों को सामुदायिक सेवा के अर्थ-वान कार्यक्रमों में प्रवृत्त करके राष्ट्रीयता तथा सामाजिक दायित्व के बोध का विकास, और
- (३) विद्यार्थियों के मानस में नैतिक तथा चारित्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, सभी धर्मों की मूलभूत एकता की समझ और उनके प्रति समान आदर की भावना पैदा करना।

शिक्षा-सम्वन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति तथा शिक्षा-मंत्रियों और कुलपतियों के सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने पंचवी पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव तैयार करते हुए १०+२+३ की नई शैक्षणिक पद्धति को स्वीकार किया और यह मतव्य भी प्रवृत्त किया कि इस पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इसे अपना ले। कई राज्य इसे अपना चुके हैं और अन्य कई राज्यों ने दो-तीन साल में इसे अंजाम देने का वादा किया है। शिक्षा मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर

दिया कि, "शिक्षा की विकास विषयक आवश्यकताओं और गोजगार के अवसरों में ठीक संवध होना चाहिए और 'कार्य अनुभव' को पाठ्य-क्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।" राष्ट्रीय शैक्षणिक अनु-सन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने 'माइड-लाइन्स फॉर वर्क एक्सपी-रियन्स' (कार्य-अनुभव की मार्गदर्शिकाएँ) शीर्षक एक पुस्तिका में कार्य-अनुभव को "शिक्षा का अभिन्न अंग" बनाने पर काफी बल देते हुए इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक संस्थाओं में ऐसी चीजें तैयार की जाएँ जो बिल्कुल ठीक और सप सके। सचिन सच कह तो शिक्षा की प्रथम दस साला अवधि के लिए परिषद् ने जो पाठ्यक्रम तैयार किया उसमें 'कार्य-अनुभव' को बहुत कम समय दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर इसे शाला के कार्यों के लिए निर्धारित कुल समय का सिर्फ २०-२५ प्रतिशत हिस्सा ही दिया गया है। माध्यमिक तथा उच्च स्तरों पर सप्ताह के अठ्तालीस घंटों (पीरियड्स) में से केवल पांच घंटे 'कार्य-अनुभव' को दिए गए हैं। इस प्रकार स्कूली स्तर पर बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों पर वास्तविक अमल बहुत ही कम हुआ है। यह काम ठीक तैयारी के बिना लापरवाही और बिना मन के किया जाता रहा है। इसका उचित अमल के लिए पहले से जितना कुछ कर रचना चाहिए था वह नहीं किया गया।

बुनियादी शिक्षा .

अब चूंकि जनता सरकार ने गम्भीरतापूर्वक यह संकल्प लिया है कि वह राष्ट्रीय आयोजना को गांधीवादी मूल्यों के अनुरूप ढालेगी और उन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखकर शिक्षा पद्धति की पुनर्रचना करेगी, इसलिए बहुत आवश्यक है कि महात्मा गांधी की कल्पना की बुनियादी शिक्षा को हर स्तर पर, बिना किसी हिचकिचाहट के, व्यवस्थित और ठीक ढंग से दाखिल किया जाए। मुझे इसमें तनिक भी संन्देह नहीं कि बुनियादी शिक्षा कोई 'गांधीवादी सनक' नहीं, बल्कि शिक्षा-क्षेत्र के अधुनातन चिन्तन पर आधारित एक ठोस योजना है। 'यूनेस्को' द्वारा नियुक्त शैक्षणिक विकास-समि

अंतरराष्ट्रीय आयोग ने भी 'लरनिंग टु बी' (जीने की शिक्षा) शीर्षक अपने प्रतिवेदन में इसे अत्यंत महत्व की बात बताया है कि "अध्यापन को विद्यालय की चार दीवारी से बाहर लेजाकर और शैक्षणिक प्रयोजनों के निमित्त अनेक प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक प्रवृत्तियों का उपयोग करके" हर व्यक्ति को "जीवन-पर्यन्त शिक्षा देने" की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों की शिक्षा-व्यवस्था के लिए प्रतिवेदन में 'बुनियादी शिक्षा' शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है, जब कि स्वयं अपने देश में हम इन शब्दों से आखें चुराते जान पड़ते हैं, मानो 'बुनियादी' शब्द से हमारे शिक्षा-शास्त्रियों को एक प्रकार की चिड़ पैदा हो गई है।

कई वर्ष पहले जब मैं न्यूयार्क में प्रोफेसर जॉन ड्यूई से मिला था तो उन्होंने मुझे अपनी यह निश्चित राय बताई थी कि शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी के विचार "खुद उनके शिक्षा-शास्त्र से कई कदम आगे हैं। डाक्टर गुनार मिरडाल ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'एशियन ड्रामा' में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "बुनियादी पद्धति की ओर उन्मुख प्राथमिक शिक्षा, भारतीय शांताओं के पाठ्यक्रम और अध्यापन-विधि में सुधार की तत्पर आवश्यकता का आदर्श समाधान हो सकती है।" अपनी एक हाल की कृति "एजुकेशन फॉर सेल्फ-हेल्प" (स्वावलम्बन के लिए शिक्षा) में यूनाइटेड किंगडम-निवासी प्रोफेसर कैसल ने वर्धा की बुनियादी शिक्षा-योजना के संबंध में कहा है कि यह "भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही दिलचस्प चीज है और सम्भावना है कि इसके परिणाम महत्वपूर्ण निवर्तेंगे। "बुनियादी शिक्षा के सफल न होने का कारण यह नहीं है कि इसे आजमा कर देखा गया और यह विफल रही, बल्कि यह अभी तक ठीक से आजमाई ही नहीं गई है। डॉ. इवान इलिच ने तो इससे भी एक कदम आगे जाकर एक ऐसे समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है जिस में आज के विद्यालयों का अस्तित्व मिट जाएगा, पारंपरिक शैक्षणिक ढाँचा अतीत की चीज बन जाएगा, और घर, सेत तथा चत-बारखाने जीवन-भर की व्यावहारिक शिक्षा देने के केंद्र बन जाएंगे।

जनता पार्टी ने सभी नागरिकों को पूरा रोजगार देने और "हर व्यक्ति को गरीबी रेखा में ऊपर ले जाकर एक दशक के अन्दर दरिद्रता का मिटा देने का वादा किया है। इसकी आयोजना-विषयक नई प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि ग्रामोत्थान तथा लघु ग्राम्य और कुटीर उद्योगों को विकेंद्रीकृत क्षेत्र में सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा। स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये बिना इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति असम्भव होगी। जनता सरकार के चुनाव घोषणापत्र के अनुसार 'शिक्षा की विषय-वस्तु प्रवृत्ति-मूलक (फनक्शनल) होनी चाहिए, और उसे जन-जीवन से तथा जिस परिवेश में वह दी जाए उससे संबद्ध होना चाहिए साथ ही यह भी बहुत आवश्यक है कि वह सामाजिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई हो। 'कार्य अनुभव' के द्वारा शिष्याओं के मानस में धर्म की गरिमा प्रतिष्ठित की जानी चाहिए।" इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि शिष्या के प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक के तमाम स्तरों पर बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त सुनिश्चित रीति से अधिलम्ब दाखिल किए जाएँ। गाँव के विकास और कृषि से संबद्ध उद्योगों के निमित्त पूरक प्रशिक्षण मण्डलों की स्थापना करना निःसंदेह समय-शक्ति और साधनों की बरबादी सिद्ध होगी। भारत-जैसा गरीब देश को यह बहुत भारी पड़ेगा। राष्ट्रीय आयोजना की नई प्राथमिकताओं की जड़ें पूरी करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की व्यवस्था स्कूलों और कानूनी को ही करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में शिक्षा का विविध सामाजिक-आर्थिक वायक्रम से अभिन्न रूप से संबद्ध होना जरूरी है। इसमें शिक्षा और विकास प्रयत्न दोनों समूह और प्राणवान बनेंगे।

सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा

भारतीय संविधान के ४५ वे अनुच्छेद का बहना है कि 'राज्य चौदह वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयत्न करेगा।' इस निर्देश के अनुसार अधिकांश राज्यों ने आठवें दशक तक सार्वजनिक प्राथमिक (बुनियादी) शिक्षा की

व्यवस्था कर दी है। साधारणतः प्राथमिक विद्यालयों की पहली कक्षा में बच्चे को पूरे छ साल का हो जाने पर दाखिल किया जाना चाहिए। नई शिक्षा-पद्धति में दस साल की स्कूली शिक्षा की तजवीज है। इसके बाद दो साल में समाप्त हो सकने वाली 'टर्मिनल नेचर' की व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। लेकिन हमारे आर्थिक साधनों को देखते हुए १६ वर्ष की उम्र तक दस साल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना व्यावहारिक चीज नहीं होगी। गुजरात विश्व-पीठ के अपने हाल के दीक्षान्त भाषण में प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की अवधि केवल सात साल होनी चाहिए। लेकिन सविधान के निर्देश को ध्यान में रखते हुए देश-भर के सभी बच्चों के लिए चौदह साल की उम्र तक ७ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना वाछनीय होगा। जाकिर हुसैन समिति ने भी आठ साल की अवधि की सिफारिश की थी। इस अवधि में विद्यार्थियों को युनिटादी शिक्षा के सिद्धान्तों के अनुरूप सृजनात्मक प्रवृत्तियों के माध्यम द्वारा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी शिक्षा दी जानी चाहिए।

शिक्षा-क्रम में उत्पादन कार्य के लिए पूरी अवधि का लगभग आधा समय दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों को भारत की सामाजिक संस्कृति की विरासत से भी अवगत कराना चाहिए, अर्थात् उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों, अहिंसा, सामाजिक न्याय और सर्वधर्म-समभाव की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। कहने की जरूरत नहीं कि प्राथमिक या युनिटादी स्तर के पाठ्यक्रमों में भाषा, प्रारम्भिक विज्ञान, गणित, स्थानीय भूगोल और आरोग्य तथा सफाई से संबंधित युनिटादी बातों— जैसे प्राकृतिक-चिकित्सा द्वारा रोग-निरोधक उपाय, जड़ी-बूटियों का उपयोग आदि— को भी शामिल किया जाना चाहिए।

यह बहुत आवश्यक है कि नए ढंग की प्रारम्भिक या युनिटादी शिक्षा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक साथ आरम्भ की जाए। गाँवों और शहरों में अपनाई जानेवाली उत्पादन प्रवृत्तियाँ तो

अलग अलग प्रकार की होंगी, लेकिन 'कार्य-विशेष द्वारा ज्ञानार्जन का मुख्य सिद्धान्त', सभी स्कूलों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण लोगों के मन पर यह छाप न पड़े कि उन्हें घटिया किस्म की शिक्षा दी जा रही है। आरम्भ में हमने मिर्क देहाती इलाकों में बुनियादी शालाएँ खोलकर यही भूल को, उसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। १९३८ में राज्यों में जो कांग्रेसी सरकारें बनी उनके सीमित आर्थिक साधनों को देखते हुए गांधीजी यही चाहते थे कि बुनियादी शालाएँ पहले गाँवों में खोली जाएँ। तीस माल की राजनीतिक स्वतंत्रता और आयोजित आर्थिक विकास के उपरान्त अब शिक्षा के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कोई दुराभाव नहीं रहे जा सकते।

इसी वर्ष अगस्त महीने में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने मिकारिग की थी कि छठी आयोजना के अंत तक मावंत्रिक प्रारम्भिक शिक्षा (६-१४ के आयु-वर्ग के निमित्त) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखना चाहिए। बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य को विकास-खंड स्तर पर तफसीलवार योजनाएँ तैयार करनी चाहिए। निर्धारित अवधि में वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक या गैररسمी शिक्षा भी रखना पड़ेगी जिसमें अंग-कालिक शिक्षण, बहु-बिंदु प्रवेश और लोचदार नीचे के वर्ग से बढ़ाने की पद्धति भी रहे।

माध्यमिक शिक्षा :

माध्यमिक शिक्षा, अर्थात् उत्तर बुनियादी शिक्षा १४ वर्ष की आयु के बाद नवी कक्षा में आरम्भ होनी चाहिए और बारहवीं कक्षा तक पाने १७ साल की उम्र तक चलनी चाहिए। इस प्रकार, माध्यमिक विद्यालयों में जिन चार वर्षों तक शिक्षा दी जाएगी, उनमें से अंतिम दो वर्ष रोजगार के अवसर सुलभ कराने वाले व्यवसायों की शिक्षा

में लगाए जाने चाहिए। चूंकि इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का स्वरूप ऐसा होगा जो शिक्षार्थी को तैयार करके जीवन के लिए एक निश्चित मजिल तक पहुँचा देंगे, इसलिए इन्हें पूरा कर लेने के बाद अधिकांश विद्यार्थी या तो अपना ही धंधा शुरू कर लेंगे या दूसरों के यहाँ चलने वाले अलग-अलग धंधों में खप जाएँगे। लेकिन जो विद्यार्थी भविष्य में कभी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों, उनकी आकांक्षा पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, माध्यमिक शालाओं में अंतिम दो वर्षों तक दो जानेवाली व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए जो आगे विद्यार्थियों के लिए विद्योपार्जन में कोई अवरोध या काम करे। अन्यथा ज्यादातर प्रतिभाशाली बच्चे इस व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर से विमुख हो जाएँगे और जो बच्चे इसे ग्रहण करेंगे उन्हें अल्पबुद्धि माना जाने लगेगा।

यह बड़े दुःख की बात है कि राष्ट्रीय धैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने माध्यमिक शिक्षा की +२ अवस्था का व्यावसायिक और ज्ञान प्रधान (अकादमिक) इन दो धाराओं में बाँट दिया है। व्यावसायिक धारा के विद्यार्थियों से अपना ५० प्रतिशत समय व्यावहारिक कार्य में लगाने की अपेक्षा रखी जाएगी, और शेष समय वे भाषाएँ, विज्ञान और गणित, साहित्य तथा शास्त्रीय विषयों (होम-निटीज) के अध्ययन में लगाएँगे। निस्संदेह, यह बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी शिक्षापद्धति है। लेकिन परिषद् की योजना में ऐसी तजवीज भी है कि ज्ञान प्रधान धारा को चुननेवाले विद्यार्थियों से व्यावसायिक कार्य में समय लगाने की अपेक्षा ही नहीं रखी जाएगी। अपना ७५ प्रतिशत समय तो वे विज्ञान, समाज-शास्त्रों तथा साहित्य-सहित अन्य शास्त्रीय विषयों के अध्ययन में देंगे और शेष २५ प्रतिशत समय भी भाषाओं की शिक्षा लेने और सामान्य अध्ययन में ही लगाएँगे। परिषद् द्वारा पेश की गई योजना में निस्संदेह यह एक गंभीर भूल है। ऐसी योजना पढाई के कमरों में बंद वर्तमान शिक्षा-पद्धति को ही स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होगी और बानेजों तथा स्कूलों की

और भागने का मौजूदा सिलसिला ज्यों का त्यों कायम रहेगा। इस लिए माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायोन्मुख होने की सारी चर्चा कोरा सपना बनकर रह जाएगी। स्वभावतः अधिकांश विद्यार्थी पढाई लिखाई वाली धारा चुनेंगे ऐसे युवक बहुत कम मिलेंगे जो व्यावसायिक धारा को अपना कर योगों की दृष्टि में अपने को 'मदवर्द्धि' सारित कराना चाहें।

परिपद की पुस्तिका में कहा गया है कि अकादमिक धारा के विद्यार्थियों के लिए भी 'कार्य-अनुभव' पर जोर देना अनिवार्य होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें ये विद्यार्थी हर साल कम-से-कम एक महीना कामों कारखानों और स्मॉलरो में काम करना सीखते हुए बिता सकें। यदि इस चीज को अकादमिक धारा के पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शामिल नहीं कर लिया जाता तो यह एक गृभच्छामान बनकर रह जाएगी इस पर अमल कभी नहीं होगा। इसलिए यादनीय यह है कि विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक ही मुख्य धारा हो और साथ में भाषा साहित्य विज्ञान गणित समाज शास्त्रों और राष्ट्रीय विषयों (ह्यूमेनिटीज) के अध्ययन की भी व्यवस्था कर दी जाए। शिक्षा विभाग सम्बन्धी 'यूनस्को' आयोग (१९७२) की यह राय बहुत समीचीन थी 'विभिन्न प्रकार के शिक्षण—जैसे सामान्य बैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक—के बीच की दुर्भेद्य दीवारें गिरा दी जाएं और प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को एक साथ सैद्धांतिक तकनीकी व्यावहारिक और शारीरिक रूप प्रदान कर दिया जाए।"

विभिन्न दलों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण बरके माध्यमिक शिक्षा के ११ वें और १२ वें दर्जों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी ढंग के विविध पाठ्यक्रम मावधानी के साथ तैयार किए जाने चाहिए। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को दाखिल करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्थान विषय में विभिन्न आवश्यक

क्षमता को पूरा करने योग्य शिक्षा की जरूरत है और वहाँ किस तरह के रोजगार की गुंजाइश है, क्योंकि इनके बिना समाज की सच्ची आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। शैक्षणिक विस्तार और आर्थिक विकास की ऐसी व्यवस्थित क्षेत्रीय आयोजना के अभाव में विद्यार्थियों को घोर निराशा ही हाथ लगेगी, और कानेजों में दाखिला लेकर भविष्य के बुरे दिनों को टालते रहने की प्रवृत्ति ज्यों की त्यों कायम रहेगी। इससे शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को जीवन में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार करने के ध्यान से रखे गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

माध्यमिक शाखाओं की नवीं और दसवीं कक्षाओं में किसी विशेष ममुदाय के भौतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोगी ढंग की सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। भाषा, विज्ञान, गणित, समाज-शास्त्र, साहित्य आदि मुख्य विषयों के अतिरिक्त अनेक वैकल्पिक विषय भी रखे जाने चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार चुनाव करके उनका अध्ययन करें। कहने की जरूरत नहीं कि इस स्तर पर भी शिक्षा का केन्द्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादक प्रवृत्तियाँ ही होनी चाहिए। प्रथम मार्चजनिक परीक्षा देश के सारे राज्यों में दस साल के अन्त में समान रूप से आयोजित की जानी चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव आम तौर पर मैट्रिकुलेशन स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद ही किया जाना चाहिए। कारण, इसी उम्र तक विद्यार्थी की बुद्धि इतनी परिपक्व हो सकती है कि वह अपने भविष्य के मन्त्र में सौम्य ममत्व को ही ठीक निर्णय ले सकता है।

लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चार साल की माध्यमिक शिक्षा अविभाज्य इकाई मानी जाए; अंतिम दो वर्षों के पाठ्यक्रमों की शिक्षा की व्यवस्था भी कानेजों में नहीं, बल्कि स्कूलों में ही होनी चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश को ऐसे विद्यार्थियों को कानेज की शिक्षा देना नहीं पुरा सकता जो माध्यमिक शिक्षा पूरी

करके उपयोगी नागरिकों की तरह जीवन-क्षेत्र में प्रवेश कर जाने का इरादा रखते हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए गुंजाइश करने के उद्देश्य से कालेजों को 'कनिष्ठ' (जूनियर) और 'धरोय' (सीनियर) ऐंसे दो हिस्सों में बाँटने की व्यवस्था ठीक नहीं है और इसलिए इमको बन्द कर देना चाहिए।

सामान्य शाला पद्धति :

कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य शाला पद्धति की व्यवस्था होनी चाहिए। जाति, वर्ग या धर्म के किसी भेद-भाव के बिना सभी बच्चों को इन शालाओं में दाखिले का समान अवसर सुलभ होना चाहिए। इन सामान्य शालाओं में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए और उचित अनुशासन के साथ कार्यकुशलता कायम रखनी चाहिए, ऐसी पद्धति सामाजिक समानता तथा राष्ट्रीय एकता में सहायक होगी; और इसके अंतर्गत गरीब और अमीर लड़के साथ-साथ शिक्षा पाएँगे, जिनमें समतावादी समाज के विकास में मदद मिलेगी।

बहरहाल, कम-से-कम मौजूदा पब्लिक स्कूलों से, जो सिर्फ ममूद वर्गों के बच्चों की पहुँच के अन्दर हैं, माफ कह देना चाहिए कि वे अपनी रीति-नीति बदलकर राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति के ढाँचे में अपने को ढालें। इम दृष्टि से उन्हें जो परिवर्तन करने पड़ सकते हैं उनमें शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाने और त्रिभाषा-मूत्र को लागू करने की बातें भी शामिल होनी चाहिए। ये सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेते, महज इसीलिए उन्हें अपने वर्तमान रूप में चलने नहीं रहने दिया जा सकता। ये स्कूल हमारी उमरकी हुई पीढ़ी को एक विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देते हैं और उनका मानसिक सपोषण विदेशी तौर-नरीकों में करते हैं। इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति वर्ग-भेद कायम रखने की ओर बन जाती है और वे भारतीय लोकतन्त्र के बुनियादी तथ्यों के खिलाफ चलते हैं। उन्हें सामान्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार समान शिक्षा की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, साथ ही अपने कक्षाओं के ५० प्रतिशत स्थान समाज के

अब तक माध्यमिक शिक्षा मुख्यतः मध्य और उच्च मध्य वर्गों के बच्चों तक ही सीमित रही है। अब इस स्तर की शिक्षा का नाम अधिकाधिक प्रमाण में सुविधाहीन तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को मिलना चाहिए। इस दिशा में सत्काल कदम उठाने चाहिए, इसमें विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यह काम नये तरीकों को अपनाकर रिया जा सकता है। इन तरीकों में अंश-कालिक और अनीप-चारिक शिक्षण को भी स्थान मिलना चाहिए। गावों के गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को बूढ़ निकालने के लिए सुनिश्चित प्रयत्न किया जाना चाहिए और उदार छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था करके इन प्रतिभा-सम्पन्न विद्यार्थियों को सक्रिय महायत्ना दी जानी चाहिए। संक्षेप में, भारत में समाजवादी समाज की रचना के लिए माध्यमिक स्तर पर सबको शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

यद्यपि सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय मेल-जोल की दृष्टि से सामान्य ज्ञाना पद्धति काफी उपयोगी चीज है, किन्तु राज्य सरकारों को चाहिए कि वे शैक्षणिक संस्थाओं को अध्यापन के तरीकों, परीक्षा-सुधार, पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने और अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्रों में नए-नए प्रयोग करने के लिए निश्चित प्रोत्साहन दें। एकरूपता पर जोर देने का भरोसा यह बदापि नहीं होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में नई-नई गोजों और अनुसंधान की प्रवृत्ति रुक हो जाए। फोठारी-आयोग द्वारा मूझाई गई स्वायत्त कालेजों की परिकल्पना में उपयुक्त सुधार और परिवर्तन करके उसे माध्यमिक शिक्षा पर भी लागू किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप ये संस्थाएँ ऐसे नए सुधार आरम्भ कर सकती हैं जो विभिन्न दिशाओं में शिक्षा के स्तर को उठाने में सहायक हों। तात्पर्य यह कि शैक्षणिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम रहना चाहिए।

विश्वविद्यालयीन शिक्षा :

इस बात पर आम तौर पर मतभेद है कि विश्वविद्यालयीन स्तर पर, प्रथम उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल हो। केन्द्रीय शिक्षा

कमजोर बगों के प्रतिभा-सम्पन्न बच्चों के लिए सुरक्षित रखने चाहिए और इन बच्चों के शिक्षण पर होनेवाला खर्च सरकार को उठाना चाहिए। हमारे अतिरिक्त इन स्कूलों को आठवें दर्जे तक कोई गुत्त नहीं देने देना चाहिए क्योंकि नौदह मान की उम्र तक निगुत्त और अनिरार्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधा जुटाना हमारा सर्वप्रधान दायित्व है। हमने की जरूरत नहीं कि जो पन्निव स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति को स्वीकार करने से इनकार करें उन्हें बिना किसी रिग्रेट उस-मूलाहित के मद पर देना चाहिए। किन्तु ऐसा करते हुए इस बात का ध्यान रखा जा चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३० में अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अधिकारों पर कोई आंच न आए।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुमोदन तथा प्रशिक्षण परिषद और राज्य सरकारों ने दम-भाना स्कूलों शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया है वह सचमुच ही बहुत शोभीला है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं की गणना बहुत ज्यादा है और बच्चों को अपनी पीठ पर अपने भारी बस्ते लादे जैसे-तैसे विद्यालय की ओर जाते देखकर बड़ा दुःख होता है। इनके अलावा पुस्तकीय ज्ञान पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और उत्पादक या सर्जनोत्पन्न कार्य के भाग पर तो वहाँ शायद ही कुछ हो। स्कूलों के पाठ्यक्रम पर विचार करके उनमें बड़े परिवर्तन सुमाने के लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति करके शिक्षा मन्त्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है। आशा है यह समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी और अधिकारी इसकी सिफारिशों पर शीघ्रता से अमल करेंगे। यह काम अगले अगस्तमय सत्र के पूर्व पूरा हो जाए, यह वाछनीय है। पाठ्यक्रम के बोझ को हल्का करने का मतलब शिक्षा के स्तर को कम करना या उसकी गुणवत्ता को घटाना नहीं है। स्कूलों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे छुट्टियों की अवधि काम करके उनका उपयोग सर्जनोत्पन्न प्रवृत्तियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामुदायिक सेवा में करें।

अब नव माध्यमिक शिक्षा मुख्यतः मध्य और उच्च मध्य वर्गों के बच्चों तक ही सीमित रही है। अब इस स्तर की शिक्षा का लाभ अधिकाधिक प्रमाण में सुविधाहीन तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को मिलना चाहिए। इस दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिए, इसमें विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यह काम नये तरीकों को अपनाकर किया जा सकता है। इन तरीकों में अग्र-कालिक और अनौपचारिक शिक्षण को भी स्थान मिलना चाहिए। गांवों के गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को बंद निवालने के लिए सुनिश्चित प्रयत्न किया जाना चाहिए और उदार छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था करके इन प्रतिभा-सम्पन्न विद्यार्थियों को सक्रिय महायत्ना दी जानी चाहिए। संक्षेप में, भारत में समाजवादी समाज की रचना के लिए माध्यमिक स्तर पर मयूको शिक्षा के समान अस्मर सुलभ करने की बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

यद्यपि सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय मूल-जोल की दृष्टि से सामान्य ज्ञान पद्धति काफी उपयोगी चीज है, किन्तु राज्य सरकारों को चाहिए कि वे शैक्षणिक समस्याओं को अत्यन्त से तरीकों, परीक्षा-सुधार, पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने और अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्रों में नए-नए प्रयोग करने के लिए निश्चित प्रोत्साहन दें। एक-रूपता पर जोर देने का नतीजा यह बन्यपि नहीं होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में नई नई न्योजी और अनुमोधान की प्रवृत्ति बढ हो जाए। कोठारी-आयोग द्वारा सुझाई गई स्वायत्त कालेजों की परिकल्पना में उपयुक्त सुझाव और परिवर्तन करके उसे माध्यमिक शिक्षा पर भी लागू किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप ये समस्याएँ ऐसे नए सुझाव आरम्भ पर सफल होती हैं जो विभिन्न दिशाओं में शिक्षा के स्तर को उठाने में सहायक हों। तात्पर्य यह कि शैक्षणिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम रहना चाहिए।

विश्वविद्यालयीन शिक्षा :

इस बात पर आम तौर पर मतभेद है कि विश्वविद्यालयीन स्तर पर, प्रथम उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल हो। केन्द्रीय शिक्षा

सलाहकार समिति के सुझाव के अनुसार सामान्य पाठ्यक्रम (पाठ कोर्स) दो साल का और विशिष्ट पाठ्यक्रम (ऑनर्स कोर्स) तीन साल का रखा जा सकता है। लेकिन यह तय करना देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों पर छोड़ देना बेहतर होगा। विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर दिया है। उसका हेतु यह है कि उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों को मुख्यतः 'बाबूगिरी' के लिए तैयार करने का माध्यम बनकर न रह जाए। कहने की जरूरत नहीं कि विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों को संबंधित क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि उच्चतर शिक्षा पर होने वाले खर्च को एक अच्छे-त्तासे हिस्से का उपयोग युवक-युवतियों को राष्ट्रीय आयोजनाओं के अंतर्गत आवश्यक विशिष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने में हो सके। विश्वविद्यालयों तथा विकास-योजनाओं के बीच ऐसा समन्वय स्थापित करके ही हम आज की इस अव्यवस्थित अमरगति को दूर कर सकते हैं कि एक ओर तो बड़ी संख्या में ऐसे पढ़े-लिखे लोग पड़े हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और दूसरी ओर उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित लोगों के अभाव में बहुत-सी विकास-योजनाओं पर अमल नहीं हो पा रहा है।

स्पष्ट है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को दाखिल करने में विवेक से काम लेना होगा। मसलन, इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा कि पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और अध्यापकों की कहां कितनी सुविधा मुलभ है साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रशिक्षित स्नातको (ग्रेजुएट) की माँग का भी खयाल रखना होगा। नई शिक्षा-पद्धति के अधीन यह आशा की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद कम-से-कम आधे विद्यार्थी या तो अपने प्रयत्नों से अपने-अपने निजी रोजगार आरम्भ कर लेंगे या उन्हें विभिन्न प्रकार के घघों में दूसरों के यहाँ पूरे समय का काम मिल जाएगा। पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों (बडर ग्रेजुएट कोर्सेज) में केवल उन्ही विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो विभिन्न ज्ञान शाखाओं

की उच्चस्तर शिक्षा के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हों और जिनके पास उसके लिए अपेक्षित तैयारी हो। स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) पाठ्यक्रमों में तो दाखिले को और भी सीमित रखा होगा तथा इसके लिए विद्यार्थियों के चुनाव की कसौटी और भी बड़ी रखनी होगी। इस मामले में सुयोग्य और विशेषज्ञता प्राप्त लोगो की हमें सचमुच कितनी आवश्यकता है इस पर ध्यान रखना होगा। भारत-जैसे गरीब देश के लिए यह पुमाने सागव बान नहीं है कि वह स्नातकोत्तर शिक्षा पर लबी-चोड़ी रकमें लगाए और जो लोग ऐसी शिक्षा पूरी करके निकलें वे या तो देश का अपनी प्रतिभा के लाभ में वचिन करके हमारे देशों की जरूरतें पूरी करने बाहर चले जाएँ या यह लाभ पर हाथ धरे हाना बैठे रहें।

समाज के अपेक्षाकृत सुविधाहीन वर्गों के लोगो को उच्चस्तर शिक्षा की विविध सुविधाएँ सुलभ कराने के लिए अग्र कालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए। इनमें रोजगार में लगे नौजवानों को अपनी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि करके अपने-अपने रोजगार-क्षेत्र में तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षा सबधी राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि 'अग्र-कालिक तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रदान की जानेवाली शिक्षा को बड़ी र्त्ता दिया जाना चाहिए जो पूर्ण कालिक शिक्षण को प्राप्त है।'

शिक्षा का माध्यम

अब सब स्वीकार करने लग है कि सभी स्तरों की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। लगभग सभी राज्यों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर यह स्थिति बायम भी हो चुकी है। अगवाद या तो 'पब्लिक स्कूलों' और आज भारतीय समाज द्वारा संचालित स्कूलों या उन राज्यों में ही देखने को मिलते हैं जिनकी सरकारी भाषा अंग्रेजी घोषित की गई है। उच्च स्तर की तकनीकी

और विशेषीकृत शिक्षा देनेवाली अखिल भारतीय संस्थाओं को छोड़ कर अन्य सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में अविलंब, शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जहाँ क्षेत्रीय भाषा-भाषी लोगों के सिवा अन्य भाषाई लोग पर्याप्त संख्या में हों वहाँ हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम वाली कुछ संस्थाएँ चलाई जा सकती हैं।

समान अवगदमिक स्तर कायम रखने के लिए बहुत ही तकनीकी ढंग की शिक्षा देनेवाले कालेजों और विश्वविद्यालयों में अभी कुछ समय और, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए, यह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन कृषि कालेजों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का चयन निस्संदेह एक गंभीर विसंगति है। जब राष्ट्रीय आयोजन में कृषि-विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही हो, तब आवश्यक हो जाता है कि कृषि-शिक्षण संस्थाओं में उच्चतम स्तर की शिक्षा भी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए। निश्चय ही यह चीज कृषि-रसायनों तथा भारत के करोड़ों किसानों के बीच की विशाल खाई को पाटने में किसी हद तक सहायक होगी।

सभी स्तरों की शिक्षा का माध्यम तो अनिवार्य रूप से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही होनी चाहिए, लेकिन सपक भाषा हिन्दी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी का अच्छा काम चलाऊ ज्ञान कराने का अग्रह माध्यमिक और कालेजी दोनों स्तरों पर रखना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा-युक्त को समान रूप से सबको अपना लेना चाहिए और इसके प्रति अन्त और विरोध का भाव छोड़ देना चाहिए। हिन्दी-भाषी राज्यों में विद्यार्थियों को हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा एक कोई आधुनिक भारतीय भाषा, बने तो दक्षिण भारत की कोई भाषा, सिखानी चाहिए, और अहिन्दी-भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि तमिलनाडु सरकार भी इस राष्ट्रीय नीति को स्वीकार करेगी विश्वविद्यालय स्तर पर भी हिन्दी और अंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्य-

क्रम सुलभ बनाने चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने और दृढ़ करने के लिए विद्यार्थियों में इन भाषाओं के ज्ञान की अभिवृद्धि की जा सके।

पाठ्य पुस्तकें

राष्ट्रीय भाषाओं को विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों की स्तरीय पाठ्य पुस्तकें तैयार करना नितांत आवश्यक है। कुछ सान पढ़न शिक्षा मंत्रालय न विभिन्न भाषाओं में विश्वविद्यालयीन पाठ्य पुस्तकें तैयार और प्रकाशित करने के लिए हर राज्य को एक एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की। कुछ राज्यों में इन राशियों का बहुत ठीक उपयोग हुआ है। जरूरी हो तो इसके लिए उन्हें और रकम देनी चाहिए। जब राज्यों में इस महत्वपूर्ण काम को अधिक गंभीरता से हाथ में लेना चाहिए ताकि भारतीय भाषाएँ जिन के सक्षम माध्यम के रूप में विश्वविद्यालयीन स्तर पर अपनाई जा सकें। इसमें देरी करना उचित नहीं है। पाठ्य पुस्तकों को बार बार बदलते रहने की प्रवृत्ति में बचना चाहिए और उनकी कीमत इतनी कम होनी चाहिए जिससे साधारण हैसियत के विद्यार्थी भी उन्हें खरीद सकें। जहाँ तक नए विभिन्न भाषाओं के तकनीकी शब्द एक स होना चाहिए और जहाँ जरूरी हो कम से कम सश्रमण की अवस्था तक अंग्रेजी शब्द भी कोष्ठको में दिए जाएँ तो बेहतर होगा।

भाषा-नीति

राष्ट्रीय गृह मंत्री यह घोषणा कर चुके हैं कि भारत सरकार की भाषा-नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सरकारी कामकाज में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग माय-साय होता रहेगा। प्रधान मंत्री न भी बार बार कहा है कि देश की आवादी के किसी भी वर्ग पर हिन्दी जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी। इसमें इस सन्देश में चलते रहने का विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। साथ ही सभी सश्रमण लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय भाषाएँ अपनी पूरी

उंचाई तक तभी उठ सकती है जब आमतौर पर प्रशासनिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में, उनका प्रयोग रूढ़ हो जाए।

हमारी शिक्षण-संस्थाओं के आत्यंतिक अंग्रेजी-मोह का एक मुख्य कारण यह है कि भारतीय सिविल तथा सैनिक सेवाओं में भरती के लिए ली जानेवाली परीक्षाओं का माध्यम आज भी अंग्रेजी ही है। माता-पिता स्वभावतः यह उम्मीद लगाए रहते हैं कि उनके लड़के-लड़कियाँ सरकारी सेवाओं में स्थान पाएँगे। इन सेवाओं में प्रवेश के निमित्त होने वाली प्रतियोगिताओं में सफल होने का एक मात्र रास्ता यह है कि लिखित तथा मौखिक दोनों परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल की जाए। निश्चय बात है कि आज भी अधिकांश राज्यों में ऐसी परीक्षाओं का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ नहीं, बल्कि अंग्रेजी ही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन प्रतियोगिता-परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी के बजाय क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया जाए। गलत कारणों से अखिल भारतीय प्रतियोगिता-परीक्षाएँ केन्द्रीय स्तर पर हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं ली जा सकती, क्योंकि उस हालत में विभिन्न भाषाओं को इस्तेमाल करनेवाले प्रतियोगियों की योग्यता को परगने के लिए सामान्य मापदंड का प्रयोग लगभग असम्भव होगा। इसलिए उचित यह होगा कि केन्द्र सरकार हर राज्य की आबादी और जय में भारतीय सिविल और सैनिक सेवाएँ आरंभ हुई हैं तबसे उस राज्य के मकल उम्मीदवारों की संख्या, इन दोनों बातों के आधार पर उसके लिए एक 'कोटा' निश्चित कर दें। हर राज्य के निमित्त ऐसा 'कोटा' तय करने के लिए कोई बुद्धिमत्त आधार ढूँढ निकालने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित प्रतियोगिता-परीक्षाओं द्वारा उम्मीदवारों का चुनाव कर लेने के बाद इन सेवाओं के अखिल भारतीय रूप को कायम रखने के लिए उन्हें हिन्दी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान कराया जा सकता है। प्रशिक्षार्थियों को भारतीय इतिहास, संस्कृति, विधान तथा पंचवर्षीय आयोजनाओं की मोटी-मोटी बातों की भी जानकारी हासिल

करनी चाहिए। कुछ साल के अनुभव के बाद हम व्यवस्था पर फिर विचार किया जा सकता है।

भारतीय विश्वविद्यालयों को अंग्रेजी के अलावा और भी विदेशी भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई कारण नहीं कि स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रूसी, चीनी, जापानी तथा हमारे एशियाई पड़ोसियों की अनेक भाषाओं का अध्ययन न करें।

भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत के विशेष महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों को स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर इसके अध्यापन को और अधिक सुविधाएँ देनी चाहिए। चूँकि अधिकतर भारतीय भाषाओं का मूल संस्कृत में है, इसलिए इन भाषाओं के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का एक पत्र अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रतिरिक्त लिपि के रूप में देवनागरी के उपयोग का प्रचार किया जाना चाहिए।

नैतिक शिक्षा

राधाकृष्णन् आयोग और कोठारी आयोग दोनों ने यह सिफारिश की थी कि स्कूलों और कॉलेजों में भी एक स्तरीय तथा विभिन्न चरणों में बँटे कार्यक्रम के अनुसार नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, सभी शिक्षण संस्थाएँ अपना काम कुछ मिनट की सामान्य प्रार्थना, और यह न हो सके, तो मौन प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से कर सकती हैं। सभी धर्मों के प्रति समान आदर का श्रेयस्वर यातावरण तैयार करने के लिए हफ्ते में एक-दो वर्ग ऐसे शिक्षण के लिए अलग से रख दिए जाने चाहिए। आरम्भिक अवस्था में विद्यार्थियों को महान धर्म-गुरुओं, उनकी प्रसिद्ध कृतियों, और सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान मूलभूत शिक्षाओं से अवगत कराना चाहिए। उच्चतर कक्षाओं में विभिन्न धर्मों के सुसनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित दिया जा सकता है। भारत तथा एशिया, अफ्रीका और अमरीका के अन्य विकासशील देशों में बहु भाषी, बहु जातीय तथा बहु-धर्मी समाज की रचना के लिए यह सब अनिवार्य है।

कक्षाओं में धार्मिक शिक्षा देने के अतिरिक्त हमारी शिक्षण-संस्थाएँ वर्ष में पाठ्यक्रमेतर कुछ प्रवृत्तियों का आयोजन करके भी धार्मिक समन्वय और सामाजिक एवता का स्वस्थ वातावरण तैयार कर सकती हैं। आज भारत के सामने अनैतिकता का संकट उपस्थित है और इसलिए तरुण पीढ़ी के मानस पर नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा सर्वोच्च महत्व की बात है। विभिन्न धार्मिक और नैतिक विषयों का अध्ययन करनेवालों को हो नहीं, बल्कि सभी शिक्षकों को इसे अपना दायित्व समझना चाहिए।

परीक्षा-सुधार :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ठीक ही कहा है कि "यदि विश्वविद्यालयीन शिक्षा में कोई एक ही सुधार सुझाने की बात छूटे तो यह है परीक्षा-सुधार की बात।" यह बात प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की परीक्षा-पद्धति पर भी अधिक लागू है। मौजूदा पद्धति विद्यार्थियों की दारौरिक, मानसिक तथा नैतिक क्षमताओं को कुठित करती है। इनके कलस्वरूप अकादमिक स्तर में गिरावट और अनुशासन में शिथिलता आई है तथा प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और डिग्रियाँ पाने के लिए अनुचित और अवाछनीय तरीकों का उपयोग व्यापक हो गया है। इसलिए वर्तमान परीक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन अत्यावश्यक है। विभिन्न समितियों और आयोगों ने समय-समय पर इस विषय की गहरी छान-बीन करके कई सिफारिशें की हैं। लेकिन इस समस्या को ऊपर-ऊपर से हल करने की कोशिश अब कारगर होनेवाली नहीं है। 'अव-व्यवस्था' के स्याम पर ग्रेडिंग सिस्टम दाखिल करने का प्रभाव भी सतही ठहरेगा। आवश्यकता केवल परीक्षा-पद्धति में सुधार की नहीं बल्कि मंगूण शिक्षा-पद्धति में सुधार की है। यदि विभिन्न स्तरों की शिक्षा का केन्द्र उत्पादक और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी प्रवृत्तियाँ बनाई जाती हैं और उसमें समाज की प्रत्यक्ष सेवा के कार्यक्रमों को स्थान दिया जाता है तो विद्यार्थियों का उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षाओं में दाखिल

होना वर्ष के अंत में एक व्यापक परीक्षा पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उत्पादक और पाठ्यक्रम के माप की प्रवृत्तियों में उनके प्रति-दिन भाग लेने पर मुनहसर होगा। ऐसी सह-पाठ्यक्रमीय प्रवृत्तियों में खेल-कूद, समाज सेवा तथा विद्यार्थियों-का सामान्य अनुशासन और आचरण भी शामिल होंगे। वस्तुपरक दृष्टि से आंतरिक मूल्यांकन का मार्ग सुगम बनाने के लिए इन प्रवृत्तियों का तफसील रखना जरूरी होगा। यदि आंतरिक मूल्यांकन के विवरण व्यवस्थित रीति से रखे जाएं और ये विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा बाहरी परीक्षकों द्वारा जांच के लिए भेदा सुलभ रहें तो व्यक्तिगत कारणों से होनेवाली भूलों की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व और उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए व्यावहारिक-कांयों और मौखिक परीक्षाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। संक्षेप में, अंतरिम काल में बाहरी परीक्षा और परीक्षकों की आवश्यकता से छुटकारा पाना भले ही व्यावहारिक न हो, फिर भी आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति पर आज की अपेक्षा बहुत अधिक जोर दिया जाना चाहिए। यदि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त दाखिल कर दिए जाएं तो परीक्षा-मुद्धार की कठिन समस्यां लगभग स्वतः ही हल हो जाएगी।

डिग्रियों और नौकरियों का विच्छेद .

अभी विभिन्न सरकारी विभाग अपने कर्मचारी लोक सेवा आयोगों के माध्यम से, मुख्यतः उम्मीदवारों की डिग्रियों के आधार पर, चुनते हैं। फलतः विद्यार्थियों में डिग्रियाँ हासिल करने के लिए सही-गलत तरीकों से परीक्षाएँ पास करने की प्रबल प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार से नौकरियाँ पाने की सुनदें होती हैं। कई वर्ष पूर्व-केन्द्र सरकार ने इस विषय की गहरी छान-बीन के लिए विशेष समिति नियुक्त की थी। समिति की सिफारिश थी कि भारतीय प्रशासनिक विभागों को अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करने चाहिए और उन्हीं पाठ्यक्रमों के अनुसार उम्मीदवारों की परीक्षा लेकर उनका चयन करना चाहिए। सिफारिश के मुताबिक, ऐसे विभागों को

विश्वविद्यालयों की डिग्रियाँ पानेवालों को ही चुनने का आग्रह छोड़ देना चाहिए। गैर-सरकारी नियोजकों को भी ऐसा ही करना चाहिए। ये पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ग्यारहवें और बारहवें दर्जों में दाखिल किए जा सकते हैं, और इसमें पढ़ाए जानेवाले विषय विभिन्न विभागों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार तय किए जा सकते हैं।

डिग्रियों में नौकरियों को असंगत कर देने से कालेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए अनुचित आपा-धापी बरम हो जाएगी और परीक्षाओं में प्रचलित भ्रष्ट तरीके मिट जाएंगे, इतना ही नहीं इससे सरकार को भी अपने विभागीय कार्यों के लिए बेहतर उम्मीदवार मिल सकेंगे। इस महत्वपूर्ण सुधार को संपन्न करने का एक व्यावहारिक तरीका सरकारी नौकरियों में प्रवेश की उम्र कम कर देना है। उदाहरण के लिए अगर सरकारी नौकरी में प्रवेश करने की १९ साल कर दी जाए तो आज विद्यालयों में बारह साल की उम्र पाने की अधिक सुविधा के स्थान से कालेजों में दाखिला लेने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है यह अपने आप समाप्त हो जाएगी।

राज्य सरकारें तो मुख्यतः राजनीति-उद्देश्यों से प्रेरित होकर, विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक ढंग के नये-नये विश्वविद्यालय स्थापित करने में एक दूसरे से होड़ करती जान पड़ती हैं। यह बहुत ही हानिकार चीज है और इससे देश के सीमित साधनों की बरबादी होती है। इसलिए उच्चतर शिक्षा में इस तरह की बरबादी और जड़ एकरूपता से बचने के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पर कुछ निश्चित अकुल लगाना चाहिए। शिक्षा आयोग की यह सिफारिश बहुत उचित है कि “जब तक विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की सहमति न ले ली जाए और घन की पर्याप्त व्यवस्था न हो जाए तब तक कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।”

उच्चतर शिक्षा के खर्च की व्यवस्था

गांधीजी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह राय जाहिर की थी कि उच्चतर शिक्षा का खर्च राज्य को नहीं बल्कि अपने लिए आवश्यक स्नातको को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न उद्योगों और व्यावसायिक पढ़ियाँ को उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वयं गांधीजी के ही शब्दों में "टाटा कंपनी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह राज्य की देख रेख में इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज चलाए और मिल एसोसिएशन अपनी जरूरत के स्नातको को प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेज चलाए। इस अतिरिक्त इसका भी कोई कारण नहीं है कि उच्चतर शिक्षा पानेवाले सम्पन्न विद्यार्थियों के माता पिता समाज द्वारा उनपर किए जान वाले खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त शुल्क न दें। हाल में आयोजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. त्रिपाठी ने शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त करते हुए कहा "उच्चतर शिक्षा की जो शाखाएँ समाज के लिए बहुत लाभदायक हैं और फिर भी जिनमें विद्यार्थियों के पर्याप्त सख्या में दाखिल होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ कर हमें शेष उच्चतर शैक्षणिक प्रवृत्तियों का खर्च स्वयं शिक्षार्थियों द्वारा उठाए जाने की संभावना का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए।

इस बात पर किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं है कि आबादी के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के लाभ के लिए प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र को विस्तार और समृद्धि प्रदान करने के निमित्त पर्याप्त साधन जुटाने के उद्देश्य से हमारी उच्चतर शिक्षा के वर्तमान व्यय को नियोजित ढंग से कम से कम करने की जरूरत है। विशिष्ट ढंग की राष्ट्रीय योजनाओं के लिए शीघ्र ही कार्यकारी सुलभ कराने के निमित्त उच्चतर शिक्षा का अपना अलग महत्व है इसमें इनकार नहीं किया जा सकता किन्तु इस तथ्य की ओर से भी आँखें बंद नहीं की जा सकती कि भविष्य में भी बच्चों

धो जिनकी संख्या करोड़ों तक पहुँचनेगी, प्रारम्भिक, व्यावसायिक और माध्यमिक शिक्षा मुलभ बनाने के लिए हमें शीघ्र ही आज की अपेक्षा बहुत अधिक धन की जरूरत पड़ेगी।

नई शिक्षा संरचना

इस प्रकार, जैसा कि इस निबन्ध में सुनाया गया है, नई शिक्षा संरचना ८+४+३— अर्थात् आठ वर्ष की अनिवार्य बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक तत्वों की प्रमुखता से युक्त चार वर्ष की उत्तर बुनियादी या माध्यमिक शिक्षा और चार साल की विद्यविद्यालयीन शिक्षा—हो सकती है। बोर्डारी आयोग द्वारा सुझाई गई और मामान्यतया भारत सरकार द्वारा स्वीकृत १०+२+३ की संरचना में उपर्युक्त सुझावों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जो राज्य अब तक सिर्फ सात वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा देते आए हैं उनमें यह संरचना ७+५+३ की हो सकती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मैट्रिकुलेशन परीक्षा सारे देश में समान रूप से दस साल की शिक्षा पूरी होने पर आयोजित की जानी चाहिए।

लेकिन यह बात साफ समझ लेनी चाहिए कि सावधानी के साथ विशद चर्चा के उपरान्त सरकार एक बार जिस किसी संरचना को स्वीकार कर ले उसमें अगले दस पंद्रह वर्षों तक कोई फेर-बदल नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा नीति में बार-बार परिवर्तन करने से तरह-तरह की मानवीय समस्याएँ पैदा होती हैं, इसलिए ऐसे परिवर्तनों से यथासंभव बचना चाहिए।

और कुल मिलाकर देखें तो नई पद्धति और संरचना के अधीन बुनियादी शिक्षा के मौलिक सिद्धान्त की सफलता की आशा रखते हुए उसी समाज में लागू किया जा सकता है जिसमें शारीरिक तथा बौद्धिक श्रम के बीच के अंतर को कम-से कम कर दिया गया है। भारत में भजदूरी और आय की ऐसी नई नीति के अभाव में हमारी शिक्षा प्रणाली को गांधीवादी मूल्यों के अनुरूप नया मोड़ देने की संभावना निश्चित रूप से मृग तृष्णा ही बनी रहेगी। जनता पार्टी के चुनाव-

घोषणापत्र के अनुसार, करों की अदायगी के बाद न्यूनतम और अधिक-तम आयों के बीच के अंतर को कम करके १ २० पर और कालान्तर से १ १० पर लाना होगा।

प्रौढ शिक्षा .

यह मचमुच बड़ी चिंताजनक बात है कि पिछले कई दशकों के दौरान किए गए विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद हमारी आवादी का लगभग ८० प्रतिशत भाग आज भी निरक्षर है। स्त्रियाँ के बीच निरक्षरता का प्रतिशत और अधिक है। लोगों को लोकतांत्रिक समस्याओं के संचालन में बुनियादी स्तर से सहयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करने के लिए ही नहीं, बल्कि उत्पादन कार्यक्रमों, विनियम रूप में कृषि तथा ग्रामोद्योगों से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों के अमल में गति लाने के लिए भी आम जनता की निरक्षरता को मिटाना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास में गति लाने के लिए बड़ी बड़ी औद्योगिक तथा व्यावसायिक संगठनों में भी कार्यकर्त्ताओं को अपने काम के स्थान पर (फक्शनली) साक्षर बनाया जाना चाहिए। इस दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़कर मार्ग-दर्शन करना चाहिए। साक्षरता अभियान के संगठन में शिक्षकों और विद्यार्थियों का सक्रिय सहभाग प्राप्त करना होगा। उनका सहयोग विशेष रूप से सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों के अंग के रूप में प्राप्त करना चाहिए। जैसा कि शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में इंगित किया गया है स्वयं खेती वाली करनेवाले किसानों को शिक्षण देने तथा युवकों को अपने लिए आप ही किसी न किसी रोजगार की व्यवस्था कर लाने के लिए प्रशिक्षित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में गांधीजी के इस विचार को ध्यान में रखना योग्य होगा कि "केवल साक्षरता कोई शिक्षण नहीं है, 'और' प्रौढ शिक्षा बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए।" केवल पढ़न लिखन और कुछ हिसाब जाँडने का ज्ञान कराने के बदले भूमि-हीन श्रमिका, किसानों, कारीगरों तथा कारखानों के मजदूरों के उत्पादन कोशल को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। साक्षरता से

लोगों में बेहतर नागरिकता-बोध जमाने और उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को समृद्ध बनाने की भी आशा की जाती है। शिक्षासंवर्धन यूनेस्को आयोग का मुझाव है कि "साक्षरता कार्यक्रमों को नागरिक जीवन और अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित बुनियादी शिक्षण से जोड़ देना चाहिए।"

अगले चार बरसों में हमें साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक व्यापक जन-आन्दोलन की आवश्यकता होगी। इस आन्दोलन के लिए पूरे समय के कार्यकर्ता रखना बहुत व्ययसाध्य होगा। हो सकता है, यह इतना सखीला निवले कि हमारी हिम्मत इसी शुरू करने की ही न पड़े। इस राष्ट्रीय अभियान में बहुतसी स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकारी नौकरों, वकीला, डाक्टरों और अन्य लोगों की सेवाएँ प्राप्त करनी होंगी। समाचारपत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि जनसंपर्क के साधनों तथा दृश्य-श्रव्य उपादानों का सहो उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षकों और विद्यार्थियों के शिक्षण में चूँकि सामुदायिक सेवा और उत्पादक प्रवृत्तियाँ अनिवार्यतः शामिल रहेंगी, इसलिए उनके शिक्षण के अंग के रूप में उनसे इस कार्यक्रम में सहयोग लेना चाहिए। अकादमिक वर्ष के दौरान सिर्फ चार हफ्ता के लिए वे ऐसे अभियानों में शरीक हों तो यह चीज न तो वैज्ञानिक होगी और न इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा। सच तो यह है कि स्वयं शिक्षा-पद्धति को आद्योपान्त कामवाजी (फमशनल), सृजनात्मक और उत्पादक, सभी कुछ बन जाना चाहिए।

भारत सरकार ने हाल में केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा मंडल का गठन किया है। मंडल ने सिफारिश की है कि पाँच साल के अंदर आवादी के १५-३५ के आयु वर्ग के बीच प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए सभी संभव कोशिश की जानी चाहिए। इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को अपने कार्यक्रमों के बीच पारस्परिक समन्वय स्थापित करना होगा।

स्पष्ट है कि कोई भी शिक्षा-प्रणाली कागज पर चाहे जितनी आकर्षक प्रतीत हो, उसका सफल कार्यान्वयन तो ठीक प्रशिक्षित ऐसे अध्यापकों के बल पर ही संभव है जो कोई बड़ा काम करने के आदर्श और समर्पण की भावना से ओत-प्रोत हों। अपने सम्पर्क में आने-वाली उदीयमान पीढ़ी के चरित्र को सही ढाँचे में ढालना अध्यापक का काम है; वे सच्चे अर्थ में राष्ट्र-निर्माता हैं। इसमें सन्देह नहीं कि विद्यार्थियों को समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने के निमित्त प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें कुछ भी उठा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अध्यापकों के सामाजिक दर्जे को ऊपर उठाने और उन्हें दैनिक आर्थिक परेशानियों से मुक्त करने की जिम्मेदारी राज्य की है। ईंट-सीमेंट और लोहे-इस्पात पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने के बजाय, प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि करना कहीं अधिक लाभकारी होगा। शैक्षणिक सस्थाओं के स्तर का निर्णय उनके भव्य भवनों के आधार पर नहीं, बल्कि उनमें नियुक्त अध्यापकों की योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए।

इस वर्ष सितम्बर माह में सेवाग्राम में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर आयोजित गोष्ठी ने सिकारिश की थी कि बुनियादी शिक्षा के मुख्य सिद्धान्तों को अध्यापक-शिक्षण सहित, सभी स्तरों की शिक्षा में ओत-प्रोत हो जाना चाहिए। "सभी स्तरों के अध्यापक-शिक्षण कार्यक्रमों के अभिन्न अंग के रूप में उत्पादक कार्य और सामुदायिक शिक्षण के समावेश" पर भी गोष्ठी में पूरा मतैक्य था। गोष्ठी का सुझाव था कि "सभी प्रशिक्षण-सस्थाओं को अपने-आपको स्वावलम्बन, सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्थित समुदायों के रूप में संगठित कर ढालना चाहिए।"

इसके अतिरिक्त, उत्पादक तथा सोद्देश्य शिक्षा-पद्धति के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना सीखना चाहिए। इस प्रकार, "सहवीर्य

करवावहूँ" का प्राचीन आदर्श बोरे ऊँने दर्शन की बात नहीं है, बल्कि फलप्रद शिक्षा के लिए सुझाया एक व्यावहारिक मार्ग है। नए अध्यापकों को कृषि तथा कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण देने के बजाय हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कृषक-अध्यापकों या शिल्पी-शिक्षकों के वर्ग का उदय हो और हम अपनी शिक्षण-संस्थाओं की योग्य अध्यापकों की माँग पूरी कर सकें।

माता-पिता का सहयोग -

भारत में शिक्षा पद्धति की पुनर्रचना के काम में सभी स्तरों के विद्यापियों के माता-पिताओं का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। आरम्भिक अवस्था से ही माता-पिताओं को घर और स्कूल दोनों जगहों में अपने बच्चा की प्रगति की ओर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए, और उनके तथा शिक्षकों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। इसके लिए हर शिक्षण-संस्था में सक्रिय अभिभावक-अध्यापक संघ का होना जरूरी है। दोनों का ऐसा पारस्परिक सम्पर्क शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगा और इससे विद्यापियों के व्यक्तित्व का विकास अधिक ठोस बुनियाद पर हो सकेगा। शिक्षापियों को अनुशासित करने और उनके सामान्य आचार-व्यवहार में सुधार लाने के लिए भी माता-पिताओं की सहायता लेने का प्रयत्न किया जा सकता है। दरअसल, हर घर को सच्चे अर्थों में शैक्षणिक विकास की बुनियादी इकाई बन जाना चाहिए। घर और शाला के बीच दो-तरफा समागम होना चाहिए और दोनों को एक-दूसरे के पूरक बनकर एक-दूसरे को समृद्ध करने का काम करना चाहिए।

खेल-कूद -

नई शिक्षा-पद्धति के अंतर्गत हमारे स्कूलों और कालेजों में खेल-कूद का विकास बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। शरीर-स्थलों तथा अन्य मनोरंजनात्मक प्रवृत्तियों की सुविधा उदारता के साथ सुलभ करानी चाहिए। शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के अधीन योगासनो का प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिए। एन सी सी तथा ए एस एस के अतिरिक्त शिक्षण-संस्थाओं में लड़के-लड़कियों

दोनों के लिए स्वर्गति प्रवृत्ति को सुनियोजित ढंग से बढ़ावा देना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में न केवल गैर-मरवारी ढंग से अनुशासन की बहतर भावना का समावेश होगा, बल्कि उन्हें विविध प्रसंगों में सामाजिक सेवा के अवसर भी सुलभ होंगे।

— पर्याप्त वित्तीय साधन की व्यवस्था

ऊपर सूनाए गए ढंग पर शिक्षा पद्धति की पुनर्रचना के लिए स्पष्ट ही अतिरिक्त वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। पञ्चवर्षीय आयोजनों की दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं कि जहाँ तीसरी आयोजना में शिक्षा पर कुल राष्ट्रीय आय का ६.८७ प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान था चौथी में यह प्रतिशत घट कर ५ पर और पाचवी में तो ३.२७ पर आ गया। यह सच है कि यदि शिक्षा पर आयोजनाओं के अधीन और उनके बाहर खर्च की जान वाली राशियों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो आकड़े कुछ भिन्न तसवीर पेश करेंगे। फिर भी कुल मिलाकर स्थिति किसी तरह सन्तोषजनक नहीं है। जैसा कि शिन्धुनाम्नबद्धी राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में सुझाया गया है हमारा लक्ष्य शिक्षा-विविनियोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जान का होना चाहिए और यथासंभव दीर्घ ही हम उसको राष्ट्रीय आय का ६ प्रतिशत तक पहुँचा देना चाहिए। इस दिशा निर्देश का अनुसार छोटी पञ्चवर्षीय आयोजना में शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आविर्कार आगामी वर्षों में शैक्षणिक सुधार की सफलता केंद्रीय जनता सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और सकल्य पर निर्भर करेगी। यदि नई सरकार वर्तमान शिक्षा पद्धति को नए सौच में ढालने के द्वार में सचमुच गंभीर है तो उस कई साहसपूर्ण निश्चय लेन हाँगा। फूँक फूँककर कदम उठाते हुए समस्या को हल करने की मत्तही इच्छा भर से काम नहीं चलेगा। जहाँ सच्ची चाह है राह तो वहाँ मिल ही जानी है।

आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में विचारणीय प्रश्न

श्री रघुकुल तिलक

प्रधान-मंत्री जी के प्राप्ति के बाद मेरे पास बहुत कुछ कहने को नहीं है। किन्तु अध्यक्षजी ने मुझ से कुछ शब्द कहने के लिए कहा है अतः मैं अपने को केवल कुछ ऐसी बातों पर ही सीमित रखूँगा, जिन्हें चर्चा के दो दिनों के दौरान विचार-विमर्श हेतु दृष्टि में रखना आवश्यक है।

यह कहना सही है कि हमारी शिक्षा-प्रणाली हमारी सामाजिक व्यवस्थाका एक भीतरी अंग है। समाज में जो ताकत या जो कमी है वह सब हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रतिबिम्बित होती है। हमारा समाज अभी भी भर्त्सित तथा जाति-प्रसूत समाज है, जिसमें समतल और सम्व-रूप गतिशीलता बहुत कम है। इसकी प्रति व्यक्ति आप भी बहुत कम है। यद्यपि इन सबपर सबकी समान रूप से सहमति नहीं है फिर भी इन्हें हमें दृष्टि में रखना है क्योंकि ये हमारी शिक्षा-प्रणाली में प्रतिबिम्बित होती है। साथ ही हमें यह जान लेना है कि सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा अत्यन्त सक्षम और सशक्त माध्यम है। यही कारण है कि जब हम समाज के इन अस्वीकृत तत्वों को हटाना चाहते हैं तो ऐसा करने को हमारे पास शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है। शिक्षा को यदि सामाजिक स्थितियों को प्रतिबिम्बित करने और साथ ही उनमें परिवर्तन लाने की दुहरी जिम्मेवारी निभानी है तो उसे प्रासंगिक, सक्षम तथा नवीला होना चाहिए।

प्रासंगिकता स्पष्ट है और हमें यह पहचान लेना चाहिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली प्रासंगिक नहीं रह गई है। जब शिक्षा की यह

प्रणाली स्थापित की गई थी तब यह प्रासंगिक थी। अंग्रेजों का उस समय एक निश्चित उद्देश्य था, वे पढ़े लिखों के महारे अपना राजकाज चलाना चाहते थे और सर्वसाधारण को अशिक्षित रखने में ही वे अपना हित देखते थे। किन्तु अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अब यह प्रणाली गिकता इस रूप में समाप्त हो गई है। अब तो हमें यह प्रयत्न करना है कि अधिकतम संख्या में देशवामी शिक्षित हों। हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन हो गए है और हमारी शिक्षा-व्यवस्था इन तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ कदम रखने में असफल हो गई है इसी कारण वह अप्रासंगिक हो गई है।

जब गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा दी तब वे इस प्रणाली को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहते थे। यही हमें समझना है। आजकी शिक्षा को हमें अपने आज के आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक ढांचे के अनुरूप बनाना है। प्रासंगिकता पहली बात है जिसकी ओर हमें ध्यान देना है, तब हमारी शिक्षा प्रणाली लचीली होनी चाहिए। यदि शिक्षा प्रणाली अत्यधिक कठिन और बेसोच होती है तो वह तेजी से होनेवाले सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के साथ कदम नहीं रख पाएगी अतः उसका लचीला होना अत्यावश्यक है। लचीला बनाने के लिए उसका विकेंद्रीकरण आवश्यक है। लेकिन यदि उसे बहुत अधिक विकेंद्रित कर दिया जाए तो उसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन हो जाएगा। हमारे संविधान-निर्माताओं ने शिक्षा को प्रदेशों पर छोड़ा यह उचित ही था। मैं भी इस विचार से सहमत हूँ कि शिक्षा प्रादेशिक सरकारों का विषय रहे। प्रदेशों में दूसरा और विकेंद्रीकरण होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा, क्षेत्रों और जिलों पर छोड़ देना चाहिए। तब प्रयोग करना अधिक सरल हो जाएगा तथा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकना संभव हो सकेगा। अतः हमें यह देखना है कि जो भी शिक्षा प्रणाली हम अंतिम रूप से काम में लाना चाहते हैं वह अत्यधिक बेसोच नहीं हो जाती है जिससे वह समय के परिवर्तन के साथ कदम न मिला सके।

पिछले कुछ वर्षों में समाज तेजी से बदला है और आगामी कुछ सदियों तक वह सामान्य समय की अपेक्षा अधिक तेजी से बदलेगा अतः हमारी शिक्षा प्रणाली का लचीला होना आवश्यक है।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली सक्षम हो। वह अपने में निहित उद्देश्यों की ओर सक्षमता से ले जाने वाली हो। हम जानते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय युवकों को इस प्रकार तैयार कर रहे हैं कि वे रोजी पाने में असमर्थ हो रहे हैं और जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी न ठीक ही कहा है कि उनमें बहुत बड़ा ज्ञान होता है और चरित्र तो बहुत ही कम। यह ऐसी बात नहीं है कि जिस पर हम अभिमान कर सकें। यह विश्वविद्यालयों की ही जिम्मेवारी है कि वे जीवन के हर क्षेत्र में समय के अनुरूप नेतृत्व दे सकें बिना विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर रहे हैं। अतः जो भी प्रणाली हम सोचें वह सक्षम हो अर्थात् ऐसे यशस्वी तैयार करने वाली हो जो वर्तमान संदर्भ में समाज के लिए उपयोगी हो।

उच्च स्तरीय शिक्षा के संदर्भ में भी यही बात है कि वह भी लचीली सक्षम एवं उपयोगी होनी चाहिए। मुझे आशा है कि इन्हीं सब दृष्टियों से चर्चाओं में विचार किया जाएगा।

मैंने प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्रीजी चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो उसे गुरुत्व प्राप्त किया जाए। जैसा कि अपने प्रास्ताविक भाषण में श्रीमन्मन्त्री ने सकारात्मक किया है— हमने बहुत सी उपसमितियाँ बनाई हैं कई कमिशन नियुक्त किए लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। हम कई सम्मेलन करने हैं समितियाँ बनाते हैं पर परिवर्तन कुछ नहीं होता। मेरा विश्वास है कि इस सम्मेलन का ऐसा परिणाम नहीं होगा वरन् इससे कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेंगे। और उसपर भी ध्यान दिया जाएगा।



शिक्षा आर्थिक परिप्रेक्ष्य में

श्री लकड़ावाला

मैं दो रुकावट से ग्रस्त हूँ। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव विश्वविद्यालयीन स्तर तक सीमित है और वह भी विषय रूप से अर्थशास्त्र विषय तक। मेरी वर्तमान अभिरुचि योजना में है। दूसरी रुकावट यह है इस विषय के दो विशेषज्ञ मूझमे पहल बोल चुके हैं। अतः स्पष्ट है कि मेरे कहने के लिए बहुत कम रह गया है। मैं योजना से सम्बद्ध सीमा तक ही अपनी बातों को सीमित रखूँगा।

जैसा कि आप जानते हैं नई योजना में ग्रामा की आर अधिक झुकाव है, कृषि की ओर अधिक झुकाव है तथा तत्संबन्धी तकनीक की ओर अधिक झुकाव है। स्पष्टतः इन्हीं झुकावों से शिक्षा का झुकाव प्रभावित है। ऐसी स्थिति में यह भी स्पष्ट है कि हम अधिकतम महत्व प्रौढ़ शिक्षा या औपचारिक शिक्षा प्रणाली को देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस सम्मेलन में इस समस्या पर भी विचार करण और अपने आपको केवल औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखेंगे। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्रको पार करना तो थोड़ा सरल है यद्यपि इसमें तो छात्रों को अन्य कोई विवक्ष्य नहीं होता सिवा इसके कि वे पाठशाला में आकर अपना निर्धारित पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि में पूरा कर किन्तु प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र तो और अधिक आह्वान का क्षेत्र है जहाँ शिक्षाकी प्रासंगिकता की सच्ची परख होती है और यदि वह प्रासंगिक नहीं होती तो प्रौढ़ लोग उसे स्वीकार ही नहीं करते। इस दृष्टिकोण से मैं आपसे अत्यधिक प्रार्थना करूँगा कि आप कृपया अपनी चर्चाओं के दौरान प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक ध्यान देंगे।

जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है, मैं साबित करता हूँ कि हमने गत कुछ वर्षों में काफी प्रगति की है। अब मुख्य समस्या अधिक शालाएँ प्रारम्भ करने की नहीं हैं बल्कि यह है कि खुली हुई पाठशालाओं में छात्र

आते हैं और निर्धारित अवधि तब शिक्षा ग्रहण करते हैं। छात्रों के केवल भर्ती होने, शालाओं में कुछ दिनों तक उपस्थित होने और उपस्थित होकर सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम को पूरा करने—इन सब में महान अन्तर है। मैं देखता हूँ कि शिक्षकगण केवल भर्ती-समस्या को पूरी करने की ओर ही अधिक ध्यान देते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि छात्र नियमित रूप से शालाओं में उपस्थित होकर अपना निर्धारित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करें। बुनियादी तालीम इस प्रकार की आवश्यक हो कि वह छात्रों को शालाओं में आने, उपस्थित रहने तथा पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आकर्षित करे।

जहाँ तक उच्च शिक्षा का विरोध विश्वविद्यालयीन शिक्षा का प्रश्न है गत तीन वर्षों में हमने इस मद पर काफी रुपा खर्च किया है। मैं यह जानता हूँ कि अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में यह राशि पर्याप्त नहीं है फिर भी गत वर्षों की अपेक्षा हमने काफी अधिक खर्च किया है। अब हम यह देखना चाहिए कि जो कुछ हमने खर्च किया है उसके अनुकूलतम और अधिकतम परिणाम हम मिल रहे हैं क्या? मैं सोचता हूँ कि हमने उच्च शिक्षा को प्रत्येक छात्रके लिए मूलतः बहुत सस्ता बना दिया है। हाँ, इस में तो मुद्दा हो सकता है कि हम गुणवत्ता के आधार पर छात्रों का चुनाव कर उनके लिए उच्च शिक्षा को रास्ता बनाएँ। उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की उपयोगिता तभी है जब प्रत्येक व्यक्ति उसकी पूरी कीमत चुकाने को सँयार हो। यह एक प्रकार से मुक्त व्यावसायिक अर्थ शास्त्र है और दूसरा समाजवादी अर्थ शास्त्र जहाँ हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप तथा उसके द्वारा की गई समाज सेवाओं के अनुरूप देते हैं। मुझे भय है कि इन दोनों में हमने बुरी सुलह या सन्धि की है। हमने लगभग सभी को विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देने की प्रणाली अपनाई है और उसके लिए शासकीय अनुदान देते हैं जिसका भार जनता पर पड़ता है। पर आपको ध्यान होगा कि तीन चार वर्ष पहले विदेश में भीषण हड़ताल का सामना करना पड़ा था। जब तक विद्यार्थियों से चर्चा की जाती है तब तक तीन चार दिनों तक तो महाविद्यालय और विश्व-

विद्यालय बंद हो जाते हैं। परिणामतः छात्र चिंतित हो जाते हैं और जितने दिन पढ़ाई नहीं होती है उतने दिनकी दी गई फीस के विषय में सोचने लगते हैं। पढ़ाई की फीस इतनी अधिक होती है कि हड़ताल के कारण या महाविद्यालय के बंद होने के कारण न होनेवाले लेक्चर्स के सदर्थ में वे सोचने लगने हैं।

हमारी प्रणाली में चूंकि यह मूल्य कुछ नहीं होता अतः महाविद्यालयों या विश्व विद्यालयों द्वारा न किए गए काम को कोई महत्व नहीं देता। अब हमें अविलम्ब यह सोचना होगा कि हम कबल उही छात्रों को शासकीय अनुदान दे जो प्राप्त शिक्षा से अधिक से अधिक लाभ अर्जित करते हैं। दूसरों से हम पूरी फीस वसूल कर या फिर कर्ज के रूपमें उन्हें सहायता दे जिससे कर्ज लनवाले समय पाएँ कि जो शिक्षा वे पाएँ वह उस कर्ज के लायक है या नहीं।

अब मैं अंतमें यह कहना चाहता हूँ कि जब जब मैं इस प्रकार के सम्मेलनों में शामिल होता हूँ तब तब शिक्षा विशेषज्ञों में एक प्रवृत्ति पाता हूँ और वह है राष्ट्रीय आयमें से शिक्षा के हेतु आनुपातिक राशिक सबध की। यह कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय के शत प्रतिशत से भी अधिक होती है। आप इस दिशा में भी योजित और जो योजित नहीं हैं दोनों पर विचार करें और उसमें भी प्राथमिकता के क्रम से विचार करें। क्योंकि विशेषज्ञों के निर्णय राष्ट्र के तद्विषयक भाग्य निर्मितिम सहायक होते हैं और उन्हींके आधार पर कार्य की प्राथमिकता एवं महत्ता निर्धारित होती है।



शिक्षा की पुनर्रचना

डॉ. सतीशचंद्र

अध्यक्ष महोदय, डॉ. चंद्र तथा इक्ठ्ठा हुए मित्रगण ! मैं यहाँ कुछ कहने की वजाय अधिक सुनने के लिए आया हूँ। प्रधान मंत्रीजी ने वृत्तापूर्वक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा है कि राष्ट्रीय वरीयताओं की दृष्टि से शिक्षा की पुनर्रचना कैसे की जा सकती है? इन वरीयताओं का उल्लेख बहुत पहले डा. कोठारी की अध्यक्षता वाले कमीशन के सामने उनके द्वारा बोल जाते समय कर दिया गया है। उसके बाद भी प्रधान मंत्रीजी के साथ चर्चा करत समय भी इनका उल्लेख हो चुका है। कन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा. प्रताप नन्द्र चदर ने भी सरकारी वरीयता का उल्लेख अनेक अवसरों पर किया है और जहाँ तक विषय रूप से वरीयताओं का संबंध है हम कह सकते हैं कि इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं रह गया है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में भी इस विषय पर कोई बड़ा मतभेद नहीं होगा। हमारा सर्वाधिक जोर बुनियादी तालीम पर है जिसमें, हम सर्वाधिक जोर चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण पर, गुणों पर, जीवन की मूल्यों को तथा समाजवाद पर दें। ये ये कुछ तत्व हैं जिन्हें आयोग ने भी ध्यान में रखा है। आयोग ने प्रधान मंत्रीजी तथा शिक्षा मंत्रीजी को एतद्विषयक एक दस्तावेज दिया है और हम आशा करते हैं कि उनके साथ विस्तृत चर्चा करने का हमें लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा ही नहीं बल्कि वास्तव में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के साथ वरीयता के अतिरिक्त प्राथमिक समस्या—जैसा कि तिलकजी ने कहा था—यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली द्वेष है। हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी तो है लेकिन वह बहुत कम अल्पसंख्यक लोगों के लिए मूल्यवान है। इन्हीं

अल्प संख्यकों के लिए प्राथमिक शालाएँ हैं : इन्हों अल्प संख्यकों के लिए पब्लिक स्कूल हैं और जहाँ तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है यह बताया गया है कि विश्व विद्यालयों तथा विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ८० प्रतिशत स्थान तो अधिस्तम आय के दायरे वाले लोग ही रोक लेते हैं। समस्या यह है कि इस द्वंद्व ग्रासन से कैसे छटकारा पाया जाए अथवा इनके बन्धनों को ढीला कैसे किया जा सके ? यह द्वंद्व प्रणाली अन्य सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली में असमानता की पारम्परिक जड़ है। मैं एक छोटासा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे देश में ४००० से अधिक महाविद्यालय हैं। इनमें लगभग ३२०० विज्ञान या वाणिज्य महाविद्यालय हैं। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ऐसे महाविद्यालयों की सूची रखता है जो उसकी सहायता के अधिकारी हैं। इन अधिकारी महाविद्यालयों को हम दो एफ के अंतर्गत परिगणित करते हैं। इन ३२०० महाविद्यालयों में से केवल २७०० महाविद्यालयों ने दो एफ के अंतर्गत ममायिष्ट किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। ये महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता के पात्र हैं। आयोग इन सभी महाविद्यालयों की सहायता नहीं दे सकता क्योंकि वह तदर्थ छात्र संख्या, प्राध्यापक संख्या, दी जानेवाली न्यूनतम सुविधाएँ संबंधी कुछ मानदंड निर्धारित करता है। वह इसलिए कि आयोग का काम गुणवत्ता को बढ़ाना, मानदंड को ऊँचा करना आदि भी है, केवल सहायता करना मात्र नहीं। अतः जहाँ तक आयोग का सम्बन्ध है, इन २७०० महाविद्यालयों में से केवल २००० महाविद्यालय इसकी सहायता के अधिकारी हैं।

अब यह देलना है कि इस परिस्थिति का सामना हम किस प्रकार करते हैं। यह सच में योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी के मंदर्भ में कह रहा हूँ। यह सच है कि जब जब विशेषज्ञ इकट्ठा होते हैं तब तब वे अधिक अर्थ (द्रव्य) की माँग करते हैं और योजना आयोग भी विशेषज्ञों की ही एक संस्था है। वे सदा निर्णय कर सकते हैं कि हमारी प्राथमिकताएँ क्या हैं। मैं चाहूँगा कि यह सम्मेलन यह भी निश्चित करे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्राथमिकताएँ क्या हों।

या तो वह प्रत्येक महाविद्यालयों को अनुदान दे या मानदंड से उसका निर्णय अधिक सख्त हो ? अनुदान आयोग की अधिक मीमांसा को ध्यानमें रखते हुए ही विचार किया जाना इस गरीब देश की आवश्यकता है। हम थोड़ी थोड़ी रकम सभी महाविद्यालयों को दे सकते हैं किन्तु उससे स्तर पर हमारा कोई निबंध नहीं रह जाएगा और इससे द्वैध व्यवस्था तथा द्वेय परिणाम ज्यों के त्यों बने रहेंगे और यह थोड़ी रकम भी थोड़े ही महाविद्यालयों को लाभान्वित कर पाएगी। हमारा उद्देश्य यह है कि जितने भी महाविद्यालयों को दे सकें अधिकतम महायत्ता दें और वह भी विशेषतः पुस्तकों और प्रसाधनों के रूपमें। किन्तु हम यह अवश्य ध्यान रखते हैं कि जिले की इराईवार और चरणवार श्रेष्ठ महाविद्यालयों की स्थापना संभव हो जिससे अधिक से अधिक सख्या में मेधावी (बुद्धिमान) छात्रों को महाविद्यालयीन अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त हो सके। अपनाया जा सकने वाला हमारा दूसरा पर्याय या पूरक पर्याय यह है कि गरीब छात्रों को सुविधा दी जाए और इस प्रकार वे प्रतिष्ठा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश पा सकें। इन दोनों व्यवस्थाओं के लिए पैसे की आवश्यकता है और मैं सोचता हूँ, यदि योजना आयोग संकेत दे और वही संकेत दे सकता है कि कितनी राशि उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित की जाए और यदि प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं तो द्वैध प्रणाली में छिद्र करना प्रारम्भ किया जा सकता है।

जहाँ तक मैं देख पाता हूँ भूशे भय है कि सीमित साधनों के भीतर यह संभव नहीं है कि आशा की जा सके कि ३२०० महाविद्यालयों को समान उच्चस्तर तक उठावा जा सके। यदि धन ही तो ठीकते आवश्यक योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। और योजना आयोग प्रयत्न कर रहा है कि उन्नत करनेके कार्यक्रमों द्वारा वर्तमान शिक्षकों का स्तर समुन्नत किया जा सके।

मैं प्रासंगिकता संबंधी समस्या के विषय में कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। यह सचमुच एक गम्भीर समस्या है। किन्तु यह समस्या एक मान भारत के लिए ही विचित्र नहीं है। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित 'लॉनिंग टू वी' नामक पुस्तक में इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक विशेष जोर

दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि संसारके समुन्नत देश अपनी समस्त समस्याओं को सुलझा पाए हैं और केवल अर्द्ध समुन्नत या अनन्त देशों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जितनी तेजी से समाज बदल रहा है जितनी तेजी से तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं उन सबकी दृष्टि से सभी देशों में शिक्षा असामयिक होती जा रही है। हमारे देश में चूँकि वह अधिक असामयिक है और इसीलिए प्रासंगिकता की समस्या हमारे यहाँ अन्य देशों की अपेक्षा अधिक कठिन है। लेकिन यहाँ की जिस समस्याको रघुकुन तिनबजी ने उठाया है उसके संबंध में मैं स्पष्ट कहूँ कि मैं नहीं जानता कि क्या उत्तर दिया जाए ? किए जानेवाले परिवर्तन तो सहज ही सुझाए जा सकते हैं लेकिन ज्यों ही उनका कार्यान्वयनकी बात आती है त्यों ही चारों ओर से विरोध होना शुरू हो जाता है।

परीक्षाओं में सुधार का प्रश्न एक ऐसा ही प्रश्न है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक कमिशनो की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में सुधार की एक योजना प्रस्तुत की जिसमें उसने अतर्गत अकादमिक प्रश्न वैसे तथा अन्य कई महो पर बल दिया। जब नई प्रणाली को काम में लाने की बात आती है तब शिक्षक तथा छात्र नई प्रणाली के प्रयोग की अपेक्षा तथा अथवा प्रयोगोंकी अपेक्षा पुरानी प्रणाली का जारी रखा जाना ही अधिक पसन्द करते हैं यद्यपि वे उसके दोषों के जानबूझते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे सम्मेलन तथा अन्य कई माध्यमों द्वारा वैचारिक वातावरण बनाना होगा। बिना उपयुक्त वैचारिक वातावरण बनाए जो भी परिवर्तन सामने रखे जाएंगे, उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा।

और मैं यह कहना चाहूँगा कि यद्यपि उपाध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि हमने उच्च शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया है मैं समझता हूँ कि उच्च शिक्षा को हम अधिक तात्कालिक बनाना है। जब हम अपने स्तरकी तुलना अन्य प्रगतिशील देशों से करते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा किया जा रहा आवश्यक है। प्रधान मंत्री जी ने

ठीक ही कहा है कि हम छोटे देशों जितने भी विशेषज्ञ नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। मानव जीवन के विविध उद्योगों के लिए इन विशेषज्ञों की आवश्यकता है और फिर विश्वविद्यालयों का स्तर भी ऊँचा नहीं है जिससे मारी शिक्षा पद्धति पर में कसावट आ सके। हम जिस मुद्दे पर चल देना चाहते हैं, वह यह है कि विश्वविद्यालयों को विस्तार की गतिविधियाँ पर अधिक गंभीर ध्यान देना चाहिए, अर्थात् वे यह सोचें कि शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर को कायम रखना मात्र ही उनकी जिम्मेवारी नहीं है बल्कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं संपूर्ण के स्तर पर शिक्षा को ऊँचा बनाने की भी जिम्मेवारी उनकी है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण लोग, शहर के लोगों और विशेष रूप से अशिक्षित प्रौढ़ों— इन प्रकार संपूर्ण समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी का अनुभव उन्हें करना चाहिए। सरकार तथा योजना आयोग के साथ-साथ मैं भी यह कहता हूँ कि प्रौढ़ साक्षरता हमारी प्रधान प्राथमिकता है।

ये कुछ मुद्दे हैं जिनपर आयोग ने प्रधान मंत्रीजी को दिए अपने दस्तावेजों में सामने रखने का प्रयत्न किया है। हम इस सम्मेलन की वर्षाओं तथा मार्गदर्शक निर्णयों की ओर आशा भरी नजरों से देखेंगे।



बुद्धिपूर्वक किया जानेवाला श्रम ही सच्ची प्राथमिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा है।

मनुष्य न तो कोरी बुद्धि है न स्थूल शरीर है और न केवल हृदय। सम्पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए तीनों के उचित और एक-रस मेल की जरूरत होती है और यही शिक्षा की सच्ची व्यवस्था है।

बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य दस्तकारी के माध्यम से बालकों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है।

अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग के सिद्धांत का पालन नागरिकता के गुण का विकास करनेवाली सर्वोत्तम शिक्षा है। इससे बुनियादी तालीम स्वावलंबी भी बनती है।

महात्मा गांधी

भावी कार्यक्रम पर सर्वसम्मत निवेदन -

राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जो अमिल भारत नई तालीम समिति द्वारा आयोजित किया गया था, दिनांक १८-१९-२० दिसम्बर, १९७८ को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया तथा केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष और नई तालीम समिति के सभापति डा श्रीमन्नारायण ने इसकी अध्यक्षता की। गजस्थान के राज्यपाल श्री रघुबुल तिलक के अलावा सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के कई शिक्षा मंत्रियां, विश्व-विद्यालयों के ३० कुलपतियों, कुछ समद-मदस्था स्वयंसेवी मण्डलों-के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों और देश के विभिन्न भागों के लगभग १०० अनुभवी बुनियादी शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्त्ता भाग लिया। केन्द्रीय शिक्षामंत्री डा प्रतापचन्द्र चन्दर ने सभापति भाषण दिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक, शिक्षा मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षक प्रतिनिधियां ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए मुख्य विचारपत्र 'राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कुछ रचनात्मक सुझाव' पर सम्मेलन में गहराई से विचार किया गया। तीन दिन की विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निवेदन जाहिर किया गया —

१. अनेकों समितियों और आयोगों की रिफारिमेंटों के बावजूद इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी है और वह जन-माध्यारण की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए भी सममानुबल सिद्ध नहीं हुई है। ४० वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने

‘सार्वभौमिक धर्म और उत्पादक कार्य पर, केन्द्रित तथा बालक के आस-पास के परिवेश से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध’ बुनियादी शिक्षा की एक योजना देश को सामने रखी थी। इसका अभिप्राय, ‘जीवन के लिए शिक्षा, और इससे भी आगे जीवन द्वारा शिक्षा’ देना था। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का, उनकी उत्पादक क्षमता और स्थानीय समाज से निकट सम्पर्क सहित उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का, विकास करना था। गांधीजी द्वारा परिकल्पित बुनियादी शिक्षा एक गतिशील पद्धति थी जो निश्चित ही बदलती हुई परिस्थितियों में प्रगति और विकास करनेवाली है।

बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत में पूर्व-प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक सभी स्तरों पर शिक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शन और स्वरूप-निर्धारण ‘राष्ट्रपिता’ द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों के आधार पर ही होना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा आर्थिक प्रगति और विकास से सम्बन्धित समाजोपयोगी उत्पादक कार्यकलापों द्वारा दी जानी चाहिए।

बुनियादी शिक्षा के इन मूलभूत सिद्धान्तों को, बिना किसी भेद-भाव के, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सभी शिक्षा संस्थाओं और समाज के सभी वर्गों के लिए लागू किया जाना चाहिए।

२. पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के पाठ्यक्रमों में निम्न तीन आधारभूत मूल्यों पर जोर दिया जाना चाहिए—

- (१) शैक्षणिक प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य-विशेष के उपयोग द्वारा स्वावलम्बन, आत्म-विश्वास और श्रम की गरिमा की भावनाओं का पोषण,
- (२) विद्यार्थियों और अध्यापकों को सामुदायिक सेवा के अर्थवान कार्यक्रमों में प्रवृत्त करके राष्ट्रीयता तथा सामाजिक दायित्व के बोध का विकास, और

(३) विद्यार्थियों के मानस में नैतिक, चारित्रिक - व मानवी मूल्यों की प्रतिष्ठा, सभी धर्मों की मूलभूत एकता की समझ और उनके प्रति समान आदर की भावना पैदा करना ।

इन पाठ्यक्रमों में हमारे देश की समन्वयकारी संस्कृति, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता पर बल देने हुए भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संक्षिप्त इतिहास और हमारे संविधान में प्रतिष्ठित अहिंसा, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा सर्वधर्म-समभाव (Secularism) के आधारभूत मूल्यों को समाविष्ट किया जाना चाहिए ।

३. भारतीय संविधान के ४५ वें अनुच्छेद के अनुसार राज्य के चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए । इस निर्देश के अनुसार सभी राज्य सरकारों को छठी राष्ट्रीय योजना के अन्त तक आठवी कक्षा तक की देशव्यापी प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए । बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने की ओर विशेष ध्यान देना होगा । निर्धारित अवधि में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ऐसी अनौपचारिक शिक्षा जारी करना आवश्यक होगा, जिसमें अल्पकालिक शिक्षण, बहु-विन्दु प्रवेश तथा अगली कक्षा में चढ़ाने की लचीली पद्धति का अनुसरण किया जाए ।

जिन राज्यों में प्राथमिक शिक्षा केवल सात वर्ष तक दी जाती है, वहाँ फिलहाल वही पद्धति को चलने दिया जाए ।

छोटे बालकों की, विशेषतः कमजोर वर्ग के बालकों की, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के दौरान जीवन के आधारभूत मूल्यों के शिक्षण की ओर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सामान्यतः शाला का ५० प्रतिशत समय उत्पादक, सृजनारम्भक और मनोरंजन कार्यों को दिया जाए, जिसमें से कम से कम आधा समय पूर्णतः विभिन्न प्रकार के समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों में

लगे। पाठ्य पुस्तकों के वर्तमान भार और अनिवार्य विषयों की बड़ी संख्या को उचित सीमा तक कम किया जाए।

सधन शिक्षा की दृष्टि से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार छुट्टियों में बमी और रद्दोबदल किया जाना चाहिए।

४ प्राथमिक के बाद माध्यमिक शिक्षा चार वर्ष की और यह १२ वी कक्षा पर समाप्त होने वाली हो। इस अवधि में स्थानीय और क्षेत्रीय रोजगार के अवसरों के अनुसार माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू किए जाएँ, जिससे छात्र राष्ट्र के उपयोगी नागरिक के रूप में अपने जीवन में स्थिर होने के योग्य बन सकें। उत्पादक कार्यों के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों में भाषा, विज्ञान और गणित, साहित्य सहित समाज-शास्त्र और मानविकी विषय शामिल किए जाएँ। विभिन्न विषयों के चुनाव में पर्याप्त छूट और लचीलापन हो। किन्तु माध्यमिक शिक्षा की एक ही समग्र धारा चले, उसमें 'शैक्षिक' और 'व्यावसायिक' जैसी किसी उपधारा का भेद नहीं होना चाहिए। जैसा कि शिक्षा सम्बन्धी यूनेस्को आयोग (१९७२) ने सिफारिश की है 'शिक्षा के विभिन्न प्रकारों में' से कड़े अलगाव को समाप्त किया जाए और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर से ही शिक्षा एक साथ सैद्धान्तिक, तकनीकी प्रायोगिक और शारीरिक हो।'

माध्यमिक स्तर के अध्ययन के पाठ्यक्रम एक तरह 'अन्तिम' होंगे, किन्तु भविष्य में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की छात्रों को छूट होनी चाहिए।

५ माध्यमिक स्तर तक सार्वजनिक शिक्षा की 'सामान्य स्कूल' पद्धति होनी चाहिए, जिसमें सभी बच्चों को जाति, वर्ग या धार्मिक मान्यता के भेदभाव के बिना प्रवेश मिल सके। भारत में एक लोकतान्त्रिक समाजवादी और प्रगतिशील समाज के विकास के लिए यह आवश्यक है।

इस दृष्टि से समय आया है कि 'पब्लिक स्कूल' जो अधिकांश में धनिक वर्ग के बच्चों को शिक्षण देने तक ही सीमित हैं, वे सब

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में आ मिलें, जिसमें मातृ-भाषा और त्रिभाषा फार्मूला के माध्यम से ही शिक्षण देना भी शामिल है। इसके अलावा इन स्कूलों को वक्षा आठ तक कोई शुल्क लेने की अनुमति भी न दी जाए, क्योंकि १४ वर्ष की आयु तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना संविधान द्वारा निर्देशित है। साथ ही, इन स्कूलों से भी ५० प्रतिशत स्थान योग्यता छात्र-वृत्तियों (Merit Scholarships) को देकर कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित रखे जाएँ।

६ सक्रान्ति काल में विभिन्न राज्यों के वर्तमान बुनियादी और उत्तर बुनियादी स्कूलों को प्रोत्साहित करने और सुदृढ़ बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इस कार्य के लिए भारत सरकार केन्द्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड की स्थापना करे। ऐसे बोर्डों की स्थापना राज्य स्तर पर भी की जाए।

७ विश्वविद्यालय स्तर पर पहला डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होना चाहिए। केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता मण्डल न सुझाव दिया उसके अनुसार विश्वविद्यालय अपनी इच्छा से दो वर्ष का 'फास कोर्स' और तीन वर्ष का 'आनर्स कोर्स' रख सकते हैं। इस स्तर पर भी शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रम, बुनियादी शिक्षा की पद्धति पर, विविध प्रकार की उत्पादक और विकास परियोजनाओं से सम्बद्ध हो ताकि विश्वविद्यालय शिक्षा वास्तव में उद्देश्यनिष्ठ बन सके।

महाविद्यालयों में प्रवेश चुने हुए छात्रों को दिया जाना चाहिए और वहाँ उपलब्ध पुस्तकालयों प्रयोगशालाओं तथा अध्यापकों की सुविधा तथा वहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रशिक्षित स्नातकों की माँग आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। इनमें कमजोर वर्ग और अविकसित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए समुचित स्थान सुरक्षित रखने चाहिए।

८ शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम छात्रों की मातृभाषा होना चाहिए। कृषि, इंजीनियरिंग और डाक्टरों पाठ्यक्रमों समेत भारत के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

क्षेत्रीय भाषाएँ अपनाए जाने के लिए पूरे निश्चय के साथ तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए। सन्नति काल में भी 'मातृ-भाषा के माध्यम से माध्यमिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को इन राजनीती और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने से न रोका जाए। ऐसे विद्यार्थियों की भाषा सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिए इन सस्याओं में विशेष व्यवस्था की जाए।

इस सारे लक्ष्य को ध्यान में रखकर आवश्यक पाठ्य पुस्तकें और अन्य साहित्य भारतीय भाषाओं में तैयार और प्रकाशित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

९. स्कूलों और कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहने का एक मुख्य कारण यह है कि भारतीय सिविल तथा सैनिक सेवाओं में भर्ती की परीक्षाओं का माध्यम अभी भी अनिवार्य रूप से अंग्रेजी है। कुछ राज्यों तक में सिविल सेवा परीक्षाएँ अंग्रेजी में होती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंको, बीमा कम्पनियों और सरकारी औद्योगिक सस्यानों में, भर्ती अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होती है। इसलिए यह वांछनीय है कि ये सभी परीक्षाएँ क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हो। सरकारी सेवाओं में चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों का उचित 'कोटा' नियत करने में कोई बड़ी गठिनाई नहीं होनी चाहिए। चुनाव के बाद उम्मीदवार इन सेवाओं के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सेवाओं के लिए चुनाव की इस नई पद्धति में उम्मीदवार ने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के समय जो समाजोपयोगी उत्पादक कार्य किया उस विशेष योग्यता को भी अतिरिक्त माय्यता दी जानी चाहिए। इस व्यवस्था का, अनुभव के आधार पर, कुछ वर्ष बाद पुनरावलोकन किया जा सकता है।

१०. वर्तमान परीक्षा प्रणाली का छात्रों की शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक क्षमता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप छात्रों का स्तर गिरा है, उनमें अनुशासन की कमी आई है तथा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाने के लिए अनुचित

तरीकों का अपनाया जाना व्यापक हुआ है। इसलिए यह आवश्यक है कि परीक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाए। छात्रों के बौद्धिक विकास का ही मूल्यांकन न किया जाए वरन् समाज की अत्यपूर्ण सेवा के कार्यक्रमों सहित उत्पादक और समाजोपयोगी प्रवृत्तियों में उनके सक्रिय योगदान को भी देखा जाए। वस्तुपरक मरल तरीके से आन्तरिक मूल्यांकन के लिए इन प्रवृत्तियों का विस्तृत ध्येय रचना आवश्यक है। मंथोपत वर्तमान परीक्षा प्रणाली में ठीक ढंग का सुधार, मौजूदा स्कूलों और कालेजों में बुनियादी शिक्षा की पद्धति पर उनमें नवीनता लाकर ही किया जा सकता है।

११ विभिन्न प्रकार की नौकरियों से विश्वविद्यालयों की पदवियों का सम्बन्ध विच्छेद किया जाना भी वाछनीय है ताकि कालेजों में प्रवेश चाहने वाली वर्तमान भीड़ उल्लेखनीय सीमा तक कम हो सके। विभिन्न सरकारी विभाग तथा गैर सरकारी संस्थान भी विश्वविद्यालय की पदवी पर जोर न देकर, अपना पाठ्यक्रम निर्धारित कर प्रतियोगिता परीक्षाएँ ले सकते हैं। ये पाठ्यक्रम ११ और १२ कक्षा में भी लागू किए जा सकते हैं, जिससे छात्र, मात्र क्लक का म्यान पाने के लिए अपने अवसर बढ़ाने की उच्च शिक्षा लेने का लोभ न करें।

१२ उपरोक्त नई शिक्षा प्रणाली मिशनरी भावना वाले और निष्ठावान् सुप्रशिक्षित अध्यापकों के बल पर ही सफल हो सकती है। अध्यापकों को केवल तकनीकी व्यक्ति न माना जाए। वे ही वास्तव में राष्ट्र के सर्जक और निर्माता हैं। अध्यापकों को अपनी पूरी शक्ति छात्रों का चरित्र-निर्माण करने में लगानी चाहिए ताकि छात्र वर्ग समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकें। राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह उनका सामाजिक स्तर ऊँचा करे और इन्हें अधिक चिन्ताओं से मुक्त होने योग्य बनाए।

शिक्षक वर्ग की योग्यता और कुशलता बढ़ाने के लिए बुनियादी शिक्षा के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम तुरन्त बनाया जाना और व्यवस्थित रूप से अमल में लाया जाना चाहिए।

सब प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्पादक बायें, स्वयं सेवा, -आपसी सहयोग और लोकतान्त्रिक मूल्यों पर आधारित सुमम्बद्ध समुदायों के रूप में संगठित किया जाना चाहिए।

१३ देश के सभी राजनैतिक दलों से सम्मेलन अनुरोध करना है कि वे अपने द्वारा बनाई गई उपयुक्त आचार-संहिता को आधार मानकर शिक्षा-संस्थाओं के सहज चल रहे कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करें। 'शिक्षा मन्दिरों' के छात्रों और अध्यापकों का दलीय-स्वायत्तों के लिए अब और अधिक्त शोषण नहीं किया जाना चाहिए।

शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य क्षेत्रों में हिंसक आन्दोलन और घेरावों को प्रशासन द्वारा दृढ़तापूर्वक रोका जाना चाहिए।

१४ इन सकारितों में उल्लिखित नई दिना प्रणाली का ढाँचा अब होगा ८+४+३ अर्थात् आठ वर्षों की निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, चार वर्षों की माध्यमिक शिक्षा और तीन वर्षों की विश्वविद्यालय शिक्षा। जो राज्य अभी ७ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा देने है वहाँ शिक्षा का ढाँचा ७+५+३ का होगा। साथ ही, उन विद्यार्थियों के लिए, जो माध्यमिक शिक्षा पूरे समय प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखते हैं, दस वर्षों की शाला शिक्षा समाप्त करने के बाद मैट्रिक परीक्षा लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली नितान्त वाञ्छनीय है। परन्तु प्रदेश और क्षेत्रीय तथा जिला स्तर पर भी विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार करने में अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में, समान शिक्षा प्रणाली पर जोर देने के कारण, नए मूल्यांकन और शोध करने में बाधा नहीं आनी चाहिए।

सरकार को एक राष्ट्रीय नीति के तौर पर शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता को मान्य करना चाहिए, और उन पर अपना नियन्त्रण कम से कम कर देना चाहिए।

१५ देश भर में युद्ध स्तर पर प्रौढ शिक्षा को आयोजित करने के सरकार के निर्णय का सम्मेलन स्वागत करता है। इस क्षेत्र में

भी बुनियादी शिक्षा के मिद्वानों को समुचित ढंग से लागू करना होगा ताकि 'वायगत साक्षरता' से जन ममुदाय की केवल नागरिक चेतना समुन्नत न हो बल्कि उनकी व्यवसाय सम्बन्धी उत्पादक कुशलता भी बढे। अध्यापकों और छात्रों को अपने प्रशिक्षण के एक-अभिन्न अंग के रूप में प्रौढ शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेना होगा।

१६ नई शिक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के लिए माता-पिता के सहकारक बल का संगठित रूप में सक्रिय सहयोग आवश्यक है। वस्तुतः प्रत्येक घर को शिक्षा की एक आधारभूत इकाई के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। शाला और घर दोनों एक दूसरे को समृद्ध करने में परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करें।

१७ बुनियादी शिक्षा के आधारभूत तत्वों को प्रथमिक से विश्वविद्यालय तक के सब स्तरों पर समाविष्ट किए जाने के महत्वपूर्ण प्रसंग में भारत सरकार से निवेदन है कि वह एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कर जिसमें शिक्षा क्षेत्र की सर्वेच्छित सेवा संस्थाओं का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। यह आयोग यथाशीघ्र अपने विस्तृत सुझाव सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करे।

१८ स्पष्ट ही उपयुक्त रूप में शिक्षा के पुनर्नियोजन के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय लागत राशि की आवश्यकता होगी। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल व्यय के मुकाबले में शैक्षणिक व्यय का अनुपात तीसरी पंचवर्षीय योजना के ६.८७ से घटकर चौथी पंचवर्षीय योजना में ५ प्रतिशत और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ३.२७ प्रतिशत तक नीचे आ गया है। यह रुढ़ी है कि शिक्षा सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत और योजना से बाहर के व्यय दोनों को दृष्टि में रखा जाएगा तो थोड़ा भिन्न चित्र सामने आएगा। लेकिन इस पर भी सारी स्थिति सन्तोषकारी होने से पर रहनी। जैसा कि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में सुझाया गया है हमारा लक्ष्य, शिक्षा-कार्यक्रम में कुल राष्ट्रीय आय का ६ प्रतिशत व्यय किया जाने का स्तर यथाशीघ्र लागू होना चाहिए।

१९ सम्मेलन को पूरी आशा है कि इस निवेदन में जो विभिन्न सुझाव दिए गए हैं, उन पर भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाएगा ताकि इनके कार्यान्वयन की ओर त्वरा की भावना से नदम उठ सकें।

२० साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो निर्णय, ध्यानपूर्वक विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एक बार लिए जायें उन्हें आगे दस या पन्द्रह वर्ष तक न छोड़ा या परिवर्तित किया जाए ताकि राष्ट्रीय शिक्षा के सारे स्वरूप में एक स्थायित्व और सातत्य सुनिश्चित रह सके। राष्ट्रीय सहमति से निर्धारित शिक्षा का स्वरूप दलीय नहीं समझा जाना चाहिए।

२१ सम्मेलन के अध्यक्ष, सम्मेलन की सिफारिशों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए २१ सदस्यों की कार्य समिति (Follow-up Committee) नियुक्त करने को अधिकृत किए जाते हैं, जिसे सदस्य सहचरित करने का अधिकार होगा।



नई तालीम एक 'तन्त्र' नहीं 'विचार' है। बच्चों की तालीम एक शुभ कार्य है। इसे 'नई तालीम' नाम दिया गया है। लेकिन मैं इसे 'निरत्य नई तालीम' कहता हूँ। निरत्य नई तालीम का मतलब है, जो कल थी, वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं रहेगी। जैसे नदी का पानी। नदी बहती रहती है, लेकिन प्रति क्षण उसका पानी नया होता है। वैसे ही रोजके अनुभव के आधार पर जो निरत्य बदलती रहती है, वह है, निरत्य नई तालीम।

नई तालीम याने नए मूल्यों की स्थापना।

चिन्ता

सेवाग्राम आश्रम-वृत्त (नवम्बर, दिसम्बर, १९७७ का)

यद्यपि यह वृत्त नवम्बर, दिसम्बर १९७७ का है फिर भी प्रकाशन के लिए जनवरी १९७८ में दिया जा रहा है ।

मन् १९७८ तो हमारे लिए महाशुद्ध के रूप में प्रगट हुआ । हमारे गांधी परिवार के महाप्राण सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पूज्य श्री श्रीमन्नारायण जी को महामृत्युने प्राप्त लिया । उनका स्वर्गवास हुआ । सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के लिए यह कभी भी पूर्ति न होने वाली क्षति हुई ।

ईश्वर उनकी आत्मा को चिरस्थान्ति दे यही विनम्र प्रार्थना है ।

दिसम्बर के १८, १९, २० को दिल्ली में अखिल भारत नई तालीम समिति द्वारा अखिलभारतीय शिक्षा परिषद का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता पूज्य श्रीमन्जी ने की थी और दिन रात अथक परिश्रम करके इस प्रयास को सफल बनाया था । पूज्य बापू के शिक्षण विषयक विचारों को भारत के उच्च कोटि के शिक्षा-विदों द्वारा स्वीकार कराने में श्रीमन्जी सफल रहे यह विशेष आनंदकी बात है । मृत्यु के पूर्व श्री श्रीमन्जी ने एक बहुत ही बड़ा कार्य किया यह कहने में किसी तरह का सकोच नहीं होना चाहिए । सेवाग्राम आश्रम का सारा वातावरण पूज्य श्री श्रीमन्जी के चले जाने से शोकाकुल है ।

सेवाग्राम आश्रम में इस अवधि में कुल ११ मेहमान आकर रहे और आश्रम जीवन का अनुभव लिया । इनमें इंग्लैंड, नेदरलैंड, हॉलैंड, अमेरिका और जर्मनी की भाई बहनें शामिल हैं । विशेष अतिथियों में भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण, विश्वधर्म संस्थापक श्री बाहुल्लाह, तथा महाराष्ट्र के वित्त मंत्री श्री जोगेश देसाई थे ।

इस अवधि में आश्रम के सारे कार्यक्रम निरामित चले । नई तालीम प्रातः प्रार्थना की औसत हाजरी १२ रही, सायं प्रार्थना में औसत हाजरी १२-५० रही, सूत्रयज्ञ में हाजरी ५० रही ।

(अ) वापू कुटी में वापू के आसन की सुरक्षा का प्रवध किया गया दर्शनार्थियों के साथ आने वाले छोटे बच्चे वापू का आसन न बिगाड़ सकें इसकी व्यवस्था की गई।

(आ) वापू द्वारा उपयोग में लाई गई चीजों की दीर्घ कालीन रक्षा के लिए पूज्य श्रीमन्जी की सलाह से इन स्मारक चीजों पर वैज्ञानिक क्रिया करने के लिए गांधी राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय के कार्यकर्ता श्री शरद पड्या के साथ दिल्ली भेज दिया गया। आश्रम परिसर में जो सफाई कार्य प्रतिदिन चलता है वह साधकों द्वारा व्रत भावना से किया जा रहा है।

इस अवधि में कुल ४३४६ दर्शनार्थी आश्रम दर्शन के लिए आए। इनमें १।३ विद्यार्थी थे। कुल २८९ टोलियां आश्रम दर्शन के लिए आई थी। इस अवधि में एक शिविर और एक परिसयाद आश्रम प्रतिष्ठान परिसर में हुआ, दिसम्बर ४ से लेकर ८ तक समाज विज्ञान तज्ञों की सगोष्ठी यहाँ के बला भवन में सम्पन्न हुई जिसमें प्रत्यक्ष कार्य में पड़े हुए भारत के अनुभवी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। दूसरा एक शिविर २७, २८, २९ दिसम्बर को ग्रामीण मजूर संघ द्वारा संगठित किया गया।

६ नवम्बर को राष्ट्र सत श्री तुक्डीजी महाराज के पुण्य स्थल से १५० पदयात्री एक रात के वास्तव्य के लिए आश्रम में आए थे। २५ दिसम्बर को ईजू जयंति के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थना का आयोजन बला भवन में किया गया था। नित्य के प्रति ३० तारीख को सामूहिक भोजन सर्व धर्म केन्द्र के गई तालीम कुटी प्रांगण में हुआ। इस माह में कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय शिविर कार्यक्षमता के कारण नहीं हो पाया।

तूफान पीड़ितों के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित की गई राशि मदद के रूप में दी गई। ईद के दिन दुर्ग (म प्र) के ज्ञानी श्री सादिक अली ने आश्रम के वापू कुटी में हज मनाया। उन्होंने पवनार जाकर पूज्य विनोबाजी से भी भेट की।

श प्र. पांडे
कार्यालय-मन्त्री

श्रद्धा सुमन

[ठी श्रीमन्नारायणजी के अमागेयिक निधन से उनके अनेक पहेतों के मन दुर्बल होना स्वाभाविक है। उनके कुछ महत्वपूर्ण मायियों के थड़ा-सुमन यहाँ दिए जा रहे हैं।]

वे बयू तोड़कर आगे चले गए

आज श्रीमन्नारायणजी की मृत्तु की अवानक खबर मिली। आज ही वे यहाँ पहुँचनेवाले थे। लेकिन वे चले गए। दादा की उम्र ८२ है, उनकी ६५ साल की उम्र थी। बयू तोड़कर वे आगे चले गए।

गांधी-निधि के अध्यक्ष थे, वे गवर्नर भी थे, राजदूत भी थे। हिन्दुस्तान भरमें कार्य तो उन्होंने अनेक किए हैं।

सुचारुतया में शांति रखना, तटस्थ रहना यह उनका गुण था। हमेशा सत्यबुद्धि कायम रखते थे। वे हमेशा मध्यमार्ग में चलते थे। यह उनकी एक विशेष बात थी।

मेरे लिए वे सहारा थे।

ऐसे व्यक्तित्व की आज हमने खोया है। आता तो सबको है, इमामिए कुछ क्या करना? लेकिन जो इतना साधन करके, सत्य बुद्धि से परलोक गमन करते हैं, उनको निःसंशय सद्गति मिलेगी।

३-१-१९७८

विनोबा

गोवरधनदास चौखवाला

मुरत, गुजरात

१४-१-१९७८

श्री श्रीमन्नारायणजी के जाने से आप सबको भारी छोट पड़ी है। श्रीमती मवासभा बहन पर भी भारी पड़का पड़ा है। मुरखी जानकी बहन को इस उम्र में भारी आघात महसूस करने का प्रसंग आया है। श्रीमन्जी गुजरात भरने सीटी सुवास छोड़ गए हैं और आज सब कोई उनको प्रेम से याद करते हैं।

चौखवाला के सप्रेम प्रणाम

कस्तूरबा धाम

१४-१-१९७८

मुरजी श्री श्रीमन्नारायणजी के जाने से देश को बहुत बहुत खोद पड़ी। बापूजी के रत्नारमक कार्य को घेग देने के लिए उन्होंने छुट्टी मेहनत करना औरम कर दिया था। अभी अभी जात जात के सम्मेलन भरे, काया को घिस डाला। ईश्वर ऐसे आत्मा को शक्ति बक्षेगा ही। गंधी स्वयंसेवक निधि के अध्यक्ष उनके जैसा कौन मिलेगा? आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी सोचना तो पड़ेगा ही। समा बुलाने का रहेगा ही बहन मवातला बहन को मिलने के लिए आना ही है। कब आना होगा यह देखने का रहा है। हमें पास मिल गया है मेरी सेवा आश्रम को देता ही रहेगा।

अज्ञात बालक

कमुके सादर प्रणाम

श्रीमन्जी हम लोगोंके बीच प्रकाश स्तम्भ थे। देश की वर्तमान समस्याओं पर निष्पक्ष निर्भीक तथा नियोजित विचार व्यक्त करने वाले व्यक्तियों को आज कितनी कमी है। श्रीमन्जी सदैव जाग्रत थे और दूसरेसे भी यही कामना रखते थे

उनके अगुदे कार्य को हमें पूरा करने में लग जाना चाहिए जिससे उनको आत्मा को शांति मिले।

७-१-७८

रामचरित्र

हरिसिंह कालेज, खड़गपुरा मुंगेर

भीमन्जी की याद में

धी - हत हुई

मन - ललित ॥

नारायण - यह कता तेरा समाधान ?

जिन्होंने बपू और बाबा की बात

से जान का धाम किया सब ओर

सर्वोदय और सरकार के बीच

बांधा सेतु

सत्त्याओं और रचनाओं लग साधियों से

स्नेह सतु सजोए जीवन भर

राष्ट्र भाषा अब शास्त्र तात्वीय और

कुदृष्टि हलज आदि

सभी गांधी कायके बिरबोंकी सोंचा

अपनी ज्ञान-शक्ति-भक्तसे

अवस्थितता मृदुता और शालीनता

के गुणों को प्रकाशित कर

वे सदाकी सुगाधत कर गए

उपवन यह

भजन सङ्ग्रहालय }
वर्षा ३-१-८७ }

-देवेन्द्र कुमार



If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee "

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

" यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे । "

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गौहाटी - न्यू देहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

सम्पादक-मण्डल :

श्री यजूभाई पटेल - प्रधान सम्पादक

श्रीमती मदालसा नारायण

डॉ० भदनमोहन शर्मा

वर्ष २६

अंक ४

अनुक्रम

शिक्षा में ही क्षति नहीं ।	—मदालसा नारायण	
मुनहवा कूल वपातपा ।	—	२
हमारा दृष्टिकोण	—	३
बुनियादी शिक्षा तब और अब	—श्री द्वारकाप्रसाद सिंह	७
सेवाग्राम में नहीं तालीम	—श्री सत्यनाथन्	१३
सेवाग्राम वृत्त	—	२७

फरवरी-मार्च '७८

- 'नहीं तालीम' का कार्य अगस्त से प्रारम्भ होता है ।
- 'नहीं तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपए हैं और एक अंक का मूल्य दो है ।
- पत्र-व्यवहार करते समय प्राइम जर्नी सक्षमा लिखना न भूलें ।
- 'नहीं तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री प्रभाकरजी द्वारा व भा नहीं तालीम समिति, सेवाग्रामके लिए प्रकाशित जी
राष्ट्रभाषा प्रेम वर्धा में मुद्रित

शिक्षा में हो क्रांति नई !

सुख शांति समाराधन अपूर्व, दिग् दिगन्त में फैलाना है,
 शिक्षा में हो अब क्रांति नई ही, करके यही दिखाना है !
 यह पुण्य भूमि, भारत स्वदेश, सत्कार प्रवाह चिरतन है,
 एशिया खण्ड है महाद्वीप, में भारतवर्ष प्रतिष्ठित है !
 गुण-गौरव गुजन 'राष्ट्रदेव भव', भाव-रूप हो सदाचरण,
 'राष्ट्रीय ऐक्य एकता रूप, शिक्षा का हो मंगलाचरण !
 विद्यात्मक हो अध्ययन गहन, चैतन्य सजग चितन पावन,
 सम भाव हृदयमें लहराएँ, आनंद रूप हो नवजीवन !
 अंतर में हो सत्कार तरल, सब धर्मों का हो ज्ञान तिमल,
 जन मान करें, सम्मान करें, आपस में हो सदाभाव सरल !
 सत्सनेह प्रवाहित हो अंतर सर, तरल तरंगित उनत हो,
 आनंदविभोर रहें बालकगण, तन-मन स्वस्थ, समुन्नत हो !
 उद्योग-परायण शिक्षण हो, उत्पादन का हो भाव भरा,
 दिन दिन उत्साह थड़े जीवन-अवलंबन सुखमय हरा-भरा !
 उत्साही हो, सब विद्यार्थी, सहयोगी हो, तेजस्वी हो,
 निर्मल, उज्ज्वल, जागृत, उद्यत, निर्भय हो सभी मनस्वी हो !
 जीवन को स्याई-सर्वो को वे समझें वृद्धता धरें सभी,
 बुनियाद सुदृढ़ हो जीवन की यह लक्ष स्पष्टता धरें सभी !
 उत्क्रान्ति प्रदायक हो शिक्षा, हो प्रगतिशील जीवन सुंदर,
 सकल्पवान वृद्ध धैर्यवान हो तरुण राष्ट्र-दर्शन सुंदर !

— मदालसा नारायण —

दिल्ली

३१-१२-'७७

सर्वोदय के शिक्षा पुष्प श्रीमन्जी के प्रति श्रद्धाजलि—

सुनहला फूल कपास का*

झर गया

सुनहला फूल

कपास का

हाथ फटेगी कैसे रातों

कौन बनेगा दियना-धातों

बिछुड़ गया वपिता से गायक—

प्रिय जीवन — निवास का ।

शांत बुद्ध का सा मुख-मण्डल

मन था-अमृत बरा बमण्डल

तन था ऐसा पावन जैसे —

दोहा तुलसीदास का ।

कितनी आस्थामय थी भाषा

‘रोटी का राग’ ‘अमर-आशा

‘रजनी में प्रभात का अदुर’—

स्वर बाणो-विलास का ।

भक्ति विनोबा प्रति थी गहरी

गांधी के सपनों का प्रहरी

था जो रथ सर्वोदय का, पथ—

रचनात्मक प्रयास का ।

हुई शिशिर में कसी धरखा

मौन हुआ साँसों का चरखा

हाथ कटेगा कस धामा ?—

शिक्षा के विकास का ?

एक आश्रमवासी सेवाग्राम

* साधु चरित सुभ चरित नपायू । निरख विसद गुणमय फल जायू ॥

जो सहि दुख परछिन्न दुरावा । बदनीय जहि जग जस पाया ॥

—श्री रामचरित मानस

— श्रीमन्नारायणजी के काव्य संग्रह

हमारा दृष्टिकोण

पुनरीक्षा समिति का विवरण :

। एम. सी ई आर. टी द्वारा दसवी कक्षा तक की पाठशालाओं के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों पर ईश्वरभाई पटेल पुनरीक्षा समिति का विवरण भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा जनचर्चा हेतु प्रकाशित किया गया है। समिति को निम्नलिखित पुनरीक्षा करने को कहा गया था:—

- (१) क्रमवार और विषयवार उद्देश्य जो 'दसवर्षीय पाठशाला' के लिए पाठ्यक्रम सम्बन्धी एन सी ई आर टी के दस्तावेज में अभिन्न अंग के रूप में सबद्ध किया गया है।
- (२) एन सी ई. आर टी पाठ्यचर्या पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों की इस पुनरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म परीक्षण करना। तथा
- (३) अध्ययन की योजनाओं का सूक्ष्म परीक्षण करना तथा इस बात की जाँच करना कि क्या (कोई उपयुक्त) अध्ययन की योजना या समय पत्रक या दोनों में कोई उपयुक्त आपरिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए तथा कर्मचारियों का उपयुक्त ढाँचा सुझाया जाए।

'समिति' को नई योजना के व्यवस्था के सिद्धान्त प्रस्थापन की पूरी स्वतंत्रता थी।

३० सदस्यों की इस समिति के अध्यक्ष उपबुलपति थे तथा सभी प्रदेशों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों के साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के डिप्टी कमिशनर, वाउन्सिल आफ इडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के मंत्री, अध्यापकों के दिल्ली

स्थित यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि, दिल्ली के पालक शिक्षक असोसिएशन के प्रतिनिधि तथा तीन अन्य शिक्षाविद् इसमें समाविष्ट थे। अन्य सभी एन सी ई, आर टी के अधिकारीगण थे।

समिति ने जो सुझाव दिए वे संक्षेप में इस प्रकार हैं—

१ प्रादेशिक सरकार, स्थानीय अधिकारियों तथा शिक्षा और परीक्षा बोर्डों को पाठ्यक्रम योजना में स्थानीय एवं विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे उसमें यथार्थता एवं लचीलापन आ सके, वह सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त हो, उत्पादक हो तथा सामाजिक सेवा के अनुरूप हो। उसका शालेय पाठ्यक्रम में केन्द्रीय स्थान हो। इस योजना को कारगर बनाने के लिए कक्षा १ से ४-५ तक १० प्रतिशत समय दिया जाए, कक्षा ५-६ से ७-८ तक प्रति सप्ताह ६ घंटे के हिसाब से कुल ३२ घंटे, कक्षा ९ से १० तक ६ घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से कुल ३२ घंटे समय दिया जाए। ()

सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्यों को पूरे विषय का स्तर दिया जाए। भाषा को बोठारी कमीशन की सिफारिश के अनुरूप महत्व दिया जाए। कक्षाओं में पढ़ाई २॥ से ३ घंटे से अधिक न हो। भाषा को छीटकर पहली दूसरी कक्षा में बाई पाठ्य पुस्तक न हो, तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में भाषा की एक पाठ्य पुस्तक हो, गणित की एक तथा स्थितिगत अध्ययन के लिए एक पुस्तक हो। अध्यापकों के लिए भी अध्यापन हेतु मार्ग दर्शिका हो। समय सारिणी लचीली हो। अन्य पाठ्य पुस्तक कम की जा सकती हैं विज्ञान की एक और नागरिक-शास्त्र तथा इतिहास की मिलाकर एक तथा उनकी पृष्ठ संख्या कक्षा ५, ६, ७, ८ के बालकों की उम्र के आधार पर रखी जाए। गृह-कार्य के स्थान पर कक्षा में ही अपनी देखरेख में कार्य कराए जाने की सिफारिश की गई है। स्वाध्याय हेतु सचित्र पुस्तिका का प्रकाशन वाछनीय है। (२)

गणित और विज्ञान के वैकल्पिक पाठ्यक्रम रहें और उनके पाठ्य-विषय निर्धारित रहें। २ के स्तर पर प्रवेश हेतु गणित या विज्ञान विषयक उपलब्धियों को उन विषयों के विशेष पाठ्यक्रमों हेतु बरीयता दी जाए।

इतिहास, नागरिक शास्त्र तथा भूगोल क्षेत्रीय पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाया जाए। अन्य वैकल्पिक विषयों में कला क अन्तर्गत संगीत, नृत्य, चित्रकला में से तथा गृह-विज्ञान, कृषि, अर्थशास्त्र, परिनिष्ठित भाषाएँ आदि में से किसी एक का अध्ययन किया जाए।

17. पाठ्य पुस्तकानी कामग्री ऐसी रह जो विषय सबधी आवश्यक जानकारी देने की दिशा में उपयोगी हो। क्षेत्रीय आवश्यकतानुरूप उपयुक्त शिक्षका का निर्धारण हो तथा उत्पादक कार्य पर अधिक बल दिया जाए। शिक्षक और छात्रों में उपयोगी तथा आवश्यक ताल मेल की आवश्यकता पर भी भर दी गई है।

18. उपर्युक्त सभी कल्पनाएँ सचमुच उत्साहवर्द्धक हैं। फिर भी यदि हम पाठ्य-चर्या पर अधिक निबटस अध्ययन करत हैं तो हम उसमें कल्पनाओं और उनके कार्यान्वयन में अधिक स्पष्ट असंगति पा पात हैं कक्षा। 19. 19-20 में सामाजिक उपयोगिता क उत्पादक कार्य में सप्ताह में केवल 6 घंटे ही निर्धारित किए गए हैं। उत्पादक कार्य क संयोजन का जिन्हें प्रत्यक्ष अनुभव है व एकदम यह कह दग कि कार्य और सामग्री उत्पादन की दृष्टि से सप्ताह में 6 घंटे का समय कोई सतोपजनक परिणाम नहीं द सकेगा। होगा यह कि 6 घंटे का समय 6 तासिकाओं में परिवर्तित कर दिया जाएगा और तयान्वित अच्छी पाठशालाओं में तो इतना भी समय नहीं दिया जाएगा। अतएव यदि इस दिशा में हम सचमुच गंभीरता पूर्वक सोचत ह तो इस कार्य क लिए उपयुक्त आवश्यक समय दिए जाने की आवश्यकता पर विचार करना होगा।

भाषाएँ, विज्ञान तथा गणित को पाठ्यचर्या को तो नवोन्मेषिनी कहना नठिन ही है। वे सभी विषयवार ऐसी पाठ्यचर्या हैं जो आजकल सवसाधारणतः परीक्षावाली निर्धारित अध्यापन प्रणाली में उपयोगमें आती हैं। उनमें पूर्णकरण के लिए नठिनाई स ही कुछ गुंजाइश होती है। यदि शिक्षा को कार्यशील बनाना है, जैसा कि उसक उद्देश्य में निर्दिष्ट है— तो उसकी रूपरेखा एकदम भिन्न प्रकार की होनी आवश्यक है। नयानुभव, सामाजिक जीवन तथा सामुदायिक उन्नति, स्वास्थ्य

तथा सामुदायिक सफाई जैसे अन्य कार्यक्रमों से जन तथा कार्य नुपलता की उपनधि होनी चाहिए। हमारी पाठ्यचर्या के डीके यह बताएँ कि बार्मा-नुभव तथा शिक्षा अनुभव कैसे हर वदमपर एक दूसरे से गुंथे हुए और एक दूसरे से विश्वस्त तथा एक दूसरे से पुष्ट है।

पुनरीक्षा समिति ने इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास किया है ऐसा नहीं दिखाई देता। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक मुझे भय है कि समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की बल्बमा कागंजपर ही रह जाएगी।

पुनरीक्षा समिति के गलत गठन के कारण ही ये तथ्य अन्य कई कमियाँ रह गई हैं। लोगों का किस प्रकार चयन किया गया है इसका उल्लेख मैंने ऊपर जान बूझकर किया है। यदि समिति ऐसे ही सदस्यों की बने कि जिन्हें यास्तविक बल्बमा ने अनुरूप कार्य-शिक्षा का शालेय स्तर तक का अनुभव नहीं है और यदि स्वेच्छिक संगठना के उपयुक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था न की गई हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं यह स्पष्ट ही है।

यदि जनता सरकार सचमुच शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए उत्सुक है तो उन्हें कार्य के उपयुक्त व्यक्तियों को चुनना चाहिए।

बज्रमोई पटेल



बुनियादी शिक्षा : तब और अब

१११ १ श्री द्वारिकाप्रसाद सिंह

आज से छ महीने पहले मुझे श्री वज्रभार्द्वाजी ने राष्ट्रीय शिक्षण भवन में आकर व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रित किया कि बुनियादी शिक्षा के बारे में मैं अपने विचार दूँ। सुनकर मर मन में भव उठे यह कसा देता है जिसमें लोग गांधीजी के सानिध्य में रहे उनके विचारों का अनुभव करते रहे फिर उन्हीं के गिप्य विनोबाजी को सुनत आए फिर भी बुनियादी शिक्षा के सत्वजन को नहीं समय। फिर मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, कैसे समझा सकता हूँ?

मैंने सोचा देश की वर्तमान शिक्षा के प्रति इतना आग्रह है। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में सबेदनशीलता असतोष की भावनाएँ व्याप्त हैं जिससे विघटनकारी प्रवर्तन हो रहे हैं समाज अपनी संस्कृति से जो कि सर्वव्यापक उत्तम उदाहरण मानी जाती है दरबिनोर होता जा रहा है, ऐसे वातवरण में दश व सामने एक ही राह है और वह है बुनियादी शिक्षा की। बापू की दश निर्माण की तपस्या मानव सृजनार्थ दिए हुए मानवमूल्य से अहिंसक शक्ति से नए मूल्य से नए समाज की स्थापना हो सकती है।

१९६८ में एक अधिकृत शिक्षा-आयोग ने निवेदन प्रस्तुत किया कि प्रत्येक स्तर पर (प्राथमिक माध्यमिक, उच्च) बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एन सी, ई आर टी तथा शिक्षा विज्ञान के द्रन उस पर गहराई से सोचा है और सभी ओर से एक ही निष्कर्ष स्वीकृत हुआ कि बुनियादी शिक्षा में ही देश की स्थिति बदलने का सामर्थ्य है। उसकी देश में व्यापक रूप से फैलाने में शिक्षक ही अपसर होकर कार्य कर सकता है। अतः ट्रेनिंग कालेज के विद्यार्थी जो शिक्षक बनने वाले हैं उनसे मिलने का तथा उनके समक्ष अपने विचार रखने के लिए मुझे यह मौका दिया गया इसलिए मैं आप सबका हार्दिक

आभारी हैं। सन् १९३८ से मैं बुनियादी शिक्षा के काम में लगा हुआ हूँ। इस राजेन्द्रप्रसादजी ने मुझे गदानन्द आश्रम में बुनार कहा था तुम इस शिक्षा में आ जाओ। तब मैं एक होईस्वर्ग में शिक्षण का काम करता था फिर भी निष्ठावन्त शिक्षक के नाते मैं उसमें आ गया। इस काम के सत्रमिने में राज्य सरकार के उच्चतम ओहदो पर, एवं साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया। अतः ये सब विचार मेरे निजी जीवन के अनुभव हैं।

बुनियादी शिक्षा का विकास— यह विषय बहुत व्यापक है और कम से कम ५ व्याख्यान उससे लिए चाहिए फिर भी तीन व्याख्यानों के लिए इन विषय का तीन खंड में विभाजन करेंगे।

(१) अपने देश में बुनियादी शिक्षा का विकास।

- (क) बुनियादी शिक्षा की पृष्ठभूमि
- (ख) कल्पना की आरम्भ की स्थिति
- (ग) प्रयोग की स्थिति

(२) १९४७ के बाद बुनियादी शिक्षा के विकास का प्रथम चरण।

- (क) स्पष्ट दर्शन
- (ख) योजना
- (ग) उपलब्धियाँ निवारण

(३) १९५९ से बुनियादी शिक्षा में गिरावट के कारण और निदान, आजादी के बाद शिक्षा की स्थिति आज की स्थिति तथा जे पी की संपूर्ण क्रान्ति में उसकी व्यवस्था।

पृष्ठभूमि — यह मानें कि नई शिक्षा की कल्पना गांधीजी की निजी मौलिक कल्पना थी। बहुत लम्बे समय से १९ वीं सदी के मध्य से हमारे समाज सुधारका ने देश में आधुनिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में सुधार करने के बारे में सोचा था तथा प्रयत्न किए थे। उन्ही सुधारकों की सूची में गांधीजी भी हैं।

गांधीजी ने भारत के गाँवों को देखा था, किन्तु बिहार के—बपारन में गाँवों को नजदीक से देखा और जाना। उन्होंने गाँवों में अत्याचारों

का नया चित्र देखा। बूढ़ रिपोर् के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली से गांव टूटते जा रहे हैं और गांवों के टूटने से देश जी नहीं सकता। और बापू ने शिक्षा में चरमा हाथ में लिया। उनकी दृढ़ भावना थी कि ब्रिटिश साम्राज्य चरम से ही हटाया जा सकता है।

गांवों की आर्थिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिस्थिति एकदम बिगड़ती जा रही थी। इस समस्या का हल करने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय चलाने का प्रारम्भ हुआ था ताकि भारत के यवका को सच्ची शिक्षा मिल सके। स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेनेवाले यवक जिन्होंने कालेज को छोड़ दिया था उनकी शिक्षा के लिए ऐसे ढंग के विद्यालय की आवश्यकता थी जिनमें बिहार गजरात काशी विद्यापीठ तथा रवीन्द्रनाथ के गाति निकेतन आदि के नाम आते हैं।

१९२० से १९३० तक के दक्षिणी अफ्रीका के अपने निवास के दरम्यान गांधीजी के मन के शिक्षा विचार मर्मिमान हुए थे उन्हीं के विचारों के अनुसार उपर्युक्त विद्यापीठ चले थे। उन विद्यापीठों से जो ग्नातक निकले वे स्वावलम्बी सहयोगी स्वस्थ तथा सामाजिक जिम्मेवारी की समझने वाले नागरिक थे। इन्हीं दिनों गांधीजी 'हरि जन' में राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में लेख लिखते थे। ये लेख अँग्रेजी में होते थे। श्रीमन् नारायणजी ने बापू से पूछा कि ये अँग्रेजी में लिख हुए लख नितन लोग पढ़ सकते हैं? आप एक राष्ट्रीय सम्मेलन बलाइए। १९३७ जन की २२-२३ को वर्धा में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविद शिक्षामन्त्रिया तथा शिक्षका न भाग लिया। कुल मिलाकर इसमें ८०-८५ लोग थे। सभी न गांधीजी के विचार सुन। शिक्षा में श्रम काम तथा उद्योग के महत्व के बारे में गांधीजी न अपन विचार बताए। बापू का यह स्पष्टीकरण जोरदार रहा।

आज हमारे १५ लाख विद्यार्थियों के १५ लाख मस्तिष्क और तीस लाख हाथ निष्क्रिय बना दिए गए हैं। एम ए करने के बाद भी उनका जीवन में नैराश्य के सिवा कुछ नहीं रह पाता। निष्क्रिय शिक्षा

के ने राक्षसपूर्ण ३० लाख हाथ और १५ लाख मस्तिष्क से देश का विकास नहीं हो सकता। हर हाथ को काम मिले हर मस्तिष्क को चिंतन मिले वही सच्ची शिक्षा है, और तभी देश का विकास हो सकता है।

सम्मेलन में बापू ने कहा “मैं दस साल तक अराजकता (Anarchy) सहन कर सकता हूँ किन्तु एक मिनट के लिए भी ब्रिटिश शासन नहीं सह सकता हूँ। ब्रिटिश साम्राज्य देश को हिन्दू साम्राज्य के लिए तैयार नहीं कर सकता। उसे हटाने के लिए एक मात्र प्रभावी साधन है शिक्षा। उसके स्वरूप सम्बन्धी उन्होंने चार सिद्धांत निश्चित किए थे—7

(१) देज यदि स्वनत्र हुआ तो लोकतन्त्र की खरी कसौटी यह होगी कि लोग शिक्षित हो तथा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों। जनतन्त्र का विकास मछली जिला से होता है। प्रयत्न नागरिकता के लिए प्राथमिक जिला अनिवार्य होनी चाहिए। एक टोकरी में आम है। उसमें एक भी आम गिराव होगा तो सारे आम खराब हो जाएंगे। वैसे ही एक गरागती व्यक्ति सारे समुदाय को चैन से नहीं जीने देता। छोड़ जानेवालों की सरकार की रिपोर्ट पढ़ी होगी। १९६४ में मिडल क्लास तक पहुँचते पहुँचते ६९% सातवी तक पहुँचते पहुँचते ८१% और माध्यमिक तक पहुँचते पहुँचते ८०%, इसके बाद के मालूम नहीं कितने छोड़ जाते हैं। यह है छोड़ जानेवालों की स्थिति। जब तक शिक्षा नि शुल्क नहीं होती तब तक गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते। समन्वित समाज रचना के लिए, जनतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था के लिए बच्चों को न्यूनतम शिक्षा देना अनिवार्य है।

(२) जो भी शिक्षा १४ साल की आयु तक दी जाए वह नि शुल्क हो, अनिवार्य हो और अपनी मातृभाषा में हो। किन्तु पाँचवी कक्षा में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करा दी जाए। पाँचवी से अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता की बात का भाजंत्री साइकल ने जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि जहाँ शतप्रतिशत लोगों को अक्षरज्ञान नहीं है वहाँ पाँचवी से ही अंग्रेजी सीखने सिखाने से क्या फायदा?

(३) शिक्षा, स्वावलम्बी हो :— छात्र तथा शिक्षक मिलकर परिश्रम करेंगे। उससे जो कुछ आर्थिक प्राप्ति होगी उससे शिक्षकों का वेतन तथा विद्यालय का खर्च निबलना चाहिए। १९४६ में इसमें परिवर्तन किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा बनाने की योजना तय हुई। उस योजना को बनाने का भार एक समिति को सौंपा गया। उस समिति के अध्यक्ष डा. जाकिर हुसेन थे। उस समिति के सदस्य देश के श्रेष्ठ चिंतकों में से थे। उनका नाम था :—

(१) डा. जाकिर हुसेन	सभापति
(२) श्री स्वाजा गुलाम संयदेन	सदस्य
(३) श्री काका कालेलकर	"
(४) श्री किशोरीलाल मशरवाला	"
(५) श्री के. सी. कुमारप्पा	"
(६) श्री कृष्णदास जाजू	"
(८) श्री विनोबाजी	"
(७) श्रीमती आशादेवी	"
(९) श्री आर्यनायकम्	संयोजक सदस्य

समिति ने २-२॥ महीने में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के पाँच हिस्से थे—

(१) स्वास्थ्यवर्धक त्रिम्याशीसता :— देश को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन-यापन करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि अपने तथा अपने परिसर की स्वच्छता तथा स्वस्थता के विषय में जाग्रत बने तथा उसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दे।

(२) सामुदायिक जीवनयापन :— धर्म, जाति, रहन-सहन विचार, खानपान इनमें विविधता में एकता कैसे हो, उसमें समता, एकता कैसे प्रस्थापित करे इसका बराबर खयाल रखें।

(३) उत्पादक कार्य :— रिपोर्ट में वस्त्रस्वावलम्बन, भोजन स्वावलम्बन, लकड़ी और लोहा, खेती, खादी और शिल्प के उद्योगों—

जिनमें प्रशासनिक कठिनाई न हो— की प्रियाओं और मापदंडों को बताया ।

(४) समाज सेवा :— छात्र श्रमिक हो विन्तु वह व्यक्ति-निष्ठ न बने यह देसना होगी । उसीसे मनुष्य का संतुलित विकास होता है ।

(५) मानसिक विनास :— छात्र के मस्तिष्क, का संतुलित विकास हो ।

शिक्षा तीन प्रतिवेगों के आधार पर चलेगी । शिक्षा के केन्द्र में बच्चा होगा । बच्चे का समाज, बच्चे के जीवन के लिए उद्योग और बच्चे के चतुर्दिक व्याप्त प्रकृति ये तीनों उसकी शिक्षा के समर्थ साधन होंगे । उद्योग का स्रोत प्रकृति है । समाज के अवलम्बन से उद्योग चलेगा । प्रकृति के उपयोग में चिन्तन, शोध और विज्ञान की ओर मुड़ना होगा । क्रियाशीलता की व्यवस्था में पारस्परिक श्रम, सहयोग, संस्कार इत्यादि की आवश्यकता होगी । उक्त तीनों आधारों के माध्यम से तरह तरह के ज्ञान-विज्ञान बच्चों को सहज रूप से मिल जाएंगे ।

योजना तैयार हुई । गांधीजी के विचार से यह तब किया गया कि जिन प्रान्तों में कांग्रेस का प्रशासन है वहाँ यह नई शिक्षा प्रयोग में लाई जाए । इसीलिए आसाम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बम्बई और मद्रास में नई शिक्षा के प्रयोग की पृष्ठभूमि तैयार हुई ।

१९३८ के जून महीने में १५ दिन का एक शिविर सेवाग्राम में आयोजित हुआ । उस शिविर का आयोजन हिन्दुस्तानी तालीम संघ ने किया । उस शिविर में विनोबाजी, काका काललकर, किशोरीलाल मशरुवाला, आर्यभायकम्जी, आशादेवी, जाजूजी जैसे महानुभावों का साथ शिविरार्थी को मिला । कार्यकर्त्ताओं के शिविर से लौटने के बाद कांग्रेसी प्रान्तीय सरकारों ने बुनियादी शिक्षण का काम शुरू किया ।

नई शिक्षा का दर्शन तो स्पष्ट था । फिर भी उसके अनुसार काम करना कठिन था । मुझे ही कताई, बुनाई में निष्णात बनने में तीन साल लगे ।

बुनियादी शिक्षा का काम मुश्किल से एक साल चला होगा कि १९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ा। कांग्रेस मन्त्रिमंडल ने युद्ध प्रारम्भ होते ही त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के प्रयोग काल में अनुकूलता के लक्षण नहीं दिखाई पड़े। किन्तु बेडछी, गांधीग्राम आदि स्थलों पर जो प्रयोग हुए उससे साबित हुआ कि इस दशक की इसी योजना के साथ जीना होगा।

१९४७ विकास का प्रथम चरण है, जिसके अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा का स्पष्ट दर्शन, योजना तथा उपलब्धियाँ और सिफारिशों के विषय का समावेश होता है।

१९३८ से १९५८ तक के २० वर्षों का इतिहास बुनियादी शिक्षा के विकास के मध्याह्न का इतिहास है।

अंग्रेज शासकों ने बुनियादी शिक्षा की भारीबी की समझा। ग्रेट ब्रिटन के शिक्षा शास्त्री साजेंट ने उसका स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इसी शिक्षा से देश बनेगा। किन्तु उसमें एक बात खटवती है और वह यह कि आप इस शिक्षा में स्वावलम्बन की बात न रखिए स्वावलम्बन को हटा दीजिए। गांधीजी ने कहा सारी शिक्षा योजना का प्राण स्वावलम्बन ही तो है। उस हटाना नामुमकिन है। स्वावलम्बन ही इस शिक्षा की कसौटी है अन्तः परीक्षा है। स्वावलम्बन के बिना पाठशाला निरूपयोगी है।

एक प्रसंग याद आ रहा है। १९३९ में चंपारन में मैं बुनियादी शिक्षा का प्रयोग कर रहा था। गांधीजी के समक्ष पाठ देता था। स्कूल के बच्चे नगधड़ग, धूलि धूसरित, मटमेल थे। मैं ३३ लड़कों को कुएँ पर ले गया, हाथ मुह, धुलाया, पोछा, गांधीजी ११ बजे आए किन्तु मरा सफाई का काम चलता रहा। लड़कों को स्वच्छ करके लाया और बताई-बायें शुरू हुआ। गांधीजी ने समीक्षा की—'दि लक्षण कायमें निपुण किन्तु बताई ठीक नहीं।' बलभस्वामी ने जब उस टिप्पणी का विरोध किया तब गांधीजी ने कहा था मैं आदर्शों में मुलह नहीं कर सकता।

१९४० से १९४५ तक का समय सत्रमण काल था। बिहार में ७२ बुनियादी विद्यालय, २ ट्रनिंग स्कूल और उत्तर बुनियादी स्कूल खुले।

विहार में इस प्रसार योजना की यह विशेषता थी कि विहार के एक कोने में चम्पारन जिले के बृन्दायन क्षेत्र में २८ बुनियादी विद्यालय चल रहे थे, वहाँ विहार के सभी जिलों में बुनियादी विद्यालय स्थापित किए गए और सभी जिलों में उत्तर बुनियादी और ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निश्चय किया गया। बेंगलूर, धुलिया आदि में बुनियादी शिक्षा के स्कूल खोलने की योजना बनी। उत्तर प्रदेश में तो एक ही रात में सभी स्कूल बुनियादी शिक्षा के स्कूल बना दिए गए।

स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय शिक्षा बुनियादी शिक्षा है ऐसा प्रयोगों पर से महसूस हुआ। भारत सरकार ने भी राज्य स्तर पर योजना बनाई। उस योजनानुसार राज्य की प्राथमरी शिक्षा बुनियादी शिक्षा रहेगी यह भी तय हुआ। बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रतिष्ठान की स्थापना हुई जो बुनियादी शिक्षा के लिए साहित्य के निर्माण में मदद करता था। ट्रेनिंग कालेज के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए। (१) परीक्षा महा-विद्यालयों में सूचनात्मक सामग्री (instructional materials) होने चाहिए तथा उनका आदान-प्रदान हो सके, ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। (२) प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए उसका एक सेवा-क्षेत्र होना ही चाहिए। उस सेवा क्षेत्र में बच्चों के घरों की सफाई, खुला रंगमंच, बालक मंदिर, उद्योग, महिला मंडल, सड़कें आदिवा, समावेश होगा।

भारत सरकार के निर्देशन के अनुसार राज्य-सरकारों ने नई तालीम का पहला कदम उठाया। राज्य सरकारों ने अपने प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों को नई तालीम की तरफ मोड़ा। नए प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए उनके पास नई तालीम के अनुभवी शिक्षक नहीं थे इसलिए राज्य सरकारों ने अपने कुछ चुने हुए शिक्षकों और निरीक्षकों को नई तालीम में प्रशिक्षण के लिए सेवाग्राम भेजना शुरू किया। हिन्दु-स्तानी तालीम सच ने राज्य सरकारों को इस काम में बड़ी मदद की।

सन् १९५७ से १९५९ के मार्च तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने नई तालीम की दिशा में दृढ़तापूर्वक पहला कदम उठाया।

इसी बीच १९५५ में भारत सरकार ने देश में नई तालीम का जो कार्य चल रहा था उसके मूल्यांकन के लिए एक समिति बनाई जिसके निम्न लिखित सदस्य थे ।

(१) श्री जी रामचन्द्रन	संयोजक
(२) श्री रामशरण उपाध्याय	सदस्य
(३) डॉ सैयद अन्सारी	सदस्य
(४) डॉ एम डी पाल	सदस्य
(५) श्री जे सी बोस	शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार

इस समिति ने वेसिक शिक्षा के बारे में सात स्तर पर सुझाव दिए । ये सात स्तर इस प्रकार हैं — (१) भारत सरकार, (२) राज्य सरकार, (३) जनता, (४) बुनियादी तालीम के शिक्षकों के प्रशिक्षण कॉलेज, (५) विश्वविद्यालय (६) माध्यमिक विद्यालय (७) प्राथमरी बुनियादी तालीम विद्यालय ।

उस दृष्टि में भारतीय बुनियादी शिक्षा का प्रचार वैसे हो, उसके प्रसार के लिए क्या क्या उपाय करना जरूरी है उसके सबन्ध में सुझाव दिए गए थे जिससे शिक्षा-मयधी निश्चित कल्पना स्पष्ट हो सके ।

इस प्रकार कार्य का आरम्भ हो गया, जिससे ३ अनुभव स्पष्ट रूप से सामने आए —

(१) यह शिक्षा जनता के जीवन से अलग नहीं होगी, जनजीवन के आधार पर होगी । जो व्ययक्त्य दिए गए हैं, या सिनाए जाएंगे वे वास्तविक जीवन से ही सबद्ध होंगे न कि केवल स्कूली ।

(२) इस शिक्षा के कारण काम करने वाले हरिजन, ब्राह्मण जो एकसाथ नहीं आते थे, उनमें भेद कम होने लगे । गांव के लोगों में भी मनोरंजन में सांस्कृतिक जीवन के प्रति आस्था जाग उठी, संगीत और नाटकवा उसमें समावेश होने लगा । इस प्रकार सांस्कृतिक प्रवृत्तियों पर जोर दिया गया ।

(३) उत्पादकता — इस निष्ठा की मज्जे बड़ी विरोधता यहो है कि विद्यार्थी उत्पादक इराई बन गया। निष्ठा के माध्य उत्पादन द्वारा स्वावलम्बी जीवन की यह कल्पना बिलकुल अभिनव थी।

इस तरह से बुनियादी शिक्षा निश्चित रूप में प्रयोग में लावार हो गई। गुहाई द्वारा टिप्पण (आगम) में अच्छा काम हुआ। शितीश राय चौधरी के द्वारा यमान में ठीक से नहीं हुआ। उड़ीसा में, बिहार में उल्लेखनीय कार्य हुआ। उन सबके प्रयासों में कुल ५३५ स्कूल खुले, ७४ प्रशिक्षण महाविद्यालय, ७४ महाविद्यालय खुले। १९५७ में सर्वोच्च महाविद्यालय की स्थापना की गई। दिल्ली में जामिया मिलिया ने अच्छा काम किया। उत्तर प्रदेश में डा. अब्दुर्रहमान खान के नेतृत्व में काफी सफलता मिली। पंजाब, राजस्थान में, असफलता रही। मध्यप्रदेश में काफी विकास हुआ वहाँ तो बापू थे ही। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएँ अच्छी तरह सफल हुईं। इस प्रकार गिनोबा जी, रविशंकर शुक्ल मिनापचन्द दवे बाणीनाथ तिवारी, डा. दिवेकर इन लोगों ने बुनियादी शिक्षा के प्रसार में सहायनीय कार्य किया। भद्रास में भी सरकारी या निजी स्तर पर अच्छा कार्य किया गया।

इस सिलसिले में सारे प्राथमिक स्तरों को बुनियादी बनाने की योजना बन रही थी। राज्य-सरकारों ने प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा एक-अनस्थापन (Orientation) पाठ्यक्रम चलाने की आवश्यकता को महसूस किया। अतः सेवाग्राम द्वारा यह व्यवस्था की गई। जिसमें सारे देश के लोग आकर २-३ महीना का प्रशिक्षण लेने लगे। ये लोग राज्य स्तर पर उसी प्रकार का एक पाठ्यक्रम चलाते थे। इस तरह से चार क्षेत्रों में यह कार्य बँट गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक जाल की तरह अनुस्थापन का काम चलने लगा।

उसी समय विभिन्न प्रान्तों में नई तालीम के उपलक्ष्य में सम्मेलन होते थे उससे भारत की सारी संस्कृतियाँ समेटकर राष्ट्रीय स्तर पर एक विशाल भारतीय संस्कृति का रूप मूर्तिमान हो रहा था। भारत

सरकार न भी एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। जिसमें बुनियादी शिक्षा पर संशोधन कार्य करने के लिए फ़ैलविन क्लाइड, बेजामिन, सुलेमान जैसे लोग विदेशों से आते थे और गांधीजी के तत्वज्ञान का अभ्यास करते थे। यह बुनियादी शिक्षा के इतिहास का एक गौरव युग, एक स्वर्ण युग था। उस समय की जब मैं याद करता हूँ तो भीतर से आज भी उल्लास उमड़ आता है।

१९५८ में विनोबाजी ने इस मौलिक कार्य को मद्दे नज़र कर क 'अपना मत लिखा था कि अब बुनियादी तालीम का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है। पर रामचन्द्रन समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि कार्य गलत दिशा में चल रहा है। प्रायमरी बुनियादी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जब माध्यमिक विद्यालय में आते थे तो उनका साधा हुआ जीवन उपयोगी नहीं होता था और उद्योग भी बंद हो जाता था। अतः केवल प्रायमरी स्तर पर चलनेवाली शिक्षा निरुपयोगी है। जहाँ विज्ञान में माध्यमिक स्कूलों में भी उसका काम चलता था वहाँ भी उन विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता था। अतः डा. राधाकृष्णन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण बुनियादी संस्थाओं का आरम्भ हुआ किन्तु वहाँ से डिप्लोमा लेने वाले छात्रों को डिग्री के लिए प्रवेश नहीं मिलता था। अन्य बातें भी थीं। यदि शिक्षक अपना काम निष्ठा से करेंगे तो भारत के नागरिक भी उपयुक्त बनेंगे। और फिर शिक्षक वैसे ही बनेंगे जैसे कि प्रशिक्षण महाविद्यालय होंगे। परन्तु उन्हीं के काम में गिरावट आने लगी।

निष्ठासे काम करनेवाले शिक्षकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए इसके सम्बन्ध में बिहार के विद्यालय के एक शिक्षक को समझाते हुए कहा था कि खादी की कल्पना अलग ही है। नौकरी की पूर्वगर्त में खादी पहनना भले ही न हो, खादी के बारे में मैं हृदय परिवर्तन भी नहीं कर सकता पर जरूर कह सकता हूँ कि यह वस्त्र साधारण वस्त्र नहीं है, इसके अंदर में पीछे तो एक भावना है। अहिंसा की विचारधारा के लिए जीवनयापन करनेकी प्रणाली को अपनाना यही खादी पहनने का लक्ष्य है। उमकी विचार धारा है :—(१) सादा जीवन बिटाना, (२) नियमित

धम करना, (३) योग्य वतवि करना, (४) नशा सेवन न करना, (५) समन्वयपूर्ण जीवन, (६) अमंग्रह, (८) हफ्तेमें दो घंटे गमाज सेवा करना। उनके लिए अनिवार्य नहीं कि खादी पहनकर ही उसका महत्व समझना चाहिए, खादी न पहनकर भी खादी के संस्कार मनमें रह सकते हैं। चरखे का उपयोग, तो व्यवसाय के विकेन्द्रीकरण के लिए है।

मेरा तो खादी के साथ सीधा संबंध है इसलिए मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ। रही विकेन्द्रीकरण की बात। अंबर चरखे की कमाई से स्त्रियों को काम मिला। हररोज चार घंटे काम करने से ४ गुंडिया बनती हैं, उनसे ९ गज कपड़ा बनता है, गाल में ७०००० गज। उतना कपड़ा गांव की ग़रीबी दूर करने में मदद करता है। इसीलिए चरखा धड़ा का म्यान बँटा है।

आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में खादी का महत्व ग्रहण कर के अपने संस्कारों की विशेषताओं को कायम रख सकते हैं पर वे जड़ (rigid) न हों तबोले (flexible) होने चाहिए। जिंदगी के लिए जिन तत्वों को नहीं छोड़ा जा सकता वे महत्व हैं — (१) सादा जीवन, (२) स्वस्थ जीदन, (३) सहयोगी जीवन, (४) समन्वित जीवन, (५) सांस्कृतिक एकता, (६) फौदुम्बिक भावना, (८) विश्व पारिवारिक जीवन।

कोई भी राष्ट्र इन विचारों को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकता।

सभी अच्छाइयों को बावजूद भी प्रशिक्षण में गिरावट आने से उसका भविष्य अच्छा नहीं रहा। आचार्यों के भरसक परिश्रम के बाद भी उनमें अपार न घर्ष छिड़ गया।

तब भारत सरकार ने निश्चय किया कि अपने देश में शिक्षा की दो दो प्रणालियाँ एक साथ नहीं चल सकती अतः एक समन्वित पाठ्यक्रम बनाना होगा। प्रत्येक राज्य का एक ही पाठ्यक्रम होगा, १८ राज्यों ने प्राथमरी व बेसिक तत्वों का समन्वय करके एक पाठ्यक्रम बनाया।

समीक्षा इस प्रकार हुई कि उसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं। १९५९

कै जनवरी से ३ राज्यों में उसपर अमल किया गया, वहीं उसका पटन का क्षण था। पूरी ईमानदारी से बनाई हुई अच्छी योजना की शुरुआत थी वहीं जमका लय हुआ।

आम जनता की धारणा है कि यह शिक्षा असफल हो गई, पर उसकी उपलब्धियाँ भी हैं और वे बुनियादी शिक्षा की असफलता के बावजूद भी महत्वपूर्ण हैं। इन दो दिनों में आपने बुनियादी शिक्षा का २० वर्षों का इतिहास देखा आज उसकी उपलब्धियाँ देखेंगे जो आपको प्रेरणा दे सकें।

बुनियादी शिक्षा की उपलब्धियाँ तीन खंडों में देखने मिलेंगी।

(१) स्वास्थ्य सफाई— लोगों को सफाई के महत्व का भान हुआ। लोग साफ-सुथरे रहने में गौरव महसूस करने लगे। स्वच्छताका असर जनस्वास्थ्य पर भी पड़ा। वंशभूपा में परिवर्तन हुआ किन्तु लोग सादगी से रहते थे। महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को पारंपरिक जीवन से अलग एक नई दृष्टि मिली। एक ऐसी नई बात जैसे पहले कभी बताई नहीं गई थी, कभी सोची नहीं थी। उदाहरणार्थ पटना के विद्यालय के बच्चे ७० एकड़ का मैदान बिना नौकरों के साफ करते थे। बड़े बड़े अमीरों के लड़के श्रम की ओर उन्मुख हुए, उनके घरों में जैसे दर्जनों नौकर काम करते थे। सादिपनी आश्रम में कृष्ण सुदामा एकत्र जीवन बिताते थे उसी प्रकार बुनियादी विद्यालयों में गरीब अमीर एक साथ काम करते थे यह एक महान क्रांति थी। इस प्रकार की वृत्ति और वातावरण धीरे-धीरे बनता जाता था, देहातो में मलमूत्र विसर्जन की बड़ी समस्या थी। देश के पाँच लाख गाँवों में बसने वाली स्त्रियों की दयनाक स्थिति थी, नई बहुएँ शौच के लिए बाहर नहीं जा सकती थीं। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाए यह सोचा गया और कुछ उपाय भी किए गए। उसीके कारण सर्वोत्तम सुलभ शौचालय; आधुनिक मुविद्याओं के साथ बन जा आज भी विहार में उपयोग में लाए जाते हैं। स्वास्थ्य के बारे में यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।

(२) स्वास्थ्यमय और श्रम का महत्व :— श्रम के काम में सज्जा का भाव जीवन से मिट गया। सुबह की प्रार्थना से लेकर सायंकाल

की प्रार्थना के समय तब वाम किया जाता था। राजा जनक की हल चलाने की कहानी रामायण में है और बम्बुनिस्टो का हँसिया और हथोड़ा भी श्रम का प्रतीक है। १९५३ का साल श्रमोत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शृषि बागवानी, सागवानी, फलरक्षण, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन, गोपालन, कुकटुपालन, घताई, रगाई, छपाई, सिलाई, गलीचे दरियो की बुनाई आदि उद्योगों के जरिए ३ लाख ३० हजार की आय हुई। बिहार सरकार ने तब किया कि ऐसे उत्पादन का ५०% फायदा विद्यार्थियों को, और ५०% स्कूल को मिलेगा। बिहार में सरकार के पास ३५ लाख रुपये जमा हो गए। गाँव साफ हो गए, श्रम उत्पादन की दिशा मिल गई।

(३) सांस्कृतिक जीवन — सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के परिवर्तन में गांधीजी रुकल हुए थे। बगंभेव, छूआछूत, छोटे बड़े के भेद मिटे और अपनेपन की भावना पनपी। चपारन, बेंडछी, मछलीपट्टन आदि जहाँ जातिभेद ऊँचाई पर था वह यम हुआ।

मनोरंजन के लिए देहातो में सांग शहरों में जाते थे, पर देहातो की मोदम डलियों के कार्यक्रमों को देखने, सुनने के लिए देहात के लोग इकट्ठे होते थे। अतः सिनेमा के उत्तेजक गाने जो कि शहरों के प्रभाव से गाये जाते थे बद हुए क्योंकि लोगों ने मनोरंजन के लिए शहरों तक जाना छोड़ दिया। सिनेमा गीतों की जगह भजनो, समूह गीतों ने संगीत ने ल ली।

मेकैल ने कहा था, हमें भारतीयों को ऐसी शिक्षा देनी है जो रफ्त और देह से भारतीय हो विन्तु मस्तिष्क और विचार में अंग्रेजियत रखते हों। इस व्यापक अंग्रेजियत के प्रसार का विरोध बुनियादी शिक्षा के इन विभिन्न कार्यक्रमों से अहिंसक रूप से हुआ। प्रार्थना सभाएँ बनाई गई, बच्चा व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बलेरिज नं० ७९ स्कूलों का निरीक्षण कर के कहा आत्म ज्ञान का बोध इस शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। बिहार के इस १९४३ के कार्यक्रम के बारे में स्टुवर्ट ने रिपोर्ट लिखते समय कहा था कि इस शिक्षा व्यवस्था से उत्पन्न आत्म-विश्वास, स्वावलम्बन ये गांधीजी की आत्मा के परिणाम हैं।

गिरावट कैसे आई? — ऊपर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद शिक्षा में गिरावट कैसे आई वह विचारणीय है। ममन्वित पाठ्यक्रम के द्वारा धीरे धीरे स्कूल के कार्यों में परिवर्तन होने लगा। उसके निरीक्षक निरीक्षण में विभिन्न प्रकार की सूचना देने लगे जैसे सफाई बंद करो, 'प्रार्थना बंद करो आदि। कताई नहीं हो सकी क्योंकि उनके लिए व्यवस्था भी नहीं थी। अतः विद्यार्थी विवश होकर पारंपारिक स्कूल में जाने लगे। लोगों में भी निराशा फैल गई और बुनियादी शिक्षा का अगले का भविष्य बिलकुल निराशाजनक रहा। वैसे भी आदर्श को निर्माण करना आसान है उसे जीवन में उतारना कठिन होता है। गलत लोगों के हाथ में शिक्षा जाने से काम अमफल होने लगा। फल-स्वरूप ६०-६८ तक तो यह बिलकुल वद सी हो गई। इसी काल में कोठारी कमिशन की रिपोर्ट निकल गई। उसमें उन्होंने लिखा है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बुनियादी शिक्षा के प्रयास आज उसके ढाँचे के रूप में ही हैं उनकी आत्मा मर गई है।

आज की वर्तमान स्थिति — आज तो बुनियादी शिक्षा का नामो-निशां नजर नहीं आ रहा है। बिहार में जहाँ सबसे अच्छा काम हुआ था वहाँ आज एक भी नलास नहीं रहा। कितने ही उच्च शिक्षित प्रशिक्षितों को अन्यत्र काम नहीं मिलता है। इस प्रकार जो बुरी परंपरा चल रही है उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए। जे. पी. की संपूर्ण क्रान्ति की घोषणा हो चुकी है। उस पार्श्वभूमि में बुनियादी शिक्षा के बीज पनप सकते हैं। बेकारी, शिक्षित विद्यार्थी, राजनेताओं की नीति तथा देश की दुर्दशा की स्थिति में इस बुनियादी शिक्षा से सहारा मिल सकता है।

हमारे पंतप्रधान श्री मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल के प्रथम भाषण में कहा है— पहले बच्चों को आदमी बनाओ बाद में उन्हें दूसरी बातें सिखाओ। इस कथन को तथा जे. पी. की संपूर्ण क्रान्ति को सफल करने के लिए बहुत ही संगठित प्रयत्न करने चाहिए। बुनियादी शिक्षा के नवनिर्माण का काल है। उनके लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :—

(१) भारत सरकार बुनियादी शिक्षा को कार्यान्वित करने की घोषणा करे।

सेवाग्राम में नई तालीम

श्री सत्यनाथन

भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम का एक बालक 'नई तालीम' है जिसकी सेवाग्राम में प्रगति इस संग्राम के उबार भाटे के साथ अनमिल थी। गांधीजी ने इस संग्राम का तथा शिक्षा योजना का दिशानिर्देश किया था तथा इन दोनों को बदलने वाली परिस्थितियों के अनुरूप इन्हें ढाला था।

सन् १९३७ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ९ प्रदेशों में शासनसूत्र सभावा अतः वह शिक्षा के लिए भी जिम्मेवार बनी। वह अनिवार्य शिक्षा तथा दारुबंदीको लागू करने के लिए वचन दद थी। गांधीजी ने इसे अमल पाया कि शिक्षा मददान की कमाई की बगई पर आधारित हो। ऐसे समय पर मारवाडी शिक्षा मंडल वर्धा अपनी रजत जयन्ती मना रहा था। इस उत्सव के एक अंश के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किए जाने की योजना पर विचार किया गया। यह सम्मेलन दिनांक २२-२३ अक्टूबर १९३७ को वर्धा में हुआ तथा इसमें भारत सरकार तथा अन्य प्रादेशिक सरकारों के शिक्षा मंत्रियों तथा प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों ने भाग लिया। गांधीजी ने अपने अध्ययनीय भाषण में हस्त उद्योगों द्वारा शिक्षा को आत्म निर्भर बनाने की अपनी योजना को समझाया। उचित विचार विमर्श के पश्चात् गांधीजी की कल्पना सम्मेलन द्वारा स्वीकृत की गई। तत्पश्चात् मार्च १९३८ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा (गुजरात) के ५१ व अधिवेशन में इस सम्मेलन की सिफारिशें स्वीकृत की गईं और उसी के तत्वावधान में एक स्वायत्त मस्यौदा 'हिन्दुस्तानी तालीमी मध' का गठन हुआ। इन मस्यौदों को राष्ट्रीय शिक्षा की योजना को आग बढाने का काम सौंपा गया। इस मस्यौदों के सविधान के अनुरूप इस निम्नलिखित कामों का अधिकार था —

- (अ) बुनियादी तालीम के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करना
- (ब) बुनियादी तालीम की समस्याओं का संचालन एवं निरीक्षण

(क) अध्यापकों के प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, सहायता एवं निरीक्षण

(ङ) उपयुक्त साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन

(ख) आवश्यक शोध कार्य का किया जाना

(ग) आन्दोलन का आयोजन

(घ) प्रादेशिक तथा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित बुनियादी तालीम के कार्यक्रम के स्वीकार हेतु आवश्यक कदम उठाना।

संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार हिन्दुस्तानी तालीमी संध ने सेवाग्राम में तथा अन्य कई प्रदेशों में सन् १९५९ तक नई तालीम का काम प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् वह सर्व-सेवा संध में विलीन हो गया।

नई तालीम के सेवाग्राम के कार्य को तीन अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है —

(१) बुनियादी शिक्षावस्था : १९३९ - १९४४

(२) समग्र नई तालीमवस्था - १९४४ - १९५२

(३) ग्राम स्वराज्य— नई तालीमावस्था : १९५२, १९५२

(१) बुनियादी शिक्षावस्था: (१९३९-१९४४) -

हिन्दुस्तानी तालीमी संध ने अपना प्रमुख कार्यालय सेवाग्राम में इस हेतु स्थापित किया था कि जिससे कार्यक्रम संचालन हेतु गांधीजी का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। संध की २३, २४ अप्रैल १९३८ को हुई इसकी पहली बैठक में संध ने सेवाग्राम में प्रायोगिक बुनियादी पाठशाला प्रारम्भ करने का निश्चय किया, किन्तु यह निर्णय सितंबर १९३९ में ही एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल शिक्षक तथा चार छात्रों के साथ क्रियान्वित हो सका। संध की बैठक से पहले या पाठशाला के प्रारम्भ होने से पहले योजना को कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रदेशों द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों की माँग की गई। इसके लिए वर्षा में २१ अप्रैल १९३९ को शिक्षकों तथा निरीक्षकों के लिए एक अल्प कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। सन् १९४१ तक जब दूसरा बुनियादी सम्मेलन दिल्ली के पास जामिया नगर में हुआ तब तक सेवाग्राम की यह पाठशाला चौथी

वक्षा के स्तर तक की पाठशाला हो गई थी। उक्त सम्मेलन के लिए दिए गए अपने संदेश में गांधीजी ने इस बात पर बल दिया था कि "पूरा प्रयोग बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप और सघिके वही न वही किया जाना है।" अपने सीमित साधनों के भीतर इस प्रयोग को सेवाग्राम के कार्यकर्ताओं द्वारा उसके सही रूप में करने का प्रयत्न किया गया।

देशपर जब तूफान के बादल उमड़े तब १ अगस्त १९४२ को जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है आवासीय बनियादी पाठशाला तथा प्रशिक्षण शाला नई तालीम भवन— केवल प्रशिक्षण महाविद्यालय ही नहीं था, किन्तु एक ऐसा घर था जिसमें शिक्षक और छात्र आत्मीय भाव से एक साथ रहते, काम करते एवं अध्ययन करते थे। क्योंकि जैसा कि डॉ. झाकिर हुसैन ने निर्दिष्ट किया है "सच्ची शिक्षा वह है जो प्रेमपूर्वक दी जाती है।" आप देखेंगे कि शिक्षा की पुस्तक के पहल पृष्ठ पर ही 'प्रेम' शब्द लिखा हुआ होगा।

इस भवन का दूसरा उद्देश्य यह था कि उस का आधार 'सत्य' होना चाहिए। इसी उद्देश्य से वहाँ की दैनिक प्रार्थना, उपनिषद् से ली गई थी जिस का अनुवाद इस प्रकार है— मैं केवल सत्य ही बोलूंगा, सत्य मेरी रक्षा करेगा, सत्य मेरे शिक्षक की रक्षा करेगा।

इस प्रार्थना को सुनकर इस भवन का उद्घाटन करते हुए बापू ने आशीर्वाद दिया था— "यह प्रार्थना आपकी रक्षा करे।" कुछ दिनों बाद ही वे जेल में थे।

(२) समग्र नई तालीम अवस्था (१९४४-१९४७)

१९४२-४५ तक का समय इस लघु समाज और राष्ट्र के लिए अधिकार और नैराश्रय या उदासी का था। किन्तु यह समय वैसा ही अण्डे-मेवन का था जैसे अधिकार में धरती से अकुर फूट निकलता है। इस समय में नई तालीम की विचार धारा धीरे-धीरे बाह्य और सेवाग्राम के मस्तिष्क में रूप ग्रहण कर रही थी। नई तालीम योजना के जनक गांधीजी भी उस योजना के आशय या मूढार्थ के विषय में चिन्तन कर रहे थे। मन् १९४४ में जब वे जेल से बाहर आए तो 'नई तालीम' के तथा उसके उद्देश्य या क्षेत्र के विषय में उनकी नई दृष्टि थी।

गुरु में जैसा कि सोचा गया था यह योजना केवल अनिवार्य शिक्षा अर्थात् ७ से १४ वर्ष तक की उम्र के लिए ही थी। गांधीजी 'नई

(क) अध्यापकों के प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, सहायता एवं निरीक्षण

(ड) उपयुक्त साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन

(ख) आवश्यक बोध कार्य का किया जाना

(ग) आन्दोलन का आयोजन

(घ) प्रादेशिक तथा निजी-संस्थाओं द्वारा संचालित बुनियादी तालीम के कार्यक्रम के स्वीकार हेतु आवश्यक कदम उठाना।

संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने सेवाग्राम में तथा अन्य कई प्रदेशों में सन् १९५९ तक नई तालीम का काम प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् यह सर्व-सेवा संघ में विलीन हो गया।

नई तालीम के सेवाग्राम के कार्य को तीन अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है—

(१) बुनियादी शिक्षावस्था : १९३९ - १९४४

(२) समग्र नई तालीमवस्था : १९४४ - १९५२

(३) ग्राम स्वराज्य— नई तालीमवस्था : १९५२, १९६२

(१) बुनियादी शिक्षावस्था: (१९३९-१९४४) :

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने अपना प्रमुख कार्यालय सेवाग्राम में इस हेतु स्थापित किया था कि जिससे कार्यक्रम संचालन हेतु गांधीजी का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। संघ की २३, २४ अप्रैल १९३८ को हुई इसकी पहली बैठक में संघ ने सेवाग्राम में प्रायोगिक बुनियादी पाठशाला प्रारम्भ करने का निश्चय किया, किन्तु यह निर्णय सितंबर नवम्बर १९३९ में ही एक डिस्ट्रिक्ट कोशिल शिक्षक तथा आर छात्रों के साथ क्रियान्वित हो सका। संघ की बैठक से पहले या पाठशाला के प्रारम्भ होने से पहले योजना को कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रदेशों द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों की माँग की गई। इसके लिए वर्षा में २१ अप्रैल १९३९ को शिक्षकों तथा निरीक्षकों के लिए एक अल्प कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। सन् १९४१ तक जब दूसरा बुनियादी सम्मेलन दिल्ली के पास जामिया नगर में हुआ तब तक सेवाग्राम की यह पाठशाला चौथी

सेवाग्राम आश्रम-वृत्त

(जनवरी, फरवरी, १९७८ का)

आश्रम प्रतिष्ठान परिक्षेत्र में इस अवधि में पूर्णतया शोक की छाया ही फैली रही । उधर आंध्र प्रदेश के अवनिगुड्डा क्षेत्रमें सूफान तथा जलप्रपात द्वारा जो मानव हुआ और जो मानव सहार हुआ वह भी अति भयानक था । इस तरह १९७८ का प्रारम्भ ही शोकग्रस्ता से हुआ । फिर भी आश्रम का काम पूर्ववत् ही चला । आश्रम प्रतिष्ठान के मंत्री श्री० प्रभावराजी ने पूरे तीन माह तक अहोरात्र अन्याहत परिश्रम कर अवनिगुड्डा क्षेत्र के पुनर्रचना के कार्य में सहयोग दिया । आश्रम प्रतिष्ठान की ओरसे श्री सूर्यनारायण मूर्तिजी तथा श्री चरणदास भी इस क्षेत्र में सहायता कार्य के लिए गए थे ।

स्वर्गीय आचार्य श्रीमन्नारायणजी की आत्माकी चिरशान्ति के लिए आश्रममें तथा १३ जनवरी को विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया और दिवंगत आत्मा की स्मृति में आश्रम प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया ।

इस अवधि में ७६१० दर्शनार्थी आश्रम देखने आए जिनमें २३३ टोलियाँ भी शामिल हैं । विद्यार्थी वर्ग की उपस्थिति विशेष प्रसन्ननीय रही । इस अवधि में हॉलैंड एन्स, जापान, कॅनेडा, जर्मनी, अमेरिका से कुल मिलकर २१ विदेशी अतिथि आश्रम में दर्शन तथा अध्ययन हेतु रहे ।

जनवरी २२ से लेकर २५ तक “ग्रामाभिमुख विज्ञान” इस विषयपर एक अन्तर्राष्ट्रीय परिसंवाद आश्रम प्रतिष्ठान परिक्षेत्र में मगन सप्रहालय की ओरसे आयोजित किया गया । इस परिसंवाद में कुल ३२ विदेशी वैज्ञानिक तथा ५० भारतीय वैज्ञानिकाने भाग लिया

और दारिद्र्य रेखा के निचले स्तर वालों के लिए विज्ञान का उपयोग किम तरह हो सकता है इस संबंध में चर्चाएँ की। श्री देवेंद्रभाई गुप्त ने अपने साथियोंकी मदद से इसका सुन्दर आयोजन किया था।

आश्रम के नित्य कार्यक्रम नियमित रूपसे चले। प्रातः प्रार्थनाओं में कुल औसत उपस्थिति ६.५ रही, तथा सायं प्रार्थना में औसतन १४.५ लोग ही रहे। दोपहर के सूनयज्ञमें ८.५ उपस्थिति रही।

स्मारक कुटियों की रक्षाकी दृष्टि से इस अवधि में बापू के बैठने की गद्दी और पात के सामान की सुरक्षा को ध्यानमें रखते हुए एक बारीक रस्सी से यह स्थान घेर दिया गया। इस व्यवस्था को आश्रम प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष पू० चिमनलाल भाईजी तथा मंत्री श्री प्रभाकरजी ने मजूरी दी। अब बापूके गद्दीकी पूरी सुरक्षा तो हुई है किन्तु दरनायियोंके लिए भी कोई असुविधा नहीं हो पाई। बापू द्वारा उपयोग में लाई गई स्मारक वस्तुओंमें से दिल्ली के गांधी संग्रहालय के पास दीर्घकालीन सुरक्षा उपचार करने के लिए बापू के कपड़े दिये थे वे सारे उपचार के बाद वापिस लाए गए हैं। अब सफ़ाई की चीजें तथा धातुकी बनी चीजोंको थोड़ी थोड़ी करके दिल्ली भेजी जाएंगी जिसकी प्रतिकृतियाँ बनवाकर तथा उनपर दीर्घकालीन सुरक्षा उपचार कराकर वापिस सेवाग्राम आश्रम में रखी जाएगी।

शं. प्र पांडे

५६

संस्था कुल

गांधी स्मारक निधि का मासिक

सम्पादक - श्री पूर्णचन्द्र जैन

वार्षिक शुल्क-५ रुपये,

एक प्रति-५० पैसे

रचनात्मक प्रवृत्तियाँ वार्यों सर्वोदय संगठन एवं

राष्ट्रीय हस्तशिल्प की जानकारी देनवाला

एक प्रभावशाली माध्यम

संपक करें-व्यवस्थापक, संस्थाकुल

गांधी स्मारक निधि,

राजघाट, नई दिल्ली-२

गांधी मार्ग

गांधी विचारक सृजनात्मक साहित्य का मासिक

सारगर्भित लेख, लघु लेख, कहानी, नाटक, कविता,

संस्मरण एवं व्यक्ति-चित्रों से युक्त

विचारणीय पाठको एवं मवसाधारण पाठका के लिए पठनीय

सम्पादक

श्री भवानोप्रसाद मिश्र

वार्षिक शुल्क रु १२

द्विवार्षिक रु २२

एक प्रतिका मूल्य १ रु

संपक करें व्यवस्थापक 'गांधीमार्ग' (हिंदी मासिक)

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, २२१-२२

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली-२

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action 'alone these can increase Thee."

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

"यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गौहाटी - न्यू देहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

हिंदुस्थान शुगर मिल्स लिमिटेड का विभाग मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स की शुभ कामनाएँ

उच्च धेनी का 'शक्ति' छाप सीमेंट जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सब तरह के नवनिर्माण कार्य के लिए मजबूती तथा विश्वस्तता के साथ किया जाता है।

व्यवस्था एवं बिक्री कार्यालय—

फैक्टरी,
पो आँ बजाज नगर
(सी एफ ए)
जि उदयपुर (राजस्थान)
फोन दबोक ३६ और ३७
उदयपुर २६०६

शहर कार्यालय,
६० नया पत्तेपुरा
उदयपुर ३१३००१
फोन ४४९, ग्राम 'श्री'
उदयपुर

नयी तालीम



संयोजक
प्रौढ़-शिक्षा अंक

प्रौढ़ शिक्षा पर गांधी जी के विचार
प्रौढ़ शिक्षा पर विनोबा जी के विचार
हिन्दी का विकास क्या हो ?

—जयप्रकाश नारायण



भारतियेल भायत नयी तालीम अमिति

वर्ष २६
अप्रैल
नवम्बर

अंक

प्रधान संपादक — श्री के० अक्षयचलम्

संपादक मंडल — श्री द्वारिका सिंह

श्री बज्रमार्ग पटेल

श्री काशीनाथ त्रिवेदी

श्री ज्योति भाई बेष्टाई

सम्पादक — डा० देवेन्द्र दत्त तिवारी

संपादकीय १

शुद्ध विषयेयुं ज्ञान शक्तिं न लभयेत् ४ पू० विनोबा

श्रीष्ठ शिक्षा पर चापीजी के विचार ३

श्रीष्ठ शिक्षा पर विनोबाजी के विचार ८

हिन्दी का विकास क्या हो १० श्री जयप्रकाश नारायण

हमें स्कूल को क्यों समाप्त करना है ११ अनु० डा० देवेन्द्र दत्त तिवारी

उत्तर प्रदेश और श्रीष्ठ शिक्षा १५ श्री द्वारिका प्रताप माहेश्वरी

समाजोपयोगी संपादक कार्य के द्वारा शिक्षण २० श्री बज्रमार्ग पटेल

राष्ट्रीय श्रीष्ठ शिक्षा कार्यक्रम-एक रूपरेखा २२ शिक्षा एवं समाज उत्थापन-समाजवादी भारत सरकार, नयी दिल्ली

श्रीष्ठ शिक्षा नीति वक्तव्य ३२ शिक्षा तथा समाज उत्थापन, मंत्रालय, भारत सरकार

मानवसंश्लेषण साक्षरता दिवस ३५ ज्ञान ई० पाठ्य, उप निदेशक, यूनेस्को

श्रीष्ठ शिक्षा की समस्या है ४१ श्री बाबूराम मधवाल

नयी तालीम

शिक्षाको प्रशिक्षणको एवं समाज शिक्षा के लिए

सम्पादकीय

प्रौढ शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम इतिहास की पुनर्जागरिता

दिसम्बर १९७३ में प्रौढ शिक्षा का राष्ट्रीय नीति घोषित की गयी और प्रौढ शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देने पर बल दिया। इसके पूर्व जो ध्यानपूर्ण चर्चा चल रही थी सामाजिक शिक्षा और विकास का बल दिया गया था किन्तु इस बार का प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम मुख्यतः साक्षरता केन्द्रित है। नीति वक्तव्य के अनुच्छेद ३ में कहा गया है कि प्रौढ शिक्षा में समाज के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वंचित लोगों को साक्षरता प्रदान करने पर बल देना चाहिए। यह बात भी संकेत रूप में कही गयी है कि यह कार्यक्रम सीखने वालों के जीवन में सम्बन्ध होना चाहिए।

प्राथम्य के तहत १० करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का बड़ा चाली सक्षम निर्धारित किया गया है। वर्ष १९७३-७४ की यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से अधिकार के रूप में चलाया गया तो प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने ठीक ही कहा कि इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारण ठीक नहीं है और उन्होंने यह सुझाव दिया कि १५ वर्ष से ऊपर के लोगों को भी इस कार्यक्रम में लिया जाय। वैश्वीय शिक्षा मन्त्री जो उस समय समा में उपस्थित थे। यह सुझाव स्वीकार कर लिया। इस ही कार्यक्रम की मुक्ता और भी बढ़ जाती है।

राष्ट्रीय नीति के घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम को जन-आन्दोलन के रूप में चलाते की आवश्यकता है। घोषणा का अर्थ महत्वपूर्ण कि यह है कि कार्यक्रम विकेंद्रित रूप में संचालित किया जाय और इसके निम्न प्रतीति पुनर्-संरचना कर भी जाय। इससे किसी की आपत्ति नहीं हो सकती कि निरक्षरता रोक के लिए किया गया है किन्तु जन-आन्दोलन की बात घोषणापत्र में कही गयी है उसका कोई स्वरूप नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यह स्पष्ट है कि जन-आन्दोलन सरकारी तंत्र और लोकतन्त्रादी द्वारा नहीं चलाया जा सकता। यदि इसे जन-आन्दोलन का रूप देना चाहे तो इस योजना का कम से कम सरकारी तंत्र के क्षेत्र में नहीं चलना पड़ेगा। आज यह कार्य ऐसे सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है जिनकी संपत्ति अव्यवस्था और सेवाप्रदाता से ही लोगों को सहे है। यह कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र की समस्त योग्यता तथा सेवाप्रदाता पर भी लोगों को सहे है किन्तु इन सहे में सतरा कम है और यदि है तो फिर विकेंद्रिकरण की बात घोषणापत्र में की के पहले ही होनी चाहिए थी। आवश्यकता इस बात की थी कि राज्य मन्त्रालय, मन्त्रालय सभी स्तरों पर सरकारी स्थापना का सहयोग लेकर कार्यक्रम को जन-आन्दोलन के रूप में चलाया जाय।

जनवरी १९७८ में राष्ट्रीय कार्यक्रम की विस्तृत योजना सामने आई। जिन अनुमानों पर योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है अब ये ही आधारहीन हो तो योजना की सफलता संवेहास्पद हो जाती है। योजना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'कार्यक्रम जन आन्दोलन का रूप लेता है यह इस बात पर निर्भर रहेगा कि नवमुख और विद्यार्थी वही तक इस कार्यक्रम से प्रतिबद्ध किये जा सकते हैं। आम शिक्षण संस्थाओं का जो वातावरण विभिन्न प्रदेशों में है और उनके समाचार प्रति दिन अखबारों में आते हैं, उसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि आम का मुखक स्तरित या अन्वित रूप से अत्यंत सूख है, उसकी समस्याओं का समाधान होने का कोई बम्प्रीर प्रयास किसी रिवा में नहीं हो रहा है। अतः युवकों का सहयोग एक काल्पनिक आधार मान रह गया है।

योजना की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में (५०) पर प्रोड शिक्षक से कार्य चलाने की योजना है। ग्रामीणों को विकास कार्य के प्रति समुच्च एव प्रेरित करना, का विकास-कार्यों को माध्यम बनाकर साक्षरता का कार्य पूरे करना कोई सरल कार्य नहीं है। यह निश्चित है कि ५० व० पर कार्य करने वालों से कार्य की पूर्ति नहीं होगी और केवल पढ़ी-लिखी छात्रों को भेजे जाते रहेंगे जैसा अब तक का इतिहास रहा है।

प्रोड शिक्षा के शिक्षकों, प्राधिकाधिकों आदि की प्रशिक्षण की भी व्यवस्था योजना में है। किन्तु जिस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह न केवल अपर्याप्त है बल्कि एक रचनापूरी मान है। उ० प्र० में मार्गल स्कूलों में प्रशिक्षण दिया गया है। यह सर्वविधित है कि मार्गल स्कूलों के पास प्रोड शिक्षा का कोई जानकारी नहीं है। यों नहों कल्प ही विषय की जानकारी नहीं है। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था उ० प्र० में साक्षरता निदेशक समन्वय में की गयी है। वहाँ जो कुछ प्रशिक्षण मिलता है, उसकी भी जानकारी लोगों की है। उनको स्वयं से ही साक्षरता के बारे में चले चल रहे हैं यह भी भोग जानते हैं। अब प्रशिक्षण की वह स्थिति है जो योजना की प्रगति के साक्षर में अनुमान लगाया जा सकता है।

साक्षरता की संपादनी का काम का केन्द्रीय सरकार के निर्देशावली में हो रहा है, कुछ राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषदों अनुसंधान परिषद किसी तथा कुछ प्रदेशों के राज्य सरकार के भी पर। यह बिंदु का विषय है कि जो कुछ भी सामग्री सामने आ रही है वह परम्परागत विधियों पर आधारित है। उपलब्ध साक्षरता की सही समीक्षा की जाए तो साक्षरता तदर्थ सामने आयेगी। इसका एक कारण यह भी है कि साक्षरता की संपादनी के पीछे वैज्ञानिक दृष्टि का वैज्ञानिक योग नहीं है। भारतीय 'निरक्षर' को बर्दाश्त में रखकर सामग्री को साक्षरता के लिए वैज्ञानिक दृष्टि का वैज्ञानिक योग नहीं है। भारतीय 'निरक्षर' उनसे अधिक मजबूती माना मोल सजता है उनसे अधिक बग से जाने पानी की समीक्षा कर सजता है और उसे मोल मोल और मोल सजता है उनसे नहीं अप्रत्या ज्ञान है। रूप से उपलब्ध विवेचना यह समझते हैं कि यहाँ की प्रोड शिक्षा की समस्या मुख्यतः 'विश्वित को साक्षर बनाने' है न कि अविश्वित को साक्षर बनाने की। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यक्रम पर नये विवे से विचार न दिया गया तो प्रोड शिक्षा के इतिहास की केवल पुनरावृत्ति होगी।

स्व० धीरेन्द्र मजूमदारजी अब नहीं रहे

स्व० धीरेन्द्र मजूमदार के कितना बड़ा था पीता मे अवसान कृष्ण द्वारा निरूपित स्थितप्रज्ञ की परिभाषा की समझता था । एक उन्मुख निर्भीक चिंतक और विचारक बनता, पावा, कर्मका एकक, अद्वय्य नातिकारी कलम और हुदास दोनों के एक साथ चली, यह है शरीर में यह महान् व्यक्तित्व जो २१ मजूमदार, १९७५ को ७७ वर्ष की अवस्था में हमने सर्वे के लिये भौतिक रूप से अस्तित्व हो गया । किन्तु उनके विचार उनके अद्वय्य अवधारणों द्वारा अद्वय्य लोगों को प्रेरणा दे चुके हैं । उनकी पुस्तकें 'समग्र ग्राम सेवा की ओर' 'नयी तालीम' और उनके अनेक लेख आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं ।

[१९०० में अलहबाद आन्दोलन में बागो हिन्दू विश्वविद्यालय के इतिहासकार के द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में उन्होंने अपना नातिकारी जीवन प्रारम्भ किया और आचार्य जे० बी० हुदासाजी के साथ रचनात्मक कार्यों में मग गए । १९१४ में उनके द्वारा स्थापित रबीन्द्र आश्रम, १९४६ में स्थापित सेवासुरी, १९५२ में स्थापित छात्रीघर (नू गैर) उनकी स्थापना एवं व्यवस्था के जीवित स्तम्भ हैं । १९४५ में अखिल भारत छात्रों संघ के अध्यक्ष तथा १९५२ में सर्वे सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश का रचनात्मक कार्यों में नेतृत्व किया ।

१० वर्ष की अवस्था में उन्होंने सहायक कार्यों में समाज के लिये और घर की सेवा में गाँव-गाँव बढ़ते और नातिक की दीप-दिल्ला प्रभावित रही ।

नयी तालीम तथा सहोदय परिवार उनके विषय में अत्यन्त प्रवीण और विवेक है । पूर्य विनोबाजी के एषों में '११० धीरेन्द्र मजूमदार करते थे' नातिक की नहीं जाती हो जाती है, नातिक की इसी अनिवार्यता के पक्ष में वे अपनी मजिद लोगों के भी आह्वान देते रहे । हम ऐसे महान् व्यक्ति के प्रति असीम आदरानि अर्पित करते हैं ।

पत्रिका के प्रकाशन के सम्बन्ध में

अखिल भारत नयी तालीम समिति ने 'नयी तालीम' पत्रिका अखिल में वाराणसी से प्रकाशित का निश्चय किया । प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण पत्रिका के प्रकाशन में विलम्ब हुआ है । अभी भी प्रकाशन सम्बन्धी औपचारिकताएँ पूरी नहीं हो पाई हैं । तद्विषय यह अकल्प्य पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं । भाषा है पत्रिका मजिद में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहेगी । पत्रिका की व्यवस्था का दायित्व अब उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति ने लिया है । अतएव इसका वार्षिक्य सेवापुर्ण (वाराणसी) में था गया है । हमें खेद है कि यह अकल्प्य अन्तरात से सभी आह्वानों की सेवा में प्रस्तुत हो रहा है । अन्तिम में इसका प्रकाशन नियमित हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे ।

सुद्र विषयेषु ज्ञानशक्ति न क्षपयेत्

चिन्तोदा

वाचनार्था जो कई चर्चाएँ एनी गेली ? जो गमो-गम विचार के आद्वय नहीं होती। ये नांव करते हैं कि कई विषय ऐसे हैं जिसका विषय हम करता पाहिण। मरे विषय में उनको गिनावत है कि मैं आलोचना करता हूँ तो बोध्य भाषा में नहीं ला करता हूँ। मेरे विषय में यह विचार नहीं है। जब बहुत अच्छत हमारे हैं तभी मैं किसी की आलोचना करता हूँ और वह जो तत्त्व पर चर्चा में। मोक्ष का बोध के बारे में मैंने ऐसी ही आलोचना की थी। दश। और जो ज्ञान आवे, जिस पर गिना तो बोध्य आलोचना की या नहीं की। यह मेरी कमजोरी भी हो सकती है या फिर तात्पर्य।

मेरी व्यक्तिगत बात छोड़ दोस्त। अहिंसा और नैतिक आलोचना का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि समाचारमय चिन्तन नहीं करता। दावा का उच्चारण और जारी करना नहीं करना चाहिए ऐसा नैतिक आलोचक मानते हैं। जहाँ जो मुद्दा है उसे ग्रहण कर मना पाहिण। जहाँ गुणों का ग्रहण करने दिया होय लगता हो जाने है। जब लोग बेचते हैं और उह बट देने हैं तो वे बट जाते हैं। विपरीत इतर, जब दीया नहीं देते, तो फिर गुणों के अतिरेक प्रमुख न अर प्रयोजन कर हम उतना बान पकड़ कर उतना दीया दूर कर पाते हैं। दोनों के अतिरेक किसी के अंदर प्रवेश करना नहिण है। मैं हीनार के माग में पना में क्यों प्रवेश करूँ, जब कि दरमामे और सिद्धियों से प्रवेश मेरे लिए सुना हुआ है।

कार्यकर्ता नहीं समझते कि यह एक बहुत बड़ा नैतिक आलोचक हमने खड़ा दिया है। वह छोटी-छोटी बातों से सगम नहीं। हम उसे छोटे आलोचकों में बट कर अपनी शक्ति धीछ नहीं करती है। अगर सिवाय और तकलीफें होती हैं और उहें सजावर दूर करती जाय तो सजावर की पकड़ मजबूत होती जायेगी। और जिसकी अच्छी सरकार होती, हमारा बान उतना ही बहिण होगा। बारहों तम वाद्यन मुक्त समाज कैसे बनेगा ? आप सरकार के पक्ष में हैं और सभी समुष्ट है। मजबूर के राज्य की मिसाल हमारे सामने है। यह बहुत अच्छी सरकार थी। फिर भी सक्त भाषा और सब जो सक्त आन्वासा है ऐसा मानना पड़ता।

तो हमें छोटे छोटे मतलबों पर अपना बहुत अधिक विषय और शक्ति नहीं लगानी चाहिए। यह बान करनेवाले तो बहुत से भोग हैं। तुमसीदासजी ने भी कहा है रामायण के कि बांधे की तो बहुत हैं पर छुड़नेवाला सिर्फ राम ही है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा अवश्य करनी चाहिए, ऐसी सेवा बिनाम पात्रिण कीज (वचनारम्य ज्ञान) जाग्रत होती जाये। ऐसा हो कि आपकी पास से ही हम आपको सतम करना चाहते हैं।

महाभारत की घटना है। महाभारत युधिष्ठिर भीष्म के पास पहुँच प्रणाम करने गया। भीष्म कुछ हुए। फिर भीष्म के पूछा गया कि वितामहकी भाषा में मुझे किस प्रकार होनी कृपा कर दयाइए। इस प्रकार किसी भी महाकाय में नहीं जाया। भीष्म वितामह ने यथा दिया कि बिना तब जरूरी प्युम्न होगी। इस तरह हिसक सवाई में भी न होने लगी अहिंसक रवैया अपनाया। फिर हम तो अहिंसक आन्दोलन ही छूट हुए हैं। तब हिसक रवैया की ओर क्यों जायें ? हमें अपने निरोधियों और सहयोगियों के अंदर प्रवेश कर उहें पूछना चाहिए कि तरीका क्या हो सकता है। इस प्रकार हम सफल होंगे इसमें मुक्त तनिक भी संदेह नहीं। मैं इसी बात की दृष्टि से रख कर नेताओं और बट बट लोगों के साथ करता हूँ जो मुझसे मिश्रते हैं। यह मेरी दृष्टि है, जो मैंने आपसे सामने रख दी। मैं नहीं जानता कि इसका आप लोगों का क्या क्या समझ न होगा। फिर भी संतुष्टि नहीं है यही मेरा दृष्टिकोण है। हमें छोटी छोटी बातों से बट कर अपनी शक्ति नहीं खानी है। सब मैं इस बारे में इतना ही कह कह सकता हूँ। यह भी ठीक, जब कि कार्यकर्ता बार बार मुझसे पूछते हैं।

प्रौढ़-शिक्षा पर गांधीजी के विचार

[१९४२ के प्रवा में प्रौढ़ शिक्षा समिति की बैठक हुई थी, उसमें प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में बापूजी ने कुछ प्रश्नों पर हुआ था। वह नीचे दिया जा रहा है, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा पर बापू के विचार पाठकों को साम्मुख हो सकें। वर्षों की मुक्त बरतें हुए बापूजी बोल]

“भाषने प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं प्रौढ़-शिक्षण के बारे में अपने विचार भाषने सामने रख दूँ। मैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में विचार करता ही रहता हूँ। मुझे करना ही चाहिए। आज भी मैं सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग बहुत द्रव्यमान भोज है। मैंने उल्टे पेट से प्रश्न करने के लिए चुनौती को स्वीकारा है। मैंने यह भी दृष्टि रखी है कि शिक्षण में जो मिला मिलता सराए है, उनके विद्यार्थी और वाचक भी अगर इस दिमाग के प्रश्नों को रोजाने के काम में शिक्षा में ही मुझे वह प्रिय लगेंगे। मैं जब इस काम को इस दृष्टि से देखता हूँ, तो पाता हूँ कि इसमें प्रौढ़-शिक्षण का हीमा सम्मिलित है। यही तो प्रौढ़ शिक्षण है। मैंने सर्वोच्च में प्रौढ़ शिक्षण की व्याख्या की है—एकदम एम्प्लोयमेंट इन एम्प्लोयमेंट फार लाइफ, यानी प्रौढ़ शिक्षा जीवन भर के लिए नहीं, जीवन के लिए है, और दूसरे यह कि वह अक्षरज्ञान देने के लिए नहीं है। जब हम वृद्धि से प्रौढ़-शिक्षण पर विचार करते हैं, तो वह सब चीजों को धेरे लेती है। अगर आज मैं खाली होता, तो इसीसे लेकर बैठ जाता। मैं हाथ का उपयोग भूष बाऊला, अगर-तान भूष बाऊला, उस इसी पर खड़ा भूष दूष कि बालने को मैंने निश्चय बाण। मैं छात्रों को सभी भूष गया हूँ लेकिन एक बार मदन के प्लेब की पहचानी ऐसी आई की कि सारा सदन सतप हो गया था। फिर सदन में भाग नहीं थी। (यह भाव नहीं की, ईश्वर की महारानी थी, नहीं तो आज सदन का तामोनिधान को नहीं रहता।) जिस तरह वह रोग

मदन से निकाला गया, वैसे ही ग्राहकों से भी। जब जोहानिस्वय ने निजाला गया, तब मैंने मुँह भी उल्टा हाथ बढ़ाया था। लेकिन कितनी सज्जन से, बिलाली मुँह से, कितने लक्ष से, बिलाली जोरों से वह गिटाया गया कि फिर नहीं नहीं आया। हमारे गांव में जय हुआ जाता है तो लोग बहते हैं कि देवी का कोप है। इस तरह को मराना प्रौढ़ शिक्षा का काम है।

प्रश्न क्या गांव में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कोई अलग कार्यकर्ता होना चाहिए या समस्त ग्रामसेवक ही प्रौढ़ शिक्षा का काम भी करेंगे? प्रौढ़ शिक्षा का कार्यकर्ता पूरा समस्त ग्रामसेवक होगा या नहीं?

उत्तर इस प्रश्न के दो प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। जो कार्यकर्ता समस्त ग्रामसेवक की दृष्टि से गांव में जाता है और प्रौढ़ शिक्षा नहीं जानता, वह ग्रामसेवक नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा को अगर सब ग्रामसेवक जानें कि प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ व्यापक है, वह धारें जीवन को धेरे लेती है तो कोई सामी नहीं रह जाते। वह किसी गांव भादमी का काम नहीं है। अगर एक भादमी जाता है, तो बड़ी दूसरे का काम नहीं रह जाता। मैं तो आदर्श बना देना चाहता हूँ। आदर्श को बहूतने का प्रयत्न करें। दरमस्त देना जाने तो जहाँ शिक्षण के लिये एक साधन भादमी है, वहाँ दूसरे भादमी का स्थान नहीं है। जब उन साधन भादमी नहीं मिलता, तब तक जो मिले उसी को लेवें। अच्छा प्रौढ़ शिक्षण जब हमारे हाथों में आ जायगा, तो वह ग्रामसेवक भी होगा। अपनी साधनी यह कार्यकर्ता मुझ तैयार करेंगे। यह अक्षर भादमी नहीं होगा, जो कहुँगा मुझे स्वयंसेवक चाहिए। उसे तो प्रौढ़ विचार नहीं

वहूँगा। प्रोढ-शिक्षण देनेवाला तो जादूगर होगा। वह तो अपनी जादू की साठी से सब कुछ पैदा करेगा। यह कहेंगे मुझे आपसे एव चीड़ी नहीं चाहिए। उस पिठना समय देना है यह वह जान लेगा। प्रोढ-शिक्षण जो भी कुछ करता है प्रोढ-शिक्षा या ही नाम है। उसने किए दूसरा नाम रह ही नहीं जाता।

प्रोढ-शिक्षा के कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए कितना समय लगाना चाहिये और उसकी शिक्षा का क्या रूप हो?

इसमें आप से कहूँ कि हाथ के मारपट होने वाले चोरे उद्योग किसने हैं, चीड़ी की खेती, थोड़ा सामान्य ज्ञान देना है, तो आपको सतोष नहीं होगा चाहिए। लेकिन मुझे आपसे यह पूछना चाहिए कि ट्रेनिंग का कारण क्या है। एषो पहले तो जो ट्रेनिंग लेने आया है, उसकी योग्यता आपको जाननी चाहिए। मैं उससे पहले तो यह जान सूना कि जिसका से लया है या नज़ाक लगाने आया है। और जब उसे आया ही रहा, तो जो ज्ञान उसे आज तक मिला है वह उसको भूलकर ही मेरे पास आया। और उसने प्रति मेरा यह जवाब दिया कि उसे बुद्धि का व्यायाम भिन्न नुका है अब खरीद का व्यायाम चाहिए। उस बुद्धि का उपयोग भी करूँगा, लेकिन विरुद्ध दिशा में। मैं उनके हाथ के चरखा रंगना और कहूँगा कि इससे वे कितना निवास सकी निवासो। और उस चरखे ने मारपट ही उसे देहाती बनाईगा। दूसरी ओर मेरे पास एक निरक्षर देहाती आता है। यह उत्साह है, चरखा चलाता है, उसे मैं दूसरी तरह का काम दूँगा। जो भी मेरे पास आये, और जिस किसी प्रकार के होवे, उन्हें ले लूँगा। लेकिन यदि किसी को देखकर देहाती ने मन में यह भाव नहीं होगा चाहिए कि वह किसका देहाती है और मैं कितना नीचा हूँ। क्योंकि देहाती के दिल में तो एक प्रकार की बाह्यनिक शक्ति का

बई है कि मैं छोटा हूँ, यह बड़ा है। इसलिए मेरी पहली शिक्षा यही होगी कि तुम दोनों एक हो। एव के पास एक ज्ञान है और दूसरे के पास दूसरा ज्ञान है, इसलिए दोनों को मिलाकर चलाना है। और जिस दिन पी-एच० डी० सोच लेगा कि अगर वह देहाती न रहा तो शहर में आयगा, उसी दिन सहरो का भन्त समझो। मैंने आपसे व्यावहारिक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं तो दृष्टि देना चाहता हूँ।

प्रश्न विन्नु कार्यकर्ता की शिक्षा की अवधि क्या हो?

उत्तर कोई भी अवधि नहीं है, निरवधि है। मैं आपको मालूम है मैं मुझे कि उसे कहीं तक सिखाएँ। जब सब वह स्वावलम्बी नहीं बनता, उसे सिखाना है और समझना है कि शिक्षा पूरी नहीं हुई। वह हमारे पास पड़ा रहेगा। उसने बिल को अगर हमसे नहीं बीठा है तो हमारी भूल होगी। मेरा क्या ही यह है। मैं अनुभव से आपको यह बताता हूँ। मेरे पास तो आदमी जिस तैयार होता है। कोई जीवन भर भी रहता है, कोई दो दिन में बना जाता है। अनुभव से, विचार से मैं इस नीति पर आया हूँ कि कुछ अवधि मैं मानूँ। कोई आये तो भले, नहीं आये तो भले। जिसको लें, हम साफ साफ कहें कि अवधि में हम नहीं मानते। जो सच्चा है, स्वच्छता से, शुद्धता से, सबई से काम करता है, पूरा समय देता है, उसका अज्ञान दिन प्रति दिन घटता रहता है। जो सब तैयार हो जाए तब यह अपने आप रह सकता है। मेरी सरस में बनाने वाला होके, तो कहूँगा कि कार्यकर्ता जब तक स्वावलम्बी नहीं होता, तब तक रहे, फिर उसे भले ही एक्कीस वर्ष रहता पड़े। जगत की तो हमें आदित्य मार्ग बताया है। हम इस्ताबैट (दिवालीया) तो हमेशा ही हैं। लेकिन एव बार बीज अच्छा जब गया, तो आदित्य में जरूर निश्चय। यह हमारा आदर्श रहे। और जैसे

उसने आना रयेने कि वह सवाई से चले, बंसी सवाई होने भी रहती है।

प्रश्न : स्वायत्तता का सारा अर्थ क्या है ? जो प्रौढ़ बाने को और अपने परिवार को बाँट या उससे अधिक घटे व्यय करने पाता है, उसके लिए स्वायत्तता का रूप क्या होगा ?

उत्तर : वह आठ घंटे काम तो करना है, लेकिन परिवार का प्रतिपालन करता है, वह वहना विनम्र है। हम ज्ञान की दृष्टि से देखें, तो जानेंगे कि वह स्वायत्त नहीं है, विचारों है। मजदूरी में जो खुद है, जो जान है, जो सतोष है, जो वह नहीं जानता। मजदूरी उसकी गुलाबी की निधानी है। मजदूर भूमिपर हो, उसमें जान हो, उसमें सतोष हो, सभी वह आजादी का निधान बनाता है।

प्रश्न : क्या शिक्षा मुख्य वेला है, उनकी शिक्षा का साम्य भी नताई-बुनाई होगा ? और तब सेती के दिनों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे समय कहा पावेंगे ?

उत्तर : तुम्हारा मतलब यह है, न कि जो आदमी आठ घंटे सेती की मजदूरी करता है वह क्या रहेगा, नताई-बुनाई के लिए समय कैसे निकालेगा ? लेकिन ध्यान में यह रहना है कि जो आठ घंटे मजदूरी करता है, वह बौद्धिक शिक्षा सेने के लिये लागा रहता है। वह मेरा अनुभव है। मैं दाल्टन शर्म में काम करता था। पहले पहले मीद जाती थी। लेकिन मीद के बाद कुछ करने के लिये लागा हो जाता था। सच्चा आदमी तो अवसर जागता है वह तक काम करता है। और शिक्षण लिये सेती का धंधा मुक्त करते हो, वह उसका मुख्य धंधा नहीं, मुख्य बुतलमी है। वह सेने के साथ बल बन जाता है। सेने के साथ एक टुकड़ा मूखी रोटी खाकर सेने में चल देता है। मधुसूदन दास की बात जानते हो न ? जब उसने देखा कि देहाती मीद बल के पीछे बल हो रहे हैं,

यही जानवर भी रहते हैं, यही आदमी भी रहते हैं, उनमें कोई अविधान नहीं है, तब उसने समझा कि सिर्फ, सेती सेती से हमारा मुक्त बड़ा नहीं हो सकता। मुख्य धंधा सेती होने से अगर मुक्त बड़ा होगा, तो हिन्दुस्तान को बहुत ऊँचा होगा चाहिए। लेकिन बंसा नहीं है। सभी जेते हरेक काम में ईश्वर को देवता है, प्रौढ़-शिक्षा का कार्यकर्ता भी बंसे ही देवता है। किसान को वह शिक्षाएँ बल सेने रखना है आदि। उसे उसके हाथों की शक्ति का विकास करना है, उसके मस्तिष्क की शक्ति का विकास करना है। जो सिर्फ, मस्तिष्क का विकास करता है वह सतान है। आज जो प्रौढ़-शिक्षण है, वह तो मिथ्या है ही नहीं। मैं पहले बस्तुकारी गिराऊंगा। उसे सील सेने के बाद अक्षरज्ञान होगा।

प्रौढ़-शिक्षण की उत्पत्ति मैं बताता हूँ। मैं एक दिन भी आयत्तायकम् से बाहर कर रहा था। उपर से एक बूझ बना जा रहा था, साथ में बल भी था। मैंने भी आयत्तायकम् से बाहर, ७ से १४ की छत्र तक काव शिक्षाने वाले हैं, लेकिन उस बूझ को भी धिखाना है। बूझ ने तो सो करके यही चुका। यही प्रौढ़-शिक्षा मुक्त हुई। मैंने उससे पूछा, बूझ, तुम्हें पूछता है, उसका मतलब क्या मतलब है ? अगर उस बूझ को मैं हूँ मैं, तो वह प्रौढ़-शिक्षा न होती। उसे तो समझाना है कि इसका क्या अर्थ होता है। वह कोई बड़ा कार्यकर्म नहीं, लेकिन यही प्रौढ़-शिक्षा है।

कमेटी ने जो प्रौढ़-शिक्षण की व्याख्या देवदार की थी, उसमें दोषहर की बैठक में पाथीजी ने घोड़ा सा सुधार किया . . . यह शिक्षा जीवन के लिए और जीवन मरने लिए है। आज का मंड्रिगुलेट शिक्षण निषय सेता है उसने भी नाम में नहीं लाता। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ शिक्षाएँ, वह शिक्षा यहाँ से जाते समय यही नहीं रहेगी। प्रौढ़-शिक्षा एक भी चीज ऐसी नहीं देता है जो नाम की नहीं है। उसे जो सिखाना है वह घर-घर

जानकर सिखाएगा। ७ से १४ वर्ष की बुनियादी तालीम के लिए भी यही है। अच्छा घर पर जो काम करता है, वह करता उसके लिए स्वराज्य भी बूझी है, बुद्धि के विकास का साधन है। दूधवा रोब घर जायगा तो या बाप पूछेंगे कि माय हमारे लिए क्या जाए ? प्रौढ़ शिक्षण में तो हमें ऐसा शिक्षण मिलने वाला है, जो जीवन भर के लिए है। प्रौढ़ शिक्षण में आत्मस्य का स्थान नहीं।

इसके बाद जब गांधीजी ने साधने कमेटी का वह निमन धामा कि मनी रचनात्मक संस्थाएँ किसी न किसी में प्रौढ़ शिक्षण का काम करती हैं और उसमें मदद है तो उन्होंने कहा सब संस्थाएँ मदद तो करती हैं। लखित पपा शिक्षाही है। वह शिक्षा है ऐसा मेरे जैसा आदमी तो नहीं बहूना। मैं तो बहूना कि इन संस्थानों की विधि प्रवृत्तिवा जो पड़े मिलानी हैं, वे पड़े हो शिक्षा में लाहू हैं। प्रौढ़ शिक्षा का नाम है इस पक्ष में प्राण डाना। आज यदि हम समझें कि हम अपने इन नामों से प्रौढ़ शिक्षा में मदद है, तो प्रौढ़ शिक्षा को मार दिना समझिए। कादो का काम गांधीजी

सब और परछा सब दोनों जबह पसता है। लेकिन गांधीजी सब के काम को ऐसा ध्यावरन बनाता है कि चर्चा सब भी कहने लगे कि हमारे काम को गांधीजी सब द्वारा प्रोगन मिलता है। इसी तरह तेज पानी भी शिक्षा का वाहन है। वह शिक्षा का वाहन बनकर ही गांधीजी सब के सामने आती है। लेकिन अगर आज हम कहे कि दूसरी संस्थाएँ भी प्रौढ़ शिक्षण का काम करती हैं, तो गांधीजी सब का काम बंद कर देना पड़ेगा। यह प्रौढ़ शिक्षा को विचित्रता है। इसका संग मर्यादित नहीं बल्कि व्यापक है। कानरा, प्लेग आदि नाशक शक्तिमा भी शिक्षा के अन्त में पोषक (निपेटिब) बन जाती हैं। आज हम जो काम कर रहे हैं, कल तो है, शिक्षा तो है, शिक्षा तो है लेकिन बड़े व और पर। उसका विचार नहीं है। तालीम से करना है। प्रौढ़ शिक्षण तो जीवन कला सिखाने की बात है बीदन बना सीख गये तो मनुष्य बन गये। सबसे सिखन कर सकते हैं। इसे कल्पना वा ही बिना समझो। बलवान को कोई नहीं पहुँचा है। सब में पहुँचूया यह कैसे यह एकदा है, और हमने भी कैसे आधा रण एकदा है।

मद कर सकते हैं। यानी हमारी चाहिए कि जो कमिया है उनकी हम दूर करें।

ग्रीक शिक्षा में भाव लोग व, स, य पढ़ाना शुरू करते हैं। सवाने लोगों को दिन में समय नहीं है, इसलिए हम रात में ऊह बताते हैं। यह हमारा योग। और हमारी पक्ष साक्षरता की जारी रखते हैं अथवा हुआ क्षेत्र। इस प्रक्रिया के लिये पुस्तकें भी जाती हैं। और फिर बरबादी होती है।

चाहिए यह कि हम सवानों के जीवन की प्रति करें। यह तभी होगा जब हम स्वयं अपने जीवन में हिंसा करेंगे। हिंसा केने का मतलब यह नहीं है कि सवाना यदि भाठ पटा थप करता है, तो हम भी उसने बाव भाठ पटा थप करें, सारा समय उसके साथ सवायें। हम चाहिए कि उसने व्यवसाय में काम लेते हुए उसके जीवन में जो कमिया हा उनकी शिक्षा दें।

देहात के लोग अपने हाथों से काफी परिश्रम करते हैं। और फिर हमके बाद उनकी आँखें भी दिन भर मज्जि की दुनियाँ केनेनी हैं। मज्जि बाँवों का भी काफी सम्पाद बनाया जाता होता रहता है। उनकी अवचेन्द्रिय को अवेसादृत जतना सम्पाद करते हैं और गरी मिलता। तो हमारी चाहिए कि उनकी जो इन्द्रिया काँधी परिश्रम करती हैं उन्हें फिर न थप दें, बल्कि उन इन्द्रियों से ही उनके शिक्षण में काम लें जो अवेसादृत काम में नहीं आती। मेरे नहने का मतलब यह हुआ कि पढ़ने सिखाने की अपेक्षा सफाई की अवचेन्द्रिय हाथ ही काम करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। गहर के भाग ज्यादा पड़ सके हैं, इसलिए जहाँ सराव हो जाती है। गहर से मास सारा और देहात में काम खराब।

क्या पत्रिका काम यह भी एक सवाल है। हम उसे बहुत कुछ सम्पाद इन की बात सोचते हैं। यह सब नामुमकिन है। जैसे कि उसे विज्ञान सिखाना है या यह समझ नहीं हो सकता। उसे साक्षर करना है तो सरलता

और सुयमता पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं लिपि सिखाने का एक तरीका बनाया है, जिससे दो महीनों में कोई पढ़ना सिखना जान सकता है। यह प्रयोग मैंने जेल में किया था। वह सब लोग तो उस वक्रे में सम्पाद तक अपना काम समाप्त कर लेते थे, किन्तु रसोदवा लोग ३ बजे प्रातः तक वक्रे तक काम करत थे। दोपहर को भोजन के बाद उन्हें कुछ ऐसा समय मिलता था, जब हम उन्हें कुछ मिलता करत थे। मैं यह प्रयोग करने ऊपर किया। क्योंकि वे इच्छुत थे। महीने के महीने में उन्हें पढ़ना भी गया।

तो मेरे नहने का अर्थिप्राय यह है कि लिपि में भी सुयमता के दृष्टिकोण से सुधार चाहिए। ग्रीक शिक्षा में साक्षरता तो होती थी चाहिए किन्तु पढ़ने-लिखने पर उनका और न दीजिए। ग्रीक को केवल ज़रूरत ज्ञान देने से ज्यादा काम न होय। बल्कि धर्म के माध्यम से जितना प्रदान करने का भी ज़रूरत रखना चाहिए। ग्रीक-शिक्षण के लिए तात्कालिक आवश्यकताओं पर तथा अपनी आवश्यकता के दृष्टि के प्रयोग से भी काम लेना चाहिए। जेल में एक बार बहुत सक्रियता बढ़ गई थी। मैंने ऐसे समय में मज्जिधानी को मज्जिधानी बना दिया और उसके भीतर बँडर काय करना शुरू दिया। इसके एक दृष्टि को लोगों को मिली।

एक विशेष बात पर अवश्य ध्यान रखिए। यह पत्र कि भाव का शाव आज ही दीजिए, जिस शाव प्रभाव को आज करती सम्पादने हैं वही भाव दीजिए।

हमने भाव लोगों का ध्यान मुख्यतः बार भावों पर आँट किया है। एक तो यह कि हमारी ग्रीक-शिक्षा का उद्देश्य यह रहे कि वह शिक्षा पूर्ण शिक्षा हो। दूसरा यह कि शिक्षा प्रदान करनेवाले लोग लोगों के दैनिक कामों में हिंसा लेख हुए अपना काम करें। तीसरा यह कि थोड़ी ही पढ़ाई पर ध्यान दें और उस पर ज्यादा जोर न दें। और चौथी बात यह कि जो बात आज बतायें आज की ही समझा हो।

विद्यार्थियों के लिए डिग्री नौकरी के लिए केवल एक पात्रगोटे है। अधिकांशतः तथा माता पिता की भी शिक्षा तथा डिग्री के प्रति यही प्रवृत्ति है। विद्यार्थियों और अध्यापकों में इसमें कुछ अन्तर भी होने बिना उससे स्थिति की सामान्य तस्वीर में कोई फर्क नहीं पड़ता।

ऐसी तस्वीर तस्वीर के सामने मैं बुनियादी दम का कोई वैश्विक सुधार सम्भव नहीं है जब तक कि (१) या तो डिग्रियाँ समाप्त कर दी जायें या (२) डिग्रियाँ नौकरी से अलग-थलग कर दी जायें अर्थात् डिग्री और नौकरी में कोई सम्बन्ध न रहे। रोजगार देने वाले सरकारी अथवा गैर सरकारी, अपने काम छपा की जरूरत की देखते हुए अपनी परीक्षाएँ स्वयं संचालित करें। सेवा में होने के पक्षपात के अपने वहाँ काम करने वाली को अपने आवश्यकतानुसार सेवागत शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की करें। विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण में ऐसा बुनियादी परिवर्तन एकदम तुरन्त किया जा सकता। यह एक सम्बन्धी प्रक्रिया होगी जिसे विद्यालय और रोजगार देने वालों को पारस्परिक मान के लिए, पारस्परिक सहयोग से अथवा क्रिया-प्रति-क्रिया करना चाहिए।

डिग्रियों को समाप्त करने या विचार ऐसा क्या या अनिवार्य नहीं है। वर्तमान स्थिति में यह अत्यन्त सम्भव है। डिग्री का विनश्यत क्या होगा? केवल एक प्रमाण-पत्र जिसमें यह लिखा होगा कि कोई विद्यार्थी कितने वर्ष कॉलेज में रहा है, कितने पढ़े वह कक्षाओं में उपस्थित रहा है और कितने घंटे उसने पुस्तकें, रसयान, कार्यालय और मैत्री आदि में काम किया है तथा किन विषयों में उसकी रुचि रही है। यह उसकी अपनी रोजगार देने वाले का काम होगा कि वह विद्यार्थी की क्षमता और योग्यता का मूल्यांकन करे। यदि किसी विद्यार्थी ने किसी काम-पढ़ने में लगने की ओजना बनाई है, तो विश्वविद्यालय और अन्य सम्भव ज्ञानार्जन के साधन जैसे वर्कशॉप, कार्यालय, फार्म आदि उसकी सहायता इस बात के लिए करें कि उसे अपने रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान तथा विशेष उपकरण हो जाए।

मुझे पूरी आशा है कि इस तथे वैश्विक वास्तव्य में उन विद्यार्थियों को जो आन्दोलन में अग्रगण्य बन रहे हैं सहायता मिलेगी, और जो अपने को उच्च तम परीक्षा में बैठने के लक्ष्य बनाने के लिए अपनी कमियों को दूर करने तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को उच्च तम परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए न्याय के माध्यम से। इसका अर्थ यह है कि उन विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम बख्शान्वित न अतिशय के प्रतिपक्ष में दृष्ट दी जायेगी जिनकी क्षमता विहार में कॉलेज और विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों की ८० प्रतिशत है। न केवल उपस्थिति का अर्थ एक अनिवार्य अध्यापकत्व होगी, प्रत्युत वे विद्यार्थियों का अवसर होगा जो स्वतंत्रता प्राप्त न बनाने पहली बार राष्ट्रीय महत्व की अवसर समझाया जा। तब तक रहे हैं और इतना बीरोचित स्थापित कर रहे हैं। वास्तव में अधिकारियों के लिए उपस्थिति के विषय को लागू करना असम्भव होगा क्योंकि उसके सामने पूरे विद्यार्थी समाज का विरोध होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इसे भी दृष्टि में रखना होगा कि वर्तमान आन्दोलन स्वयं में एक तबक शिक्षा है और जो इसमें सम्मिलित हैं वे बहुसंख्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सामूहिक विचार-विमर्श तथा प्रशिक्षण-सिविर इस शिक्षा के एक अंग मानें। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम से उन्हें आज की महत्वपूर्ण समस्याओं को पहचानने में सहायता करने में सहायता मिलेगी। अशांति, युद्ध स्थिति, बेरोजगारी—ये मुद्दाइयाँ जिनसे लड़ने के लिए यह आन्दोलन है—की समस्याओं पर विचार-पत्र सामूहिक विचार-विमर्श के लिए प्रसारित किए जाएँगे।

सारी विद्यार्थियों एक शिक्षा के लिए समान-निर्वाह तैयार करनी पड़ी है जिसमें आवश्यकताओं और सहायता की सुधी बनाई जा सके। जैसे ही प्रस्तावनाओं पर उत्तर प्राप्त हो जायेंगे, आपके या आपके कार्यक्षेत्र पर किया जायेगा और यह कार्यक्रम लागू कर दिया जायेगा।

हमें स्कूल को क्यों समाप्त करना है

अनुवादक—देवेन्द्रदत्त तिवारी

[इवान इलिच की प्रसिद्ध पुस्तक 'छो स्कूलिंग सोसाइटी' का अनुवाद हम 'नयी तालीम' में इस विषय पर प्रकाशित कर रहे हैं कि इसका इलिच ने बिचार-गोपीवारी बिचारघारा से मिलते जुलते हैं। यह अनुवाद सर्वाधिकार सुरक्षित है।]

अधिकांश विद्यार्थी विरोधपूर्ण भाव से होते हैं। वहन हो यह जान लेते हैं कि इन उनके लिए क्या करते हैं वे स्कूल तार (substance) और प्रक्रिया (process) के अन्तर्गत करते हैं। एक बार जब इनके विषय में आसक्ति हो जाती है तो एक नया एक प्रस्तुत किया जाता है—जितना अधिक इलाज (treatment) होगा उतना ही अच्छा परिणाम निकालेगा, अथवा दूसरे शब्दों में, इलाज को बढ़ाने से सफलता मिलती है। इस प्रकार से विद्यार्थी को यह शिक्षा दी जाती है कि वह शिक्षण को सामाजिक समझते, देखते आगे बढ़ने को ही शिक्षा समझ ले, शिक्षण को योग्यता समझ ले और प्रवाह-मुक्त जीवन को मौलिक अधिष्ठाता की समझ समझने की भूल करे। इसी वजह से इन प्रकार शिक्षित की जाती है कि वह सेवा की दृष्टि से स्वयं पर रहने पर। इसी प्रकार चिन्तनशील उपचार को प्रत्यक्ष स्वस्थ की देन मिल, सदा सेना की सामाजिक जीवन का उन्मूलन, पुनर्निर्माण की दृष्टि से सुरक्षा, संश्लेषण तैयारी की राष्ट्रीय सुरक्षा और निरन्तर अनुचित प्रतिरोधिता को उत्साह प्राप्त माना जाता है। स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक सम्मान स्वतन्त्रता और सज्जनतायक प्रणाली की परिभाषा यह मानी जाती है कि वे उन सम्भावनाओं की उपलब्धि हैं, जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने को अधिकृत मानती हैं और इन सम्भावना का उन्मूलन इन बात पर निर्भर करता है कि अवसरानुसार स्त्रोत और अन्य प्रशासनिक प्रतिस्थापन (agencies) के प्रत्यक्ष से लिए अधिष्ठाता समायोजित करें।

इन दिनों में मैं यह बताऊंगा कि मूल्यों का संस्थापन अनिवार्य रूप से शारीरिक रूप, सामाजिक व्यवस्था, तथा मनोवैज्ञानिक निष्पक्षता की ओर से जाता है—ये विषयवाची अथवा तथ्यात्मक आधारित दुर्दशा के तीन पहलू हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किस प्रकार अधिष्ठाता की यह प्रक्रिया उस समय तेज हो जाती है जब अधिष्ठाता आवश्यकताएँ या मान्यताएँ मौलिक वस्तुओं की धारों में परिवर्तित की जाती हैं, जब स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत गरिबी, व्यक्तिगत हित अथवा मनोवैज्ञानिक उपचार को सेवाओं का 'इलाज' के परिणाम के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि अधिष्ठाता के विषय में जो अधिकांश अनुमान हैं उसकी प्रवृत्ति मूल्यों के और अधिक संस्थापन का प्रयत्न करने की ओर है। किन्तु हमें इन स्थितियों को परिभाषित करना चाहिए जिससे विस्तृत उत्तरी स्थिति उत्पन्न हो सके। हमें ऐसी तकनीक के सामाजिक प्रयोग पर अनुसंधान करना चाहिए जिससे ऐसी संस्थाएँ बन सकें जो व्यक्तिगत, सज्जनतायक एवं स्वतन्त्रतायक प्रणाली में और ऐसे मूल्यों के विकास में सहायक हों जिन पर तकनीक के अनुसंधान की निम्नलिखित प्रवृत्ति प्रभावित करने के रूप में हमें अनुमान करने की आवश्यकता है।

मैं अनुमान से सम्भाव्य और आधुनिक संस्थाओं की परम्परागत परिभाषा का व्यापक प्रश्न उठाता चाहता हूँ जो हमारी विवेकशक्ति और हमारी भाषा से सम्बन्धित है।

इस हेतु मैंने स्कूल को अपना उदाहरण चुना है। इसलिए मैं राज्य की (जो एक सम्पत्ती की तरह है) अथवा नौकरगाहों की एजेंसियों के सम्बन्ध में अवश्यता चर्चा ही करूँगा—उपमात्मा परिचाय, दल सेना चर्चा तक नौकी मापन आदि। स्कूल की छिपी हुई साक्ष्यवर्षों के मेरे विश्लेषण से यह स्पष्ट होगा कि समाज की स्तुति बिहीन बनाने में सांख्यिक विज्ञान का काम होगा। जैसे सांख्यिक जीवन राजनीति, सुरक्षा घण और संपादन की ऐसी समकालिक प्रविष्टि से काम होता जाता स्कूल के सम्बन्ध में मैंने बताया है।

मैं इस प्रपन निबन्ध में अपना विश्लेषण इस बात का समझने के प्रयास से प्रारम्भ करता हूँ कि किसी स्तुतिपुक्त समाज को स्तुतिबिहीन करने का क्या क्या होगा। इस चरण में यह समझना सरल है कि इस प्रविष्टि से सम्बन्ध उन पाँच विधिगत चर्चाओं को क्यों चुन रहा हूँ जिन पर मैं आगामी अध्यायों में चर्चा करूँगा।

न केवल शिक्षा प्रत्युत स्वयं सामाजिक उत्तर भी स्कूल के रण में रण भुके हैं। एक ही सेवित धन में अमीर और गरीब दोनों को शिक्षित करने का सच मोटे तौर से बराबर है। अमेरिका के बिन्ही २० वर्षों के सम्पन्न उपलब्धों और गरीब बस्तियों में प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च एक ही सीमा में आता है। कभी-कभी गरीबों के घर में ज्यादा बँटता है। १० वर्षों और अमीर एवं समाज उन स्तुतियों और असम्पत्तियों पर निबन्ध करते हैं जो उनके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं उनकी विद्यार्थिता का निर्माण करते हैं और उनके लिए यह परिभाषित करते हैं कि क्या उचित है और क्या नहीं। इसी का परिणाम है कि गरीब और अमीर दोनों ही स्वयं अपना दान करत अनुसूचितविलक्षण सच समझते हैं और स्वयं सीखने पर भी उनका विश्वास नहीं

है। यहाँ तक कि सामाजिक समझने की अव्यवस्थित अधिकारियों से चैता नहीं मिलता तो ये उसे अव्यवस्थित (aggression) या विध्वंस (subversion) मानते हैं। दोनों ही चर्चाओं की सहायता समाज पर निर्भरता का अभाव होता ही जाता है कि स्वतन्त्र रूप से से प्राप्त उपलब्धियों को ये स्टेड की दृष्टि से देखते हैं। आत्म नियन्त्रण और सामाजिक नियन्त्रण का बड़ा हुआ प्रभाव जीवन के उत्तरपूर्व की अवस्था में स्टेडोस्टैट ॥ अधिक प्रचारात्मक (typical) है। हर गणतन्त्र में केवल शिक्षा प्रत्युत पूरे समाज को स्तुतिबिहीन करने की आवश्यकता है।

कल्याणकारी नौकरगाहों का समाज की नेतृता पर प्रोत्साहन, राजनीतिक, आर्थिक एकाधिकार का दावा रखती हैं और इस प्रकार वे समाज का मानदण्ड निर्धारित करती हैं कि क्या मूल्यवान है और क्या बाक्य है। यह समाज एकाधिकार ही गरीबों के अनुनाकरण के रूप में है। हर छोटी छोटी अव्यवस्थितता जिसकी प्रति के लिए समाज की स्थापना के रूप में उत्तर मिलता है, इस बात की अनुकूलता देती है कि गरीबों के एक नये वर्ग का गृहण हो और गरीबों की एक नयी परिभाषा बने। इस रूप पूर्व में जिसकी ये अपने घर में जन सेना और नयी मरना तथा अपने पिछे द्वारा दक्षताय जाना एक सामान्य बात थी। केवल आत्मा की आवश्यकताएं चर्चा नामक समाज के बिम्बे रहनी थी। अब घर पर जीवन प्रारम्भ करना और समाज करना या ही गरीबों का यह समाज में विशेषाधिकार का (privilege) प्रतीक है। मरना और मृत्यु दास्यों तथा आम देखभाल करने वाला के सम्भाव्य अवस्था के अन्तर्गत आ गए हैं।

एक बार जहाँ बुनियादी आवश्यकताएँ समाज द्वारा संज्ञात्मक रूप से उत्पादित वस्तुओं के रूप में बदल जाती हैं वहीँ उन मानदण्डों से परिभाषित होती हैं जिन्हें सार्वजनिक अवस्था द्वारा बदल सकते हैं। गरीबी से सब उस भोगों का अवबोध होता है जो उपभोग के किसी महत्वपूर्ण सदन में निष्ठापित कारण से पीछे रह जाते हैं। मेरे, गरीबों के हैं बिन्ही तीन चरण की स्तुति

• एनरोम जो रजतान, ड्रुइस इन एलोनेट्री एंड ठेनेट्री एनरोम एनरोमिस्ट्री, सेटुल बिन्ही एनरोम कर्मरिज १९६२ १९६८, यू० एच० आरिफि आक एनरोम आरिफि आक प्रोफेसर एनरोम इन्ट्रान्सून फून, १९०६,

शिक्षा नहीं मिली और न्यायों में गरीबों के हैं बिना
कारणों की स्त्री शिक्षा नहीं मिली ।

गरीब समाज में सदैव अक्षरहीन रहे हैं । सत्समाज
वैतना पर बढ़ती हुई निर्भरता उनकी अक्षरहीन स्थिति
में एक नया पहलू जोड़ देती है—मनोवैज्ञानिक निष्पि-
पता और अपनी वैतनात्मक स्थिति करने की अक्षरता ।
एशिया के जैसे पड़ोसों पर अमीरों और व्यापारियों
द्वारा निरालों का शोषण किया जाता है । इसके विप-
रित एक बार जब के सीमा में बस जाते हैं तो वे
राजनीतिक क्षेत्रों पर आश्रित हो जाते हैं और स्कूली
शिक्षा के प्रभाव में पड़ जाते हैं । नयी (moder-
nised) गरीबी परिस्थितियों के प्रति उनकी असमर्थता
के साथ उनके व्यक्तिगत पुनर्वास के समाज को जोड़
देती है । गरीबी का यह नया रूप विश्वव्यापी घटना है
और वर्तमान अर्थविकास के मूल में है । यह अवश्य है
कि यह विभिन्न स्तरों में अमीर और गरीब दोनों में
अभिन्नता होती है ।

यह बात की तीव्रतम अनुभूति अमरीका के लोगों
में होती है । अब वही भी गरीबी का उपचार इसके
अधिक स्तरों पर नहीं किया जाता । जमा कही भी
गरीबी का इलाज इसी सामाजिक, शैक्षणिक, निराला
और अधिकाधिक मार्गों नहीं उपलब्ध करता और अब
कही भी यह बात इतनी स्पष्ट नहीं होती कि गरीबी एक
एक बार जब गरीबी रूप धारण कर लेती है, तो वेबल
हॉपर के मन पर बिसे जाने वाले उपचार की प्रति-
रोधिता बन जाती है तथा सत्समाज कांति की अपेक्षा
करती है । आज अमरीका में वाले हृदयी और प्रगती
प्रोत्साहन प्रभाव के ऐसे स्तर की आवश्यकता बन सकते
हैं, जो पीछिया पूर बिसे प्रोत्सा भी नहीं जा सकता था
और जो पीछी दुनिया के अधिकांश लोगों को विस्तृत
वैदेशी लक्ष्य होगा । उपलब्धता के लिए, अमरीका के
के गरीब एक वैश्ववैदेशी अधिकारी पर बह गरीबी
कर सकते हैं कि यह उनके बच्चों को १० वर्ष के उम्र
तक स्कूल पहुँचाया, या एक डॉक्टर पर गरीबी कर
सकते हैं कि यह उन्हें बलात्कार में एक निराला देना

जिनकी नीमता साठ डॉलर प्रतिदिन (लगभग ५०० रु०)
होनी चाहिए वे बहुत से लोगों के तीन मास के वेतन के
बराबर । विन्तु ऐसी देखभाल उन्हें और अधिक आश्रित
बना देती है, और उन्हें उत्तरोत्तर इस बात के लिए
आवश्यक बना देती है कि वे अपनी जिदगी अपनी अनु-
भूतियों के निर्देशों और अपने सहायकों के अनुसार अपने
समाज में समाहित पर सकें ।

अमरीका के गरीब उस दुर्दशा की बातों की अति-
शीघ्र स्थिति में हैं जो आधुनिक युग में सभी गरीबों के
लिए भवभारी है कि अब एकबार इन सहायकों की
शोकेक्षण सीढ़िया समाप्त हो यह विश्वास दिया देती
है कि उनमें जाचार नैतिक दृष्टि से आवश्यक हैं तो
हॉपर की सीढ़ी राशि सत्समाजवादी सहायकों की स्वभाव-
गत विनाशकता दूर नहीं कर सकती । अमरीका के
अन्यत्र के गरीब अपने अनुभवों से उस भूत को
स्पष्ट कर सकते हैं जिसपर एक रक्त दीप्ति समाज का
सामाजिक विधान आधारित है ।

सुश्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विविध श्रो० अक्षर
में बता या कि 'जिसी सत्समाज को स्थापित करने का एक
ही तरीका है, और वह है, उसके लिए मन की व्यवस्था
करना ।' इसका उपलब्धता भी सत्य है । उन सहायकों
की जो इस समय शिक्षा और सत्समाज की व्यवस्था
करती हैं, डॉक्टर से चिकित्सा करने से ही, भागे की
यह गरीबी बनाने की प्रक्रिया रोनी जा सकती है,
जो वास्तव में सहायकों के बहुत करने वाले पारम्परिक-प्रभावों
का परिणाम है ।

यह बात उस समय सब में रहनी चाहिए कि जब
हम सही सहायता के कार्यक्रमों का सूचनित करें ।
उदाहरण स्वरूप १९६३ और १९६८ के बीच २०,०००
साठ डॉलर ६० लाख बच्चों के अभावों की प्रतिपूर्ति
करने के लिए अमरीका के स्कूलों में सर्व बिसे बिसे गये
थे । कार्यक्रम 'टाइम बर्न' के नाम से जाना है । ऐसा
सार्वजनिक सचिव सचिव कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में
अन्य कक्षों में नहीं बताया गया फिर भी कोई सामंजस्य
मुधार इन विभिन्न बच्चों के सींगने में नहीं दिखाई पड़ा ।

पापम भाप के घरो से धुत्ते बाते उनके सहपाठियो से
 दुलगा नियो जाने पर यह पता चला कि वे और बिछद
 गये है। इनके प्रतिदिन इस कामभ्रम के दौरान प्रोफेशनल
 विरोधो ने यह पाया कि एक करोड़ ऐसे बच्चे और
 बड़ गये है जो आर्थिक एवं चैखिक दृष्टि से वंचित है।
 प्रथीय पद की और अधिक माप बच्चे के समर्थन म
 अब और अधिक कारण उत्पन्न है।

शायद इसके कि अधिक सर्वांगीण हलाय किया गया, पीछे की शिक्षा के सुधार की पूरा अवस्था को ही छोड़ो से स्पष्ट किया जा सकता है।

१-१०,००० लाख डॉलर ५ साल बच्चों की जातिविषय (performance) को सुधारने के लिए एक मापनीय माप में मजबूती है, या

२. एक आधोम्यता से लक्ष्य किया गया विभिन्न पाठ्यपथों, वेदों प्रशासन, गरीब बच्चे पर चर्चा की और केन्द्र करने तथा और अधिक अनुसंधान को आवश्यकता है और इससे संलग्नता मिल जायेगी।

॥ सफाया जो स्वयं न हो जाती है ।

पहली बात तो यह तर्क सबाय ही सत्य है जबकि
पैसा स्कूल के बजट से सार्थ हुआ है। पैसा तबमुख वन
स्कूलों की गया जिनमें अधिकांश अनुविभागाध्यक्ष बच्चे थे,
किन्तु वह परीय बच्चों पर ही गड़ी सब हुआ। वे
बच्चे बिनके लिए धन दिया गया था उन बच्चों ने तब
बन माये थे जो इन स्कूलों में जा रहे थे। इस प्रकार
यह था उपयोग सारसम्पूर्ण देखमात्र, प्रचार और
सामाजिक भूमिका के ध्यान और साथ हीसाथ शिक्षा
पर धरें हुआ। ये सभी कार्य मविच्छिन रूप में
शीतिक स्थापना, पाठ्यक्रमको, शिक्षकों, प्रशासकों
तथा इन स्कूलों के अन्य प्रमुख व्यक्तियों से और अंत
वर्ती बजट से जुड़े हुए है।

भनिरित्त पन हँ सूलो को यह अवसर मिला कि
विला मनुपान के अपेक्षाकृत लज्जमीर बच्चों व सतोष
के लिए प्रयास करें जो इन दृष्टि से अनुविद्यालय के कि
एक स्तर में प्रवेश बच्चों के साथ पढ़ना पड़ता था ।

यह भी हर ज्ञान में साथ ही सत्य है कि धन अयोग्यतापूर्वक व्यय किया गया। किन्तु स्कूल व्यवस्था की अयोग्यता में किन्हीं असाधारण अयोग्यता की ही हार मान देती है। स्कूल अपनी सारचना (डिज़ी) के साथ ही उनपर सुविधाएँ केंद्रित करने का विरोध करते हैं जो अन्यथा सुविधाग्रस्त हैं। विशेष पाठ्यपदार्थ, अलग कक्षाएँ, लम्बी अवधि और अधिक भेदभाव उत्पन्न करती हैं और अधिक खर्च पर।

टैन्स देने वाले प्राणी इस बात के बाधी नहीं हैं कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्प्राप्त से १०,००० लाख डॉलर विनियम करने की अनुमति दें जैसा कि वे पेंटागन के लिए कर सकते हैं। वर्तमान प्रशासन यह विश्वास कर सकता है कि वह पिछले का कोष एहद कर सकता है। सम्पूर्ण अमेरिका के लोगों का कोई सुझाव नहीं होगा यदि यह प्रोग्राम काट दिया जाए। शरीर में बाप खोजते हैं कि उनका सुझाव होगा, किन्तु उससे भी अधिक वे इस बात की मान कर रहे हैं कि जो धन उनके बच्चों के लिए है उस पर नियंत्रण रखा जाए। बजट काटने का एक हर सतत तरीका, और आजा है, साम बहाने का भी यह है कि पदार्थ अनुदान की व्यवस्था की जाए जैसा मिल्टन फ्राइमैन और दूसरों ने प्रस्तावित किया है। इनसे पैसा उस तक पहुँकेगा जिसकी मितना है, जिससे घर अपनी इच्छानुसार शिक्षा का अपना मास खरीद सकता है। यदि हम प्रसार की क्रेडिट (credit) देनी खरीद कर सीमित कर दी जाय तो स्कूल की गवर्नमेंटों में फिट बैठती है, जो उपचार की समानता की व्यवस्था करिये हो गयी, किन्तु इसका सामाजिक अधिकारों की समानता में छूट नहीं होगी।

यह स्पष्ट है कि समान गुणों के स्तूतों में भी एक-दूसरे से अलग-अलग गुणों की वजह से अलग-अलग स्तर पर पहुँच सके, अर्थात् वे समान स्तूतों में भी आते हैं, और एक ही उन्नत या क्षीण प्रारम्भ करते हैं। फिर भी स्तूतों के अलग-अलग स्तरों के कारण वे अलग-अलग स्तरों पर पहुँचते हैं।

से मिल जाते हैं। प साम धर पर बातचीत और पुस्तकों से लेकर छुट्टियों में यात्रा और अपने निपट में एक अनन्य अनुभूति तक मिलते रहते हैं और बच्चों के लिए सुखम होते हैं जो उनका स्कुल और स्कूल के बाहर दोनों ही जगह खाने-पाने लगाते हैं। अतः गरीब विद्यार्थी सामान्यतः एक एक पीछे रहेगा जब तक वह स्कूल पर अपनी प्रगति

अथवा पानाजन के लिए निग्रह करता है। गरीबों को इसलिए पैसा चाहिए कि वे कुछ चीजें लें न कि अपनी बिना अनुपात की तथाकथित बचियाँ के उपचार के का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए

कमरा

उत्तर प्रदेश और प्रौढ़ शिक्षा

हारिकप्रसाद माहेश्वरी

उत्तर प्रदेश और निरक्षरता का आकार

विगत चार दशकों से अपने देश तथा प्रदेश में निरक्षरता उन्मूलन के कारण प्रयास किये गये किन्तु उन चार दशकों के बादबुद्ध भारत में साक्षरता का प्रतिशत जो कि वर्ष १९४७ में १४ था वर्ष १९७१ तक लगभग ३४ तक ही हो पाया। वर्ष १९७१ के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत लगभग १२ था जो सर करीब २४ होगा। इस प्रतिशत में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत लगभग ३२ तथा महिलाओं का १० है। अगर भारत के अन्य प्रदेशों से अपने प्रदेश के साक्षरता प्रतिशत की तुलना की जाय तो ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश का १२ का स्थान है अर्थात् २२ प्रदेशों में से केवल ४ प्रदेश ऐसे हैं जो अपने प्रदेश में साक्षरता में कुछ कम हैं। इसमें यह स्पष्ट है कि साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत नीचे स्तर पर है। हमें इस बिना में गम्भीरता पूर्वक विचार करना है।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस समय लगभग १० करोड़ होगी। इस संख्या में १५ से ४९ तक की उम्र की वर्ग में निरक्षर पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या लगभग साठ लाख करोड़ से अधिक जाये है जिसमें करीब ४ करोड़ निरक्षरों की संख्या हो जायेगी ही है। अगर

निरक्षरों की इस पूरी संख्या में सीधे की भांति के निरक्षर शान्त वासिवाओं को और जोड़ दिया जाय तो यह समस्या करीब ६ करोड़ निरक्षरों की साक्षर बनाने के रूप में उत्तर कर सामने आती है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा नीति के अनुसार अगर हम १५ से ३५ वर्ष-वर्ष के सभी पुरुषों का उच्च समूह सामने लें तो यह ज्ञात होता है कि इस वर्ग में से कुल निरक्षरों की संख्या लगभग १ करोड़ ८० लाख आती है जिसमें से करीब ७२ लाख पुरुषों की संख्या होगी और शेष लगभग १ करोड़ ८ लाख स्त्रियों की।

यह है उत्तर प्रदेश की निरक्षरता का आकार और स्वल्प जिसको ध्यान में रखते हुए हमें निरक्षरता व मूलन की योजना पर विचार करना है।

उद्देश्य

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा नीति के अनुसार साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा दोनों के कार्यक्रम चलाने हैं तथा साक्षरता इन कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस नीति निर्देशक विज्ञान की ध्यान में रखते हुए प्रदेश की प्रौढ़ शिक्षा योजना के तीन उद्देश्य होंगे —

१—निर्धारित वयस समूह की साक्षर बनाना।

२—निष्कारित तथ्य समूह को ऐसी जानकारीया, बीजान और ज्ञान प्रदान कराना, जिससे कि वे अपने जिन व्यवसाय में लागे हुए हैं उसमें बेहतर बनते हुए अपने स्तर को और अच्छा बना सकें तथा सामाजिक स्तर को और उन्नत कर सकें ।

३—उनकी दक्षियों, व्यवहारों और अभिवृत्तियों में ऐसे बाह्यीय और स्वयं परिवर्तन लाना जिससे वे जागरूक और विवेकशील नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों और दायित्वों को समझ सकें, उनका निर्वाह कर सकें, समाज के उत्साह और अवसरों में भाग ले सकें तथा वर्तमान विज्ञान तथा तकनीक-प्रधान परिवर्तनशील विश्व के नागरिक के रूप में समझदारों के साथ अपनी भूमिका भरा कर सकें ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रोष्ठ विज्ञान व सम्बन्धित कार्यक्रम अनिवार्य शिक्षा की उपाय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रावीण्य होवे, जो मुद्रण पठने-लिखनेवालों की सुविधाओं, आवश्यकताओं, समस्याओं आदि पर आधारित होवे हैं तथा जिसके अन्तर्गत इन पढ़ने-लिखनेवाले पढ़ें अथवा दक्षियों की सुविधासुसार स्थान, समय व पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है । बहने की आवश्यकता नहीं कि वे आयोजन सम्पादन, सुसज्जित तथा व्यवस्थित हो होंगे ही, औपचारिक शिक्षा-व्यवस्था की तरह उन पर सख्तात्मक तथा व्यवस्थात्मक प्रतिक्रिया हावी नहीं होगी । संक्षेप में, पाठक अथवा प्रतिभागी, अधिकार अपनी राय दे, जहाँ पढ़ना चाहेंगे, 'कहाँ' पढ़ना चाहेंगे और 'जो' पढ़ना चाहेंगे, इन सिद्धान्त के अनुसार उनकी शिक्षा का आयोजन किया जायगा ।

हमने अभी आपके सामने १५ से ३५ वर्ष वर्ष के प्रौढों के तथ्य-समूह की जो चर्चा की है, उसके सम्बन्ध में यही यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि उनके पढ़ने-लिखने में यथोचित निरन्तर सहिमाओं, निरंतर चर्चा, प्राचीन तथा लक्ष्यी तरीकों, धर्मिकों, वैज्ञानिक सज्जुत, छोटे-बिस्ताओं तथा निम्नियों की भी आवश्यकता ।

प्रौढ-शिक्षा एवं साक्षरता-केन्द्र

१५ से ३५ वर्ष-वर्ग के निरक्षरों की हमने जो समझ १ करोड़ ८० लाख तथ्य जापने सामने रखी है, उसकी

ध्यान में रखते हुए, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें ५ वर्ष में इन्हें साक्षर बना देना है, ८० प्रतिभागी प्रति केन्द्र के हिसाब से तो तो ६ लाख केन्द्रों की आवश्यकता पड़ेगी होगी है, किन्तु उत्तर प्रदेश के पर्यन्तीय तथा अन्य कई राज्यों को ध्यान में रखते हुए लगभग ७ लाख साक्षरता-केन्द्र आवश्यक होंगे, यानी १४० लाख केन्द्र प्रति वर्ष । और अगर ५ वर्ष के ध्यान पर, हम निरक्षरता-उन्मूलन की अवधि १० वर्ष मान कर चलें, तो १ करोड़ ८० लाख की संख्या के लिए ७० हजार प्रतिवर्ष केन्द्रों की आवश्यकता होगी ।

पाठ्यक्रम तथा पठन-पाठन सामग्री

जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, प्रोष्ठ प्रतिभागीयों के लिए यह उनकी अनुभूत आवश्यकताओं, दक्षियों तथा समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करना होगा । उस पाठ्यक्रम में पर्याप्त लचीलापन रहेगा । यह आवश्यक होगा कि शिक्षा स्तर पर जो अधिकारी, पब्लिक तथा केन्द्रों के शिक्षक हों, वे अपनी-अपनी स्थानीय समस्याओं को एकत्र कर पाठ्यक्रम में समाविष्ट करते-करावे रहें । लेकिन एक सामान्य पाठ्यक्रम को विवेकपूर्ण की समिति द्वारा तैयार कराकर जिलों में सार्वजनिक हेतु भेजना आवश्यक होगा ।

इस पाठ्यक्रम का प्रमुख विषय साक्षरता और प्रौढ-शिक्षा होगा । साक्षरता के अन्तर्गत भाषा और गणित की शिक्षा प्रदान की जायगी तथा प्रौढ-शिक्षा के अन्तर्गत प्रतिकावियों की स्वस्थ दक्षियों, अनुभूत आवश्यकताओं, दैनिक समस्याओं, व्यावसायिक दक्षताओं, सामाजिक दृष्टियों, जीवनशैली परम्पराओं, अपवित्रता स्वस्थ एवं सफाई, पौष्टिक आहार, सज्जित मोचन, धिनु-पावन चर्च-शी माताओं की देखभाल, पारिवारिक जीवन की गुल समृद्धि, परिवार बलान, पैर-जन, सज्जनक रूप, नागरिक चर्च एवं अधिकार, राष्ट्रीय विकास की योजनाओं तथा आर्थिक-साधन एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण और सज्जित विकास आदि से सम्बन्धित ज्ञान और जानकारी प्रदान की जायगी । इस सबका उद्देश्य प्रमुख यह होगा कि प्रतिभागी एक ओर तो माया में

कोशल तथा दैनिक गति की जानकारी प्राप्त कर सकें तथा झुगरी और भे सुखी, समृद्ध, समृद्ध और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए अपने को समर्थ और सक्षम बना सकें। इसके अतिरिक्त, सर्वोपरि यह कि वे अपने अपने परिवार, अपने परिवेश, समाज, देश और अपनी दुनिया के सदन में एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे भाई या बहन अच्छे पति या पत्नी, अच्छे सहयोगी और पड़ोसी तथा एक योग्य, योग्य और विवेकशील नागरिक बन सकें और इस प्रकार अपनी समस्याओं के समाधान स्वयं ढूँढ़ते हुए न केवल अपनी जीविका के रख को उन्नत बना सकें, बल्कि जीवन के स्तर को भी उन्नत कर सकें, जिससे उनके माध्यम से समूचे समाज और राष्ट्र का समुचित विकास हो सके।

श्रीधर के लिए जिस पठन-पाठ्य सामग्री की आवश्यकता होगी, वह भी उनकी रुचियों, आवश्यकताओं तथा समस्याओं और उनके विषय पर आधारित होगी जो उनकी सांस्कृतिक उपयोगिता से सम्बंधित होंगे और उनमें पढ़ने तथा ज्ञानार्जन की रुचि भी निरंतर विकसित करते रहने।

श्रीधर शिक्षा के कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोचक ढंग से ज्ञान प्रदान करने के लिए यह भी आवश्यक होगा कि सोलर, पार्ट, फोड वार्ड, चित्र-बोर्ड, कटपुस्तिका, माट्रा, माट्रा-पत्र, पाठ्यपत्र, प्रतियोगिताएँ, भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण, माट्रा, प्रदर्शन आदि का प्रयोग किया जाए, जिससे जो कुछ जानकारी देय हो वह दृश्य रूप से प्रतिभाषियों के मानस के सामने रहे और वह ठोस रूप से उनके ज्ञान का अंग बन सके।

शिक्षक अथवा अनुदेशक

आइये हम इस पर विचार करें कि हम इस कार्य के लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यदि हम १५ से २५ वर्ष-वर्ग के लिए १,४०,००० केन्द्र प्रति वर्ष खोलते हैं तो हर साल १,४०,००० शिक्षकों की आवश्यकता होगी और यदि ३ वर्ष के स्तर पर निरक्षरता उन्मूलन की अवधि १० वर्ष मान ली जाए तो हर साल ७०,००० शिक्षक आवश्यक होंगे।

ये शिक्षा अथवा अनुदेशन व्यवसाय स्थायी होगा, हार्दिक रूप से बेरोजगार होंगे, अवकाश-प्राप्त अध्यापन, सेवारत अध्यापन तथा अन्य उपयुक्त स्थानीय व्यक्ति होंगे, विन्तु वरीयता प्रसिद्धि हार्दिक रूप से बेरोजगारों को दी जायेगी।

प्रशिक्षण

श्रीधर प्रौढ़ शिक्षा का यह कार्य मानकों को दी जाने वाली शिक्षा से अलग शिक्षाओं में भिन्न होगा, इसलिए इस कार्य के लिए नियुक्त शिक्षकों का पाठ्य प्रशिक्षण भी अत्यन्त आवश्यक होगा। इस प्रशिक्षण में सर्वेक्षण, जन-सम्पर्क, केन्द्रों का चयन, पठन-पाठ्य-सामग्री का उपयोग, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विभिन्न स्थानीय उपलब्ध सुविधाओं और सामग्री के पुटाने, आवश्यकतानुसार स्थानीय समस्याओं से सम्बंधित साहित्य की रचना, उपस्थिति तथा आस्था-प्रवृत्ति करना, आवश्यक दृश्य उपकरणों का उपयोग, प्रबोधनात्मक प्रौढ़-वक्ताओं में प्रशिक्षण-अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन तथा मुन-मनज दली, चेतना-बोध के गहन भाषा की जानकारी को सम्मिलित होगी, प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए पचास, वास्तविक विचार विमर्श जैसी उन शिक्षण-तकनीकियों में जो प्रमुख रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा जिनमें प्रतिभाषी सीखने की प्रक्रिया में स्वयं-आशीर्वाद हो, शिक्षण शिक्षा की प्रक्रिया उतनी ही है, जितनी कि स्वयं सीखने की अवधि वह प्रतिभाषी-केन्द्रित हो शिक्षक-केन्द्रित नहीं, जिससे उनमें आत्म-विश्वास की भावना उत्पन्न हो, स्वावलम्बिता का भाव आगत हो तथा निष्कर्ष उनमें लिए लोक न होकर अधिक शिक्षा हो। प्रशिक्षण में इन प्रयोगों के अलावा प्रौढ़ों को पढ़ाने की विधि, अ-व्युत्पादन तथा परीक्षा की तकनीक आदि भी सम्मिलित होगी।

शिक्षण

प्रौढ़-शिक्षा के इस कार्यक्रम में शिक्षक स्वतः जितना पढ़ा-लिखा सकेगा तथा अन्य जानकारी प्रदान कर सकेगा, उतना ही पर्याप्त नहीं होगा। प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत प्रतिभाषियों के व्यावसायिक ज्ञान की बढ़ोतरी,

स्वाम्य सुधार सहकारिता, सेवी सिपाई आदि स सम्बंधित तबनीकी जानकारीसे ले लिए उसे जिले के भण्डागार के सम्बंधित सिपाया के अधिकाग्रिया और बिगपशे से भी सम्पन्न करना आवश्यक होता जिससे कि उन्हें आमंत्रित कर वह उनकी साक्षरता-वेड पर जाताएं करा सके, प्रधान आदि निवा सके तथा मौखी पर से आकर जाय होते हुए भी दिखा सकें। इस दृष्टि से उसे एक सम-वयव (कोऑर्डिनेटर) की सुविधा असा करनी होगी।

पर्यवेक्षण, परीक्षण और मुख्य फल

साक्षरता केन्द्रों के प्रभावी संचालन के लिए उनका समय-समय पर पर्यवेक्षण भी आवश्यक होता है। जो केन्द्र प्रायः सरकार द्वारा चलाये जायेंगे उनका पर्यवेक्षण सरकारी पर्यवेक्षक करेंगे तथा जो केन्द्र स्वच्छिन्न सत्ताओं द्वारा चलाये जायेंगे उनके पर्यवेक्षण का दायित्व उही सत्ताओं पर होगा। किन्तु हमका यह सा-पक्ष भी होना चाहिए कि सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों में कोई सहयोग न हो।

साक्षरता तथा प्रौढ शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी बड़ा आवश्यक है। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया योजना के प्राथमिक से लेकर अन्त तक चरनी होगी। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत एक हीर तः शिक्षक स्वयं प्रत्येक प्रतिभावी की प्रगति का ऐता-लेखा समय-समय पर ऐता रहेगा दूसरे पर्यवेक्षक समस्त प्रतिभागियों की प्रगति का साम-हित अलग भी करता रहेगा और अन्त में उन उद्देश्यों और स्तरों के सम्म में साक्षरता केन्द्र पर दिये गये कार्यों का समग्र रूप से मूल्यांकन भी किया जायगा जिससे यह पता हो सके कि निर्धारित उद्देश्य और स्तर तक हम किस सीमा तक पहुँच सके हैं और जहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं उनके लिए हमारे क्या रचनायें कर मुकाबल हैं।

प्रमाण-पत्र

प्रौढ-साक्षरता तथा प्रौढ शिक्षा केन्द्रों के विभिन्न परीक्षण और मूल्यांकन के परधान सारा समस्त बड़े प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी दिया जायगा याकनीय होगा किन्तु वे स्वयं उक्त निम्न तम योगों के लिए प्रस्ता

का प्रोत्त नव सकें। जिा वय वर्गों के बालक-शालिकाएँ, जो किसी प्रकार से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गये थे और जो शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश पाना चाहेंगे, उनके लिए तो ऐसे प्रमाण-पत्र और भी अपि उपदेश मिद्ध होंगे।

अनुगमन

साक्षरता तथा प्रौढ शिक्षा के कार्य-क्रमों के अन्तर्गत प्रतिभागियों को जो योग्यता और पान प्रदान किया जायगा उसको बनाय रखने तथा उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिए अनुगमन कार्य जरूरी होगा। हम कार्य के निमित्त सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ पुस्तकालय पुस्तक सेवे समर्थ, रेडियो-टेलीवीजन चर्चा मण्डल सम्पन्न बोली आदि के अयोग्य आवश्यक होंगे।

गैर-सरकारी संस्थाओं का योगदान

प्रौढ शिक्षा का वर्तमान कार्यक्रम एक वृद्ध कार्यक्रम है और इसे ३ वय या अधिक से अधिक १० वय की अवधि में पूरा किया जाना है। स्पष्ट है कि इस तथ्य की प्राप्ति के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा ही नहीं हो सकती। अतएव हम कार्य के प्रदेय की गैरसरकारी संस्थाओं तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तिगत मय को एवं प्रयासों की भी सहस्रता अपेक्षित होगी। यी भी साक्षरता एवं मोडलिता का कार्य एक ऐता विविध कार्य है जिससे सदा की जायता को अपेक्षित है ही सरकारी तान के नियम और बाधन बाधन-तंत्रों की दृष्टि होते हुए भी, प्रायः बाधक बन जाते हैं। हा बाधक्यों के सफलन की व्यवस्था में आवश्यकता-नुसार लक्ष्योत्पन्न होना आवश्यक होता है किन्तु सरकारी नियमों के कारण यह लक्ष्योत्पन्न प्रायः सम्भव नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त इतनी विभिन्न योजना के विचार-विवेक का भार प्रायः सरकार पर ही छोटा भी नहीं जा सकता, सर्वोच्च संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के साथ-साथ गैर-सरकारी और व्यक्तिगत द्वारा भी इस शिक्षा में योग्यता और सफल सेवा की जायता से प्रति-होकर अपनायक पत्र मोडलिता दिया जाना होगा और सभी

निरक्षरता-उन्मूलन के इस अभियान में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धि हो सकती है।

बोर्ड तथा समितियों का गठन

प्रौढ-शिक्षा-कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह भी आवश्यक होगा कि एक राज्य-स्तरीय प्रौढ-शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाय और साथ ही जिला-स्तरीय प्रौढ-शिक्षा-समितियों का तथा तथा नगर समितियों का, गांव और बाई समितियों का, तथा बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थानों की प्रौढ शिक्षा समितियों का भी गठन किया जाय।

सुदृढ़-प्राप्ति

इस प्रकार, यदि प्रवेश में प्रौढ-साक्षरता एवं प्रौढ-शिक्षा के कार्यक्रमों का मन्त्रालय स्तरों पर पूरे मनोयोग के साथ विधिवत् रूप से कार्यान्वयन किया जाय तो, भाषा है कि १३-२५ वर्ष-वर्ष की प्रौढ महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत २०-२२ तक पहुँच सकता है, और प्रौढ पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत तो ५ वर्ष में लगभग दस-प्रतिशत सम्भव हो सकता है। बढ़ने की आवश्यकता नहीं कि यह उपलब्धि सर्वथा उल्लेखनीय होगी।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के द्वारा शिक्षण

बैजू भाई, मंत्री, अखिल भारत नयी तालीम समिति

इस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम पर गठित की ईश्वर भाई एटेल समिति तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति (जिसमें अल्पश्रद्धा ० मास्टर एम० आदित्यसिंह हैं) ने स्पष्ट रूप से समाजोपयोगी उत्पादन कार्य की स्कूल की शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का आवश्यकता स्पष्ट स्वीकार किया है। उन्होंने सर्व-ग्राह्य कहा है कि बीकानेर की प्रथम समाजोपयोगी उत्पादन कार्य की माध्यम से विकसित की जानी चाहिए।

ईश्वर भाई एटेल समिति ने इस विचार की व्याख्या करने का प्रयास किया है तथा ० आदित्यसिंह समिति ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है। व्याख्या इस प्रकार है :— समाजोपयोगी उत्पादन कार्य से अभिप्रेत है कि वह प्रमाण के लिए सोद्देश्य, सार्वक, ऐसा हाथ का कार्य हो जिसने किसी वस्तु का समाजोपयोगी उत्पादन बनवा सेवा-कार्य पूरा हो सके। सोद्देश्य उत्पादन कार्य तथा सेवा-कार्य का समाज की आवश्यकता से अनुसृत होना तथा शिक्षार्थी के लिए सार्वक होनी। ऐसा कार्य

संभव नहीं किया जाना चाहिए। नियोजन, निरीक्षण तथा श्रमिक स्तर पर विस्तृत पूर्वतैयारी आवश्यक है जिससे वह भूकृत वैधिक हो। जहाँ भी सम्भव हो, उपलब्ध विकसित बीकानेर तथा रायपुर का तथा माध्यमिक तकनीकी का उपयोग, उपनीत पर आधारित विरासतीय समाज की आवश्यकताओं का ध्यान कराने में सहायक सिद्ध होगा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने आगामी वर्ष से अपने से संबंधित स्कूलों में समाजोपयोगी, उत्पादन कार्य को अनिवार्य कर दिया है। परिषद् ने १ से ६ जुलाई १९७० को स्कूलों के लिए समाजोपयोगी, उत्पादन कार्य पर आधारित पाठ्यक्रम हेतु निर्देशिका तैयार करने के लिए एक कार्यशाळा का आयोजन किया है। राष्ट्रीय वैधिक शोध तथा प्रशिक्षण परिषद् ने भी १५ से २२ जुलाई तक समाजोपयोगी, उत्पादन कार्य का पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु एक कार्यशाळा आयोजित की है। प्रस्तावित कार्य-पाठ्यक्रमों से इन कार्य के प्रति ध्यान के उद्देश्य की

सम्भीरता परिलक्षित होती है। मैं इस कदम का हृदय से स्वागत करता हूँ।

ऐसे सभी लोगों को जिन्हें हमारे देश की सही स्तूल की शिक्षा को समझित करने और विकसित करने में अभिरुचि है, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य पर आधारित उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित करने पर सम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। दुर्भाग्य से देश के किसी भी विश्व-विद्यालय में, स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम विकास की एक स्वतन्त्र विषय के रूप में सम्भीरतापूर्वक स्थापित करने का प्रयास नहीं हुआ है। ईरवर माई समिति तथा आदिदेशिया समिति द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के मार्गदर्शक प्रारूप भी इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। अखिल भारत नवी छातीन समिति सेवाग्राम ने ह्यान में हो 'कार्योन्मुख विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संरचना' नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में कार्य के द्वारा शिक्षा के दिशा निर्देश के साथ ही इस विचार पर आधारित पाठ्यक्रम का संस्था भी प्रस्तुत किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय धर्मशाला और तथा प्रतिभालय परिषद द्वारा आयोजित कार्य-पालाओं में उपयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा समितियों द्वारा प्रस्तुत दिशा निर्देशों का भरपूर उपयोग किया जायगा और ये प्रत्याश्र अपना पाठ्यक्रम भी संवार करेंगे।

इस समय जब कि राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम की योजना बनाने तथा ईरवर माई समिति द्वारा संवार निर्देशों के आधार पर समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की सूची संवार करने का काम प्रारम्भ किया जा रहा है, इस संरचना में अन्तर्निहित मौलिक पहलुओं पर विचार करना उपयोगी होगा। उदाहरणार्थ, क्या हम वर्तमान

औद्योगिक धर्मशालाओं के अन्तर्गत समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को परिकल्पना करते हैं? वर्तमान में औद्योगिक शिक्षा का स्वरूप क्या है—अ इसमें ज्ञान और सूचनाओं पर आधारित पाठ्यपुस्तकों से विषय-वस्तु सी जाती है।

आ—सीखने की प्रक्रिया के समय सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है।

इ—आवाजें का मूल्यांकन मुख्यतः अंत में परीक्षा के रूप में होता है।

क्या हम मानते हैं कि समाजोपयोगी उत्पादक कार्य भी एक अलग विषय है, जैसा कि कार्य-अनुक्रम के सम्बन्ध में किया गया था। या हम समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की शिक्षा का माध्यम स्वीकार करें तो पाठ्यक्रम का स्वरूप कार्यचक्र शिक्षा का होगा। कार्यचक्र शिक्षा क्या है? कार्य से शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? सामुदायिक कार्य शिक्षा का भाष्यम कैसे बनेगा? कैसे ज्ञान, कुशलता तथा अभिरुचि का सम्बन्ध किया जायगा? शिक्षा यानि यह कोर्स सीन क्यों में (मिडिल और हाई स्कूल) अलग-अलग पाठ्यक्रम का जड़ बनाया जा सकता है?

एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण भी है। क्या हम सामाजिक कार्यों को समाजोपयोगी उत्पादक कार्य से भिन्न मानेंगे? अच्छा नहीं? उदाहरण के लिए क्या बचन योजना कार्यक्रम को समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की सूची में जोड़ेंगे? ईरवर माई पटेल समिति ने इसकी परिस्थिति देते समय सीरी-अम पर बल दिया है। क्या हम इसे स्वीकार करते हैं? ये और अन्य अनेक मुद्दे, क्या संवदन, शिक्षा-प्रशिक्षण, शिक्षा-पुनर्वशीकरण के सम्बन्ध में विचार करना होगा और उसके अनुरूप ही स्कूल का काम बनाना होगा।



राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा-कार्यक्रम - एक रूपरेखा

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, १९७८

इस लेख का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा किए गये नीति बलवत्तम को कार्यक्रम में परिणत करने की दृष्टि से क्रियात्मक विवरण की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। किन्तु प्रभाव यह नहीं है कि कार्यक्रम के लिए जनघर और अपरिवर्तनीय मार्ग-दृष्टिक रेखाएँ निर्धारित की जाएँ। प्रस्तुत उद्देश्य यह है कि विभिन्न विषयों की ओर की जाए। इसको दोहराना आवश्यक है कि उद्देश्य यह है कि १५-३५ आयु वर्ग के लगभग १००० लाख निरक्षरों के लिए ऐसे प्रौढ़-शिक्षा के कार्यक्रम जिनमें साक्षरता एक लक्ष्यार्थ बन हो, इस दृष्टि से व्यवहारित किए जाएँ जिनसे लगे स्वमेरित हानाई के कोशल प्राप्त हो सकें और वे अपने और अपने आतापरण के विकास में आत्म-निर्भर और सक्रिय भूमिका निभा सकें। सक्षमतामय और कार्य नीति का विवरण प्रौढ़-शिक्षा के नीति बलवत्तम में दिया गया है और उसे इस लेख के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

कार्यक्रम के स्तरीयता

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा-कार्यक्रम का बुनाराम २ अक्तूबर, १९७८ को होगा। सभी व्यावहारिक दृष्टियों से अब से लेकर मार्च, १९७९ तक की अवधि समय तैयारी की अवधि होगी। तैयारी का काम निम्नलिखित चीजों में होगा।

(१) सर्वप्रथम लगभग ५ लाख के स्तर पर १९७८-७९ में कम से कम १५ लाख तक ले जाने के लिए कार्यक्रम में डीठ कदम उठाना।

(२) रा. प्रौ. शिक्षा का अनुमान चलाने के लिए उपरिक्त आशय बनाना।

(३) निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष अध्ययन तैयार करना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में निम्नलिखित अनुभवों को ध्यान में रखकर प्रयोग रा. प्रौ. शिक्षा-कार्यक्रम के नियोजन और निष्पादन पर पड़ेगा।

(४) कार्यक्रम के विभिन्न अंगों में विस्तृत नियोजन हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति। इसमें प्रत्येक राज्य और युनियन टैरीटरी के लिए विस्तृत योजनाओं की तैयार करना भी सम्मिलित होगा।

(५) प्रशासन एवं सम-वय के लिए तथा कार्य-प्रणालियों तथा उनके रूपों में आवश्यक सुधार करने के लिए आवश्यक ढाँचे की स्थापना करना।

(६) सरकारी और अर्ध-सरकारी विभिन्न अधिकारियों को, जो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, चुनना और उनका वांछित स्तर का सहयोग प्राप्त हो के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(७) वांछित योग्यताओं को, विशेषकर साक्षरता एवं पढ़ाई में, स्पष्ट करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करना। ये योग्यताएँ सभी क्षेत्रीय कार्यक्रमों का अंग होंगी।

(८) राश्यों के विविधतायुक्त एवं आवश्यकता पर आधारित विवरण। अधिपत सामग्री तैयार करने की समता का विकास करना, साथ ही कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए उन्हें उचित सामग्री उपलब्ध करना।

(९) प्रशिक्षण-विधियों का विकास करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए संयोजन तैयार करना तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यक्षेत्रों की प्रशिक्षण देना।

(१०) मूल्यांकन तथा मानिटरींग एवं आवश्यक प्रायोगिक अध्ययन के लिए सुव्यवस्था व्यवस्था करना।

तैयारी का काम १९७८-७९ के अंत तक पूरा नहीं हो पाएगा। रा. प्रौ. शिक्षा के प्रारम्भ करने के बाद कम से कम एक वर्ष तक लगभग उन सब विमुक्तों पर कार्य करना होगा जिनका उत्तेजित उपर किया गया है। वास्तव में एक वर्ष में तैयारी का काम को सहायता सहायता पर

साधारित होगा, परन्तु वे भी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत होंगे।

पूर्ववर्ती वर्ष की उपलब्धियों के स्तर के आधार पर वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। तैयारी के कामों में समय की अनुमानित उपलब्धता भी सम्मिलित होगी। कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रथम दो वर्षों में किन्तु प्रकार कार्य प्रारम्भ किया जाता है और इस प्रयास इस बात के लिए किया जाएगा कि १९८३-८४ से अन्त तक १५-१५ आयु वर्ग की पूरी जन संख्या साक्षर हो सके। लक्ष्यों का वितरित प्रयोग इस प्रकार है —

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य लाख में	सुचारित लक्ष्य लाख में
१९८३-८४	१५	१५
(तैयारी का वर्ष)		
१९८४-८५	४.५	६.०
१९८५-८६	६.०	१५.०
१९८६-८७	१८.०	३३.०
१९८७-८८	१२.०	२५.०
१९८८-८९	३६.०	१००.०

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ये प्रत्याशित लक्ष्य हैं, और वास्तविक सफलता से कार्यक्रम गठित करने पर भी की शक्ति हो सकती है और इस बात की ध्यान में रखकर कार्यक्रम को गठित करना होगा।

उद्देश्य यह है कि १९८३-८४ तक १५० लाख लोगों के लिए प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों से गठित करने की क्षमता का निर्माण हो जाए। इस लक्ष्य वास्तविक होता है कि कार्यक्रमों में विविधता लाई जाए—उद्देश्य यह भी होता है कि एक ऐसे साक्षरजन के लिए उचित समान की स्थापना की जाए जिसमें आजीवन शिक्षा जीवन का एक अनिवार्य भाग बनती हो।

अनुकूल वातावरण बनाना

एनवॉल्वमेंट सर्वे निरन्तर प्रोत्साहन के परिणाम तथा लक्ष्यों के अनुभव, जहाँ निरन्तरता दूर करने के कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक विमानित किया गया है यह बताते हैं कि हमने बड़े कार्यक्रम को चलाने के लिए एक अनुकूल

वातावरण बनाने के लिए व्यवस्थित प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। कदाचित् जीवन की छोड़कर किसी अन्य देश के सामने साक्षरता की समस्या इस पैमाने की नहीं रही जैसी हमारे सामने है। साथ ही साथ ही कोई ऐसा देश हो जहाँ साक्षरजन और ज्ञान के प्रति इतना आसक्ति हो जैसा हमारे बड़े साक्षर हो जितने हम लोगों के पास हैं। वास्तव में रा प्रौद्योगिकी का मैंने हम सभी लोगों को प्रेरित करने की पूर्णव्यवस्था यह है कि उनमें आसक्ति और निरन्तरता की भावना उत्पन्न हो जाए। प्रशासनिक तथा शिक्षण दोनों में यह योग्यता की है कि प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायगी। लक्ष्य में लक्ष्य सभी राजनीतिक दलों के नेताओं में कार्यक्रम का पूरे हृदय से स्वागत किया है और समर्थन का आवश्यक दिशा है। यह आकांक्षी जैसी है कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले नेता भी जैसे डॉक्टर, शिक्षक, व्यापार और उद्योग विधायी तथा नवप्रवृत्त—इस समर्थन का अनुसरण करेंगे। इस सर्वमं में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मूल्यांकन किस्मों, टी वी, रेडियो, समाचार-पत्र, प्रचार-पोस्टर इत्यादि के द्वारा सेवा की जा सकती है। इसके लिए कुशल एवं समन्वित प्रयास की आवश्यकता होगी जिसमें सरकारी और निरन्तरकारी माध्यम एकजुट होकर कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विधियों—विचार सम्मेलनों एवं विचार-भेंटियों का आयोजन, स्कूलों और कॉलेजों में विषय साक्षरता-विषय बनाना आदि का भी आशय दिया जा सकता है। उन विभिन्न विधियों का, जिनके द्वारा एक वातावरण बनाया जा सकता है, विचारपूर्वक अध्ययन करना होगा और सहायक उसके अनुकूल आवश्यक कदम उठाने होंगे।

दृष्टिकोण

जबसे देश के सामने बरीबी और निरन्तरता की दृष्टि-बादी समस्याएँ हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी की अभाव और उपोपनि की स्थिति में लोगों के लिए विचार करती है और दूसरी विकास के दरवाजों को खोलने में बाधा पहुँचाती है और बरीबी में अपनी स्थिति पर काम

माने की योग्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।
यह स्तय में गरीबी और मिश्रणता एक ही विषय समझा
के दो पट्टा हैं और बिना एक के समाधान के लिए
तत्काल सपथ बनाए दूसरे का समाधान निबालने
के लिए सपथ करना निश्चय ही हम पर-पुष्ट करेगा
और निर्यात का कारण होगा। इस कारण से प्रौद्योगिकी
का भी सामाजिक आर्थिक विचार की प्रक्रिया में उच्च
बुनियादी परिवर्तन माने के स्थापन के रूप में सोच।
वाहिए—बुनियादी परिवर्तन उस स्थिति में जिसमें गरीब
विकास कार्यों के बिना प्रतिकूल रूप से बचने में सक्षम
रहते हैं। इन्हें बिना के सौजन्य विकास कार्यों के नेत्र
में सक्रिय भागीदारी का रूप में जाना है। सीधे की
प्रक्रिया में सारता पर ध्यान है कि तुलना ही पर्याप्त
नहीं है इसमें इस बात का महत्व पर भी ध्यान है जिससे
गरीबों और निरक्षरों की मान सम्मान का उन्नयन हो
और वह अपनी दुर्गा की अधिकाधिक क्षमता हो।

परन्तु के अनुसार सीमित तथा व्यापक दृष्टिकोण में भेद माना जाता है। कार्यक्रम की गुणात्मकता तथा व्यापकता पर यह भेद आधारित है। रा.प्रौ. वि.का. एन.ऐवा. व्यापक कार्यक्रम है जिसमें एक सीमित कार्यक्रम के निर्माण और हिमा धर्म के कुछ भी सन्निहित हैं। वास्तव में सीमित वालों की आवश्यकताओं के कार्यक्रम को समझकर इसे द्वय रा.प्रौ. वि.का. परम्परागत सीमित दृष्टिकोण से अधिक साफ बत जाता है। वास्तव में यह मानकर चलना होगा कि इनके बीच वैधानिक का काम अभी ही चल रहा है जब रा. प्रौ. वि.का. की जन आलोचन के रूप में दृष्टा जाए।

[illegible]

भाव'यकताओं से सम्बन्धता है तो पीछे मार्गों के निरंतर सहयोग के हेतु पूर्वावस्थाओं की पूर्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जनकत अभयम के समूह के लिए अनुसूच जातानरुण की रक्षा भी प्रभावी प्ररुण। वा सोत हो सकती है। यह सब फिर भी न्यायित्वात्त न हो। अतः इस विषय पर और विस्तार से सोचने की आवश्यकता है।

एक समय म संघ हुए प्रौढ़ विद्या के वायक्य से
संघटित विद्या को व्यवस्था से युक्त एक बड़ी प्रौढ़ आकाशी
को समझा हूँ नहीं हो जायगी । अतः आजीवन विद्या
क परिश्रम और उद्यम अनुरूप प्रयत्न पारमक प्राविधान को
राष्ट्रीय प्रौढ़ विद्या कार्यक्रम का निर्माण एवं सकल
उपायों के तहत समय दृष्टि से रक्षित होगा । इस दृष्टि से
रा० प्रौ० वि० का० पाठ यहाँ के बा० समाज नहीं हो
जायगा । अतः रा० प्रौ० वि० का० के प्रारम्भ से
ही व्यवस्थित अनुसंधानात्मक व प्रयोग चलाये होंगे ।
इसके अत्यंत पुरस्कार के अभाव में उपाय तदा प्रसार
और संचालन की प्रक्रिया में समस्याओं को सम्मिलित विद्या
यायगी । प्रौढ़ विद्या वायक्य को विचारानुसंगिक कार्य के
साथ साथ चलाना वांछनीय होगा ।

यह महत्त्वपूर्ण है कि प्रौढ़ शिक्षा या होलन को ऐसी नियोजन कार्यनीति से ध्विष्ट न करने के सम्बन्ध किया जाए जो सघन शैक्षिक नियोजन और रोजगारी मूल विकास कार्यों द्वारा घरीबी को दूर करने पर बल दे।

प्रत्येक राज्य विभिन्न अधिकरणों को दी जाने वाली तुलनात्मक प्राथमिकता को निश्चित करेगा। मोटे तौर से यह संकेत किया जा सकता है कि स्थानीय स्तर के साधारण नियोजन की आवश्यकताओं कारण शैक्षणिक अधिकरणों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शैक्षणिक अधिकरणों के अतिरिक्त कार्यक्रम को कार्यक्रम में परिचलित करने के लिए अन्य अधिकरणों को भी निश्चित करना होगा। इनमें नेहरू युवक वेद विध्वंसिणा" विभिन्न प्रकार की रोजगार देने वाली संस्थाएँ आदि सम्मिलित हैं। सरकार का काम इन विभिन्न अधिकरणों में समन्वय स्थापित करना और आवश्यकताओं को दूर करना होगा। देश के बहुत से भागों में सरकार को सम्मान परी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वहाँ भी ऐसा करना आवश्यक हो वहाँ प्रारम्भ में

कुछ चुने हुए जनपद और चुने हुए जनपद के कुछ कार्यपत्र विकास सड़ लिये जायेंगे। उद्देश्य यह होगा कि प्रयास को एक सुपरिमाणित क्षेत्र में केन्द्रित किया जाए और तब कार्यक्रम का प्रसार किया जाए।

प्रचलित में विभिन्न अभिवर्धन अपने ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे जो उन्हें अत्यन्त आवश्यकता सम्बद्ध और व्यावहारिक प्रतीत होंगे। सभी दशाओं में, यह समझ लेना आवश्यक है कि कार्यक्रम नीति व्यवस्था की रूपरेखा को बदलने के लिए लिये जायेंगे। अद्योचित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की दियाएँ निम्नलिखित होंगी —

- विविध अनुसरण के साथ साक्षरता।
- परम्परागत कार्यपरक साक्षरता।
- किसी प्रमुख विकास कार्य क्रम में सहायक कार्यपरक साक्षरता।
- सामाजिक एवं कृषिगत क्षेत्रों की साक्षरता।
- गरीबों को उपलब्ध करने और उन्हें पैतृगोत्र एवं भागदक करने के लिए साक्षरता।

संसाधनों का विकास

नीति-व्यवस्था में जो सहायक-व्यवस्था शिष्टि रच्य है उसका मर्म यह प्रोत्साहित करना के लिए एक सहायक आधार की बनावट और उसका विकास करना है। सहायक-आधार में बहुविध और आवश्यकता पर आधारित सामग्री की तैयारी सम्मिलित होगी चाहिए जिससे विभिन्न स्तर के कार्यकर्ता सक्षम की सहायता से अपनी बुद्धि बढ़ाकर सकें और कार्यक्रम की गतिशीलता प्रदान करने के लिए मूलभूत एवं दोष की व्यवस्था का समावेश किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित-निर्देशन तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अधिकरण एवं स्वच्छिक अधिकरण राष्ट्रीय सहायक ग्रुप के रूप में कार्य करेंगे। सहायक विकास में महत्वपूर्ण स्थान राज्य सहायक केन्द्र (राज्य) का है जो, राष्ट्रीय सहायक-ग्रुप के सहयोग में और वार्य क्षेत्र से निरंतर सम्पर्क रखते हुए सहायक-विकास का केन्द्र स्थल बन सकता है। इसके का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वे सहायक-आधार का

स्तर पर या प्रोजेक्ट स्तर पर विकेंद्रित करा सकें। वे वस्तु सहायक से अलग स्तर पर कार्य नहीं करेंगे, प्रायः ऐसी विभिन्न सहायक और अन्य लोगों को सहायक-विकास में योगदान कर सकते हैं, सहयोग करने में उद्देश्य से सम्बन्धितक प्रतिक्रिया करा करें। इसके की उपयोगिता उनके द्वारा विकसित प्रोजेक्ट्स तथा प्राथमिक क्षमताओं पर निर्भर करेगी तथा इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उसमें अपने सेवित क्षेत्रों में सहायक तथा व्यक्तियों के सहायकों में सम्बन्ध स्थापित करने की वित्तीय क्षमता है और कितना समय उनमें सम्पत्ति राज्य सरकारों से मिला है। जो कुछ भी हो, कार्यक्रम के लिए सहायक का सम्बन्ध मुख्यतः जनपद, प्रोजेक्ट स्तर का शक्ति है। सहायक विकास का साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा अन्य अधिकरणों द्वारा सहज हो सभी आवश्यक भाषिक तथा प्रशासकीय समर्थन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सहायक विकास के कार्य में जनता का सक्रिय सहयोग सब विवरण लोगों का सहयोग जिनके लिए यह कार्यक्रम मुख्यतः बनाया जाएगा, सहायक प्रचार की विवक्षनीयता के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यही बात नीति-व्यवस्था की सरलता में निहित है और उसमें स्पष्ट भी की गई है। इस प्रकार के सहयोग के लिए विविध उपाय करने होंगे। इनमें कुछ निम्नलिखित हैं :—

- सीखने वालों की आवश्यकताओं को समझने के लिए सुनियोजित सर्वेक्षण।
- प्रोत्साहित सीखने वालों की सहज प्रतिनिधित्व प्राप्त कर विविधों तथा सामग्री की वार्षिक जांच एवं परीक्षण।
- ऐसे स्थानों पर जहाँ राज्य जनपद सहायक केन्द्र पर काम करने वाले कार्यकर्ता प्रायोगिक के साथ सोचते हैं और काम करते हैं, बहुधा सम्मेलनों और दिवसों का आयोजन करना।
- सक्रिय प्रायोगिक व्यक्तियों का पता लगाना और उन्हें कार्यक्रम की ओर उन्मुख करना जिससे उनके सम्पूर्ण से प्रोत्साहित सीखने वालों की व्यवस्था और सम्पन्न समस्याएँ सामने आती रहें।

—ऐसे व्यक्तियों का व्यवस्थित सहयोग जो ग्रामीणों के साथ रहते हैं और भाग करते हैं।

पोर्टलैंड सीमेंट बालो के सहयोग के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि सहायन वेड चाहे राज्य स्तर स्तर का हो या अल्प स्तर का, अपने काम में सहयोग और उसकी समीक्षा निरीक्षण तथा प्रोड सिया के शिक्षको से भी प्राप्त करें। इसको व्यवस्थित ढंग से शिक्षावित करने के लिए बिना प्रस्ता में फेंके, समुचित प्रबन्ध करना होगा। आवश्यक बात स्मरण रखने की यह है कि रा० प्री० वि० का० सीमेंट बालो के जीवन की आवश्यकताओं से बहिष्कृत रूप से सम्बन्ध हो, और इसके लिए यह आवश्यक है कि विशेषज्ञों तथा प्रसाहकों और सीमेंट बालो में सम्बन्धपूर्ण सम्पर्क स्थापित किया जाए।

सहायक के विभिन्न भव निर्माणाधीन हो सकते हैं —

શિક્ષણ હાનાજન સામગ્રી

इस सम्मेलन में प्रारम्भिक कार्य सीखने वालों की भावप्रकृताओं का पता लगाना होगा। विरतृत पाठ्यक्रम जिसमें भय दावों के साथ साथ प्रत्यावृत्त अधिगम परिणामों का भी प्रलेख होगा, सुनिश्चित सीखन की भावप्रकृताओं के आधार पर निश्चित करना होगा। भावप्रकृता परीक्षण के प्रस्ताव, पाठ्यक्रम के आधार पर, निश्चित सहायक सामग्री तथा सीखने की सामग्री सभी छात्रमानव से संसार करनी होगी। नीति वक्तव्य में बोलचाल की भाषा में साधरता की बात प्रदान करने का प्रलेख किया गया है। इस बात को बिना भयप्रकृता सीखन के जाते हुए, यह सम्मेलन होगा कि सीखने की प्रक्रिया की भावप्रकृता की भाषा में व्यवस्थित किया जाए और वहाँ भावप्रकृता की सीखने वालों के लिए ऐसे केतु बनाए जायें जिससे वे सीखने भाषा में समता प्राप्त कर सकें। अतिरिक्त रूप से राज्य प्रशासन के दृष्टिकोण या राष्ट्रीय मानक भाषाओं, बोलियों में सामग्री के आधार करने के बावजूद भाषा की एक रूप के सीखन निश्चित शास्त्रात्मक सामग्री विवक्षित करना सम्भव न होगा। दूसरे का सीखने का एक यह सम्मेलन हो जाये कि जनप्रतिपक्ष स्तर पर भी सामग्री के आधार की बात हो।

प्रशिक्षण

बिना वर्गों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी, वे निम्नलिखित हैं

—राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मुख्य कार्यकर्ता ।

—विशेष क्षेत्रों जैसे पाठ्यक्रम रचना, शिक्षण ज्ञानार्पण, सामग्री को तैयार करना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन इत्यादि के लिए प्रोफेशनल एवं विशेषज्ञ ।

— जिला प्रोजेक्ट तथा विकास खंड स्तर के कार्यकर्ता ।

— श्रेणीय निर्देशक ।

-प्रौढ विद्या केन्द्र के शिक्षक ।

प्रौढ शिक्षा का विशेषाध्ययन, यूनेस्को तथा अन्य राष्ट्रीय अधिकरणों की सहायता से विधियों तथा प्रशिक्षण का संयोजन तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय, राज्य तथा जनपद स्तर के मुख्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सभापति-केंद्रों की प्रोब्लेम तथा ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं एवं निरीक्षकों के प्रशिक्षण का समन्वय करना चाहिए तथा प्रौढ शिक्षा-क्षेत्रों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम की जिम्मेदारी क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम के दिशान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकरणों की होनी चाहिए। प्रशिक्षण की भाषा, एकाधिक तथा सावक प्रशिक्षण पर तुलनात्मक बात, प्रशिक्षण विधियों इत्यादि का सम्बन्ध में विभिन्न विवरण सोचने होंगे। जब तक अनिवार्य न हो, उदाहरणार्थ प्रशिक्षण सभाएं न सोची जाएं। वर्तमान प्रशिक्षण सभाओं की रा० प्रौ० शिक्षा का० में खड़े हुए विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता का विनाश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस सदन में दिव्य विद्यालय तथा अन्य उच्चशिक्षा की सभाएं मूल्यपूर्ण योगदान कर सकती हैं। सामान्यतः दो अधिकरण प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार हैं उदा० ऐसी विभिन्न सभाओं तथा व्यक्तियों से, जो संशोधनक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल में सहयोग दे सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने की दृष्टि से समन्वयकर्ता के रूप में कार्य कर सकें चाहिए।

मानिटरिंग, मूल्यांकन तथा अपडाइट रिसर्च

अन मिश्र के कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से बहुत सी एच एच एन सीएचओ को आवश्यक रहती है। इस चरण में व्यवस्थित मानिटरिंग तथा मूल्यांकन के महत्व को समझी जा सकता है। इनके पूरे कार्यक्रम में प्रभाव करना चाहिए और समय समय पर आवश्यक कार्यक्रम में सहोपन करने को दृष्टि से वे पूर्णवर्णक हो सकते हैं। अनपेक्षित, अपेक्षाकृत तथा उम्मीदित कार्यक्रमों की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है जिससे रा. प्रौ० वि० का० के अनुभवों से व्यवस्थित रूप से विश्लेषण हो सके और भविष्य के लिए मार्ग निर्देशन मिल सके। के०ड को तथा राज्य की सरकारों को व्यवस्थित मानिटरिंग में स्थायी रूप से शामिल होना चाहिए। विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा की सरकारों और उनके को मूल्यांकन तथा अपडाइट कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका भरा करनी होगी। मानिटरिंग तथा मूल्यांकन-तक व्यवस्था तथा प्रोजेक्ट स्तर पर भी गठित होने चाहिए क्योंकि मुख्यतः वहाँ पर कार्यक्रम में सहोपन के हेतु पूर्णवर्णक का प्रयोग किया जाएगा।

'सिद्धान्त'-अन्वितकरण

भीति वक्तव्य में उन विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख है जिसका प्रयोग शिक्षण व्यवस्था में किया जाएगा और जो रा० प्रौ० वि० का० में सरकार के साथ जिम्मेदारी बाँटने में मिलान की जिम्मेदारी देने में प्रभावी बात उन सम्बन्धित व्यक्तियों की उपस्थिति होनी चाहिए जिनके कार्यक्रम गठित करने में सहस्रमन्त्रक पदक ही और कार्यक्रम के प्रति आस्था एवं प्रतिबद्धता का भाव हो। विभिन्न प्रकार के लोग जिन्हें शिक्षण की जिम्मेदारी दी जा सकती है निर्मलक्षित होय।

(ब) मध्याह्न

मध्याह्न के कार्य सम्बन्धी अनुभवों की ध्यान में रखा जाये और उनकी बहुत सी स्पष्ट सीमाओं के बावजूद, विशेष रूप से औपचारिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकाधिकार-धन पर चर्चा, मध्याह्न ही रा० प्रौ० वि० का० के

शिक्षण-प्रबन्ध की व्यवस्था करने वाले मुख्य अधिकारण होंगे। भविष्य व्यवस्थाओं के प्रति शिक्षा-केन्द्र-कार्य शिक्षक के अनिवार्य दायित्वों में रहना होगा, इस समय मध्य पूर्णवर्णक स्वीकृत हो रहेगा। उन लोगों में भी, जो इस जिम्मेदारी को स्वेच्छा से लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों का चुनाव करना पड़ेगा जिनसे वास्तव में इस कार्यक्रम के प्रति निष्ठावादी होने की आशा की जा सकती है। उचित होगा कि इस कार्य के लिए ५०-६० प्रति भाग दिया जाए। स्कूल के मध्याह्न के सहयोग प्राप्त करने में सुविधा हो सकती है, यदि उनके प्रौद्योगिकी सफलता का समर्थन प्राप्त किया जाए।

(ब) विद्यार्थी

चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना के अंग के रूप में इसे उचित रूप से समायोजित कर लिया जाए, और चाहे अन्य किसी उपयुक्त विधि से, उच्चशिक्षा के विद्यार्थी प्रौद्योगिकी केन्द्रों के गठन में बहुमूल्य अधिकारण बन सकते हैं। इसके लिए इस स्तर की संस्थाओं के मध्याह्न को भी समायोजित होगा। वैश्विक सर्वे की वर्तमान समय विधियों के लिए व्यवस्था, प्रमाण-पत्र आदि के बारे में पुनः सोचना आवश्यक होगा। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों का सहयोग स्वीकृत होना चाहिए किन्तु विश्वविद्यालय के मार्गदर्शकों को एक सहायक व्यवस्था होगी जिसमें विद्यार्थियों को इस कार्य के सहयोग मिल सके और वे इसे सहायक समझें।

(स) छापील नवयुवक

बहुत से बेरोजगार या अल्प रोजगार में लगे छापील नवयुवक हैं जिन्हें थोड़े बहुत शिक्षा की मिली है। उन्हें अपने वैश्विक स्तर के आवश्यक उन्मुख हेतु साधकाला के नियोजित प्रशिक्षण देकर तथा मोटिवेशन देकर इस जिम्मेदारी में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गाँव के नवयुवकों को भी जो किसी प्रकार के रोजगार में नहीं लगे हैं और जिन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की है, प्रौद्योगिकी केन्द्रों के सहयोग के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्थितियों और जन जातियों के कार्य की बड़ी सुविधा हो सकती है यदि उन्हीं में से लोगों को लेकर उन्हीं को प्रौद्योगिकी-

केन्द्र चलाने का नेतृत्व दिया जाय। ऐसे लोग अपने काम-पथ में सने रह सकते हैं और उन्हें आर्थिक बन्धोपा दिया जा सकता है। बैरोमन्टर या अल्परोजगार वाले व नव-पुरुष भी, जो इस काम को पूर्णजातिव आधार पर लेते हैं १ से १५ मासुव के बन्धो का रहस्य बन्धो के लिए मनोवैचारिक शिक्षा दे दो के चलाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। इससे न केवल प्रौढ़ शिक्षा व शिक्षा को वा एव मध्यम उपपुत्र तथा मित छात्रा, प्रत्युत इसल छात्रोण क्षेत्र में एव नये प्रसार के नेतृत्व का सुजन होवा और साथ ही राष्ट्रीय बैरोमन्टर को काम करने में भी सहायता मिलेगी।

(ब) नृत्यक अवकाश सेवा निवृत्त सैनिक

इस वर्ग के लोग राष्ट्रीय तथा नगर-क्षेत्रो दोनों ही के मूल-वर्गों भूमिका अथवा नृत्य सकते हैं। सैनिकनृत्य कार्य-चारियों की अपनी कामदानी बलाने की आवश्यकता होती है, समान रूप से यह भी महसूसपूर्ण है कि उन्हें अपने को व्यस्त रखने के लिए काम की भी आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि नीति बलवत्त में बलित अवकाशियों के अनुरूप कार्यक्रम चलाने की कठिनी क्षमता के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट सीमाएँ हैं तथापि उन्हें अपने अनुभवों की सुविधा है। साथ ही इस बात का भी साक्ष मिल सकता है कि मानव में वे सम्मान की दृष्टि से देने जाते हैं।

(ई) क्षेत्रीय स्तर के सरकारी तथा अन्य कार्य क्रम

यह सम्भव है कि ऐसे कार्यकर्ता जैसे ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्राम-वैदिक दाल सेविका, ग्रामसेवक, सहकारी समितियों द्वारा पचायतो के कार्यकर्ता आदि।

(क) क्षेत्रीय-स्तरीय सामाजिक कार्यकर्ता

विशेषरूप से गरीब लोगों में काफी सख्या ऐसे लोगों की है जो सामाजिक विकास में अपना योगदान करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों की क्षमता का उपयोग किया जाय और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाय।

क्रियात्मकता के अभिव्यक्ति (प्रज्ञा-सीमा)

रा. प्रौ. शिक्षा का. की जिम्मेदारी निम्नलिखित के लिए

सरकार को स्वयंसेवक चुनना होगा। समीक्षा के आधार पर ऐसे कार्यकर्ताओं को जो सरकारों अभिव्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हैं नये मिरों में बनाया जाएगा। यह उपयोगी प्रतीत होता है कि प्रजाप देश में सभी जनपदों में सभी भागों में कार्यक्रम को हलके रूप में चलाने के प्रारम्भ में बर्धन दोनो म प्रजाप को संश्लिष्ट रखा जाय। शिक्षा मन्त्रालय के कार्यक्रमों और उ के विभागत की पर्याप्त रूप से बढ़ाना होगा जिससे विभिन्न अधिकारियों का सहयोग व्यापक रूप से मिल सके। जो कुछ भी हो, ऐसा जन-प्राप्तोत्पन्न जो हलकी यन्त्री मावाची की प्रभावित करेगा, एक मन्त्रालय तथा विभाग द्वारा चलाया नहीं जा सकता दूसरे मन्त्रालयों एवं विभागों को सम्मिलित करने का हर प्रयास होगा चाहिए जिससे वे सब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के चलाने की जिम्मेदारी में भाग ले सकें। दूसरे मन्त्रालयों, विभागों को इस प्रकार के कार्यक्रमों के निर्माण में कार्यपरक साक्षरता एक अवश्य हो, चलाये के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही वे सब शिक्षा-संविचारियों द्वारा चलाए गए सामाजिक कार्यक्रम में भी योगदान करें। इन मन्त्रालयों विभागों के लिए यह आवश्यक होवा कि वे अपने बजट प्राविभाग की सीमाओं में कुछ परन्तुपि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए मरग से निर्धारित करें। चाहे यह कार्यक्रम क्षेत्रीय योजना का अथवा और चाहे किसी अन्य अभिव्यक्ति द्वारा संचालित हो, राज्य-सरकार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित होगी। सभी म्यावहारिक दृष्टियों से यह कहा जा सकता है कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूरे तौर से राज्य-सरकारों की जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को उन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का जो वे विगत वर्षों में चला रही थी, पुनर्मुखान्वयन करना होगा और उन्हें धरोपित और पुनर्द बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। यद्यपि सम्बन्ध तथा क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य-सरकारों की होगी, क्षेत्रीय सरकार न केवल नीति-निर्धारण और सामान्य मार्ग-दर्शन-पूरी के निश्चय करने से सम्बन्धित होगी, बल्कि यह भी देखेगी कि राज्य सरकारों द्वारा नीति बलवत्त के अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम जो राष्ट्रीय एवं विषय वस्तु से सम्पन्न एवं विभिन्नता को महत्व देता है, स्वेच्छिक उपकरणों की सहायता से सर्वोत्तम रीति से क्रियान्वित हो सकता है। इस समय स्वेच्छिक छात्राओं का सहयोग कुछ सीमित था है और सर्वप्रथम इस समय प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले स्वेच्छिक अभिनेत्रणों अपना ऐसे अभिनेत्रणों का, जिनमें काम करने की क्षमता है सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वेच्छिक प्रयास करना होगा। दूसरे, इस बात का भी प्रयास करना होगा कि नये अभिनेत्रणों के उद्भव के लिए परिस्थितियाँ सज्ज न हों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ ऐसे अभिनेत्रण कम हैं। स्वेच्छिक अभिनेत्रणों की सहयोगी भूमिका को मान्यता देना आवश्यक है और यह वांछनीय होगा कि निर्णय लेने के हर स्तर पर उनके परामर्श लिया जाए, विशेष रूप से उन मामलों में जो इन अभिनेत्रणों के कार्य को प्रभावित कर सकते हों। साथ ही अनुदान देने की विधियों का पुनरावलोकन करना होगा।

रा० प्रौढ शिक्षा का० एक जन-भाग्योत्थन का रूप लेता है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस योजना तक मध्यमको तथा विद्यापिठों की इस कार्यक्रम के प्रति निष्ठावान् बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पुनरावलोकन के लिए यह कहा जा सकता है कि नेहरू मुद्रांकरो की कार्य-प्रतिष्ठा का पुनरावलोकन किया जाना और उनके प्रयास को प्रौढ शिक्षा पर केंद्रित किया जाना। इसी प्रकार ऐसे मध्यम और नवप्रतिष्ठा वि-हीने अपनी शिक्षा प्राप्त कर भी है और जिसके मत में इस कार्यक्रम में बाधा देने की योजना है। इस प्रयास में स्वाभाविक सहयोगी होंगे। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा की संस्थाओं के विद्यापिठों का वर्ष भरका सहयोग है। बहुत सस्ते समय से संवैधानिक रूप से विश्वविद्यालयों में समाज से सम्पर्क रखने की वांछनीयता पर बल दिया है। राष्ट्रीय औद्योगिक-कार्यक्रम विश्वविद्यालयों तथा कानूनों के सामने एक चुनौती को प्रस्तुत कर रहा है जिसे स्वीकार करने अपना कर्तव्य समझकर सकते हैं और उन शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि प्रौढ-शिक्षा को केवल एक विषय का विषय न समझा जाय, प्रस्तुत इसम पूरे समाज के सदस्य, जिससे जिस भी भी

निश्चय ही सम्मिलित हैं, सब ऐसे क्षेत्र में रहे हैं कि विश्वविद्यालय इस प्रकार के बड़े योगदान की तैयारी कर रहे हैं और तदनुसार अपनी प्राथमिकताओं में भी आवश्यक सुधार कर रहे हैं।

रोजगार देने वालों को चाहे डाइरेक्ट सेक्टर के हो या इन्डियन, अपने न्याय-क्षेत्रों में प्रौढशिक्षा प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका देना करनी चाहिए। शासक में यह उचित होगा कि रोजगार देने वालों के लिए प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों को बलान्तर अभिवर्धन कर दिया जाय। इस मौक़े पर स्पष्टता तथा सहयोग एवं अन्य रोजगार देने वाले अभिनेत्रणों के माध्यम से प्रयासों द्वारा न दिया जा सकता है। एनिक डेक्टर तथा निर्माण के कार्यों में सरकार को इसके लिए अलग बजट का प्राविधान कर नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। परिणामस्वरूप काम के पट्टे से कमो और कुछ अधिक व्यय का पर्याप्त सुरक्षा कार्य-क्षेत्रों के काम में गुणात्मक सुधार के रूप में तथा विशाल-कार्यों में उनके सशक्त सहभाग के रूप में मिलेगा। स्वच्छित सेक्टर में काम करने वालों की शिक्षा सुविधा-पूर्वक ही या खराबी है यदि कार्यक्रमों के सुनिश्चित सत्य रूप से सम्मिलित हो जा सकें।

स्वाधीन विकास जैसे नवप्रतिष्ठा तथा पञ्चायती-राज सरचाएँ औद्योगिक शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करती रही हैं। इन अभिनेत्रणों को जो नागरिक और विशाल बलों से सम्बन्धित हैं, यह सुविधा है कि उनका धनता से सम्पर्क है—उनकी दैनिक समस्याओं से तथा उनकी आवश्यकताओं से। मत उनसे यह आशा करनी चाहिए कि वे रा० प्रौ० शि० का० के विद्यालय में सहयोग देंगे।

नियोोजन प्रशासन एवं निरीक्षण

यह प्रश्न अबसर है जब सरकार ने गिरदार आवादी के इतने बड़े माय के लिए एक नियोजित प्रौढ-शिक्षा-कार्यक्रम बनाने का निश्चय किया है। इतने बड़े कार्यक्रम के नियोजन तथा उसके क्रियान्वयन के लिए बहुविध नोनों का समर्थन प्राप्त करना होगा जैसे सामाजिक कार्य-कर्ता, परिवर्तन नियोजन विवेकज्ञ, प्रत्यक्ष विवेकज्ञ, निरन्तर विवेकज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञों की अतिरिक्त टोनिदा

तथा प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार। नियोजन का व्यापार्य व केवल केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा होना है, बल्कि स्थानीय निकायों स्वैच्छिक अधिकारों, विश्वविद्यालयों, शिक्षकों व संगठनों द्वारा भी हो। सरकार को विभिन्न स्थितियों सम्पादन और संगठनों के सहयोग के लिए नेतृत्व प्रदान करने वाली भूमिका बजा करनी है। यह भी आवश्यक है कि राज्य तथा जनपद स्तर पर समुचित मजिस्ट्रेट सम वष और सत्रेयस की दृष्टि से स्थापित किये जाएं। राज्य की सरकारें राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषदों की स्थापना की सम्भावना पर विचार कर सकती हैं और इसी प्रकार की परिषदें जनपद स्तर पर स्थापित की जा सकती हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए केंद्र, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर के प्रशासकीय ढांचे निम्नलिखित अपर्याप्त हैं। ऐसे प्रशासकीय ढांचों का जो इस कार्यक्रम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगे सफेद देने के लिए सम्बन्धितपूर्वक अध्ययन प्रारम्भ कर दिया गया है इस समय केवल मोटी आंखें नहीं दी जा रही हैं।

केंद्र सरकार

प्रौढ़ शिक्षा विभाग को ही नई जिम्मेदारियों को देखते हुए मन्त्रालय की व्यवस्था उचित रूप से सुदृढ़ की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा के निदेशालय को अपने काम कलाप का पूर्णतः विस्तार करना होगा और इस दृष्टि से कि वह प्रभावित भूमिका बजा कर सभी सहे आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाती चाहिए।

राज्य-स्तर

ऐसे राज्य स्तरीय प्रशासकीय तथा नियोजन यन्त्रिणी की स्थापित करने के लिए तुरत कदम उठाने की आवश्यकता है जिसमें एक स्वतन्त्र निदेशक या अतिरिक्त निदेशक हो जो शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करे। राज्य-स्तरीय संगठन के लिए आवश्यक सहायक स्टाफ भी देना होगा। प्रत्येक राज्य सरकार राज्य तत्विधालय के शिक्षा विभाग में प्रौढ़ शिक्षा के कार्य को करने के लिए एक पूर्ण विभिन्न की स्थापना पर विचार करे जो अच्छा होगा।

जनपद तथा ब्लाक स्तर

कार्यक्रम के लिए पूर्ण वष जनपदों में सहायक स्टाफ के साथ एक अतिरिक्त शिक्षा शिक्षा अधिकारी की आवश्यकता होगी। प्रशासन और निरीक्षण की दृष्टि से तथा आवश्यक टेक्निकल सहायता की दृष्टि से भी आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ की पर्याप्तता पर ध्यान देना होगा।

स्वैच्छिक अधिकारण

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय स्वैच्छिक अधिकारणों, राज्य सभासम ईम्न आदि को आवश्यक समर्थन देना होगा जिससे वे राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में योगदान करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक क्षमता स्थापित कर सकें।

इसने बड़े कार्यक्रम में सुपरविजन तथा मार्ग-दर्शन हेतु, पूर्णतः प्रबन्ध होना चाहिए। सुपरवाइजर परम्परागत रूप से निरीक्षण नहीं होना चाहिए बल्कि वह विशेष रूप से चुना हुआ प्रोफेशनल होना चाहिए जिसे काम में अधिकृत हो और जो प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र के वृत्तों को काम में सुविधा प्रदान कर सके। स्वैच्छिक सस्थाएँ स्वतन्त्र रूप से सुपरविजन व्यवस्था स्वयं बनना चाहेंगी। उन क्षेत्रों में जहाँ कार्यक्रम सरकारी अधिकार्य द्वारा चलाया जा रहा हो, यह देखना होगा कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए पूर्ण सुपरविजन व्यवस्था रखना आवश्यक होगा या सहे प्राथमरी स्कूल सुपरवाइजर से सम्बन्ध रखना। इस विषय पर कठोर तथा राज्य-सरकारों द्वारा विस्तार से विचार होना चाहिए।

सरकारी तथा स्वैच्छिक अधिकारणों के सामने एक बहुत बड़ी नयी प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षकों के प्रोफेशनल स्वयं के अभाव की है। विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के स्टाफ को तैयार करने की वर्तमान सुविधाएँ अत्यन्त सीमित हैं और उनके विस्तार की आवश्यकता है। सरकार, विश्वविद्यालयों तथा स्वैच्छिक अधिकारणों द्वारा प्रोफेशनल विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, कार्यक्रम चलाये होंगे। प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सहे प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं के देहन ढांचे के

सम्बन्ध में भी विचार करना होगा। जहाँ तक सम्भव हो, यह सुनिश्चित करना वांछनीय होगा कि प्रौढ़ शिक्षा-संस्था में जो लोग प्रवेश करें वे उसी व्यवस्था में बड़े और उन्नति करें न कि वे बाहर चले जाने के लिए विवश हों।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ और लक्ष्य

विगत वर्षों का अनुभव यह बताता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकारें प्रौढ़ शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि को वांछित शिक्षा को देने, कार्यक्रमों में लगाती हैं या विकास के माध्यम से। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे प्रौढ़ शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि इतर उद्योगों को जा सके। साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि राज्य में कार्यरत के निवेशन एवं शिक्षाव्यय की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर ही रखनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी ऐतिहासिक अधिकारों से व्यापक सहयोग प्राप्त करना, नये कार्यक्रमों का प्रारम्भिक परीक्षण आदि होती है।

धनराशि की व्यवस्था के अतिरिक्त, उसकी पर्याप्तता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। योजना आयोग तथा योजना के विभागों का एक दृष्टि यह निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रति सीखने वाले पर, केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रशासकीय व्यय, मूल्यांकन, मान्यता, लेख तथा नये प्रयोगों के सर्व को विकास कर, ५५ व० व्यय आया। दृष्टि से इस व्यय की गणना छात्र-संख्या के आधार पर की है, न कि उस संख्या का जो कार्यक्रम को अन्त तक सफलता पूर्वक पूरा करेगी। ऐसे सफल सीखने वालों की संख्या पूरी संख्या की लगभग ३ होती। अतः यह मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि प्रति सीखने वाले पर व्यय

७० व० से कम नहीं होगा। केन्द्रीय तथा राज्य-प्रशासकों, मूल्यांकन बोध आदि पर व्यय लगभग उस कुल व्यय का २० प्रतिशत होगा जो प्रति सीखने वाले की दर से गिराता गया है। इन गणनाओं के आधार पर पर्याप्त धन आवंटन करनी होगी।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के सफल के रूप के अतिरिक्त प्रारम्भ के ही नवसाक्षरी तथा उन लोगों के, जिन्होंने औद्योगिक व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त की है, अनुसरण और निरंतर शिक्षा को चलाने के लिए व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा नहीं की गयी है किन्तु यह तर्क सगत होगा कि कुल व्यय का लगभग २० प्रतिशत इस कार्य के लिए रखा जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

गरीबी और निरक्षरता की सीमाएँ राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर दूर तक जाती आती हैं। एक देश के अनुभव और सुझावों से परस्पर आदान प्रदान एवं निरंतर सहाय द्वारा दूसरे देश को लाभ उठाना चाहिए। सम्भावित इन अपने व्यक्ति तथा मानवीय संसाधनों को पूरे तौर से ध्यान में रखते हैं जो वास्तव में बहुत सीमित नहीं हैं जब राष्ट्र के माध्यम का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न सामने है। रा० प्रौ० वि० का के निर्धारण एवं शिक्षाव्यय में सुझावों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अधिकारों को परस्पर सम्मान तथा समानता के आधार पर सहयोग देने के लिए अतिवृद्ध होना आवश्यक है। रा० प्रौ० वि० का० के उद्देश्य किन्तु भी अप्रत्याशित बनें हो, हमें अपना कार्य उन देशों से, जो इस क्षेत्र में अप्रत्याशी रहे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है विवेक पूर्वक सीखने की आवश्यकता से प्रारम्भ करना चाहिए।



प्रौढ़-शिक्षा

नोटि बक्तव्य (दिसम्बर, १९७८)

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

शिक्षा की प्रक्रिया से लोगों की अव्यक्त समस्या को प्रकट करना संभव तथा सामाजिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण बिन्दुबिन्दु है। वर्तमान सरकार जब मार्च, १९७७ में सत्तारुद्ध हुई तभी से उसकी दृष्टि में यह बात सर्वोपरि रही है। एक ओर जहाँ १४ करोड़ तक प्राथमिक शिक्षा को सामग्रीय बनाने का पूरा प्रयास होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर धार्मिक सुविधा प्रौढ़ों तक भी प्रसारित होनी चाहिए जिससे वे अपनी धार्मिक व प्रेमियों की सुधार तक और अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विनियमित कर सकें।

२. सरकार ने निरक्षरता के विच्छेद सुविधित, सुनियोजित तथा अद्वय्य रूप से करने का निश्चय किया है। निरक्षरता सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों में अपनी सभी गूँथों को हटाने का प्रयास करे। निरक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य के भविष्य अविनाशक रूप से मान्य होनी चाहिए।

प्रौढ़-शिक्षा के सम्बन्ध में वर्तमान चिन्तन निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित है।

(क) - निरक्षरता व्यक्ति के विकास और देश की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए अत्यन्त सम्भोदनायक है।

(ख) - स्कूली शिक्षा और शिक्षा समाचार्य नहीं हैं। प्रारम्भिक शिक्षा की प्रक्रिया बढ़ना काम और जीवन की परिस्थितियों में ही चलती है।

(ग) - ग्रीष्मकाल, पर्व त्योहार, और जीवन। वे तीनों अवसर हैं और इनसे वे प्रत्येक सभी समाज होता है जो यह एक दूसरे से सम्बन्धित रहता है।

(घ) - विद्या की प्रक्रिया में, जिसमें लोग सबेरे होते हैं, साप्ताहिक रूप में काम करने की मूल्यपूर्ण है जितने कि समय।

(ङ) - निरक्षरता तथा निर्धन लोगों के ऊपर उच्चतर साक्षरता, पत्र-पत्र विचार-विचार और शिक्षा द्वारा अपनी स्थिति में सुधार प्राप्त कर सकते हैं।

३. प्रौढ़-शिक्षा में समाज के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वरिष्ठ वर्ग के लोगों का साक्षरता-कौशल प्रदान करने पर बल देना चाहिए। किन्तु ऐसे लोगों में बहुत-सा साक्षरता और उसके अनुसरण - कार्य-क्रमों में निरक्षरता सम्मिलित होने के लिए सत्रों का अभाव रहता है। इस सम्बन्ध में शिक्षाने की प्रेरणा देने पर बल देना चाहिए। साथ ही साक्षरता-कार्य-क्रमों में बोलने की भाषा के प्रयोग और आचार्यन के सामूहिक रूपों पर भी बल देना चाहिए। सर्वोपरि कार्य-क्रम में भाग लेने वालों की दृष्टि-क्षमता पर भी विचार करना है कि वे अपने जीवन को बदल सकते हैं और इस पर कि प्रौढ़-शिक्षा के कार्य-क्रम, उद्देश्यों की प्राप्ति में उनकी कार्य-क्षमता बढ़ाने में सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसा साक्षरता का कार्य-क्रम, जो बोलने वालों की काम करने और जीवन-साधन करने की दृष्टि से असम्भव हो अथवा साक्षरता की बुनियादों और देश की विचार-सम्बन्धी सामाजिकताओं से असम्भव हो, उन्हें सक्रिय प्रतिभागी बनाने में समर्थ नहीं हो सकता और न ऐसा कार्यक्रम शिक्षा तथा उन्नति का साधन बन सकता है। अतः प्रौढ़-शिक्षा जहाँ साक्षरता-कौशल पर बल देती है वहाँ उसे

—शौचने वासी की आवश्यकताओं तथा मातामरण से सम्बन्ध होना चाहिए,

—कार्य की अवधि, समय, स्थान, शिक्षण-प्रवन्ध आदि के सम्बन्ध में मन्त्र होना चाहिए,

—पाठ्यक्रम, शिक्षण तथा शौचने की सामग्री और विधियों के सम्बन्ध में बहुविध होना चाहिए,

—और सगठन के सभी पक्षों में सुव्यवस्थित होना चाहिए,

४ प्रौढ़ शिक्षा में सर्वोच्च प्राथमिकता निरक्षर लोगों को दी जानी चाहिए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् को प्रथम में साक्षरता के क्षेत्र में सफलतापूर्वक किसी प्रकार सतीतजनक नहीं रही है। १९४७ में साक्षरता की दर १४% थी जो १९७१ में ३३.८५% (०-४ के आयु वर्ग की छोड़कर) हो गई। फिर भी साक्षरों के बढ़ने और पुनः प्रयासों की अर्द्धसमरता के कारण निरक्षर लोगों की संख्या १९५१ में २४०० लाख से बढ़कर १९७१ में १०६० लाख हो गई। १९७१ की जनगणना के अनुसार १४ वर्ष से ऊपर निरक्षर लोगों की कुल संख्या २११० लाख है जिसमें ६८२ लाख १५-२५ आयुवर्ग में हैं और यह संख्या इस समय लगभग १००० लाख है। साक्षरों के १४-२५ आयुवर्ग के इस बड़े भाग को शिक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित जाना चाहिए और यह कार्यक्रम ५ वर्ष के भीतर व्यापक रूप से चलाया जाए। इसका अर्थ है कि शिक्षा, अनुसंधान, व्यक्तियों और संग-जातियों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने होंगे। उन क्षेत्रों पर, जहाँ निरक्षरता अधिक है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

५ जहाँ अनुसूचित २ और ३ में उल्लिखित संरचना पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वही एक बात को भी रेखांकित करने की आवश्यकता है कि कार्यक्रम को एक जन-संयोजन के रूप में देखा जाए। सगठनात्मक दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि बड़े क्षेत्रों पर कार्यक्रम चलाने के पूर्व संप्रदायिक संस्थाओं को भी शामिल किया जाए। जिसमें का अर्थ और जहाँ सम्मिलित करना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण

अनुसंधान सामग्री तैयार करना और प्रशिक्षण—ये अतीत में प्रौढ़-शिक्षा-कार्यक्रमों की दुर्घटना के मुख्य क्षेत्र रहे हैं। कार्यक्रम चलाने के पहले इन क्षेत्रों में सतीतजनक तैयारी आवश्यक हो जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह त समझना चाहिए कि प्रौढ़ शिक्षा केवल वैश्विक व्यक्तियों के कामों है। प्रौढ़ शिक्षा विकास के सभी क्षेत्रों में अति-व्यापक स्तर के रूप में समझी जानी चाहिए, विशेष रूप से जहाँ विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति में सामाजिक होने वाले लोगों का भाग लेना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो। प्रौढ़-शिक्षा मानवोत्थान की पूर्वावश्यकता यह भी है कि सभी अधिकारों सरकारों, स्वैच्छिक, निजी, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, औद्योगिक शिक्षा की सहायता आवि इस आयोजन को बल प्रदान करें। स्वैच्छिक अधिकारों की विशेष भूमिका भरा करनी है और उनका पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। शिक्षण-कार्य शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा वैश्विक स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाना चाहिए। यह अच्छा होगा यदि वैश्विक स्त्री या कमरोंचदार वाले नवयुवकों की बिना प्रौढ़-शिक्षा-कार्यक्रमों को संचालित करने की अवकाश है, आवश्यक शिक्षण विषय जाए और सब उन्हें ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करने का उत्तरदायित्व दिया जाए। समस्याओं के प्रभावों और व्यक्तित्व विशेषण के लिए कार्यक्रमों में निर्देशन, मूल्यांकन तथा प्रयोगात्मक क्षेत्र के लिए अनाविहित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे अनुसंधान कार्यक्रमों को, जैसे पठन-समय का प्रकाशन एवं वितरण, संचालित ज्ञानार्जन और सामुदायिक शिक्षा, विशेष महत्व देना चाहिए।

६. इसने बड़े कार्यक्रम के सगठन के लिए पर्याप्त आर्थिक और प्रशासनिक समर्थन की आवश्यकता होगी। इस कार्यक्रम के लिए जिसमें साक्षरता और मातामरण-सम्बन्धी तथा सामाजिक शिक्षा सम्मिलित होगी और जो लगभग ३००-३५० घंटे या लगभग ३ सप्ताह के लिए, आर्थिक प्राविधान करना होगा और अन्य व्ययों की भी ध्यान में रखा होगा। आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सरकार, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक अधिकारों, व्यवस्था

तथा संशोधन आदि को करनी होगी। इस बात का एक प्रमाण अनुमान लगाया होता है कि उस प्रोफेसरनस और प्रदासकीय दान का बिस्तार और समता क्या होगी जो इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक होये और उस इस दान को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

निरंतर प्रोत्साहन के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम समर्थित करने के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि विशेष वर्गों के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

—पुरुषों में जाग कराने वालों के लिए जिससे वे अपने कौशल को लगातार सक्रिय और प्रभावशाली में अपने उचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए अपने को सतत बना रहें तथा प्रभावशाली में भाग ले सकें,

राजकीय कर्मचारियों के लिए जैसे न्यायपालिका के अधिक, क्षेत्र के सेवा-विस्तार कार्यक्रमों तथा नीति एवं कानून के कर्मचारी, जिससे वे अपनी योग्यता बढ़ा सकें;

—व्यावसायिक उद्योगों के कर्मचारियों के लिए जैसे बैंक

तथा बीमा कम्पनियों के कर्मचारी, जिससे वे अपने काम में और दक्ष हो सकें;

बुद्धिजीवी-वर्ग के लिए जिससे वे पारिवारिक जीवन की समस्याओं तथा समाज में स्थिति के स्थान को अच्छी तरह समझ सकें।

इन लोगों के लिए और इसी प्रकार के अन्य वर्गों के लिए कक्षा-प्रशिक्षण के द्वारा, पत्राचार कौशल प्रदान सामूहिक साधनों द्वारा अथवा इन सभी को मिलाकर कार्यक्रमों को चलाया जा सकता है।

यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि प्री-प्रशिक्षण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन विकेंद्रित हो। यह भी आवश्यक होता है कि समय-समय पर उद्योग के लिए अधिकारियों की स्थापना की जाए।

केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी-विकास की स्थापना इसी उद्देश्य से की है। इसी प्रकार की परिषदों की स्थापना राज्य - स्तर पर भी होनी चाहिए। विभिन्न अधिकारियों के कार्यों के समन्वय तथा उनका सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता-दिवस

जॉन ई० फोन्स

उपमहानिदेशक, यूनेस्को

यह बड़े मानस का विषय है कि यूनेस्को में हम लोग अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में परम्परा के अनुसार पर्व मनाते हैं और उन नर - नारियों की सज्जुगता से अपने की तुल्यता करते हैं जो साक्षरता के विश्व सम्मेलन में लगे हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत मना रहा है, उस निर्णय का परिणाम है जो निरक्षरता समाप्त करने हेतु पठित विज्ञान-मनियों के उस विषय-सम्मेलन में लिया गया था जो १९६५ में तेहरान में हुआ था। यह दिवस इस बात का अवसर प्रदान करता है कि हम अब तक के किये गए कार्यों को समर्थ, प्रविष्ट की ओर और अपने सपने की ओर मजबूत बनाएँ।

अपर हमें अब तक की माना के फाटने की नापना हो, तो है निष्पक्ष रूप से यह कहेंगे कि यह परिणाम असतोषजनक है। यह स्पष्ट है कि काम बहुत बड़ा है और अब भी बहुत कुछ करना है, फिर भी हम मानते हैं कि निरक्षरता की दूर की जाय और यह कि सहायक की उपलब्ध किये जा सकते हैं।

वास्तव में मानस बहुत है कि प्रवृत्ति के निरक्षरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। आज उन की संख्या अनुमानतः ८० करोड़ होगी। प्रत्येक ३ प्रौढ़ों में से एक न तो पढ़ सकता है, न लिख सकता है और न निश्चित रूप से श्रम हितार्थ लगा सकता है। निरक्षर विधियों की संख्या, जो निरक्षर आबादी का ७०% होगी, निरक्षर दुर्गों की संख्या से अधिक होती है बढ़ रही है। यह प्रमाणा नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रहित है। विकासशील देशों में निरक्षरता अत्यधिक व्याप्त है। बहुत से देशों में ८० प्रतिशत निरक्षर हैं। यह

मासपूर्व की बात नहीं है कि निरक्षरता के लोग वही हैं जहाँ विद्यु - मूल्य, कुपोषण, बेरोजगारी और गरीबी हैं। दूसरे शब्दों की दृष्टि बहुत ऊँची है। उद्योग प्रधान देश भी निश्चय ही इसके बचे नहीं हैं। इन देशों में निरक्षरता, स्थान परिवर्तनशील काम करने वालों तथा उनके परिवारों अथवा स्थानीय आबादी के कुछ टुकड़ों की जो यद्यपि बाहरी तौर से साक्षर हैं किन्तु अपनी दैनिकीय समस्याओं से सहायता के लिए न तो पढ़ने का प्रयोग करते हैं और न लिखने का, प्रभावित करती है।

इससे भी गम्भीर बात यह है कि अनेक समाजों के निरक्षरों की एक बहुत बड़ी संख्या आबादी के युवा-वर्ग की है। जब इस वर्ग की अपेक्षा करना असम्भव है कि बहुत से देशों में बाबजूब बड़े शिक्षा प्रसार के बड़े प्रयास के परिणामस्वरूप के छकेत पुष्ट मान की लिये पाएँ, समा-कथित तीसरी दुनिया के देशों में १-१९ लाख वर्ष के स्कूल न जाने जाते बच्चों की संख्या १९८२ में १३ करोड़ ४० लाख हो जाएगी जिसमें ३ करोड़ ५० लाख बालिका हैं, १ करोड़ ५० लाख में, और १० लाख लैटिन अमेरिका में होने। यह भी मानना होगा कि आधुनिक शिक्षा के अब तक बहुत कम बच्चे स्कूल में एक पाते हैं और बहुत बड़ी संख्या ऐसे अज्ञान के साव (नूल छोड़ देती है जो जीवन की दैनिक वास्तविकताओं में उत्तमकर समाप्त हो जाता है। विकासशील देशों में केवल बात इतनी नहीं है कि बढ़ती हुई आबादी की संख्या एक लम्बे समय तक अज्ञान-संख्या से भागे बढ़ती रहेगी, बात यह भी है कि शिक्षा के बन्दों में विस्तार के विषय दैनिक संपत्ति के बढ़ते हुए व्यय का घटन मर्यादित बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार उच्चपरीय और बहुपरीय श्रमिकों का आवेदन घटता जा रहा है।

निर, बुनियादी एवं निरंतर सभी बासी विद्या एक
ऐसा बुनियादी मातृ अविचार है जिस पर और अवि-
चार निवार करते हैं। ऐसी बुनिया, जिस पर इस अविचार
को उपेक्षा की जाती है और इस प्रकार यहाँ व्यक्तिता
और उनके सम्बन्ध समाजों का विकास अव्यक्त होता है,
एक निराशा, नाशयुगी और समाज की दुनिया ही हो
सकती है।

इस परिस्थिति को तो हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी
चाहिए कि निराशा का निवारण में कुछ प्रयत्न, यह
विश्वी भी कम नहीं हो हुई है। एक बड़े पैमाने पर
साक्षरता का प्रसार सम्भव है। हम लोगों को एक कम
सा यह है कि इसमें तो बहुत ही कम निश्चय नहीं
करते और न इसके अनुसार कार्य ही करते हैं।

किन्तु हम लोगों का चाह हम इस बात से बचना चाहिए
कि बहुत ही सरकारी और राष्ट्रीय संगठन निराशा
के विरुद्ध लक्ष्य में लगे हैं। नव दायें, राष्ट्रीय तथा
स्थानीय कार्य समितियाँ, निरंतर विचारों पर लगे हैं।
सोच, लगे प्रयोग तथा सुधार-योग्यता आन्दोलन विद्या
के लक्ष्य में और विद्या के समस्त पुनरुत्थान के लक्ष्य में,
इस बात की सुनिश्चित करने का प्रयास है कि औद्योगिक
विद्या-अध्यापक मनीषाचारित्र आगमन से अधिक प्रभावी
रूप में सम्भव हो जाए।

मह. यूनेस्को तथा अ. विज्ञान अविचारों को
राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सहायता करने और उनमें लगे
विचार लक्ष्य का प्रयत्न महत्तर है। मैं यहाँ पर एक ० ए०
बी०, आई० ए० बी०, इन्फो० ए० बी०, यू० ए०
बी० पी०, युनिसेफ तथा द्वितीय लक्ष्यों के प्रति अपना
सम्मान स्थापित करना चाहता हूँ।

एलिसेरियोस पर मिट्टी की प्रोद्योगिकी जिसे यूनेस्को
की सहायता मिली थी और जो १९६६ और १९७४ के
बीच १६ सत्र पर राष्ट्रीय में सम्पादित गया था, अंतर्राष्ट्रीय
सहयोग का एक प्रयत्न ही उत्साहक है।

यद्यपि कार्यक्रम में लगे नहीं अधिक साधकों
पर काम चलाकर दस विद्यार्थी प्रारम्भ से सोचा गया
था, और बावजूद इस अवधि में तथ्य के कि कुछ बगल

में सम्पादन परिलक्ष्य दृष्टिगत लक्ष्य के अनुसार नहीं
निचले, तद्विषय प्रयत्न लक्ष्य और अनुभव अवश्य प्राप्त हुए।

उत्तरे जो विद्या प्राप्त हुई वह उन लोगों के लिए
प्रेरणा का स्रोत है जो साक्षरता विद्या कार्य में लगे हैं।
यह प्रोद्योगिकी के विद्यालय में जो अनुभव मिले उनके आधार
पर नये आन्दोलन सामय लगे हैं जिनमें सम्पादन
तथा पुनरुत्थान दृष्टि से सम्पादित परिणाम मिलते हैं।

१४ प्रकार विद्ये कुछ लोगों से, बहुत से लोगों से
अपनी विद्या - व्यवस्था अविचार दस प्रकार तथा प्रोद्योगिकी
साक्षरता - विद्या के प्रयास में दृष्टि करने, निराशों के
प्रतिफल में बारीकी नहीं करने में समझता प्राप्त की है।
मैं इस लक्ष्य में अलबीनिया, भारत, ईरान, माली,
म्यान्मार, यमन, जम्वीका, क्यूबा तथा सोमालिया को
रखता हूँ।

इसलिए यह स्वाभाविक है कि यह लक्ष्य नेरीबी की
भारत कार्य में निराशता के विरुद्ध लक्ष्य ही करने
पर विशेष लक्ष्य और एक प्रयास प्राप्त किया जिसमें
सदस्य - राज्यों के लक्ष्य गया कि 'ये अपने साक्षरता के
कार्यक्रमों का अधिक लक्ष्य के लक्ष्य अनुसरण करें और
आन्तरिक जनरल से आग्रह दिया गया कि यूनेस्को के
बासी कार्यक्रम से 'निराशता के विरुद्ध अभियान में
बासी लक्ष्य का बासी।' अविचार में लक्ष्य दो वर्षों
(biennium) की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। यह लक्ष्य
राज्यों द्वारा लक्ष्य लक्ष्य लगे साक्षरता के कार्यक्रमों की
उत्प्रेरित एवं सुदृढ़ करने के लिए लक्ष्य कार्य कर रहा
है। लक्ष्य लक्ष्य अपनी लक्ष्य की योजनाओं का सम्बन्ध
है मैं यह कह सकता हूँ कि हम लक्ष्य लक्ष्य कार्यक्रमों के
बाद में लक्ष्य लक्ष्य जो लक्ष्य लक्ष्य राज्यों के लिए हैं
जिनकी साक्षरता की आवश्यकताएँ विशेष रूप से लक्ष्य
लक्ष्य हैं और जहाँ साक्षरता - अभियान एक राष्ट्रीय
राजनीतिक लक्ष्य की परिस्थिति है।

हमें लक्ष्य है कि हमारे सहायता लक्ष्य कार्य राष्ट्रीय
तथा स्थानीय स्तर से विभिन्न लक्ष्य लक्ष्यों द्वारा अविचार।
लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। हम लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य हैं कि हम
साक्षरता तथा साक्षरता के लक्ष्य के लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य

काम करने वाली राष्ट्रीय सत्त्वामों का पास बिना है जिससे सूचनाओं तथा अनुभवों के आदान-प्रदान में सुविधा हो और एक क्षेत्र के विभिन्न देशों के बीच बिनके विकास-स्तर तुलनीय है या समरस एक प्रकार की है, पारस्परिक सहायता के कार्य-कलापों की उन्नति में भी सुविधा हो। शिक्षण तथा प्रशिक्षण-कार्यों के लिए मस्ती-मोहिया सामग्री की और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की बात भी सोचो आ रही है। हमने ही शासक-शासक सम्बन्धी सहायक सामग्री के विषय-परि-शिष्टियों में सत्यापन की, जब समरसों से अथवा हैं जो अर्थात् सत्त्वामों में शैक्षिक सुविधाओं के अभाव के कारण और भी कठिन हो जाती है।

साक्षरता-कार्यक्रम का दूरगामी प्रभाव वस्तुतः सभी ही वर्गों में जब विद्य के सभी राष्ट्र अपनी भावकला एवं साधनों के अनुस्यू स्वरूप में सम्मिलित हों। इसी बात को ध्यान में रखकर जनरल काफ़ेड ने सभी प्रस्ताव में बाइसेक्टर जनरलको यह निर्देश दिया था कि वे साक्षरता-कार्यक्रम के समाने और एक अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता कोष स्थापित करने की सम्भावना का अध्ययन करें। 'अध्ययन' का अर्थ है—एक नये मान्योत्पन्न के लिए जनमत के वातावरण का परीक्षण करना। इस भोज देश कर रहे हैं और इस सम्मेलन में जनरल काफ़ेड के द्वारा सम्मिलित में विषयों प्रस्तुत करेंगे। क्या ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय चौड़ाई विद्यमान है जिससे उन्नतपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता के व्यापक वृद्धि की जा सकती है? क्या इस चौड़ाई का प्रथम प्राथक समारम्भ बुनियादी भाषाओं और व्यक्तिगत के आधार पर और साथ ही निम्न राष्ट्रों की पहली सामाजिक भावना और सदस्यों के पारस्परिक हितों पर आधारित है?

मैंने पहले कहा था कि १२ वर्गों के अनुभव से हमें कुछ शिक्षा है और ऐसे विद्वानों भी और सकते क्या है निम्नलिखित - कार्यक्रम के सचिवों में एक नये भारतीय प्रयास की प्रेरणा मिलनी चाहिए।

संश्लेषण यह बात सुष्ट हो गयी है कि सर्वाधिक विदेशीय शोषणार्थ, महारानीय सवर्णों के सर्वाधिक विदेशीय प्रत्याय तथा प्रत्येककारी सवर्णों का सर्वाधिक

साधनायुक्त सहयोग अतोगत्या अर्थ है जब तक आरम्भ से ही राष्ट्रीय राजनीतिक संकल्प स्पष्टतः अभिव्यक्त न हो। और यह संकल्प श्रेष्ठिक समाज की अपनी कार्यनीति से परिसंस्थित होना चाहिए। यह संकल्प पूरे सभी आवश्यक मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक साधनों की शक्ति करेगा और लोगों की गहराई से इस बात की अभिप्राय कराने सहायक होगा कि साक्षरता-शिक्षण समाज की बदलने में एक अग्रगण्य साधन बन सकता है।

दूतों ने यह पुरे दौर से स्पष्ट हो गया है कि साक्षरता-कार्यक्रमों में सम्पूर्ण मानव को विकास के केन्द्र में रखना चाहिए। साक्षरता के कार्यक्रम को फँसदरी के एक भयदूर को, कृषि क्षेत्र के एक खेतिहर को केवल प्रभावित बढाये एवं शैक्षिक लाभों को समझ करों और व्यक्ति विकास के चर्चे से पढ़ना निखाना और गिनती सिलाले हैं, स्वामी नहीं होते और यन्त्रों साक्षरता समझाए प्रस्तुत करेंगे।

साक्षरता कायें स्वभावतः कार्यपरक तथा बहुविध होना चाहिए। कार्यपरक वह ऐसा हो जिससे समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सांस्कृतिक पक्ष एक पूर्णता का ध्रुव में बंध सकें। इसमें सम्पूर्ण मानव केन्द्रित होना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य उसके वातावरण को यथार्थ वास्तविकता के आधार पर उसे अपनी वैदिक व्यवस्थाओं के हत करने में सहायता देना है। हम लोगों के विचार में कार्यपरक साक्षरता की मौलिकता अनुष्ठान की पट्टी से पट्टी प्रणालियों और परिण की आवश्यकताओं को अनुष्ठान करने में सहायता पहुँचाने के दृष्टी प्रकाश में है। सम्बन्धित समाजों के जीवन तथा साक्षरता में सम्बन्ध, कार्यधर्मों के अन्तर्गत में, अर्थव्यवस्थाओं के अन्तर्गत में तथा उन व्यक्तियों के जो शिक्षण से रहते हैं और जो रहते हैं, परस्पर सम्बन्धों के समग्र में, परित्याग होना चाहिए।

एक लीखरा बिदु मावी साभरता कायंरुम के लिए
बाल्य महत्वपूर्ण है और यह है बनता ॥ मागीशर
बनता ।

निष्पत्ति के लिये जोरदार आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। तभी से हम लोगों ने यह प्रयत्न

किया कि साक्षरता-अभियान की सफलता निश्चयनैह १५
 बात पर निर्भर करती है कि किस सीमा तक समाज
 इसके मागीदार बनता है। यह सहभाग सूचना के उभय-
 पक्षीय प्रवाह पर बल देता है जिससे निरंतर व्यक्ति अपने
 अनुभवों और विचारों को अभिव्यक्त करते हुए, विचार-
 शक्ति तथा सार्वजनिक मस्तिष्क को विकसित करते हुए
 तथा अपने सांस्कृतिक अस्तित्व पर खर देते हुए, प्रारम्भ
 से ही अपने शिक्षण की जिम्मेदारी महसूस करने लगता
 है। इस सम्बन्ध में यूनेस्को की इस बात की प्रशंसा है
 कि साक्षरता कार्यक्रमों में राष्ट्रीय प्राथमिक एवं सस्कृतियों
 के प्रयोग में इतर समिवृद्धि हुई है।

साक्षरता कार्यक्रमों में जनता के सहभाग का अर्थ
 स्पष्ट है। और इसके निकलने वाला यह कर्म महत्व का
 दिखने मही है कि स्थानीय स्तर पर निम्न विकेंद्रित
 हो। उक्त वैयक्त भावना का प्रतिकार करने के लिए जो
 पहले के अविकसित साक्षरता-कार्यक्रमों की विशेषता हुआ
 करती थी, समुक्त राष्ट्रीय स्तर पर, एक्सेपेरिमेंटल कन्वेंटि-
 रणों प्रोत्साहन की समिति के साथ इस बात का अनुवातन
 की कोशिश की है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग राष्ट्रीय
 एवं स्थानीय सक्रियता एवं जिम्मेदारी को कभी हतोत्साह
 नहीं करता।

चौथा पाठ जो सोचा गया वह ठेहरान में आयोजित
 विशालमन्त्रियों के सम्मेलन की, जिसकी हम बारहवीं बार
 बात मता रहे हैं रिपोर्ट में विश्लेषण है। यह यह है कि
 साक्षरता का कार्यक्रम सब से अलग मही किया जा
 सकता। इसे आजीवन शिक्षा की प्रक्रिया और विकास की
 योजनाओं में छोड़ना और समन्वित करना पड़ेगा।

यह साक्षरता का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से विनाश
 कार्यक्रमों तथा सामाजिक, साहित्य और सांस्कृतिक गुणों
 से जुड़ जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्थिति
 के मुताबिक एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन कर सकता है।
 ऐसा समभव आत्मनिर्भर के एक नये दृष्टिकोण की प्रेरण
 करता है, ऐसा दृष्टिकोण जो समन्वित होने वाले लोगों
 को उच्च तकनीकों पर निरभर के प्रयोग करता चाहते हैं,
 एक प्रभावशाली विपणन दे सके। इस का अर्थ यह भी है

कि संबंधित विभिन्न बुनियादी तकनीकी सेवाओं में पर-
 स्पर परामर्श करने और स्थायी रूप से मिलजुल कर कार्य
 करने की प्रवृत्ति बनाई जाय जिससे औपचारिक तथा
 अनीपचारिक शिक्षा-अवस्थाओं में निरंतरता और सम्यता
 बनी रहे।

इन चार बुनियादी विन्दुओं में में बहुत से बातें
 अनुभव और चोटला बाहों, किन्तु समवायुताएँ कुछ
 बिन्दु ही प्रस्तुत करेगा। मैं सोचता हूँ कि साक्षरता-
 कार्यक्रम साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत या
 सुव्यवस्थित रूप में रहे जाएँ। पियेटर, बस-पुस्तकालय,
 लोक-समीक्षा, समाचार-पत्र तथा स्थानीय प्राथमिकों में
 पाठ्य सामग्री जिसमें विषय-वस्तु परामर्शों की प्राप्ति-
 स्थितियों और कर्मियों के अनुकूल हो-ये साक्षरता-
 कार्यक्रम के अनुसरण की विधियाँ हैं जिससे परामर्शों
 को नये मजबूत शान का प्रयोग करने, अधिकार प्राप्त करने
 और बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

हम लोग यास मोरिया के योगदान के बारे में भी
 सोच रहे हैं, विशेष रूप से यह बहुत से मोरिया का एक
 साथ प्रयोग किया जाता है। उम्मत तकनीकी पर आधा-
 रित नये संश्लेषण सामग्री से बहुत से अवसर सामने आ
 रहे हैं और कहे-कहे लक्ष्य में कार्य हो रहा है।

जैसे मैंने प्रारम्भ में कहा था, हम जानते हैं कि हमें
 क्या करना चाहिए और उससे भी अधिक हम यह जानते
 हैं कि जो आवश्यक है उसे कैसे करना है।

तो फिर प्रयास करने अवर्थात क्यों है और परिणाम
 इसके निराशाजनक क्यों हैं? मैं सोचता हूँ ऐसा इस
 लिए है क्योंकि, जैसा चिन्तन करण के साथ है—अधि-
 कार्य लोग यह माना नहीं करते कि कोई अव्यवस्थित प्रवृत्ति
 की जा सकती है। भाषा और विज्ञान को कभी है।

इसके अतिरिक्त एक बड़ा सवाल है कि इस समय उप-
 रिक्त लोगों को खोजकर, यह अनुभव नहीं करते कि
 साक्षरता का प्रयास वास्तव में उन्हें मरती सुविधापूर्व
 स्थिति में सुरक्षित रखने के लिए वास्तव में आवश्यक है।
 यह भी सचता है कि कुछ मेला यह भी सोचते हैं कि
 आवश्यक साक्षरता सार्वजनिक हो सकती है। या बहुत

की समझाए उत्पन्न कर सकती है।

जब इन परिस्थितियों में, चिनबारी वहाँ से कुछ हेली और रोशनो की वजहसे वहाँ से बहामद्दुल्लाह नामक प्रमुख साहसिक उद्धारण की गयी प्रेरणा वहाँ से मिलेगी ?

चीन में भीतर ही हम सोच तुल्य विकास दमक प्रारम्भ करे और जैसा बुनको के दार्जेदर उदाल की सम्राट् महार एम' बो वे (Amardou Mahtar M' Bow) इकनामिक और सोशल कार्डिनल के 63वें अधिवेशन में कहा था, द्वितीय वनस्टेट नेसनल डिवेन के दौरान प्राप्त हुए अनुसंधान के आधार पर, हमें तुरन्त वह कार्यवाही परिभाषित करनी होगी जो अन्तर्राष्ट्रीय समाज की नयी आवाजाओ की पूरा ध्यान में रहेगी।

क्या हम ऐसे मत नरन के आधार पर भी आशा कर सकते हैं—ऐसी नैतिक अनुमति की, एक ऊर्ध्वमुख सोहार्द मानना की जो बहुपक्षीय व्यवस्था को और बल प्रदान कर सकती है (बनोकि उन्मेषणीय सहजता की संज्ञा वह अधिक अच्छी है), जो हमारे विकास दमक में साक्षरता बड़े रूप में मिल सके ? कदाचित् ऐसा ही। इन बातों के कि भी हम को और उनके समान अन्य गैर वर प्रदात करेंगे जिससे ऐसा हो। मेरा सुझाव है कि एक और साक्षरता की समुच्च की बुनियादी भाव शक्तियों की पूर्ति करने वाले कर्मजान केन्द्र बिन्दु के बोधना चाहिए और दूसरी ओर अनुच्च के बुनियादी परिवारों की बढ़ती हुई क्षमता से।

इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि दो बातें निश्चय अधिष्ठ में निरक्षरता को कम करने में एक वास्तविक गन्ना मोड़ दे सकती हैं। दोनों ही समाज की बलों से एक प्रभावी मान के उद्भव की ओर संकेत करती हैं—ये बल हैं परिवार तथा स्थानीय समाज।

पहली बात का उद्भव रोजगार की आवश्यकता से होता है। समझना सभी देशों में जैसी जैसी अवरोधन वर-पुर्णों की समस्या बढ़ती है और जैसी-जैसी बहुत ही कार्पिक व्यवस्थाओं की परम्परागत भावों में रोजगार देने की

क्षमता कम होती है, वैसे वैसे ऐसी स्थिति में लोग मामले को अपने हाथों में ले लेंगे। स्थानीय समाज अपने सदस्यों के लिए सामग्र्य कार्य बलाघ आयोजित करेंगे। स्थानीय सक्रियता और प्रवास बढ़ेंगे और आत्मनिर्भरता के लिए समझ से साक्षरता की मान स्थान उत्पन्न होगी और उच्च की पूर्ति के साधन भी निश्चित होंगे।

दूसरी बात सम्भवतः अधिक सक्रियता होगी—सभी राष्ट्रियों से अधिक गति देने वाली। यह ऐसे लोगों से आएगी जो सभी प्रकार से वंचित हैं, केवल साक्षरता से ही नहीं। मैं भिन्नो की बात करता हूँ। आवाज ऊपर उठेगी 'हम सोच विकास में जान लेना चाहते हैं और हममें योगदान करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए वह जीवन मरण का प्रश्न है। और पुनः, विश्व के दुखों, धारणीय स्तर पर समाज को भागे बढ़ाने और उनके विकास के लिए जोर से काम नहीं कर रहे हो। हम विश्व की गरिमा साक्षरता के साधन की मान करती हैं जिससे हम अपनी पूरी भूमिका बजा कर सकें।'

मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि निरक्षरता के विपक्ष अधिवान उन भाषेया अब स्थिया इसकी मान करेंगी।

दूसरों को इन सभी बातों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और जहाँ गी रोशनी दिखाई दे उसका उपयोग करना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोगों की अपने कार्य का सुवर्णक करने का और सन्धि पर विश्वास करने का अवसर देता है। इसमें हम अपनी उपलब्धियों को मनाते हैं और प्रवासों को पुरस्कृत करते हैं तथा नयी सक्रियता को प्रोत्साहन देते हैं।

सदस्य राज्यों की ओर से ॥ दोहम्मदरजा बहुत ही नारेन्दर कल्पकाया पुरस्कारों के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पुरस्कारों के लिए अधिवस्था ईरान के शाह-दाह और यूएन एल एम एर की सरकारों के कारण सम्भव हो सके हैं। हम यहाँ एक बार पुनः इन सरकारों के प्रति, समस्त राष्ट्र सच को उद्देश्य मुक्त समर्थन देने के

लिए तथा मानवीय सौहार्द के इस सुन्दर उदाहरण के लिए, हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

समुक्त राष्ट्र संघ तथा ट्राइटेक्टर जनरल की ओर से हर इम्पोर्टन्ट हार्दिक प्रिण्डेबल बक्षरफ पहलवी और एम्बर नेशनल पुरी के सदस्यों को, जिन्होंने बावजूद अपने धन्य कार्यों की व्यस्तता में नमस्कार की समोसा करने और पुरस्कार-विजेताओं और सम्मान प्राप्त करने वालों का चयन करने में सर्वश्रेष्ठ अपने कोशिश और निष्ठा का परिचय दिया है, धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं ऐसे अनेक प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ जिनकी उपस्थिति इस वक्त में एक नवीनता है। जब से साक्षरता-पुस्तकालय की स्थापना हुई है, पहली बार छपारोह में ऐसे लोग उपस्थित हैं जिनकी कुछ मात्र पूर्व ऐसे साक्षर स्वी-पुष्टो में गणना की जाती थी जिन्हें कुछ भी अक्षर-ज्ञान नहीं था। मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि पूरा अन्तर्-द्वीप समार उनके प्रयास में आनन्द हीन छवि रहता है। मुझे माया है कि उनकी इस छपारोह में उपस्थिति से उन्हें नविनता में भी पढ़ने-लिखने की कला पर अधिकार प्राप्त करने में परिश्रम करते रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

अपने उदाहरणों पर परिलानों के लिए जो उन्होंने प्राप्त किए हैं, पुरस्कार - विजेताओं को मैरी हार्दिक बधाई है। शिक्षकों और सीने वाले की दृष्टि तथा कुशल-स्वता

जो उन्होंने दिखाई है और जो त्याग उन्होंने किया है, व्यर्थ नहीं गए। वे लोग एक ऐसे दुनिया के अग्रदूत हैं जिसने अभी बलान की भ्रंशनाई नहीं ली है और जो ज्ञान की प्यासी हैं जिससे वह अपनी अभिव्यक्ति कर सके और विकसित हो सके। अपने प्रयासों में सगे रहने के लिए हम लोगों को, जो यूनेस्को में है, इनसे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। इससे हमें यह माया होती है कि करोड़ों स्वी-पुष्ट अथ इतिहास के कोने में नहीं पड़े रहेंगे।

यह मेरे यूनेस्को की ओर से विश्व के सभी राष्ट्रों के मत-करण से बचील करता चाहूँगा। हर एक को अपने उद्देश्यों और कार्य देखी की परिभाषित करना है और मानवीय, आर्थिक तथा बौद्धिक सवाधनों को, जिनकी साक्षरता-कार्यक्रमों में इतनी कमी है, जुटाना है। उन्हें वह राजनीतिक इच्छा प्रदर्शित करनी है जो 'इरादों' की घोषणाओं की व्यावहारिक कार्य - बलाप में बदलती है। साक्षरता - कार्यक्रमों के लिए निर्धारित बजट के साथ सामंजसिक व्यवस्था के सदस्य से परीय रिश्तेदारों-भाध्य-बहार में किया जाय। जो राष्ट्र इस प्रकार का ज्ञान उठाएँ, उसके नागरिकों की प्रतिक्रिया प्रेरणा-प्रद होगी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उस राष्ट्र का स्थान बहुत ऊँचा हो जाएगा।

प्रौढ़-शिक्षक की तलाश है

(बाबूराम अग्रवाल, सहायक शिक्षा निदेशक, वीरपुर हाउस, मदनग)

प्रौढ़ शिक्षक की तलाश है। प्रौढ़ों को पढ़ाना है। प्रौढ़ों की उम्र १५ से १५ के बीच में है। इनमें कुछ भी है। यहिनाए' भी है। अधिकांश गाँव में रहते हैं। कुछ शहर में रहते हैं।

ये प्रौढ़ वे लोग हैं कि जब इनकी पढ़ने की उम्र थी, तब इन्होंने नहीं पढ़ा। गाँव में प्राइमरी स्कूल था। तीन-तीन, चार-चार मास्टर थे। पढ़ने के लिए समय था। तब इन्होंने नहीं पढ़ा और न इनके मा बाप (स्वयं निराक्षर) ने इनके पढ़ने पर कोई ध्यान दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके परिवार में सीढ़ियों से निराक्षरता फैली जा रही है, घर में कभी कोई विताप नहीं आती।

ये निराक्षर प्रौढ़ बचपन में खेलते रहे या बरीबी के कारण घर भयबा खेन पर माँ-बाप के साथ काम करते रहे। छोटे भाई-बहिन की सेवाते रहे। जानवर चराते रहे। बैत घर रोटी पहुँचाते रहे। घास छीतते रहे। बीबी बनाते रहे। शहर में बूकान भयबा घरों में भोहरी करते रहे। माहि।

कुछ लोग स्कूल गये, तो इनकी गुरीबी के कारण मास्टर ने तब पर ध्यान नहीं दिया। ये कक्षा १ या २ से आगे न चल सके। इन्हें स्कूल का भीरस वातावरण पसंद नहीं आया। स्कूल के सक्त अनुशासन में तो इनका बस घुटता था। ये मास्टर की डाँट और मार के डर से स्कूल से भागते रहे और बाहर गुरीबी दण्ड खेमत रहे या बाप में बचकर चुराते रहे। कुछ की भी स्कूली अनुभव इतने दुख रहे कि इन्हें पढ़ने ही के बिना हो गई।

यह है इनके बचपन का इतिहास। अब ये जगनी में रोनी रोटी कमाने में जुटे हैं। पेट भरना धुनिक पड़ रहा है। घर दन्ने पढ़ने की फुरतक नहीं है। ये निराक्षरता के भारी हो गये हैं। इन्हे साक्षरता का मोचित और अनगद समझ में नहीं आता है। ये अब यह भी सोचने

लगे हैं कि इनके पढ़ने की उम्र निकल गई है। खुदे सीते भी नहीं पढ़ते हैं।

ये प्रौढ़ व्यवसाय, बालि, धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बंटे हैं जिनमें आरसी प्रतिद्विष्टता, डेय, मन्दा और समाय समता रहता है। घर एक बात इन सब में एक सी है। यह यह कि ये सरोख और निरदार हैं और इसलिए इनकी सामाजिक स्थिति बहुत नीची है। ये उपेक्षित और साक्षित हैं, दलित और पीडित हैं। न तो किसी बात में कमी इनकी राय मांगी जाती है और न किसी निर्णय में इनकी सामाजिक क्रिया जाता है। इनमें कुचि, छेतिहर मन्दा, छोटे किसान और छोटे-छोटे बन्ने में लगे लोग हैं। ये जीवन पर हर बात के लिए दुखरे पर निर्भर रहते हैं। निराक्षरता और बरीबी के कारण पन-पन पर इनके काम पकते हैं और जबह जबह वे ठगे जाते हैं। ये मारम-निर्भरता की पुके हैं। इनमें आरय विराज नहीं रह गया है। ये अपनी दुबंजा को अपनी निवलि साधकर चूपचाप स्वीकार कर चुके हैं। औरों की हानय और भी बचतर है।

प्रौढ़-शिक्षक की तलाश है की तब दोन-हीन प्रौढ़ों को इस प्रकार पढ़ावे कि इनकी सामाजिक और सामाजिक स्थिति सुधर सके। इन प्रौढ़ों में इनकी स्थिति, इनके सक्तों, इनके अधिकारों, इनकी समस्याओं और इनकी सम्भावनाओं के प्रति चेतना दस्तल करनी होती। इनमें आरम-विषयाय और स्वाभियान बगाना होगा। इन्हें व्यावहारिक ज्ञान विद्या जारेगा जिससे इनकी व्यावहारिक दस्तता बढ़े और ये अपने दैनिक कार्य सुपलतापूर्वक सम्पादित कर सकें। इन्हें छवि एवं जसोय की उन्नत विधियों, कानूनी अधिकारों, न्यूनतम वेतनों, श्रम-सुविधाओं, विकास कार्यक्रमों, स्वास्थ्य एवं विस्तार-केमों आदि की जानकारी कराई जायेगी। इन्हें साक्षर बनाकर

इहें पढ़ने की आवश्यकता नहीं आयेगी। इनमें पढ़ने का शौक पैदा करना होगा। ज्ञान और जानकारी जीवन में हर काम के लिए जरूरी होती है। साक्षरता ज्ञान का एक प्रमुख और स्थायी साधन है। गरीबों की प्रगति और सफलता ही यह सुनिश्चित कर सकेगी कि वो विभिन्न नीतियों, कानून और योजनाएँ उनके काम के लिए अनाई या रही हैं, उनका साथ इन्हें मिले। इसके लिए इन्हें साक्षर और शिक्षित बनाना जरूरी है।

श्रीष्ठ शिक्षक की तलाश है जो उक्त प्रकार से सर्वोपयोगी लोगों को प्रबुद्ध एवं सक्षम बना सके और जो उन्हीं की मदद से समाज में रहता हो वहाँ के लोगों के बीच उसे काम करना है। वहाँ (गाँव/मूल्यों में) सबका अपनी कुछ दियत हो, अपना कुछ भुगत हो। कुछ लोग सबको बात मानते हैं। सबने गाँव में जनसेवा के कुछ काम किये हैं। गाँव गाँव, मूल्यों में मुहूर्त प्रौढ शिक्षा केंद्र खुलेंगे। एक केंद्र पर १० प्रौढ पढ़ेंगे और एक शिक्षक पढ़ायेगा। रोज दो घण्टे पढ़ाई होगी। कठोर ज्ञान समय और स्थान पढ़ने वाली की सुविधा पर होगा। एक केंद्र १० पढ़ाने वाले। महिलाओं के केंद्र अधिक सुलभ हों। महिला शिक्षक अधिक चाहिए।

श्रीष्ठ शिक्षक की तलाश है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएँ हो।—

—वह ऐसे व्यक्ति पर के लोग के नहीं, बल्कि जनसेवा की भावना से इस कार्यक्रम में भाग चाहता हो और इस कार्यक्रम की सफलताओं को सम्पन्न हो। उसे बेतन नहीं, बल्कि सम्मान २०-२५ मासिक मानदेय मिलेगा।

—वह सच्चा और ईमानदार हो। झूठ का सहारा न ले। उसे छोटी बेइश्वरी और बेइश्वरी को पढ़ना पड़ेगा।

—उसके दिव्य, सदन, व्यवसाय और व्यवस्था की भावना हो।

—उसे समझना और सामाजिक मूल्य में विश्वास हो।

—वह बुद्ध-सहस्रों एवं ताकती हो और भावों, मूल्यों और मान्यताओं की स्थापना एवं रक्षा के लिए सक्षम कर सके।

—वह अपने विचारों का हो। ईमानदार हो। दूसरों की बात मानने से मुक्त हो। विचारों में परिवर्तन के लिए तैयार रहता हो। कल्पनाशील हो। व्यावहारिक हो। पढ़ाई कर सके।

—वह प्रौढों को दक्षिण, आकाशवाणी, भावपूर्णताओं एवं समस्याओं को समझता हो। वह जानता हो कि प्रौढ कैसे सीखते हैं। उसे प्रौढ शिक्षा के विद्यार्थी, विधियों और विचारों का ज्ञान हो।

—उसे निरंतर प्रौढों की समझाओ में विश्वास हो कि ये सीख सकते हैं।

—उसे इस कार्यक्रम की सफलता की आशा हो।

—उसके हृदय में गरीबों के लिए प्यार हो। वह गरीबों की दुबलताओं के कारण उन पर दया नहीं, उनसे प्यार करे।

—वह विनम्र हो। प्रौढों को छोटा न समझे। उन्हें आदर दे। मुस्कुराता बात करे। गुरु शिष्य की भावना न ले। मित्र मित्रता सम्बन्ध हो। प्रौढ निरंतर और गरीब जरूर हैं, पर कई बातों में वे शिक्षक से अधिक जानकारी और अनुभव हो सकते हैं। शिक्षक को उनसे सीखना। शिक्षक और प्रौढ दोनों एक साथ मिलकर सीखेंगे।

—वह कम से कम कक्षा ८ पास हो। उसे पढ़ने का शौक हो। उसने खूब पढ़ा हो। वह रोज कम से कम पढ़ता हो। वह वाकपटु हो। कथा-वार्ता में कुशल हो। प्रयोगात्मक अच्छी कथाएँ और समझाएँ सुना सके। बौद्धिक खेल ऐसा सकता हो। व्यवसायिक प्रौढों को हुंसा सकता हो। शिक्षक उपदेश नहीं देगा। आपत्त नहीं करेगा। समाज और परिस्थितियों से केंद्र को बचाना देगा वहाँ प्रौढ होंगे बेमेल, गायेंगे बचावेंगे, अपने गाँवों और सीखेंगे। शिक्षक एक जीवनोपयोगी, सर्वोपयोग एवं रोचक अनुभव होगा। प्रौढों में एक तत्त्व-संज्ञा एवं विवेकानात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा।

—उसे विभिन्न विचार-कार्यक्रमों की जानकारी हो। वह अधिकारी और नेताओं से बात कर सके। विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को केंद्र पर लाकर उनकी बातें कर सके और विभिन्न विचारों से मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने में प्रौढों की सहायता कर सके।

—वह प्रौढों की रास्ता ही न बताये, उन्हें रास्ते पर चलना भी सिखाए।

—भावपूर्णता पढ़ने पर वह प्रौढ के साथ भावपूर्ण, व्यवसाय, यानि व्यवसाय दण्डर आकर उच्चता काम कर सके।

—वह प्रौढों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन कर सके और उसका विकास कर सके।

—वह सर्वोपयोग एवं अन्य अधिकारियों से बराबर संपर्क बनाये रखे। वह केंद्र की प्रगति और दक्षिणों में उन्हें सफलता रहे और उनसे मार्गदर्शन लेता रहे।

—बात में, वह ऐसा हो कि प्रौढ को उसके पास जाना अच्छा लगे, उसकी बात सुनना अच्छा लगे और उसके बात करना अच्छा लगे। *

उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति के उद्घाटनार्थ

‘नयी तालीम’ पत्रिका

के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

उत्तर प्रदेश गाँ० स्मारक निधि सेवापुरी * वाराणसी

गुठी, ऊनी, रेणुमी, सादी, रबन, तारपीन का तेल, सूती, चपड़ा, चमड़ा जामान, रिशतलाई, साबुन, रोम, कुम्हारों बर्तन तथा आवश्यक चीजों के उत्पादन एवं विहंता।

जिल्ला स्तर — दीदी बाग बाराणसी, सोहरा, दुर्ग, विर्मापुर बाहर, बसप्रकाश नगर, बलिया, कमठा (देवरिया) मुन्तानपुर, करछना, बोर्य (सहाबाद) गोहाद, मगरोड (हमीरपुर) गाँधी भवन सचनक धावस्तो (बहराच) शाखापुरी (पीलीभीत) मोरा धनीना (बहारनपुर) धावपुरी, धनीना, कोसानी (बनधोरा) तथा बहराच

उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति के उद्घाटनार्थ

‘नयी तालीम’ पत्रिका

के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

गाँधी भवन महात्मा गाँधी मार्ग

लखनऊ

दीदी सहायन, पुस्तकालय एवं वाचनालय गाँधी विचार के सदन ग्रन्थों, पुस्तकों एवं विचारों के लिए सुयोग्य माया से बात पुस्तकें, चित्र, एवं चार्टों के प्रकाशन एवं विहंता।

समाज की चमरौटियां

भ्रष्ट, फालेज और विश्वमिवालय
 समाज की ये चमरौटियां हैं,
 जहाँ अस्पृश्य नौजवानों की
 मणसे अक्षय
 एक पस्ती पहाई जाती है।
 वहाँ ऐसे कारोबार रहते हैं
 जिनके हाथ-पैर नहीं चलते
 और जिनको निर्धन ज़मान चलती है।
 उन्हें काम-काज की फूल समन्द नहीं,
 उन्हें बहार के फूल समन्द नहीं,
 वे मर-दबोय हैं जैसे कृष्ण बाला ही,
 वैसे ही ज़िन्दगी के उन पर कोई निशान नहीं।

०६३

नयी तालीम



अन्तर्राष्ट्रीय शांति वर्ष

ग्रौढ़ शिक्षा की प्रगति

अखिल भारत नयी तालीम समिति का प्रस्ताव

शुनिषादी शिक्षा शंकाएं और समाधान

ग्रौढ़ शिक्षा का विकास

हमें भ्रष्ट क्यों समाप्त करना है



अखिल भारत नयी तालीम समिति

मार्च २५
दिसम्बर
जनवरी

अंक ३
३

प्रधान सम्पादक	—	श्री के० प्रध्यापतम्
सम्पादक मण्डल	—	श्री द्वारिका सिंह
		श्री बन्धू माई बटेल
		श्री नान्ही नाथ त्रिवेदी
		श्री ज्योति माई देसाई
सम्पादक	—	डॉ० देवेन्द्र दत्त तिवारी
सह सम्पादक	—	श्री चन्द्रशूक्ल

सम्पादकीय

आन्तराष्ट्रीय बाल वर्ष

ग्रीक शिक्षा की प्रगति

अन्तराष्ट्रीय बाल वर्ष

श्री सद्गुण बटेल

पृष्ठ १

अखिल भारत नवी तालीम समिति का प्रस्ताव

३

कुनिबादो शिक्षा संकाय और समाधान

बाबी जी

४

ग्रीक शिक्षा का विकास

श्री जीवन नायक

५

हमें स्कूल नवी समाप्त करना है

अनुवादक डॉ० देवेन्द्र दत्त तिवारी

१०

आदरणीय धीरेन्द्रा की स्मृति में

दिनोबा

११

ग्रीक शिक्षा

कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट

१६

दिसम्बर — जनवरी, ७८-७९

नवी तालीम का वार्षिक पुस्तक—बारह रुपये तथा एक अंक का मूल्य दो रुपये है ।

पत्र व्यवहार के लिए सुधी पाठक कृपया अपनी ग्राहक पहचान अवश्य लिखें ।

पत्र व्यवहार के लिए पता — सम्पादक नवी तालीम, सेवापुरी, (वाराणसी)

नवी तालीम में व्यक्त विचारों का सम्बन्ध पूर्वतया लेखक का है ।

सम्पादकीय

अन्तर्राष्ट्रीय बाल-वर्ष

१९५६ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के कुछ अधिकारों की घोषणा की थी जिसकी परिणति इस नियम में हुई कि १९७६ को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया जाय। इस प्रकार ॥ वर्ष मनाने का उद्देश्य यह होता है कि प्रत्येक बाल बचप्य पर सभी राष्ट्र संयुक्त स्थान दें।

स्पष्टि यह है कि गरीबों के अनेक अधिकारों में एक अधिकार यह भी है कि वह देशी सत्ता की आज देती है जिससे गरीबी में निरन्तर बढ़ती जाय। जब बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी शारीरिक तथा मानसिक विकास नहीं हो सकेगा और सबसे दुखद बात है कि संस्थान का विकास अव्यवस्था हो जाता है जिसके दुष्परिणामों से जीवन भर मुक्ति नहीं मिल सकती, अनेक ही बात में कितना भी पौष्टिक भोजन क्यों न दिया जाय। आज देश में प्रतिवर्ष १२००० मरते हो जाते हैं और १४ करोड़ बच्चे (१-५ आयु वर्ग के) राग के लक्षणों से मुक्त दिखाई पड़ते हैं। इनमें ५० प्रतिशत वर्ग ५ करोड़ बच्चे रक्तमार्ग के दोष से ग्रस्त रहते हैं।

यद्यपि गरीबी के कारण बच्चों का समुचित विकास असम्भव है, फिर भी गरीब माता पिता की स्वास्थ और सफाई की कुछ जानकारी हो आज तो बच्चों के विकास में सुधार सम्भव है। शिक्षकों का इस क्षेत्र में विशेष योगदान हो सकता है। सभी को तो बड़ा था कि सफाई सुनिश्चिता शिक्षा का प्राण है। यदि शिक्षा से सम्बद्ध लोग इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देते तो शिक्षा का प्रविण्य बच अव्यवस्थापूर्ण हो जायगा, क्योंकि जब ऐसे बच्चे विद्यालयों में जायेंगे जिनमें संस्थान और शरीर के विकास में अवरोध के कारण कोई सुधार सम्भव न हो सकेगा तो शिक्षकों के लिए बहुत कुछ करना होगा न रह जायगा। इसलिए आवश्यक यह है कि शिक्षक वर्ग ॥ शिक्षा में सभी शक्ति विचार करके कोई योजना क्रियान्वित करें जिससे गरीब और दाम के अग्रणी बच्चों ॥ जीवन सुखमय हो सके और सभी देश का अधिकार उन्नत हो सके।

प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना की घोषणा के अन्तर्गत वर्ष १९७०-७६ मुख्यतः लैंगिक ॥ वर्ष है और यह समाप्तमय है। लैंगिक नई शिक्षाओं से होती थी—प्राथमिक व्यवस्था, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण की व्यवस्था, माता-पिता लैंगिक करना आदि। अभी तक प्राथमिक व्यवस्था का प्रश्न है प्रौढ़-शिक्षा-अधिकारियों की विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियों हुई हैं। राज्य स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा-समितियों का गठन भी हुआ है। किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण लैंगिक दिक्कत व्यवस्था की भी जिसमें क्षेत्रीय, जनपद, तहसील तथा ग्राम स्तर पर समिति गठित करके और विभिन्न अधिकारियों के कार्यक्रमों में समय-समय की व्यवस्था करना अनिवार्य था। प्रौढ़ शिक्षा-कार्यक्रम की लैंगिकी से यह बड़ी कमजोर रही है। इसलिए आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता।

जहाँ तक वादग्रहण और विचारण सामग्री सेवार करने का प्रश्न है, इस दिशा में कुछ वादग्रहण निर्धारित हुआ है और विचारण सामग्री भी सेवार की गई है। किन्तु यह प्रौढ़-विचारण की सामग्रियों को देखते हुए न केवल अपर्याप्त है। प्रत्युत अनुपयुक्त भी है। कारण जैसा कीछरी समीक्षण ने कहा है कि प्रौढ़-ज्ञानार्जन व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कोई एकक या वादग्रहण या विचारण सामग्री निर्धारित नहीं की जा सकती। एक ही प्रौढ़ विचारण के ३ पर विभिन्न योग्यताओं सामग्रियों में प्रौढ़ आयेगे। एक जैसी सामग्री सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। स्थानीय स्तर पर वादग्रहण तथा विचारण-सामग्री सेवार करने की सामग्री उत्पन्न करना आवश्यक था।

प्रतिक्षण की जो व्यवस्था की गई है, वह तो अपर्याप्त सम-तोषजनक है। जो विषय में जानकारी नहीं है, वे प्रतिक्षण वे रहे हैं, जिनकी कार्य में रुचि नहीं है वे प्रतिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रौढ़-विचारणों के लक्षित चुनाव पर दल दिया गया था, वह प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है।

जहाँ तक वातावरण सेवार करने का प्रश्न है, इसका भी कोई कारखाना से निर्माण नहीं हो सका। जन-आन्दोलन के लिए अनेक योजना तथा प्रतिमान नेतृत्व आवश्यक था, किन्तु दुर्भाग्यवश राजनीतिक परिस्थिति में अनुपलब्ध न होने के कारण वातावरण नहीं बन सका।

सेवारी के सम्बन्ध में अतिरिक्त बात यह है कि यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा की समस्याओं को इस कार्य में लगने के निर्देश दिए हैं किन्तु विश्वविद्यालयों पर कोई प्रभाव नहीं हो सका है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ कहना पड़ता है कि सेवारी के वर्ग की स्थिति अपराजनक नहीं है।



अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष

यदुनाथ शर्मा

पहली जनवरी से ११ दिसम्बर, १९७८ तक अन्तर्राष्ट्रीय बालवर्ष मनाने की बुनियाद पर जो देशों ने संधिबद्धता की रही है। आमतौर पर सरकारें ही इसमें अनुमति देती हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकारी काम करने का अपना एक ढंग होता है, वे अपनी ओर ध्यान देते हैं। मरणा मरणा करती हैं। उनका जगता के ऊपर नहीं करती, फिर बाह्य यह सरकार लोकान्तरिक हो या एक-विचारकारी। इस दृष्टि से सम्भव है कि अन्तर्राष्ट्रीय बालवर्ष की कहीं एक सरकारी प्रवर्तन नाम से मन जान। सरकारी तन्त्र की एक विशेषता यह है कि वही हर बात विचार से हटा करती है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सूचना देती, फिर राज्य सरकारें बिना परिषद्, नगर परिषद्, ताबुता चचापत और अन्य से काम चलायती तक सूचनाएँ पहुँचायेगी और सम्भव है, अन्तिम कड़ी तक पहुँचाएँ पहुँचते - पहुँचते दिसम्बर १९७८ या तो या बायेला अवस्था भीत जायेगा। क्या इस अन्तर्राष्ट्रीय बालवर्ष से आम जनता का कोई सम्बन्ध नहीं है? जगता इस वर्ष क्या नहीं कर सकती?

जनता अवश्य ही कुछ कर सकती है और जनता के काम करनेवालों को इस दिशा में अपना अधिकतम दिशाना चाहिए। गांधी तथा सर्वोच्च विचार से प्रेरित रहने वाली का दावा अनाधारित संगठन होने का है। वे मानते हैं कि वे लोक पक्ष की जागृता, उदबुध तथा सजगता रूप देने में जुटे हुए हैं। अब उनका दावाएँ अधिक बढ जाता है। सभी हस्त में एक सम्जन ने कहा कि 'द बिनेट रकट्टो इन द बर्ड्स इन डेप द-बर्ड्स'—दुनिया में सबसे बड़ा उद्योग अगर है तो मारकाट का है। सुधदा और व्यवस्था के नाम पर बहुत सब आज हो रहा है और दिन-ब-दिन उसमें वृद्धि हो रही है। इससे सरकारें बातचीत मनायेगी और अगर व्यवस्था बनने से पता भी

बन करती रहेगी। सरकारों के नाम पर बनने वाले उद्योगों में जो सचें आज होता है उसका भौतिक प्रत्यक्ष प्रतीति के पीछे संगम ५००) २० हैं लेकिन दूसरी तरफ बुनियाद की बाकी व्यवस्था की बाधित भाग इतने बाधित है। मानव विचारशील प्राणी माना जाता है। जीवन की शा विवर्धित को देखकर, उसे दूर करने की दिशा में कुछ कदम उठेंगे?

एक कदम यह हो सकता है कि यू० एन० ओ० के महासचिव तथा अपने राष्ट्र प्रमुखों के पास इस आग्रह के निवेदन अपने अपने हस्ताक्षर करके भेजें। वे माँग करें कि सेना तथा पुलिस पर होने वाले सचों की वाच प्रतिष्ठित बढाया जाय। इस और अमरीका साक्षात्कार निर्माण से जो सचें कर रहे हैं उसको अगर इस तरह बढाया जाय तो दुनिया-भर के कम्पान कार्यक्रम अपने गुणाव रूप से चल सकते हैं। लेकिन छोटे देश भी अपने व्यवस्था सचों को बढाने के लिये तैयार न हो तो उनका नैतिक दबाव बड़े देशों पर नहीं पड़ेगा। ऐसा हस्ताक्षर अभियान अगर इस वर्ष में चले तो सम्भव है कि नया मानव रहेगा।

दूसरी बात है अवस्था वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि को अगर न रोका जाय तो मानव व्यवस्था की कोई योजना नहीं बन पायेगी, इतना ही नहीं मानवीय मूल्य भी ध्वस्त हो सकते हैं। इस सम्भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होने वाला मानव नया मानव मेरी रोटी छीनेगा, मेरा कपड़ा छीन लेगा, मेरे घर में ऊँट की तरह घुसकर मुझे ही एक दिन बाहर निवास देगा, ऐसी स्थिति हो जाय तो मानव मानव की सभा नहीं, बैरी मानने लगेगा। यह ही अवस्था हो जायेगी। समय से अगर सच्चा सजगता की बा लगे तो बड़ी सुधी की बात है, अगर नहीं सजगता है तो रोटी जिस तरह इलाज करवाता है वैसे इलाज करवाने की तैयारी रखने में

अवश्यही है। दुनिया की आज की जनसंख्या ४०० करोड़ के करीब है और जनसंख्या - वृद्धि अगर आज की तरह बेरोकटोक होती रहती तो सम्भव है कि पचासवीं के अन्त तक यह ८०० करोड़ न हो जाय। ऐसा हुआ तो प्रकृति का समुजन बिगड़ जायेगा और पृथ्वी वीरान हो जायेगी। वैज्ञानिक, व्यासजी की बातें तो से हमको भायाहूँ कर रहे हैं। यह रहे हैं कि सदा वृद्धि रोक लो, नहीं तो यह समुद्रों से भी एक सवानक बरसना संभव होगा। तब नये बच्चे का स्वागत नहीं होगा और आदमी मर जाय तो सौग कहेंगे, भगछा हो क्या एक जना हमारे लिए के हुंटी। यह तो अमानवीय निश्चित होगी। दूसरे बच्चों के जिन मानवीय मूल्यों का विनाश हमने किया के सब मूल्य बर्बाद हो जायेंगे। स्वायत्तता-समता एका ध्युता के लिये कोई अड़काया नहीं रहेगा।

महिलाओं की दृष्टि से ये दो बातें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, विश्व स्त्री-शक्ति-सम्मेलन की तैयारी में बहने लगा है। बहुपारिणीतियों के अन्वय को हम परा छोड़ दें, लेकिन सर्वसामान्य स्त्री शक्ति अपने को बड़ा अहमर्ष वा रही है। ऐसी कौन माता होगी जो अपने बालकों के सर पर तलवार टेंगी देवता चाहेंगी? जिसने अपनी सम्मान के चमकी आया देवताओं को लड़ा और कृत्रिमों का अनुमन किया वे अपनी सम्मान पर मृत्यु का साह्य जाना कभी बर्बाद नहीं कर सकेंगी। उनको अपनी आवाज

बस-बद करके दुनिया की सभी सरकारी से बहना चाहिए कि अगर सपमूल्य आवाज बाल-वस्थाएं चाहते हैं तो उन्हें लिये पॉन्ड फोसटो फास्फोरस के चर्च पटाओ और इसी राशि बाल-वस्थाओं के लिए उपलब्ध करो। यह लही विषय में परना ब्रह्म होगा।

सदा हुआ मातृत्व प्रविष्टि अस्थापार ही मानना चाहिए। ऐसी कोई मता गायन ही होगी जो अपने बालकों को दार्ष्टि, विषमता, अघाय, गुलामी तथा बंद की परोहर देना चाहेंगे। उताओं की उम्मा मर्वादा से अधिक हो तो उनही छीन से देखाऊत गयीं हो उनको। अत जेता कि शायीको ये मास्टेट सेंसर ॥ कहा या—“अदने पक्षि को न कहने की शक्ति उसने मानी चाहिए” गांधीजी की स्त्री-शक्ति की वस्वता ऐसी थी। ना कहने की सत्ता-इही शक्ति उनमें आ पाय तो सतान सत्ता मर्वादि करना समय होता। लेकिन सरासही शक्ति की कचोटी के नाय पर जनसंख्या-वृद्धि के लिए कारण नहीं बनता चाहिए। इस बोले से बच कर भी वह जसोरी कर लवती है। विश्व स्त्री-शक्ति-सम्मेलन का काम करते हुए इन बातों के बारे में समान की सामयान करन का काम की करना चाहिये। ऐसा सवता है बाल-वस्थाओं के बारे में स्त्री-शक्ति कमो और सतावधानी नहीं कर सकती ॥

अखिल भारत नयी तालीम समिति

दिनांक ११ अगस्त १९७८ को सेनाग्राम में हुई अखिल भारत नयी तालीम समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव—

‘दिनांक १६७७ में दिल्ली में हुए राष्ट्रीय विद्या सम्मेलन के बाद से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा इन दोनों के परिष्करण की दिशा में किये गए प्रयासों के निष्पत्ति के पश्चात् समिति उसका स्वागत करती है। ममानव ने प्राथमिक शिक्षा के सर्वे सामान्यीकरण तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा के कार्यक्रम की योजना को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि १५ (विकसित) से २५ वर्ष की आयु के बीच के लगभग १० करोड़ अधिलिखित उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। सभी प्रदेश तथा देश की बहुत बड़ी संख्या में ईर्ष्यासक्त समाज भी इस दिशा में प्रादेशिक तथा शिक्षा स्तर पर योजनाओं को विकसित करने के लिए प्रेरित की गई हैं।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा की प्रगति के लिए की गई सिफारिशों पर भी यह समिति सज्ज है।

‘शिक्षा की प्रगति हमारी प्रत्येक स्तर पर उपलब्धकारी शासकीय के सम्यक अध्ययन के पश्चात् समिति अनुभव करती है कि सरकार द्वारा किये गये उचित प्रयास यद्यपि स्वागतार्ह हैं फिर भी वे वांछित सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकेंगे क्योंकि सरकार शिक्षा को प्रणाली में ही परिवर्तन माने। कार्य की उच्च बरीयता नहीं देती। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा कार्यक्रम इस तरह नहीं बनाया गया है कि वह सब संभावित समुच्च के जीवन की दीनविन समस्याओं को सुलझा सके। जो छात्रों और सामान्य जनता के साथ उचित संबंध है। उसी प्रकार,

सामाजिक उपरोधी उत्पन्न कार्य यद्यपि मुनिदायी तालीम दर्शन से विभाजित है फिर भी सम्पूर्ण शाखा प्रणाली के विषयानुसारी होने से कारण उनमें बहुत कम अंतर हो जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के नीति निर्धारण सम्बन्धी सुझाव की कागज पर ही रह जाने सम्भव है क्योंकि देश में विश्वविद्यालय भी कक्षाभिमुख रहे हैं। जब तक उच्च शिक्षा, कमबोरी तर्ग के लिए कानूनी की सुविधा का लाभ बाधक अधिक दृष्टि से सामान्य विचार नहीं बनाई जाती, तथा जब तक मोहरी पाठों की शक्त से समाविष्टों का सम्बन्ध विच्छेद नहीं होता तब तक उच्च शिक्षा अनुत्पादक और परामर्शी या परोपकारी ही बनी रहेगी।

‘इसलिए यह समिति भारत सरकार से पुरजोर अपील करती है कि यह शिक्षा की वाय की जीवन की वास्तविकता तथा छात्रों और प्रामाण्य जीवन की सामाजिक उत्पत्ति और प्रगति के साथ जोड़े। संस्था के प्रति कार्सीन अधिवेशन में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति विषयक प्रस्ताव शिक्षा नीति में परिवर्तन करने वाला हो न कि केवल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उसके ढांचे या सामग्री में परिवर्तन लाने वाला या दोनों में कुछ परिवर्तन सुझाने वाला मात्र हो। समिति आशा करती है कि भारत सरकार उस जनता को सामाजिकशास्त्र और मरणात्मा की ओर पूरा ध्यान देगी जो जीवन चाहती है, काम करना चाहती है। जनता शोषणहीन प्रजातन्त्रीय समाज चाहती है, तथा ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहती है जो उसके आविर्भाव और मरण-मोक्ष में निरुत्पन्न छद्मप्रकार हो। यह शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के प्रस्ताव का शिक्षा के आदर्शों के अनुसरण होना

आवश्यक है। समिति परिवर्तन समय से साने सम्बन्धी निम्नलिखित सिद्धांत एवं मुक्तिप्राप्त सुझावों हैं—

(अ) प्रत्येक शिक्षा संस्था को पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन सम्बन्धी स्वायत्तता।

(आ) दोन मूलभूत मूल्यों पर जोर ॥१॥ पहले अध्ययन पाठ्यक्रम।

(i) मातृ-निर्गौरवता, आत्म-विश्वास तथा औद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत काम द्वारा अपनी प्रतिष्ठा।

(ii) समाज सेवा के सर्वप्रथम कार्यों में शामिल किये जाने के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीयता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का निर्माण।

(iii) वैश्विक और पारिवर्तित मूल्यों को मन में बैठाना तथा धर्मों की एकता तथा सब धर्मों का समान रूप से मान्य करने की आवश्यकता को उचित रूप से समझना।

(द) विकेन्द्रीकृत शासन, जिसमें सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो।

(ई) उच्च शिक्षा में बांधी विचारों का अध्ययन, महिला और पार्श्व छोड़।

(उ) लोकरी की शक्तों से उपाधियों का सम्बन्ध बिच्छेद। साथ ही को उद्योग, व्यवसाय तथा सरकार में जाना चाहते हैं उनके लिए उपाधि रहित पाठ्यक्रम प्रणाली।

‘शिक्षा की प्रगति का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने तथा समय-समय पर उसकी प्रगति का सैद्धांतिक-बोला प्रस्तुत करने और मार्गदर्शन करने के लिए

(ऊ) वैधानिक स्वायत्त राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन जिसके अधिकारों का सर्वसम्पन्न वैधानिक संस्थाओं के हों।

‘इसी प्रकार की परिषदें प्रादेशिक स्तर ॥२॥ भी बंठित की जाए।’



बुनियादी शिक्षा : शंकायें और समाधान

गांधी जी

[सर्वप्रथम में गांधी जी की पंचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर तालीमी राष्ट्र के प्रतिनिधि गांधी जी से मिलने आये। उन्होंने गांधी जी से बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में जो बातें की, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संकलित बातें यहाँ दी गई हैं।— सम्पा०]

शंका : यदि बालक और बालिकाओं, दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न हो तो तो क्या मात्र बालिकाओं के लिए ही बेसिक पाठ्यासाह संश्लेषा संकलित है ?

समाधान : (गांधीजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा) मान नीति के लिए करोबी बालक

बाते हैं। क्या हमें स्थानांतरण के कारण उनको शिक्षा देने ॥ इन्कार कर देना चाहिए ? मैं सुझाव कहता हूँ ॥ मैं इन्कार नहीं कहूँगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं उन्हें एक गुँथ की छाया में बिठा दूँगा और उनके हाथों में बाँध दूँ। तबसिवा यथाकर धीरे-धीरे उनके द्वारा उनको शिक्षा देना आवश्यक कर दूँगा।

(ग्रीक शिक्षा की चर्चा करने पर बायीं ओर से यह मधुसूत किया। स्पष्टतः बुनियादी तालीम के क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए। उसके प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण पर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा का समानता होना चाहिए। उन्होंने कहा—) वैदिक स्कूल के सम्पादन को अपने मापकी जीवन की प्रत्येक स्थिति में सम्पादन सम्पन्नता चाहिए। जैसे ही हमारे व्यक्ति—एबी अथवा पुत्र—उसके सम्पूर्ण से कार्य जैसे ही उसे अपने मन से पूरना चाहिए—मैं इसे क्या शिक्षा दे सकता हूँ?

शिरा : क्या उसका इस प्रकार शिक्षा देना विद्या विधान का सूचक न होगा ?

समाधान : नहीं। मान लीजिए, एक ऐसे बूढ़े से मेरी मेट होती है जो गन्ना और मजानी है। अपने पाप को ही वह अपनी दुनियाँ समझता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति मेरा वह कर्तव्य होगा कि मैं उसे स्वच्छ रहने की शिक्षा दूँ, उसकी मजानगी दूर करूँ और उसके मानसिक सितिलन का विकास करूँ। मुझे उसके यह करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं उसका सम्पादन हूँ। मैं तो उसके मस्तिष्क के पाप कीविल सम्पूर्ण स्थापित करने की चेष्टा करूँ और इस प्रकार उसका विकास प्राप्त करूँ। वह हमारी अनिपन्नता दाओं की मछे ही उपेक्ष करे, लेकिन मैं हार स्वीकार नहीं करूँ। मैं अपना प्रयत्न सतत जारी रखूँगा जबतक कि उसे अपना मित्र नहीं बना लूँगा। एक बार उपसर्ग मिलने पर वेप की पूर्ति होती रहेगी।

मुझे बच्चों पर ही उनके जगत् में ही दृष्टि रखनी होगी। मैं तो एक बच्चा और भागे बड़ों और यह कहूँगा कि शिक्षक का काम तो हमके पहिले से ही आरम्भ हो जाता है। उदाहरणार्थ यदि रानी गर्भवती हो जाती है तो माता देवी उसके पारा चारों ओर कहेगी मैं बँसी ही माता हूँ जैसी तुम बननेवाली हो। मैं अपने अनुभवों

के आधार पर तुम्हें यह बता सकती हूँ कि तुमको अपने अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वयं अपने स्वार्थ की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। वह उसके प्रति को यह भी बतायेगी कि सबका अपने पलों के प्रति क्या कर्तव्य है और उन्हें गर्मस्व शिक्षा की देखभाल में क्या भाग लेना चाहिए। इस प्रकार वैदिक शिक्षा का सम्पादन जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अपना प्रमुख स्थापित कर लेगा। ग्रीक शिक्षा को स्वभावतः उसके कार्य-क्षेत्र का अंग बन आयेगी।

ग्रीक शिक्षा का कुछ कार्य अनेक स्थानों में हो रहा है। वह अधिनायक मिलवाली और उत्ती स्थिति के बड़े बड़े नगरों के मोहों के हाथों में केन्द्रित है। वास्तव में बाप को किसी ने रखे नहीं दिया है। केवल 'दीन भार' की शिक्षा और राजनीति पर मापन से मुझे सतोष नहीं हो सकता। मेरी उल्लास की ग्रीक शिक्षा में दुश्मनों और स्त्रियों को क्षुब्ध नागरिक बनाना होगा, बच्चों के लिए सात वर्ष की शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने की अपेक्षा। ग्रीक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाना और उसके कार्य को सुम्पवर्षित करना सम्भव कठिन है। बीबी (प्रारम्भिक शिक्षा और ग्रीक शिक्षा) का सामान्य केन्द्रीय उद्देश्य राष्ट्रीय उद्योग के पाठ्यक्रम से शिक्षा देना होगा। बुनियादी तालीम के क्षेत्र पर ग्रीक शिक्षा ने कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। अंतराज्य की शिक्षा को भी स्थान मिलेगा पर बहुत ही बाले मौखिक हो शिक्षार्थ प्राप्त होगी। विद्यार्थियों की अपेक्षा सम्पादनको के उपयोग के लिए अधिक प्रसक्त होगी। हमें बहुमतवालों की यह शिक्षा देनी होगी कि वे सम्पन्नताओं के साथ और इसी प्रकार सम्पन्नता के सम्पन्नताओं के साथ केला व्यवहार करें। ग्रीक शिक्षा का उचित और सच्चा रूप यह है जो अपने परोक्षियों के साथ मित्र पुत्र कर देने की शिक्षा देता है और अनुभवता तथा साम्प्रदायिकता की बट बटता है।

प्रौढ़ शिक्षा का विकास

जीवन मायक

अंग्रेजी के भारत में आने के पूर्व यहाँ प्राचीन व्यापारों के मार्गदर्शन में एक उत्तम और सुव्यवस्थापित शिक्षा-प्रणाली प्रचलित थी। १६०० में १८३३ के बीच इस प्रणाली में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुए पर व्यवस्था बनी रही। १८३३ से १८५७ और १८५७ से १८६७ के बीच सामाजिक शिक्षा की स्थिति सीधे-सीधे रहो। जब ब्रह्मको की शिक्षा की ऐसी दवा दी तो प्रौढ़ों की शिक्षा पर कीमती ध्यान देना ? १८६७ से १९०१ तक शिक्षा की स्थिति में उत्तरीतर सुधार हुआ और १९३७ में शिक्षा को दिया और कार्यक्रम निश्चित किये जा गये। १९३७ में प्रथम बार संसद गठित होने का संकेत-संकेत के इस और विशेष ध्यान दिया।

शिक्षा-व्यवस्था पतन की दृष्टि में मध्य प्रायः सबसे अधिक बर्णना विद्यमान है। इस कारण यह स्वाभाविक है कि शिक्षा-प्रणाली का जोरदार आन्दोलन शुरू हो। प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रारम्भ सबसे पहले मद्रास में ही हुआ। वहाँ हरिजनो के लिये प्रौढ़-शालाएँ खोली गयीं। किसान और मजदूर की इन शालाओं में आते थे। मद्रास के बाद बंगाल और सगुल-प्रान्त में भी प्रौढ़-शालाएँ खोली गयीं थीं पर अनेक कारणों से अव्यक्त रही।

सबसे पहला कारण यह था कि प्रौढ़ों की शिक्षा का काम प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों से ही लिया जाता था। ये बच्चों के स्कूल में दिन-रात बिना-विचलित-तक तो बने जाते थे और प्रौढ़-शालाओं में जाकर नींद लेते थे। कहीं-कहीं दली शिक्षकों की डाक्यूमेंटों में भी काम करना पड़ता था।

एक शालाओं में प्रौढ़ों की पढ़ाई-लिखाई के लिये बड़ी साहित्य काम में लाया जाता था जिसे प्राथमिक शालाओं के बच्चे पढ़ते थे। प्रौढ़ों के लिये विशेष प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है, यह विचार केवल ईसाई धर्म-प्रचारकों

के मन में जाता था। ईसाई धर्म-प्रचारकों का ध्येय प्रौढ़ों में ईसाई-धर्म के प्रति आस्था जमाना हो था, परन्तु यह काम तब तक सफलता से नहीं चल सकता था जब तक उनमें निष्पक्ष-पक्षों की सामान्य योग्यता न होती। अपने स्वयं की पुनः के लिये उन्होंने भारत की प्रमुख भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद प्रकाशित किये। पाठकों के विचार में इनकी छात्रों में भी सावधानी बढ़ती। सरल भाषा और मोटे टाइप में छोटी-छोटी पुस्तकें तैयार कीं। प्रमुख भाषाओं के अतिरिक्त 'कोडिओ' में भी वे अनुवाद किये गये और देश के प्रमुख नगरों में स्थापित 'मिशन' प्रेसों में छापे गये।

१९वीं शताब्दी के आरम्भ में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन पड़ोश में हुआ। इस आयोजन में उपयुक्त पाठन-सामग्री पर ध्यान दिया गया और पुस्तकालयों की स्थापना की गयी। १९१९ में मद्रास में प्रौढ़ों की राखी 'पाठशाला' खोली गयी। परिचित पुस्तकालय भी स्थापित किये गये। 'मिशन' नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गयी। इस तारे कार्य का ध्येय मद्रास के तत्कालीन दोवार सर एम० क्रिस्चियनरैंग को दिया जाता है।

नव सातहों के लिये साहित्य-गृह का विधिवत कार्य बिहार में १९३६ में शुरू हुआ। वहाँ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डा० रमेश प्रह्लाद ने ऐतिहासिक दारे 'ईश्वर धर्म धर्म' के साथ काम शुरू किया। 'महमूद-सिरोह' के अन्तर्गत प्रौढ़ों के लिये तो पुस्तकें तैयार करायी गयीं। इस माना की प्रथम दो पुस्तकें थी—'राजेश्वर हिन्दी प्रदीप' और 'राजेश्वर चिन्ता'। इनके द्वारा प्रौढ़ों को अक्षर-ज्ञान कराने और भाषा-रहित घराने घरानों के द्वारा सामान्य-वृत्तान्त पढ़ाने का सरल प्रयत्न किया गया। भाषा की लेख पुस्तकों में सेठी, पद्मनाभन, स्वास्थ, महा-

पुरो की जीवनो, आविष्कारों की तथा गृह-उद्योग, कृषि सम्पत्ति, परिवर्तनमार्ग की उद्देश्यता तथा नागरिकता आदि विविध विषयों पर प्रौढ़ नर-नारियों को ध्यान में रखकर छायावी दी गयी थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में विकासोन्मुख परिवर्तन की गति तीव्र हुई। पञ्चवर्षीय योजनाओं द्वारा सर्वोत्तम प्रगति का मार्ग प्रणाला गया। वैज्ञानिक, औद्योगिक, सांख्यिक तथा स्वास्थ्य आदि विविध विकास आयक्रम बनाये गये।

यह विचारधारा स्वतन्त्रों हुई कि पञ्चवर्षीय योजनाओं एवं छायाधार के हित सुख व उद्देश्य से निर्धारित विकास-कार्य की रूपरेखा है, जिनके रत्न अन्तः के हाथों के स्वयं से ही उभरेंगे और समय वाक्य देग की सामर्थ्य का बहुराज चित्र स्पष्ट हो जायेगा। यदि चित्र में रत्न करने वाले हाथों की कार्यक्षमता न बनाया गया तो तत्काल कोमो दूर रहेगी।

हाथों की कार्यक्षमता उन्हें संचालित करने वाले मशीन के सहकार पर निर्भर है। मशीन का बड़ी सहकार अनुपम को मनुष्य बनाता है, ईर्ष्यान्वित जीवन की शीत ज्ञानों वाली निरन्तरता से उसे मुक्त करता है, प्रज्ञा क्षमता, सामुदायिक और सौन्दर्य के साक्षात्कार से उसका प्रवेश कराता है, श्रेष्ठतर समाज-व्यवस्था के निर्माण में उसे प्रेरित करता है और मावी आयोजन के सिला-घात की सामर्थ्य प्रदान करता है। लोक-रीति नीति लोकोत्तम और लोकसत्ता तथा ऐसे ही अन्य उपकरण मुक्तमुक्त से वे सत्कार प्राप्त करते रहे हैं।

सामाजिक महत्त्व के सम्यो का निष्पन्न और सामाजिक भावना शिक्षा के व्यापक आयोजन के बिना अतथ्य है—एक मान्यता से प्रेरित होकर विभिन्न देशों में शिक्षा के आयोजन तब एक आरम्भ किये जा चुके थे।

इनसे सामंजस्य अपने देश में लाने की योजनाओं का सुवर्णत विद्या जाये, हृष्ट विचार से देश के जाने माने शिक्षा-कारणों की, मनाया, इकोनॉमिक्स, विप्लवनाम, यमो और अमरीका आदि देशों की यात्रा करने गये। विदेशों में प्राप्त अनुभव के आधार पर उन्होंने यह बात

प्रकट किया कि प्रौढ़ शिक्षा समाज शिक्षा का ही अंग है, यद्यपि नर-नारियों को पूर्ण विकास-युक्त नागरिक के रूप में प्रभावकारी व्यवहार-प्रणाली में दीक्षित करने के लिए समाज-शिक्षा का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिये, प्रौढ़ शिक्षा केवल अल्प प्रौढ़ों के लिए ही आवश्यक नहीं है, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता का प्रसार मात्र नहीं है नये विचारों को आत्मसात् करने की क्षमता उत्पन्न करना ही समाज-शिक्षा का उद्देश्य है और समाज शिक्षा का यहो महत्त्व है जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का है। जिस तरह प्राथमिक स्तर के बालक-बालिकाओं के लिये वैज्ञानिक र्व से निरूपित अनुपम साहित्य का सूत्रन परम आवश्यक है उसी तरह समाज शिक्षा में लिये की साहित्य-सूत्रन का विविध अनुष्ठान करनी है।

इन शिक्षाविदों ने उन देशों का चित्र भी उपस्थित किया जहाँ कमबल आर्थिक नियोजन की नीति अपनायी गयी है, जहाँ समाज-व्यवस्था की मिश्रित कर्म बदलने के चल चल रहे हैं जहाँ नागरिकों को नये सधिये डाखने की बहुराज वा पड़ी है और सर्व-साधारण की शिक्षा या 'इनिंग' बहुरी हो गयी है, जहाँ वैश्वी बड़ रही है और प्रौढ़ शिक्षा ने प्राथमिक शिक्षा का रूप लेलिया है। उस अनुपम की शिक्षा की आवश्यक हो गयी है जो काम-साज में लग है, शिक्षा की बहुराज की परिस्थितियाँ जहाँ है, जो कामकाज के सिलसिले में एक दूसरे के पूरक होता जा रहा है। लोगों को दुरासत है समय का पूरा पूरा लाभ छठने की सिला देनी बहुरी हो गयी है; व्यवसायिक क्षमता बढ़ने और जीवनमान उठा कर है। उद्देश्य से भी लोगों को शिक्षा दी जा रही है। मूल, सफ़े, अ-पे और सुधारणधर्म से सजा कष्टन वाली प्रौढ़ों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा आवश्यक हो गयी है। स्कूल और कलेज से शिक्षा वाक्य निरन्तर के विद्या-धियों को अपनी र्व और योग्यता का काम हुँदने में कठिनाई का सामना करवा पड़ता है। उनके लिए विभिन्न देशों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना की गयी है जहाँ उन्हें उचित मार्गदर्शन मिलता है और उनका कुशल का समय किसी उपयोगी काम को सीखने में शीतता है।

सरकारी नौकरी में प्रवेश वा जाने वाले अपने काम की योग्यता बनाया ही प्राप्त नहीं कर लेते। सरकारी काम-काज की जटिलता परिकल्पना की गति और महत्वपूर्ण पर आसानी व्यक्ति से अपेक्षित कार्यकी मर्यादा—इन बातों का ध्यान रखते हुए समय समय पर 'इन सर्विस ट्रेनिंग' दी जाने लगी है।

श्रीद्धी की शिक्षा के इन विशेष सेवा क अतिरिक्त, समाजों की जाति, राजपद की सुरक्षा, संरक्षणी अस्मिता गणतंत्र का विकास, अनिवार्य से रखा, पीने के पानी की व्यवस्था, सरकारी नर्मधारियों की सहामता और विभिन्न विकास कार्यक्रमों में जन सहयोग आदि के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा प्रणय अनिवार्य हो गया है। ऐसा प्रणय होने पर ही उस वातावरण का निर्माण हो सकेगा जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए अनिवार्य है।

एक विशेषण को सामने रखकर 1938 से 1947 तक श्रीद्धी शिक्षा अथवा समाज शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जांच विभिन्न राज्यों में हुई और सत्ता हस्तांतरित होने के बाद इन पर मनोयोगपूर्वक अगल किया गया। यद्यपि नर नारियों के लिए समाचार पत्र, किस्में और पुस्तकें तैयार करने की शिक्षा म जोरों से काम शुरू हुआ श्रीद्धी के लिए पुस्तकें तैयार करने के लिए लेखकों को आमंत्रित किया गया। स्वाभ्युत्थन सभाओं को अनुदान देकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अल्पकालीन दिवसों में काम करने के लिए अतिरिक्त परिश्रमिक देकर शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त की गयीं। 'मिटरली हाउस' सञ्चालन से उठाया, बिहार एजुकेशन सोसाइटी की ओर से हिन्दी और मराठी में पाठ्य प्रकाश और रोपनी मध्यप्रदेश सरकार की ओर से हिन्दी और मराठी वैमानिक दीपक आदि पत्र पत्रिकाएँ श्रीद्धी के लिए छापी गयीं। मोटे टाइप में 16 पृष्ठों तक की सूक्तों रचीन पुस्तकें एवं निर्धारित पत्र के माध्यम पर की गयीं। श्रीद्धी की शिक्षा देने वाले शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए पद्धिमाएँ तैयार की गयीं। संवाधान से इस क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों और मर्यादों के लिए मार्गदर्शक साहित्य विनियमन बम्बई और मध्यप्रदेश राज्यों में प्रकाशित किया।

श्रीद्धी शिक्षा की योजनाएँ विभिन्न राज्यों में बसाई गयीं इनमें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित समाज शिक्षा योजना को विशेष महत्त्व प्राप्त हुई। मध्यप्रदेश में उत्कालीन गृह-मन्त्री द्वाराकाप्रसाद मिश्र उक्त योजना के 'अवक' कहे जाते हैं। उनका नारा था—'सोशल रिकन्स्ट्रक्शन यू सोशल एजुकेशन'। श्रीद्धी शिक्षा अथवा समाज शिक्षा के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई और मध्यप्रदेश में सरकारी अथवा गैर-सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रकाशित साहित्य पर यूनेस्को ने एक विचार बोध की आयोजित की और यह मत प्रकट किया कि मध्य-प्रदेश राज्य के समाज-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत काम करने वाले साहित्य केन्द्र में श्रीद्धी के विचार से विविध विषयों पर हिन्दी और मराठी में जो साहित्य प्रकाशित किया है वह उद्दिष्ट और उपयुक्त है।

इस साहित्य की विशेषता यह थी कि इसके लेखन, मुद्रण, बिक्रय और विषय-वस्तु में पक्षी सुझ-बुझ से काम लिया गया था। युतपूर्व मध्यप्रदेश द्विभाषी-राज्य था, अतः द्वारा साहित्य हिन्दी और मराठी में एक साथ छापा गया था। यह साहित्य इस निर्देश के साथ बिना-सूझ बाँटा जाता था 'पक्षी और दूसरे की पक्षी दो'। श्रीद्धी का हिन्दी-मराठी वैमानिक दो रंगों में मोटे टाइप के लोको पर छापा जाता था और प्रति भक की एक सप्तक प्रतिपाद्य होती थी। शेष साहित्य नी पाठकों की सत्ता में उपयुक्त मुद्रण पद्धति से छपता था।

मार्ग सरकार ने नव साक्षरों के साहित्य-सृजन को प्रोत्साहित करने के विचार से नीचे तिली योजनाएँ शुरू की थी :

(१) १९५० में शिक्षा मन्त्रालय ने द्वारा तालीम-ओ तरकमी नई दिल्ली का अधिक सहायता देकर पुस्तकें तैयार करायीं। अस्था में १७० पुस्तकें तैयार कीं, जिसमें से प्रत्येक की दस हजार प्रतियाँ छापी गयीं। इन पुस्तकों की प्रतियाँ राज्य सरकारों की बाँटी गयीं ताकि वे अपनी भाषाओं में पक्षी पुस्तकें तैयार कर सकें।

(२) १९५३ में शिक्षा मन्त्रालय ने साहित्य दिवस

(विशेषी वाचाल) स्वादिष्ट निम्न ताहि नव मान्यो के निम्न माहृष्ट्य हेतु नवन नाम सेगको को प्रविणितु निम्न या मने । इन निम्नानि नर हो । याना नुन भव्य पारा करदार न ह्वा जगवा । नमन विमिन स्वाना नर १६७८ तक १३ निम्नर अमोचित निम्न नमन । प्रत्येक निम्नर में १० सेगको को न निम्न दी यानो या ।

(३) १९५४ में पिना राजस्थान के तब मालको के विप प्रमुख भारतीय भाषाओं में रचित सर्वोच्च साहित्य को प्रस्तुत करने के विचार से एक पाठ्यक्रम शुरू की थी। इस योजना अद्य भी चले रही है। इसके अन्तर्गत प्रति वर्ष पाँच-पाँच से नवह तक गुरुवारों पर आयोजित हैं। योजना को चलते हुए १८ आयोजित हो चुके हैं। इसको को गुरुवार देते के अनुरोध अथवा गुरुवार। सुमन की १९वीं प्रतियाँ गुरुवार दिनांक विवरण में दिए गये हैं।

[illegible]

(२) भारत सरकार की प्राथमिक तद्गतता से निजी सहायता न ही दी जा सके व पुनः प्रशासन की है। इनके मुख्य ॥ राजा मरीचर (राज मरीच) और हिमालय विजयराज (राज मरीच) हैं। व दोनों विषयकोष हैं।

(६) १९५७ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक योजना की स्थापना इस अभिप्राय से की थी कि पहले सभी में साक्षरता सहायता पुस्तकालयों और सचिवालयों को राष्ट्रीय पुस्तक योजना हो सके।

१६५१ में भारत में वेने लोगो का प्रतिष्ठान १६९५ का
को केतव गठ निज सरो ये । १६६१ अ यह प्रतिष्ठान
२४० पुत्रा ओर १६७१ में २६४४ । पञ्चवर्षीय को
नामो के मतपत्र प्रीट निजस को तीस प्रगति हुई है ।
१६६१ ७१ के बीच १५-२४ साधु वष के साधार स्त्री
पुत्रा को सप्रा १७६६ करोड की है । पृथिवी कोनस

के अन्वयन शीघ्र सिखा के निदे देते बरौद लाप का
 प्राथमान है जब कि शीघ्री योजना में यह प्राथमान ८
 बरौद भव्य हो गा ।

श्री ११११ का दायित्व राय सरदारों का है तो श्री
कृष्णजीय। वाचन प्रारम्भ होता है कुछ वरके
उत्तर के लिए आरंभ होना है। ८१ को मंगल
२०० वर्षीय मन्त्रों श्री ११११ व ११११ व ११११
प्राप्त है।

विष्णु के पुत्र यशो के श्री गंगा न भापवना से
स सारना प्रसार पर उतना इन गद्दी सिद्धा प्रह्लाद
जिन्ना तृनिमयक गद्दी विद्या पर श्री विद्यापियों के
गवनाम रहत छह और उतक समाज की विवरन मूलक
भाषा-महनामो ॥ मधुप्र हो ॥

वायस एजन्सल लिटरेसी प्रोडस १९१७-१८ में पाठ्यपुस्तक योजना के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। इनके सलाह पर निम्नलिखित विचारों को ग्राह्य करने के लिए ही माध्यमिक स्तर की शिक्षा में समावेश किया गया था।
 १. लैटिन इनके माध्यम में। २. हिंदी उच्चारण बढ़ाया जा सके।
 यह योजना कृषि, वन्यजीव, मूलभूत और प्रसार मंत्रालय तथा विज्ञान विभाग द्वारा १९१७-१८ में तैयार की गई थी।
 १९३८-३९ में इनके माध्यम के १५ भागों की योजना को १५ में बढ़ाया गया था।

[illegible]

उपयुक्त विधि न अवलोकनार्थक विद्या काव्य आशासे
 व सिद्ध उपयुक्त साहित्य की आवश्यकता निम्नतर बहती
 जा रही है। ऐसे साहित्य व विद्या और प्रकाशन
 निम्न उपयुक्त लक्ष्य के साथ साथ निम्न शक्ति व जो
 अभियान चलाये जाने चाहिये। एक बार साक्षर हो जाने
 के बाद ऐसे ही उपयुक्त पुन निरचरता व अघरे से न
 दब जाये। एक विधि यह उपयुक्त लक्ष्य सामग्री तथा
 तार मिलनी चाहिये। योही व सिद्ध उपयुक्त साहित्य की
 आवश्यकता बहती जायगी और यह आवश्यक होगा कि
 ऐसे साहित्य के निरचरता की सुवाद व्यवस्था की जाय और
 आवश्यकतानुसार चले और अन्तर्गत पुस्तकालय स्थापित
 किये जाय।

हमें स्कूल क्यों समाप्त करना है

अनुवादक—देवेन्द्रसिंह सिन्धु

[इसका इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक 'डी-स्कूलिंग घोषाद्वयी' का अनुवाद हम प्रमत्त मधी लाओम मे इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं कि इसका इतिहास के विचार साधोवादी विचार-धारा से मिलते-जुलते हैं। यह अनुवाद सर्वाधिकार सुरक्षित है।] [मतास से आगे]

यह सब निर्णय तथा समूह राष्ट्रों दोनों ही के लिए है, किन्तु दोनों ये यह विभिन्न रूपों में व्यक्त होता है। ज्ञान की नये प्रकार की गुरीबी निर्णय राष्ट्रों में अधिकतर लोगों को अधिक प्रत्यक्ष रूप में किन्तु अधिक इसके रूप में प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए लैटिन अमरीका में दो तिहाई बच्चे पाँचवी कक्षा पास किये बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। किन्तु स्कूल छोड़ने वाले इन बच्चों की वह बुद्धि नहीं होती जो सामान्य राष्ट्र अमरीका में होती है।

मान बुनिया में बहुत कम राष्ट्र ऐसे हैं जो पुराने प्रकार की गरीबी के विचार हैं वह गरीबी अधि टिकाऊ किन्तु कम प्रभावितों से बरी हुई होती भी। लैटिन अमरीका के बहुत से देश आर्थिक विज्ञान तथा प्रतिपत्ति को बिना में अक्षर हो चुके हैं जबकि ज्ञान की नयी गरीबी की ओर बढ़ चुके हैं। वहाँ के नागरिकों में अमीरों की तरह सोचना और गरीबों की तरह बिना रहना सीखा गया है। वहाँ के कानूनों के अनुसार १ से १८ वर्ष तक की स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। न केवल अमेरिका दक्षिण अमेरिका का ज्ञान में भी व्यापार लक्ष्य करती अमेरिका के पड़ोसों से पर्याप्त शिक्षा की परिभाषा करता है, यद्यपि अमरीका जैसी लम्बी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर बहुत कम सम्प्रा में कुछ लोगों को मिलेगा। इन देशों में अधिकतर रूप में लोग स्कूल-प्रति हो चुके हैं, मगर उनमें उन लोगों के सदृश में हीन भावना । पृथ्वी है किन्हीं बच्चों स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की बुद्धि है। स्कूली शिक्षा के लिए उनका पाठ्यपत्र उनके सोहे सोपान की बुद्धि से तैयार करता है : एक तो

इससे कुछ घुने हुए लोगों की शिक्षा के लिए निरक्षर अधिनायक सावर्जनिक धनराशि की व्यवस्था की जाती है और दूसरे अधिकांश लोग इस प्रकार के सामाजिक नियमों के प्रति अपनी अधिकाधिक स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह एक विचित्र स्थिति है कि यह विश्वास कि सर्व-साम शिक्षा सर्वथा आवश्यक या अनिवार्य है, उन देशों में अधिक दृढ़ है जिनमें बहुत कम लोग स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके हैं या कर सके हैं। फिर भी लैटिन अमरीका में अधिकांश अधिनायक और बच्चे स्कूली शिक्षा के विभिन्न रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं। अनुपाततः राष्ट्रीय बचत की वह धनराशि जो इन देशों के स्कूलों और विद्यालयों पर खर्च की जाती है, समूह देशों की तुलना में अधिक होती किन्तु यह धनराशि अधिकांश लोगों के लिए पार वर्ष की भी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए निरक्षर अवस्थित है। फीदेल कास्ट्रो (Fidel Castro) ऐसा समझते हैं कि वे स्कूल-विहीनता की ओर जाना चाहते हैं जब वे यह वास्तविकता देखते हैं कि १९८० तक बच्चा में विद्वानिवालय समाप्त हो जाएगा क्योंकि बच्चा में पुरा जीवन ही एक धार्मिक अनुभव होगा। किन्तु बच्चा अन्य लैटिन अमरीका के देशों की तरह, ग्रामर और हाई स्कूल स्तर पर, ऐसे नाम कर रहा है जैसे एक परि-यापित 'स्कूली छात्र' की व्यवधि से पुनर्जात सभी के लिए निर्विवाद लक्ष्य निश्चित विद्या गया हो और यह लक्ष्य केवल छात्रों के अज्ञान के कारण विलम्बित हो रहा हो।

बहुते हुए इसकाय के दो धोखे—एक जैसा वास्तव में अमरीका में है और दूसरा जैसा लैटिन अमरीका में आका-

जित सपना आशयित हैं—एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तरी अमरीका के गरीब बारह वर्ष के इलाज से सही तरह पब्लिक हैं जिसकी कमी के कारण सेंटिन अमरीका के गरीब देश विद्यार्थी समझे जाते हैं। न तो उत्तरी अमरीका में और न सेंटिन अमरीका में गरीबों को अनिवार्य स्कूलों में प्रवेश मिल पाती है। लेकिन दोनों स्थानों में स्कूल के अतिरिक्त के कारण ही गरीब अपनी शिक्षा पर निरभर नहीं रह पाता और हतोत्साह तथा मजबूर हो जाता है, हाथमेलिक शिक्षा का इलाज प्राप्त करने के लिए विषय में सभी अवस्था तथा पर स्कूल का प्रभाव शिक्षा विरोधी है। स्कूल को यह माना जाता है कि यह शिक्षा में विशेषज्ञता रखता है। स्कूल की असफलता को सीधे इस बात का प्रमाण समझते हैं कि शिक्षा बहुत कीमती है, बहुत पेशीबी है, खर्च रहस्यमय है और बहुधा दुष्प्रभाव है।

स्कूल सेवा केन्द्र है, उसमें आदमी लगते हैं और शिक्षा के प्रति जो सम्भावना है उसको भी लता है। साथ ही अन्य समस्याओं की सीमा कार्य करने के प्रति हतोत्साहित करता है। काम, मजदूरी, राजनीति, गृहरी जीवन यह सब कि पारिवारिक जीवन पूर्व निर्धारित आदतों और ज्ञान के निरूपणों पर निर्भर करता है, बचपन इसका कि ये सब सब शिक्षा के साधन बन जायें। एक साथ ही स्कूली तथा उन समस्याओं का मुख्य जो स्कूलों पर निर्भर करती है बाजार से बाहर लगाया जाता है अर्थात् बाह्यिक आवश्यकताओं से उनका सम्बन्ध नहीं रहता।

अमरीका में प्रति व्यक्ति स्कूली शिक्षा का खर्च सती तेजी से बढ़ा है जिस तेजी से भविष्य का। लेकिन बाहरों तथा शिक्षकों द्वारा जो जड़ता हुआ इलाज है उसमें परिणाम भी बड़े ही प्रतिकूल है। पिछले वर्षों में ४२ वर्ष से ऊपर की उम्र वाले पर विविधता के व्यवसाय गुना बढ़ा है जबकि प्रचाराय से आयु केवल ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संसिक खर्च से वृद्धि के विषय परिणाम हुए हैं। अन्यथा प्रसिद्ध निगम को १९७० को यह आवश्यकता देने के लिए बाध्य होना पड़ता कि प्रत्येक बच्चे को बीस हो पढ़ने का अधिकार (Right to Read) स्कूल छोड़ने के पूर्व मिलेगा।

अमरीका में यह शिक्षा के लिए जिसमें शिक्षकों के अनुसार काम तथा हार्ड स्कूल में सबसे समान शिक्षा विधेयी, प्रतिवर्ष ८०० अरब डॉलर (१ डॉलर = लगभग ८५०) की आवश्यकता पड़ेगी। यह ३६० अरब डॉलर की उच्च धनराशि दुनिया है जो इस पर खर्च किया जा रहा है। स्वाभाविक, शिक्षा तथा कल्याण विभाग और पतोरिहा विनविद्यालय के द्वारा तैयार किये गए स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार वर्तमान ४२० अरब डॉलर के अनुमानों के स्थान पर १६७४ तक यह धनराशि १०० अरब डॉलर हो जायेगी। इन आंकड़ों से यह बड़ा भारी व्यय नहीं सम्मिलित है जिसे 'उच्च शिक्षा' कहा जाता है और जिसके लिए भाग बड़ी तीव्रता से बढ़ रहे हैं। अमरीका, जिसने १९६६ में लगभग ८०० अरब डॉलर 'प्रतिरक्षा' पर खर्च किये थे, जिसमें विद्यार्थियों की लड़ाई का व्यय भी सम्मिलित है, लगभग एक ही शिक्षा खर्च के लिए बाह्य में खर्च है। स्कूली खर्च-व्यय के लिए नियुक्त राष्ट्रपति की समिति को यह पूछने का बचाव कि कैसे पहले हुए खर्च का प्रबन्ध किया जा सकता है या कीते से कम किया जा सकता है, यह पूछना चाहिए कि इस खर्च से क्या जा सकता है।

कम से कम यह तो मानना ही पड़ेगा कि अनिवार्य समान स्कूली शिक्षा अधिक दृष्टि से समान नहीं है। लेकिन अमरीका में प्रत्येक 'पेंसिल' विद्यार्थी पर उच्च धनराशि का ३६० से १२०० गुना आर्थिक धन व्यय किया जाता है जो उच्च साधारण आगरिक पर व्यय होता है जो विनियम तथा सम्प्रदाय के बीच में स्थित है। अमरीका में अन्तर कम है किन्तु वेद अधिक है। सम्प्रदाय सम्प्रदाय १० प्रतिशत अनिवार्य बच्चे बच्चे के लिए प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं और वास्तविक अनुदानों में उनकी सहायता करते हैं। इस अतिरिक्त वे आधुनिक धनराशि के प्रति सालक १० गुना अधिक प्राप्त करते हैं' यदि विनियम १० प्रतिशत बच्चों पर किए गए प्रति मानक खर्च से उसकी तुलना की जाए। इससे मुख्य कारण यह है कि बाकी बच्चे सभी अवधि तक स्कूल में रहते हैं' विनविद्यालय को शिक्षा का एक बड़े स्कूली शिक्षा के एक वर्ष से बेहतर अधिक खर्चा होता है, और अधिकांश

प्राप्त होते हैं जैसे पुराने समय में दीक्षा के कर्मनाम्न और सम्पन्न परोपकारिता हुआ करता था। आधुनिक राज्य ने यह धार्मिक अपने ऊपर ली। सिवा है कि वह अच्छे हरादे वाले आचार्य अधिचारियों और काम की आवश्यकताओं के माध्यम में अपने शिक्षार्थों के निर्णय को लोगों के ऊपर उसी तरह से मारें जैसे स्पेन के राजा अपने धर्म-दासियों को विवेकाओं तथा धार्मिक स्वाध्यायों के माध्यम से पर्ववन्ती लावा करते थे।

बी सतावी पुर्व अमरीका में एक वर्ष के एकाधिकार को समाप्त करने के आन्दोलन में विश्व का नेतृत्व किया था। अब हमें स्मृत के एकाधिकार को सर्वधार्मिक रूप के समाप्त करने की आवश्यकता है जिससे एक ऐसी व्यवस्था समाप्त हो सके जो पलायन को भेदभाव के विषाक्त सम्बन्ध करती है। आधुनिक राजकीय समाज के अधिकारों के मानन की पहली चारा कुछ बंधों ही होती होती। अमरीका के संविधान के प्रथम संशोधन में है 'शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया जा सके' सिवा कोई अनिवार्य प्रणाली नहीं होगी।

स्कूल की इस प्रकार समाधि को प्रभावी बनाने के लिए हमें कानून की आवश्यकता है जो ऐसे शासकों के को-ही में, जो किसी पाठ्यक्रम की पूर्ण उपस्थिति पर आधारित होते हैं किया है। भेदभाव मतदान या प्रवेश को रोकित करे। इस कारण का मय यह न होना कि किसी विशेष कार्य या भूमिका को लिए योग्यता सम्बन्धी नियामक प्रतीति न हो जाए। लेकिन इससे यह अवश्य होना कि इस समय ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसने सर्वांगिक सामाजिक भवन वर्षों के कोई कोशिश प्राप्त कर लिया है या जैसा सर्वथा सम्भव है, जिसने एक दिल्पोषा प्राप्त कर लिया है जिसका सम्बन्धित कोशल या काम से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो अक्षय्य पक्षपात है कि वह सम्भव हो जाए। जब नागरिकों को यह कारण मिलेगा स्कूल के जीवन की किसी बात से यह काम के अवश्य न जाना जाएगा, तभी स्कूल की धार्मिक समाधि मनोबैज्ञानिक दृष्टि से प्रभावी होगी।

स्कूलों शिक्षा से न तो ज्ञान बढ़ता है और न न्याय की प्रतीति होती है क्योंकि शिक्षा के लिए को प्रमाणपत्रों

में सपेटते हैं। सामाजिक तथा सामाजिक भूमिका की निम्नकारी स्मृति शिक्षा में विरोध हो जाती है। सीसने का अर्थ यह है कि कोई नया कोशल या नवी दृष्टि प्राप्त की जाय, जब कि क्लोप्रति उस अस्मिता पर निर्भर करती है जो दूसरों का है। बारबार सीसना शिक्षा का परिणाम है किन्तु काम के कारण में निती वर्ष या भूमिका के लिए चुनाव अधिकारिक उपस्थिति की सहाई पर निर्भर करता है।

सहाय्य उन परिस्थितियों का चुनाव है जो सामाजिक में सहाय्य होती है। परिस्थितियों का वाद्यक्रम बनाकर भूमिका निर्धारित की जाती है। इन परिस्थितियों को विचार्यों को भगना है यदि उसे क्लोप्रति चाहिए। स्कूल इन भूमिकाओं, सीसने को नहीं, शिक्षा को जोड़ता है। न तो यह तर्क सत्य है और न प्रतिपक्ष। सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह सम्बन्धित गुणों का योग्यता को भूमिका से नहीं जोड़ता, बल्कि उस प्रक्रिया को जोड़ता है जिससे यह समझ आता है कि वे कुछ अतिरिक्त गिने जाते हैं। यह प्रतिपक्ष या सीसने नहीं है क्योंकि स्कूल जनताओं के लिए शिक्षा सुरक्षित रखता है जिसका सीसने का हर एक कदम सामाजिक नियमों की पूर्णानुबोधित प्रणाली के अनुकूल होता है।

वाद्य क्रम का प्रयोग सर्वदा सामाजिक भेद-निर्धारण के लिए हुआ है। कभी-कभी ऐसा काम के पूर्व भी होता है। काम हमें किसी जाति या सम्पन्न वंश-परम्परा के जोड़ता है। पाठ्यक्रम एक कर्मकाण्ड का रूप ले सकता है, या कर्मबद्ध पवित्र रीतियों का, अथवा युद्ध या शिकार में निरन्तर बढ़ादुरी के कारणों का अथवा प्रत्येक पूर्व की राजकुमारों पर निर्भर प्रदति भी हो सकती है। सामाजिक स्कूलों शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन के इतिहास से भूमिका निर्धारण को अनवरत करना था। इसका उद्देश्य यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक वर के लिए समान अवसर मिले। अब भी बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि स्कूल इस बात को निर्धारित करता है कि सम्बद्ध व्यक्ति उपलब्धियों पर कदम का विश्वास रहे। किन्तु अब-

सरो को समान करत ने बलाय स्त्री की व्यवस्था ने उन पर
एवाधिकार कर दिया है ।

पाठ्यक्रम से योग्यता को अलग करने के लिए, अनुप्य
के सीखने की इतिहास की जीव को निषिद्ध कर देता
बाह्ये जैसे उसके राजनीतिक प्रभाव, गिरिजाधर ने उप-
स्थिति, दश परम्परा, दान रचनाय या जातिगत वृद्धि
के बारे में प्रस्ताव नहीं को धाती । ऐसे कानून बनने
बाह्ये जिनमें पूर्वाज्ञित स्त्री शिक्षा पर आधारित भेद-
भाव बलित हो । यह ठीक है कि कानून उसके प्रति पूर्वा-
ग्रह को नहीं समाप्त कर सकते जिन्ने स्त्री शिक्षा नहीं
मात की है और न उनका सहोदय यह है कि वे किसी काठिन्य
से विवाह करने के लिए किसी को बाध्य करें । किन्तु वे
अनुचित भेदभाव को निरस्तहित कर सकते हैं ।

एक दूसरा प्रमुख भ्रम जिसपर स्त्री व्यवस्था निर्भर
करती है, यह है कि बहुत सा सोजना शिक्षा का परित्याग
है । यह ठीक है कि शिक्षा विशेष प्रकार के जावाजन में
सहाय्य हो लेकिन अधिकतर लोग अपनी अधिकतर ज्ञान

स्कूल में बाहर प्राप्त करते हैं जहाँ जैसा कुछ समुदाय देशों
में है स्कूल उनके अधिकांश जीवन के लिए पर्याप्त के
स्थान हो गए हैं ।

अधिकतर जीवन आवश्यक होता है और अत्यंत
सोचदेख प्रभावार्जन को शिक्षा कार्यक्रमित परित्याग
नहीं है । सामान्य बच्चे अपनी प्रथम भाषा आत्मिक
वय में सीखते हैं, और यदि मा-बाप उनके ऊपर ध्यान
देते हैं तो और सीघ्रता से सीखते हैं । बहुत से लोग जो
बुझी भाषा अच्छी तरह सीखते हैं वे विविध परिस्थि-
तियों के परिणामस्वरूप सीख पाते हैं, न कि प्रमत्त
शिक्षण के कारण । ऐसे लोग अपने पितामह के पास रहने
प्ये जाते हैं, या वे यात्रा करते हैं अथवा किसी विदेशी
से प्रेम करने लगते हैं । पढ़ने में प्रवाह को बहुधा ऐसी
पाठ्यपुस्तक शिक्षा का परित्याग होता है । बहुत से लोग
जो व्यापक रूप से पढ़ते हैं और ज्ञान के लिए पढ़ते हैं,
यह सोचते हैं कि ऐसा पढ़ना उन्होंने स्कूल में सीखा ।
किन्तु जब उनमें प्रश्न किया जाता है, तो उनका यह भ्रम
दूर हो जाता है ।

कमल



आदरणीय धीरेन्द्र की स्मृति में

विनोद

भाप कोशों ने सायद वेयर में जड़ा होगा, धीरेन्द्र दा की मृत्यु हुई। धीरेन्द्र दा को शोक नहीं आया? वे विनोद में कहते थे कि बाबा से मैं एक दिन बड़ा हुआ और मैं बाल छोटा हूँ। एक दिन का मतलब है कि बाबा का जन्मदिन ११ सितम्बर का है और उनका १० सितम्बर का है। बाबा ने बर्ष पूर्ण करके ८५ में प्रवेश कर रखा है। धीरेन्द्र दा की ११-१२-१३ के गये। कृष्णराज उनसे मिलने १८ तारीख को गया था। शाम को एक घण्टा भर उनके बात की और उठी बत्ती उन्होंने कह दिया कि 'बाबा की मेरी प्रणाम कह देना।' उसके बाद १९ तारीख को वे बेहोश हो गए और २१ तारीख को गए। कीर्ति-कीर्ति ७८ की उम्र थी। कम तोड़ करके वे चले गए। इस प्रकार कम होकर भीमन् की भी गए। कम तोड़ने वालों का क्रम तोड़ना जारी है। मैं समझ करता हूँ कि यहाँ कोई कम नहीं होवेगा। धीरेन्द्र दा तो बाबा के साथ बरसों रहे। एक ॥ बाद एक साथी छोड़े जा रहे हैं। हमको सबको बाबा है ही, यह उनकी बात है। लेकिन आने के पहले प्रार्थनाप्रार्थना करने जाना चाहिए। बाबा तो रोक धुप का पूर्ण प्रयोग होने से पहले करता है और भगवान से कहता है, मैं सुखी से तेरे पास आऊंगा। अगर तू मुझे इसका काम देना तो मैं सेवा करता, ऐसी प्रार्थना से रोक करता हूँ। इसलिए हर एक को जाना छोड़े ही है।

धीरेन्द्र दा ने बहुत बड़ी बात कही है—'अति भी नहीं जाती, होती है।' और रचनात्मक काम, सेवा-कार्य करते रहना चाहिए। एक-एक जिला लेकर उसमें सब तरह का रचनात्मक कार्य करता चाहिए। इसको उन्होंने मार्गकोश नाम दिया है। गाँव के लोगों के पास हमको जाना चाहिए। उनके पास जो ज्ञान है वह उनको परम्परा से प्राप्त हुआ है। वे निरन्तर तो हैं लेकिन निरन्तर होने

पर भी निरन्तर नहीं, मार्गक हैं। उनके पास आकर हम-को काम करना चाहिए। इस तरह एक-एक जिला लेकर काम करेंगे तो हमको मार्ग मिलेगा।

धीरेन्द्र दा मार्ग सोचते-सोचते गए। १८ तारीख को 'बाबा से प्रणाम कह दो' कहना और १९ तारीख को बेहोश हो जाना, २१ तारीख को चले जाना। यह छोटी बात नहीं है कि जगत में प्रणाम कहकर चले जाना। [बाबा का क्या घर जाता है और आए रहते हैं]।

भगवान सबको सन्तति दे, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने निरन्तर सत्कार्य किया है।

उनकी मृत्यु से बाबा की बुद्धि बरकर हुआ इसलिए कि वे बाबा के पहले चले गए। (अथ) वास्तव में बाबा को पहले जाना था, उनकी बात में जाना था। इसलिए बुद्धि हुआ। लेकिन जिसका प्रारम्भ समय होता है उसको जाना ही पड़ता है। धीरेन्द्र दा की सन्तति मिलेगी और वे भगवान के पास निरन्तर रहेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं।

दो शब्द हैं—क्याचित्नाह, क्याचित्नाह। फल फलनाह यात्री भगवान ने फल हो जाना। क्याचित्नाह यात्री जानी रहता, भगवान के साथ बातचीत करना। ऐसे धीरेन्द्र दा भगवान के साथ बातचीत करते हैं। हम जितने साथी हैं वे सब भिन्न-भिन्न के भगवान के पास बैठकर के बातचीत करेंगे। जैसी जगह वहाँ बैठकर हो रही है वैसे ही बैठकर वहाँ होथे। बाबा ने जाहिर ही किया है 'जैसी कारनामी कदा'—हिन्दी में उसे कहा जाता है। भगवान के पास पहुँचकर फिर दुनिया की सेवा ॥ लिए ऊपर से नीचे जाना। अखिल बाबा है—'हरिता जग तो मुक्ति न माये।' (अथ) हरि के लेकर मुक्ति नहीं मांगते। बुद्धराज महाराज ने कही कहा है—'न सगे मुक्ति न

सम्पदा, तुका हमने पसंदाओ सुखें घासाये आम्हाही ।' मुक्ति मागते नहीं, सत्पथ की इच्छा करते हैं और केवल मक्ति की कामना करते हैं। यही लिखा है अमरिषा में, 'मुक्ति निस्पृह जितो' । (यथु) नामधेया का पहला श्लोक है—'जो मुक्ति की कामना करने नहीं, रसमय भाषो हो भवति।' इस मक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते नहीं। मक्ति रसमय है। तो बाबा ने जो बात किया है—बाबा मरेगा, शान्त नहीं कब मरेगा, जब आरम्भ क्षण होगा जब मर जाएगा। मरेगा तो ऊपर जाएगा। 'नक्षत्रवेगिनंक्षत्रो' में

मिल जाएगा।

धोरेन मार्द वा मुख्य विचार वा, मार्गलोचन करना। तो सब लोग एक-एक जिला लेकर गांव-गांव में जाकर लोगों के पास पहुँचें और उनको एक परिवार बनाने की बात कहें। इसी मार्ग वा चिन्तन मनन करें तो यह मार्ग खोजन की प्रक्रिया हम सबको, जो जीवित हैं उन सबको करनी चाहिए।

अब इसके बाद दो मिनट भोज होगा और फिर विष्णु-सहस्रनाम का पाठ होगा।

१७-२२

प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र

(कोठारी आयोग की रिपोर्ट से)

17.1 स्कूल की पढ़ाई के साथ ही शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि यह एक जीवन-व्यापी प्रक्रिया है। आज के समय की तेजी से बदलते हुए संसार और समाज की बढ़ती हुई जटिलताओं की सम्पन्ने की आवश्यकता है। जो लोग परिष्कृततम शिक्षा पा चुके हैं, उन्हें भी लगातार सीखते रहने की जरूरत है, अन्यथा वे पिछड़ जाएंगे।

17.2 उच्च समाज की, जो आर्थिक विकास, सामाजिक क्रान्ति और प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति करने का निश्चय कर चुका हो, कार्यनीति का मुख्य आधार यह होता है कि यह अपने नागरिकों की विकास-कार्यक्रमों में स्वयं अपनी इच्छा से स्विकृत्य और कुशलता से भाग लेने की शिक्षा दे। उच्च समाज में तो ऐसा करना विशेष रूप से आवश्यक हो जाता है—जहाँ बहुव्यक्त श्रेणियों में न पड़ सके हों और जो शिक्षा की जा रही हो उसकी तात्तव्य विकास की जरूरतों से न भँझती हो। जमीन जोतने वाले किसानों को अपनी जमीन या मशीन चलाने वाले कामगारों को अपनी मशीन की विशेषता समझ लेनी होगी और उत्पादन सम्बन्धी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की कुछ जानकारी प्राप्त कर लेनी होगी

ताकि वह सफ़र तरीके अपना सके और उनमें सुधार कर सके। अनुसूच-विनय या जोर-जबरदस्ती मात्र तो बढ़ती हुई अवस्था को नहीं रोका जा सकता। लोगों को लगातार बढ़ती हुई जन संख्या के परिणाम समझने होंगे, जीवन के नियमों की जानकारी प्राप्त करनी होगी और परिवार-नियोजन के कार्यक्रमों के प्रति अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझनी होगी। कोई भी राष्ट्र केवल पुष्टि और सेवा पर अपनी सुरक्षा का धार नहीं छोड़ सकता, राष्ट्र की सुरक्षा बड़ी सीमा तक उसकी जनता की शिक्षा, गतिविधियों के बारे में उसकी जानकारी, परिण और अनुशासन की भावना तथा सुरक्षात्मक उपायों में प्रभावकारी रूप से भाग लेने की उसकी योग्यता पर निर्भर होती है।

17.3. इस दृष्टि से, प्रशासन में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य यह है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दे जिस प्रकार की शिक्षा वह चाहता है और जो उसकी व्यक्तिगत समृद्धि, व्यावसायिक प्रगति तथा सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रभावकारी रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक हो।

17.4 सामान्य स्थितियों में प्रौढ़ शिक्षा ने कार्यक्रम यह मानकर बनाए जाते हैं कि सभी लोग साक्षर हों। पर भारत में, जहाँ 70 प्रतिशत लोग पढ़ लिख भी नहीं सकते, निरक्षरता को समाप्त करना स्वभावतः राष्ट्रीय चिन्ता का तारकालिक विषय बन गया है।

17.5 प्रौढ़ शिक्षा का रोज बहुत विस्तृत है—इतना विस्तृत जितना कि स्वयं जीवन है। इससे आपसबताए सामान्य स्कूली पढ़ाई से भिन्न है। यह इस पर विचार है कि अनेक एजेंसियों में, विशेषकर विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थाओं और पुस्तकालयों में उसे कितनी सहायता मिलती है। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रभावकारिता प्राप्त प्रशासन तन्त्र पर निर्भर होती है।

17.6 भारत में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें होनी चाहिए

- निरीक्षण का निरूपण,
 - निरंतर शिक्षा,
 - प्रशासनिक पाठ्यक्रम,
 - पुस्तकालय,
 - प्रौढ़ शिक्षा में विश्वविद्यालयों का योगदान, और
 - प्रौढ़ शिक्षा का संगठन और प्रशासन।
- इस अध्याय में हम इनकी चर्चा करेंगे।

निरक्षरता का निर्मूलन

17.7 कार्रवाई की आवश्यकता—360 करोड़ निरक्षर और बड़ जान से सन् 1951 की अंशेला सन् 1961 में भारत में निरक्षर हो गया था। सन् 1966 में सन् 1961 की अंशेला 2 करोड़ निरक्षर और बड़ था। प्राथमिक शिक्षा के अक्षतपुत्र निरक्षर और अनेक साक्षरता अभियानों और कार्यक्रमों के बावजूद ऐसा हुआ है। यद्यपि साक्षरता का प्रतिशत सन् 1951 में 16.6 से बढ़कर सन् 1961 में 24 और सन् 1966 में 28.6 हो गया है तो भी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने सर्वप्रथम साक्षरता के अक्षय की प्राप्ति के अवसरों में देर की और पीछे चलेते विषय है इसके जो शिक्षा मिलती है वह स्पष्ट है, कि साक्षरता को हस्तगत से बढ़ाने के

परम्परागत तरीके लगभग व्यर्थ हैं। यदि इस प्रवृत्ति को बदलना है तो गंभीरता से सामुहिक राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत है।

17.8 निरक्षरता के लिए व्यक्ति को, और राष्ट्र को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यद्यपि बहु, इस निरन्तर व्यक्ति का व्यय हो जाता है और उससे होने वाली हानि के प्रति जड़ हो जाता है। आयुर्विज्ञान जीवन की परिस्थितियों से निरक्षरता को निरक्षरता ठहरा कर उसे होने जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर देती है। उसके लिए उचित वास्तविकता की कोई समाधान नहीं पड़ती। प्रजातान्त्रिक सरकार और वाणिज्य बजार जैसी परिष्कृत सामाजिक प्रक्रियाओं से वह अलग-थलग पड़ जाता है। अनपढ़ व्यक्ति, वास्तव में, स्वतन्त्र नागरिक नहीं है। सामुहिक प्रक्रिया के रूप में निरक्षरता व्यक्ति और सामाजिक प्रवृत्ति को अक्षत कर देती है तथा व्यक्ति उत्पादित, जनसंख्या, निरक्षरता, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और सफाई के सुधार को दुष्प्रभावित करती है। योजना आयोग के सदस्य, प्रो० बी० के० सार० बी० राय के शब्दों में, "प्रौढ़ शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता के बिना न तो उस विस्तार और गति में व्यक्ति और सामाजिक विकास संभव है जिसकी हम आवश्यकता है, और न ही हमारे व्यक्ति और सामाजिक विकास को वह तत्त्व, गुणानुकूलता अथवा शक्ति मिल सकती है जो मूल्य और हितकारिता की दृष्टि से उसे सार्थक बनाए। इसीलिए, व्यक्ति और सामाजिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता को प्रथम स्थान मिलना चाहिए।"

17.9 उपयुक्त सामाजिक संस्थाओं से मदद लेनी पड़ती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले भी किसी न किसी रूप में, इन्हें स्वीकार किया जाता था। पर इस विषय में अब तक जो मुख्य कार्यसूची अपनाई गई है वह यह है कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के अवश्य के विचार पर ही बन दिया जाए। यदि इसे प्रशासकीय ढंग से सन् 1960 तक कार्यान्वित किया जा सके, जसा कि एक बार समझा गया था तो वह समस्या बहुत घटती हो जाती। पर

अनेक कारणों से, जिनकी व्याख्या सम्भव नहीं है, अभी तक यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हो सका है और हम अधिकारिक सन् 1976 तक प्रत्येक वर्षों को पाच वर्षों की ओर सन् 1986 तक सात वर्षों की प्रभावकारी शिक्षा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा की पद्धति अभी तक अधिकांशतः प्रभाव शून्य और निष्फल ही रही है। बहुत से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने या तो काम चलाने योग्य साक्षरता प्राप्त नहीं कर पाते या बाद में प्रीम ही किए निरक्षर हो जाते हैं। निरक्षरता को समाप्त करने के लिए यदि हम केवल इसी कार्यक्रम पर निर्भर रहे तो सन् 2000 तक भी इस सदय को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि अब हमें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम के विकास के लिए बड़े पैमाने के बुट बनाना चाहिए और सामूहिक निरक्षरता के निवारण के लिए गणक और सीमा अभियान करना चाहिए।

17.10 अभिप्राय यह नहीं है कि सामूहिक निरक्षरता के निवारण के लिए अब तक सीमा कार्यक्रमों किया ही नहीं गया। माल्द ने, प्रोड शिक्षा के निम्नलिखित चरणों के इतिहास से पता चलता है कि राज्यों के वा स्थायी आधार पर अनेक साक्षरता अभियान बड़े पैमाने से संचालित किए गए थे पर कुछ वर्ष बाद उदासीनता और प्रयत्न-मरहा के कारण विफल गए। इसके अनेक कारण हैं। वे अभियान इतने छोटे पैमाने पर चलाए गए थे कि उनके आधार पर निरिपक्ष प्रगति नहीं हो सकती थी और न ही वे बड़े प्रयास के लिए प्रेरणास्पद थे। वे छुटपुट अभियान थे जिनमें समन्वय का अभाव था—सरकारी विभाग, स्वैच्छिक एजेंसियां, शिक्षा संस्थाएं और व्यक्ति एक-दूसरे से मिलकर काम करने के बदे अधिकतर अपना ही राग जमावते थे। वे अभियान प्रायः अस्थायी थे शुरू किए जाते थे—प्रौढों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यानपूर्वक समझे बिना, जगता में शिक्षा के प्रति रुचि या पढ़न लिखने की सामान्य व्यापक विना, और अनुवर्ती कार्य की पर्याप्त व्यवस्था किए बिना, अगला में कोई स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसीलिए वे निरर्थक रहे और यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

17.11 साक्षरता-कार्यक्रमों का दीर्घकालीन समर्थन और उन्हें सोहोष्य बनाना इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ बुनियादी तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाए। उदाहरणार्थ, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि निरक्षर लोगों की भारी संख्या, जिसमें ही कार्यक्रमों पर तैयार होता है, औद्योगिकरण और कृषि के औद्योगिकीकरण की गति और सामान्यतः देश की आर्थिक प्रगति को अवरोध कर देती है। यदि यह मान लें कि 15—44 वर्ष का आयु-वर्ग कार्यकारी दल है, तो इसमें 14.4 करोड़ लोग, या इस आयु-वर्ग का 67.4 प्रतिशत, ऐसे हैं जो अवपक्ष हैं। इसके अतिरिक्त, अवपक्ष लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं और जीवन की पारम्परिक पद्धतियों से चिपके रहते हैं, जबकि सामाजिक जीवन के आधुनिकीकरण की मांग है कि स्वीकृत जाये कि नवीनकारी परिवर्तन लाया जाए। युग-मायना के साथ सामूहिक निरक्षरता की समस्या नहीं बँधती, क्योंकि आज वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ही जीवन की पद्धति और रहन-सहन के स्तर को निर्धारित करती है। नए विचार और नए तरीके उन लोगों के मन में प्रभावकारी रूप से पैदा नहीं जा सकते जो उन्हें ग्रहण करने और उनसे लाभ उठाने के अक्षम न हों। परिवार-नियोजन हो या स्वच्छता के स्तर को उन्नत करने की बात, सामाजिक सुरक्षा का कोई कार्यक्रम हो या कोई ऐसा आन्दोलन जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण में या जीवन-पद्धति में परिवर्तन की मांग करता है, लोगों की समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार, यह भी समझ लेना चाहिए कि अवपक्ष लोग वास्तविक प्रजातन्त्र नहीं बना सकते। सशक्त नागरिक जीवन में और महत्वपूर्ण निर्णय करने में लोगो का योगदान मिले यही प्रजातन्त्र का सार है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, और यह बात जितनी आज के संस्कृति पर लागू है उतनी ही भविष्य के। हमारे देश में जितने शिक्षा की अपनी महान परम्परा पर गर्व है, निरक्षर लोगों की भारी संख्या उपहास की बात है। ये सीधे सादे और स्पष्ट तथ्य हैं जिन पर मतभेद नहीं है। फिर भी, यह समझ लेना जरूरी है कि

निरक्षरता-जन्यता को विनाशित करने के लक्ष्य के लक्ष्य के अनुसार व्यवस्थापन तक तक प्रतिष्ठित रहेगा। अब तक राष्ट्रीय नेताओं की इस बात का पूरी विद्वानता न हो जाए कि जनपदों के समूह की शिक्षा का आर्थिक और सामाजिक प्रयोजन तथा राष्ट्रीय जीवन की सुगमता पर तोषा प्रभाव पड़ता है। इस विद्वानता के अभाव का प्रभाव यह है कि ओढ़ शिक्षा के किसी कार्यक्रम के प्रति अब तक कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। कुछ ही तक समयों की विद्वानता इसका कारण हो सकती है। निरक्षरता को समाप्त करने का अधिक है, इसके लिए विज्ञान के आधार और विज्ञान के आधार पर। इसके अधिक अवधि है कि परस्पर प्रतियोगी प्रणालियों के समूह इस समय को अप्राप्त मान कर छोड़ देने अथवा समय के और प्राथमिक शिक्षा के सामाजिक विकास के मरोठे इसका हम छोड़ देने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। इस रविवे के कोई सह्यता नहीं मिलती। हमारा विचार है कि निरक्षरता के साथ और समापन के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। हमारा विचार है कि इसके प्रति उदासीनता का दृष्टि तो मिलेगा ही।

17.12 इस प्रवृत्ति स्थिति का अन्त करने के लिए हम सिफारिश करते हैं कि निरक्षरता को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय और वित्तिकारी अभियान चलाया जाए। अभियान इसलिए आवश्यक है कि हमारे पास साधनों का समाप्त है और इस समस्या को सुलभ करना पड़ती है। वह अभियान राष्ट्रीय जीवन में इसके अनिवार्य महत्व के प्रति आस्था के प्रेरित होना चाहिए और देश के सामाजिक तथा राजनीतिक नेतृत्व को इसका समर्थन और प्रेरणा प्रदान करना चाहिए। केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों, सभी सरकारी एजेंसियों, सभी स्वैच्छिक एजेंसियों और गैर-सरकारी समस्याओं एवं उद्योगों, निरक्षरता के लिए एक प्राथमिक स्कूल तक की सभी शिक्षा संस्थाओं, और इन सबके मजदूर, शिक्षित नगरवासी को इसमें भाग लेना चाहिए। इसके हल्के स्तर का प्रयास इसे अपेक्षित प्रेरणा और गति प्रदान करने में असमर्थ रहेगा। यह अत्यन्त कठिन कार्य है। इसके लिए समर्थन का प्राप्ति, वित्तसाधनों का संग्रह, सभी सम्बन्धित एजेंसियों का निकटपूर्ण सहयोग और कार्य-

कर्ताओं के अनेक प्रयत्न और त्याग अपेक्षित है। यह कार्य पूरा हो सकता है, यह ने कान्ति के तरफत बाद इसे पूरा कर लिया था। कुछ निरक्षरता के प्रयास ने अपने देश के लिए सार्वभौम शासन-मान्यता के अधिक प्राप्त किया। सोवियत संघ में उपमहाद्वीप और राष्ट्रीय जीवन का भाव जाग्रत हुआ और वे सामाजिक क्रांति के भाव लेने के लिए तैयार हो गए। भारत में परिस्थिति थोड़ी भिन्न है, पर स्तर की तरह एक कोरदार प्रयास किया जाए तो वह राष्ट्रीय महत्व का वैश्विक अनुभव सिद्ध होगा।

17.13 सुझाव—शासन-कार्यक्रम में वित्त-साधनों की अनिवार्यता यह है कि इसकी योजना प्रत्यक्ष बनाई जाए और इसके लिए अपेक्षित पैसारी बहुत बढ़ते ही कर ली जाए। सामूहिक कार्यक्रमों के संगठन, सामग्री की पैसारी, कर्मियों के प्रशिक्षण और कुछ अन्य अपेक्षाओं में समय बचता है। हम देश के सभी भागों में एक-साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की बात नहीं सोचते। पर यह बखब है कि जनसमूह सुविधाओं का ध्यान रखते हुए प्रत्येक राज्य का एक के बाद दूसरा क्षेत्र लेकर धीरे-धीरे सारे राज्य और फिर सारे देश में कार्यक्रम का विस्तार किया जा सकता है। क्षेत्र-विशेष के वैश्विक विकास की अवस्था, जन-सहयोग और संगठन की कार्य-कुशलता के आधार पर विभिन्न समय में विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण शासन प्राप्त करना संभव होगा। निरक्षरता का समाप्तन में समय एक अनिवार्य तत्व है। समस्या को हल करने में 10 या 15 वर्षों के अधिक समय लगे तो इसका उत्प्रेषण ही समाप्त हो जाएगा। हमारा विचार है कि योजनाबद्ध प्रयत्नों से राष्ट्रीय शासन के प्रतिष्ठित को बढ़ाकर सन् 1971 तक 60 और सन् 1976 तक 80 तक लाया जा सकता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित बहुत बड़ा प्रयास और समर्थन अपेक्षित है, पर ये अव्यावहारिक नहीं हैं। हम सिफारिश करते हैं कि देश भर से निरक्षरता को समाप्त करने के लिए हर सम्भव कोशिश की जाए और देश के किसी भी भाग में, चाहे वह कितना ही पिछड़ा हुआ हो, इसके लिए 20 वर्षों के अधिक समय दें।

17.14 साक्षरता की अवधारणा—केवल पढ़-लिख लेने की योग्यता प्राप्त कर लेने को हम साक्षरता नहीं मानते। साक्षरता तभी साध्य होती है जब कामक्षम हो। साक्षर को साक्षरता के साधनों में पर्याप्त कुशल बनाया हो दृष्ट नहीं है, बल्कि उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के योग्य भी उसे होना चाहिए ताकि वह अपनी रुचि के काम और ध्येय को पूरा करने में सक्षम हो सके। निरक्षरता सम्मूलन कार्यक्रम में यूनेस्को द्वारा विह्वलन में (1965) आयोजित शिक्षा मन्त्रियों के विश्वसम्मेलन का यह निष्पत्ति था कि साक्षरता को साध्य मानने के बदले समुदाय को सामाजिक, नागरिक और आर्थिक योगदान के लिए तैयार करने की ऐसी प्रणाली समझना चाहिए जो साक्षरता प्रशिक्षण की उन प्रारम्भिक सोचाओं को बाध पायी है जिसमें पढ़ने लिखने मात्र की शिक्षा शामिल है। रहन रहन के स्तर को उन्नत करने में सतृप्त काम आने वाली जानकारी को प्राप्त करने के अवसर व रूप में पढ़ना लिखना सीखने की प्रशिक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए। पढ़ना लिखना केवल प्रारम्भिक सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि कुशलता से काम करने, उत्पादित वस्तुओं के नागरिक जीवन में अधिक उपयोगी बनने और अपने पास काम की दुनिया को ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए होता चाहिए। अतः उसे मूलभूत मानव संस्कृति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस इन सम्मेलन के विचारों से सहमत हैं। साक्षरता कार्यक्रम वषरकों को वसतिगिर बनने और इन योग्य बनने के लिए होने चाहिए कि वे अपने अक्षर ज्ञान का उपयोग अपने की शिक्षा के लिए कर सकें। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि निरक्षर शिक्षा की उस योजना का लाभ उठा सकें जिससे वर्षों हम लाभ करेंगे। इस दृष्टि से, साक्षरता कार्यक्रम में ये तीन अनिवार्य तत्व होने चाहिए

- (1) यह क्या समय "कार्यप्रारित होना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति और रुचि जागृत करना तथा ऐसी कुशलता और जानकारी प्रदान करना जगता स्वेय होना चाहिए जो व्यक्ति को उस काम में निरक्षरता प्राप्त करने में सहायता हो जिसमें वह सक्षम है।

(2) अवशेष व्याक्त को उससे ऐसी मदद मिलनी चाहिए कि वह बहु-वर्षीय राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि ले सके और देश के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में प्रभावकारी भाग ले सके।

(3) उसके पक्षस्थरूप अवशेष व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई और गणित में इतनी कुशलता प्राप्त हो जानी चाहिए कि उसके आधार पर यदि वह चाहे तो अपना-आप या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम उपलब्ध साधनों में अपनी शिक्षा जारी रख सके।

इस प्रकार साक्षरता कार्यक्रम की तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रारम्भिक अवस्था में पढ़ाई लिखाई और गणित का सामान्य ज्ञान तथा समूह समाज से सम्बन्ध रखने वाली नागरिक और राष्ट्रीय समस्याओं की तथा शिक्षार्थी के अपने व्यवसाय की सीधी बहुत जानकारी, शामिल होगी। दूसरी अवस्था शिक्षार्थी के प्रारम्भिक ज्ञान और कुशलता को गहनता प्रदान करेगी। प्राप्त साक्षरता के सहारे वह व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने और जीवन को समृद्ध बनाने में सक्षम हो सकेगा। वयस्क को निरक्षर शिक्षा के किसी-न किसी कार्यक्रम में जुटा देने का काम तीसरी अवस्था में होता चाहिए।

17.15 निरक्षरता की वृद्धि को रोकने के कार्यक्रम—निरक्षरता को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि निरक्षरों की बढ़ती हुई संख्या को इस प्रकार रोका जाए—

- साक्षरता स्कूल शिक्षण का विस्तार कम से कम 5 वर्ष के लिए 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए किया जाए,
- 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के उन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए जों या ही स्कूल में नहीं गये या पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते,
- 15-30 वर्ष के आयु वर्ग के उन युवा प्रौढ़ों को अनिवार्य सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा

दी जाए जिन्होंने स्कूल से कुछ वर्षों शिक्षा प्राप्त की है, पर वह इतनी पर्याप्त नहीं है कि उन्हें स्वाधीन साक्षरता की अवस्था तक पहुँचा सके। अथवा आस पास की परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सुयोग्य बना सके।

17 16 अथवा साल में हमने 6-11 वर्ष के आयु-वर्ग के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ति के कार्यक्रमों पर विचार किया है। हमने यह विचार रखा भी की है कि प्रारम्भ में 11-14 वर्ष के आयु-वर्ग के लिए कुछ वर्षों की अवकालिक शिक्षा को स्पर्धवात्मक स्पर्धा आधार पर हम जाना से की जाए कि उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाने पर उसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। हम यह भी जरूरी समझते हैं कि ये सुविधाएँ 15+ वर्ष के उच्च आयु वर्ग को भी दी जाए जिनकी स्कूली शिक्षा अपूर्ण है। स्कूली पढ़ाई की सुविधाओं के विस्तार को स्कूलों की धारण क्षमता के विचार के साथ-साथ उठाए गये थे। तब, निरक्षरता को मिटाने के मुख्य माध्यम रहे।

17 17 कार्यनीति—साक्षरता की योजना। देश में स्पष्ट विधि की आवश्यकता और उचितता के अनुकूल ही बनाई जानी चाहिए। इस अर्थ में इस स्थिति का विश्लेषण करने का विचार नहीं है क्योंकि इस दृष्टिकोण के तहत का अनुमान इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि वर्ष 1961 की गणना के अनुसार, देश में 15+ आयु वर्ग के 18 0 करोड़ व्यक्ति हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा (19 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों की साक्षरता (47 प्रतिशत) अधिक है। साक्षरता के मापदंड में देश के एक क्षेत्र की साक्षरता दूसरे क्षेत्र की साक्षरता से बहुत कम है—दिल्ली में 42 7 प्रतिशत से लेकर नेपा में 18 प्रतिशत तक। देश के विभिन्न भागों में स्त्रियों और पुरुषों की तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों की साक्षरता में भी अंतर है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिक्षा की प्रेरणा भी भिन्न है और शिक्षा के विकास और उपयोक्तृत्व जैसी अनेक बातों पर निर्भर है। स्पष्ट है कि इस समस्या को सुल-

झाने के लिए कोई एक या सरल तरीका नहीं हो सकता, अत्यंत विविधता की अति विविधता जांच करनी होगी तथा सुधार के उपाय ऐसी स्थानीय सुविधाओं पर निर्भर होंगे जो या तो उपलब्ध हों या उपलब्ध हो सकें। हम समझते हैं कि हम कुछ सामान्य सिद्धान्तों की ओर ही संकेत कर सकते हैं।

17 18 देश में निरक्षरता को मिटाने के लिए हम एक विविध कार्यक्रमों की सिफारिश करते हैं, जिसे सुविधा के लिए हम

(ए) ध्येयनात्मक पद्धति, और

(बी) सामूहिक प्रदर्शित कह सकते हैं।

इन दोनों पर आधारित कार्यक्रमों का प्रारम्भ करें, उन्हें एक दूसरे का पर्याय न माना जाए।

17 19 ध्येयनात्मक पद्धति—ध्येयनात्मक पद्धति विशेष रूप से उन वर्गों के लिए उपयुक्त है जिन्हें सामाजी के अन्तर्गत जा सकता है, जिन पर नियंत्रण रखा जा सकता है और जिनमें साक्षरता के महान् कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इन वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है और उन्हें पूरा करने के लिए सोई-संगत साधन उपलब्ध बनाया जा सकता है। इन वर्गों को समझना प्रेरणादायक साधन है और इनकी साक्षरता के लिए सगई बई पूजा है। परिणाम की दृष्टि से और लाभदायक होवे। ध्येयनात्मक पद्धति का एक और लाभ यह है कि इसके साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऐसा प्रशिक्षण भी शामिल किया जा सकता है जो ध्येय-साधक और श्रुतिक कर्म को बढ़ावा दे।

17 20 उपसंहार के लिए, हम निम्नलिखित तीन सुझावों हैं जहाँ ध्येयनात्मक कार्यक्रम तत्काल बनाए जा सकते हैं और सबसे लाभ उठाया जा सकता है।

(1) औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाएँ एक बहुत बड़े कार्यक्रमों पर को नियुक्त करती हैं जिनमें लगभग 40 प्रतिशत निरक्षर होते हैं। यह समस्या इतनी बड़ी है कि इस पर ध्यान देना जरूरी है। हम सिफारिश करते हैं कि बड़े-बड़े कार्यों में तथा वाणिज्य, उद्योग, ठेकेदारी और

अथ समाप्ति में काम देने वालों को यदि आवश्यक हो तो कानून द्वारा इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि वे अपने सभी निरक्षर कामगारों को उनकी नौकरी बनाने के तीन वर्ष के भीतर इसका साक्षर बना दें कि वे अपना काम खला सकें। कामगारों को शिक्षित करने की पूरी जवाबदारी उनके निवेशकों की ही होनी चाहिए जो उन्हें किसी स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा देने की छूट दिया करें। निरक्षरों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी उन्हें करनी चाहिए और शिक्षा प्राप्ति के लिए यत्न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनकी शिक्षा पर होने वाला सारा खर्च सरकार को उठाना चाहिए और अध्यापकों वृत्तियों तथा पढ़ने को अन्य सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। इस बात में हमें तब तक भी संदेह नहीं कि सम्प्रसारण निवेशकों अपने कामगारों को शिक्षित कर सतत स्वयं सामर्थ्यवान् होंगे।

- (2) हम सिफारिश करते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में विद्यालय औद्योगिक उद्यमों को पहला कदम परीक्षा उठाना चाहिए और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को गति देनी चाहिए।
- (3) व्यक्ति और सामाजिक विकास की सभी योजनाओं का एक मानवीय पक्ष है। उससे ऐसे लोग नाचे सक्षम के सम्बन्धित हैं जिन्हें स्कूली शिक्षा नहीं मिली। इसीलिए यह एक सत्य है कि उद्योग ऊर्ध्व वायुमण्डल स्वास्थ्य, शिक्षा आदि किसी भी क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने के कामगारों की विशेषकर निरक्षर कामगारों की शिक्षा उल्लेख अति आवश्यक है।
- (4) सामाजिक कल्याण के विचार से लोगों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षित करने के लिए सरकार ने जो कुछ योजनाएँ चलाई हैं, उदाहरण के लिए आर्य और प्रामोयोग योजना की आदी उदाहरण

योजना अथवा सामुदायिक विद्यालय विद्यालय की अनुपयुक्त पोषण और बात कल्याण कार्यक्रमों की योजना। जिनसे कई लोग स्थितियों का सन्धान है। हमारा सुझाव है कि मानवता कार्यक्रम को इस प्रकार की सभी योजनाओं का अनिवार्य रूप से बनाया जाना चाहिए।

ये उदाहरण किसी तरह अन्तिम नहीं हैं। साक्षरता कार्यक्रमों की योजना बनाने वालों को अन्य उदाहरण सोचने चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए।

17 21 सामूहिक पद्धति-सामूहिक पद्धति का सार यह है कि निरक्षरता को मिटाने के लिये देश भर में उपलब्ध सभी शिक्षित स्त्री-पुरुषों का एक बल संगठित किया जाए और साक्षरता अभियानों में उसका प्रभावकारी निवेश किया जाये। यह परंपरा पद्धति तो नहीं है परंतु प्रेरित है। जनसांख्यिक पद्धति अपनी आंतरिक सीमाओं में सिमटी हुई है। सक्षम हल के रूप में समाधान अग्रिम वकारी है। सामूहिक पद्धति विषय ही कारण ही सकती है। सामूहिक पद्धति को देश में उसके समीप सफलता मिलती है। अक्षय हल से और छोटे पैमाने पर ग्राम शिक्षण मुहिम के रूप में यह पद्धति गहाराष्ट्र में कार्यालय की जा चुकी है। निरक्षरता को मिटाने के लिये इस मुहिम में गांव की स्थानीय देश शक्ति का व्यवस्था और अध्यापकों तथा स्थानीय शिक्षित नगरियों का सहयोग निम्न। इस योजना पर बहुत ही कम खर्च हुआ और जो लाख हुए वे साक्षरता के मान से कहीं अधिक थे। इस मुहिम के आयोजकों ने इसकी ठगरी से यह कई कुछ बर्तनों और अनुवर्ती काम की कमजोरियों की ओर संकेत किया है। इन दोषों का उपचार किया जा सकता है।

17 22 निरक्षरता को मिटाने के लिये सामूहिक आंदोलन प्रशासनिक और शिक्षक दोनों की सामर्थ्य से बाहर है। ऐसा आंदोलन निम्न ही देश के राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व का दायित्व है। निरक्षरता राष्ट्रीय विकास में रुकावट बनती है—यह विश्वास राष्ट्रीय मामलों से सम्बन्धित क्षीमस्व व्यक्तियों के मन में जितना उठ होना उतनी ही सफलता इस पद्धति को मिलेगी। सफलता इस बात पर भी निर्भर है कि ऐसे व्यक्ति हैं

विश्वास को लोगों के दिल में कहा तक उत्तार सकते हैं और जनमें किसना प्रबल उत्साह और प्रेरणा जगा सकते हैं। हमारा विश्वास है कि यदि राष्ट्र-देसवाचियों को साक्षर बनाने के लिए श्रुतिविश्वास है और इस काम के अनुसृत प्रयास और त्याग करने की तयारी है तो भारत निकट भविष्य में ही साक्षर राष्ट्र बन सकता है।

17.23 ग्रीक शिक्षा-समाज एक स्वेच्छित प्रक्रिया है जिसकी मूल प्रेरक शक्ति व्यवस्था की अपनी अंतःश्रेणी है। साक्षरों, शिक्षाविदों और प्रशासकों को यह स्पष्टतः जान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता उत्पादित और जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था-व्यवस्था प्रोत्साहित तथा प्रवर्धित द्वारा ही संभव होना। प्रत्येक शिक्षण या यह पक्षों पर यह बात साफ़ एकाएक इसकी स्पष्ट होगी कि ऐसी शिक्षा देने के लिए यह स्वेच्छा से कई पक्षों दे-भाले—इसलिए, यह जरूरी है कि साक्षरता कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए कि वे बच्चों को साक्षर बनाने और उनकी प्रतिष्ठित परिस्थितियों तथा वातावरण से स्पष्टतया सम्बन्धित हों।

17.24 सामूहिक साक्षरता का अभियान अधिकतर सभी विधियों की स्वेच्छित सेवाओं पर निर्भर होता है जिनमें सरकारी कर्मचारी सामाजिक उपकरणों के उपयोग, बनीन, बायटर इन्फोमर और अन्य लोग शामिल हैं। पर इस अभियान का प्रमुख भार स्कूल और कालेजों के अध्यापकों पर पड़ना और उनके संगठन का प्रमुख वास्तविक सभी प्रकार की शैक्षिक समस्याओं पर पड़ना। इस सिफारिश करते हैं कि उपर्युक्त प्राथमिक, माध्यमिक उपर्युक्त माध्यमिक तथा व्यावसायिक स्कूलों और निम्न विद्यालयों की पूर्ण स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अभिवाय राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत के रूप में, जिसकी सभी हानि-अपघात की है, प्रीमो को बढ़ावा व्यवस्थापक ठहराया जाना चाहिए। जल्द ही आवश्यक यह भी है कि भवितव्य माने पर सभी प्रकार के व्यवस्थापक प्रीमो को पढ़ाए और इस अभियान में अभिवायत भाग लें। प्रीमो शिक्षा उनके सामाजिक व्यवस्था का अंग होनी चाहिए। उन्हें ऐसा करने में सहायता देने के लिए यह आवश्यक है

सकता है कि जो लोग स्कूल के सामाजिक कार्य से उन्हें छूट दी जाए या प्रीमो शिक्षा कार्य के लिए कारगरमिष्ठ दिया जाए। जब भी आवश्यकता पड़े, उनकी सेवाएं प्रीमो शिक्षा सम्बन्धी कार्य में लिए उपलब्ध होनी चाहिए। निम्न-पूर्वक साक्षरता कक्षाएं बनाना सभी शैक्षिक समस्याओं के लिए आवश्यक होगा चाहिए और उन्हें अपने निकट के निश्चित क्षेत्र में निरक्षरता को समाप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। क्षेत्र का आकार स्कूल के उन अध्यापकों और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए जो साक्षरता कार्य के लिये उपलब्ध हों।

17.25 स्कूल के लिये कार्य—प्रीमो शिक्षा की गई जिम्मेदारी का अर्थ यह होगा कि स्कूल के कार्य और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाए। उसका मुख्य कार्यक्षेत्र स्कूल के बच्चे तक ही सीमित नहीं होगा। बल्कि वह शारीरिक स्थानीय जनता उसकी परिधि में आ जायेगी जिसको यह सेवा करता है। उसे समुदाय के जीवन के दृष्टि से यह कार्य करना होगा। बच्चे स्कूल में बच्चे उसका रूप बदलकर जनता का स्कूल हो जायेगा। ऐसी स्थिति में उसे समुदायिक जीवन के केंद्र और विस्तार सेवाओं के महत्वपूर्ण आधार के रूप में सज्जित और तैयार करना होगा। अन्य व्यवस्थापक सामग्री के अभाव में, उन्हें पुस्तकालय, रेडियो, प्रदर्श, स्नातक, माध्यम और प्रीमो शिक्षा की अन्य सामग्री रखनी होगी।

17.26 साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें—साक्षरता का एक धर्म रहा आवश्यक है। प्रीमो साक्षरता का कोई भी अभियान पूरा योजना और सतत सेवाओं के बिना नहीं चलाना चाहिए। यद्यपि हमारा सुझाव यह नहीं है कि किसी कार्यक्रम को आरम्भ करने से पहले प्रत्येक क्षेत्र का वर्गीकृत अध्ययन और सर्वेक्षण अवश्य है, तथापि हमारा विश्वास है कि यदि नीचे लिखी अपेक्षाएँ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाये तो साक्षर होना और निराशा नहीं होगी

(1) किसी भी कार्यक्रम को आरम्भ करने से पहले लोगों में रुचि जगाने और उनकी समायोजन प्राप्त करने के लिये सभी आवश्यकता, सामाजिक

और अन्य नेताओं को तथा सभी सरकारी विभागों को जुट जाना चाहिये।

- (2) जिन प्रौढ निरक्षरों को कार्यक्रम में शामिल करना हो उन्हें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तैयार करना चाहिए और उनमें प्रेरणा जगानी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि साक्षरता का उनके लिए क्या अर्थ होगा और उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि साक्षरता प्रगति के लिये वे को प्रयास और त्याग करेंगे, यह उन्हें गहरी किया जावेगा।
- (3) लोगों के मन में दृढ़ निश्चय बनाने, उसे बनाये रखने तथा कार्यक्रम के दौरान और बाद में उन्हें सहारा देने के लिये सामूहिक संचार साधनों का व्यापक उपयोग करना चाहिए। साक्षरता कार्य की सफलता के लिये अनुकूल पाठ्यावरण बनाने और उसे बनाये रखने के लिए रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पापण और अन्य साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- (4) प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवेक्षित सामग्री पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए और अभियान शुरू करते समय उचित पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इसमें पाठ्य-पुस्तकों और अन्य पाठ सामग्री, चार्ट, नक्शे, निर्देश-पुस्तकें और अन्य दौलत सामग्री तथा कार्यक्रमों के लिए गृहमय सामग्री बांटी होनी चाहिए।
- (5) साक्षरता कार्यकर्ताओं को योजना स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर संचालनी से बनाई जानी चाहिए। पहले शिक्षण में कुछ बनाने के बिना निरक्षर व्यक्तियों को उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में जानकारी और कुशलता उठाने में भी सहायता मिलनी चाहिए, वे अपने समुदाय, देश और सहारा की महत्वपूर्ण समस्याओं के प्रति जागरूक हो जाएं और उन्हें जनसंख्या नियंत्रण जैसे गृह-

त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका देना आवश्यक जान पड़े और देश के जीवन और संस्कृति में समझने में सहायता मिले।

- (6) साक्षरता कार्यक्रम ऐसे हों जिनमें सबसे अधिक निरक्षर शिक्षा देने के लिये सहायित रहें। साक्षरता को सर्वाधिक सफलता तभी मिलती है जब व्यक्ति अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझाने के लिए अपनी जानकारी का उपयोग करना सीख जाता है और स्वयं, पुस्तकालय तथा सत्रात्मक जैसे ज्ञान-वृद्धि के साधनों से लाभ उठाने सक्षम है। योजनाबद्ध अनुवर्ती कार्यक्रम साक्षरता अभियान का अनिवार्य अंग है।
- (7) यदि अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि साक्षरता कार्यक्रम, जैसी रूपरेखा एकलपना है, केवल व्यापकता के अन्तर्गत नहीं चलाए जा सकते। व्यापकता के अर्थ को इस प्रकार सहारा मिलना चाहिए
- (क) विश्वविद्यालयों और उद्योग, कृषि, जन-स्वास्थ्य, सहायिता, सामुदायिक विकास आदि विभागों की विस्तार-नेतृत्वों के द्वारा लोगों को व्यावसायिक जानकारी कुशलता और दक्षिणों की विस्तार करने में सहायता मिलनी चाहिए, और
- (ख) नागरिक जीवन और राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रति प्रौढ निरक्षरों को चेतना जगाने के लिए सामूहिक संचार साधनों और विशेषतः साक्षरता कार्य का उपयोग किया जाना चाहिए।
- (8) यदि पुस्तकालयों की स्थापना नहीं की गई और अच्छी पाठ सामग्री तथा संचार पत्र संचालन में विस्तार रहे तो साक्षरता-कार्यक्रमों के प्रभाव स्थायी नहीं होंगे।
- (9) सोच समझकर बनाई गई कार्य योजना में स्थानीय नागरिकों, अन्य अधिकारियों तथा

नेताओं का पूर्ण प्रतिपाद्य समितित होना चाहिए। कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यक्तियों को कार्रवाई विस्तार से समझा दी जाए और यह भी बता दिया जाए कि विशेष रूप से उन्हें क्या करना चाहिए।

- (10) जो रिटायर् और शिक्षित व्यक्ति पढ़ने के लिए अपने नाम दें, उन्हें शिक्षण पद्धतियों और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित करने के बारे में अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाए। उनके लिए निरर्थक पुस्तकों और अन्य सहायक सामग्री को भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

- (11) प्रशासन और वेल्फेयर के लिए एक कार्यपुस्तक सफाई अपेक्षित है। सर्वोच्च संस्थाओं का सहयोग सुनिश्चित होना चाहिए तथा सततता पूर्ण मूल्यांकन और अनुमोदन का जग मौ मिलना चाहिए।

- (12) सतत साक्षरता अभियान को समाप्ति के बाद जो कार्रवाई करनी हो उसका समन्वय भी योजना में होना चाहिए। साक्षरता कार्यक्रमों में जाए केन्द्र बानों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि शिक्षा जारी रखने के लिये वे एक दूसरे की सहायता करें और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अध्ययन-बसों, संस्थाओं, बसों या गरीब राज बसों की स्थापना करें।

- (13) साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता, समर्पण और उत्साह अत्यावश्यक है। कार्यक्रम की सफलता पर सार्वजनिक प्रशंसा, प्रतिनिधियों की जिम्मेदारता पर सार्वजनिक जिम्मेदारता, प्रशिक्षण के सुधार में सार्वजनिक सहयोग, उद्घाटन कार्यक्रमों को सार्वजनिक प्रोत्साहन—ये सभी बातें अत्यन्त महत्व की हैं। समाचार पत्रों, साप्ताहिक और राजनीतिक नेताओं, विद्वानों और अन्य सभाओं की सहायता से जन-सहयोग और समर्थन को बनाए रखना आवश्यक है।

17.27. स्त्रियों में साक्षरता—स्त्रियों में साक्षरता को स्थिति विशेष दुखदायी है। सन् 1961 की जनगणना से पता चलता है कि सहरी क्षेत्रों में 34.5 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 8.8 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर हैं। यह संवेगान्वय है कि जब तक स्त्रियाँ साक्षर नहीं हो जाती, सामाजिक स्थानान्तरण की कोई आशा नहीं। फिर भी, यद्यपि स्त्रियों को साक्षर बनाने के नगण्य प्रयत्न हुए हैं। इस दृष्टि से जोरदार निष्कर्ष नहीं कर सकते कि स्त्रियों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियों में, साक्षरता बढ़ाने के लिये साहसपूर्ण सुविधाएँ और प्रभावकारी कदम बहुत जल्द उठाने चाहिए। इस रिपोर्ट में इन कारणों पर विस्तारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो स्त्रियों के बीच साक्षरता कार्यक्रम चलाने में बाधक हैं। यह सर्वविदित है कि स्त्रियों में शिक्षण की प्रणाली ही होती है, स्त्रियों के बीच साक्षरता कार्यक्रम चलाने में सामाजिक बाधाएँ बाधक होती हैं, स्त्रियों को अवकाश कम ही मिलता है और वे निश्चित ही सख्त समय की प्रतीक्षा में बैठी नहीं रह सकतीं जब उन्हें पढ़ने की फुर्सत हो। स्त्रियों के लिये अध्ययन-बसों की समस्या सबसे कठिन है। कुछ कठिनताएँ तो हमारे इस मुद्दे से दूर हो सकती हैं कि उन्हें पढ़ने का काम स्कूल के बच्चों की सीखा जाए। बच्चे घर-घर जाकर स्त्रियों को उनकी सुविधा के समय में पढ़ा सकते हैं। घर-घर जाकर स्त्रियों को पढ़ाने वाले इस 'छोटे अध्ययन-बसों' का सामाजिक विरोध भी नहीं होगा।

17.28. भाषा की बातें हैं कि स्कूलों में अध्यापक अध्यापिकाएँ नियुक्त की जाएँगी और स्कूलों द्वारा केवल छात्रों को निरन्तर स्त्रियों को पढ़ाने की विशेष जिम्मेदारी उन्हें सौंपी होगी। फिर स्त्रियों की शिक्षा अबूरी रह गई है उनके लिये 'सह-पाठ्यक्रम' बनाने तथा शिक्षा और उपयोगों से कुछ संशोधन में उन्हें सारे प्रशिक्षण देने की व्यवस्था केन्द्रीय सचिव कक्षाओं को द्वारा कार्य-निर्वाह जिम्मेदारता में है वह हम सक्षम जान पड़ती है। हमारा यह भी सुझाव है कि ग्रामीण स्त्रियों को पढ़ाने और स्थानीय स्त्रियों में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए 'ग्राम बहनों' की नियुक्ति की जानी चाहिये। जहाँ तक

हो प्राप्त रहन ऐसी स्थानीय स्त्रो ही होनी चाहिए बिन्ने प्रौढ शिक्षा काम के लिए कुछ बेतन दिया जा सके । वह प्रशिक्षित होनी चाहिए और प्रौढ शिक्षा के नए तरीके सीखने के लिए उस समय समय पर दुबारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । सहरी श्रमों की स्थितियों के बीच सावधानता प्रसार सरकारी पब्लिक मोबी और सेवानिवृत्त व्यक्ति कर सकते हैं ।

17 29 रेडियो, टेलीविजन और दृश्य-श्रव्य साधना का योगदान—हमारा विचार है कि निरक्षर और अशिक्षितों की भारी संख्या राष्ट्रीय जीवन और उसके विकास के लिये बहुत बारीक बाधा है । इसलिए ज्ञानी गिनाम और करना सतरा मोन लेना है । यह भी स्पष्ट है कि निरक्षरता धीरे धीरे ही मिट सकती है । अधिकतम राष्ट्रीय प्रयास के लिये के फलस्वरूप देश के कुछ ही भागों में सम्पूर्ण साक्षरता के लिये दो दशक लग सकते हैं । इससे अधिकतर यह भी देखा गया है कि साक्षरता का उपयोग करने में जो पढ़ना है उसका चुनाव करो म और जो पढ़ा गया है उसे समझने में समय लगता है । जिसे लम्बे समय तक शिक्षण गिनामिरी है उन्हे भी पठन-समय का नाम बढ़ाने के लिये शैक्षिक परिपक्वता की जरूरत पड़ती है । फिर भी दोनों को शिक्षित करने का काम तब तक रुका नहीं रहना चाहिए जब तक कि वे साक्षर न हो जाय, बल्कि यह काम साक्षरता कार्यक्रम से पहले, उसके साथ साथ और बाद में भी होना चाहिए । इसी उद्देश्य से हमने सिफारिश की है कि सामूहिक व्यापार-साधनों और चिकित्सी तथा अन्य दृश्य श्रव्य साधनों का पूरा पूरा साथ बढाया जाए । वास्तव में मिनेमा रेडियो शिक्षित विद्यार्थी और इस प्रकार के अन्य साधन पहले से ही निरक्षर और साक्षर दोनों को शिक्षित कर रहे हैं । इन गिनाम और अशिक्षा के बीच फुलाव नहीं करता है, बल्कि चुनाव ऐसी गिनाम जहाँ राष्ट्रीय विकास और एकात्मकता आवश्यक है तथा यह जो सेवन सामाजिक समोर-जन व निरक्षरता है जो बीच करता है । दोनों के साथ साथ और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनुसूचित जाति-जन तथा जाति-जाति और कुल-जन जन करने के लिये सामूहिक व्यापार साधनों का उपयोग

सहायक माध्यम के रूप में होना चाहिए । इस दिशा में हमारा विचार यह था कि प्रौढ शिक्षा के लिए रेडियो और टेलीविजन सेवाओं के उपयोग के सम्बन्ध में व्यापक सिफारिशें प्राप्त की जायें । परन्तु ए० के० चट्टा की अध्यक्षता में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा स्थापित समिति की रिपोर्ट ने हमारा काम बहुत हल्का कर दिया है । इस सम्बन्ध के सम्बन्ध परामर्शों में शिक्षा है कि विभिन्न प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों के लिये रेडियो और टेलीविजन का क्या विशेष उपयोग किया जाय । प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो और टेलीविजन के उपयोग के सम्बन्ध में सूचना और प्रसारण समिति द्वारा की गई सिफारिशों का हम सामान्यतः समर्थन करते हैं । हम समिति के सहमत हैं कि टेलीविजन निरक्षर प्रौढों के लिये अधिक उपयुक्त साधन है । अपेक्षाकृत कम शिक्षित स्त्रियों को और मनसों को सामान्य शिक्षा देने के लिए टेलीविजन और रेडियो दोनों का उपयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, इनका उपयोग बढावन बढ़ाने और समाज को बदलने के साधन के रूप में भी किया जाना चाहिए । आधुनिक जीवन की परिस्थितियों में जनता की प्रगति और रुचि निश्चित करने में रेडियो, टेलीविजन और विद्या का योग महत्वपूर्ण हो सकता है इसलिए यह आवश्यक है कि उनका उपयोग मानवीय और राष्ट्रीय हित में किया जाय । बहुचक्षुष जनता को उपयोगी जानकारी देने और उन्हें यह समझाने के लिए इसके बढा और रोई साधन नहीं हो सकता कि देश बढा चाहता है और किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और समय कर रहा है ।

17 30 अनुवर्ती धार्य—सारे अभियान स्वभावता समाप्त हो जाते हैं पर साक्षरता अभियान समाप्त नहीं होता । यदि गिनाम प्राप्ति की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में जारी न रहे तो साक्षरता-अभियान का उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा । प्रायः वस्तु की जाने जाती यह विज्ञा अनुभव से सिद्ध हो चकी है कि साक्षरता कार्यक्रम के बाद निरक्षरता घीम हो पुन जा भरती है । सीमित विज्ञान साधना और प्रशिक्षण पात्रियों में अभाव में जब निरक्षरों को पढ़ाने के लिये विद्यापियों और अध्यापकों की

वैज्ञानिक सेवाओं का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है तब यह आग का प्रदल हो जाती है। जीवन के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाचार उपयोग करने पर ही प्राप्त साक्षरता की बनाने रखा जा सकता है। हम यह सुझाव दे चुके हैं कि साक्षरता कार्यक्रमों की प्राथमिकता समाचार के रूप में शिक्षा प्राप्त की रखा साथ न करना कितना जरूरी है। समाचार में सामाजिक शिक्षा सामूहिक समाचार समाचारों तथा अन्य ऐसे माध्यमों की सहायता से शुरू की जानी चाहिए जिन्हें लोगों को जीवन के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक मामलों का ज्ञान हो सके। साक्षरता की आवश्यकता और उसके अभाव में होने वाली हानि या अनुभव निरक्षर को ही होना चाहिए। पढ़ना मिलना सीखने हुए उद्योग किए यह जानना भी जतना ही आवश्यक है कि प्राप्त ज्ञान का उपयोग वह किस तरह कर सकता है। निरक्षरों को पढ़ाने के लिए विद्यालयों और विभिन्न स्थानों से जो परिस्थितियाँ ही सामान्य पढ़ता है परंतु वे लोगों को बहुत ही कम भावें बड़ा पाते हैं। वे पढ़ना पढ़ना और पढ़ती शिक्षा सकते हैं और निरक्षर का उनके अक्षिप्त और सामाजिक जीवन की कुछ समस्याएँ भी समाप्त सकते हैं। इस प्रारम्भिक अवस्था के बाद अध्ययन नियमित अर्थात् पढ़ी द्वारा स्कूलों में होना चाहिए और निरक्षरों की घरेलू जीवन विविध प्रकार की ऐसी मनोरंजक शिक्षा की और प्रयत्न करना चाहिए जिसकी वर्षा हम आगे करेंगे। प्रौढ़ों को यह सिखाया कि मनोरंजन और सामाजिक लिए वे पुस्तकालय का उपयोग किस तरह कर साक्षरता कार्यक्रमों का प्रयत्न कर सकते हैं। ज्ञान यह कि हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि अनुवर्ती कार्यक्रम समाचार का कार्यक्रम से भिन्न नहीं है। अनुवर्ती कार्य के अतिरिक्त समाचार कार्यक्रम में ही निहित होने चाहिए। यह समझना बहुत है कि अनुवर्ती कार्य विधि के अन्तर्गत वर्गीकृत कार्यक्रमों साक्षरता अध्ययन की समाप्ति पर और पढ़ने के पढ़ना निरक्षर क्षेत्र से परे ही शुरू किए जाने चाहिए। साक्षरता के हस्तक्षेप कार्यक्रम के रूप में ही ऐसे सब होने चाहिए जो साक्षरता को स्थायी और उपयोगी बनाने में लिए जरूरी हों। साक्षरता कार्य के एक

बार शुरू हो जाने पर उसे प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न रूपों में से किसी न किसी एक रूप के साथ सम्बन्धित कर देना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाने पर उसे जारी रखने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिए।

17-31 हमने सुझाव दिया है कि साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की योजना में अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की तयारी की जानी चाहिए जो आवश्यकता पड़ते ही गुप्त हो सकें। निरक्षरों के लिए पाठ्य पुस्तकों में पसंद तथा विविध प्रकार का अध्ययन—जैसे सूचना पत्र, पत्रिकाएँ, पत्रिकाएँ, विभिन्न कृषि विज्ञान अवस्था मिल्य या प्रयोगों की तब के किसी विषय के किसी पत्र के बारे में उपयोगी सूचना हो—सामाजिक सहचर की सामग्रियाँ हैं। अध्यापक स्वयं सबको भी बड़ी सजा के लिए पाठ्यक विषय पुस्तकों तथा ऐसे ही अन्य साहित्य के गुण का भी बड़ा हो यह है। बाद में, माहल विभिन्न विषय पत्रिकाओं और विविध प्रकार के अन्य दृश्य अध्ययन तयार करना बहुत आवश्यक है। यह विचारत लाभ है। इसके लिए बहुत सूक्ष्म बुद्ध और सफल चाहिए। यदि सामग्री तयार न हुई तो समाचार का कार्यक्रम रुक जायेगा। सामग्री तयार करने का काम बहुत से स्तरों पर होना चाहिए। कम से कम निरक्षरों तथा उनके व्यावसायिक या अन्वयसायिक अध्यापकों के लिए पुस्तकों की तयारी करनी ही चाहिए। माया सम्मती कारणों से और प्रत्येक भाषा में पुस्तकों की भारी मात्रा के विचार से प्रत्येक राज्य में साहित्य गुणन के लिए एक सतत अनुभाग की स्थापना जरूरी हो जाएगी। स्थानीय समस्याओं हितों का ध्यान रखने से वे पुस्तकों खरीक हो सकेंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राज्य सहयोग होना चाहिए कि जो साहित्य समाचार किया जाए वह राष्ट्रीय नीतियों का प्रसार करे और राष्ट्रीय स्तर तथा देशभक्ति की भावना को संचाल करे। अन्तर्राज्य सहयोग से कुछ भाषाओं में उत्साहन समाचार को चलाने में भी मदद मिल सकती है। हमारा विचार है कि साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा में कार्यक्रमों के लिए उपेक्षित साहित्य के गुणन के लिए राज्यों और विभागों के बीच सहयोग स्थापित करने का काम शिक्षा मंत्रालय की करना चाहिए।

निरन्तर शिक्षा

17.32 महत्त्व—समय बीतते-बीतते निरन्तरता समाप्त होनी चाहिये और स्कूल-पद्धति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसकी पुनरावृत्ति न हो। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य निरन्तर चलता है। द्रुत परिवर्तन ज्ञान की पृष्ठभूमि के विचार से मनुष्य को निरन्तर सीखते रहना होना चाहिए यह पूर्णता से है। सीखते रहना सभ्य जीवन की रीति है।

17.33 अब यह सिद्धान्त सर्वमान्य हो गया है कि शिक्षा की आधुनिक पद्धति के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की और विभिन्न स्तरों की पूर्णकालिक शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं होती बल्कि उसमें पाठ्यक्रम और अध्यापन के ऐसे बहुविध प्रकार सम्मिलित होते हैं जो पूर्णकालिक स्कूली शिक्षा के अनिश्चित प्रौढ़ के व्यक्तिगत, व्यावसायिक सामाजिक और भयं हितों का साधन में सहायक होते हैं। इस दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा ऐसी उपज और फल है जिसके लिए विविधतया नामांकित अध्यापन केवल रोपण और वर्षण का काम करता है। यह आवश्यक की बात नहीं है कि विकसित समाजों में प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा का सर्वाधिक तेजी से बढ़न वाला अंग बन गई है।

17.34 सामान्य शिक्षाविशेष—मोटे तौर पर निरन्तर शिक्षा की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो दो विभिन्न स्तरों के लोगों के लिए उपयुक्त हो। इनमें पहला वर्ग उनका है जो दीर्घकालिक व्यवसायों में या विविध ऐंजेलियों द्वारा विविध विषयों में आयोजित तदर्थ शिक्षा की कक्षाओं में मध्यकालिक अध्यापन के लिए दूसरों के साथ विश्वर समूह बना सकते हैं। ये ऐंजेलिया हैं—विकास से सम्बन्धित विभाग, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तकनीकी, व्यावसायिक और कृषि शिक्षा संस्थाएँ या विदेश मंत्रियों और स्टेन्डिड संस्थाएँ। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जिन्हें अपने घर उस समय के बीच बचना है जो उन्हें इस उद्देश्य से मिले, घर जो अपनी सुविधा के अनुसार सहायता चाहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विविध उद्देश्य पूरे करे और प्रौढ़ों के ऐसे विभिन्न समूहों के काम आए जिनके वैश्विक स्तर ही निम्न नहीं हैं, बल्कि जिनको व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक महत्वादायक और सांस्कृतिक मामलों में प्रति दायित्व-

भाव भी एक दूसरे में मिले हैं। हम पहले लोगों का उत्तेजक कर चुके हैं, जिन्हें प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पूर्व ही स्कूल छोड़ देना पड़ा, और सुझाव दे चुके हैं कि उन्हें इस स्तरकी शिक्षा पूरी करने योग्य बनाना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं जो विविधतया शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं और अनेक विषयों में, जिनमें विज्ञान, शिल्प विज्ञान और कृषि शामिल हैं, विश्वविद्यालयी डिग्री लेना चाहते हैं। ऐसे भी हैं जो सेवों, कारखानों, फ़ैक्टरियों, वाणिज्य संस्थानों में काम कर रहे हैं, और ऐसे जो अपने ही घरों में बने हैं और अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण चाहते हैं। उनके व्यवसायिक स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों को भी अपने ज्ञान को ताजा करने और अपने विशिष्ट क्षेत्र में हुए नव-चिन्तन और नई रीतियों की जानकारी प्राप्त करने की जरूरत होती है। विशेष रूप से सभी स्तरों के अध्यापकों को, जिनमें विश्वविद्यालय के अध्यापक भी शामिल हैं, जवहर विषय चाहिए कि वे ज्ञान के बढ़ते हुए सीमानों में परिचित रह सकें। यही बात वकीलों, बाजारों, व्यापार प्रबंधकों, उद्योगप्रमुखों और व्यवसायों के अन्य शीर्षक व्यक्तियों पर भी लागू होती है, ऐसे लोग भी हैं जो केवल 'स्वतन्त्र सुधार' कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं, उदाहरणार्थ, कोई विदेशी भाषा, या चित्रकला, या संगीत या आन्तरिक सरक्षा, पाठ्यक्रम, पुष्प-विन्यास, या कोई ऐसा काम जो उनके व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा को सब की सब और आवश्यकता के अनुकूल बनाना जाना चाहिए। महत्त्व की बात यह है कि बहुविध विषयों के विचार से तैयार किए गए प्रच्छेद और कल्पनापूर्ण पाठ्यक्रम ही अध्यापन की प्रेरणा देने वाले सफल साधन बन जाते हैं।

17.35 हम शिक्षाविशेष करते हैं कि सभी प्रकार की और सभी स्तरों की वैश्विक संस्थाओं को प्रोत्साहन और सहायता दी जाए कि काम के निश्चित पटों को छोड़कर ऐसे समय में किन वैश्विक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर सकें, करें, और बदले द्वारा उन सब लोगों के लिए खोजें जो शिक्षा प्राप्त करने में योग्य हैं और जिला पाने के

निए इच्छुक हैं। इन दृष्टिकोण को सतार-भार में समर्थन मिला है, पर हमारे देश की परिस्थितियों के विचार से तो स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक है, यद्यपि उचित शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना ही जीवन आरम्भ करने के लिए देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों ने बहुतों को विवश किया है। इसलिए हमारा सुझाव है कि उन लोगों के लिए, जो शैक्षिक समस्याओं से वैश्व धारा को व्यवहार के कुछ घटो के बीच अवस्था अन्य सुविधानलक समय में हो जा सकते हैं, एक समान-तर शिक्षा-पद्धति अपनाई जाए ताकि वे भी उस प्रवाह-धारी शिक्षावादी और शिक्षियों के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें जिनके लिए शैक्षिक समस्याओं के नियमित विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। देश के विभिन्न भागों में छात्रकालीन कालेज का जो विकास हुआ है, वह हमें प्रामुख है। हमें साक्षात् है कि विभिन्न भागों में चलने वाले छात्रकालीन कालेज ऐसे वातावरण में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करके विद्यार्थी अध्ययन की प्रेरणा मिल, नियमित शिक्षा पद्धति में बाहर के लोगों को नाममात्र की हानिरी देने करते परीक्षामोपबैठन की पात्रता खरीदने के योग्य नहीं

बनाये। भाष्यमिक स्कूलों और कालेजों को ही नहीं, सभी समस्याओं को निरोपकर व्यावहारिक, तकनीकी और कृषि संस्थाओं को काम के नियमित घटो के बाद अद्य-कालिक शिक्षा की व्यवस्था करने चाहिए।

17 36 शैक्षिक समस्याओं को ऐसे तरबं वाट्पकम में प्रणयों होना चाहिए जो लोगों की अपनी समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने में तथा व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने में सहायता दें। संसाधरण के लिए भूमि प्रणय, उर्वरकों का प्रयोग, मुर्गी-पालन, कलो-पालन, छिन्नुपालन, पोषण, उपवर्ग सम्बन्धी समित्त वाट्पकमों के नाम मिलाए जा सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों की समावधानों अलग हैं वस्तु की सज्जों तरह योजना बनाई जाए और सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, तकनीकी संस्थाओं और स्थायीय नेताओं का सहयोग मिले। इन वाट्पकमों की आरम्भित करना ही पसंद नहीं, पक्ष की बाव है-सोचों में अध्ययन, जो प्रवृत्ति कक्षाओं और विभिन्न वाट्पकमों में दृष्टि लेने वालों के समूह संगठित करता।

—कमल:

अखिल भारत नयी तालीम

कार्यकर्ता सम्मेलन

२५, २६ तथा २७ मई १९७६

को

पश्चिम बंगाल में होगा।

सम्मेलन के निश्चित स्थान की सूचना बाद में दी जायेगी।

सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रतिनिधि अपना शुल्क रुपये आठ प्रत्येक की दर से श्री बजू भाई पटेल, मंत्री, अखिल भारत नयी तालीम समिति, राष्ट्रीय शिक्षण मन्दल, बम्बई।

४००५४ को भेजकर रेलयात्रा या रियायती फार्म भेजावे।

नयी तालीम दिसम्बर-जनवरी ७८-७९

रवि० सं० WDA/I

साइस न० ५

जब तक लाखों बरोणों लोग
 भूख और अज्ञान से ग्रस्त हैं
 तब तक मैं उस आदमी को
 गद्दार मानता हूँ
 जो उन गरीबों के दो पैसों से
 भीखकर उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते ।
 मेरे विचार के अनुसार हमारा
 सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप है
 आम जनता की ओर हमारी उपेक्षा
 और हमारी अवनति का
 एक कारण यही है ।
 बिलौली भी राजनीति करते रहो
 उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है ।
 जब तक कि भारत की आम जनता
 अच्छी तरह शिक्षित नहीं होती ।
 उन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिलता
 और उनकी फिक्र नहीं की जाती ।

—मन्मोहि विवेकानन्द



प्रमाण भारत नयी तालीम समिति के लिए श्री अशोक कुमार वर्मा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति द्वारा प्रकाशित तथा विद्या मुद्रण स्थली भदोही, वाराणसी से मुद्रित ।

नयी तालीम

विश्वविद्यालय प्राणियों में अस्तित्व
सामाजिक परीक्षाएं
ग्रैंड शिक्षा की पुष्टि
हमें स्वतंत्र नयी समाज करना है
पूर्व बुनियादी या नर्सरी शिक्षा



अखिल भारत नयी तालीम समिति

पृष्ठ २७
पत्रवरी
मार्च

अंक

प्रधान सम्पादक—	श्री के० अरुणाचलम
सम्पादन मंडल—	श्री डारिकर विह
	श्री बन्धू माई पटेल
	श्री काशीनाथ बिबेदी
	श्री ज्योति भार्द पटेल
सम्पादक	श्री दयानंद दास तिवारी
सह सम्पादक	श्री चन्द्रशूषण

सम्पादकीय

पृष्ठ १

चिरविविधालय छात्रों के असतोष

सांस्कृतिक परीक्षाएँ

सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रीट्ट शिक्षा बोर्ड

आ० देवेन्द्र दास तिवारी

३

प्रीट्ट शिक्षा की पृष्ठ भूमि

डा० श्रीलालदास आदरदास

४

शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का स्थान

चन्द्रशूषण काव्यमीमांसा

५

हमें स्मरण क्यों करना करना है

डा० देवेन्द्रदास तिवारी

१२

प्रीट्ट शिक्षा की छात्रों की शिक्षा काव्यमीमांसा की रिपोर्ट

१४

प्रीट्ट शिक्षा में आध्यात्मिकता

कृष्णदास मिश्रा

२२

पूर्व बुद्धिदायी या नवरो शिक्षा

शुभदा संलग्न-चन्द्रशूषण

२३

गोबध पर प्रतिबन्ध

के० अरुणाचलम

१९

छात्रों का पत्र '७६

नवी तामील का धार्मिक गुरुक बारह रुपये तक का मूल्य दो रुपये है ।

नवी तामील धार्मिक धर्मिका है, इसका मूल्य अत्यंत ही प्रारम्भ होता है ।

यह धर्मद्वारा के लिए सभी पाठक कृपया अपनी साहसिक सहायता अवश्य भेजें ।

नवी तामील में अत्यंत विचारों का धार्मिक धर्मोत्तम लेखक का है ।

नयी तालीम

विद्यार्थी, प्रशिक्षकों तथा शागुनित वित्तों के लिए

विश्वविद्यालय प्रांगणों में असंतोष

देशीय विद्या मन्त्री डा० प्रतापचन्द्र ने मोहताया में बताया कि वह कहना चाहते हैं कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में असंतोष है और संसिक कार्य आत व्यत है। उन्होंने आँखें देते हुए कहा कि देश के १०२ विश्वविद्यालयों में केवल ३३ अतः तोष और सम्बन्धों से प्रभावित रहे। देशीय विद्या मन्त्री एक सम्बन्धित क विज्ञान और अनुसंधान स्थिति हैं। किन्तु जिस प्रकार अन्तःस्थ सम्बन्धों से प्रभावित है उससे यह प्रतीत होता है कि मोहताया ही ऐसे स्थिति पर भी जिस प्रकार प्रभाव अन्तःस्थ है। माननीय विद्यामन्त्री की के समक्ष जो आँखें प्रस्तुत गिये गये हैं उन पर उन्हें विश्वास बरता है। कभी कभी हम किसी विशेष परिस्थिति से रहकर गलत बातों को वास्तव में नहीं समझते लगते हैं।

ये आँखें विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अधिकाधिकों के देखे होये और इनमें अधिकांश वे हैं जो सामान्य के दृष्टिकोण हैं। इनका अपना न तो कोई प्यारिल है और न कोई लक्ष्य। ऐसे लोग जैसे ही आँखें भेजते हैं जिनसे छात्रों में लोग यह समझें कि विश्वविद्यालय पूर्णरूप से अनुशासित हैं और कम से कम पटनाई ब्यापित, सम्बन्धों और अतः तोष की सुविधा की जाती है। स्थिति कुछ बेसी ही है जैसे पुलिस प्रशासन व्यवस्था की व्यवस्था में कभी इस आधार पर प्रदर्शित करता है कि पुलिसवालों पर बहुत ही बटवाई या तो बर्ग ही नहीं की जाती या लोग इस दुर्घटना से बर्ग न करने हैं। नहीं आते कि लोग बवाल में पड़ें।

वास्तविक स्थिति यह है कि ३३ या लगभग इतने ही विश्वविद्यालय ऐसे और होंगे जिनमें छात्रों के सम्बन्धों और विश्वविद्यालय प्रशासन की दुर्गन्धों के कारण संसिक वातावरण भरत-भरत रहा होगा। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें देर से सत्र प्रारम्भ हुए किन्तु परीक्षाओं सम्बन्धों से बर्ग की बर्ग आ कर दी जा रही है। छात्रसंगठनों की छात्रों के सम्बन्धों से बर्ग की बर्ग रखा जा रहा है। शिक्षण कार्य अत्यन्त विकृत स्तर पर चल रहा है। प्रकाशक अपनी चरम सीमा पर है। ऐसी स्थिति में यदि माननीय विद्या मन्त्री को यह सम्बन्धों है कि केवल एक विद्याई विश्वविद्यालय सम्बन्धित हैं और ७९ विश्वविद्यालय ठीक से चल रहे हैं तो यह दृष्टान्त को सामने देखकर सुबुर्बुर्ग वाली नीति अपनाते सभी बात परिवर्तित होती है।

यह प्रभावता की बात है कि सांख्यिक चयनक्रांति के सम्बन्धों से सम्बन्ध होने के पूर्व प्रभावमन्त्री को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इस बात पर लिखा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय सम्बन्धों के बर्ग की सहृदों में फले हुए हैं और उन्मत्त अवस्था की स्थिति व्याप्त है। यह सम्बन्धों में नहीं आता कि विद्या मन्त्री के सम्बन्धों पर निश्चाय दिया जाय या कीदनात्मक है।

दसरा समाधान कहा है? यह प्रश्न आज देश के सामने है। मोहतायिक सरकार सबसे बड़ा उपकार यह करेगी यदि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पाठ्यक्रांति और सुविधा के आधार पर नहीं प्रमुख वास्तविक योग्यता और सम्बन्धों के आधार पर की जाय। ऐसे स्थिति इस मोहतायिक पर की सुशोभित करें जो

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रौढ़-शिक्षा केंद्र

छात्र-केन्द्रित एवं सार्वजनिक

जीवन के ज्ञानात्मक करने और ज्ञानात्मक कराने की दृष्टि प्रारम्भ से ही रही है। इसीलिए वैश्विक प्रसारण का क्षेत्र यहाँ कभी रूढ़िवादी नहीं रहा। विश्वविद्यालय में आने के पूर्व अनेक सामाजिक आवश्यकताओं, समस्याओं और व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मैं अभिप्रेरित कर चुका था। स्वयं भी कम से कम दो प्रौढ़ों को शिक्षित करने का काम भी कर चुका था। दोनों प्रौढ़ों के लिए दो निम्न निम्न मार्ग उपलब्ध थे। एक सामाजिक चेतना का परिपूर्ण था, जबकि वह विरल था। मैंने उसे समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ने की प्रेरणा दी। जब पढ़ना आ जाता है तो शिक्षा की अपनी राहों को पहचानने की क्षमता का विकास करने में कठिनाई नहीं होती। था वह पहले से अज्ञान पर प्रकाश है और सोच बहुत अपनी कामकाज बनाने के लिए जिस भी लेता है। उसमें एक भावविशेषता है और यदि वह अविश्वसनीय रूप से रहता तो कदाचित् कोई परीक्षा भी पास कर लेता।

दूसरा व्यक्ति भी मेरे निजी सम्पर्क में ८२ वर्ष रहा। वह मेरा मोस्त पाना था और पुरा शिक्षा कापीय के बाधुओं से निरुत्साह था। एक दिन मैं सबसे कहा कि तुम दूसरों को तब बता दोगे ही कि मैं क्या करता हूँ, शाने पर कितना खर्च करता हूँ। उसकी यह बात लग गई और उसने अगल आज तथा कुछ बहुत सोच लिया। मायाएँ उसने नहीं छोड़ी, लेकिन 'टपाटर' को 'टपाटर' और 'नोनी' को 'बग' लिखकर काम चला लेता था और मैं उसे समझ लेता था।

मेरे ये दो उदाहरण हमारे दिलों में हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को यह स्पष्ट हो जाना कि

प्रौढ़ों की प्रेरणा का क्षेत्र निम्न-निम्न होते हैं, जिनमें एकोनव्यक्त नहीं होती और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर प्रौढ़ जिस रूप में शिक्षित करना चाहते हैं, उसकी प्रेरणा का स्तर नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रौढ़ों की निर्धारित पाठ्यक्रम का धारण नहीं बन सकता। कुछ ऐसे भी निरुत्साह धारणों को कोई परीक्षा देना चाहते हैं लेकिन यह सम्भव नहीं है और बहुधा इससे कोई उल्लेख भी नहीं होने वाला है। पान यह बात पर रहना चाहिए कि वह अपने काम को अपनी तरह से कर सके, ऐसी शिक्षा उसे भी लाभ। प्रौढ़ों के शिक्षा और समाचार पत्र या फिर स समाचार पत्र निरुत्साह है।

मेरे विश्वविद्यालय में जब यह शब्द के कार्यक्रमों को करना चला तो एक दिन विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित एवं विद्वान विपक्षीय यह भी सुनने को मिला कि प्रौढ़ शिक्षा का उच्च शिक्षा का क्या सम्बन्ध है और दोनों को एक साथ जोड़ना उचित नहीं है, जब कि प्रौढ़ शिक्षा की 'राष्ट्रीय नीति को पोषण' तथा 'प्रौढ़ शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम' इन दोनों अभिलेखों में प्रौढ़ों के विकास के विश्वविद्यालयों के विचार दायित्व पर बल दिया है। 'प्रौढ़ शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य को बनाने के क्षेत्र में प्रौढ़ों के विकास के लिए है —

“For too long the universities have theoretically espoused about desirability of contact with the community. The NAEP Provides a challenging situation for the University and college to overcome their seclusion and to

enter the main stream of mass education".

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस कार्यक्रम से विश्वविद्यालयों को सम्बन्धित करने के लिए अनेक सुझाव अपने एतद्विषयक परिपत्र में दिये हैं। विश्वविद्यालय में प्रोढ़-शिक्षा इकाई की स्थापना की बात भी उही गयी है। तदनुसार विश्वविद्यालय में कुम्पटि की सम्पन्नता में एक परामर्शदात्री-समिति ब्रिटीश की गई है और प्रोढ़-शिक्षा को विद्याचार्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। इस सच्य का उल्लेख इसलिये किया गया है कि अग्यी विश्व-विद्यालय के लोगों को इस बात का आभास नहीं है कि प्रोढ़-शिक्षा उच्च शिक्षा से किस प्रकार सम्बन्धित है। विद्यालय: शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है इसलिये निरन्तर प्रोढ़ भी कभी उच्चशिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। सन्धन में वो 'खुला विश्वविद्यालय' (Open University) है उसमें प्रवेश पाने के लिये केवल २१ वर्ष की सीमा का ही एक प्रतिबन्ध है। मर्यादा कोई भी उम्र में प्रवेश के सकता है और आज उच्च विश्वविद्यालय में ७०,००० छात्र-छात्राएं हैं।

सैलिक-अनुसन्धान की दृष्टि से प्रोढ़ों को सीखने-विज्ञाने, सम्प्रेषण आदि के सम्मन्ध में खोप की आवश्यकता है जो विश्वविद्यालय ही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों को यह समझना है कि प्रोढ़-शिक्षा का सामर्थ्य उसी प्रकार है जिस प्रकार उच्च-शिक्षा का आवश्यक क्षेत्र में।

इस सम्मर्ध में विश्वविद्यालय के प्रोढ़ शिक्षा क्षेत्र को पहानी बता देना आवश्यक है। पहले मने यह सोचा कि अधिकारियों के अधिकार का प्रयोग करके बचाएँ बनाई जायें। इस पर अधिकारियों ने आदेश निर्यस्त किये कि वो बर्बकारी इन बन्दाओं से लाभ उठाना चाहें के विद्यालय-विभाग में उपस्थित हो किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। फिर मने बर्बकारी सभ के परामर्शकारियों और विद्यार्थियों का सहारा लेना उचित समझा। अब जब बात हुई तो यह बंधा कि पहले दिन जब हस्ती गयी छात्रों में ४

वर्षा हो रही थी और बिजली भी नहीं थी, लगभग २५ बर्बकारी भीषते हुए बाहर बैठे रहे। उनसे बात किया और उन्होंने इन कथाओं में रुचि दिखाई और दूसरे दिन जाने कहा।

दूसरे दिन सख्या बढ़ गई। कुछ विश्वविद्यालय के और कुछ बाहर के लोग भी आए। कुछ बच्चे भी आए जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गये हैं, दण्डि बोपला प्रोढ़ों की शिक्षा के लिए ही को रखी थी।

इस प्रकार २ बच्चे ग्राहमरी मायु वर्ग के और २४ प्रोढ़ सचम निरक्षरता की परिधि में तथा लोग ऐसे हैं जो बू. हा. स्कूल से ऊपर भी शिक्षा पाये हुए हैं, किन्तु आगे पढ़ने की उनमें इच्छा है। विभिन्न मायु-वर्गों की इस कथा रचना में यह बात स्पष्ट हुई कि प्रोढ़-शिक्षा का जो भी केन्द्र हो उसमें इस बात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता कि वे किसी निश्चित मायु के हो या केवल निरक्षर ही हों। यह इस बात का भी संकेत करता है कि सबकी आवश्यकताएं, उपस्थितियाँ और क्षमताएं भिन्न-भिन्न हैं और सबको एक ही कक्षा में नहीं रखा जा सकता है।

अतः पहले ही दिन बार यू.ए. में कथाओं की बात देना पड़ा। समस्या यह भी थी कि अनेक ही कंठे इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। मेरे छात्रों और छात्राओं ने मेरी कठिनाई को समझा। एम. एड. कक्षा के विद्यार्थियों ने मेरी परेशानी समझ कर अपना सहयोग दिया। एक-एक ग्रुप को उन्होंने सहायता ली। इस छात्र छात्राओं का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। यह होगा भी तो अपने बचपन या पर में अपने से छोटे से सन्निवत अनुभव ही होगा। इनमें से एक छात्रा ने तो प्रोढ़ों की भाषा में ही दोस्त-चाल कर उनसे तादात्म्य कर लिया। परिणाम यह हुआ कि प्रतिदिन सख्या तथा उपस्थिति बढ़ने लगी।

मेरे पास कोई साधन नहीं था। अपनी सामर्थ-हीनता के कारण परेशानी भी थी। देव में करोड़ों रूपया प्रोढ़-शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। किन्तु यदि कोई काम अच्छे ढंगसे प्रारम्भ किया जाय तो उसके लिए कोई मोटा-

हा गयी है। उ० प्र० के प्रौढ़ शिक्षा विभाग के सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अगर ये इस प्रकार के सेंट्रल को सहायता देने का कोई प्राविधान नहीं है। यू० जी० सी० ने मुझे यह बताया कि २५०० डॉ० की अनराइजिड योग रूप में स्वीकृति की गई है कि तु विश्वविद्यालय ने अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। एन० एच० एच० के अन्दर इस प्रकार के काम करने का दायित्व है कि तु, उधर से भी कोई ठोस सहयोग नहीं है।

कुछ प्रशासि स्टेट, भाग, पुस्तकों के ऊपर खर्च की गयी है, उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पायी है। प्रौढ़ शिक्षा विश्वविद्यालय के दायित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है, योशिन मैं पहले ही कह चुका हूँ, कि तु विश्व विद्यालय परितर में इसका आकाश भी नहीं है।

मुझे एक श्रम और परेशान कर रहा है, वह पाठ्यक्रम से सम्बन्धित है। केन्द्र को पता है कि वह स्पष्ट हो रहा है कि कोई पूर्ण विरहित पाठ्यक्रम काम नहीं बना और पाठ्यक्रम प्रायः प्रौढ़ से परामर्श करके तैयार बनाया होगा। जहाँ तक शिक्षण विधि का प्रश्न है, चूंकि हम लोग एक-दूसरे इसकी सहाय से सम्बन्धित हो गये, अतः किसी विधि या सुविधिपल रूप से क्या चलाने की उम्मीद भी हम लोग नहीं कर पाये। कुछ परम्परागत विधि, कुछ समाचार पत्र, कुछ पत्र-व्यक्तियों का प्रयोग करके काम चलाया जा रहा है।

अपेक्षित विवरण से यह प्रतीति स्पष्ट है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना के कार्यक्रम में जो ५० डॉ० के एक प्रौढ़ शिक्षक से काम कराने की बात कही गयी है, वह निश्चित अल्पवर्ष है और एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर एक शिक्षक से किसी भी अवस्था में काम नहीं चल सकता है। जो दिल्ली में बैठकर योजना बनाते हैं और लोग से काम करने के लिये बिना के पास समय नहीं है, वही एक प्रौढ़ शिक्षक से केन्द्र चलाने की बात कर सकते हैं।

मैं तो मे मुझे इस बात की वि ता है कि इस केन्द्र की स्थायी और अस्थायी रूप से इस प्रकार बताया जाय। यह बन सके तो लगभग २०० १०० प्रौढ़ जाने अपने सरकारी नियमों में क्या यह प्रयोग, प्रयोग ही यह चाहेगा या विरविद्यालय सहाय सेवा के द्वारा कार्यक्रम को अपना बना लेंगे। यह प्रश्न चिन्हा सामने है।

कुम्भपति, भाषार्थ बड़ीभाष मुक्त की नये प्रयोगों में चर्चा रहती है। समाज-सेवा-कार्यों में उनकी उत्पन्न है। उ होने वाली बाधों से समर्पण प्रिया है मुझे विश्वास है कि काम प्रकार से भी इनका समर्पण इस कार्य के लिए प्राप्त होगा।

छात्र छात्राओं के प्रति मैं हृदय से कहना चाहूँ कि मेरी इस सन्तान को साकार करने में वे निस्वार्थता से परिश्रम कर रहे हैं और अपना समय भी रहे हैं।



प्रौढ़ शिक्षा की पृष्ठभूमि

डा० सोलाशान जायसजाल, शिक्षा विभाग, सततक विरविद्यालय

सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार भारत में पाण्डिता संख्या २२ प्रतिशत है। दूसरे पक्षीय गणना के अनुसार ७० प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। यदि भारतीय मोरटन को प्रतिशाली और दुष्ट बनाना है तो हमें भारत को निराक्षर के समिधान से मुक्त करना होगा।

प्रश्न यह है कि भारत में निराक्षरता की मात्रा इतनी अधिक क्यों है? भारत में लक्ष्मों का जन के पूर्व शिक्षा

की स्थिति काफी अच्छी थी। निराक्षरता की मात्रा भी कम थी। प्रमाणितकर १८२३ ई० में प्रकाशित ईस्टइंडिया कंपनी की एक रिपोर्ट का विष्णुसिंह सदा उल्लेखनीय है "विद्या की दृष्टि से सभार के किसी भी भाग देश में शिक्षा की दशा इतनी अच्छी नहीं है जिसकी चिट्ठा भारत के अनेक भागों में है।"

जन्मीसवी शती में दूसरे और तीसरे दशक में भारतीय

१. दे० तिलक की पुस्तक प्रौढ़-विद्या प्रसार हि० रकार्ड रक्षारी प्रकाशन, इलाहाबाद, १९४८, पृ० १५.

जनता गरीबी और अक्षरता से पीड़ित न थी। ३ जून १८१४ को प्रजासत्ताक गवर्नर जनरल ने अपने पत्र में लिखा था : ' शिक्षा की जो प्रणाली बहुत पुराने समय से भारत में यहाँ के आचार्यों के अधीन जारी है उसी सबसे बड़ी प्रशंसा यही है कि देखते ब्रह्म वेद के अधीन जो मद्रास में वादरी रह चुके हैं, वही सभीका इस देश (इण्डिया) में भी प्रचलित किया गया है, अब हमारी राष्ट्रीय सरकारों में इसी प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती है क्योंकि हमें विश्वास है कि इससे माया का हिलाना बहुत सरल तथा सौकर्यपूर्ण हो जाता है ।'

भारतीय शिक्षा जन सामान्य में विश्व रूप में प्रचलित की इसका वर्णन हम उस प्रतिवेदन में भी मिलता है जो भारतीय वृद्धि विभाग ने सन् १८८२ में प्रेषित भारत सरकार के शिक्षा आयोग (हार्डर कमिशन) के सम्मुख प्रस्तुत किया था। शिक्षा आयोग की प्रस्तावनों के प्रश्नों का उत्तर भारतीयों ने लगभग २०,००० पन्नों में अंग्रेजी भाषा में लिखकर भेजा था। अपने शाब्दिक भाषांतरों में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से पूर्व परिवर्तन-सदृश भाव के तथ्यों में प्राचीन परिपाटी की शिक्षण व्यवस्थाओं के बड़े सदा में होने का उल्लेख किया था।

भारतीय वृद्धि विभाग के प्राचीन परिपाटी की वैश्विक व्यवस्थाओं का सात धर्मियों में वर्गीकरण किया था जो कि निम्नलिखित हैं :

१. षट्साले, जिनमें नागरी, बंसी या महाजनी रूपमाला पढ़ावे, मौलिक गणित, जोड़, बाँट, गुणा, भाग मूल तथा मूल दर मूल निकासक सिखाया जाता था।

२. सङ्कत पाठशाळाएँ जिनमें खोतिय, गाय, रसम काव्यशास्त्र गद्यमा आता था।

३. वेद, मीमांसा वेद व आदि की शिक्षा देने वाली पाठशाळाएँ।

४. महाजनी पाठशाळाएँ जिनमें देखी व्यापार, बलिष्ठ तथा वहीलता निम्नलिखित सिखाया जाता था।

उपर्युक्त चार धर्मों की पाठशाळा में में आम हिंदू विद्यार्थी हो पड़ते थे।

५. मातृव बिमों भारतीय शिक्षा और पढ़ाई सिखाया जाता था। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों विद्यार्थी पड़ते थे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद इन मतधर्मों की व्यवस्था तेजी से घटाने लगी थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने फारसी की जगह अंग्रेजी को राजभाषा बना दी थी।

६. अरबी साहित्य, व्याकरण, गणित, दर्शन आदि की शिक्षा देने वाले मकतब।

७. कुशाग्र शिक्षण करने वाले मकतब।

यदि प्राचीन परिपाटी को वैश्विक व्यवस्था में पसंदीदा तरीका माना जाये तो भारत में निरंतरता की वृद्धि होगी। लेकिन विदेशी शासकों की नीति थी कि भारत के लोगों को दबा कर रखा जाय और उन्हें ऐसी शिक्षा न दी जाय जो उनके मन में राष्ट्रीय चेतना और वैश्वगति उत्पन्न करे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शासकों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए प्रयास किया। प्राचीन धर्मों की विदेशी शासकों ने उपेक्षा की और लोगों से रहने वालों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाने लगी जो उन्हें विदेशी शासकों के प्रति निष्ठावान बनाती थी। सन १८५७ से १९१९ ई० तक ब्रिटिश शासकों ने धर्मशास्त्र की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। पसत कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं ने अपने प्रयास से कुछ संस्थाएँ खोलीं। बंगाल राज्य में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना सन् १८१० में की गयी। इसी प्रकार बंगाल में भी वैद्यमन्त्र लोको के प्रयास से कई प्रौढ़ पाठशाळाएँ स्थापित की गयी।

प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में दूसरी ऐतिहासिक लिपि है १८१९। १८२९ से लेकर १८४७ तक की अवधि में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का एक व्यवस्थित स्वरूप विकसित होता है। यह स्वरूपीय है कि प्रथम दिवस मूल १८१९ में सम्पन्न हुआ था। प्रथम दिवस मूल के बाद भारत के लोगों में देश की आकांक्षी के प्रति एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ। फलतः भारत में साक्षरता प्रसार के प्रयास भी होन लगे।

१. यही पृ० १५-६ २. रणतम भारत, साप्ताहिक परिशिष्ट, ३ सितम्बर सन् १९७८, पृ० ८

गांधीजी और प्रौढशिक्षा

प्राचीन जी मे जीवन के सभी पहलु पर समुचित प्रकाश
 डाला है। उन्होंने प्रोद्योगिकी के महत्व की खूब समझ
 बनायी थी जब भोग देवल साधारण पर ही ध्यान दे रहे थे।
 यह उल्लेखनीय है कि प्रद्योगिकी युद्ध के बाद प्रोद्योगिकी साधारण
 पर अधिक प्रकाश दिया गया। इसका कारण यह था
 कि खूब समय कम सुचारु के माध्यम, जैसे रेडियो और
 टेलीग्राफ, का विकास नहीं हुआ था। फलतः युद्ध के और
 पश्चात्प्राचीन के माध्यम से ही लोगों को नवी व्यवस्था की
 प्राप्ति होती थी। अतः जो लोग निरक्षर थे, उन्हें साधारण
 बनाया जायावक सम्भव था।

इससे तादेह नहीं कि प्रीति विद्या का एक महत्वपूर्ण अंग साक्षरता है। खेदिन केवल अक्षर ज्ञान ही वर्णनीय नहीं है। इस स दर्शन में वर्णनीय जो का निम्नलिखित कथन प्रदान देने योग्य है:

^१'दाशतम मेरी राख म हूँ। मैं लक्ष्मीनारायण और मजिब होने । कारण निगराहा इतना नहीं है जिसका कि ध्यान है । इसलिए कदर सोचो की शिक्षा के लिए भी मुझे अपना अज्ञान ही दूर करने का एक उपाय कर लेना पड़ना चाहिए । मेरे कहने वा मतलब यह नहीं है कि उन्हें परमात्मता का ज्ञान नहीं करा जाता । .. नहीं, इसकी तो मैं अधिक कीमत मानता हूँ जिधिया के एक छात्र के रूप में मैं उसे हमेशा नज़र स नहीं देता ।

• यह बात नापीबी ने जून १९१७ में कही थी और माननीय मध्य पूर्णतः सत्य है। प्रौढ़ साक्षरता और शिक्षा का वाधन है न कि साम्य। लेकिन अविचलित लोगो ने प्रौढ़ साक्षरता को ही प्रौढ़ शिक्षा मान लिया था। वर्ष १९०॥ में जब भारत में अधिष्ठित प्रत्येक मं ब्राह्मण के लिए प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य तय की गई थी।

श्री ८ दिशा ■ अन्तर्गत समाज के दुर्लभ वर्गों, विशेष-
कर धार्मिक समाज के अल्पवित्तीयों की आवश्यकताओं

पर ध्यान रखते हैं। ऐसे विषयों को प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में स्थान देना आवश्यक है जो व्यक्ति और समाज की दृष्टि से उपयोगी है। इस सन्दर्भ में गांधीजी का यह कथन महत्वपूर्ण है कि निरक्षरता से अधिक आवश्यक है अज्ञान के अन्वेषण को दूर करना। दूसरे शब्दों में, गांधीजी ने यहाँ एक ऐसे तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो प्रायः हम भूल जाते हैं। यह तथ्य है साक्षरता और शिक्षा में अन्तर। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक साक्षर व्यक्ति अशिक्षित हो सकता है और एक निरक्षर व्यक्ति को शिक्षित माना जा सकता है यदि हम शिक्षा को सही अर्थों में स्वीकार करें।

महात्मा गांधी ने अनुसार, विद्या वह है जो मुक्ति
 विधाने पाती हो 'यः विद्यां या विमुक्तये' .. ऐसी शिक्षा
 बोले गांधीजी थे श्रेष्ठ विद्या खती है ।.. यह विद्या ही
 जीवन की पुस्तक है शिक्षा है ।

अब यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीयीकरण के लिए भी शासकों को ज्ञान का प्रयोग नहीं मानते थे। उनका ज्ञान जीवन में जीवन को आगे जीवन के लिए प्राप्त होता है। यही कारण है कि नई तकनीक की आवश्यकता पड़ते हुए उसे जल्द से जल्द जीवन पर्यन्त चलन वाली शिक्षा के रूप में स्वीकार दिया गया। इतना ही नहीं, नई तकनीक का प्रत्यक्ष और अद्वितीय पर आधारित नए प्रकार के संस्कृति के अन्तर्गत जीवन में स्थापित किया गया और व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में राज्य और अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया।

सबसे अधिक भारत में प्रौद्योगिकी शिक्षा

१६ अथर्व ऋग्वेद की भारत पर वस्तुतः हवा तथा मौसमों अत्यन्त बुरा प्रभाव पड़ा। मनी निम्नलिखित किये गये। इन्होंने प्रौढ शिक्षा के स्थान पर सामान्य शिक्षा प्रयोग पर बल दिया। इसका कारण बताते हैं कि प्रौढ शिक्षा केवल प्रौढ शिक्षा पर बल देकर प्रौढ के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर भी ध्यान देने लगे। शिक्षा में भी मौसम

२. महारवा धर्मी, क्राष्म दलजाज, नवशीवत
प्रवाशन, अहमदाबाद, (१९३), प० ७४

१. रमनाथ गुप्त, शिक्षण और संस्कृति
(भाषी), उत्तर प्रदेश भाषी स्मारक निधि, बाधगुप्त
१९५५, पृ. २३३

अबुल कलाम आझाद ने यह स्पष्ट घोषणा की कि प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत सामाजिक चेतना के विकास पर भी बल दिया जाय। फलतः समाज शिक्षा का एव पत्र पुनर् कार्यक्रम बनाया गया जो इस प्रकार है।

१. साक्षरता प्रसार

२. स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों के ज्ञान का प्रसार

३. वयस्क व्यक्तियों के आर्थिक स्तर की उन्नति

४. नागरिकता की भावना, अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति जनता में जागरूकता को प्रोत्साहन देना, और

५. सामाजिक बदलि की आवश्यकताओं के अनुकूल स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।

इसमें सन्देह नहीं कि समाज (प्रौढ़) शिक्षा का यह कार्यक्रम समग्र जीवन को प्रभावित करने वाला या क्योंकि इसका सम्भाव्य अवधि और समाज की आवश्यकताओं से भीषा गया था।

सन् १९५२ के आसपास जब भारत में सामुदायिक विकास की योजना बनाई गई तब उसमें समाजशिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया और इसके लिए समाजशिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। लेकिन ज्ञाना तत्पश्चात् सामुदायिक विकास की योजना का परिणाम आशासीत न हुआ। सामुदायिक विकास की योजना में प्रदर्शन और प्रचार की ओर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया गया। जागरी योजनाएँ और उनके सम्बन्धित उपबन्धों के माफ़े अविवक्षित्य हो गये।

भारत की परिस्थिति और कुछ समय बाद चीन से जुड़ करना पड़ा। इसका प्रभाव भी अब कल्याण की योजनाओं पर पड़ा। आर्थिक अभाव के कारण समाज शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ी। सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार पर यह बात हुआ कि १९५१ से लेकर १९७१ की अवधि में भारत में साक्षरता की वृद्धि केवल १२.९७ प्रतिशत हुई जो कि अत्यन्त-उपजवक वाली जायगी यदि हम १९५१ से लेकर १९७१ की अवधि में साक्षरता की प्रगति देखें तो यह केवल १.३१ प्रतिशत हुई।

१. ओपर मुखर्जी, भारत की शिक्षा, भाषाएँ, कुल शिक्षा, बरौदा, १९६०, पृ. २५३

नवी तालीत / ५

जब यह स्पष्ट है कि भारत में निरक्षरता और ज्ञान की समस्या का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से नहीं हो सकता। इसके लिये प्रत्येक शिक्षित नर नारी को प्रयास करना होगा।

प्रौढ़शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम

समाज शिक्षा की संरचना में निम्नलिखित मान्यताओं का धारण हो चुका है। इसने बाद क्रियात्मक साक्षरता (कलिंग), अनवरत शिक्षा [कॉन्टिन्युअस एजुकेशन] तथा धनोपार्जित शिक्षा [नान पार्मेस एजुकेशन] होने लगी। इन मूल्य संरचनाओं के मूल में यह भावना प्रमुख थी कि रोमित समय के लिये प्रदान की जाने वाली धनोपार्जित शिक्षा तोत्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य में अपूर्ण होती है। फलतः शिक्षा में दिया और दस्तकारी का समावेश करके इसे जीवनोपयोगी बनाने पर बल दिया गया। साक्षरता के कार्यक्रम की भी क्रियात्मक रूप दिया जाने लगा।

यह उल्लेखनीय है कि हमारे देश के परिधान में ५ से १४ वर्ष के बाल, बालों के बालों एवं बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान है। अतः १२ वर्ष और उसके ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए बाह्य में निरक्षर हो खपवा साक्षर ऐसी प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था होनी जो उनमें देश प्रेम, संवृद्धि का अनुकूलता से साक्षात् जगत् में नागरिक बनने की प्रेरणा प्रदान करे।

भारत सरकार की वर्तमान जनता सरकार ने यह अनुमान दिया कि जब तक देश में अज्ञान और निरक्षरता का बोझ बाला रहेगा तब तक समाज के पीछे और दुर्लभ वर्ग का संरक्षण नहीं संभव। यह स्मरण है कि करोड़ों और अशिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम अपने देश से करोड़ों को हटाना है तो ऐसी प्रौढ़ शिक्षा की योजना बनानी होगी जिसका सीधा सम्बन्ध समाज के करोड़ और दुर्लभ वर्ग से हो। इतना ही नहीं प्रौढ़ शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की ध्यान से रचना होगी और शिक्षा की ऐसी पद्धति अपनायी होगी जो लोकतन्त्र और मनोरंजन दोनों में सहज हो।

भारत की सांस्कृतिक संपदा अपार है। कबीर, नानक दादू, रैदास आदि स १ सयने युग के सही बर्णों में प्रौढ़ शिक्षा के। इन्होंने जनता को भाषा में सत्य का उद्घाटन किया और सच्चाई से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा प्रदान की। एत्यों की सरल बातियों को हमें फिर से प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में सम्मिलित करना होगा। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि हम सभी वर्गों की मूल एकता को जब जन के मन में घर दें। राम, रङ्गो, कृष्ण, कबीर को लेकर कबीर ने विश्व नवमानववाद का प्रसार किया था वह मात्र भी सभी लोगों के लिए, चाहे वे साधारण हो अथवा निरक्षर, उपयोगी है।

अन्त में एक बातको देना चाहता हूँ। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम एक प्रकार का साधन या बल है। यदि कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम को व्यक्तिगत लाभ का साधन

बनाता है तो यह राज्य के प्रति एक अपराध माना जायगा जब्त त्रयेक शिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह कम से कम एक विस्तर व्यक्ति को साधारण अवस्था बनाए। इसका हो नहीं, अपने पास पब्लिस में भी मोर रखन तथा मनोरजन के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करे जो सामाजिक दूरी को घटा कर सभी वर्गों के लोगों में मध्ये सम्बन्ध विकसित करने में सहायक हो।

प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता बिना जन सहयोग के सम्भव नहीं है। इसमें सरकारी को भाग्य प्रद कर कार्य करना होगा और सरकार को चाहिए कि यह इनकी आर्थिक सहायता करते हुए परीक्षण से समय-समय पर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करे। यदि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में सरकारी तन्त्र की प्रधानता होगी तो इसकी सफलता में संदेह होगा सामाजिक है।



शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का स्थान

अन्धविश्वास और साधुजीविका

धर्म और शिक्षा दोनों ही जीवन के प्रेरक और व्यापक हैं। एक किया है तो दूसरा उसका आधर है। धर्म दोहरा सम्बन्ध स्थापित करता है—“पहला मनुष्य और ईश्वर के बीच, और दूसरा ईश्वर की सत्ता होने के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच।” मनुष्य और मनुष्य के बीच सम्बन्ध तभी स्थापित हो सकता है जब हम पूरी धर्मिता से दूसरों की प्रार्थना करें। यह तभी सम्भव है, जब हम मन्त्र, पवित्र, स्थान और नियम हों।

धर्म का उद्देश्य मानव सभ्यता और सभ्यता के उद्देश्य के साथ ही होता है। एक समय था जब धर्म जीवन में सब वर्गों पर पूरी तरह हाव हाव होता था। उसने व्यक्ति और समाज को अन्धकार से हटाकर सत्य की ओर, अग्नि के हाकर शिव की ओर और अन्धकार से हटाकर प्रकाश

की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया। जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखने पर भी आज धर्म वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक उत्थान, कुछ स्वार्थियों के कुचक्र तथा ऐसे ही कल्पित अन्धविश्वासों से प्रभाव रखने वाला हो गया है। जो धर्म कभी विश्वधर के देशों की शिक्षा संस्थाओं में अग्रगण्य भाग आज हटकर दिया गया है।

धर्म और शिक्षा में सम्बन्ध —

प्राचीन काल में शिक्षा का वैश्व आध्यात्मिक था। धर्म ने मानव हृदय का परिष्कार किया और शिक्षा ने बुद्धि का। धर्म, मानव जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं से सम्बन्धित है तो शिक्षा भी व्यक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक जीवन पर प्रभाव डालती है। यदि शिक्षा

द्वारा मानव के व्यवहार में सुसज्जता से परिवर्तन लाया जा सकता है तो आदर्श शिक्षा धार्मिकता और व्याख्यात्मकता धर्म द्वारा ही मिलती है। मनुष्य को भौतिक सुख शांति की वित्तीय आवश्यकता है, उससे भी अधिमानसिक सुख दान्ति की। मनुष्य कितना ही धनवान हो, कितना ही ऐश्वर्य सम्पन्न और समृद्ध हो, परन्तु वह भी मानसिक शांति के लिए अटवत्ता बेमा गया है। स्पष्ट है कि शांति के लिए उन्हें धार्मिक शिक्षा गनी मिलनी। मनु ने धर्म के इस सतण बताया है—

प्रति, क्षमा, दण्डप्रिय, ग्रीव विनिर्मुक्त निष्ठ, -
 धी विद्या, सत्यश्रुषो, रक्षक धर्मं सख्यम् ॥
 ने है— धैर्य, क्षमा, दण्ड, अरुण, स्व-उदा, हिंसा
 निष्ठ, विद्वत्ता, शिष्ट, शीलता, सत्य और प्रीति।
 इन लक्ष्यों के प्राप्त में पूर्णता प्राप्त हो इच्छा की पूर्ति होती है और श्रुति के साथ प्रेम भाव रखने की प्रेरणा मिलती है।

धर्म मानव जीवन की एक उत्कृष्ट और उदात्त पक्षीत और दमि मायका है। किस वैदिक ग्रन्थोक्त का कहना है "धर्म एक शाश्वतित होका है जो लोकोक्ति समया धर्म पाराल से सम्बन्ध रखता है जैसा कि उन विविध स्थितियों द्वारा विचार दिया जाता है जो धर्म द्वारा रचते हैं।" धार्मिक मायकाओं से मनुष्य से मानव प्रवृत्तियों का उदय होता है। प्रतीकार "समाज सेवा, सहयोग, सहानुभूति आदि भावनाओं कापत होती है। धर्म के विषे मनुष्यों को धर्म धर्म करमा चाहित और प्रभु धर्मों का परिचय कर देना चाहित। बाप, क्रोध, मोह मोन आदि मानसिक प्रवृत्तियों मनुष्य के धर्म से प्राप्त उपस्थित रहती हैं। धर्म मनुष्य के भौतिक सुखों की अचरितता करता है। वष्ट सहता है, चर-उत्पत्ति धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। हिन्दू धर्म के अनुसार मनुष्य की शरमा, समर है और शरीर, साधन है। मनु के परपत भी मनुष्य अपने सुख शरीर से अपने लिए हुए शुभ और अशुभ धर्मों का फल मोखता है। धार्मिक धर्म रत्न, नरक और परलोक में आस्था रखते हैं। इसलिए जनता विचार यह है कि इस अल्प जीवन में सुख मोखने की अपेक्षा अल्प परलोक सुधारों का प्रयत्न करना चाहित।

धार्मिक शिक्षा से मनुष्य भारतीयों में जीवन सुमर्य की ओर बढ़ा। उन्होंने मनुष्य से ऐश्वर्य प्राप्त किया वित्त में ही उच्चवर्ग के महापुरुषों जैसे महापान महावीर, श्रीराम बुद्ध, महात्मा गांधी आदि ने राजकीय सेवा का त्याग कर तथा सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, सत्य आदि को अपनाकर अपना जीवन परहित के सिधे उत्तम कर दिया। पण अन्धों को प्रकाश दिया और उनके प्रभाव से वित्त में ही व्यक्तियों का जीवन सुधर गया। इन महापुरुषों के जीवन से जन हृदय में श्रद्धा उत्पन्न रही। उनके प्रभाव से छोटे तथा बड़े सभी नरों में सती, प्रसिद्धी और साधनों की स्थापना की गयी।

धर्म धर्म धर्म के वास्तविक शिक्षाओं में विचार उत्पन्न होने लगा। धर्मोपदेनको, साधुओं, महात्माओं और नई इच्छा में विस्थापन की मायकाएं बन गयीं। इस प्रकार जो धर्म समाज को उन्नति की ओर ले जा रहा रहा था वह मनुष्य विज्ञान और मनुष्य धर्म में मनुष्य पत का कारण बन गया। विज्ञान, दुरोहित तथा धर्म युक्त मोक्षी और अनपढ़ जनता को ठगकर यथमान का स्थान रखने में सुनिश्चित करने लगे।

विद्या की उन्नति के साथ ही अन्धकार और अज्ञान विनाश हो, निरवधार मानव में बुद्धि और तर्क की शक्ति थी। धर्म की साह से जो लोग अपने स्वार्थ साधन में लक्ष्मण से, जनकोहितो से शिक्षा को बहुत गहरा धर्मका पूर्णता।

धर्म और शिक्षा —

धर्म पूर्ण सत्य, पूर्ण कल्याण और पूर्ण सुखरता प्राप्त करना चाहता है, किन्तु इसकी प्राप्ति के लिए मानव का वैयक्तिक तथा आध्यात्मिक विकास आवश्यक है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा यह विकास सम्भव हो सकता है। अतः शिक्षा धर्म की प्रथम धोड़ी है। दूसरी ओर धर्म शिक्षा को उच्चतम मनुष्य प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है, "ता विद्या या विमुक्तये" अर्थात् विद्या नहीं है जो मुक्ति प्रदान करे। अतः विद्या और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि दोनों के उद्देश्यों में समानता है।

दोनों ही व्यक्ति की भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। दोनों व्यक्ति के दृष्टिकोण

हमें स्कूल क्यों समाप्त करना है

अनुवादक डॉ. देवेन्द्र दत्त तिवारी

[इवान इलिच की प्रसिद्ध पुस्तक 'डिस्कल्बिंग सोसाइटी' का अनुवाद हम क्रमशः 'नयी तालीम' में इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं कि इवान इलिच के विचार गांधीवादी विचारधारा से मिलते-जुलते हैं। यह अनुवाद सर्वाधिकार सुरक्षित है।]

(गलाक से आगे)

अब भी प्रशिक्षण ज्ञानार्जन आकस्मिक रूप से होता है और ऐसी क्रियाओं का उपपरिणाम है जो कार्य-व्यवसाय (Leisure) की परिभाषा में आते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सुनिश्चित शिक्षण से सुनियोजित ज्ञानार्जन को धाम नहीं होता है और न यह समझना चाहिए कि दोनों में सुधार की आवश्यकता नहीं है। दस-बरी प्रेरणामय शिक्षार्थी, जो एक नवीन विषय की ओर सीखना चाहता है उस विषय से पर्याप्त लाभ उठा सकता है, जो अब पुराने ढंग के उस शिक्षक से सम्बद्ध है जो पढ़ा, देख, प्रस्तोच और गुला रटाकर छिलाता था। स्कूल के इस प्रकार के रट्टु-छिल्लु को अब बहुत कम और प्रतिष्ठाहीन कर दिया है। फिर भी बहुत से कोष्ठक ऐसे हैं जिनपर एन. प्रेरणामय और सामाज्य अभिव्यक्ति शिक्षार्थी कुछ ही महीनों में अधिकार प्राप्त कर सकता है, यदि उनका शिक्षण परम्परागत ढंग से किया जाय। ये प्रतीक (कोष्ठक) और उनके योग द्वितीय तथा तृतीय भाषा ज्ञान के लिए उनका ही उत्तर है जिसका सामान्य शिक्षण और पढ़ने के लिए और उतना ही सत्य एवं विवेक प्रणाली के लिए है जैसे बीजगणित, कम्प्यूटर, (प्रोग्रामिंग) रासायनिक, विद्युत्चुम्बक या हाथ के कोष्ठक के लिए जैसे टायर करना, पकड़ी बनाना, मिट्टी का काम करना, तार सजाना, टी.वी. या गुर्र, मोटर चलावा या पम्पुची की बसा सीखना।

कुछ मागवो म, ज्ञानार्जन के उस वायव्य में, जिसका पर एन. विवेक की ओर स बरता प्राप्त करना हो अभिहित होने के लिए किसी दूसरे कोष्ठक की दक्षता भी नयी तालीम/१२

आवश्यक हो सकती है किन्तु उसके ऐसी प्रक्रिया पर निर्भर होना आवश्यक नहीं है जिनके द्वारा ये कोष्ठक छोड़े गये थे। टी.वी. की परम्परा के लिये साक्षरता तथा कुछ गणित का पूर्णज्ञान आवश्यक है, पम्पुची की कला के लिये अच्छी तैयारी और ग्राइडिंग के लिये दोनों का बहुत कम पूर्णज्ञान चाहिए।

ज्ञानार्जन का कोष्ठक नाश जा सकता है। एक अभि-प्रेरित औसत प्रशिक्षण के सीखने के लिये उपयुक्त समय और सामग्री का अनुपात सरलता से ज्ञाया जा सकता है। अमरीका में एक दूसरी परिचय योरोप की उच्चशरीर भाषा सीखने का छह बार से छ सौ घण्टा के बीच में आता है और किसी प्राग्ज भाषा सीखने के लिये दुगुना समय लगेगा। फिर भी यह सब न्यूयार्क नगर में १२ वर्ष की स्कूली शिक्षा पर होने वाले व्यय की तुलना में बहुत कम होया (उपार्थ विभाग में कार्यकर्ता के लिये अनिवार्य योग्यता यह अवसर पन्द्रह हजार बरस होया। नि.स. वेह न केवल शिक्षक प्रत्युत औपधि निर्माता अपन व्यवस्था के इस आवेकनिक प्रसरण प्रवर्धित कर सुरक्षित रखते हैं कि उनके लिये प्रशिक्षण बहुत सचोत्ता है।

१०५

इस समय स्कूल बहुत सा संशिक्र पन हरिषा सेते हैं। शिक्षण की द्रिज को स्कूली सच से कम सचोत्ता है अब उन पनिको का विशेषाधिकार है जो स्कूली बिदा की उपाय कर सकते हैं और जिन्हें या ता सेना या बडे उपाय-पति सेवाकालोन प्रशिक्षण के लिये भेजते हैं। अमरीका में शिक्षा के अधिक रूपसे स्कूल बिहीन होने के कार्यक्रम में द्रिज प्रशिक्षण के लिये शायन अत्यंत सीमित

होये। किन्तु अन्तर्गोपना विधियों के बिना जीवन में किसी समय में भी जनता के सच पर सँकड़ो कौशल से उसे किसी एक कौशल के शिक्षण की चुनने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

मनो को किसी कौशल - शिक्षण केन्द्र पर सैद्धिक क्रेडिट केवल गरीबों को नहीं बल्कि सभी वर्ग के लोगों को एक सीमित माप में मिल सकता है। मैं यह सोचता हूँ कि प्रविध्य में हर नागरिक को उसके जन्म पर ही इस प्रकार की क्रेडिट एक संश्लिष्ट-वास्तवोपदेष्टा या या संप्रिक्त क्रेडिट काट के रूप में मिल जाय। गरीबों के प्रति सहानु-भूति की दृष्टि में, जो अपनी बाल्यिक सहायता आर्थिक जीवन में प्रयोग में नहीं ला सकते, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि बाद में एकटा क्रेडिट काट प्रयोग में लाने वालों को व्याप्त मिलता रहे। ऐसी क्रेडिट से ऐसे कोमल बालकों को अधिक होनी, अपनी सुविधा से अधिक अच्छे ढंग से, अधिक सीधता से और अधिक सटीक विधि से प्राप्त कर सकेंगे और स्कूल के दूरे पारंगत प्रभावों से भी बच सकेंगे।

पेटेंट्स कौशल—शिक्षकों की अधिक विनोद तक नहीं पहुँची। किसी समाज में कौशल की मांग उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। दूसरी ओर जो कौशल का प्रयोग कर सकते हैं, वे उसे सिखा भी सकते हैं। किन्तु एक समय जो ऐसे कौशल का प्रयोग करते हैं जिनकी माप अधिक है और जिनके लिए मॉर्निंग अध्यापक की आवश्यकता है, उन्हें इस बात से हतोत्साहित किया जाता है कि वे उसे दूसरों को भी सिखाए। ऐसी स्थिति या तो उनके शिक्षकों द्वारा उत्पन्न की जाती है जो सार्वजनिक पर एक विचार रखते हैं या मूनिशियों के द्वारा जो अपने व्यावसायिक विनोदों की परिणामों के माध्यम पर किया जायगा, वह कि उस स्टाफ के आधार पर जो उनके पास है और न उन शिक्षकों के आधार पर जो वे काम में लाते हैं। काम के अवसरानुसार अवसर उपरिष्ठ विनोद जा सकते हैं, बहुधा उन लोगों के विषये जो जिन्हें वास्तविक रोजगार से लगाने के सर्वाधिक समझा जाता है। वास्तव में इसका कोई कारण नहीं है कि वे कौशल—शिक्षण—के प्रकाश करने के स्थान पर ही मनो न हो। इससे रोजगार देने वाला

और उससे सहकर्मी, जो शिक्षण भी देंगे और आप ही उन लोगों को काम भी देंगे, जो अपनी सैद्धिक क्रेडिट का इस प्रकार प्रयोग करना चाहते हैं।

१९३६ में न्यूयार्क में प्रकाशित क्षेत्र में स्पेनिश शिक्षाने हेतु सैकड़ों अध्यापकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं जिससे वे स्पेनिश लोगों से सम्वाद स्थापित कर सके। मेरे मित्र मेरी भावना में एक स्पेनिश रेडियो स्टेशन से यह बोधना की कि हर्निस (न्यूयार्क में नीची लोगों की आवाही) से मूल भाषा—भाषियों की आवश्यकता है। दूसरे दिन लगभग २०० टोल एक्टर (दोस्त वर्ग से कम उम्र वाले) उनके कार्यालय का सामना दरवाजा हो गए और उन्होंने उनमें से ४० को चुन लिया। उनमें से काफी संख्या यहाँ स्कूली शिक्षा लिए हर्निस (न्याय आउटस) की थी। उन्होंने उन लोगों को यू.एच. कार्डों सहित ह्यूस्टनपुट संयुक्त के प्रयोग में प्रविष्टि दिया। यह संयुक्त स्नातक प्रविष्टि प्राप्त पाठ्याभितो के प्रयोग के लिए बनाई गयी थी। एक सप्ताह के भीतर उनके शिक्षक (हीन एक्टर) आराम निर्भर हो गए और प्रत्येक ने चार ऐसे न्यूयार्क के रहने वाले को सिखाते के लिये चुना जो स्पेनिश कौशल चाहते थे। ६ महीने के भीतर शिक्षण पूरा हो गया। कांक्रिस रॉसमैन ने यह यह बात कि जबके १९३७ गिरिलायो में कम से कम तीन लोग ऐसे थे जो स्पेनिश कौशल सकते थे। कोई भी स्कूल इस प्रकार का कार्य पूरा नहीं कर सकता था।

कौशल के बिलको की कमी का कारण साइलेंट में विश्वास है। प्रवास-पत्रिकारण बाजार का गोरक्षवादा है और केवल स्कूली परिवर्तक हो इसे व्यवहार में ला सकता है। कौशल कला के अधिकतर स्कूलों अध्यापक मन्त्रे सिलकारों और व्यवसायों को अपेक्षा कम नियुक्ता कम नीतिगत और कम प्रवृत्तिवादी रखते हैं। बहुत से हाई स्कूल के शिक्षक स्पेनिश भाषाभासी लोगों को उतनी अच्छी तरह नहीं बोलते जितनी अच्छी तरह उनके विषय ६ महीने के उपरिष्ठ अध्यापक से बाद बोल सकते हैं। न्यू-टोरिको में एजितविश्वीयों ने जो प्रयोग किए हैं उनके स्रोत मिलता है कि बहुत से टोल एक्टर, यदि उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाय और साधन भी दिए जायें तो अपने

प्रौढ़ शिक्षा कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट

(प्राप्त होने के अंश)

1737 औद्योगिक कामगारों की शिक्षा—सब
उद्योगों के कामगारों को शिक्षित करके क लिए
अवधारण पद्धति प्रारम्भ करने की आवश्यकता
पर हम पहले ही बातें चुके हैं और यह सुझाव भी दे
चुके हैं कि वह तीन वर्षों की अवधि में कराया जाय।
हमने यह सुझाव भी दिया है कि उनकी शिक्षा निम्नो
तोषों और शिक्षा विभाग व सहयोगात्मक प्रयास के
रूप में होनी चाहिए। निम्नोक्त समय व व सुविधाएँ
और प्रोत्साहन दें तथा शिक्षा विभाग शिक्षा कार्यक्रम
तैयार करें अध्यापकों और पुस्तकों की व्यवस्था करें
यही तात्पर्य/१४

तथा अन्य प्रकार की सहायता दें। उत्पादन बढ़ाने में
अधिक वृद्धि के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें
काम पर प्रोत्साहित होने के साथ ही उनकी शिक्षा समाप्त
न होने दी जाय। हम शिक्षा से करते हैं कि कामगारों
को भी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका ज्ञान, कारी
गरी समस्त हो जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यापक
हो अपने व्यवसाय के प्रति उन्हें शक्ति प्राप्त हो सके
और वे अपने काम में जागे रहें। उनके लिए विशेष
अवकाशिक और 'सेल्फिनिंग' कार्यक्रम चलाये जाय ताकि
वे समय व ठेकानों को अपनाते जाय।

1738 इस विषय में एक महत्वपूर्ण उपाय यह

होगा कि औद्योगिक कामगारों में लिए ऐसे विशेष पाठ्य-क्रम चलाए जाए जो सुलभता और स्तर के विचार से स्कूल के नियमित विद्यार्थियों के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के समतुल्य हों। कारखानों के चरकर, धायाबंदाई और व्यवहार बुगल कामगार तथा जीवन में किसी निश्चित व्यवसाय में न जाने हुए स्कूलों के निश्चित किशोर—इस शीर्षों की प्राप्ति प्रवृत्तियों और चरकराव (धाराओं) का अन्तर समझना आवश्यक है। स्कूलों से निकल कर विद्यार्थी जैसे जैसे उच्चतर शिक्षा स्तरों में पहुँचते जाते हैं आयु पद्धति के साथ यह अन्तर घटते जाता है, पर माध्यमिक स्तर तकना जो अन्तर महान है वह कामगारों के लिए ऐसे गुण-वृद्ध असाधारण और चरकराव पाठ्यक्रमों द्वारा मिला होना चाहिए जिनमें उनकी परिपक्व आवश्यकताओं तथा विविध व्यावसायिक और अन्य हितों पर धन दिया गया हो।

17.33 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तत्काल ही शिक्षा के कार्य प्रारम्भ होना चाहिए। सरकारी स्तर के औद्योगिक स्तरों की भी अनेक कारखानों के लिए कारखानों का आयोजन करने की और उन्हें परीक्षाओं की संवारी के लिए प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति करनी चाहिए। विशेष रूप से संसार स्तर के कार्यक्रमों के अन्तर्गत चलाने गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के कामगारों की ओर भी सहमति मिलेगी जो उनके प्रविष्टि के समुचित सामान्य, तकनीकी, प्रशिक्षण विषय और अन्य प्रकार की शिक्षा के विविध क्षेत्रों में उन्हें चरकराव के स्तर तक के आने में सफल हों।

17.40 कामगारों की शिक्षा, शिक्षा मन्त्रालय तथा श्रम और रोजगार मन्त्रालय का समुचित दायित्व होना चाहिए। औद्योगिक कारखानों के जिम्मे शिक्षा के सन्त-भारक पक्ष का दायित्व श्रम और रोजगार मन्त्रालय का होना चाहिए जो विभिन्न समुहों के लिए कारखानों की व्यवस्था करे, शिक्षा के लिए उचित समय पर छोटें बं, चरकराव के लिए कमरे, पुस्तकालय, बालनालय और बड़ी सम्पत्ति हो प्रयोगयोग्य बाकि की सुविधाएँ के तथा सबसे अधिक यह है कि जो प्रवृत्ति दिशाएँ, उन्हें प्रोत्साहन दे।

श्रम और रोजगार मन्त्रालय, निषेधित विवरणियाँ, साम्यमिक शिक्षा बोर्ड और तकनीकी शिक्षा के प्रमारी विद्यार्थियों के चरकराव करके औद्योगिक कामगारों के लिए अकेलित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और पाठ्य-क्रमों की तैयारी का सम्बन्ध शिक्षा मन्त्रालय रहे। अन्त्या-पक्ष, पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य सुविधाएँ भी शिक्षा मन्त्रालय की देनी चाहिए और सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा की पड़ोसी स्तरों में कामगारों की शिक्षा के लिए जो भी सहमति मिल सके, दिशावी चाहिए।

17.41. औद्योगिक कामगारों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की योजना सर्वाधिक बलान और सोवोदय प्राप्त होना ही चाहिए। जो वर्तमान कार्यक्रम चरकराव चरकराविक स्तरों, अन्य नीतियों और स्वी प्रकार की अन्य व तों अन्तरा साधारण और मन्त्रालय के चरकरावों पर ही धन देते हैं उनमें पाए जाते बने अन्तरा इन चरकरावों में न रहे ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि अविकसित कामगारों को उच्चतर तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा मिले ताकि वे उद्योगों में व्यवसायिक पर समान सकें। इस उद्देश्य के विचार के कारखानों की शिक्षा को सामान्य, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की मुख्य धाराओं से वृद्ध नहीं समझा जा सकता। जैसा कि हम अन्य बार दोहरा रहे हैं सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के स्कूलों, बालेजों, माध्यमिक शिक्षा बोर्डों, विवरणियाँ और तकनीकी शिक्षा स्तरों में औद्योगिक कामगारों की शिक्षा का अविकसित दायित्व होना चाहिए।

17.42 विशेष कार्यक्रम और स्तर—यह सम्भव नहीं है कि स्कूल और कॉलेज पद्धति के अन्तर्गत अविकसित पाठ्यक्रम प्रोढ़ शिक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उनमें से कुछ के लिए विशेष स्तरों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए सामान्य न्याय बोर्ड द्वारा खोले बड़े स्तरों के प्रयोग चरकराव की ओर हारा बलान दिशावा पदा है। चरकराव विभिन्न स्तरों की विविध सामान्य स्तरों का प्रतिक्रिया रहे हैं लिए वे स्तरों सहित पाठ्यक्रम आयोजित करती हैं और अन्य समान स्तरों के रूप में स्तरों को

शिक्षण की प्रवृत्ति प्रबल होगी। यंगी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्मी सहायता के लिए स्टार में दिखाई नहीं होगी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पाठ्यक्रमों को बर्बाद बना देनी चाहिए ताकि अशक्तानिष्ठ विद्यार्थियों के लिए उन्हें पूरा करना अपेक्षाकृत सरल हो जाय।

इसका जनित्राय यह हुआ कि सहित पाठ्यक्रमों के केन्द्रों को सहाय्य कई गुना अधिक होगी चाहिए और पुनी हुई सैद्धांतिक सहाय्य—जैसे कलेजों, हाई स्कूलों, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण के लिए स्टार बढ़ाया जाय और अन्य आवश्यकताएँ पूरी की जाय। प्राचीन सहाय्य और संसूच राज्य के विद्यापीठों का होने जो अंधेरा दिखा गया है हम उसमें प्रभावित हुए हैं। एक तरह से यह विद्यापीठ केन्द्रों के लोक हाई स्कूलों की तरह काम करते हैं और खुले हुए प्राचीन दलों को छोटी देर के लिए नहीं रखकर उन्हें सामान्य और व्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा देते हैं। जैसा होना चाहिए इन सहाय्यों में शिक्षा का रूप वसावनाशुक्ल होता है और उसमें कृषि और ग्राम शिक्षा पर जोर दिया जाता है। कुछ ग्राम सहाय्य, ग्राम पंचायत समितियों के प्रयागों और पंचायतारियों के दलों के लिए ऐसे संक्षिप्त पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करती हैं जिनसे उन्हें अपने पक्षों की विधेय-रियों की और नागरिक संस्थाओं को निर्णय पर पहुँचने की लोकतन्त्रिक कार्यविधियों को समझने में सहायता मिले। हमारा मुद्दा है कि विद्यापीठों और ग्राम सहाय्य के काम की धार-धार समीक्षा होगी चाहिए ताकि वे प्राचीन समाज के लिये उपयोगी हो। इन सहाय्यों का स्टाफ उच्चतम कोटि का और विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। यह जरूरी है कि यह सहाय्यें कृषि प्रदर्शन छात्रों और विद्यार्थियों के बीच के साथ मिलकर काम करें। ऐसी और सहाय्य की आवश्यकता है, पर एक-का विस्तार नहीं तथा सीमित रखा जाय जहाँ तक संभव हो और अन्य सहाय्य सेवाएँ उपलब्ध हो।

17.43 पंचायतों के लिए अशक्तानिष्ठ पाठ्यक्रमों के शोधार्थ ५ वैश्विक सहाय्य के पास वास्तविक साधन होने चाहिए, यह सुनिश्चित करना केन्द्र और राज्य सरकारों का काम है। इन नई सेवाओं के लिए, उन संस्थाओं के पास अनिवार्य स्टाफ, पर्याप्त पुस्तकें, शिक्षण सामग्री और सहाय्य साधन, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए। अशक्तानिष्ठ विद्यार्थियों को पढ़ाने की प्रभावित मिल होगी। इस बात का पूरा सावधानता चाहिए कि

नयी धामीन/१६

उनमें सीखने की प्रवृत्ति प्रबल होगी। यंगी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्मी सहाय्य के लिए स्टार में दिखाई नहीं होगी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पाठ्यक्रमों को बर्बाद बना देनी चाहिए ताकि अशक्तानिष्ठ विद्यार्थियों के लिए उन्हें पूरा करना अपेक्षाकृत सरल हो जाय।

पत्राचार पाठ्यक्रम

17.44 कोई ऐसा तरीका न होना चाहिए जिससे शिक्षा उन लोगों को करने में सक्षम हो सके जो पढ़ने के लिए अपने ही प्रयत्नों पर निर्भर हैं और जब समय मिलता है, पढ़ते हैं। हमारा विचार है कि पत्राचार या दूरशिक्षा पाठ्यक्रम इन स्थितियों में ठीक हल है।

17.45 पत्राचार या दूरशिक्षा पाठ्यक्रम अच्छी तरह मानगई और जाची हुई तकनीक है। संसार के दूसरे देशों, जैसे अमेरिका, स्वीडन, कनाडा, जापान और आस्ट्रेलिया के अनुभव से हमें प्रोत्साहन मिला है कि व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरीके में दूर-पूरा सावधानता की शिक्षा देना चाहिए। यह सावधानता निर्भर है कि पत्राचार पाठ्यक्रम नियमित स्कूलों और कालेजों द्वारा ही नहीं शिक्षा से घटिया वर्गों की शिक्षा का रूप है। भारत के भीतर और बाहर प्राप्त हुए अनुभवों से जो परिणाम निकले हैं, उन पर विचार करने से पत्राचार शिक्षा प्रणाली की मन मिलता है।

17.46 इसमें सन्देह नहीं कि पत्राचार प्रणाली में व्यापक के प्रेरक 'व्यक्ति' का काम रहता है। पर प्रेरणा देने वाले व्यापक दुर्लभ हो गए हैं। पत्राचार प्रणाली में पठन की सीखने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। इस प्रणाली में व्यापक से व्यक्तिगत और निजी सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, जिसके पत्राचार द्वारा सगठ एवं संक्षिप्त चर्चा और जर्नल को प्रोत्साहन मिलता है। वास्तव में विद्यार्थी और व्यापक के बीच व्यक्तिगत और उद्देश्य सम्बन्ध के बजाय वे प्रभावकारी शिक्षा सामने नहीं होती। अनेक उदाहरण और अधिकार्यभूत कालेजों में व्यापक और विद्यार्थी के बीच कोई सार्थक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता। इसी एक बात से हम प्रश्न ली क

वैश्विक मूल्य को समर्पण मिलता है कि पत्राचार प्रणाली में पत्रों के लिए मुख्य प्रकाश विद्यार्थी को स्वयं करना है और उसे विविध अभ्यास और परीक्षाएँ निश्चित रूप में देनी होती हैं।

17.47. पत्राचार प्रणाली का अर्थ विभिन्न विद्यार्थी और सम्पादकों का सादान् प्रदान नहीं है। इन प्रणाली का एक अनिवार्य पक्ष यह है कि विद्यार्थी और सम्पादन परीक्षा—सर्वे समय के लिए हो सके। विद्यार्थी रहते हैं और विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों में, विद्यार्थी भाषण, विचार और सामूहिक परीक्षा शामिल हैं, जिनमें सेते हैं। जिन्होंने विचार और तकनीकी विषय लिए हो, उन्हें सहाय के अंत में या सहाय के बीच प्रयोगशाला और बर्तन में जाने देना चाहिए। अनेक प्रकार के अन्य साधन पत्राचार कार्यक्रमों को समृद्ध बना सकते हैं। एक ही क्षेत्र में रहने वाले और समान विषयों में रुचि रखने वाले पत्राचार पाठ्यक्रम के विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से मिल सकते हैं और एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि उन्हें सम्मान प्राप्त विद्यार्थियों का दर्जा दिया जाय। पुस्तकालय तथा सैद्धांतिक विषयों के विद्यार्थी विद्यार्थी के रेकार्ड चुनने जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने दिया जाय।

17.48. शिक्षा ॥ कुछ लोगों में ऐसे पत्राचार या पुस्तकालय कार्यक्रम, जो क्रमबद्ध पढ़ाई के विद्यार्थी पर तैयार किए गए हो, बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। यद्यपि ऐसा है कमबद्ध कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप विद्यार्थी में बहुत अच्छे होते हैं जब विद्यार्थी को नये विषय से परिचित कराया जाता है और उसे उचित मूल्य प्राप्त करवाया जाय। इससे बहुत ही लाभदायक हो सकता है कि पत्राचार पाठ्यक्रम में क्रमबद्ध पढ़ाई का प्रयोग सामान्य हो सकता है।

17.49. रेडियो और टेलीविजन के सम्बन्धित कार्यक्रमों का सहाय पत्राचार पाठ्यक्रमों को मिलना चाहिए। सभी लाभ सम्मान नहीं हो पाया है कि कार्यक्रमों का निश्चित निश्चित विचारों से विचार दिया जाय, तथापि सम्मान के विभिन्न क्षेत्रों के अनेकानेक मूल्य और मूल्य विषयों को रेडियो और टेलीविजन उद्घाटित कर सकते

हैं। इस पक्ष परीक्षा सम्मान है कि पत्राचार पाठ्यक्रम बनाने वाले विद्यार्थीविद्यार्थी और अन्य एजेंसी-तयों को जाकाधमाली तथा टेलीविजन ॥ साथ मिलकर काम करना चाहिए और ऐसे रेडियो तथा टेलीविजन कार्यक्रम तैयार करने चाहिए जो पत्राचार पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान् हों। विद्यार्थी विद्यार्थीविद्यार्थी द्वारा सम्मानित पत्राचार पाठ्यक्रम के अनेकानेक महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न रूप से तैयार की गई पत्राचारों और पत्राचारों को 'प्रसारित' करके सुधारम्मा किया जा सकता है।

17.50. विश्वविद्यालय की विद्यार्थी की प्रति ॥ विद्यार्थी विद्यार्थियों को तैयार करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उन विषयों की सम्पूर्ण शिक्षा के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मायो जित किए जा सकते हैं जो सद्योप, कृषि और अन्य क्षेत्रों में अन्य कार्यक्रमों को सम्पादन करने में मदद दें। कुछ विषय जिनमें पाठ्यक्रम सम्बन्धित किए जा सकते हैं, का प्रकार है—रचनात्मक विचार और वापसी वास्तुविज्ञान, लेखन, बीजक विज्ञान, वास्तुविज्ञान, इकोनॉमिक्स, व्यवसाय प्रशासन, जल विचार और स्मृति रीटिंग, सम्मान, सम्मान, विचार, वीडियो, पाठ, स्वयं सम्मान, वास्तुविज्ञान, इकोनॉमिक्स, रेडियो—टेलीविजन सम्मान और प्रसारण, सहायक उपकरण, व्यवसायिक पुनर्वासि विषय, कोटोविक इलेक्ट्रॉनिक्स और सम्मान पोषाक विज्ञान और विचारों के विषय, वास्तुविज्ञान सम्मान, प्रशिक्षण, कोटोविक और विचारों सम्मान, वास्तुविज्ञान सम्मान, होटल सम्मान, फैक्टरी सम्मान और कार्यक्रमों प्रशिक्षण, द्वारक सम्मान प्रशिक्षण, कोटोविक, सहायक विचारों का सम्मान, विचार और सम्मान सम्मान, विचारों से विचार पूर्वक सम्मान अच्छे पत्राचार पाठ्यक्रम अपनी सम्मान पक्ष कर लगे और उत्पादन को अच्छी पत्राचारों के लिए सहायक सम्मान प्राप्त करने के सहायक होने।

17.51. पत्राचार पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए भी होने चाहिए जो सामूहिक और स्वायत्त विषयों का सम्मान द्वारा जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं जिनमें—

पापाए दर्शन, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्यालोचन, मनोविज्ञान आदि। ये विषय वस्तुनः विशेष उपयोग के लिये हैं, और मले ही ये आर्थिक उन्नति में विशेष सहायक न हों, बौद्धिक और कलात्मक स्तर को उठाने और जीवन दृष्टि के रूपान्तरण में ज़रूर सहायता करते हैं।

17 52 यह स्पष्ट है कि हम पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन करते वक़्त ऐसी विषयविधानय हो नये होनी चाहिए। पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना कृषि, उद्योग, गृहकारिता, स्वास्थ्य जैसे सहकारी विकास-विभागों की विस्तार सेवाओं का भी एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। शिक्षित और नवजागरूक तब जो जानकारी और जनतक तक के विभाग पहुँचाना चाहते हैं उनके लिए पत्राचार पाठ्यक्रम मूल्यवान् तरीका सिद्ध होता है।

17 53 हम यह भी सिफारिश करते हैं कि स्कूलों के कक्षाओं के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम के विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाय ताकि वे जिन विषयों को पढ़ाते हैं उनके बारे में मई जानकारी से तथा शिक्षण के नये तरीकों और तकनीकों से परिचित रहें। यह उपाय स्कूलों की यह निराशापूर्ण स्थिति में और भी ज़रूरी हो जाता है, जिसमें अध्यापकों को काम करना पड़ता है, जहाँ पुस्तकालय की सुविधाएँ कम होती हैं तथा बौद्धिक सर्वाँ नहीं होते। अध्यापक जो भी पढ़ाते हैं उनके बारे में इसके माध्यम से जानकारी और कार्य नई बुद्धिधर्मों से प्रेरणा भी पहुँच रहे।

17 54 अन्य मन्त्रालयों के सहयोग से शिक्षा मन्त्रालय का राष्ट्रीय ग्रह कार्यक्रम परिषद को स्थापना करनी चाहिए। इस परिषद को अनेक कार्य संचालने का प्राधिकार मिलना चाहिए जिनके एजेंडायों को मान्यता देना और मूल्यांकन करना भी शामिल हो। परिषद को उन चीज़ों का पता लगाना चाहिए जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रम सामर्थ्य हो सकते हैं। यह या तो परिषद स्वयं स्थापित करे या जन्म ज्ञान के लिए सरकारी विभागों, निदेशविद्यालयों, शिक्षा - बोर्डों, स्कूलों तथा - संस्थाओं और नये मानव/१८

मैरिटरकारी एजेंसियों की सहयता करें। पत्राचार द्वारा शिक्षा देने के अनेक कार्यक्रमों का लगातार मूल्यांकन भी परिषद को करते रहना चाहिए।

१७ ५५ पत्राचार पाठ्यक्रमों की लागत के विषय में कुछ मतभेद हैं। एक विचार है कि पत्राचार कार्यक्रमों का यदि अधिक नदी तो उतनी ही लागत आती है जितनी स्कूल, कालेज और अन्य संस्थाओं की नियमित पढ़ाई पर आती है। चूँकि पत्राचार विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक होती है, इस पर आश्वासन दे दी जाते वक़्त निम्नलिखित शिक्षा की अपेक्षा निम्नलिखित ही कम खर्च आना चाहिए यह दूसरी धारणा है।

विश्लेषण देखेंगे इस पर होने वाले लागत - व्यय की तुलना सरल नहीं है क्योंकि सम्भवतः अलग - अलग हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि इसमें विद्यार्थी की संख्या-वृद्धि के साथ - साथ पर्यवेक्षण स्टाफ की आवश्यकता नहीं बढ़ती और उल्लेख स्टाफ का सात प्रिदायियों की बहुत भारी संख्या तक पहुँच जाता है। विद्यार्थी पहले के साथ-साथ काम भी करता है और कमाता भी है। यदि वह उत्पादन करने वाला कार्यधार है तो उत्पादन में भी गृहयुक्त होता है, यदि पत्राचार पाठ्यक्रम व्यवस्था से सम्बन्धित जानकारी और कारीगरी को उल्लत करने में सक्षमता केन्द्र है, यदि पत्राचार पाठ्यक्रम व्यवस्था के सम्बन्धित जानकारी और कारीगरी को उल्लत करने में सहायक होता है तो विद्यार्थी अपना काम पहले से नहीं अच्छा कर सकेगा। उसके लिए जगत से किसी इमारत और उपकरण की, सेल के मंदान और गद्यावामाना की, छात्रावास और विशेष ट्यूटलों की, विशेष पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती।

१७ ५६ हम यह सिफारिश करते हैं कि प्रादेशिक सम्पीडवारों के लिए, वे चाहें कहीं काम कर रहे हों, यह सम्भव होना चाहिए कि वे देश के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों और विश्वविद्यालयों की कोई या सभी परीक्षाएँ दे सकें। बहुत से सम्पीड विचार वाले व्यक्ति (कम आय के लोग भी) विशेषकर लड़कियाँ और स्त्रियाँ देश के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों और विश्वविद्यालयों की कोई या सभी परीक्षाएँ नहीं दे सकते क्योंकि वे उपस्थित सम्बन्धी बातों को

पूरा नहीं कर पाते। कोई कारण नहीं कि उन्हें इन परी-
क्षाओं की तैयारी के लिए अपने प्रयत्नों पर निर्भर रहने
के लिए प्रोत्साहित न किया जाय।

पुस्तकालय

१७.५४ इन अध्यापकों के विभिन्न मायों से इनके
पुस्तकालयों की आवश्यकता का उल्लेख किया है और
हमारा विश्वास है कि एक अच्छे पुस्तकालय पद्धति, जो
पुस्तकों को सबसे पास पहुँचा सके; प्रौढ़ शिक्षा पद्धति का
मूलभूत भाग है। इसके बिना, विशेष कर सामान्य क्षेत्रों
में जहाँ पुस्तकें बाँटना कठिन है, प्रौढ़ों में पढ़ाई की
मात्रा बढ़ने की कोई आशा नहीं है। योजना मायों के
कार्यकारी अपने देशभर में सके समाने पर पुस्तकालय
स्थापित करने की विचारित की है। हम सामान्यतया
इस विचारित से सहमत हैं।

१७.५८ पुस्तकालय सहायकार समिति (१९३०)
की रीपोर्ट में पुस्तकालयों का जाल बिछाने की मुक्त
विचारितों को भी हम स्वीकार करते हैं। दिल्ली में एक
राष्ट्रीय वैदेशीय पुस्तकालय, प्रत्येक राज्य में एक राज्य
वैदेशीय पुस्तकालय और जिला, सब और गुणवत्ता स्तर
पर पुस्तकालय इनमें शामिल हैं। इस तरह ऐसा जाल
जा सकता जिससे देशभर में व्यापक पुस्तकालय विकास
और संगठित सेवाएँ स्थायी हो जायगी।

१७.३६ स्कूल पुस्तकालयों की सार्वजनिक पुस्तकालय
पद्धति के साथ समन्वित कर देना चाहिए। हमने इस
बात पर जोर दिया है कि स्कूलों की प्रौढ़ - शिक्षा और
विस्तार सेवाओं का केन्द्र बनना चाहिये। इस उद्देश्य से
हमारा - पुस्तकालयों की विकसित किया जाय और इस
कार्य में उनकी सहायता की जाय।

प्रौढ़ शिक्षा के साधन की संग्रह काम में साने के लिए
पुस्तकालयों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। उन्हें ऐसी
पाठ्य सामग्री का संसार रखने की जरूरत पड़ेगी जो नव
पाठकों की भीरे भीरे सामान्य परम्परा बनकर बचने द्वारा
मूल्यवान् आवश्यकता देने वाली, अपेक्षाकृत उच्च स्तर की
पुस्तकों तक ले जाए। पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकों और
पाठ्यसामग्रियों की भी आवश्यकता है जो जिसका बचको

की व्यावहारिक जरूरतों और दृष्टियों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध
हो। जहाँ सम्भव हो, पुस्तकालयों में रेपरिकाओं, प्रामो-
कोन विकारों, फ़िल्मों और अन्य उपयोगी सामग्रियों का
संग्रह रहना चाहिए। पुस्तकालयों का उपयोग वे सभी
नियम करके जो संवैधानिक विद्या या रहे हैं, जिन्होंने
पनागार पाठ्यक्रम सहित किए हैं और जो अपने ही
प्रयत्नों पर निर्भर हैं। यह जरूरी है कि पुस्तकालय-
उपकरण में इन सबकी आवश्यकताएँ पूरी हों।

१७.६० जैसा स्वभावतः होता है, पुस्तकालय पुस्तकों
का संचार ही नहीं होता चाहिए, वे गतिशील हों, बचको
को सिद्धित करें और सहे माहफ़ूज करें। ऐसा करने के
अनेक माने-मान उप हैं। एक उन जो इस देश में प्रौढ़
शिक्षा की प्राचीन परम्परा के अनुरूप है, वह है भाषाओं
को इकट्ठा करके उन्हें कोई दक्षिण पुस्तक या कविता
पढ़कर सुनाना। नाथान, बर्मा - मजलिया और पुस्तक
बचक शुरू किए जाय और पुस्तकालय को जनबचि का
केन्द्र बनाने के यत्न किए जाय। सदाहरण के लिए हम
बिस्मिल पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा दिए गये उपयोगी कार्य का
उल्लेख करते हैं जिसने लोगों का बिना पुस्तकों की ओर
आकर्षित ही नहीं दिया, बल्कि पुस्तकालय की विविध
सांस्कृतिक कार्यक्रमाओं का पवित्रीय केन्द्र बनाने का भी
प्रयास किया है।

प्रौढ़ शिक्षा में विश्वविद्यालयों का योगदान

१७.६१ महत्व—विश्वविद्यालय के बारे में यह कल्प-
ना अब पुरानी हो चुकी है कि वह विद्वानों का ऐसा
संकुचित खैसिक समुदाय है जो ज्ञान का गुजन और प्रका-
शन करता है तथा अपने रसों को सांस्कृतिक बनाता है।
यै बीवर्तों को उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों और भवपद प्राप्ति-
ओं के बीच खंडी थी, वह चुकी है और सब दोनों की
परस्पर समृद्धि की दृष्टि से विश्वविद्यालय के जीवन को
जब समुदाय के जीवन से अलग तरह सम्बद्ध किया जा
सकता है।

१७.६२ यह कल्पना हुआ दृष्टिकोण उन विश्वविद्या-
लयों में रचप है जहाँ विश्वविद्यालय की चहार दीवारों
के बाहर विद्यार्थियों के सामान्य पनाचार पाठ्यक्रमों में

ऐसे और पाठ्यक्रमों की मांग पैदा कर दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रोड शिप्रा विभाग की स्थापना स्वागत योग्य है और उससे बड़ी मांग है। इन अनुभव करते हैं कि हमारे देश के विश्वविद्यालयों को प्रोड शिक्षा का अधिकाधिक भार उठाना चाहिए।

१७ ६२ वाक्यक्रम—विश्वविद्यालय का काम है अपने रोहित समुदाय को उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास में मदद देना। अपनी विशेष एजेंसियों के द्वारा यह लोगों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के कुछ विशेष क्षेत्रों पर स्वरूप प्रभाव डाल सकता है। इस विषय में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के बारे में नए वैज्ञानिक निष्कर्ष और नए विचार लोगों तक पहुंचाए जाएं। इसी प्रकार विभिन्न व्यवस्थाओं के मुख्य मुद्दों का निष्कर्ष की पुनर्गठना के विभिन्न कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा प्रभावकारी ढंग से बनाए जा सकते हैं। मध्याह्न की पुनर्गठना का विशेष उल्लेख भी इस प्रसंग में उचित होगा। इसकी वजह इसकी अधिक है और यह समस्या इसकी व्यापक है कि प्रभावकारी नेतृत्व के लिए देश विश्वविद्यालयों की ओर इस आशा से खेला कि वे मध्याह्न की पुनर्गठना में उन्हें मिलान की गई नीतियों, मधोम पद्धतियों, शिक्षा के अभिन्न दृष्टि और सम्बंधित गान गान में विकास से पूरी तरह अवगत कराए। कुछ मूलभूत राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जन समुदाय में स्वस्थ प्रवृत्ति जमाने में विश्वविद्यालय सहायता से सक्षम हैं। वे ऐसे वाक्यों को का माधोवन भी कर सकते हैं जो राष्ट्र के नेताओं और जनता को नागरिक और राजनीतिक जन जीवन की जानकारी दें और राष्ट्रीय जीवन की पुनर्गठना देने वाली कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान और व्यापक अनुभव का साम भी उन्हें दें। राष्ट्रीय धर्मरहित तथा जनता की भावना और सामाजिक व्यवहार के स्तर को उठाते हैं भी उन्हें सहायता देनी चाहिए। विश्वविद्यालय अपनी क्षमता को ठोके और पवित्र समाज के आशाओं को भी बहाल कराए। इस व्यापक प्रयत्न पर हम पहले ही यह चुके हैं कि क्या राष्ट्रीय २०

देश से निरक्षरता का उ मूलन करो और इस उद्देश्य से नेताओं को शिक्षित करने में विश्वविद्यालयों को क्या सहायता देनी चाहिए।

17 64 विश्वविद्यालय ऐसे तरीके स्वयं निकाट सकते हैं जिनके द्वारा अपने छात्रों के अनुसार समुदाय के लाभार्थ सेवाएं संपादित की जा सकें। साथसाथीन कक्षाएं प्रायः ऐसे व्यक्तियों के लिए आयोजित की जाती हैं जो कहीं नौकरी करते हों और जिन्हें परीक्षाओं की तैयारी करनी हो। व्यावसायिक लाभ के लिये विशेष अध्ययन महसिया और अल्पकालिक विशेष पाठ्यक्रमों के आयोजन की भी आवश्यकता है। साथ ही विविध विस्तार कार्यक्रम भी आवश्यक हैं। इनमें भाषण दान दान, प्रदर्शन कार्यक्रम तथा मनोरंजन आदि कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को समाज सेवा निधियों का आयोजन भी करना चाहिए और विकास तथा निरक्षरता कम करने के बहुत कार्यों के लिए स्कूलों और अन्य सामाजिक सेवाओं की देखभाल के लिए राशियों को अपना लेना चाहिए। ऐसे अनियमित तरीके हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अपनी विस्तार सेवा को प्रभावकारी ढंग से करने के लिए अपना सकते हैं।

17 65 प्रशासन और शिक्षा—योजनाबद्ध प्रोड शिक्षा कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक चालू करने और उनकी उपलब्धियों को सुधारन के लिए विश्वविद्यालयों के पास एक कार्यक्रम तय होना चाहिए। हमारा सुझाव है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक प्रोड शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाय जिसमें प्रोड शिक्षा कार्यक्रमों की तैयारी करो तथा इनके विश्वास के सम्बंधित सभी विभाग शामिल हों। जब कुछपति इस बोर्ड का अभ्यक्त हो। बोर्ड को नीति निर्धारित करने चाहिए और योजना बनानी चाहिए। संचालन के लिए अनेक विभागों के सम्मिलित प्रयास का दिना निर्देश करना चाहिए और कार्यक्रमों की सफलता का सुधारन भी करना चाहिए। हमारा विचार है कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों को प्रोड शिक्षा विभाग स्थापित करने चाहिए। इन विभागों का उद्देश्य होना चाहिए प्रोड शिक्षा के क्षेत्र में नियंत्रण और अध्ययनों को प्रगतिशील देना। शिक्षा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान

प्रौढ़-शिक्षा में आत्मानुभूति

सुषमा मिश्रा,

विद्याभ्यास (एड०एड०) में अध्ययन करते हुए एक दिन प्रोडो को सिखाते करने में भाषाओं की ने एकाएक मुझे लगा दिया। मैं पहले से इसके लिए बिलकुल तैयार नहीं थी। जो कुछ अनुभव था, अच्छे को ही पढ़ाने का था। इस सम्बन्ध में मैं अपने अनुभव निम्न रखी हूँ। इसमें किसी प्रकार की कृतितता नहीं है।

मेरा यह अनुभव है कि बच्चों को तो धीरे से डाढ़ रपट कर निम्नलिखित किया जा सकता है और उन्हें पढ़ाने के लिए अनेक विधियाँ हैं। उनके ज्ञानार्जन के स्तर में बहुत से शोध, अनुसंधान भी हुए हैं, किन्तु प्रोडो के साथ वही सख्ती नहीं अपनायी जा सकती है, क्योंकि वे न तो सहज निपटारा के योग्य ही होते हैं और न उनका मानसिक दृष्टिकोण ही विषय बनने के लिए उचित प्रेरित करता है। प्रोडो ने कवि उत्पन्न करना भी एक समस्या है। उनकी अनेक समस्याएँ रहती हैं।

एक दिन विभाग में हमें देर से घरना पड़ा, देखा कि हमारे विभाग के अध्यक्ष सहोदय प्रोडो को एकत्रित कर पड़ा रहे हैं। मेरी भी इच्छा पढ़ाने की हुई थी, मैंने भी वर्तमाना कम से ही पढ़ाना प्रारम्भ किया। प्रोडो ने अनेक प्रकार के प्रश्न किए। एक ने कहा—'बुद्ध की कालिदास से सीधे पढ़ाने आते हैं। सर दर्द कर रहा है।' के बच्चे वही माँदे रहते थे ही। मैंने सहानुभूतिपूर्वक कहा सोचा भाराम कर मो, फिर ठीक हो जायगा। दूसरे ने कहा—'महान की। लोकता नाही था।' मैंने समाधान करते हुए कहा कि कोई के पास जाओ तो ठीक दिखाई देगा। वे प्रश्न कुछ बात की ओर भी संकेत करते हैं कि प्रोडो की व्यक्तिगत समस्याओं को समझना पहले आवश्यक है।

इन सब प्रश्नोंपत्तरो से मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ दूसरे दिन जब मैं विषयविचारसय गयी, तो मेरे भाषाओं की ने कहा कि तुम रोब बनास लिखा करो, मैं प्रतिदिन ब्यास लेने लगी। साथ ही साथ मेरे मन में एक और भावना उत्पन्न हुई। मेरे प्रति एक सरकारी अस्पताल में डाक्टर हैं। अस्पताल में ४५५-डाक्टर, कम्पाउण्डर और स्वीपर-हैं। मैंने उनमें से स्वीपर के परिवार को पढ़ाने का विचार किया। मैंने सबसे कहा कि तुम और तुम्हारी औरत दोनों प्रतिदिन काम को हमारे पास लाया करो। पहले दिन तो उसकी स्त्री ही आयी। उसने मैंने पूछा, 'रघुनाथ क्यों नहीं आया।' उसने कहा—'उनके घरम लापट था कि साहब से हम लौते पड़ें।' मैंने कहा कि कोई इसमें लचाने की क्या बात है, कम से कम अपना नाम तो लिखवा सीस जायगा। किसी तरह वह आया और पढ़ने को राखी हुआ। दूसरे दिन वह स्वतः भाषा और बहुत ही मज्ज भाष से बोला 'साहब का बच्चा।' ठीक है तुम हमारे पास लाया करो और जिस तरह पढ़ोगे, हम पढ़ाएँगे। ऐसा मैंने सबसे कहा। उन्हें मन्तर लिखने का एक तरीका मैंने अपनाया। मैंने कहा—'अधर बनाने आता है?'

उसने उत्तर दिया—'कोड़ी पोरी साहिब।'।

मैंने कहा—'अच्छा, पहले इस प्रकार खुदा बनाओ' 'कोई पर बदाते हुए।'।

उत्तर—'बनाय देहमी साहिब।'।

मैंने कहा—'उसी से एक पूछा और बनाओ।'।

उसने उत्तर दिया—'बनाय दिहमी साहिब।'।

मैंने कहा—'दोनों के बीच एक पाई लीजो।'।

उसने उत्तर दिया—'सीक देहमी साहिब।'।

कहा—मैं उसके ऊपर एक टोपी उड़ा दो, सब तुम्हारा बँटवारा हो गया। इसी तरह से हर एक अंतर का बोध देने उठे बताया। धीरे-धीरे साठ-बत्त दिन में यह नाम आदि मिलने लगा। कुछ दिनों में रामायण आदि की किताब भी कुछ-कुछ पढ़ने लगा। मैंने जन्हीं की बोली में बोलकर पढ़ाने का काम किया और कर भी रही हूँ, मैं देखती हूँ कि उनसे तादात्म्य कर लेने पर हर विषय सहज हो जाती है।

धीरे धीरे लोगों की रुचि बढ़ रही है। हर वर्ग, हर योग्यता के लोग आ रहे हैं। तीन महिनाएँ भी आने लगे हैं बिना किसी पूर्ण प्रशिक्षण के हमने अपने आचार्य के निर्देशन में कार्य प्रारम्भ किया है। उनका कहना है, “बस करके सीखना ही, सबसे अच्छा प्रशिक्षण है। कार्यक्रम की सोचविमता ही हमारा प्रमाण है।”

३

पूर्व बुनियादी या नर्सरी शिक्षा

सुभाष चन्द्र बोस, स्वतंत्रभारत

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी छह वर्ष से ९ वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की सम्पन्न व्यवस्था न करने में और न गाँवों में हो सकी है, यद्यपि अनौपमिक परिस्थितियों के बच्चों के लिये बड़े बहुरों में परिभाषी पद्धति के काम-काज में लगे हैं। किन्तु ये पद्धतियाँ विदेशी पद्धति से प्रभावित हैं एवं सर्वोच्च भाषा पर अधिकार देती हैं, और ये सामान्य कामकाज का साधन बन गई हैं। बड़ी हुई भाषाओं और शिक्षा के लिए बड़ी हुई मात्रा की देखभाल के काम में लगे हैं और गाँवों में तो काम नहीं है। सात वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा है। परन्तु भी अवधारणा है और ये शिक्षा भी केवल सकल-अक्षर ज्ञान या पढ़ाई की शिक्षा है ही छोटी पढ़ाई है। नर्सरी और प्राथमिक शिक्षाओं में शिक्षा सरोपबलक नहीं है। संघर्षकाल के सरकार स्थायी होते हैं। शासन के परिणाम निम्नलिखित प्रारम्भ के सात वर्ष के बच्चों में देखा जा सकता है। इस अवधि में ही उनके सर्वांगीण विकास की स्थायी नींव बनती है। यह एक यह आवश्यक है कि शासन में भी स्थायी अवस्था शिक्षा की व्यवस्था सम्पूर्ण देश में। पूर्व बुनियादी अवस्था ज्ञान मन्दिर की शिक्षा का स्वरूप प्रदान करने और मानविकी के पढ़ने की शिक्षा के

विषय, सर्वे सुख तथा सर्वांगीण विकास का होना चाहिए।

पूर्व बुनियादी या नर्सरी शिक्षा के सम्बन्ध में शासन सर्वथा उत्तरदायी रहा है, बहुत साधन में इसे कुछ विशेष मोड़ देने का प्रयत्न नहीं किया है। इस कार्य में अधिकतर बड़े सरकारी व्यक्तियों या स्वयंसेवकों की ही पहल रही है और उन्होंने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पूर्व बुनियादी या नर्सरी बधाई को दी है। वस्तुतः ये सामान्य शासन की मुद्राएँ नहीं हैं और बहुरों में चलने वाली मान्यताएँ, नर्सरी या किन्हीं नर्सरी शिक्षाओं की प्रतिष्ठा की स्थापना है। इन सामान्यों में गुरु, पोता, माता-पिता आदि के लिए अधिकारिक मान्यताएँ देकर शासन से बहुत करते हैं। इन शिक्षा धानों का बहुत-बहुत पूर्णतया सहयोग होता है। इन सामान्यों में उच्च-मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति एवं आचार व्यवहार प्रचलते हैं। सर्वांगीण अवस्था में ऐसी शिक्षा सामान्य अनुपयोगी एवं सर्वोच्च सिद्ध होती है। सामान्य पर्यावरण एवं देश की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं से ये प्रतिष्ठित हैं। हातकला, चित्रकला, संगीत आदि विषय इन सामान्यों में शिक्षाएँ आते हैं, परन्तु सामान्यतया

दृष्टिकोण का अभाव इनमे थाया जाता है और ये सब केवल मनोरंजनात्मक कार्य बन कर रह जाते हैं। प्रत्यापको की दृष्टि इस दिशा में स्पष्ट करनी होगी निरुत्तरता आदि समाजोपयोगी हो और बच्चों में उनके द्वारा धर्म के प्रति आदर की भावना एवं उचित उत्पन्न हो।

शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों के ऊपर छोड़े हुए गुणों एवं प्रतिभा का प्रकाशोत्तरण करना ही होना चाहिए, तथा शिक्षा जीवन के लिए होने की चाहिए और शिक्षा द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास परिलक्षित होना चाहिए साथ ही शिक्षा औद्योगिकीय पर्यावरण में युक्त महत्त्वपूर्ण समाजवादी समाज के निर्माण की महत्त्वपूर्ण कड़ी बननी चाहिए। अनुसूचित वर्गों का नाम में प्राप्त सरकारी या प्रभाव गहरा एवं स्थायी रूप का होता है, वे ही सरकार माने चलकर उनके जीवन जीने का आधार बन जाते हैं। शिक्षा की शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसने द्वारा बच्चों के शरीर, मन, भावना और आत्मा का समुचित विकास सम्भव हो सके। अतएव शिक्षाओं की पांच इन्द्रियों दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, रस, गन्ध का विकास समुचित रूप से किया जाना चाहिए। शैक्षिक मूल्य के ज्ञान और अनुभव के ये ही द्वार हैं। विद्यार्थी की शिक्षा के लिए इन पांचों इन्द्रियों का उपयुक्त व्यवस्थापन एवं क्रिया करना चाहिए। शिक्षा को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जानक कालिका के शहर छुड़ी हुई पत्थरों की दीवारों, प्रतिभाओं का प्रकाशोत्तरण करना है और प्रत्येक बच्चे को ज्ञान में उसकी उचित और मर्यादा के अनुसार शिक्षा देने की प्रतिभा प्राप्त कराना है। एवं ही जाती है ■■■ बच्चों को हास्य और नहीं होना क्योंकि हर बच्चा अपने समय में ही विशिष्ट होता है। अतएव शिक्षा केन्द्रों में दोषा-दोष, संधीला टाइट टयुन होना चाहिए। धर्म, विज्ञान, आर्थिक के क्षेत्रों के विज्ञान ज्ञान को जारी नज़रों के लिए उपयुक्त होने चाहिए।

साक्षात्कार का संगठन एवं वातावरण भी और छात्रों में दोषों की परिभाषा पर एक शिक्षा छात्र हानी चाहिए, जिससे विद्यार्थी को घर से दूर न जाना पड़े

शिक्षाशास्त्र में आई वर्ष से ६ वर्ष के बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए और कक्षाएं खुली हवादार, साफ सुथरी होनी चाहिए। बच्चों में गर्व की भावना, प्रार्थना की भावना से सम्बन्ध की जा सकती है। वर्तमान प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। अतः इनमें से शिक्षक पूर्व बुनियादी कक्षाओं में पढ़ाने के योग्यता से जांचे जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा भी पूर्व बुनियादी कक्षाएं खोली जा सकती हैं और ज्ञान पंचायतों पूर्व बुनियादी कक्षा में चलाने के लिए स्कोलरशिप को प्रोत्साहित कर सकते इसके लिए शासन उन्हें ऐसा करने की सुविधा प्रदान करे जिसमें इन कक्षाओं का व्यय भार ग्राम पंचायतों सहित कर सके। इसी प्रकार प्रीट्ट सिद्धांत के भी पाठ भी पूर्व बुनियादी कक्षाएं खोली जा सकती हैं दोनों ही कार्यों के लिए शिक्षक को १५० ६० प्रतिभाएं देकर दिया जा सकता है। बच्चों के प्राइमरी बुनियादी स्कूलों, हाईस्कूलों तथा एग्रेग्रीगेटेड कक्षाओं के साथ पूर्व बुनियादी कक्षाएं खोली जा सकती हैं। वे पूर्व बुनियादी विद्यार्थी नियुक्ति कर सकते हैं। इससे व्यय कम होगा। परन्तु इसने लिए सरकारी विभागों में परिवर्तन करना पड़ेगा। इससे अन्तर्गत हरय सेबो संस्थाओं, साक्षर, रोटरी क्लब इत्यादि सर्वोद्यम मण्डलों रचनात्मक संस्थाओं द्वारा समितियों, ग्राम-उद्योग शाखाओं द्वारा शासन की पहल से तथा सार्वजनिक संस्थाओं की पहल से सम्पन्नित रूप से दोनों की पहल से पूर्व बुनियादी कक्षाएं खोली जा सकती हैं। शासन, की ओर से कारखानों मिलों आदि पर मद प्रतिभामें लगाया जाय कि वे संस्थाएं अपने समर्थकों व बच्चों के लिए पूर्व बुनियादी कक्षाएं खोलाएं। ऐसी कक्षाएं खोली क समीप हों और प्रभावशाली नभ संचालित मेलकद का भी मामला रतों। शिक्षा केन्द्रों में व्यवस्थापन रूप में शिक्षा के प्रतिभाएं वेलात्मक मध्यम एवं अध्यापिकाओं की नियुक्ति करना उपयुक्त होगा।

प्रत्येक शिक्षा शास्त्रों में ५०-६० तक विद्यार्थी होने चाहिए, जिन्हें कक्षाएं खुली हुई आकार में बड़ी, साफ सुथरी हवादार और रोशनीदार होने चाहिए। शिक्षा शास्त्र का माध्यम छात्र का रोम कद का पैरान हो, बड़ी

जल सेमझूझ ला। सामान हो। यह संदान देइ, फूल पोथी
से सुशोभित होना चाहिए। गर्मियों में शालग्राम जानवर, पाथी
बादि का सामोप्य शिवाजी के लिए किया जाता चाहिए।
इनके द्वारा बच्चों में स्नेह, दया, देइ-पौथी की देख-रेख
की कोमल भावनाएँ, मृदु और मिठी, हम सबका
चरण पोषण करती हैं बादि भावनाएँ पैदा की जा सकती हैं।

बस सामानों का वातावरण भाव-रसायक, प्रफुल्लित
करने वाला साक उपरा एव असायक होना चाहिए।
विद्यार्थी की यहृष्टता से शान्त, मिठी पाने से स्वर्ण तथा
पुन-पौथी को रूप-रस, रस, रस बादि पाथी इन्द्रियों
के द्वारा साक अनुभव एव ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
बच्चों में संवेदनशीलता और कोमलता की भावना बनाने
के ये ज्ञान प्राकृतिक साधन हैं। इन्हों के द्वारा बच्चों
में भावना, देइ-पौथी तथा मनुष्य मान के प्रति स्नेह और
रस की भावना बसाई जा सकती है। प्राविमान, वाचर,
रगस्तति, ओडकाल, पय-पानी सभी ईश्वर की गृष्टि
हैं। सभी में विभिन्न स्तर की देइता है। इन भाव-
नाओं का निर्माण शिक्षा कर सकता है। इसी परिवेश
में लोकता, लोकता, सामान्य, पुराण उपनिषाद की
कथाएँ साक शरीर में बसाई, शिवाजी बानी चाहिए।
पृथ्वी की सब चीजें महापुरुषों की जीवनी सति उत्तम
धर्मों में बसाकर बच्चों में सब धर्मों के प्रति आदर और
उत्तर भावना बसाई जा सकती है। सामानों से धार्मिक
प्राज्ञावाचक पैदा करना आवश्यक है। अतः सब धर्मों की
भाषना, पञ्च बादि सही कथानों का कार्य आरम्भ
किया जाना चाहिए। धर्म, मित्रता, लातिपाति, ऊँच-
नीच भावना सादि को सूरभूमि से अलगना, उनमें उत्तर
मुक्तिपैदा करना भी आवश्यक है। अन्त्याक को इसे
सुखतापूर्ण करना चाहिए।

शिव सामानों का वातावरण शिक्षा और शिक्षा-
र्थों के बीच परस्पर प्रेम आदर एव अलगना की भावना
ला होनी चाहिए। शिव सामानों में भय अतिशय विराट्, हिंसा
जैसा, ऊँच-नीच की भावना कदापि पनपनी नहीं
चाहिए। सामानता ॥ अतिशय, स्नेहमय वातावरण होना
आवश्यक है। शिक्षा की यह महत्त्वपूर्ण दायित्व हो
जाता है। शिक्षा की भावनाओं ॥ सुख संवेदनशील
भावना शिव सामानों का धर्म है।

पाठ्य विषय—

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा—सभी शिव सामानों

में शरीर के पानी की तथा शीतलपान की व्यवस्था आव-
श्यक है। बच्चों को इनका ठीक ठीक उपयोग करने की
आदत बनानी चाहिए। स्वच्छता ॥ इनका ध्यान
अच्छे बनना, स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वच्छ अतः और
शीतलपान की आवश्यकता तथा उसका सही उपयोग उन्हें
सरस समझें ॥ समझाना चाहिए। उनमें व्यक्तिगत सफाई
हाथ, नाक, कान, मुँह, जल, नालू बादि साफ करना
शिक्षाया जाय और नियम इनकी सफाई द्वारा उन्हें
अव्याप्त कराया जाय। शीतलपान, मृदापान, कदा जल
का संदान बादि शारीरिक स्वार्थों को अच्छे रहने का
अव्याप्त भी उन्हें कराया जाय। इसकी उपयोगिता की
वर्णना बसाई जाय। सफाई का शिव के जीवन पर स्वाधी
ज्ञान होता है। बच्चे हैं बाह्य दृष्टि से अन्तर दृष्टि भी
हो पाती है।

अतः यह कहना आवश्यक होता कि बच्चों में स्वास्थ्य-
प्रद आदतें बनाना शिव शिक्षा का आवश्यक अंग है।
स्मरण रहे कि केवल कक्षाविधि बतलाकर या शिक्षा कथ
में इन सभी बातों की कहना पर्याप्त नहीं है। इन सबको
व्यावहारिक रूप से शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए,
और शिक्षार्थी से कराया जाना चाहिए। सभी बच्चों
पर इन आदतों की सावधानी। उदाहरणस्वरूप यदि
शिक्षक, बच्चों की सुनी हुआ और सफाई के बारे में
बतलाता है, परन्तु कक्षा की सब शिक्षिकाएँ बन्द हैं और
साक हुआ कक्षा के आदर का ही सही समझती है, शिक्षार्थी
में बच्चों के आगे लगे हुए हैं, कमरे में, शिक्षिकाएँ पर,
सावधानी पर ध्यान सही हुई है, ऐसी दशा में केवल मान
कहने का कोई अन्तर नहीं रहेगा। व्यावहारिक रूप
से शिक्षिकाएँ प्रतिबिम्ब बच्चों द्वारा प्रशिक्षण चाहिए।
बच्चों और शिक्षा द्वारा सफाई करानी चाहिए। सभी
शिक्षा के कहने का अन्तर होता और बच्चों में सफाई की
आदत पैदा होनी है। इसके साथ ही बच्चों के हाथ पाँवों में
सफाई कराया, धर्मों में सफाई करवाना बादि, कार्यक्रम
भी सामानों के रचनात्मक कार्यों का अंग बनाया जा
सकता है, ये ही उपयोगी रचनात्मक कार्य हैं। इन्हों
के द्वारा बच्चों की शिक्षाशीलता का उपयोग किया जा
सकता है। शरीर ॥ सम्भव में तथा स्वास्थ्य के साधन
में व्यावहारिक ज्ञान लेकर बालक की शिक्षाशीलता का
उपयोग किया जा सकता है। शरीर तथा

हवास्थ के सम्बन्ध में व्यावहारिक ज्ञान देकर बालक को प्रियाशीलता बढाने के लिए उनके ज्ञान की भी व्यवृद्धि की जा सकती है।

वर्षों के शारीरिक उपयोग का उपयोग तथा उनकी
 मानो का उपयोग शिक्षा और मान प्रशिक्षण के महत्त्वपूर्ण
 साधन हैं। शिक्षा को इन साधनों का उपयोग आवश्यकता-
 पूर्वक और विवेक से करना चाहिए। यह समझित
 है कि बालक क्रियाशील होते हैं और उन्हें सब प्रकार
 की शारीरिक एवं खेल प्रकार की हस्तचालन पेश होनी है।
 यदि इस क्रियाशीलता का अनुयोगों के द्वारा जाता है तो वह
 बालक बच्चों के बाल्यक एवं मानविक विकास
 की महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में बन सकती है। कलात्मक,
 मानविक एवं क्रियात्मक विकास, 'वैश्वविद्यालय' के
 विभिन्न विभागों के विकास के एक प्रमुख उद्देश्य
 है। खेल खेल के माध्यमों से और बच्चों की
 क्रियाशीलता का उचित मार्गदर्शन करते हुए शिक्षक
 इस प्रकार के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
 विविध प्रकार की शारीरिक हस्तचालन का उपयोग विवेक-
 पूर्वक किया जाना चाहिए। यह खेलना, करना, चलना,
 पढ़ना, लड़ना, सोचना, प्रकृतिक, मनोविज्ञान, समाज,
 खेल-कौशल, लक्ष्य, गुणों का, रचना, आदि-
 विषयों की शिक्षा, लोकाचार, आदि, बच्चों की विविध
 प्रकार की हस्तचालन बच्चों के शारीरिक एवं मानविक
 विकास के साधन हैं। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन
 बना करता है। इन क्रियाओं से बच्चे मानव का अनुसंधान
 करते हैं। इनके द्वारा शरीर पर नियंत्रण, अनुसंधान
 भावी गुणों का विकास बच्चों में होता है। बच्चों की
 समझ-बुझ की भी क्रियाएं होती हैं जिन्हें द्वारा बच्चों
 का मानविक एवं मानविक विकास होता है। खेलना
 नये शब्दों की सीखना, प्रकृतिक, लोकाचार, मनोविज्ञान
 भावी बातों को समझना बचपन, लोकाचार, मनोविज्ञान
 भावी बच्चों की समझ-बुझ के साधन हैं। इन क्रियाओं
 की भी खेल-कौशल में ही किया जाना चाहिए। इन सभी
 क्रियाओं का उपयोग शिक्षा को आवश्यकता पूर्वक प्रकृतिक
 रूप से प्राप्त करना चाहिए जिससे कि बच्चों की शारीरिक
 प्रकृति का विकास हो सके। इन क्रियाओं के योग्य

[illegible]

मलग मलग मौसमों में सेतों में से जाकर बनाओं, फलों, कृमों के रंग, उनके नाम आदि का ज्ञान कराकर उनमें कोमल मोहनाएँ बघाना, मिट्टी, पानी, गोबर आदि का अनुभव कर इनकी समीपता भी जितना का आवश्यक बस होना चाहिए। जानवरों, कीड़ों, बाघ, भैंस, बकरी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता आदि जिनमें का विशेषण उनका सामान्य उनकी बोली भाषा आदि से जाना जा जान करवाना, उनमें कोमल मोहनाएँ बघाना उनमें सुवेदन भीमता देना करना एवं कुशल शिक्षक का काम है। इसी प्रकार प्रकृति के परिवर्तन हेतु जलचर, पक्षचर एवं जलचर के विषय तथा जिनमें भी वे से जा सकते हैं। पशुओं के होने मायना, शरीर, स्वर्ण, रूप, रस, गंध का विकास के उपरोक्त मुख्य साधन हैं। इसका माध्यम भाषा सम्बन्ध और कार्य ही है। इन प्रकार इन अनुभवों से बुद्धि और ज्ञान का विकास किया जाना चाहिए। भाषा बोधने का शरीर और वर्णिक साधन नहीं है। विकास सहज रूप से होता जाना चाहिए। इसमें भय, प्रशंसा या डराना का पुट न हो। पशु सामान्यों की साथ शिक्षा मातृ भाषा में ही दी जाना।

॥ शिक्षाविद ऐसा मानते हैं कि ६ वर्षों तक नहीं की मातृ के बाद ही बच्चों को हिवाब और बहना शिक्षा चाहिए। किन्तु अधिमायक किन्तु की प्रवृत्ति का मायस्थ पढ़ना निम्नता ही मानते हैं। इससे ६ वर्ष के बाद पढ़ना निम्नता शुरू करने से अधिमायक अधीर हो जायेगे। किन्तु इसका सत्य है कि केवल विषय ज्ञान पर बल देने की अपेक्षा, समग्र जीवन के लिए शिक्षा देना अधिक उपयोगी होगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। मनु मानव ज्ञान के क्षण महापुरुषों की बीजनी कविता पाठ पढ़ाएँ, सरल गणित, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा आदि का ज्ञान और अनुभव योग्य एवं व्यावहारिक रूप से कराया जाना चाहिए। किन्तु इन सब के लिए पहले बच्चों की आत्मिक तैयारी कर लेना आवश्यक है। पूर्ण बुनियादी शिक्षा कक्षा की कुछ विशेष बातें शिक्षक को ध्यान में रखने योग्य हैं जो इस प्रकार हैं—बालक के विद्यालय में भय और बल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इससे उनकी सरल, शैल और भी सहज प्रवृत्ति न कुटिल हो जाती है। इस

पद्धति में शिक्षा, खेल, पढ़ाई विचार्य रचनात्मक कार्य, स्वास्थ्य कार्य आदि सभी कार्य मलग मलग विषय में होकर एक समायोजित रूप से बालक की विद्यालयता को बल देने की प्रक्रिया मान है। सभी विद्यालय कार्य समायोजित करते हैं। उनके माध्यम से बालक खेल को अनुभूति प्राप्त करते हुए आनंद प्राप्त करें। इस प्रकार विद्यालय शुष्क या आरक्षक माध्यम नहीं होगा। खेल-क्रीडा की प्रक्रिया से बालक सब कुछ मनाने में ही रीति लेगा।

रचनात्मक कार्य — रचनात्मक कार्य पूर्ण बुनियादी शिक्षा का आधार है। मनु रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए और इस कार्य के प्रति बच्चों के हृदय में आदर और तेज की प्रवृत्ति बगानी चाहिए। उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि बच्चों का रचनात्मक कोमल बाध हो। इसके साथ ही हमें यह भी कि रचनात्मक कार्य उत्पादक हो और समाजोपयोगी भी हो और सम्बद्ध समाज के वातावरण के अनुकूल हो। ऐसा बालक है कि रचनात्मक कार्य कई क्षणों में शुरू किए गए हैं। परन्तु इनके पीछे जो बुद्धि होनी चाहिए उसका समर्थन जगता है। कई प्रकार के रचनात्मक कार्य जैसे मायक कान्वा, घुट कान्वा आदि कार्य क्षणों में दिये जाते हैं परन्तु के साथी उपरोक्त ही होते हैं। ये समय बिताने या टाइम टेबुल के अब मान बन गए हैं या ये यात्रिक रूप से किए जाते हैं या इनका उपयोग मनोरंजन मात्र के लिए किया जाता है। यहाँ पर यह कहना सचित होना कि अब रचनात्मक कार्य पर बल दिया जाता है तब उत्तर कदापि यह नहीं है कि पुस्तकीय ज्ञान या बोद्धिक ज्ञान या उसके विकास का अनुभव किम्वद बाधना। पुस्तकीय ज्ञान रचनात्मक विकास एवं आत्मिक विकास सभी विद्या के महत्वपूर्ण अंग हैं और समग्र बुद्धिकोश से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है इसको निम्नतम नहीं करना चाहिए।

शारीरक सामान्यों में बच्चों के शरीर सुदृढ़, लयल करने और बल किम्वदों द्वारा ज्ञान का अनुभव प्राप्त करते हैं। पशुओं इन्डियों द्वारा अनुभव मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करता है, इनके

हवन से ही उसे अनुभव की प्राप्ति होती है। ग्रामीण समाज में बच्चे पेड़, पोपे, सन्दी, फलफूल के बगीचे आदि देखकर उनके विदास को देखकर अनुभव पाते हैं। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जानवर आदि की हलचल, उनका स्वभाव आदि देखते सुनते हैं और इससे उनके अनुभव विकास एवं ज्ञान की सामग्री बनती है। बच्चे गांवों में खेती बर्द घीरी, लोहारगोरी, मकड़ी का काम, मिटटी के बर्तन ईट बनाया आदि काम देखते हैं और उनके विषय में सुनते हैं तथा ध्यावहारिक ज्ञान पाते हैं। अंतर्गत उत्तर कहा जा चुका है बच्चों में प्रेम भाव जोमल साधना, क्रूरता न करना, माय, मैल बकरी, पोडा, कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों के प्रति स्नेह भाव बढ़ाना, विधियों बुराई आदि के प्रति अंतर्भाव बढ़ाना इन सब की सेवा करना, पालन पोषण करना, उनकी उपयोगिता को समझना, खेलों में फूल पत्तों सरसों की पीली कासिया, पीले पीले सफेद फूल, हरियारी आदि की पोसा बेलकर प्रकृति के लोभ का अनुभव करना, घुड़न पद, सारों की देखकर लोभ में लगे करना आदि ज्ञान ध्यावहारिक रूप से बच्चों को दिया जाना चाहिए। बहुत सम्भावक इसे कुछ बूझके साध कर सकता है। परन्तु इसके लिए सम्भावक को विविध प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सम्भावक के अतिरिक्त घर में यह स्पष्ट हो कि शिक्षा केवल माय पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, परन्तु व्यवहारिकता और क्रियाशीलता के माध्यम से बच्चों की मानसिक पृष्ठभूमि को अनुकूल शिक्षा दी जाय और बच्चों का ज्ञान बढ़ा, मात्र पढ़ा और क्रिया पढ़ा सभी की बगाने की क्रिया ही सम्पूर्ण शिक्षा है। परन्तु इस प्रकार के अनुभवों की सम्भावना सहज में कम होती है। इनकी पूर्ति और प्राप्ति सहज में बच्चों को करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि अच्छी शिक्षा का यह सहजगुण साधन है। नहीं तो पाहरी शिक्षा मात्र पुस्तकीय होनी और व्यावहारिकता तथा समाज से दूर होकर रह जायगी।

रचनात्मक कार्यों में बर्तन घोलना, आडू लगायना सजाई करना, लसरी घोल, कापन आदि ने टुकड़े को टुकड़े की टोपी में बालना, बुझा साक करना, कापवाणी, पदी तालीम / १५

बगीच की सजाई करना आदि कार्यों के संस्कार देना आवश्यक है। शिक्षक को इन कार्यों के महत्व एवं आवश्यकता को बच्चों को बतलाते हुए इन रचनात्मक कार्यों को कराना चाहिए। शिक्षा में धर्म के महत्व को बढ़ावे से जातिभेद की भावना भी दूर होगी और आरोग्य लाभ भी होगा। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होगा और उनमें स्वच्छता, व्यवस्थितता की भावें पैदा होगी। इसी परिदृष्टि में शिक्षक का कार्यों द्वारा बच्चों में कुछ चारित्रिक गुणों का भी आरोपण कर सकता है। निम्नोक्त पालन साक्षात्पालन, उत्तरदायित्व की भावना बगाना, ठीक समय से काम करना, समय मद्ध न करना परस्पर सहयोग एवं सहायता की भावना बगाना आदि नैतिक गुणों का भी आरोपण शिक्षक की सुझ सुझ से करना सम्भव है। इसी प्रकार मोला विरोधा, सुई में धाया रानना, सब्जी काटना, आको और पीको का वर्ण-करण करना, कापन के आकर ने टुकड़े कैंची द्वारा काटना, कापन धिपकाना और चिपकारी, र्यों का उपयोग, गालू मिटटी से खेल तथा लठ्ठे आकार बनाना आदि कार्यों में रचनात्मक कार्य हैं। शिक्षार्थी में समारोपणीय एवं वैदिक गुणों का सज्जन करना शिक्षक का कार्य है। शिक्षक के लिए यह चिन्तन का विषय है एवं व्यावहारिक चुनौती है। उपरोक्त सभी बातों का व्यावहारिक ज्ञान शिक्षक के प्रशिक्षण का अव अवभावा जाना चाहिए।

सामूहिक कार्य—सिख बच्चों में कुछ कार्य व्यक्तिगत रूप से और कुछ कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं। सामूहिक कार्य का प्रभाव बच्चों के जीवन पर अच्छा पड़ता है। उनमें सामूहिक कार्य से सहयोग सेवामात्र कापन कार्य करने की आदत पैदा होती है। इससे वे सब कार्य जिनका जल्लेख पहले भी किया गया है उनसे सामूहिक रूपसे बचाया जाना चाहिए। जैसे बजिनद, कबिता पाठ, नृत्य संगीत, खेलगीत, लोक नृत्य, बजिन, हस्तकला, मिटटी का काम, खेलकूद, व्यायाम आदि की सामूहिक कार्यों में करते हैं। सिख बच्चों में ये कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं परन्तु यहां पर केवल यही कहना उचित है कि इन कार्यों द्वारा भी

यन्त्रों का नैतिक शिक्षा होनी चाहिए और उनमें शारीरिक गुणों का स्वर्धन होना चाहिए। सामूहिक कार्यों द्वारा शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों में एक साथ मिलकर काम करने की आदत बालें, सेन-सेन, छात्रों, सेवा, अनुशासन सिखाए, छात्राध्यक्षों न करने, पोषा धरो न करने आदि की आदतें बालें। पवित्र नागरिक धर्म पनपाने के बहुमूल्य साधन सामूहिक कार्य एवं खेलकूद के संदान ही होते हैं। शिक्षक को बहुत ही धृक्-बुद्ध के साथ इन नागरिक आवश्यकताओं को जगाना है। शिक्षक के प्रशिक्षण में इन मूल्यों को क्रियाशील बनाने के उपरोक्त साधन सम्मिलित किये जायें चाहिए।

गहरी साधुर्भूत बुद्धिवादी कलाओं के कार्य का समग्र दार्ष्टिक्य ही पद्यों का होना चाहिए जिससे वास्तव एवं विषय का समग्र भी सम्मिलित है। पात्रों में फलस के अनुसार मूर्ख, नरक, चण्डा, मन्दार आदि तथा मनश्च, भाव आदि को एकत्र कर वर्णों के लक्षणों की व्यवस्था की जा सकती है। इन दोनों कार्यों को नियमित रूप से किया जाय। इन शास्त्रों की ये आवश्यक प्रक्रियाएँ हैं। इसी प्रकार सामूहिक कार्य में वर्णों को कहानी सुनाने का भी बड़ा आवश्यक है। अच्छी तरह अधिपूर्ण नाटकीय इन से कहानियों को जाननी चाहिए। कहानियाँ अपने मार्करक रूप से कही जाय कि वर्णों मुख्य होकर रहें वृत्ते।' कहानी कहना, विधान करना, व्यवहार करना, धर्म देना, धर्म दाता बनना, धर्म दाता बनना, या केवल वे सब प्रक्रियाएँ जिन्हें कहालों के आवश्यक मन है। उनके द्वारा शिक्षाओं के शरीर, मन एवं स्वरूप को पुनः-पुनः विधान निम्नता है, उनके अन्तर और बाहर धर्म दाता बनना उत्पन्न होता है। मानसिक एवं आचारिक स्वभाव की दृष्टि से ये आवश्यक है। अनेक प्रकार की अनोखताएँ कहानियाँ, दूसरे देशों के शासकों की कहानियाँ, साहित्यिक रीति-रिवाजों की कहानियाँ आदि विविध प्रकार की कहानियाँ सुनायी चाहिए। इन कहानियों द्वारा वर्णों के ज्ञान की वृद्धि होती है, उन्हें और उनके स्वरूप को विधान निम्नता है, वर्णों का अनोखता होता है, उनकी कल्पना क्षिति को बढ़ाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें छोड़ने, भक्ति, यज्ञ, साहस, धर्म आदि गुणों का बोध कहानियों द्वारा कराया जा सकता है।

शिक्षक — यह सत्य है कि उपर्युक्त बहुत से क्रिया-कलाप छात्राओं में किए जाते हैं। कुछ आलोचक, कहे हैं कि इन विचारों में कोई नवीनता नहीं है यह भी सत्य है। खेलकूद, रचनात्मक कार्य, व्यायाम, पाठ्य विषय सभी कार्य न्यूनाधिक सभी ऐसे छात्राओं में किए जा रहे हैं। परन्तु छात्राओं की प्रगति ततोद्यत्नक नहीं मान्य होती है। उनमें बहुत कुछ कमी का अनुभव होता है। यही बात यह है कि हमारी सारी छात्राएं इन छात्रों को अलग-अलग विषय के रूप में देखती समझती हैं। वे सोच यह दृष्टिकोण अपना नहीं पाए हैं कि शिक्षण एक समग्र वा समन्वित कला है। शिक्षण एक समन्वित कार्यक्रम है, इसका भी उन्हें बात नहीं है। खेल द्वारा ही शिक्षण के विविध कार्यक्रमों को प्राप्त प्रदर्शन करना होना, यही शिक्षण की सबसे बड़ी कला है। अतः सम्पूर्ण शिक्षण क्रिया एक समन्वित, समायोजित प्रक्रिया है, इसका माध्यम शिक्षक को सतत होना चाहिए और यही दृष्टिकोण उच्चरी प्रेरणा का प्रीत होना चाहिए और माना प्रकार के नए विचारों उपायों को सोचना और प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे शिक्षक के जीवन में ताजगी आएगी और जिसका कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न रहेगा। बहुत कुछ धर्म के बाद शिक्षण, शिक्षण की अन्त पारणाओं या भूमि उद्देश्यों की मूल आत्मा है और यद्यपि सारे विषय कार्य करने लगता है। इससे शिक्षक के जीवन में चलाता और उत्साह विहीनता आने लगती है। शिक्षक की सक्रिय होत हुए भी अपने व्यक्तित्व एवं प्रचलन को प्रत्यक्ष रूप से बाह्यक मानिकामों पर भावना नहीं चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थी का मार्ग निर्देश करना चाहिए, उनके खेल की प्रवृत्ति एवं उत्साह को समायोजनयोगी बनाना चाहिए। उनमें अच्छे भाविकों के गुणों का उद्घोषण करने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षकों में मनुष्यवृत्ति स्पष्ट निर्देशन हृत्पुष्प रहन यदि गुणों का होना आवश्यक है। वस्तुतः पूर्व इतिहासी कलाओं के शिक्षण कार्य के लिए अपेक्षाकृत महिला शिक्षिकाओं का होना सामान्य होता है, क्योंकि शिक्षक में माता का धार, माता की ही सहनशीलता, दया, धर्मा, त्याग, समय, निःस्वार्थ सेवा आदि गुण आवश्यक हैं। महिलाओं में यह गुण अधिक माना

गोबध पर प्रतिबन्ध

के० अरुणाचलम्

देश में समी समय से यह गाय चली आ रही थी कि सविधान के राज्य निर्देशक तत्व के अनुसार गोधर्म पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इसके लिए १९७६ में विनोबाजी ने साधारण अनशन का भी अपना विचार घोषित किया था। किन्तु तत्कालीन सरकार के शास्य-तान पर उन्होंने इसको एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर देश के सभी राज्यों में कानून पात्र करके गाय के दूध पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसी बीच संश्लेष तथा अन्य राज्यों की सरकारों में परिवर्तन आया और सभी प्रतीक्षा के बाद विनोबाजी को फिर प्रोत्साहित करने पर ही कि वह इन दो राज्यों में भी प्रति-बन्ध नहीं लागू जात है तो वे १ जनवरी १९७६ के धार-रण अनशन प्रारम्भ करेंगे। इस पर काम स्वराज्य के कार्यकर्ताओं के समेजन में उनके यह अनुरोध किया कि उन दोनों सरकारों को कानून बनाने के लिए राजी करने के लिए वे उनके कुछ और समय हैं, और विनोबाजी ने ११ दिन का और समय दिया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने इन दो राज्यों में कोषियों की, किन्तु समूह के कुछ परि-णाम न निकले।

अब विनोबाजी को २२ मार्च के अपना अनशन प्रारम्भ करना पड़ा। उनकी उम्र, स्वास्थ्य और बीमारी के कारण इससे देश में बहुतों को बड़ी चिन्ता हुई और राज्यों में बध्मलता मिलने पर दिल्ली में इसके प्रभाव किए जाने लगे कि सत्ताधारी दल को विनोबाजी के साथ बचाने हेतु उनकी यात्रा की रूढ़ि के लिए कुछ करना चाहिए। प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई को भी तथा कि देश को विनोबाजी को छोड़ा नहीं चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप, अपनी व्यक्ति के स्वास्थ्य, व होने यह साहसपूर्ण निर्णय लिया कि सविधान में उचित संशोधन किया जाय। इसके घोषणा सत्र में २६ मार्च

को २ बजे अथवाज्ञ की गयी। उसने बड़ा कार इसी सत्र में सविधान सहायक भूत भी बादा धर्माधिकारों और भी दिल्ली में कई सत्रों, दल नेताओं से। पुरी परिस्थिति से अवगत कराई तबको ए लिए राजी कर लिया था कि विनोबाजी को लिए कोई निर्णय तत्काल लिया जाना गाय को भी रखा होना।

सत्र के प्रधानमन्त्री द्वारा दिये गये भी दावा, धर्माधिकारी, श्री राधाकृष्ण भी बार-बार ०० वाटिस के अनुसार सत्र पर अपना अनशन समाप्त कर दिया। इसके बाद सन्ध्यापियों को बड़ी राहत हुई। किन्तु राई के समर्थकों का उत्तरदायित्व भी, वह पड़ा। कानून बनाकर अपना धर्म पुरा कर दी, श्री आये बढ़कर अपना, कर्तव्य पूरा करता होना कर्मचारी, पुरुषों की, देखनाम व्यवस्था को बरतते रहे होने पर उनकी रक्षा का भार बरहा। कुछ वर्षों की मायेवा, यह कहा, जाता है गया सूख जाने पर गाय, श्री, श्रीन धर्म और और प्रति साथ २ वर्षों का प्रतिनिधि अब इसकी व्यवस्था करना समाज का धर्म है उसका उद्य समय काम उठाया जबकि यह और खेती करने तथा भार बोने के निवे सरकार के लिए बड़ी गायों की बेवजहान एक तारी समरथा होनी, किन्तु यदि स्थानीय समुदाय इस ठा ठोते हैं, तो यह भार बट जाता है। किन्तु यह स्थानीय स्तर पर संगठन का है। मोरारजी प्रधानमंत्री बनने के लिए कार्यकर्ताओं को पर इस काम को संचालित के प्रभाव शक्ति सचानी होनी।

गोबध पर प्रतिबन्ध

के० अरुणाचलम्

१११११

देश में लम्बे समय से यह माँग चली रही थी कि सविधान के राज्य निर्देशक तत्व के अनुसार गोबध पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इसके लिए १९७६ में विमोचनी ने मांगरण अवधन का भी अपना विचार प्रोत्साहित किया था। किन्तु तत्कालीन सरकार के आस्था-वन पर उन्होंने उसको एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल और कोरस की, छोड़कर देश के सभी राज्यों ने कानून पास करके राज्य के बम पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसी बीच केंद्रीय तथा उन ही राज्यों की सरकारों ने परिवर्तन मांग और लम्बी प्रतीक्षा के बाद विमोचनी को फिर मोदरा करनी पड़ी कि यदि इन दो राज्यों में भी प्रति-बन्ध नहीं लग जाता है तो वे १ जनवरी १९७९ से आभ-रण धनवान, प्रारम्भ करेंगे। इस पर आम स्वराज्य के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन ने उनसे यह अनुरोध किया कि उन दोनों सरकारों की कानून बनाने के लिए रेखी करी के लिए वे उनकी कुछ और समय दें, और विमोचनी ने ११ दिन का और समय दिया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने इन दो राज्यों में कोरिया की, किन्तु चर्च के कुछ परि-णाम न निकले।

अतः विमोचनी को २२ मार्च से अपना अवधन प्रारम्भ करना पड़ा। उनकी उम्ह, स्वास्थ्य और बीमारी के कारण इसी देश में बहुतों को बड़ी चिन्ता हुई और राज्यों में अवधनता निम्न पर दिल्ली में इसके प्रयास किए जाने लगे कि सत्ताधारी बल की विमोचनी के साथ बचाने हेतु उनकी मांग को रूति के लिए करना चाहिए। प्रयास सभी की मोरारजी देसाई की भी तथा कि देश की विमोचनी को छोड़ना नहीं चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप, अपनी अनिच्छा के बावजूद, उन्होंने यह साहसपूर्ण निर्णय लिया कि सविधान में उचित संशोधन दिया जाय। इसकी घोषणा सचद में २६ मार्च

को २ बजे अपराह्न की गयी। उससे कहा गया कि सर-कार इसी क्षण में सविधान संशोधन बिल लायेगी। इसके पूर्व श्री दादा धर्माधिकारी और श्री राधाकृष्ण बजाज दिल्ली में कई साधनों, दस नेताओं से मिले जुले थे और पूरी परिस्थिति से अवगत कराके उनकी इस बात के लिए राजी कर लिया था कि विमोचनी को बचाने के लिए कोई निश्चय सरकार लिया जाना चाहिए और इसके साथ ही रक्षा होगी।

सचद में प्रयासशील द्वारा दिये गये आश्वासन तथा श्री दादा धर्माधिकारी, श्री राधाकृष्ण बजाज और श्री भार० के० पांडेय के अनुमोदन पर विमोचनी ने अपना अवधन समाप्त कर दिया। इससे उनके हजारों अनुयायियों को बड़ी राहत हुई। किन्तु साथ ही गोरक्ष के समर्थकों का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। सरकार कानून बनाकर अपना धर्म पूरा कर ले, किन्तु जनता की भी भाँपे बतकर अपना कर्त्तव्य पूरा करना होगा। बड़े और कमबोरा, पल्लुओं की, देवमान, जनता की करवी है और बड़े होने पर उनकी उत्साह का मार जनपर है। इस पर कुछ वर्षों की धामेगा। यह कहा जाता है कि सत्ताधारण तथा सुल जाने पर साथ ही हीन वर्ग और कीर्ती है। और प्रति साथ २ वर्षों का प्रतिदिन व्यय माता है। इसकी व्यवस्था करना समान धर्म है क्योंकि उसने उसका उस समय साथ उठाया जबकि वह दूध देती थी और खेती करने तथा भार डोने के लिये बैल बेठी थी। सरकार के लिए बड़ी पायों की देखभाल एक बड़ी वित्तीय समस्या होगी, किन्तु यदि स्वामीय समुदाय इस काम को उठा लेते हैं, तो यह भार बट जाता है। किन्तु यह प्रश्न संशोधन स्तर पर संघटन का है। गोरक्ष कानून को प्रभावी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की स्थानीय स्तर पर इस काम को सक्रिय करने में अपना समय और शक्ति समानी होगी।

नयी तालीम से सम्बन्धित प्रपत्र ४ का विवरण

१- प्रकाशन का स्थान :	मेवापुरी, बाराणसी, उत्तर प्रदेश
२- प्रकाशन अवधि :	द्विमासिक
३- मूद्रक का नाम :	श्री पन्तवीर मिश्र
राष्ट्रीयता :	भारतीय
पता :	बिदाई मृदण स्थली, पदेनी, बाराणसी
४- प्रकाशक :	श्री लक्ष्मण कुमार कर्ण
राष्ट्रीयता :	भारतीय
पता :	लखनऊ, उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति मेवापुरी बाराणसी
५- सम्पादक :	सर्वे श्री से० मधुसूदनम्, डारिका सिंह, कजुमाई पटेल काशीबाबू त्रिवेदी ज्योतिबाई देसाई, देवेन्द्र कप्त तिवारी पद्मचन्द्र
राष्ट्रीयता :	भारतीय
पता :	उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति मेवापुरी (बाराणसी)
६- पत्रिका के मालिक का नाम व पता :	संजिव भारद्वाज नयी तालीम समिति, मेवापान, बघा, बहागपुर

मैं मधुसूदन कर्ण यह घोषित करता हूँ कि मेरी जानकारी और विवेक से अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

उ० अक्षयकुमार कर्ण
प्रकाशक

अक्षय कुमार

नयी तालीम पत्रिका का कार्यालय मेवापान से मेवापुरी स्थानान्तरित हुआ। इस कारण प्रत्यक्ष बिगत दो अकों में पत्रिका का नाम और अकों का प्रथम अक्षर उपा है। सुधी पाठक हमारे इस मूल के लिए क्षमा करें और बिगत अकों में दिमागत संशोधन करने पढ़ें:-

मंगलकामना

कोई कृति खो नहीं सकती
 और न कोई मंगल व्यर्थ जायगा,
 मले ही आशायें छोन ही जायें
 और शक्तियाँ लबाव दे दें
 हे बीरात्मन ! तुम्हारे उत्तराधिकारी अवश्य जनमेंगे
 और कोई सत्कर्म निष्फल न होगा ।
 यद्यपि मले और ज्ञानवान कम मिलेंगे
 किन्तु जीवन को बागदोर उन्हीं के हाथों होंगी ।
 पद भीड़ सही बातें देर से समझती है,
 तो मो चिन्ता न करी, मार्ग दर्शन करते जाओ ।
 तुम्हारा साथ वे देंगे जो दूरदर्शी हैं,
 तुम्हारे साथ शक्तियों का स्वामी है ।
 भागीरथों की वर्षा हीमी तुम पर
 ओ महात्मन् तुम्हारा सर्वमंगलमय हो ।

—स्वाप्नी खिलेकाभक

नयी तालीम



सम्मेलन विशेषांक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति
 अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन
 शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का प्रारूप १९७६
 गांधी कुटी का संदेश
 राष्ट्रीय प्रगतिशील शिक्षा : एक प्रयोग



अखिल भारत नयी तालीम समिति

वर्ष २७
 अग्र-सं. ६
 जन-सुधार

अंक
 ५, ६

प्रधान सम्पादक — श्री वे० अरणावतम्

सम्पादक मंडल — श्री द्वारका सिंह

श्री यजुसाई पटेल

श्री बाबू बाबू शिवेदी

श्री ज्योतिबाई पटेल

सम्पादक — डा० देवेन्द्रदास त्रिवारी

सह सम्पादक — श्री चन्द्रभूषण

सम्पादकीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति	पृष्ठ १
भारत मातृभूमि तारीख सम्मेलन का १९७६ का विवरण	३
भारत मातृभूमि तारीख सम्मेलन १९७६ सर्वसम्मति निवेदन	५
सम्मेलन में पारित राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव	७
अन्तर्राष्ट्रीय मातृभूमि	श्री वे० अरणावतम् ८
शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का प्राकट्य [१९७६]	११
हमें स्कूल को क्यों सम्मिलित करना है	डा० देवेन्द्रदास त्रिवारी २१
गांधी कुटी का संक्षेप	२५
राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा एक प्रयोग	डा० रामचन्द्र सिंह २७
वर्तमान समय में शैक्षिक विचारों का महत्व	श्री० कमला शिवेदी ३१
सब जगह क्यों से सुबारी शिक्षा	श्रीमती जमा सिन्हा ३३
अनौपचारिक शिक्षा कुछ विचार किन्तु	श्री प्रभाकर सिंह ३७
शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का प्राकट्य	डा० भास्कर आदिशेखरे ४१
भारत की राह पर श्री प्रभाकर जी	श्री देवेन्द्रकुमार ४७

अग्रज — गुलार् ७६

तारीख तारीख का आधिकारिक रूप से एक एक का रूप से है ।

तारीख तारीख ई-कार्ड पर है इसका यही अर्थ है प्रारम्भ होता है ।

यह व्यवहार ने लिए सुधा पाठक रूप में अपनी शास्त्र सत्यता अर्थ में लिखे ।

तारीख तारीख में अर्थ विचारों का आधिकारिक रूप से है ।

नयी तालीम

सम्पादकीय

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज शिक्षकों के लिए

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

सबसे पहले ध्यान देने के लिये राष्ट्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। १९६६ में प्रथम बार केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषणा की थी। उस समय शिक्षा का विषय राज्य के अन्तर्गत था, अतः कुछ राज्य सरकारों ने भी शिक्षा नीति विषयक कुछ चिन्तन किया था। यतः कुछ वर्षों में देश में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुए हैं जिससे लोकजीवन के विकास और ज्ञान की कक्षा सिखी गयी है और सिखी जा रही है। किन्तु यदि ध्यान किसी से भी यह प्रश्न दिया जाय कि शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं जिन पर विशेषज्ञ और मार्गदर्शकों की आवश्यकता है तो यह पक्का कहेंगे कि विद्यालयों, विश्वविद्यालयों का अद्यावत और व्यवस्थित वातावरण, शिक्षा का योग्यता और स्वाध्याय के सम्बन्ध में होना, अधिभाषकों, शिक्षकों तथा पेशिक एवं अन्य प्रशासकों द्वारा विद्यालय की व्यवस्था, परीक्षा की व्यवस्थाएँ जिन प्रणाली में लोक जीवन में सामान्य जीवन एवं समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उनके सम्बन्ध में राज्य के वर्गकारी से कुछ शिक्षा चाहते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भवनात्मक एक स्वर निराशा का स्वर कहना है। २२ पृष्ठों और २३ अनुबन्धों का यह योजना - पत्र १९६६ से यह धारणा बनती है कि हममें एक सुचना का अभाव है, अल्पज्ञान भावों की कमी है, या जो बड़े कि शरीर जो है किन्तु मानता नहीं है। प्रारूप में विभिन्न व्यवस्थाएँ दफ्ते एक साथ छोड़ दिये गये हैं। बांधी ने हमारे सामने सच शिक्षा का एक रूप प्रस्तुत किया था। यह जीवन और समाज से एक रूप था, स्वाध्याय और स्वाध्याय विचारों के मेल से अनुपातित था। प्रश्न यहाँ के बार-बार हम बात पर बल देने पर भी कि बुनियादी शिक्षा ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्वरूप है, प्रस्तुत प्रारूप से पक्का कोई सार्वत्रिक उत्तर नहीं है। पहले पृष्ठ पर

अथवा बांधी को का नाम, उनके विचारों तथा प्रयोगों का उत्प्रेषण किया गया है किन्तु बुनियादी शिक्षा या नयी तालीम शब्द का प्रयोग सब नहीं किया गया है, जिन बुनियादी शिक्षा को उस महापुरुष ने देश के लिए अपनी सर्वोत्तम देन कहा था।

प्रारूप की प्रस्तावना की प्राप्ति अत्यन्त उलझी हुई, अस्पष्ट और लंबी का नाम ही प्रतीत होती है।

प्राथमिक शिक्षा के सर्वे में उल्लास कार्य का उत्प्रेषण किया गया है। किन्तु उल्लास कार्य शिक्षा का माध्यम बनेगा, इसकी संरचना स्पष्ट नहीं की गयी है। वेयर-हूड स्कूल की योजना का उल्लेख किया गया है जो एक विदेशी संस्था है और यह है कि संस्थागत शिक्षा-विद सचिवों द्वारा प्रवर्धित करने के लिए उल्लास उत्प्रेषण कर रहे हैं। जो बाधा अपने देश के लोगों के लिए चाहते हैं उस भाषा में और अपनी स्थिति के सम्बन्ध में कथारित इन लोगों ने कुछ कहना सीखा ही नहीं है।

प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में कोई भी बात नहीं कही गयी है क्योंकि जो बातें कही गयी हैं वे सब प्रौढ़ शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में १९७७ में घोषित हो चुकी हैं। इसमें पुनः सर्वेच्छक समस्याओं की परीक्षा देने की बात कही गयी है जिसका सरकारी वर्गों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और यह स्थिति जर्मनी की जा रही है कि सर्वेच्छक समस्याओं की परीक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था में क्या हो जाय।

सांख्यिक शिक्षा में व्यवसायीकरण पर बल दिया गया है और यह ध्वनि दबावा बहुत अन्धे अन्धे ने सरकार द्वारा दोहराया जा रहा है। उच्च शिक्षा के सर्वे में अनुच्छेद ५२ में 'अनिवार्य' बात कही गयी है और यह यह कि सामान्य स्तर के काम करने के लिए जिनके लिए विश्वविद्यालय की दिवरो को आवश्यकता नहीं है, उन्हें डिग्री से अलग कर दिया जाय। यदि ऐसा हो सका और योग्यता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न कि कागजी प्रमाणों के आधार

पर, तो निश्चित है कि शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठेगा और परीक्षाओं में स्थाय प्रत्याहार भी दूर होगा ।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीन वर्षों के शिक्षा कोर्स की संस्तुति की गयी है । उच्च सच्चरित्रता के कर्मचारियों से, जिन्होंने इस प्राकृतिक रचना में महत्वपूर्ण योगदान किया होगा वह पूछा जाना चाहिए कि क्या के निम्न-विद्यालय, शिक्षा के निम्न उपकरण प्रथम दो वर्षों का समुचित उपयोग कर रहे हैं । दो से तीन वर्षों की अवधि बढ़ाने का औचित्य क्या है ? क्या अवधि बढ़ा देने से स्तर ऊपर उठेगा ? क्या उन स्नातकों का स्तर ऊपर उठा है जो किसी के लिए तीन वर्षों का समय व्यतीत करते हैं । फिर एक गरीब देश के लिए कड़ा सीट करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक वर्ष की अवधि बढ़ाना गरीबी को उच्च शिक्षा से वंचित करता है । कदाचित् सफल उच्च शिक्षा के विशेषज्ञ ऐसा चाहते भी हैं कि गरीब उच्च शिक्षा से वंचित रह जाय । देश के लोगों को इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तना चाहिए और अपनी भाषाएँ एक वर्ष की अवधि वृद्धि के विरोध में उठानी चाहिए । जब दूधरे देश शिक्षा पर बहुत कुछ धन से ऊपर कर अवधि को कम करने के उपाय पर विचार कर रहे हैं, हम तीन वर्षों बढ़ाने के उपाय सोच रहे हैं । आशा है सतत समीक्षण जो देश के करोड़ों गरीबों के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस बिन्दु पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

शिक्षा के क्षेत्र के बारे में स्पष्ट बात नहीं कही गयी है । जो मोच १० + २ योजना के संकेत, समर्थक और संप्रदाय से उठे हैं वही सुधारों से गौणमूल धर्मों में यह अंकित कर दिया है कि स्कूली शिक्षा १२ वर्षों की रहेगी । वास्तव में १० + २ की योजना केवल वर्षों का प्रश्न नहीं था । वह विदेशी प्रयोगों से मुक्त एक योजना थी जिसमें १० वर्षों की स्कूली योजना को आधार माना गया था । किन्तु गरीब देश में कदाचित् ३ वर्षों या ८ वर्षों की भी समग्र स्तर: पूर्ण शिक्षा की बात सोचनी होगी । इसीलिए गांधीजी ने ७ या ८ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा या प्रतिपादन किया या और प्रमाण सभी की इस बात पर कल दे

वह वे किन्तु १० + २ योजना से भोग इतना प्रतिबद्ध है कि सीमित क्षेत्रों की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गयी ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राकृतिक में तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा तथा चिकित्सीय शिक्षा की बात भी नहीं कही है जो समीचीन हैं । कारोबार शिक्षा, शिक्षा का माध्यम धातुभाषा हो, शिक्षाया गुरु आदि विषयों पर वर्षों की गयी हैं । देश की भाषाओं के विज्ञान पर विशेष धन दिया गया । हिन्दी की सम्पूर्ण भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है ।

परीक्षा सुधार के सम्बन्ध में सरकार बाँटें नहीं गयी हैं । बाह्य सूत्रावन पर भय है और आंतरिक मूल्यांकन पर भी । सब से हास्यास्पद बात यह है कि राष्ट्रीय नीति में क्रेडिट सिस्टम की संस्तुति की गयी है । राष्ट्रीय नीति का सक्षम नीति की घोषणा करना है, न कि कैसे वास्तविक बनाया जाय, कैसे उससे संप्रति किया जाय, ऐसे विषयों में हस्तक्षेप करना है । पुष्ट रूप पर क्रेडिट सिस्टम का अन्वेष हमारी चिन्तन परम्परा का अंग है । व्यवस्था में सन्धीकरण बिना क्रेडिट सिस्टम के भी माना जा सकता है । यह कदाचित् नीति का प्राकृतिक आधार करने वालों की बात नहीं है ।

अध्यापकों तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कार्त्तविक आदर्शवाद की ओर अग्रसर बातें कही गयी हैं । शिक्षण प्रशिक्षण की जान जो अवलोक समझा है, उनके समाधान का कोई विश्वस्त नहीं है ।

आर्थिक व्यवस्था में स्थानीय सहयोग की बात कही गयी है । किन्तु सरकार शिक्षा की हर बात का नियंत्रण अपने हाथ में रखेगी जो स्थानीय सहयोग के विरुद्ध होगा ? शिक्षा में विनै-प्रीकरण के विज्ञान की पूर्ण उपेक्षा की गयी है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्राकृतिक निष्पन्न प्रतीत होता है । इसने विभिन्न प्रकार के सुधारों की बात नहीं है । कई स्थानों पर भाषा अस्पष्ट और उलझी हुई है । फिर भी यह प्राकृतिक एक महत्वपूर्ण अवलोक है और आदर्श है देश के चिन्तनशील व्यक्ति, शिक्षा के व्यवसायिक सफल अपनी प्रतिनिधता समय से प्रस्तुत करेंगे और शिक्षा की नयी दिशा देने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे ।

अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन

मेरठपुर, पसकता का दिनांक २०, २८, २९ मई

१९७६ का विवरण

अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन का आयोजन रत बार पवित्रय बंगाल नदी तालीम समिति ने कमलता के मुक्त नगर के तत्प्राग १५ घोन दूरस्थ बाँधी सङ्ग्रहालय मेरठपुर मे किया था। सम्मेलन का हाव वम सराहति के अनुसूचन आचरण' तक हे सजाया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन प्रयाग मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने २७ मई १९७६ को पूर्वाह्न ११ बजे किया।

सम्मेलन की अध्यक्षता अखिल भारत नदी तालीम समिति के अध्यक्ष श्री अश्वनाथलम्बी ने किया। उद्घाटन सम्वी प्रयाग मन्त्री के प्रतिष्ठित अतिथि बंशाल के राज्यपाल श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, मुख्य न्यायाधीश श्री एच० पी० गिल तथा केन्द्रीय शिक्षा नदी डा० प्रकाश चन्द गुप्तर ने सम्बोधित किया।

प्रधान मन्त्री तथा सम्मेलन मे आए अन्य विशिष्ट महानुमात्री, अतिथि तथा प्रतिनिधियों का स्वागत श्री के० अश्वनाथलम्बी अध्यक्ष, अखिल भारत नदी तालीम समिति तथा श्री जलील राव चौधरी, अध्यक्ष, पवित्रय बंगाल, नदी तालीम समिति ने किया। श्री नन्दा भार्द वटेल मन्त्री अखिल भारत नदी तालीम समिति ने समिति का कार्य विवरण प्रस्तुत किया और बताया कि यह सम्मेलन श्री इय कठिन गर्मी के समय बुनाने का उद्देश्य भारत की प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार करने का तथा चर्चा के परिणाम स्वरूप अतिमत्त संपाद करने का है।

माननीय मोरार जी भार्द ने अपने उद्घाटन भाषण मे कहा कि गांधी जी ने सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली के विनाशकारी परिवर्तनों की ओर ह्वाता ध्यान दिलाया था और छात्रों को तत्कालीन प्रचलित छात्राओं की जहाँ अराष्ट्रीय शिक्षा दी जाती थी, छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालयों में

प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया। मुनिपादी शिक्षा का आविर्भाव इसी घृष्टमृति में हुआ। प्रवेश यह की गयी थी कि इसके सर्व सामान्य का विकास सम्भव हो सकेगा और वह अपनी कठिनाईयों से मुक्त हो सकेगा। नदी तालीम का मुख्याधार आत्मविश्वास, निर्भयता, उत्प्रेक्षादिता था, जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली मे नहीं था। श्री देसाई ने कहा कि मुनिपादी के परिणाम स्वरूप मुक्त और विश्व के सम्बन्ध विरक्त गया है। इसके द्वारा पुनर्जाएँ और लोक तो विन जायी है किन्तु जीवन शिक्षा नहीं। गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थी मे निर्भयता, स्वतन्त्रता के भाव विकसित हो तथा उसे जीवन की तालीम मिले। दुर्भाग्य से गांधी जी को कल्पना की नदी तालीम अथवा मुनिपादी शिक्षा नहीं अपनायी गयी। काय शिक्षा के हर क्षेत्र में परिवर्तन की अत्यन्त आवश्यकता दिखायी देती है।

प्रयाग मन्त्री ने कहा कि शिक्षा के द्वारा केवल बुनानाओं को नहीं, विवेक की आवश्यकता थी और उसके साथ ही छात्रावक कार्य और सामुदायिक सेवा कार्य आदिना था। उन्हो ने कहा कि गांधी जी ने हाव से कार्य करने पर और विचार कर और कार्य के सामान्य से शिक्षा की बात कही थी। अच्छी शिक्षा से समता, भेदभाव और अनुप्य के प्रति अनुप्य के वर्तमान की भावना विकसित होनी चाहिए।

श्री देसाई ने पाठ्यक्रम मे अधिकाधिक विषयों को उपादेयता का सर्वोत्तम व्यवस्था और यह भवेता की कि नवीन शिक्षा रखने के लिए शिक्षकों को तैयार किया जाना चाहिए। उन्हो ने एवं सामान्य ध तथा राबनोदितो

गुरमोर कपील की कि वे शिक्षा को राजनीति से अलग और उसे दमवत स्वाधी से भी मुक्त रख। शिक्षा

लेने ऐसे स्थान के निर्माण में हाथ बटा सकें, जिसमें
स्थानता हो और जिसमें निजी तथा सामाजिक जीवन के
बुनियादी सिद्धांतों के रूप में वास्तव - निर्भरता तथा धर्म-
निष्ठा को स्थान दिया गया हो ।

इसके स्तर पर विषयवस्तु को नया रूप देने तथा
इसकी व्यवस्था को साकार देने के काम के लिये गांधीजी
द्वारा प्रतिपादित यह उद्देश्य स्पष्टतया रहना चाहिए कि
शिक्षा जिसी-न जिसी प्रकार के चारीयिक और उन्नत
कर्म में ली जावे तथा शिक्षार्थी के वातावरण के साथ
कर्म में रूप में सम्मिलित हो । इस नीति के मसविदे की,
विशेष रूप से इसकी प्रस्तावना, उद्देश्य, विषयवस्तु और
कार्य के बारे में अधिक विविधता और अस्पष्टि-
कर्म की संकरता है जिससे उसमें उपयुक्त विचार प्रवि-
र्तित हो सके नदीकि हमारी जनता के एक बड़े भाग
की, जो प्रचलित व्यवस्था में बड़े महत्वपूर्ण और बुनियादी
परिवर्तन का हस्तगत रहा है, ऊँची अपेक्षाएँ पूरी नहीं हो
रही हैं । इस दृष्टि से सम्पूर्ण मसविदे के फोरम को रचना
तथा सुधारित करना होगा, जिससे यह अधिक प्रभावी
हो सके ।

विशेषकर है, उसके बारे में उत्पन्न सकारण धुर करने
के लिए निम्न स्पष्टताएँ जरूरी हैं—

१. प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया
शिक्षा के सभी स्तर पर, जिसमें उच्च शिक्षा भी है,
एक साथ प्रारम्भ होगी और काम करेगी ।

२. शिक्षा के सभी स्तर पर पाठ्य पुस्तकें, सामाजिक, सांस्क-
रिक, उच्च शिक्षा की या तकनीकी और व्यवसायिक
शिक्षा की, समाज की दृष्टि से सामान्य उत्पादन
काम और सामुदायिक सेवा पाठ्यपुस्तकें का अधिक
की शिक्षा के बराबर, जो विषय, क्षेत्र, प्रकार, मुख्य
रूप मादि की दृष्टि से मिले हैं, बराबर माना
जायगा । इसकी प्रत्येक विषयवस्तु या साथ में पसल
बाना दिया जलान नहीं माना जायगा । यह भी
आवश्यक है कि इसका साथ पूर्ण रूप से एक प्राकृतिक

विषय क्षेत्र जैसा व्यवहार हो । इसे नि-
निश्चित करना जरूरी होगा कि इस
को कम से-कम जिसना समय दिया जाए
भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह स्तर ज्ञान
की शिक्षा में बढ़ता जायगा ।

३. यद्यपि मसविदे के अन्दर गांधीजी के
हैं, किन्तु प्राथमिक स्कूल व्यवस्था में
वास्तव में प्रयोग नहीं किया गया है । इसका
सुधार आया और पूरी व्यवस्था को ही तत्काल
नाम दिया जाय । सभी सामाजिक के सामाजिक
की सामाजिक और उच्च शिक्षा पर ही ध्यान
जाय । जब तक सभी सामाजिक सामाजिक
बातों, बुनियादी शिक्षा समस्याओं की प्रस्तावना
अलग बनाए रखना होगा ।

४. वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा के मुद्दे में होने लगे
और इसलिए यह 'टर्मिनल' होगी चाहिए । जिसमें
अनुच्छेद ५२ को लागू करने की दृष्टि से प्रारम्भिक
की चारोंपि बनाने के लिए यह आवश्यक है कि
यह औपचारिक हो या अनौपचारिक यह कानून और
केन्द्र और कम केन्द्रित होगी चाहिए ।

५. चार वर्ष की सामाजिक शिक्षा को इसी मासिक
कर्म है, जिससे यह शिक्षा अधिक सुलभ होगी
है । इस स्तर पर विविधता का रूप, विषयों के रूप
में सम्मिलित होगा, न कि अलग-अलग भागों के रूप
में जैसा कि माना है । सामाजिक रूप से सामाजिक शिक्षा
को अलग-अलग चारोंपि में विभाजित करना
विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक स्कूलों का एक
विस्तृत वास्तविक नहीं है । इसका भी सर्वोत्तम
आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के रूप में
होगी और उसका प्रत्येक स्तर की शिक्षा के लिए
जान मुद्रा कर देने का नहीं होगा । जहाँ यह वास्तव
कि शिक्षा एक छोटी की भांति है, अल्पकालिक
है और जिसमें तथा विषयों के अनुचित रूप में
कर्म करना जरूरी है ।

अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन १९७६

सर्वसम्मत निवेदन

अखिल भारत नयी तालीम समिति की ओर से नयी तालीम कार्यक्रमों तथा इसमें अधिक करने वाले अन्य महानुभावों का एक अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन दिनांक २७, २८, २९ मई १९७६ को बोम्बे महानगर और मुंबई (महाराष्ट्र) में आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य सत्र के वर्तमान अष्ट सत्र में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का, जो मतविषय पैदा किया गया, उसका अन्वेषण करना था। सम्मेलन में सभी तालीम के शिक्षक, विज्ञान-मन्त्री तथा अन्य महानुभावों के अलावा योजना आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद सचिव (एन सी ई आर सी) के अधिकारियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री माननीय श्री मोरारजी देसाई ने किया। अखिल भारत के राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्यपाल के प्रधान व्याख्याता एच. के. देवीय शिक्षामन्त्री श्री वी. ए. सुंदर आदि ने सम्मेलन को संबोधित किया।

सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसविदे की शीर्षी से छात्रों की सभी तथा सभी विचार के प्रस्ताव निम्न सर्व सम्मत निवेदन स्वीकृत किया गया :-

दिनांक २७, २८, २९ मई १९७६ को और मुंबई (महाराष्ट्र) में आयोजित यह अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के मसविदे में सुचित निम्नलिखित आवश्यक मुद्दों के अतिरिक्त देश में प्रचलित शिक्षा पद्धति में पुनर्निर्माण करने के भारत शासन के प्रयासों की वृत्ति करता है :-

- १) समाजोपयोगी उत्कृष्टता कार्य
- २) समान-वैय
- ३) नैतिक शिक्षा
- ४) प्रारम्भिक स्तर को छोड़कर, सभी मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो, उच्च-शिक्षा समेत सभी स्तर पर प्रयोगित भाषा के माध्यम से शिक्षण

५) शिक्षक-व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका

नयी तालीम के कार्य में सगे समस्त एच. के. देवीय १९७७ में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आदि सभी के द्वारा इन आवश्यक मुद्दों की निवारण की गयी है। निम्न स्तरों पर स्तरों से भी अधिक समय के नयी तालीम 'समिति वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की के अनेक परिवर्तन करने की दृष्टि से तथा नयी तालीम का योग्य विवरणितानवीन, उच्चस्तरीय शिक्षण समेत सभी स्तर पर लागू करने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक प्रयत्न करती रही है। नयी तालीम की शिक्षा में निम्न तत्त्वों में शिक्षा की विचारों में जो वास्तव और समाधान है उन्हें पूर्ण रूप में समाहित किया है।

किर भी, क्योंकि शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था विभाजित करने वाली और विविध वर्गीय है तथा स्तरीकरण (स्ट्रैटिफिकेशन) और परकीकरण (परिप्रेक्ष्य) को प्रोत्साहन देनेवाली है, इसलिए केवल इतना पर्याप्त नहीं होता कि सरकार को ये आवश्यक विद्युत स्वीकार है। उसके साथ-साथ सरकार ने नयी तालीम के वर्तमान तथा कार्यक्रम के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, जो सत्य और अविनाश है।

नयी शिक्षा व्यवस्था की मूल्यांकन तभी हो सकेगा, जबकि हम हस्तिकारक प्रवृत्तियों का प्रभावी रूप से निराकरण हो, जिससे क्षेत्र में अधिकतम लोग भी, जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था से सहज हैं, उसका लाभ उठा सकें। इसलिए शिक्षा में योग्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकास किया जाय, जो व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो और जिसमें इस बात पर विशेष ध्यान हो कि इसके द्वारा ही अधिकारहीन ८० प्रतिशत लोगों को भी समझा है। इसके लिए जरूरी यह है कि शरीर, पशुपत्तक और आस्था (हाथ, दिमाग और मस्तिष्क) का एक साथ विकास हो जिससे शिक्षार्थी और शिक्षक

सब सामान्य की मुनम होनी चाहिए और उसे स्वतन्त्र, स्वच्छ और सुख होना चाहिए।

डा० चन्दर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया और शिक्षा के छावनीकरण, प्रौढ़ शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा की चर्चा की। उन्होंने ने पारिपरिक और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति निर्धारण ही चर्चा नहीं है। उसका कार्यान्वयन जल्दा ही महत्वपूर्ण है।

श्री के० अवराज बलू जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हरीपुरा कांग्रेस में बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव को स्वीकृति और उसके परिणामात्मक हिन्दुस्तानी तालीमों के गठन के नयी तालीम समिति के अद्यतन कार्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नयी तालीम में जिया और शांति का समन्वयन अद्वितीय है। नयी तालीम का कम स्कूल तक ही सिमित न रहकर जीवन पर्यन्त चलने वाला कम है। आपने प्रस्तावित व्यक्त किया कि १९७४ तथा १९७६ के 'नयी तालीम सम्मेलनों में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो मुख्य निर्धारित दिए गए थे उनमें से अन्तिम वर्तमान प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित कर दिए गए हैं। आपने इस तथ्य पर जोर दिया कि बोझारी भाषा में बुनियादी शिक्षा की सराहना की विभिन्न प्रकारों से बुनियादी शिक्षा की सहायता कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि एकत्र राज्यों के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने बुनियादी शिक्षा को समर्थन कर पुनः पुनर्जीव पाठ्यक्रम अपना लिया है। वर्तमान प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बुनियादी शिक्षा का बड़ी उल्लेख नहीं है।

आपने धन की प्रतिष्ठा पर बल दिया और छात्रों-

रिज धन तथा शैक्षिक धन के पारिपरिक में भारी अन्तर को दूर करने पर बल दिया। आपने शिक्षा की दुर्गति का उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया कि राजकीय तथा गैर राजकीय सेवाओं में चुनाव योग्यता के आधार पर किए काम। चुनाव के लिए प्रत्येक सेवा के लिए अपनी जाँच प्रणाली होनी चाहिए। शीकरियों के लिए उपायों और प्रमाण - पत्रों की बातें समाप्त की जानी चाहिए, तभी शिक्षा में स्वातंत्र्य आधार दूर हो सकेगा और सेवाओं के लिए अधिक योग्य शक्ति मिल सकेंगे।

प्रथम चारों सत्र अवराज्ज ने बड़े प्रारम्भ हुआ। श्री रामनाथ पारिषात सद ने प्रारम्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

२८ मई को प्रातः के सत्र में प्रस्तावित शिक्षा नीति में प्रारम्भिक विषय पर चर्चा हुई। इस विषय को प्रारम्भ में डा० बादक, मुख्य, शिक्षा अनुमान, योजना आयोग ने किया। इसी सत्र में राज्य नयी तालीम समितियों ने अपने राज्यों में नयी तालीम के कार्य के सम्बन्ध में अपनी आस्था प्रस्तुत किया। अवराज्ज के सत्र का शुभारम्भ डा० जय विजय, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने किया। इस सत्र में शिक्षकों की भूमिका चर्चा का विषय था।

सम्मेलन के सभी सत्र आयोजन रहे। प्रतिनिधियों ने भारी सभा में चर्चा के भाग लिया। सत्र में प्रतिनिधियों ने अविश्व का प्राक्क संधार करने के लिए एक उप सचिव का चयन किया। उप समिति ने २९ मई की प्रातः प्राक्क संधार किया। यह प्राक्क सभी दिन चल रहे थे प्रारम्भ होने वाले सत्र में प्रस्तुत हुआ और सत्रों में सहित स्वीकार किया गया।

प्रारम्भिक तथा माध्यमिक सभी स्थापक प्रशिक्षण संस्थाओं को, चाहे छात्रावासों को बुनियादी स्कूलों में बदलना है। यह पैर-बुनियादी स्कूलों में नयी तालीम के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में परिवर्तित किया जाना चाहिए। बुनियादी शिक्षा की पद्धति तथा जीवन शैली में प्रतिष्ठित अस्थायक वर्तमान अध्यापकों से कहीं अच्छे सिद्ध होंगे।

केवल सामान्य नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि सभी प्रकार की मशीनों के लिए डिग्री के भी नौकरी के सम्बन्ध विच्छेद होने से उच्च शिक्षा अधिक उपयोग बन सकेगी।

बच्चों तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के अधिकारिक सहूने होते जाने के कारण जनता का अधिकारहीन बन उसके बर्बाद रह रहा है। यह बात सभी चिन्ता की है और तात्काल प्रदान की जान करनी है।

पारिपरिक और मौखिक कार्य से होने वाली क्षति को साई है, उसको घटाने के लिए तथा बचपनी के समाज को ध्येय को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को मजदूरी नीति समझनी हो।

६. प्रवर्धित शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्माण में समर्पित स्वयंसेवी संस्थाओं का रोष ध्यान में रखना है। अतः उनको नए प्रयोग करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करने सम्बन्ध बनाना चाहिए और उनको इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि शिक्षा का सत्य नाम शोष के होना है, तो सत्ता संचालन होकर-चाहो के हाथ में न रहकर मुख्यतः से स्वयंसेवी संस्थाओं के हाथ में रहना चाहिए।

१०. शिक्षा केवल राष्ट्रीय नीति तक सीमित रहकर भारत में एक राष्ट्रीय प्रयास बने, इसके लिए अन्य बातों को समान हो यह जरूरी है कि शिक्षा सम्बन्धी निर्णय और शिक्षा संस्थाएँ स्वयंसेवक राजनीति से मुक्त हों।

इस पर तथा सम्बन्धित अन्य विद्वानों पर ध्यान विस्तृत चर्चा को प्रोत्साहन देने के लिए नयी तालीम समिति के सम्पन्न, शिक्षा धारिणियों के एक चर्चित ग्रुप को मनीषित कर सकते हैं।

विभिन्न प्रदेशों की नयी तालीम समितियों को नये विद्वानों पर प्रत्यक्ष बनाने के लिए विचार-विनिर्माण माधे-वित्त करनी चाहिए।

सम्मेलन में पारित राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम

सम्बन्धी प्रस्ताव

नयी तालीम कार्यक्रमों का यह सम्मेलन भारत सरकार के अपने अधिकतम है प्रौढ़ शिक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रारम्भ करने, साथ ही इस कार्य के लिए एक वृद्ध धनराशि स्वीकार कर इसे राष्ट्रीयता कार्य-क्रम बनाने की सहायता करता है। निम्नलिखित बातों के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अनुभवों ने गोपीयो के इस विचार से अपनी एकात्मता सिद्ध की है कि केवल छात्र-रता शिक्षण का न हो प्रारम्भ है और न अन्तः। यह ही केवल शरण निर्भरता और आजीवन शिक्षण को सिद्ध करने की प्रक्रिया का एक साधन, एक भीतर माध्य है।

सम्मेलन यह प्रस्ताव करता है कि सामाजिक शिक्षण के उचित आदमों को प्राप्त करने की समानताओं को विकसित करने की दृष्टि से यह कार्यक्रम एक विद्यालय में व्यापक अवसर द्वारा छात्रों प्रस्तुत करता है और नयी तालीम समिति से एक कार्यकारी बल 'टास्क फोर्स' को रखना करने के लिए अनुरोध करता है। कार्यकारी बल का यह प्रमुख कार्य रहेगा कि यह ही कार्यक्रम में सभी वा सन्ने वाली संस्थाओं से अपना सादात्म्य साधे और प्रौढ़ शिक्षण के कार्यक्रम को एक नयी विद्या देने में उनकी सहायता करे। प्रौढ़ शिक्षण को हमारा पारम्भ के अनुसार

ग्राम समाज ही पाठशाळा बन जाता है। ग्रामीण समाज के मानवीय, सामाजिक एवं आर्थिक स्रोत हो शिक्षण का माध्यम बनेंगे। इसी को ग्राम स्वराज्य नवी तालीम की अवधारणा कहा गया है। यह परिदृश्य न केवल उन लड़के-लड़कियों को जो बीचमे ही अध्ययन छोड़ चुके हैं तथा आर्थिक तथा सामाजिक अवयव परिस्थिति के कारण पाठशाळा में नहीं जा पाते हैं उन्हें अपने शिक्षणिक साधने में सहाय, बल्कि ऐसे श्रमियों को भी, जो जीवन में शिक्षण का अवसर तो चुके हैं और जो शिक्षा के साधन मिलने पर अपनी कुशलता समृद्ध करने में सक्षम हैं, का भी समावेश करने। यह अवधारणा अपने ही विरोधा की। पढ़े की पाठशाळा की बल्बत्ता तथा पाँधी की समन्वित प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा शिक्षा में आत्मनिर्भरता की परिदृश्य के तत्त्व समावेश करती है।

हम मानते हैं कि अब समय आ चुका है जबकि इस अवधारणा को विभिन्न प्रकार के प्रयोग तथा अनुभवों के आधार पर व्यवस्थित रूप दिया जाय। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम विकास की दृष्टि से कार्यरत तावियों को यह चुनौती स्वीकार करने का आवाहन दिया जाय। नवी तालीम के लिए इस रूप में एक नया अव्याज सुल जाता है जिसके द्वारा नवी तालीम में निहित उन मुख्य और तकनीकी का प्रत्येक परिवार तथा समूहों में तक प्रसार किया जा सक्ता है। इस प्रकार के प्रयोगों और अनुभवों में समुचित दस्तावेज 'रेकार्ड' आदि यथोचित दृष्टि से सुरक्षित रखे जाय तथा उनका विश्लेषण भी किया जाय। उन प्रयोगों के आधार पर समुचित साहित्य का निर्माण भी किया जाय। इसके आधार पर समूह राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को एक

नया गुणात्मक मोड़ और गति मिले बिना नहीं रहेगी लोक शिक्षण की सीमा या परिधियों को भी यह प्रकट करेगी क्योंकि जो कुछ हासिल होगा वह शिक्षाविदों के समृद्ध और प्रचुर अनुभवों पर आधारित होगा। सृष्टि की प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम के कार्यक्रमों का समय समय पर मूल्यांकन तथा समालोचना करना चाहिए और इस प्रकार ग्राम स्वराज्य नवी तालीम को अपनी शिक्षा की तकनीकी प्रक्रिया को जलरोधक तथा सतत समृद्ध करते रहना चाहिए।

यह सम्मेलन अपने कार्यक्रमों से अवगत करता है कि वे नये तरंगों को भर्ती करते हुए प्रादेशिक नवी तालीम समितियों को मजबूत करें तथा प्रदेय स्तर पर इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करें। यह भी एक महत्वपूर्ण बात होगी कि नवी तालीम के कार्यक्रमों अपनी बात प्रभावी रूप से प्रतिपादित करें और नवी तालीम की भावना और रूप को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षण को तालीम रूप देते हुए प्रयोग आदि करने की दृष्टि से स्वैच्छिक कार्य से इस अवसर का पूरा उपयोग करें।

समुदाय आलेख शिक्षण जब नवी तालीम की शिक्षा पद्धति को रूप में परिवर्तित होगा वह समय विभिन्न विषय वस्तु तथा पद्धतियों पर आधारित इन प्रयोगों का महत्व हमारे लिये कीमती साबित होगा।

जोशों में सामाजिक पुनर्निर्माण से लिये उपयुक्त ऐसी मनःस्थिति एवं परिस्थिति निर्माण करने की दृष्टि में अपेक्षित चेतना का विकास करते हेतु नवी तालीम के कार्यक्रमों को अपने आचरण में निष्ठापूर्वक तथा समर्पण भाव से इस काम में लग जाने के लिए यह सम्मेलन अनुरोध करता है।



अध्यक्षीय भाषण

श्री वे० अरुणाचलम्

हम नवी राष्ट्रीय समिति के वार्षिक सम्मेलन के लिए ऐसे दिन में एकत्र हुए हैं जिसने राष्ट्रीय शिक्षा के विचार को १९०६ में ही जन्म दिया है। श्री बालगे ने निरुद्ध और अनिवार्य शिक्षा का एक विधेयक साम्राज्यीय विधान परिषद में १९१९ में प्रस्तुत किया। गांधी जी उन दिनों टागोरदाय पार्स पर शिक्षा का प्रयोग कर रहे थे। वे भी होम्स के अनिवार्य शिक्षा के विचार से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ऐसी शिक्षा को मनुष्य नहीं संसार करती थी और जो हमें कर्तव्य सामग्री के योग नहीं बनाती थी, देश पर अनिवार्य रूप से लाद दी जाए।

गांधी जी प्रचलित शिक्षा पद्धति में विश्वास नहीं करते थे। अत्यंत साहसिक निश्चय किया कि टागोरदाय पार्स पर करने अनुभव और प्रयोग द्वारा ऐसी वास्तविक पद्धति विकसित करेंगे जो व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करे। अतः वर्षों के प्रयोग से उन्होंने जो पद्धति विकसित की उसे ही 'बुनियादी शिक्षा' या 'नवी राष्ट्रीय' कहते हैं। गांधी जी के अनुसार उनके द्वारा देश को दिए गए कार्यकर्ता में यह सर्वोत्तम है। नवी राष्ट्रीय 'राष्ट्रीय शिक्षा' का प्रतिरूप है। नवी राष्ट्रीय शिक्षा और ज्ञान को समन्वित करती है। यह समष्टि अद्वितीय (Unique) स्वतंत्र है। विश्वास में विश्वास और ज्ञान अलग-अलग माने जाते हैं और एकता से उत्पन्न होता है यह स्वतंत्र अज्ञान विद्या ज्ञान है। ऐसा माना जाता है कि एक ही पद्धति से कुछ वर्षों में एकल जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान विद्या जाता है। गांधी जी ने प्रारम्भ में बात कर्ष की बुनियादी शिक्षा की बात की। किन्तु १९४४ में आभा था मनुष्य से मुक्त होने के बाद उन्होंने माओदम शिक्षा—जन्म से मृत्यु तक की शिक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि होखाना, जीवन और उनकी विभिन्न प्रविधियों के साथ उत्तम चलने वाला कम है। इस प्रविद्या में कार्य से ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य के लिए कार्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य के जन्म से ज्ञान प्राप्त करने की अन्तिम सत्य है। कार्य

और ज्ञान के विमल से अधिक मनुष्य नागरिक संसार होते हैं।

हरीपुर कांग्रेस में फरवरी १९२८ के द्वितीय सत्राह में श्री सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उसके अनुसार 'बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा' का कार्यक्रम संसार करने तथा उसको विकसित करने की दृष्टि से प्रयोग करने हेतु श्री बाहिर हुनेन तथा श्री मार्क्सवादीय को को अधिकृत किया गया। इस तरह हिन्दुस्तानी तात्त्विक सत्य का जन्म हुआ। यह सत्य सर्व सेवा सब के साथ, सब समय विरोध हो गया, जब समग्र सभी रचनात्मक संस्थाएँ ज्ञान विकास का समन्वित कार्य-क्रम बनाये हेतु सज्जक हो गयी। सर्व सेवा सब ने एक स्वतंत्र संस्था "अखिल भारत नवी राष्ट्रीय समिति" इस कार्य को आगे चलाने हेतु पटित किया। अपने जन्म (Inception) के साथ ही यह विभिन्न प्रौद्योगिकी सत्राहों के साथ अपना कार्य कर रही है।

समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में १९४४ में सेवाराय में तथा १९७७ में नवी दिल्ली में अनेक प्रस्ताव देश में शिक्षा के क्रम को मजबूत करने हेतु पारित हुए। यह प्रस्ताव उपयुक्त संस्थाओं के सम्मुख कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत किए गए।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि इनमें अनेक संस्थानों राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव के प्राप्ति में स्वीकार की गयी हैं और उसमें सम्मिलित की गयी हैं। यह सम्मेलन इस प्राप्ति पर गौरव है। विचार करेगा और अपनी सुविचारित राय प्रस्तुत करेगा।

गांधी जी को बुनियादी शिक्षा स्वतंत्र सार्व में भीति के रूप में स्वीकार हुई थी और यह प्रथम तीन वर्षवर्षों योजनाओं तक चलती रही है। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के अध्ययन हेतु अनेक आयोग गठित हुए थे। मोठारी आयोग ने, जो इस तरह का अन्तिम आयोग था, बुनियादी शिक्षा को सराहना की है। किन्तु हमने सुभाष दिया कि आरम्भिक स्तरों पर शिक्षा को एकात्मता के

लिए इसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाय। ऐसे विद्यार्थियों ने, विभिन्न मूल में जागरिक धर्म के प्रति निरुत्साह था, इस अवसर पर शास्त्र उठाकर सार्व आचारित शिक्षा को पुनस्तक आधारित शिक्षा में परिवर्तित कर दिया। यहाँ तक कि प्रदेशों में जहाँ बुनियादी शिक्षा ने स्थापित पा लिया था, इस अवसर का लाभ उठाकर पुनस्तक शिक्षा को पुनः अपना लिया। संवत् एक या दो राज्यों ने राष्ट्रीय की नीति को बढ़ावा और मुद्रा को समर्थन दिया है। कुछ स्वयं सेवी संस्थाएँ भी हैं जो बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा और तकनीक के प्रयोग कर रही हैं। किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा पत्र जो १९९८ में प्रस्तुत हुआ था, अपने प्रयास के बावजूद प्रचलित पद्धति के भागे नहीं जा सका।

बीप्राय की वर्तमान स्थिति ने, जो राष्ट्रीय की के आर्यों के वादाविवरण हेतु प्रतिबद्ध हैं, नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्राथमिक प्रस्तुत किया है। यह राष्ट्रीय की के शिक्षा नीति के अधिक निष्कर्ष है। किन्तु इस प्राथमिक में भी बुनियादी शिक्षा का उल्लेख न तो आधिकारिक स्तर की शिक्षा पर है, न माध्यमिक और उच्च स्तर पर ही। इसने स्वयंसेवी संस्थाओं का उल्लेख अत्यन्त सामान्य रूप से किया है। शिक्षा तथा विद्या में नवीन प्रयोगों को एकत्रित करने के नाम पर प्रोत्साहन नहीं मिलता। सबसे उच्चान बोधा के लिए वाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जिसका विस्तार से नीचे वर्णन है नवीन विचार धारा में बदलने के लिए सक्षम कर रही है। इसने भी भी प्रयास किया है, जहाँ सम्भव नहीं हो पाया है और न ७० प्रतिशत व्यापारी को सन्तुष्ट हो कर पाया है। शिक्षा प्राप्त करने वाले (drop out and pass out) की समस्या से परीक्षण है। फिर भी वे ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं विकसित कर पा रहे हैं, जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने वाले भारी धारणा के अन्तर्गत शिक्षित कर सके। वर्तमान

प्रस्तावित शिक्षा नीति ने विद्यार्थियों को अपूर्ण छोड़कर शिक्षा के लिए कार्यपरक शिक्षा के सम्बन्ध में सोचा है। विद्यार्थियों को विभिन्न स्तर के लोगों के लिए उपयोगी बनाने की चेष्टा की प्रेरणा लोगों को वास्तविकताओं पर विद्यार्थियों को निम्न शिक्षा पद्धति विकसित करना अधिक उपयोगी है। इस हेतु परीक्षा पत्र की व्यवस्था करनी होगी। राष्ट्रीय बोर्डों को, अब वे कहीं काम कर रहे हो मरवा लेते रहे हैं, शिक्षित किया जाना चाहिए।

ग्रीक शिक्षा नीति, जो न केवल साधारण बनाने हेतु अपितु स्वयंसेवा की भावना विकसित करने हेतु सामाजिक कार्यरत करने की है, राष्ट्रीय की के विचारों के अधिक निष्कर्ष है।

दुर्भाग्य से आज शिक्षा की रोजगार में जोड़ दिया गया है। शिक्षा का कर्तव्य धर्मिक शिक्षा न होकर, औद्योगिक हेतु प्रमाण पत्र और उपाधिका प्राप्त करना हो रहा है। यह प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। शास्त्रीय सेवाओं में चुनाव के लिए कार्य करने का अपना पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए, जिसमें उपाधियों का प्रावधान हो। शैक्षणिक सेवाओं में भी नयी नीति होनी चाहिए। शीक्षणों में उपाधियों की प्रावधान हटा देने से विश्व-विद्यालयों, कॉलेजों में प्रवेश की भीड़ कम होगी, परीक्षाओं के प्रत्यक्ष तरीके समाप्त होंगे और सेवाओं में अधिक योग्य अभ्यर्थी मिल सकेंगे।

इस देश में प्रत्येक व्यक्ति धर्म की प्रतिष्ठा की भाव करता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि धर्म की प्रतिष्ठा कोई नहीं करता है। यहाँ धर्मिक हो, जोध और कलम चलाने वालों से दूर पचकट्टी मिलती है। शिक्षा नीति के धारण ही मजदूरी और आय की नीति भी होनी चाहिए। जब तक प्रमाण पत्र तथा उपाधियों के द्वारा अधिक वेतन प्राप्त होता रहेगा, तब तक धर्म और धर्मिक के विराट पर बल देना सम्भव न होगा। ऐसे प्रमाण-पत्रों और उपाधियों के पीछे ही मल्लो रहेगा। अतएव यह वास्तविक है कि शिक्षा नीति को औद्योगिक, कृषि नीति आदि के साथ जोड़ा जाय, अन्यथा वर्तमान शिक्षा नीति धर्मिक तक ही सीमित रह जायगी।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का प्रारूप [१९७६]

शिक्षा एवं समाज मन्त्रालय भारत सरकार

प्रस्तावना :—

१-१ आदर्श शिक्षा व्यवस्था वह है जो लोगों को सभी दार्शनिक और मानसिक क्षमताओं का ज्ञान कला और उन्हें पूर्णरूप से विकसित करने के योग्य बनाए, और जो उनके सामाजिक और मानवीय मूल्यों को नेतृत्व को विकसित करने में सहायता करे जिससे वे एक चरित्र का विकास कर सकें और समाज के विविध सदस्यों के रूप में बेहतर जिम्मेवारी स्वीकार कर सकें और अपने अधिकारों का निर्वाह कर सकें। मनुष्य में व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन लाकर ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है।

उद्देश्य :—

१-२ शिक्षा का उद्देश्य स्वनिष्ठ भीमवर आधारित व्यक्ति का ऐसा विकास होना चाहिए जो समाज के स्वयं और प्रगति तथा स्वतंत्रता, समता एवं सामाजिक न्याय के आकांक्षित मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इस दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य नैतिक-नैतिक धर्मनिरपेक्ष-वादी तथा समाजवादी मान्यताओं को समर्थन देना है।

शिक्षा को राष्ट्रीय एकता में अपनी सहायिका के प्रति एवं और देश के प्रति में विश्वास की भावना में सहायक होना चाहिए। जीवन में नैतिक तथा नैतिक मूल्यों का समर्थन करने तथा ज्ञान की ओर अग्रसर होने का प्रयास होना चाहिए।

विषय वस्तु :—

१-३ शिक्षा की विषय वस्तु को पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है जिससे शिक्षा की प्रक्रिया, लोगों की समता और अनुभूति, आवश्यकताओं के अनुसार वे कार्य-योग्य हो सकें। शिक्षण की अवस्था को बदलने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीखने वाले की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा में मानवीय की के विचार और प्रयोग उनकी सभी प्रकार के क्षमताओं में अन्य दर्शन की विधि, उनका ज्ञान और क्षमता के सहसम्बन्ध पर ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के रूप के सहयोग की प्राप्ति

होती है तथा उनकी शिक्षा की सामाजिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना भी महत्व रखता है। इस दृष्टि से वे अत्यन्त आवश्यक तथा उपयोगी हैं। समाज सेवा तथा स्वयंसेवक एवं समाजसेवकों को सभी में माया सेना सभी स्तरों पर शिक्षा का अभिप्राय बन होना चाहिए।

मानव निर्भरता और धर्म के प्रति सम्मान का पोषण हो सके, सभी विषयों के परस्पर सम्बन्ध पाठ्यक्रमीय और पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रमों के माध्यम से नैतिक शिक्षा पाठ्य-विषय वस्तु का अंग बननी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी सभी शिक्षकों और पूरी संस्था में होनी चाहिए। पाठ्य विषय वस्तु में महान राष्ट्रीय नेताओं की सोच और जीवनकृत्य तथा स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में समावेश होना चाहिए।

व्यवस्था :—

१-४ वर्तमान भारतीय वास्तविकताओं और आवश्यकताओं के सम्बन्ध में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन होना चाहिए, राष्ट्रीय सहमति के आधार पर निर्धारित स्वतंत्रता, समता और न्याय की बुनियादी संरचनाओं को दृष्टि में रखते शिक्षा व्यवस्था को सभी और विभिन्न परिस्थितियों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, समता के अर्थ में भी कोसला न करते हुए, उत्तमता प्राप्त करने का एक प्रयास होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में हम बात का प्रयास होना चाहिए कि जनता और निहित वर्ग के बीच की खाई कम हो और उनके स्वयं प्राप्ति, होनमानता और दूरान दूर होना चाहिए। पाठ्यक्रम का पठन विषय वस्तु तथा अवधि में लचीला-पन होने से विद्यार्थी अपने समय और अध्ययन की विषय का चुनाव स्वयं कर सकता है और अपनी गति से प्रगति कर सकता है। शिक्षा संस्थाएँ तथा समाज एक दूसरे की सहायता करें तथा अभिव्यक्ति परस्पर सहयोग में रहें। बेहतर ज्ञान और कौशल प्रदान करें और इस प्रकार उनके बेहतर भविष्य की व्यवस्था करें। स्थानीय क्षेत्र के

विकास सम्बन्धी क्रियाकार्यों से स्कूल का पवित्र सम्बन्ध होना चाहिए।

सामूहिक प्राथमिक शिक्षा

सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा :—

२-१ जैसा कि संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में वर्णित है, १४ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों की निम्नस्तरीय शिक्षा प्रदान करने को सर्वोच्च दायित्व देनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा सामान्य होनी चाहिए, न कि विशेषीकृत और विद्याविषय की भाषा तथा अन्य उपयोगी विषयों पर विशेषज्ञतापूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। भाषा ही उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश होना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य और विषय वस्तु —

२-२ प्राथमिक शिक्षा में अक्षर्य और गणित के विभाग पर बल होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की विषय वस्तु का गुणवत्ता में जोड़कर उन परम्पराओं और मान्यताओं की दृष्टि से, जो देश की समन्वित सांस्कृतिक निर्माण करती हैं, प्रत्युत वर्तमान सांस्कृतिकताओं और उनके भविष्य की संरचना की दृष्टि से भी आवश्यक है। इस स्तर पर शिक्षा की विषय वस्तु में भाषा, गणित, इतिहास, आधारभूत प्राथमिक विज्ञान, जो वर्णन और सांस्कृतिक संस्थाओं से विशेष रूप से सम्बन्धित हो, तथा सामाजिक शिक्षा का समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से सोपानेय भाषा के अन्त में माध्यम से समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों का समावेश होना चाहिए जिससे समाज की आवश्यक सामान और सेवाएँ उपलब्ध हो सकें। तथा सम्पूर्ण कृषि और उद्योग सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार शिक्षा कार्योपयोगी होनी और लोगों के जीवन तथा पर्यावरण से भी सम्बन्धित होनी। जिससे वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए जिसके फलस्वरूप आधुनिकता की समता एवं उदार मानवीय दृष्टिकोण प्राप्त होता है। जिसमें सभी जीवन और परिवर्तन की पुनर्जागरण से सम्बन्धित को बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहभागिता देनी।

२-३ प्राथमिक शिक्षा के प्राथमिक वर्षों में सामान्य जीवन के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा सर्वनात्मक आनन्दपूर्ण प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

औपचारिक शिक्षा की भाषा न्यूनतम होनी चाहिए और तीन घंटे प्रति दिन में अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे अपरिवर्तनशील रूप से हुए शैक्षिक वर्ष की निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल का सत्र निर्दिष्ट होना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा के लिए सुविधाएँ

२-४ जहाँ यह आवश्यक है कि १-१४ आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षाओं में औपचारिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाए, वही ग्राम जाउट तथा ऐसे १-१४ आयु वर्ग के अधिक आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा विधियों द्वारा भी शिक्षा नहीं मिली है, जहाँ औपचारिक शिक्षा की योजनाएँ बनाया भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उद्देश्य यह है कि आधुनिक १० वर्षों में ऐसे उपलब्ध किए जाने चाहिए जिससे १-१४ आयु वर्ग के सभी बच्चे शिक्षा की परिधि में आ जायें। इससे बच्चों को शिक्षा विशेष पुरा किए हुए स्कूल छोड़ने से रोका जा सकेगा। अव्यय की समस्या का विस्तारपूर्वक अध्ययन होना चाहिए और उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए।

२-५ पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जो विभिन्न प्रकार के स्रोतों वाली और लोकता की परिस्थितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और स्थानीय स्थितियों के आधार पर निर्मित हो।

शैक्षिक उपसम्पत्तियों और आधुनिकीकरण तथा ज्ञान की शक्ति की तुलना की दृष्टि से सुविधाओं विषय वस्तु का एक मूल आधार होना चाहिए। यह मूल आधार न्यूनतम होना चाहिए, आधुनिकता की व्यवस्था औपचारिक तथा औपचारिक प्रयोग के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए, जो अधिक रूप से सहायक तथा भागीदार हो सकती है। सहायक प्रयोग ऐसा परिवर्तनशील नहीं होना

बाहिए जिससे ऐसे ज्ञानार्जन करने वाले, जो वाणिज्य रूप से ही इस प्रश्न से लक्ष्य उठा सकते हैं, बाजित रह जाय।

प्रोत्साहन :—

२-६ गरीब विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रोत्साहन की जैसे मण्डाल भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्टेसनरी और वस्त्र व्यवस्था की जाय। पानिकुओं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

विद्यालय और समाज :—

२-७ पाठ्य पठोस के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विद्यालय को कार्य करना चाहिए। इसके करने में समाज की दीक्षित प्रभाव में पूर्णतः सम्मिलित होना चाहिए। विद्यालय के दीक्षित कार्यक्रमों के लिए समाज में उपलब्ध कारीगरों से लाभ उठाना चाहिए।

संयुक्त स्कूल व्यवस्था :—(COMMON SCHOOL)

२-८ प्राथमिक स्तर से ही संयुक्त स्कूल व्यवस्था के लिए स्थापन किए जाने चाहिए। प्रभाव यह होना चाहिए कि सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो सके। इस बात को विचार कर लेना चाहिए कि सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो और शुद्ध तथा प्रवेश के नियम एकत्र हो।

पाठ्यपठोस के स्कूल की योजना :—

२-९ संयुक्त स्कूल व्यवस्था की मुख्य विशेषता पाठ्यपठोस स्कूल की योजना होगी जिसमें एक क्षेत्र के स्कूलों को पाठ्यपठोस के सभी बच्चों को प्रवेश देना होगा, इसके सामूहिक हितों और सामाजिक समन्वय का सम्बन्ध होगा।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता :—

२-१ ऐसा अनुमान है कि अपने देश की आबादी के २३ करोड़ प्रौढ़ निरक्षर हैं। वे अधिकतर निर्धनतम तथा

सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग के हैं। यदि उन्हें कुछ शिक्षा मिल जाय तो राष्ट्रीय कल्याण में उनका योगदान अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। उनकी यह दशा है कि वे उन मामलों में बंचित रह जाते हैं जो उन्हें विभिन्न विकास योजनाओं में उपलब्ध हैं और वे शोषण और सामाजिक दुर्बलताओं के निवारक बने रहते हैं। राष्ट्र का यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें शिक्षा प्रदान करे। राष्ट्र में प्रौढ़ शिक्षा योजना कार्यक्रम, जो पालू किया गया है, तात्कालिकता तथा अवशिष्टताओं से शिथिल बनता जा रहा है। इस कार्यक्रम का तात्कालिक लक्ष्य ३ वर्ष की अवधि में १० करोड़ लोगों को शिक्षित करना है, जिससे अपने देश में पाठ्यपठोस साधारण रूप से कम समय में वास्तविकता में प्राप्त कर सके।

सकल्पना :—

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का कार्य केवल साधारण और वृद्धि शिक्षा नहीं है, प्रत्युत इसका कार्य शारीरिकी विकास तथा सामाजिक चेतना है, जिससे लोगों की स्वयं कीर्ति व्यवस्था ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति बढ़ जाय।

संयोजित मूलतम-आवश्यकता-कार्यक्रम :—

२-२ प्रौढ़ शिक्षा, संयोजित मूलतम आवश्यकता कार्यक्रम का अभिन्न अंग है जिसका लक्ष्य (अ) गरीबों तक पहुँचना है। (ब) ऐसे सभी कार्यों का समन्वय विकास में रख सभी विभागों में करना है और (ग) उन्हें क्षेत्रीय नियोजन से सम्बद्ध करना है। संयोजित मूलतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी सम्मिलित है, केवल एक मन्त्रालय, विभाग अथवा अधिकरण का प्रसारण मात्र नहीं हो सकता।

अभिव्यक्ति :—

२-३ बहुत बड़ा कार्यक्रम को लागू की अपेक्षा करता है मजदूर इसके त्रिधा पर ध्यान रखने की शक्ति योजना होना। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ध्यान में रखनी है वह यह है कि कार्यक्रम समाप्ति में है। इस कार्यक्रम के लिए अधिकतरों द्वारा लाभों को इस प्रकार निश्चित

करता है कि स्थानीय समाज तथा सरकार के बीच अधिकतम आदान-प्रदान रहे।

३-४ कार्यक्रम विविध स्तरों के माध्यम से समाज जागृत, जिसमें, बड़ा वे सुप्रसन्न हो, ऐतिहासिक प्रतिपत्तियों की प्रशंसा रहेगी। प्रारम्भ से ही सम्भावकों विद्याविधियों, व्यापार, उद्योग, मनुष्यको तथा महिलाओं के स्वतन्त्रता, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विकास-विद्याओं, नगर विकासकों, पञ्चायतों तथा अन्य स्थानीय विकासों का सहयोग सुनिश्चित कर लेना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान :—

३-५ ग्रौड निरक्षरता को वास्तविक समस्या स्वीकार लेनी है। अतएव ग्रामीण समाज तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सम्भावकों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत में सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रयास करना होगा। महिला मजदूरी और युवा स्वतन्त्रता को अधिक बचाने के लिए भी विशेष प्रयास करना होगा। समाज की ओर से भी कुछ सागत का समाना प्राथमिक होगा जिससे यह कार्यक्रम निरन्तर चल सके।

महिला अनुदेशक :—

३-६ कार्यक्रम का उद्देश्य केवल निरक्षरता दूर करना नहीं है, अपितु दूसरी समस्याओं के प्रति चेतना का निर्माण करना है। अतः यह प्राथमिक होगा कि ऐसे कार्यक्रम जैसे परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और भोजन विज्ञानों तथा माताओं की देखभाल आदि विषय भी इस कार्यक्रम में मिश्रित होना चाहिए। इसके लिए यह प्राथमिक होगा कि कार्यक्रम के लिए स्वतन्त्र अनुदेशक स्वायत्तता महिलाएं हों।

कौशल का विकास :—

३-७ निरक्षरता निवारण और चेतना निर्माण के अतिरिक्त ग्रौड शिक्षा में विकास सम्बन्धी विषय वस्तु भी देनी चाहिए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जाय, अपने क्षेत्रों में सुधार का उद्देश्य भी धारण रखना चाहिए। इसके लिए सामाजिक शिक्षा को अग्रणी भी महत्त्व देनी चाहिए।

उत्तर साक्षरता कार्यक्रम :—

३-८ ग्रौड शिक्षा कार्यक्रम में निरन्तर शिक्षा को व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे उन प्रश्नों की, जिन्होंने कार्यक्रम से लाभ उठाया है, साक्षरता में हानि पड़ी रहे और वे अपने आप अपने ज्ञान और कौशल का विकास कर सकें। इस अर्थों में कम दान की पुस्तकें और साहित्य ग्रन्थ-पुस्तकालय, मासमिडिया के द्वारा प्रसारित सामग्री भी सम्मिलित होगी। ग्रामीण-पुस्तकालय-व्यवस्था का विकास, निरन्तर शिक्षा के कार्यक्रम के लिए आवश्यक है।

४ माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक सुधार :—

४-१ यद्यपि सर्वोच्च वरीयता माध्यमिक शिक्षा के विस्तार और ग्रौड शिक्षा के विकास को दी जाती है, तद्वि माध्यमिक शिक्षा की सुधारता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जिससे विद्यालय छोड़ने पर विद्यार्थी मायलिनरता और विद्यालय के साथ जीवन में प्रवेश कर सकें और सामान्य ज्ञान तथा सम्बन्धित कौशल से युक्त होकर काम में लग सकें।

शैक्षिक बोझ का विविधोत्तरण तथा कम करना :—

४-२ माध्यमिक शिक्षा का वादग्रस्त बहुरिध होना चाहिए और अतिरिक्त शैक्षिक भार को हटाकर इसका नैतिक बल बढ़ा देना चाहिए, जिससे सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिल सके। वादग्रस्तता और वादग्रस्त कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा, खेल, सामाजिक-मोदी स्वायत्त कार्यक्रम और समाज सेवा ऐसे होने चाहिए जिसमें विद्यार्थी जीवन में प्राथमिकी भावों से युक्त लोकतांत्रिक, समन्वित और सामाजिकी समाज के लिए ज्ञान और कौशल, कनिष्ठताओं और मायलिनर शक्ति बढ़ सकें।

४-३ शैक्षिक कार्यक्रम के विविधोत्तरण में ग्रामीण ओद्योगिकरण, गण-विद्या, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युत्-उत्पत्ति, ग्रामीण स्वास्थ्य-व्यवस्था और अन्य ग्रामीण विद्याओं का ध्यान हो। ग्रामीण क्षेत्रों

को विविधोक्त विवेचिता अर्थ - व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा की भूमिका :—

४-४ दूरी शिक्षा व्यवस्था को एक श्रुत सलाह समझना चाहिए। इस श्रुत सलाह में केन्द्रीय बड़े माध्यमिक शिक्षा है, क्योंकि इसी के माध्यम से पिछले और जागामी कर्मियों को भी पढ़ाई है। प्राथमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएँ सुदृढ़ हो और माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी परीक्षा मात्र और भीतरी से मुक्त होकर व्यावहारिक जीवन के विरोधी भी क्षेत्र में सीधे भाग ले सकें। माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप व्यापक होना चाहिए। एक ओर यह उन लोगों के लिए भी आने शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहते या नहीं कर सकते, अन्तिम पीढ़ी हो और दूसरी ओर उन क्षेत्रों के लिए जिसके पास प्रतिभा है और उच्च शिक्षा के लिए अभिरुचि है, माध्यमिक शिक्षा उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए सुदृढ़ बुनियाद तैयार करे। इसके अतिरिक्त व्यवस्था इन प्रकार की होनी चाहिए कि विद्यार्थी जब उनकी इच्छा हो एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा सकें।

व्यावसायिक शिक्षा :—

४-५ कुछ भी हो, माध्यमिक शिक्षा की दोनों धाराओं के प्राथमिक में सुदृढ़ व्यावसायिक अर्थ होना चाहिए और उसमें इतनी विविधता होनी चाहिए कि वह सम्पूर्ण दोनों धाराओं की आवश्यकता पूरी कर सके। स्पष्ट अन्तिम पीढ़ी के रूप में माध्यमिक शिक्षा में दूसरी धारा की अवस्था व्यावसायिककरण का मग नहीं अधिक होना होगा। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण में बुनियाद समाजोपयोगी उत्पादक कार्य से कर के और पहले से ही दालनी होती जिससे व्यावहारिक कार्य पर सब प्राथमिक शिक्षाओं के प्राथमिक का अनिवार्य मत होगा।

४-६ व्यावहारिक शिक्षा में विविध ज्ञान और कोशल तथा सम्बन्ध विज्ञान, दृष्टि तथा अन्य प्रवृत्तिकरण कार्य के साथ साथ तकनीकी के प्रवृत्तियों को सम्मिलित होने। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिक में उच्च-

तम सुविधाओं से व्यवस्थित सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि विद्यार्थी रोजगार के योग्य बन सकें या उनमें स्वयं काम में लगने की क्षमता उत्पन्न हो सके।

४-७ व्यावसायीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ करने में पूर्ण सर्वेक्षण करना होना जिससे रोजगार के सम्बन्ध और स्थानीय अवसरों का मोटे तौर से अनुमान अनुमान लगाया जा सके। ऐसे सर्वेक्षण और अनुमान समय-समय पर किए जाने चाहिए, जिससे व्यावसायीकरण के कार्यक्रम का पुनरीक्षण हो सके और समय-समय पर उचित परिवर्तित या संशोधित किया जा सके।

४-८ ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों और अवसरों की व्यवस्था करने का प्रयास होना चाहिए जिससे स्वरूप और समानता प्रवृत्ति रख सके, ऐसा धनोपचारिक विधियों के आधार पर उचित स्थिति में। सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रों की व्यवस्था करके किया जा सकता है। व्यावसायिक क्षेत्रों से निकले हुए लोगों को अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षण होने का व्यवस्था करना चाहिए।

४-९ जो व्यावसायीकरण स्तरीयों की दृष्टि से किया जाय उसमें श्रेष्ठ प्रकार आदि की दूरक मागत का भी ध्यान रखना चाहिये, साथ ही उद्देश्य यह होना चाहिए कि शिक्षा औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य सम्बन्धों से जिसको देश में स्थापना हो रही है, जनता की सम्बन्ध की मायकाओं का बिस्तार हो सके। उस विद्यार्थी को, जो व्यावसायिक क्षेत्रों परा करता है, उचित मान्यता मिलनी चाहिए। व्यावसायीकरण को आगे बढ़ाने में निम्ने प्राथमिक योजनाएं इन क्षेत्रों में भी भागू की जानी चाहिए।

समाज का सहयोग :—

४-११ विद्यालय और समाज दोनों को एक साथ जोड़ना होगा। कार्यक्रमों और क्षेत्रों को सुनिश्चित करने में और काम करने में सुविधाओं की व्यवस्था करना में समाज का सहयोग प्रयत्नता मुक्त होगा। इसके अतिरिक्त इनसे स्वयंसेवा के लिए बहुत से अवसर भी निकलेंगे।

विश्वविद्यालय की व्यवस्था को समाज के विकास और विशेष रूप से पूरी शिक्षा व्यवस्था के विकास की बढ़ती हुई जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को कालेजों से सहयोग करना चाहिए और इस प्रकार कालेजों को पाठ्य प्रशिक्षण के माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों से सहयोग करना चाहिए जिससे अत्यधिक समय पर शिक्षा को स्तर में सुधार आ सके। विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा समाज के पारस्परिक संबंधों का विकास हेतु पण्डित सम्मेलन होना चाहिए। विश्वविद्यालयों के विस्तार, कार्यक्रमों की वही स्थान मिलना चाहिए जो शिक्षण और शोध को मिलता है। अवकाश के दिन अक्षा व्यवस्था को कम कर दिए जाए और उनकी ऐसी पुनर्व्यवस्था की जाए जिसे विद्यार्थी तथा अध्यापक सामील समाज के विकास के कार्यक्रमों में हाथ बटा सकें।

उत्तमता के केन्द्र—

५५ उत्तमता के केन्द्र शिक्षा स्तर विश्व के सर्वोत्तम केन्द्रों से कम न हो, अत्यन्त आवश्यक है। इसे विशिष्ट करने के लिए हर प्रयास किया जायगा।

११ शिक्षा का ढाँचा—

शिक्षा के ढाँचे में मोटे डोरों से तीन स्तर होये प्राथमिक माध्यमिक तथा स्नातक। स्कूली शिक्षा १२ वर्ष की होनी जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक सम्मिलित होये। माध्यमिक शिक्षा के अन्त में एक सार्वजनिक परीक्षा होनी। स्नातक स्तर की शिक्षा ३ वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। विश्वविद्यालय चाहे, छोटा बड़ा दो वर्ष का सामान्य कोर्स और ३ वर्ष का आगम कोर्स रख सकते हैं।

७. तकनीकी शिक्षा—

जनशक्ति की आवश्यकता और तकनीकी शिक्षा—

५६ तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी राष्ट्रीय जनशक्ति सुचना व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसका विकास आगामी ५ वर्ष में हो जाना चाहिए। सामाजिक जीवन विकास की परिवर्तित प्राथमिकताओं को धृष्टि में रखते हुए सभी स्तरों पर एक जीवन सम्बन्धित तक-

नीकी शिक्षा व्यवस्था सशक्ति की जानी चाहिए। तकनीकी शिक्षा का कार्यक्रम अधिक दृढ़ और सार्वक आदार पर निर्भर होना चाहिए।

कोर्सों का पुनर्गठन

७२ तकनीकी शिक्षा की संस्थाएँ विशेषकर प्राचीन-ऐकनिक ऐसी केन्द्र विद्युत् जैसी जहाँ प्राचीन क्षेत्रों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जायगा और उनका समाधान निकाला जायगा। कार्यक्रम ऐसे क्षेत्रों जिसमें शोध के साथ सार्वक सम्बन्ध और सहयोग अनिवार्य रूप से होया। प्रयोगशालाएँ और कार्यशालाएँ सुदृढ़ की जानी चाहिए और प्रतिष्ठान में सुधारमक सुधार होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा कोर्सों का उद्देश्य काम का प्रारम्भ करने का कोर्स प्रदान करना की होना चाहिए। प्रथम, विज्ञान शिक्षण के कोर्स इस प्रकार से पुनर्गठित किए जाने चाहिए, जिससे प्राचीन क्षेत्रों की छोटी और मध्यम स्तरों पर जो तथा ऐसी विशालीय आवश्यकताओं में लिए जैसे आतायात, विद्युत्, स्वास्थ्य, कृषि, सहयोग और सामाजिक विकास, प्रदम्यतात्मक जन शक्ति मिल सके, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक और सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य कोर्स रखे जाने चाहिए जिससे मजठे दूसरे का विकास हो सके।

७३ देश में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में एक अवधि के विविधतापूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो चुका है, इसलिये छात्रों की तकनीकी सतुति आवश्यकता कायम रखने में और शोध तथा विज्ञान के आधार का निर्माण करने में बिदे तकनीकी जनशक्ति का उचित उपयोग करने में अपनी अधिकाधिक मूर्तिरा कक्षा करनी चाहिए।

अनुसन्धान

७४ अनुसन्धान में औद्योगिक और सामाजिक विज्ञान पर बल होगा। संस्थाओं से यह क्षेत्रों की काती है कि वे उच्च स्तरीय शोध इन क्षेत्रों में करेंगे जो राष्ट्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जैसे—ऊर्जा के साधन और सामाजिक विकास के लिए तकनीकी।

८-कृषि शिक्षा

अध्ययन के कोर्स

८.१ सभी प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए और कृषि के विविध कार्यों के माध्यम से अपने आप काम में लगने पर बल देना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालयों को बड़ा तक दे हों, कृषि तथा सम्बन्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रदेश-व्यापी जिम्मेदारी लेना चाहिए। प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में एक सुदृढ़ अनुसंधान केन्द्र, प्रत्येक कृषि सम्प्रदायी पक्षबाधु क्षेत्र में रहना चाहिए, जिससे स्थल विशेष के लिए अनुसंधान किया जा सके। कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि विकास से सम्बन्धित राज्य स्तरीय अध्ययन और सुविधाओं अनुसंधान करना चाहिए। दूसरे विश्वविद्यालयों के कृषि विभागों और संकायों की, जिन के पास आवश्यक समता है, सहायता इस दृष्टि से की जानी चाहिए, जिससे वे कृषि शिक्षा के पूरक कार्यक्रमों का विकास कर सकें।

सम्बन्धन

८.२ कृषि विश्वविद्यालयों और विकास विभागों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे नयी राष्ट्रीय पाठों को स्थानांतरित किया जा सके। कृषि विश्वविद्यालयों को मनोरंजन शिक्षा के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, जिससे पंचाचार कोर्ष भी सम्मिलित होंगे। इससे ग्रामीण तमाम की जातीयदीनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरन्तर शिक्षा की जा सके।

कृषि विज्ञान केन्द्र

८.३ कृषि विश्वविद्यालयों तथा उपयुक्त स्वयं सेवी समितियों को कृषि-विज्ञान केन्द्रों का संयोजन और संयोजन करना चाहिए जिससे ग्रामीण सुबको को सम्बन्ध कीमतों में प्रशिक्षित किया जा सके और वे शोध शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग ले सकें।

६ चिकित्सीय शिक्षा

६.१ चिकित्सीय शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा की जाती है विशेष रूप से स्नातक स्तर पर वह अध्ययन की आवश्यकताओं पर आधारित होती है और बड़का बहुत कम सम्बन्ध देश की वास्तविक समस्या स्वास्थ्य रक्षा की आवश्यकताओं से रहता है। फलस्वरूप अहाँ भूमिक चिकित्सीय पद्धति में विश्व के विकासों के साथ अपनी प्रति अधिकतर ठीक रहो है, वहाँ हमारे वैदिक कालों में निकले हुए स्नातक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से सम्भलने में और उस स्तर की समस्याओं और परिस्थितियों को सुलझाने में असमर्थ रहते हैं। अतः हमारी चिकित्सीय शिक्षा को स्वास्थ्य जन शक्ति की आवश्यकताओं के वास्तविक भूस्थान के आधार पर पुनर्गठित होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्था को इस प्रकार समुल्लू करना चाहिए, जिससे वह समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुकूल हो सके।

६.२ इसके साथ ही वैकी चिकित्सा पद्धति (परंपरागत चिकित्सा पद्धति) जैसे मानुष, युगानी, मित्राण, प्राकृतिक चिकित्सा और होमियोपैथी सभी की उपेक्षा के परभाव अपना स्थाय प्राप्त कर रही है। राष्ट्रीय सरकारों के उचित उपयोग की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वे सब पद्धतियों और आयुर्निक पद्धति की अपनी सीमाएँ और क्षमताएँ समझे। परस्पर एक दूसरे को सहयोग दें और एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करें।

१०-संस्कृति

संस्कृति और शिक्षा का सम्बन्ध

१०.१ परम्परागत और आजकल के सांस्कृतिक तथ्यों का औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्ध सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र प्रवास होना चाहिए। शिक्षा पद्धति ने देश की समृद्ध और विविध विरासत का और उन विरासत सांस्कृतिक संस्करणों का, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से निम्ने हुए समाज में उपलब्ध है, अभी तक पूरा साम नहीं ठठाया है। इन सभी संतापनों का

प्रयोग किया जाना चाहिए और उन्हें सभी स्तरों में शिक्षा के ठाने-बाने में सुना जाना चाहिए।

११-शारीरिक शिक्षा

शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में शारीरिक शिक्षा—

११.१ शारीरिक शिक्षा जिसमें खेल-कूद, रेजि खेल, योग, व्यायाम तथा घाटुस की भावना के बढ़ाने वाले कार्य समावेश सम्मिलित हैं, शिक्षित स्तरों पर शिक्षा का अंग होना चाहिए। बालकों और बालिकाओं को प्रविष्टा शास्त्र करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे अपनी समस्याओं का विकास कर सकें और खेल-कूद की दक्षता में राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्पर्धाओं को प्राप्त कर सकें। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता के लिए व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए।

१२-शिक्षा का माध्यम

माध्यम और भाषा का अध्ययन—

१२.१ सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। आदेशनी स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा होनी चाहिए।

१२.२ स्कूलों में अनेकों विद्यार्थी एक विदेशी भाषा के शिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती हैं जिससे विद्यार्थी अपने अपने मातृ भाषा क्षेत्र में विश्व की विशेष और सम्पूर्णज्ञान प्राप्त कर सकें।

१३. त्रिभाषा सूत्र

१३.१ माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें हिन्दी भाषा प्रदेशों में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन करना होगा। यथासम्भव क्षमता की भारतीय भाषा हिन्दी भाषा क्षेत्र प्रदेशों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का अध्ययन करना होगा।

१४. भाषाओं का विकास

१४.१ भाषा शिक्षण की तकनीकों में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा।

१४.२ भारतीय भाषाओं और साहित्य में विकास के लिए प्रयास जारी रखा जाएगा और सुदृढ़ किया जाएगा।

१४.३ अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाओं को सरलता से किशोर किशोरी रूप में प्रभावित किया है। सरलता के अध्ययन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा।

१४.४ अन्य प्राचीन भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

१४.५ एकलिंग भाषा के रूप में हिन्दी के विकास और प्रचार को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा।

१४.६ स्कूलों के अध्ययन को उचित माध्यम और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

१४.७ विदेशी भाषा में अध्ययन की भी प्रवृत्ति दिया जाएगा।

१५. परीक्षा सुधार

परीक्षाओं का स्थान

१५.१ परीक्षाएँ विशेषकर वे सार्वजनिक परीक्षाएँ आधुनिक अधिक प्रतुनिष्ठ और विपरीतनीय होनी चाहिए? मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थी की प्रभावशीलता समझ सकते हैं और विद्यार्थी अपने सीखने के प्रयासों के परिणाम का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन, शिक्षण और आत्मनिर्भर प्रशिक्षण, जिसमें पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और शिक्षण विधियों को सम्मिलित है, दोनों में ही सुधार लाने के साधन के रूप में कार्य करता है।

१५.२ मूल्यांकन की विधि ऐसी होनी चाहिए, जिसमें छात्रों को हस्तक्षेपित किया जाए और वह अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकें। शिक्षण और पाठ्यक्रम के कार्यक्रमों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में अनुभवों को उचित सम्मिलित किया जा सके।

सार्वजनिक परीक्षाएं

१५.३ सामान्यतः पुरी शिक्षा की अवधि में स्नातक

संस्थाओं के विवेक व्यवहारों को उच्च माना दो चावनी ।

क्षेत्रीय वसन्तुलन—

१७१ कुछ राज्य देश में अन्य भागों की अपेक्षा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। अतः तथा सम्बन्धित राज्यों को सबसे समान स्तर पर आने के लिए सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विशेषरूप से व्यवस्थापन रूप से कम समय में साक्षरता को स्तरीय बनाने के क्षेत्र में विशेष प्रयास करना चाहिए। ऐसा ही देखा गया है कि एक ही राज्य के अर्धवर्ग सभी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार एकत्र नहीं है। इसलिए साक्षरता योजना अथवा शिक्षा के शुद्ध प्रयोग की व्यवस्था को जलवायु और क्षेत्रीय योजना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिससे यह निश्चित हो सके कि सभी क्षेत्रों में शिक्षा के लिए आवश्यक हो जा सके।

विकासों के लिए शिक्षा—

१७७ सभी विकास क्षेत्रों के लिए उच्च शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने हेतु हम प्रयास किया जाएगा। अधिक विकास क्षेत्रों के लिए उचित परिधि में शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जिससे उनकी समस्याओं का पूर्ण विकास हो सके। अन्य क्षेत्रों सामान्य स्तरों में रहे जा सकते हैं और उन्हें आवश्यक अभिरक्षित सुविधाएँ दी जा सकती हैं। विकासों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण तकनीकों का विकास, अनुसंधान तथा अन्य देशों में प्रयुक्त तकनीकों के अध्ययन के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।

१८. अध्यापक—

अध्यापकों की भूमिका—

१८१ सभी स्तरों पर शिक्षा में सुधार लाने के लिए अध्यापकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इसके लिए उन्हें सर्वसाधारण साक्षरता और प्रेरित होना चाहिए और अपने व्यवसाय के प्रति उच्च गौरव या अनुभव करना चाहिए। सभी स्तरों पर अध्यापकों के व्यावसायिक

मुक्तता उन्नत करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। शिक्षकों की अनुसंधान तथा परिवर्तन करने के लिए वैज्ञानिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए।

१८२ अध्यापक तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रति उत्तरोत्तर ज्ञानरूप होना चाहिए जो उन्हें देश के सभी भागों के जीवन और परिवर्तन के निर्माण में सम्मिलित प्राप्त है। इससे लिए राष्ट्रीय सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्य से प्रतिबद्ध होकर वह स्वयं आदर्श मार्गिक बनना चाहिए।

अध्यापकों की शिक्षा—

१८३ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों की शिक्षा का उद्देश्य है उचित परिदृश्य दिए जाने से जिससे शिक्षा में सुधार आने लगे। शिक्षा अपनी उचित सुविधा अथवा कर सके। उच्च शिक्षा में भी अध्यापकों के लिए विद्या विज्ञान सम्बन्धी और व्यावसायिक सुविधाओं सुनिश्चित होनी चाहिए। वेबार्थ प्रतिष्ठान की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पाठ्यक्रमों और सहायक शिक्षण सामग्री का विकास करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों के साथ ही लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

१९ सामाजिक सहयोग—

स्थानीय सामाजिक सहयोग—

१९१ स्थानीय समितियों की स्थापना करके एक क्षेत्र में विद्यालयों को स्थानीय समाज से प्रयुक्त करना चाहिए होगा। ये समितियाँ सचिवों में शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार लावने और अधिक दक्षता के काम करने के लिए विद्यालयों की सहायता करेंगी।

२० स्वैच्छिक सहयोग—

राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित करने के लिए ही कार्य कर बनाया जाएगा उसके समर्थन और सहयोग के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

२१. जल सत्यको की शिक्षा—

सरकार इस बात को जानती है कि धार्मिक और मायावी अलसत्त्वको द्वारा संचालित संस्थाओं ने देश की समुक्त संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सरकार इस बात को भी जानती है कि उन्हें इच्छानुसार कामून सम्मत ऐसी संस्थाओं को स्थापना करने और धराने के लिए अधिक है जिससे सम्बन्धित भारतीय समाज का लक्ष्य पूरा हो सके।

२२. शिक्षा में लागत—

२२१ बेस में शिक्षा पर सरकारी व्यय निरन्तर बढ़ता रहा है और अब प्रति वर्ष २८०० करोड़ लक्ष हो रहे हैं। जो नीति उनपर निर्धारित की गयी है उसे कार्यान्वित करने के लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी होगी फिर भी धन का अभाव करके उपलब्ध संसाधनों, के प्राधिकारों का और प्रभावी उपयोग करके तथा ऐसे कार्यक्रमों 'कार्य के लिए प्रयत्न' जैसे कार्यक्रमों द्वारा लोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास होना चाहिए।

२२२ साम्प्रतिक और उच्च शिक्षा की कक्षाओं में

आवासी के उन वर्गों से जोस सी जा सकती है वो ऐसी घर घर दे सकते हैं जिसका उचित सम्बन्ध शिक्षा की व्यवस्था करने के लक्ष्य से हो।

२२३ स्थानीय समाज से नकद तथा अन्य स्थापक रूप से, वर्तमान की अपेक्षा अधिक समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

२२४ यह ठीक है कि नीति को त्रिविधित करने के सम्पूर्ण प्रयास में धार्मिक सामंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किन्तु उससे भी महत्वपूर्ण स्थान दाइरा से प्रतिबद्ध मानवीय धर्म, मानसिक और नैतिक शक्ति का है। बिना इस मानवीय सहयोग के ऊपर निर्भरित करने के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन और विस्तार तथा गुणात्मक सुधार सम्भव नहीं है।

२३. पुनर्वासन—

२३१ भारत सरकार प्रत्येक ५ वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्वय-व्यय का अन्वयन करेगी और अनुभव के आधार पर संशोधन करेगी।

हमें स्कूल को क्यों समाप्त करना है

अनुवादक—डॉ. देवेन्द्र दत्त तिवारी

(गतों से आये)

किन्तु ये बात ज्ञात प्रस्ताव इस अत्यन्त गहरे तौर पर प्रारम्भ होता है कि कबरेस्टेन, तिवारम तथा उपर्युक्त सभी ने कभी न कभी यह विचार्यत की है कि अमरीकी शिक्षा व्यवस्था पेशेवर शिक्षकों को बहुत कम प्रोत्साहन देती है जिससे अधिकांश शिक्षकों को उत्तम शिक्षा नहीं मिल पाती। इस प्रकार का प्रस्ताव दृष्टान्त अनुदान, जो शिक्षा पर सर्व शिक्षा आयोग, प्रस्तावित करके स्वयं अपने को नगिनीय बना देता है।

यह बात ऐसी है कि किसी लम्बे आदर्श को र्थवासी हुए आध्य से वे ही आस कि वह इसका प्रयोग सभी करे जब तक कि शरीर एक साथ आस दिए जाय। दृष्टान्त अनुदान कर जैसा स्वयं यह समर्थ है उसका दुरुपयोग न केवल पेशेवर शिक्षक करते हैं प्रायुक्त आतिथ्यादी आधिक स्कूलों के समर्थक तथा वे लोग भी करते हैं "जिनके स्वार्थ सामाजिक इष्टि के विभाजित रहते हैं। सर्वोपरि बात यह है कि वैश्विक गहनता, जो शिक्षा व्यवस्था में प्रयुक्त होनी चाहिए, उन लोगों के हाथों में पड़ जाती है, जो ऐसे समाज में रहते हैं जिनमें सामाजिक प्रवृत्ति वारंवारिक ज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि ज्ञान की लक्ष्य पर आधारित है जिससे द्वारा वह प्रवृत्ति वस्तु तथे के प्राप्त की जाती है। शिक्षा की मापिक सहायता के सम्बन्ध में जैसा के विवेचन में शिक्षा व्यवस्थाओं के पक्ष में यह भेदभाव प्रधानता रखता है और इससे शिक्षा के सुधार सम्बन्धी अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण ज्ञान विद्वान्त को अव्यवस्था होती है जिससे ज्ञानार्जन पर प्रत्येक अत्यन्त समीक्षण विषय की सक्रियता तथा आधिक निम्नकारी पर लक्ष दिया जाता है।

समाज को स्कूल से मुक्त करने का सर्व ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के दो पहलुओं की आवश्यकता है। केवल कोशल के अन्तर्गत पर लक्ष देना आवश्यक होता है। उद्योग कम कम ज्ञानार्जन की विभिन्न प्रक्रियाओं पर नहीं होना

चाहिए। किन्तु आवश्यकता यह है कि कोशल के साथ ही लिए भी स्कूल लीक जगह नहीं है और शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से तो वह और भी खराब स्थान है। स्कूल दोनों काम बहुत खराब ढंग से करता है, हमका अधिक कारण यह भी है कि स्कूल दोनों बातों के अन्तर को नहीं समझता। स्कूल कोशल देने में असमर्थ है क्योंकि वह वास्तविकता को सीखाने में विविध रूप से बाधा रहता है। अधिकांश स्कूलों में एक कार्यक्रम, जो किसी एक कोशल के सुधार के लिए होता है, सर्वत्र विभी बुरे सम्बन्ध कार्य से जुड़ा रहता है। इतिहास की गणित की प्रवृत्ति से और वस्तु में उपस्थिति को खेल के मैदान का प्रयोग करने के जोष दिया जाता है।

स्कूल उन परिस्थितियों की व्यवस्था करने में और भी बुरे हैं जो अति कोशलों को मुक्त और व्यवसायिक प्रयोग से सहायक होते हैं। इसके लिए मैं 'उत्तर शिक्षा' (तिवरम एकेडम) का प्रयोग सर्वथा। इस स्थिति का मु य कारण यह है कि स्कूल के कार्य में एक अनिवार्यता है, और वह शिक्षा की व्यवस्था केवल स्कूल के लिए रहती है—अध्यापकों के साथ अवसरहीन रहना और इस तरह के और अधिक संघर्ष को प्रोत्साहन। जैसे कीशल को शिक्षा की वास्तविकता के सम्बन्धों में मुक्त रखना चाहिए इसी प्रकार उत्तर शिक्षा को अनिवार्य उपस्थिति से अलग कर देना चाहिए। सर्वोपरिकता और व्यवसायिक व्यवहार के लिये कोशल ज्ञान तथा शिक्षा को संस्थागत प्रक्रम द्वारा प्रोत्साहन दिया जा सकता है, किन्तु के माध्यम से और विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं।

अतः तो कोशल में अन्तर्गत से सुधार हो जाता है क्योंकि कोशल का सर्व परिचायक तथा अनुमान व्यवहार पर अधिकांश प्राप्त करना है। कोशल के शिक्षण में उन कार्यात्मिक स्थितियों पर निर्भर किया जा सकता है, जिससे कोशल का सम्बन्ध सम्भव है। किन्तु शिक्षा

कार्य में बीजल ने विशेषाधिकार तथा सर्वनात्मक प्रयोग में अभ्यास पर निर्भर नहीं किया था क्षमता। शिक्षा, शिक्षण का परिणाम हो सकती है, यद्यपि यह शिक्षण जिसका परिणाम शिष्या हो, अभ्यास से बुनियादी तौर से शिष्ट होना। शिक्षा अपनी प्रक्रिया के सहयोगियों के परस्पर सम्बन्धों पर निर्भर करती है, उनके पास ऐसी कृती होती है जो समाज के उन समस्याओं से परिचय कराती है, जो वह सुरक्षित रखता है। यह शिक्षा उन सबके उस विशेषतात्मक उद्देश्य पर निर्भर करती है जो स्वकारों का सर्वनात्मक रूप से प्रयोग करते हैं। यह शिक्षा प्रयोग के अवस्थापित प्रयोग के परस्पर पर निर्भर करती है जो साधक और उसके सहयोगियों के लिए ज्ञान के ये द्वार खोलती है।

बीजल का शिक्षण निश्चित परिस्थितियों की व्यवस्था पर निर्भर करता है जिसमें सामाजिक की निश्चित उत्तर देने का उद्देश्य करना पड़ता है। ऐश्वर्य निश्चित या शिष्या का पार्थक्य होता है कि बीजल को देने के भागीदारों की एक दूसरे से मिलने में सह्यता दे जिससे सामाजिक सम्भव हो सके। वह ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक बैठका है जिनके पास अपने ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान उनके पास नहीं है। अधिक से अधिक वह सीखने वाले को अपनी समस्या से निश्चित करने में सहायता देता है क्योंकि समस्या ही दृष्टता में ही उसके अनुकूल और सामाजिक रखने वाला व्यक्ति मिल सकेगा जो सभी की तरह प्रेरित होकर उसी प्रश्न का समाधान उसी समर्थ में सभी समय साथ रहा है।

बीजल शिक्षण और सेवा के भागीदारों की अपेक्षा शिक्षा की दृष्टि से सामाजिक रखने वाले भागीदारों का मिलना प्रारम्भ में अधिक बढित प्रतीत होता है। इसका

एक कारण यह सम्भोदक भाव है जो स्कूल के हमारे मन में जमा रखा है और जिसने हमें आसना पुक्त बना दिया है। बिना किसी भाव्यता के बीजल के आशान प्रदान के परिणाम सराब बीजल के आदान-प्रदान भी भासानों से अनुमानित किए जा सकते हैं और इसीलिए आदान-प्रदान के उन असीमित क्षमताओं से कम खतरनाक है, जिसमें कोम मिलते हैं और ऐसी समस्या से सम्बद्ध होते हैं जो उनके लिए सामाजिक, बौद्धिक तथा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है।

बीजल के अध्यापक वाली ओर से अपने अनुभव से यह आनते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से यह पाया कि शोध ४० घण्टों में अपना प्रारम्भ कर देता है, यदि पहले कुछ समय बिन्दु वह पहुँचाता है। सामाजिक कार्य और सत्य रखते हैं। वह अपने अध्यापकों को गाँव में जाने के लिए कहता है और ऐसे कार्य लोगों के सिधे निर्देश देता है जो ऐसी महत्वपूर्ण समस्याओं से सम्बद्ध रहते हैं जैसे बीजल और सामाजिक के लोगों पर प्रत्यक्ष ध्यान। सामाजिक गाँव के साथ इनके बीच दायी पर विचार करने के सिधे दृष्टता होते हैं। वे यह समझते लगते हैं कि कार्य समापन पर ठहरा रह जाता है, यद्यपि उसकी प्रति समाप्त हो जाती है। अक्सर उनके जीवन के कार्य को उद्घाटित करने सकते हैं और समाज के रूप में उनका समाधान करने में वे अपने को समर्थ पाते हैं। मने बहुधा देखा है कि जिस प्रकार गाँव के विचार करने वाले लोगों की सामाजिक चेतना में विकास होता है और वे अपनी ही क्षमता से सामाजिक बढा उठाने के लिए प्रेरित होते हैं जिसकी क्षमता से वे जैसे-जैसे शिक्षा सीखते हैं, वे-वे-वे वे जीवन की वास्तविकता को भी करतमगत कर केने हैं।

(अमरा)

गांधीकुटी का संदेश

[प्रसिद्ध विचारक इयान इन्विने ग्रामीण विज्ञान केन्द्र वर्षा द्वारा तीसरी दुनिया के गरीबों के लिए सार्वजनिक विषय पर आयोजित गोष्ठी का उद्घाटन श्री गांधी आश्रम प्रतिष्ठान रोबाग्राम वर्षा में किया। यहां उसका सारांश दिया जा रहा है। सं०]

सुबह कुछ समय में मेधाशाम-आयुष्य की इस कुटीर में बैठा था, जहाँ महात्मा गांधी रहते थे। तेजी कुटीर में रहने के पीछे भी उनकी साधना बहल करने की तथा उनका सर्वोत्तम आत्मसाधन करने का भी प्रयत्न किया। इस कुटीर की दो चीजों ने मेरे चित्त पर गहरी छाप छोड़ी। एक तो उसका आध्यात्मिक गहनता और दूसरी है उसमें रहने वाले सुख-सुविधा। इस कुटीर के पीछे गांधी जी का बड़ा दृष्टिकोण है। इस कमरे की कोमलता में करता रहा। गुप्त उसकी सादगी सुनरता ■■■ मर्यादापूर्ण व्यवस्था थी। यह कुटीर अपने प्रति प्रेम और समानता के सिद्धांत की घोषणा करता है।

गांधी कुटीर में साधन प्रकार के स्थान हैं। प्रवेश करते ही एक जगह आधूनात्मिक विचारों और अर्थ के शारीरिक रूप से कुटीर के भीतर जाने के लिए तैयार करेंगे। फिर मध्य स्तर आता है जो एक बड़े परिवार की मर्यादा के लिए पर्याप्त है। आज और वे चार बने हैं बड़ा धर्मनाम मंडा था। तब मेरे साथ चार लोग एक बीमार का सहायक केन्द्र थे। आने की ओर भी उल्टे ही लोगों को बंधन की अवस्था। यह बमरा प्रभाव दे रहा हर कोई का सकता है, मित्र बनता है। तीसरी जगह थी, जहां गांधी जी स्वयं रहते थे। एक बमरा अवस्थिति के लिए और एक दूसरा बमरा बीमार के लिए है। एक मुला बरामदा है और एक अच्छा प्राण स्थान गुरु है। ये सब जगह एक दूसरे के साथ चित्तुक्त नैतिकरूप से सम्बन्ध रखती हैं। उन सबके बीच एक आधुनिक—जीवन और प्रत्यक्ष व्यवस्था है।

यह कुटीर बाह्य सचटी और मिट्टी से बनी है। उसकी बनाने में धर्म ने नदी बलिष्ठ मनुष्य के हाथों ने काम किया है। मैं उसे कुटीर कहता हूँ लेकिन हकीकत में यह है एक घर ही। दिल्ली में कुछ समय पहले जहां बस रहता हुआ, वह मर्यादा तरह-तरह की सार सुविधाओं और अनुकूलताओं की दृष्टि से बामा गया था। पूरा मर्यादा डेट व सिमेंट से बना था, और खाते जैसा था।

तात्पर्य यह है बिचरी के जो सब सार्वजनिक और तरह तरह की चीज हम इकट्ठा करते रहते हैं, वे हमें आधुनिक बन जायावि नहीं के सकेगी। वे सब तो हैं माओ वगु मनुष्य की संभावना। जैसे-जैसे हमारे पास ये सब सुख सुविधाएं बढ़ती जावेंगी। हम ज्यादा से ज्यादा उन पर निर्भर होते जायेंगे। हमारा जीवन बिना-बिना अधिप्राधिक सीमित बनता जायेगा। गांधी कुटीर में हमें जो पर्यावरण दिया है वह सब कुछ सम्भव ही प्रकार का है वह इस प्रकार का है कि मनुष्य उस पर अवलम्बित बन जावे ऐसा कोई कारण नबरे नहीं जाता।

अधिक सुविधा न भगवत् मर्यादा बताता है कि हम अपनी माया में निकल बने हैं। जैसे हमारी जालसा बढती है बस ही उसकी पूर्ति के लिए स्मृति की गंधी चीजों पर हमारी निर्भरता बढ़ती जाती है। यह ता ऐसी बात है जैसे मोषी के बरामदा के लिए हम अवस्थाओं पर निर्भर रह और अपनी बचपन की शिक्षा के लिए स्मृति पर। दुर्भाग्य से अवस्थाओं और मूल शब्दों के आशय और सुविधता दर्शन बाधा बोटें पाए ही नहीं हैं। बसुत अवस्थाओं की बढती हुई

सो अनुदेशको के चुनाव के बाद भारत सरकार के प्रौढ शिक्षा मन्त्रालय के साथ सम्पर्क स्थापित करके अनुदेशको के प्रशिक्षण का कार्यक्रम बना। इस कार्यक्रम के निर्माण में हम निदेशक प्रौढ शिक्षा मन्त्रालय, का ए के जलामुद्दीन तथा डा. कैजनाथ सिंह जी वनस्पति शिक्षा मन्त्रालय का विशेष योगदान मिला। विशेष माहिर भी हम लोगों को मन्त्रालय द्वारा मिला। साथ ही हम इस कार्यक्रम में विशेष भाग्यस्त्रेण श्री करण माई जी डा. बी. डी. शिवाजी अथर्व शिक्षा सभा के सम्पूर्ण-मन्त्र सहित विश्वविद्यालय का रहा। डा. जलामुद्दीन निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना गोरखपुर विश्वविद्यालय, आर एन अग्रवाल परिसर मिर्जापुर फरिदाबाद गोरखपुर डा. कृष्ण मुरारी सात अग्रवाल आध्यात्म श्री आर डी कालेज बैरिया, मदन सिंह प्रौढ शिक्षा सभा बैरिया, श्री जलामुद्दीन त्रिपाठी, सोहरी पाट आजमगढ़ श्री केशवप्रसाद श्री मिश्र प्राचायक मन्वीर डी कालेज कादवारानी तथा शिक्षाविद श्री कलकल विद परबना मीन दवरिया का मिला। श्री तिहासन सिंह, श्री सुरभि नारायण मणि त्रिपाठी, मूलभूत कुलपति सम्पूर्णमन्त्र सहित विश्वविद्यालय पारसगढ़ी, श्री सातजी सिंह महा प्रणयन रेलवे तथा आयुक्त गोरखपुर ने भी उदात्ततापूर्ण समय दिया। श्री विमुक्त प्रसाद त्रिपाठी, जित सविन उत्तर प्रदेश सरकार तथा श्री जलमन्त्र सिंह जिलाधीश गोरखपुर ने तो रात में ८-१० बजे २ जुलाई को पचार कर अनुदेशको के श्री प्रशिक्षण विचार में से सम्मोहित किया। श्री हसनमीन परिचोजना प्रसातक (प्रसार) गङ्ग परियोजना से श्री जङ्ग सत्योन्म मिला। श्री देवकुंदा जी उपनिषाद समाज वस्त्राध ने विशेष समय दिया। प्रशिक्षण सिविल के सवालन श्री जित विहारी चन्द्रजी से

प्रशिक्षण के बाद सात मन्त्रा श्री ध्यवस्था करके १० बेंद्रों का सम्बालन १५ जून से और से १० जून १५ जुलाई से शुरू कर दिया गया। प्रत्येक अनुदेशक को २० प्रौढ शिक्षा बेंद्र दिया गया। इस तरह निर्मित बेंद्रों का नाम इस प्रकार -- १-अग्रवाल श्रीवो क्षेत्र

२-रौंगोर क्षेत्र ३-अरविन्द क्षेत्र, ४ जयप्रभा क्षेत्र, ५-विनोबा क्षेत्र।

यह कार्यक्रम बिना जनसहयोग के सम्भव नहीं—अब प्रत्येक गाँव में प्रौढ शिक्षा समिति, जिसे हम लोक शिक्षण समिति कहते हैं—संघटित हो गयी। इन समितियों के संघोदकों की गोष्ठियों और सिविलों का आयोजन होता रहता है। उनसे द्वारा समिति की विचार और गति मिलती रहती है।

आयोग सिविल, शिक्षित युवकों का सहयोग लिए बिना यह कार्यक्रम जन आन्दोलन नहीं बन सकता। इसके लिये प्रत्येक गाँवों में युवक शान्ति सेना भी स्थापना की गयी है। इसका उद्देश्य तत्त्वों के विकास के साथ उनके द्वारा गाँव का विकास है। इनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है—इस सम्बन्ध में २ दिन का स्कालटिंग का सिलार और ३ दिन का शान्ति सेना का शिबिर १०, ११, १२ सितम्बर को श्री अमरनाथ माई, अधिक भारतीय शान्ति सेना मदन द्वारा होते जा रहा है।

अनुदेशकों के सर्वप्रथम अपने अपने गाँवों का सर्वेक्षण किया और १५ से ३५ आयु के बच्चों में सभी तैयारी करके ३० बेंद्रों की कक्षा प्रारम्भ किया। प्रारम्भ करने के पूर्व कुछ सम्पर्क और आयोजन का भी कार्यक्रम रखा। इधर बेंद्रों के बच्चों और अध्ययन करने से बिना अनुभव मिले। इन बेंद्रों में २० बेंद्र महिलाओं के हैं। उनका भी प्रशिक्षण अनुदेशकों के साथ ही हुआ तथा उनको कुछ विशेष कार्यक्रम दिया गया और एक महिला सर्व-वेष्टिका भी है—उन्होंने इनका समय समय पर विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग के दौरान हो दिया। इनके गाँवों में महिला मण्डल भी बनाने की योजना चल रही है। साथ ही इस क्षेत्र में गाँवों में प्रतिनित स्थितियों को सहज हल करने की जगह है। हम लोग गाँवों में आध्यात्म से सम्पर्क करने एवं ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहते हैं कि जिस दिन जब बहुत बदलन और रूढ़िगत गाँवों आध्यात्म पर आती है—उस दिन गाँवों आध्यात्म के ही सहयोग से २, ३ घंटे का ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें उन्हें आज के स्थितियों तथा घरों की आज की समस्याओं को कार्यक्रम और पारिवारिक सहाय, स्वास्थ, बच्चों का सानन आसन, मनुष्य, परि-

द्वार नियोजन तथा साक्षी इत्यादि पर चर्चा हो। इसका एक पाठ्यक्रम बने और कुछ सपनरूप से चीन के लिए चीन और उन मानो में स्थितों के चीन भी विफलता सम्पन्न और महिला मण्डल का कार्यक्रम चले। इस योजना को हम बिन्दोवा जयन्ती से शुरू करने जा रहे हैं और महिला पर्यवेक्षिका के देख-रेख में यह कार्यक्रम चलेगा।

अनुदेशको - द्वारा केन्द्रों पर कार्यक्रम चरती पर बनाने को जो अनुभव हुए और हो रहे हैं, वे जसाह-बर्द्ध और मार्गदर्शन हैं। लोगों को विभिन्न प्रतिनियार्थक हैं।

स्थानीय स्तर पर अध्ययन सामग्री तैयार करने में हम कार्य शुरू कर दिए हैं। इस सम्बन्ध में हम सासुरता कीमत और व्यावसायिक कीमत को आज की स्थिति में तथा विकास के दिशा बलाओं से जोड़ कर एक सूत्र में बाँधने का प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में 'द्वितीय' की अध्ययन सामग्री से भी हम सहायता लेने जा रहे हैं।

प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता व्यावसायिक बुद्धि तथा साक्षरता है। प्रशिक्षण में भी इस पर बल दिया गया है लेकिन प्रौद्योगिकी साक्षरता ही कार्य पर अभी बल दिया दे रहे हैं। प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को एक औद्योगिक कार्यक्रम के रूप में चिन्तित करना मूल होगी—निष्कर्षता बरीबो में सबसे अधिक है साथ ही इस कार्यक्रम का निर्धन इतिहास एवं आर्थिक दृष्टि में निम्नलिखित रूप में सुलेखित है स्वागत किया है। साक्षरता को पारम्परिक भाषण को रोजगार प्रदान कारणात्मक साक्षरता के रूप में परिचित करने का प्रयास किया जा रहा है। बर्द्धाई अक्षर है, फिर हमें इसके लिए सहयोग भी मिल रहा है।

सम्पन्न और निम्नित मानों में इस कार्यक्रम के प्रति न जसाह है और न इस कोई सहूल दिया जा रहा है। मानों में स्थित बर्द्धों के कुछ प्राप्ताओं और भाषाओं की प्रारम्भ है कि प्रौद्योगिकी पर सच समान के रूप में पर बालको की शिक्षा पर साधन संपादन साम्य होगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की और सामाजिक

दोनों दृष्टिकोणों से सामाजिक पूर्वाहो को तोड़ने, लोगों को प्रतिष्ठा को आधुनिकीकरण के विचारों से जोड़ने के लिए अनिवार्य थी। साथ ही यह मानों के सर्वाधिकार विचार कार्यक्रम है जिससे सभी गैर स्वतन्त्रता हो, कोई वैरोजगार न रहे, और हर प्रकार से मुक्त हो। यह मुक्ति का आन्दोलन है। हर प्रकार का शोषण, जो चीन के आधार पर है सामाजिक, सांख्यिक, अर्थव्यवस्था, भाष्यवादित इत्यादि सभी से मुक्त हो। एक ऐसे सहयोगी समाज का निर्माण हो जिसमें सभी प्रेमपूर्ण वातावरण का सृजन करके एक सच्चे समुदाय का निर्माण कर सके।

आज एक महीने से अधिक कार्यक्रम के संचालन का अनुभव है कि पूरे क्षेत्रों २० केन्द्र ऐसे हैं जिन्हें हम लगभग की सजा दे सके हैं। उसमें हमारा अभिप्राय है जहाँ केन्द्र के लिए पर्याप्त सभी जगह हो तथा सुविधिपूर्ण रूप से सजा और सुव्यवस्थित हो। जहाँ प्रौद्योगिकी २२ अक्षर उपस्थित हो, प्रौद्योगिकी में बेतन्हा का लयी हो और इस कार्य में बर्द्ध सेते हो। साहित्य मूल्य भी शिक्षा में कुछ कार्यक्रम हो। लोक शिक्षण समिति तथा युवक संगठन साक्षि सेवा का निर्माण हो। महिलाओं की चीन कार्यक्रम हो। यदि वे स्थानीय रचनात्मक नमूने इस कार्य के लिए उत्तर रहे हो या भाषा और कुछ क्रियेवरी बहुत कर रहा हो। साक्षरता का भी स्तर ठीक हो।

इसके बाद 'अच्छा' दूसरी स्थिति के २२ हैं, जिनमें उपर दिए कार्यक्रम निर्धारित होकर व्यवस्थित १५ से २० तक है। केन्द्र का स्थान है स्थिति सन्निहित है। सभी विभिन्न कार्यक्रम सचकारणात्मक जो नियम हैं—वे जो अभी चल रहे हैं। २३ ऐसे हैं जहाँ उपस्थिति १५ में नीचे है और ठीक केन्द्र का स्थान भी नहीं बन पाया है।

साथ ही यह भी अनुभव दिया है कि एक दर्जन केन्द्रों पर प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी से आगे है। वे मास्टर का ही कार्य नहीं कर रहे हैं—बल्कि म आनेवाले प्रौद्योगिकी को इकट्ठा करने और सब प्रकार की व्यवस्था

सत्या लोगो के विरुद्ध हुए आरोग्य की और मृत्यु की बढ़ती हुई सत्या उनके बढ़ते हुए अज्ञान की सूचक है। उसी तरह जीवन में ऐसी सब सुख-सुविधाएँ अनेक प्रकार से बढ़ जाती हैं, जो उनमें मानव जीवन में सर्व-सामग्र्य की अभिवृद्धि कम से कम होती जाती है।

आज की परिस्थिति की विवचना यह है कि जिनके पास चित्त की व्याप्ति सुख-सुविधाएँ हैं उन्हीं के लोग व्याप्ति प्रविष्टि माने जाते हैं। जिन समाज में बीमारी को व्याप्ति महत्व दिया जाता हो, और कृत्रिम चेतना के उपयोग करने वालों को धेड़ धिमा जाता हो, क्या उस समाज की अनेकता समाज नहीं कहा जा सकता ?

गांधी जी की कुटीर में बैठे बैठे मैं आज की इस विवचना और विपरीतता के बारे में खेदपूर्ण सोचता रहा। मैं इस मनोबल पर आया हूँ कि आज की हमारी भौतिक समझता हमें मनुष्य जाति के विकास की ओर ले जा रही है ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। अब साबित हो चुका है कि हमारे आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के बड़े बड़े औद्योगिक यन्त्रों की और व्यापक व्याप्ति इजिप्शियन, काबटरी, आध्यात्मिक यन्त्रों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए एक बात बची हो गयी है कि ऐसे सब लोग तब, जब और जीवन की दृष्टि से दृष्टि होते हैं। ऐसे लोगों की ही, गांधी जिसमें रहे थे, उस कुटीर की अपेक्षा अधिक बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। ऐसा बरताना करके वे लोग सुख की एवं अपने जीवन व्यक्तित्व को निर्बल रूप से हथकड़ी कर देते हैं। अंतर्गृहीत, प्राणहीन बनावट की शरण जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने गरीब या लचीलापन और निम्न जिन्य स्थिति की अनुभूति हो जाने की शक्ति को खो देते हैं। अपने जीवन का तब भी गया देते हैं। प्रकृति के साथ उनके व्यवहार बिच्छेद हो जाता है और अपने मानवपुत्रों के साथ की निकटता भी कम हो जाती है।

आज के आधुनिकतावादी को जब ये पूछा जा कि गांधीजी का सिद्धांत यह सरल अधिकतम आपकी समझ में क्यों नहीं आता ? तब वह कहते हैं कि गांधीजी का

रास्ता बड़ा बज्जिन है, सोच उस रास्ते से नहीं जा सकते। परन्तु सही बात यह है कि गांधी जी के सिद्धांत में बीच के बिन्दु दोनों दलानों के लिए स्थान नहीं है और केन्द्रित व्यवस्था के लिए भी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आधुनिकतावादी, व्यवस्थापकों और राजनीतिज्ञों को गांधीजी के सिद्धांतों के प्रति खास आवेग नहीं है। मध्य और अहिंसा का इतना सरल सिद्धांत भी क्यों नहीं समझ में आता ? क्या लोगो की लगता है कि अस्तित्व और हिंसा से उनका काम बनेगा ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। साधारण मनुष्य इतना जटिल समस्या है कि सच्चे साधन ही उसका सच्चे धर्म की प्राप्ति करा सकते हैं। सिर्फ वे लोग इस बीच को समझने में इनकार करते हैं, निजवा इतने कुछ न कुछ स्थापित स्वार्थ होता है। सभी लोग यह बात समझना नहीं चाहते। 'सभी लोगो' में मैं उस समय समावेश समझता हूँ, जिन्हें आज साधारण मनुष्य की अपेक्षा ऐसी सारी सुख सुविधाएँ प्राप्त हैं। वे लोग सब अपना हो गए हैं। उनके उपयोग का प्रकार ऐसा है कि सत्य को समझने की उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए गांधी को समझना, पहचानना मुश्किल है। सादरी और सरलता का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। दुर्भाग्य से उनकी परिस्थिति उ वे सत्य का ध्यान नहीं करने देती। उनका जीवन इतना उत्साह भरा और सज्जन बन गया है कि जिस काल में वे फँसे गये हैं, उससे छूटने की शक्ति उनमें नहीं बची है। भगवान का उपकार मान कि सभी भी बहुधर्म लोगो के पास अपनी दोलन नहीं है कि वे सरलता और सादरी के साथ के लिए सबकुछ छोड़ दें। अपना ये इतने अधिक दरिद्र नहीं है कि समझने की अपनी शक्ति गवा दें।

एक बात बिल्कुल सच हो जानी चाहिए कि आत्म-निर्भर समाज में ही मनुष्य का गौरव रह सकता है। अन्तिम-अन्तिम हम सर्वोपयोगिता की दिशा में जाने बढ़ते जायेंगे जैसे जैसे मानवीय गौरव को हाथ गड़बड़ती रहेगी।

यह कुटीर समाज में साथ सरल होने से भिन्न मानवता का प्रतीक है। यहाँ स्वावलम्बन धर्मपद

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा : एक प्रयोग

बाबा रामचदास सेवाश्रम देवगांव
रामचचन सिंह, संचालक

बाबा रामचदास सेवाश्रम देवगांव, देवरिया में १०० प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्वीकृति गत मार्च १९७६ में मिली और यह कार्यक्रम के अन्तर्गत १ वर्षकेअंदर १०० अनुदेशकों का चुनाव करके प्रशिक्षण दिलाया गया। वर्षदेशकों का प्रशिक्षण गांधी प्रबल कक्षमंड और माधरता निवेशन में हुआ, तथा १०० अनुदेशकों का प्रशिक्षण दो बार में आधम पर ही आधम पद्धति में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्य में हमे कमिश्नरी स्तर के सभी विभागीय अधिकारी, विश्वविद्यालय के अधिकारी एर प्राधेनर, आय मिश्राविद, विभिन्न संस्थाओं तथा सार्वजनिक रचनामंडल कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

इन कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि तथा प्रारम्भिक तैयारी गत जनवरी १९७५ में ही विशेषरूप में श्री अमिल बांडिया, मयूता शिक्षा सचिव भारत सरकार के देवगांव भागमंड के समय में प्रारम्भ हुई। इन कार्यक्रम हेतु सचिव शाखावरणों की कई वर्षों में निर्मित विभिन्न वैश्विक कार्यक्रमों तथा आचार्यकुल, संस्कृत ज्ञानि सेवा द्वारा होता रहा। गोरखपुर मंडल में आचार्यकुल के अनेकों सम्मेलन हुए और १२५ शिक्षा संस्थाओं में आचार्यकुल की गोरखिया हुई। गांधी विचार, विश्वविद्यालय, कातेज तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाई तथा तथा १२५ शिक्षा संस्थाओं में गांधी साहित्य प्रयोगों को स्थापित किया गया। इन कार्यक्रमों में डॉ० हरदारी अमल, सयुक्त शिक्षा निदेशक तथा डॉ० देवेश्वर तिवारी, उप शिक्षा निदेशक की अमूल्य प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला। डॉ० तिवारी तो आचार्यकुल की दलों में मोठियों को सम्मोहित की लिए थे। देवरिया में १९७७ में एक जनश्रुतीय अनीर-कारिक शिक्षा सम्मेलन डॉ० हरदारी अमल की, सयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में किया गया था। इन

सब कार्यक्रमों का केन्द्र बाबा रामचदास सेवाश्रम, देवगांव, देवरिया ही रहा है और आज भी रहता है।

समय रूप से प्रौढ़ शिक्षा कार्य की तैयारी भी करन आई तथा श्री जेम्स साई की प्रेरणा और डॉ० देवेश्वर तिवारी की से मार्गदर्शन में जनवरी १९७५ में प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम शिक्षा विभाग के अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक, उपविद्यालय निरीक्षक, जी, पी ओ, तथा मौरी बाजार और बंहालपुर प्रखण्ड के बीडीओ के सक्रिय सहयोग में १०० गांव का एक क्षेत्र निमा गया। इस क्षेत्र के गांवों से सम्पूर्ण स्थापित हुआ तथा आधम पर इस सम्मेलन में मोठियों तथा शिबिरी का आयोजन हुआ। फिर मौरीबाजार और बंहालपुर ब्लॉक के सचिव विकास अधिकारियों के सक्रिय सहयोग में इन क्षेत्र के १०० गांवों का सर्वेक्षण किया गया।

अप्रैल १९७५ में गांधी जगदी सप्ताह मनाया गया। उसके कार्यक्रमों में समापन समारोह में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ ३ गांवों में जिलाधीन श्री पुनिया, आई ए एन न किया। जिसमें डा० क्षामास तथा जी, श्री मधुसूदन उपाध्याय न इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग दिया तथा श्री बीरेंद्रिहारी पांडेजी, जो आश्रम के मंत्री हैं पूर्ण जिम्मेदारी से गांव समर्पित मानना से आश्रम पर बंहालपुर ब्लॉक क्षेत्रों और आयोजन में लगे।

तो अनुदेशकों की खोज धर्मोपचारिक रूप में प्रारम्भ कर दी गई थी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिलन पर गांव के २ रचनात्मक व्यक्तियों की, जिनकी इन कार्यक्रमों में प्रति आस्था है, एक छोटे मिसन समिति बनायी गयी। इस समिति को सहयोग में अनुदेशकों का चुनाव हुआ। इनमें कुछ गांवों में दलगत भावना से रचनाईर्वादी भी उपस्थित हुई, लेकिन विचारमंडल भी हो गया।

पुरुष नियोजन तथा सादी इत्यादि पर चर्चा हो। इनका एक पाठ्यक्रम बने और कुछ सयनरूप से गाँव से लिए जाय और उन गाँवों में शिक्षकों के बीच भी निरक्षरता उन्मुख और महिला मण्डल का कार्यक्रम चले। इस योजना को हम बिन्दोवा जवाली से शुरू करने जा रहे हैं और महिला एवं वैश्विका के देश रेल में यह कार्यक्रम चलेगा।

अनुदेशनों द्वारा बेजोड़ पर कार्यक्रम परती पर उतारने को जो अनुभव हुए और हो रहे हैं, वे उत्साहपूर्ण और मार्गदर्शी हैं। लोगों की विभिन्न प्रतिनिधार्थ हैं।

स्वाधीन स्तर पर अध्ययन सामग्री तैयार करने में हम कार्य शुरू कर दिए हैं। इस सम्बन्ध में हम साक्षरता योजना और व्यावसायिक कौशल को आज की चुनौतियों से तथा विकास के ज़रिया बलापों से जोड़ कर एक सूत्र में बाँधने का प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में पुनर्स्थापना की अध्ययन सामग्री से भी हम सहमति लेने जा रहे हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य व्यावसायिक साक्षरता तथा साक्षरता है। प्रतिष्ठान में भी इस पर ध्यान दिया गया है लेकिन प्रौढ़ शिक्षक साक्षरता ही कार्य पर अभी धन बचाये दे रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को एक संगठित कार्यक्रम के रूप में प्रतिष्ठान करना शुरू होनी—निरक्षरता गरीबों में सबसे अधिक है साथ ही इस कार्यक्रम का निर्वहन दक्षिण पूर्व आशियन दृष्टि में पिछड़े वर्ग के सुते दिल के स्वागत किया है। साक्षरता की पारस्परिक धारणा की रोज़गार प्रवाह कार्यक्रमिक साक्षरता के रूप में परिचित करने का प्रयास किया जा रहा है। बटिमाई जरूर है कि हमें इससे लिए सहयोग भी मिल रहा है।

सम्पन्न और शिक्षित गाँवों में इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठान उत्साह है और न इस कोई महत्व दिया जा रहा है। गाँवों में शिक्षित नाशियों के कुछ प्राचार्यों और भाचार्यों की धारणा है कि प्रौढ़ शिक्षा पर न धन खर्च करने पर बालकों की शिक्षा पर साधन खर्च करना लाभदायक होगा। प्रौढ़ शिक्षा तकनीकी और सामाजिक

दोनों दृष्टिकोणों में सामाजिक पूर्वाग्रहों को तोड़ने, लोगों को मस्तिष्क की आधुनिकीकरण के विचारों से जोड़ने के लिए अनिवार्य थी। साथ ही यह गाँवों के सर्वांगीण विकास कार्यक्रम है जिससे सभी लोग स्वावलम्बी हो कोई बेरोज़गार न रहे और हर प्रकार से मुक्त हो। यह मुक्ति का आन्दोलन है। हर प्रकार का घोषण, जो गाँव के आधार पर है सामाजिक, आर्थिक, व्यवस्थित, भावनात्मक इत्यादि सभी से मुक्त हो। एक ऐसे बहुमोदी समाज का निर्माण हो जिसमें सभी प्रेमपूर्ण माता-पिता का ध्यान करने एक सच्चे समुदाय का निर्माण कर सके।

आज एक महीने से अधिन कार्यक्रम के संचालन का अनुभव है कि पूरे क्षेत्र में २० सेंटर पुरे हैं जिन्हें हम उत्तम की सलाह दे सके हैं। उत्तम में हमारा समिप्राय है जहाँ सेंटर के लिए पर्याप्त छात्रों जमा हो तथा सुविधिपूर्ण ढंग से सभा और सुव्यवस्थित हो। जहाँ प्रोडों की २५ अक्षर उपस्थिति हो प्रोडों में बैठना आ गयी हो और इस कार्य में रुचि लेते हो। साहित्य धुनन भी दिया है कुछ कार्यक्रम हो। तीन शिक्षण समिति तथा मुख्य सगठन साहित्य रीता का निर्माण हो। महिलाओं के बीच कार्यक्रम हो। गाँव में स्वाधीन रचनात्मक मनुष्य इन कार्य को लिए उभर रहा हो या भागे भाकर कुछ जिम्मेवारी बहुत कर रहा हो। साक्षरता का भी स्तर ठीक हो।

इसके बाद 'अच्छा दूसरी थैली' के २५ हैं, जिन पर उपर दिए कार्यक्रम विनियमित होकर व्यवस्थित १५ से १० तक है। सेंटर का स्थान है लेकिन अनुचित है। सभी विभिन्न कार्यक्रम सगठनात्मक को लिए गए हैं—वे जो अभी बन रहे हैं। २५ ऐसे हैं जहाँ उपस्थिति १५ से नीचे है और ठीक सेंटर का स्थान भी नहीं बन पाया है।

सम ही यह भी अनुभव मिला है कि एक दजन सेंटर पर प्रौढ़, प्रौढ़ शिक्षण के साथ है। वे मास्टर का ही कार्य नहीं कर रहे हैं—बल्कि वे आनेवाले प्रोडों को इकट्ठा करने और सब प्रकार की व्यवस्था

और सहयोग में आते हैं। एवं स्थान पर एक पौध ने बताया कि हमारे लिए तब बड़हन बात बा कि बिग भरी बाकान धूर हो जात बा—हम पुरान कुदारी न पटा टपने बाड़ी जब राति क बजाद से सब जा आसा। ऐसी ही चर्चा कई जगह सुने में मिली।

महिलाओं ने भी २० म १२ नेट्र अच्छ हैं। ५ की स्थिति आमत से भी नीचे हैं। उसको लिए प्रयास हो रहा है।

एक १० गांव का ऐसा क्षम बना है जिसमें स्थानीय नेतृत्व-विशेषरूप से कार्य समान रहा है। उस क्षम में विशेषरूप से कार्य करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसी गांव के कार्यक्रम की बिकसित करने के लिए स्वेच्छा से ही अवकाश प्राप्त किया गया। राज्य बर्ष अधिकारी ने जो इस क्षम के निवासों हे अपने ऊपर

(पृष्ठ २९ का समाप्त)

है। हमें समझ सेना चाहिए कि मनुष्य अनावश्यक चीजों और सामग्री का जितना ज्यादा संग्रह करता जाता है उतनी मात्रा में अपने आवासों की परिस्थिति और आवासीय से आनंद प्राप्त करने की उसकी गति घटती जाती है। इसीलिए गांधी ने बार बार कहा है कि उत्पादकता की हमारा अपनी ज़रूरतों की सीमा में ही रहे। परन्तु उत्पादन का आज का प्रकार ही ऐसा है कि जो किसी प्रकार की सीमा की ही नहीं मानता बल्कि दिन के बाद-रात के उत्पादन रहते रहते में ही पचता मानता है। आज तक यह सब हम सब काम है। परन्तु अब समय का गया है जब मनुष्य को समय सेना चाहिए कि आज बार अधिक बिस्तर होत जाने में यह अपना ही आसना बन रहा है।

समर्पित समय दुनियाँ अब यह बात समझने लगी है कि यदि हमें विनाश करना है तो उपरोक्त मांग ठीक नहीं है। व्यक्ति ने और समाज ने स्वयं के लिए यह स्पष्ट है कि लोग स्वयं अपनी प्राथमिक आवश्यकताएँ ही अपने पास रखें। हमें ऐसी कोई पद्धति ढूँढ निकालनी चाहिए जो इस विचारधारा के प्रतिपक्षीय प्रयत्न की दुनियाँ में मुश्किल बाधन परित्यक्त कर दे। यह मूल्य-व्यवस्था बनाने का दायर सच हो सकेगा। नदित समस्याओं के हल भी यह बाध नहीं आयेगा। इस लिए गैर-आवृत्ति पर आवासीय बनाया गया है।

किया है। साथ ही स्थानीय लोगों के सुझाव में मैं इस अपना क्षम मान लिया है।

जब सहयोग उन गांवों में ज्यादा मिल रहा है जहाँ पिछले वर्ष में निरक्षर लोग हैं। वे निरक्षर साक्षर हैं। वे चाली हैं विचारवान हैं उनके जीवन के मूल्य हैं। उनका जीवन धर्म आधारित है। वे हृदय प्रमाण हैं और उनके हृदय में बल्लभ और स्नेह है। धननिष्ठा व साथ बतव्यपरधनता बिनमला और गान्धिमित्रता है। वे सरल और मोद हैं अतः आभावा के विचार बन पाते हैं। उनके जीवन और जीविका में अनुग्रह है। अतः हमसे सा हृदिक मृजन का स्रोत है। ऐसा आवास होता है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा पीछा से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित किया गया होना। २०

लोगों की यह समझना पड़ना कि समाज में सुनिष्ठा की चीज चीनरी है।

आज तो मोटरधार रखने वाला मनुष्य साक्षरित वाले से अपने की शक्ति मानता है। परन्तु यदि इसका और हम सवसाधारण की दृष्टि में देखें तो ध्यान में लायें कि मोटर की अपेक्षा साक्षरित ही सवसाधारण लोगों का वाहन है इसलिए वस्तुतः सबसे अधिक महत्व साक्षरित को देना चाहिए। पहले एक वाहन व्यवहार कर रहे सब प्रकार का आयोजन भी सामाजिक की केन्द्र में रख कर हाना चाहिए और मोटर की रीज स्मार्त विनया चाहिए। परन्तु आज परिस्थिति इससे ठीक नहीं है अतः तो पूरा आयोजन मोटर की ध्यान में रखकर किया जाता है। साधारण मनुष्य की ज़रूरतों का प्रतिबिम्ब ध्यान नहीं दिया जाता। सारा विचार इन विनय लोगों की ज़रूरतों का धार में ही किया जाता है।

गांधी का यह कुटीर दुनियाँ को बता रहा है कि साधारण मनुष्य का मोरव किश प्रकार रक्षा जाय। सचनी सरलता सेवा और राज्य का पालन कर हम जितना सामान्य प्रयत्न कर सकते हैं इस बात का भी यह गांधी-कुटीर एक प्रतीक है। गांधी-कुटीर का यह संदेश हम आत्मसाद करें। २१

वर्तमान सन्दर्भों में गांधी जी के शैक्षिक चिन्तन का महत्त्व

कु० कमला द्विवेदी

अपितर ओप यही समझते हैं कि गांधी एवं राजनीति से और उनका विचार से कोई सीधा संबंध नहीं था। इसी आम धारणा यह है कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में जो कुछ विचार देना बोधिया उसका आशय नये 'सन्दर्भों' में तो कोई महत्त्व है, न उसकी कोई उपयोगिता ही है। भला यह मन है कि गांधी जी का सम्बन्ध में वे दोनो धारणाएँ अत्यन्त भ्रमपूर्ण हैं। न तो गांधी जी मूलतः राजनीतिज्ञ ही पड़े और न उनका विचार किसी एक ही ओर ध्यान देने लायक है। गांधी जी न मनुष्य जातन को सर्वत्र समग्र दृष्टि से देखा जिसमें राजनीति अथ मम आदि अपना-अपना रूप न रखते हैं। उनका चिन्तन सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों पर आधारित था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि यदि भिक्षु का मित्रता का हृदन पर प्रकाश हो तो वह प्रकाश ही है उस स्वीकार नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि गांधी जी पूर्ण मानवता को अपनी दृष्टि में रखते थे।

गांधी जी न बुनियादी शिक्षा की जो बातें उही यह धारणा देना की हास्यपूर्ण अवधारणाओं से सम्बन्ध की शिक्षा बुनियादी शिक्षा के मित्रता सम्बन्ध में 'साधन' और साधन ही और इसीलिए किसी का यह दावा नहीं होता कि उनको निरन्तर की दृष्टि से देना। बोझारी प्रयोग न सत्य के अन्तर्गत दिया है कि बुनियादी शिक्षा के मित्रता सम्बन्ध है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की (१९७६) की घोषणा भारत सरकार ने की है उसमें भी गांधी जी के शैक्षिक विचारों का अनुसरण करने की बात नहीं कही गई है। इसलिए ऐसा समझना कि गांधी जी के शैक्षिक विचारों की नए सन्दर्भों में आवश्यकता नहीं है नम से नम जातिवार्तिक अन्तर्गत से निम्न नहीं होता। फिर प्रत्यक्ष यह उल्टा है कि नये आम धारणा यह कभी हुई है कि गांधी जी के शैक्षिक विचारों की आज उपयोगिता नहीं है।

इसका कई कारण हैं। एक तो यह कि अर्थों की हस्त में हमारे मन में शिक्षा की या समझना कभी भी यह आज भी सिद्ध नहीं है और आज भी अच्छी शिक्षा उही समझी जाती है जिसमें अच्छी मौखिक शिक्षा के। इसमें अतिरिक्त के सम्पूर्ण विचार का कोई महत्त्व नहीं है। दूसरा कारण यह है कि गांधी जी न जो शिक्षा के मित्रता प्रतिपादित करते उनमें आज के समय पर अधिक बात दिया गया। हाथ द्वारा उत्पादन कार्य को ही शिक्षा का माध्यम माना गया। आज भी शिक्षा का काम उच्च जग के ही लोग प्रदान करते हैं। वे ऐसी शिक्षा की विस्तृत समझते हैं जिसमें शरीर का धर्म या हाथ से महत्त्व रखी गई। तीसरा कारण यह है कि 'योग' का मर्म आज शैक्षिक विचार से प्रदान सुविधा की न प्रति बड़ा आकर्षण है। वे आवश्यकता न होते हुए भी मोटा पर चले का स्थान रखते हैं। अन्तर्गत मर्म में अन्तर्गत की सुविधा प्राप्त है। चार कारणों का उत्पादन पर अपनी जिदगी दूसर करना चाहते हैं चाहे उनसे निम्न ही निम्नकारी प्रत्यक्ष नहीं न हो रहा हो। चौथा कारण यह है कि उच्च वर्ग के हाथ में ही प्रगतन की वापस है और वे गांधी जी के शैक्षिक विचारों की मांग प्रकाश करते हैं और भीतर ही भीतर उनको पूरा करते हैं। यद्यपि वे अपने को शिक्षित समझते हैं किन्तु वास्तु में अधिक बुनियादी देना वे नम लोग होते नम कि उन्होंने अनुचित सुविधाओं प्राप्त कर दूसरों को पीछे रखने की बात कही है। उन्होंने विस्तृत परीक्षा प्रणाली के आधार पर सुस्वास्थ्य आज प्राप्त करने समाज के व्यावहारिक जीवन से अलग को अलग रखा है। उनका दृष्टिकोण मनुष्य और स्थापित होता है। ऐसे लोग अर्थों के समय में भी और आज भी प्रगतन की रीढ़ समझ जाते हैं। गांधी जी के विचारों को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्यतः इही लोग पर है।

हम पुराने और नये सन्दर्भों पर विचार करें। आज गांधी जी के दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता और भी अधिक प्रतीत होती है। आज उद्योग और तकनीकी के विकास के कारण लोग गहरो में सिमटने जा रहे हैं वही जाने भीने रहने विश्राम करने, शिक्षा प्राप्त करने की मुविधा अधिकांश लोगों को नहीं मिल पाती है और बड़े-बड़े नगरों के जीवन को यदि देखा जाए तो वहाँ के वातावरण में भीना इन्सान के लिए भुविबल हो रहा है। बड़े बड़े शल्य-कारखानों के कारण न केवल आर्थिक विपमणा को प्रथम मिल रहा है बल्कि समस्त वातावरण प्रदूषित हो रहा है। समाज और परिवार का विघटन बड़ी तीव्रता से हो रहा है। अगल में रहने वाले व्यक्ति को लोग नहीं पहचानते और न उसके दुष्पर को समझने की प्रयत्नियों को सुर्क्षित हो है। विनाश-पूष बलि-पत्नी, माई बहन के सम्बन्ध आर्थिक शिन्नाओं पर टकरा कर चूर-चूर हो रहे हैं। आज यह स्थिति केवल दूध देश की ही नहीं है प्रभुत विषय में उन सभी समाकषित प्रगतिशील देशों की है जो अपने को सम्मान समझते हैं।

वही नहीं आज विभिन्न राष्ट्रीय विध्वंसक सम्प्राप्तों के निर्माण में लगे हुए हैं। जो करीब है ये भी मजबूत बनाने की तैयारी में हैं। यह कहा जाता है कि विभिन्न राष्ट्रीय ने आज इतने विनाशकारी बम बनाकर रख लिए हैं कि जितने एक बार बम दम बार यह पृथ्वी निष्प्राण की जा सकती है।

य है हमारे मये सन्दर्भ। इनसे बचने के लिए अगर कोई रास्ता है तो वह गांधी जी का बताया हुआ मार्ग ही है। गांधी जी ने जीवन की अथ व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था को विवेचित करने की बात कही थी। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कम करने और आत्म नियंत्रण

बनने की बात भी कही थी। यह सभी की बात है कि बिना आत्म विमर्शता के चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक व्यवस्था राष्ट्रीय स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। उन्होंने जीवन के इस साद्वत लक्ष्य को बुनियादी शिक्षा के द्वारा प्राप्त करने की बात प्रतिपादित की थी। आज नये सन्दर्भों में उनके दार्शनिक सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है। यह वही वह सब है जो सामने लगे हुये विनाश के प्रति उदासीन हो और जिन्हें यह किता नहीं है कि मानवता किसी भी समय सर्व्व के लिए विनाश के मार्ग में विलीन हो सकती है।

जैसा मैंने पहले कहा है कि गांधी जी राजनीतिक बम और मानववादी अधिक थे। वे एक महान शिक्षक थे। यह बम लोगों को माजूम है कि गांधी जी जहाँ एक ओर ऐसे साम्राज्य से लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें प्रेषित नहीं होता था। वही वे हिन्दी सीखने के लिए पहली पुस्तक बम बोधी भी लिख रहे थे। जितने विद्वानों ने इस आवश्यकता को महसूस किया है? परी नहीं गांधी जी ने उस पुस्तक में लिखा है कि बच्चों और शिक्षकों के लिए कम से कम पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाय क्योंकि इससे शिक्षण और शिक्षक दोनों की ही मौलिकता बचती है। शिक्षाक आवश्यकता पड़ने पर सन्देह बच्चों का प्रयोग कर सकते हैं। गांधी जी ने सूचक में एक बहुत बड़े शिक्षा मिशन की जो बात कहो है उसे सम्पादित करना तो अल्प सम्पत्ति भी अनेक सम्पादित मितावास्त्रियों के लिए मुक्तिकारक होगी। उनका यह सूच इतना चान्तिकारी है कि यदि उत्तम अनुसरण किया जाय तो आज के भौतिक पाठ्यक्रम और भौतिक पुस्तकों से मुक्ति अवश्य मिल जायगी और शिक्षा वास्तविक जीवन से सम्बद्ध हो सकेगी।

गत दस वर्षों में हमारी शिक्षा

—श्रीमती उषा चिन्हा

प्रस्ता

आज हमारा देश मन्त्री शैक्षीय परिवर्तनों के साथ माने जा रहा है। एक के परिवर्तनों को भी गति और भी तीव्र होगी। देश को प्रगति पर चलाने का येय शिक्षा को है। भारत में आज राष्ट्रीय और प्राथमिक शिक्षा-पद्धति का अग्रिम महत्व है। शिक्षाविदों के प्रयासों में आज की परिधि का जिस अनुपात में विद्या है वह अनुपात में इस मने आज के प्रति हमारा उत्तर-वापस भी बना है।

देश में शिक्षा के वर्तमान विस्तार को मही अर्थों में मण्डले के लिए हम सम्पूर्ण राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करना होगा, क्योंकि आज देश में बहुत जाने जाये हुए विद्यापिठों की संख्या १० करोड़ है। विद्यार्थी वर्ग के शैक्षणिक शिक्षा की प्रगति पर पहुँची नजर डालने में पता चलता है कि देश में इस क्षेत्र में निश्चित नीति और योजना के अधीन प्रगति की है। यह सर्वथा स्वाभाविक था क्योंकि इन वर्षों में ही देश में शिक्षा आयोग की रिपोर्टों और दीर्घा बाद शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का स्वीकार किए जाने के परिचय की गयी हवा यह पत्ती है। संक्षिप्त मन्त्रालय में पूर्ववत् काम होता रहा किन्तु बादवर्तमान परिवर्तन होने लगा। इन प्रकार ऐसे पुनः का प्राथमिक शिक्षा जिसमें आज पर ही सम्पूर्ण ध्यान दे दिया जाता था, इसके साथ ही शिक्षा को उसका माते बनने से मुक्त करना तथा आर्थिक बन्धनों के बाद भी शिक्षा का सर्वोत्तमता पर पहुँचाने के लिए नयी विचारधाराएँ बननी।

आज की दृष्टि में भी शिक्षा की प्रगति अनुत्ती रहो है आज शिक्षा पर ध्यान देने वाली धनराशि कुल १,६० करोड़ रुपये है जब कि १९५७ में शिक्षा पर केवल २० करोड़ रुपये खर्च होते थे। इस अवधि में विभिन्न स्तरों पर बहुत जोर देकर काम और पढ़ाई में

बमजोर मद्रको की समस्या विशेषतः विचारणीय मानी गयी थी। विद्यार्थी वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में नये मोड़ पर खड़ा था।

शिक्षा आयोग ने इस बात पर और दिया था शिक्षा को सामाजिक एवं आर्थिक संपन्नता का साधन बनाया जाय। उसमें इस बात का भी पता लगाया कि शिक्षा के बारे में एक सुसंगत नीति की आवश्यकता है। मद्रनुसार सद्य में १९६५ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीति को स्वीकार किया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रथमिक क्षेत्रों को महत्व दिया था जहाँ राष्ट्रीय व्यक्तियों के अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता थी।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड ने १९७२ में शिक्षा क्षेत्र में व्यापक स्थिति की समीक्षा की और पाकवी पञ्चवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम की योजना की स्वीकृति दी। इन कार्यक्रमों पर १,९२० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था। इस बात को देखते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड की स्थाई समिति ने जून, १९७२ में एक संगठित कार्यक्रम तैयार किया और प्राथमिकता के अनुसार कुछ निश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड की बैठक नवम्बर १९७४ में देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करने के लिए पुनः हुई। बोर्ड ने यह स्वीकार किया कि देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा को भी अपने व्यय में कटौती करनी होगी। अपने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक नीति की घोषणा की थी।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ—१. एक कार्यक्रम और प्रयासों की भी अब उपबन्धों नहीं हैं, समाप्त करने के लिए सभी योजनाएँ खर्च की गयीं थीं की गयीं और

इस प्रकार बताया गये घन से गये कार्यक्रम शुरू करने या उन वर्तमान कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता बतायी गयी जिन्हें अतिरिक्त धन की जरूरत है।

२—योजनागत और नैसर्गिक योजनागत खर्चों को मिला देने की आवश्यकता बतायी गयी ताकि नैसर्गिक योजनागत खर्चों का कोई भी अर्थ वसूली बाधों के लिए उपलब्ध न हो।

३—शिक्षण कार्यक्रमों में नये व्यक्तियों का अधिक कारगर उपयोग करने पर बल दिया गया।

४—अधिक छात्रों को भर्ती करने या नये कार्यक्रम विकसित करने के लिए उपलब्ध हमारतों का उत्तम उपयोग करना आवश्यक बताया गया।

५—योजना के लिए नियत राशि को बढ़ाने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता बतायी गयी।

नयी नीति—

बोर्ड ने निम्नलिखित सिफारिशों को १. उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा में वर्तमान स्थापनों को सुसिक्त बनाने, उचित मानकों को बनाए रखकर और छात्रों को भर्ती में नियमित करके व्यवस्थित और शिरोधार्य विस्तार को रोका जाए। नये विषयविद्यालयों की स्थापना में सक्षम बनना, और बहुत ही पिछड़े इलाकों को छोड़कर नये मामलों की स्थापना पर रोक लगाने की अपेक्षा है जहाँ पिछड़े और उपरिष्ठ वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण करने के साथ प्रौढशिक्षण छात्रों को भर्ती को नियमित किया जायगा। अनौपचारिक शिक्षा का विस्तार दिया जायगा, ताकि उन सभी को, जो उच्च शिक्षा की इच्छा रखते हैं, इसका लाभ मिले।

२—कुछ विशेष महत्वपूर्ण और प्राथमिकता के कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें प्राथमिक शिक्षा की अविनाश व्यवस्था और उच्च गुणवत्ता माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करना, सभी राज्यों में शिक्षा की १०+२+३ प्रणाली का चलन, युक्त सहायता का विस्तार और १५-२५ आयु वर्ग के बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था शामिल है।

३—अनौपचारिक शिक्षा पर जोर दिया जाने वाला जोर समाप्त कर दिया जाए और इस व्यवस्था के जोर को अनौपचारिक शिक्षा की जाए। बहुप्रतिष्ठ और अमान्य शिक्षा का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर अमान्य और पत्राचार शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए।

४—नैसर्गिक पुनर्निर्माण के सभी कार्यक्रमों में अध्यापकों छात्रों और समाज को पूरी तरह से शामिल करने सभी शिक्षा स्तरों में उदाहरण और निरंतर पठन परिणाम का वातावरण बनाया जाना चाहिए।

पिछले दशक के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विकास—

शिक्षा का समान अवसर—अब सभी राज्यों में ५-११ आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। १२ राज्यों में ११-१४ आयु वर्ग के बच्चों के लड़कों की शिक्षा भी निशुल्क है। १९७४-७५ के अन्त तक ६-११ आयु वर्ग के ६६ प्रतिशत बच्चों के लिए और ११-१४ आयु वर्ग के लिए ३६ प्रतिशत बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। पाचवीं पंचवर्षीय योजना में ६-११ आयु वर्ग के ६७ प्रतिशत और ११-१४ आयु वर्ग के ४७ प्रतिशत बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य है। इसमें १९८२-८४ तक ४५ पर न सर्वसाधारण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सहायता मिलेगी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्युलतम आवश्यकता कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को दूर करने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, लड़कियों एवं समाज के दुर्बल वर्गों को, विशेषकर शिक्षा व्यवस्था में सहभागिता मिलेगी। शिक्षा व्यवस्था में प्रभावित परिवर्तन से जिसमें अनौपचारिक शिक्षा पर जोर दिया जाना और नये विदुषों पर प्रवेश स्थानांतर

जिसे चायया, बहन ऐसे बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं यथवा जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है।

शैक्षणिक—सरकार सामान्य व दुर्बल वर्गों विशेष रूप से अनुपस्थित जाति व इनके बच्चा और सदस्यों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट तरफ़ से प्रोत्साहन और छात्रवृत्तियाँ दे रही है। दोगहुर का जीवन लज्जियों की निवृत्त गीतान, नाथन वैज्ञानिक जाति की भी व्यवस्था की जाती है। सामान्य व सभी वर्गों की शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकारें योग्यता और आय के आधार पर छात्र वृत्तियाँ प्रदान करती हैं। इन्होंने शिक्षा में विज्ञान की शिक्षा की विशेष महत्वा दिया गया है। समुक्त राष्ट्र बाल-बोध की सहायता से विज्ञान के सम्पादन का प्रतिष्ठान की व्यवस्था और विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार करने शुरू की प्रविष्टि की पढ़ाई में सुधार किया गया है।

साइट एक दूसरा क्षेत्र जहाँ गुणात्मक सुधार हो रहा है, शिक्षा प्रौद्योगिकी है। उपग्रह, दूरदर्शन शिक्षा कार्यक्रम साइट के अधीन वैज्ञानिक प्रसारण की गुणात्मक बढ़ावा के लिए छ. राज्यों के ४०० गाँव की पाठशालाओं में दूर दर्शन सेट लगाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली द्वारा आयोजित विज्ञान प्रतिष्ठा योजना और अनुसंधान कार्यक्रमों से भी स्कूलों स्तर पर शिक्षा के सुधार में सहायता मिलती है।

शिक्षा क्षेत्र में निवेदन—

१९४७ में शिक्षा पर होने वाला कुल व्यय २७ करोड़ रुपये था। अब यह बढ़कर १,६०० करोड़ रुपये हो गया। स्कूल स्तर पर सबसे अधिक उत्प्रेषणीय कतर बढ़ा १० तक की छात्राध्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में वापसीय की शामिल करना है। इसका लक्ष्य छात्रों में बुनियादी कुशलता पैदा करना है। उपर्युक्त सामान्य निर स्तर पर पाठ्यक्रमों को व्यवसायिक स्तर प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है।

शिक्षा और राष्ट्रीय विज्ञान को समुक्त करने वाला एक दूसरा कार्यक्रम वस्तु शिक्षा कार्यक्रम है। इससे

दो भाग हैं, एक का सम्बन्ध अतिप्रति, अर्द्ध विभिन्न व्यवस्था जनता के समूह से है और दूसरे का विज्ञानों की उनमें काम से सम्बन्धित शिक्षा देने से है। पहले का उद्देश्य उन लोगों की न्यूनतम शिक्षा देना है जिनको सभी प्रारम्भिक शिक्षा पाने का भी अवसर नहीं मिला। उन्हें लोगों की सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है और इस प्रकार अपनी व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। दूसरे कार्यक्रम में आधीन शालीनों की उनमें कार्य से सम्बन्धित शिक्षा दी जाती है। इसमें १९७२-७४ के अन्त तक तीन लाख विज्ञान लाभ उठा चके थे। १९७४-७५ में १५० लाख विज्ञान अपने कार्य से सम्बन्धित शिक्षा के रहे थे। यह कार्यक्रम १९७० जिलों में चल रहा है। पाचवी योजना के दौरान इसे अग्र्य विज्ञान योजनाओं जैसे बनायी होती, छोटी और सीमान्त तटी, औद्योगिक विकास और परिष्कार नियोजन से जोड़ देने का प्रस्ताव है।

अनीयचारिक शिक्षा—

इसके अतिरिक्त अनौद्योगिक शिक्षा का कार्यक्रम है, जो शिक्षा विकास की मुख्य रणनीति है। इसका लक्ष्य निम्नी काम से बने लोगों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना और शिक्षा प्रदान की विकास कार्यों के साथ जोड़ना है, जिससे वे युवक, विशेष रूप से १५-२५ आयु वर्ग के विद्यार्थी कार्यों में सामर्थ्य रूप से बने रह सकें। प्रारम्भिक पेशेवर और व्यावसायिक कुशलता के विकास की और जो युवकों को रोजगार और अपना काम सुरक्षित के लिए तैयार करेगी, समुचित ध्यान दिया जायगा। देश के सभी जिला मुख्यालयों में नेहरू युवक रेजि की स्थापना की जा रही है, ताकि उन युवकों को, जो छात्र नहीं हैं, राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। १९७४-७५ में ऐसे ११० नेहरू देव घर में कार्य कर रहे थे।

उपयुक्त विवरण पिछले दशक के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्शाता है। नेहरू और पारिष्टिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्प्रेषणीय प्रगति हुई है।

सेलकूट को प्रोत्साहन—

इस क्षेत्र में पिछले दशक की एक उत्सेसनीय विशेषता ग्रामीण और जन जातीय युवकों की भावपूर्ण करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किये जाने की है। नेहरू युवक केन्द्रों के साथ विशेषज्ञों को सम्बद्ध किया गया है, नवो कि ग्रामीण और जन जातीय युवक, अधिकांशतः सेल-कूट की मुख्य धारा से अलग रहे हैं। १९७०-७१ में ग्रामीण सेलकूट प्रतियोगिताओं का एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन कुछ निश्चित क्षेत्रों में देश भर में छण्ड स्तर पर प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। इससे अब तक ९ लाख युवक युवतियों में काम किया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है।

देश के सभी नगरों, विश्वविद्यालयों एवं गाँवों में सेल-कूट सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं। नवे स्टैटिस्मो एम रिश्मिज पुल के निर्माण के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। नीचे स्तरों पर सेल-कूट के विकास का एक मूल्यतम कार्यक्रम तैयार किया गया और राज्यों को कार्यान्वयन के लिए भेजा गया है। आशा है कि गाँवरी योजना के अन्त तक ५० लाख ग्रामीण और जन-जातीय युवक सेल-कूट की गतिविधियों में भाग लेने लगे हैं।

इस क्षेत्र में देश में वृद्धिक्रमिय प्रगति की है। हिंदी और भारतीय भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं के शिक्षण का कार्य न केवल पूर्ण स्तर तक चलाएँ रखा गया है वरन् पिछले १० वर्षों में उसमें तेजी लक्ष्यी भयो है। ब्रिहिरी भाषी राज्यों में २,००० से अधिक अध्यापक हिन्दी शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आभासी वर्षों में उसमें वृद्धोत्तरी की जासगी। विभिन्न राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के १६ प्रतिशत वृद्धोत्तम कर रहे हैं। दो नवे प्रतिशत वेद मणिपुर और मिजोरम में शुरू किये गये हैं। गैर हिन्दी राज्यों के छात्रों को मैट्रिक के बाद हिन्दी की पढाई के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। ११वीं योजना के अन्त तक ऐसी छात्रवृत्तियों की गन्ना २,५०० कर देने का प्रस्ताव है। स्वयंसेवी सभाओं को हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए अनुदान

दिया जाता है। गैर हिन्दी राज्यों में हिन्दी की बधाएँ चबाने के अतिरिक्त हिन्दी टाइम की कक्षाएँ और पुस्तकालय भी चलाये जाते हैं।

सांस्कृतिक मामले—

स्वतन्त्रता के बाद संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए कई कदम उठाये गये हैं। साहित्य अकादमी, सलित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी ने भारत की प्राचीन समृद्ध संस्कृति में धमक नये और समन रूपों में भावने को प्रकट किया है, जिसे पुनर्जागरण 'रेनैसा' का नाम दिया जा सकता है। साहित्य, संगीत, कला, सभी मंचों की स्थापना साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के स्वाति प्राप्त लोगों को पुरस्कार चतुर्ती फिरती प्रब-संनिधों का आयोजन और सांस्कृतिक सभाओं के साथ सदस्यों का आवाग-प्रदान इन अकादमियों का निवमित कार्य है जो प्रतिवर्ष विस्तार और विविधता से प्रगति कर रहा है। इसके अतिरिक्त विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। प्रत्येक वर्ष अनेक दलों का अवान-प्रदान होता है, इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान से विभिन्न देशों की चम्पता एक दूसरे के समीप आती है। इससे विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान में सहायता मिलती है।

शिक्षा और संस्कृति पर अनुरीवी उप-आयोग की स्थापना एक प्रमुख घटना है। इस उपा-आयोग ने विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में परियोजनाओं की मजूरी की है। देश के भीतर स्थैच्छिक सांस्कृतिक सङ्घनों, ध्यानात्मिक, नृत्य, नाटक, थियेटर समूहों की सहायता देना, अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सभा की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालाओं की स्थापना, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में छात्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक प्रतिभा की खोज, छात्रवृत्ति योजनाएँ आदि प्रमुख सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं। इसके अलावा भारतीय नरतत्वीय सर्व-क्षण सङ्गठन, भारतीय अखिलेखापार, राष्ट्रीय समग्रक्षण मेघनल गैलरी भाषा मार्ग और राष्ट्रीय पुस्तकालय, हवाई सम्पन्न विरासत को बनाएँ रखने के लिए निर्-न्तर प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति के सम्पूर्ण क्षेत्र में नवे प्रगति के लिए सभी स्थितियाँ विद्यमान हैं।

अनौपचारिक शिक्षा : कुछ विचार विन्दु

प्रभाकर सिंह

क्षेत्रीय सप्ताहकार (१० जे० को० एच प्र० स०)

हमारे सविधान में केवल दस वर्षों में ही मूलतः (१-१४ वर्ष वर्ष) अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य सिद्धि की गयी है, जो हमारे तारकात्मिक उल्लास तथा आकांक्षा का द्योतक है। द्वितीय समय की औपनिवेशिक शिक्षा-व्यवस्था से छुटकारा पाने की सभी लोगों ने दुहाई दी। फलतः बेमिन्न, मातृमिन्न तथा उच्च शिक्षा की तत्प्राप्त नई संरचनाएँ उभरी। उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक नरेश देव समिति ने प्रस्तावों की बहुत बर्बाद हुई और कुछ कार्य 'योगनाथ' बनी। स्पूल और बनेजों की टीली से बृद्धि हुई। परिणाम हमारे सामने है— 'निरक्षारी की सख्या में बड़ीसरी' 'मन्द गति से प्रतिष्ठित में बृद्धि की बात छोड़िए' और साथ ही शिक्षितों में अधिप्राप्त बेरोजगारी, हस्तशिल्प और बढ़ती हुई बेरोजगारी। एक ओर शिक्षा पर लागत में कमी की बात उठाई जाती है, तो दूसरी ओर परिणामों के सम्बन्ध में अप्रत्यक्षता भ्रमों का प्रचलन है तदुपयोग में कमी का भी शोष लगाया जाता है। बड़ी विचित्रता की परिस्थिति है। १९७० तक शिक्षा ने सम्मन्य में जो भी गुणवत्ता का अनुभव ही रहा था, उसका अन्त दिखाई देने लगा। गीठारी माध्यामिक में शिक्षा सुविधा, स्वरूप और व्यवस्था के विकल्पों के बारे में सोचना, इस परिस्थिति की प्रत्यक्ष प्रतीति है। आज हम ऐतिहासिक सच के ऐसे विन्दु पर का गृहीत हैं, जो हमें कुछ कर मुचरने के लिए चुनौती देता है। ऐसा लगता है कि अब हमारे पास सम्पूर्ण रूप से सोचने के लिए भी समय नहीं। विज्ञातम् वा नहीं विस्मृत न हो जाय, भव्य लगता है।

वैराग्य के गह्वर से उभरने के लिए हम सब विकल्पों की रज्जु की पकड़ने में प्रयासशील प्रवृत्त होते हैं। लोक-नायक आपमनाथ जी ने व्यक्ति के निवास तथा सामाजिक परिस्थिति के परिवर्तन हेतु शिक्षा की सक्षमता को स्वीकार करते हुए विचार व्यक्त किया है कि "अभाव-

कत औपचारिक शिक्षा" यद्यपि हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करती है। दूसरी ओर यह उच्च और मध्य वर्ग के लोगों की भी, जो इच्छा सामान्य होते हैं। गलत शिक्षा देती है। [भूमिका, एन्क्रेडन फार भावर पीपुल] सम्म-वत अनौपचारिक शिक्षा विकल्पों के खोज की प्रवृत्ति न एक गृह्यता है।

शिक्षा के विकल्प—

प्राविधान की दृष्टि से शिक्षा के तीन स्रोत बड़े जा सकते हैं। (१) आकस्मिक (२) अनौपचारिक (३) औपचारिक। इनके छात्रिक अर्थ पर न आकर इनको सार्वक बनाने के लिए पारिभाषित करना जरूरी है। आकस्मिक शिक्षा [इनफोर्मल अथवा इन्फोर्मल] हम हर समय अपने जीवन के अनुभवों के साथ मिलती रहती है जिससे हमारे ज्ञान, जीवन तथा भावना पक्ष की अभिवृद्धि बनायाप्त होती रहती है। हम इसके बारे में कोई संकेत अथवा संरक्षित प्रयास नहीं करते, किन्तु इस माध्यम का तथाज के नेता अथवा सरकार औपचारिक तदुपयोग करने व्यक्ति और समुदाय को एक शिक्षा विशेष में अवसर कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा सरप्रास व्यवस्थापक शिक्षा को कहते हैं। अर्थात् कि हम सभी जानते हैं सरप्रास शिक्षा में एक निश्चित पूर्णकालिक शिक्षाक्रम होता है। इस शिक्षाक्रम में अध्यापक एक प्रयासशील क्षेत्र विशेष अथवा समुदाय विशेष को दृष्टि में रखकर एकत्रता पायी जाती है। जनन, गर्भवती, उपकरण आदि का एक व्यवस्था के अनुसार प्राविधान होता है। गैरसरप्रासिकों की निपुणता, शिक्षा प्रयास ऐतिहासिक कार्यक्रम, विद्यार्थी की पूर्णकालीन उपस्थिति जैसे नियमों का आचरण इसमें विहित है।

अनौपचारिक शिक्षा के सम्बन्ध का प्रयोग औप-चारिक शिक्षा के विच्छाद्य में किया जाता है। किन्तु आज ऐसी नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा क-

प्रलय में मृत्युवन्धित सत्त्वा, एक निश्चित भवन, एक सुनिश्चित और एकरूप विधाक्रम फेरोवर अम्पापनो की नियुक्ति, विद्यालय में पूर्व-शालिक उपरिष्ठित आदि नियमों का पालन जरूरी नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि एक निश्चित योजना होती है और कुछ न कुछ व्यवस्था भी—ऐसी व्यवस्था जो अपने द्वारा व्यर्थ की भाषा उपस्थित नहीं करती। दूसरे पक्षों में यह कहा जा सकता है कि अनौपचारिक शिक्षा का एक प्रधान लक्षण समताशीलता है। अनौपचारिक शिक्षा आकस्मिक शिक्षा की भाँति केवल प्रसंगपर ही नहीं है वह प्रयोजनपट्ट है। अतः अनौपचारिक शिक्षा को आकस्मिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में बीच की गड़ी कहना अप्रिय उचित होगा। अथवा यों कहिए कि यह उन दोनों के सातत्य पर नहीं धीरे या एक कार्यवरण समझीता है। कहा जाता है कि इस लक्षणी के कारण शिक्षा में अनौपचारिकता की प्रकृति बरबाद सिद्ध हो सकती है। क्यों और कैसे? वह विचारणीय है। इसे कम व्यवसाय कौं मताया जाता है। इसकी उपादेयता के क्या आधार हैं? जो परिणाम एक अवस्थित शिक्षा से नहीं निकल सके, उनको एक तीली व्यवस्था के द्वारा प्राप्त करने की क्या सम्भावना है?

औपचारिक शिक्षा का मोह भग

'कहा जा रहा है कि सार्वजनिक शिक्षा स्त्रुव के माध्यम से सम्भव नहीं है।' "शिक्षा में समान व्यवहार एक वांछित ही नहीं, अपितु सम्भाव्य सत्य है। किन्तु इन प्रत्येक में अविनाश स्मृती शिक्षा को जैसे ही समझना चाहिए जैसे कि मन्दिर जाने से श्रुति प्राप्त का भ्रम।" (इवान इल्लिच से स्मृति सौष्टादी।)। स्मृती शिक्षा मानव समान में सर्व श्रेष्ठ पैदा करती है, यों कि यह व्यवसाय है। यह उत्पादनवरक व्यवसाय को कम, समतोषपरक अधिक है। स्कूल स्कूल में भेद होता है। 'अमीरों को स्मृतीका गरीबों के स्मृती से अच्छा होना स्वाभाविक है।' गुनार मिहेंस 'सैलन आक पर्व पार्वती। यह भी कहा जाता है कि "सम्भाव्य शिक्षा शैक्षिक समता। वीच बनाने का कारक सिद्ध होती है" हेन्सी

एन्ड्रयुज आन्ड्रयुज ५०० ८३)। इसी अथवा सम्भाव्य शिक्षा, इगम वाजेज, विद्यविद्यालय की सामिल है, के द्वितीय महामुद्र के पदनात एकाएक मोहमय या क्या कारण हो सकता है? भाषी यों के विचारों पर आधारित लेकिन शिक्षा ने भी सत्ता की समझ देता था उर्नपन करने का साहस नहीं किया। अतः लेकिन शिक्षा के सम्पर्क में अनौपचारिक शिक्षा का क्या महत्व है?

महापति शिक्षा की असमानता या एक कारण बताया जाता है, किन्तु सोचने की बात है, कि यदि व्यवस्था से नियमित शिक्षाक्रम सौजन्यमय समानता के सिद्धांत का विचार-व्यवहार नहीं कर सकता है, तो एक कीर्ति काती यों अनौपचारिक शिक्षा इस कमी को कैसे पूरा करेगी? शिक्षा एक बहुत मन्दुक्त क्षम है। उचित शान्तिनिर्देशन अथवा नियन्त्रण के अभाव में अनेक विद्य-शिक्षा पैदा हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि शिक्षा तब पर हावी होकर विदेशी शक्तियाँ अथवा भाषा-परिणाम-शक्तिशाली मन-निर्देशन अपने स्वार्थों को सिद्ध कर लेते हैं। अमीरों के बने राज्यों की शिक्षा पर पाश्चात्य प्रभाव की ऐसी खबर है कि वह ऊपरी भाषिक सत्ता की अपने स्वार्थों के अनुकूल मोड़ लेते रहते हैं। नहीं नहीं अपने आन्तरिक बरह और भाषा-परक शैक्षिक पैदा करने में भी नहीं चूकते। "जब स्वाधीनता प्राप्त पर ली, तब नेहरू तथा अन्य नेताओं ने पूरी शिक्षा व्यवस्था में विपलवकारी परिवर्तन लाने की बात नहीं। किन्तु यही साम्यवाद बल भी, जो भारत तथा कुछ हद तक भी सका यों छोटकर अन्य एशियाई देशों में नहीं हुई।" (गुनार मिहेंस, एशियन मुक्त)। यद्यपि कि अनौपचारिक शिक्षा ऐसी ही शैक्षिक बटमारी के लिए आसित स्थल न बन जाय और शैक्षिक असमानता का एक बहाना न हो जाय। सम्भव है कि लिए औपचारिक शिक्षा, समतोल तथा के लिए अनौपचारिक शिक्षा अतन्त्रता मुक्त है। इसके लिए क्या आवश्यकता बरखी जाय? नियन्त्रण तथा नियोजन का क्या स्वरूप हो, ताकि कार्य सुचारु रूप से चले और प्रशासनिक जनक से बचत भी बनी रहे।

विकल्पो का संयोजित प्रयोग

जिन तीन विकल्पो की ऊपर चर्चा की गयी है, वे एक दूसरे के विरोधी अथवा निवारक नहीं हैं। सम्भवतः शिक्षा का अपना महत्व और उसका सम्बर्द्धन भी होता है। नही मर्यादात शिक्षा में बाध नहीं पड़ रहा है, अथवा अपसाम्य निम्न हो रही है। जहाँ अन्य विकल्पो का प्रयोग जरूरी है। इस दृष्टि से अनौपचारिक शिक्षा एक विरोधी विकल्प नहीं है, और यह अन्य विकल्पो का सम्पूरक है। उदाहरणार्थ ६-११ वय के छात्रों में विशेषरूप से प्राचीन धर्मो में मननका दो तिहाई का ह्रास है, यद्यपि यह बालक पूनर्जातिका स्कूली शिक्षा के लिए समय नहीं दे सकते। कुछ प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा पारकर कोई व्यक्ति कुछ और पढ़कर अपनी नौकरी में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अप्रवाहिक अथवा अपने समय की सुविधा के अनुसार आगे की शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है। ऐसी अन्य अनेक परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, जिनसे सम्बन्ध में अनौपचारिक शिक्षा को एक सम्पूर्ण विकल्प के रूप में चलाना सम्भव उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ६-१४ वय वर्ग के स्कूल की अपूर्ण शिक्षा वाले बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की एक व्यापक योजना पर कार्य हो रहा है, जिसे वैदेशी सरकार की सहायता से राज्य सरकार चला रही है। इसकी एक प्रगतिक अवस्था भी बनायी जा रही है। इसी तरह प्रौढ शिक्षा से सम्बन्धित भी एक अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रणाली में यह तथ्य विचारणीय है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम क्यासमय आकस्मिक शिक्षा के कार्यक्रम भी एक दूसरे के रित्त प्रकार सम्मिश्रित हो।

देखने में आता है कि शिक्षा की विभिन्न योजनाएँ बहुत एक दूसरे से घुलती अलग अलग करके चलती हैं कि जिस घन और घन के अवलम्ब हैं हम शिक्षा में क्षेत्र में काम करना चाहते हैं यह एक कार्यक्रमों के प्रारम्भ से उभरा बढ़ने लगता है। ऐसा मान्य होता है कि प्रगतिक सत्ता एक व्यापक समन्वय हेतु योगदान देने में असमर्थ सिद्ध होती है। नास्त्य में औपचा-

रिक और अनौपचारिक शिक्षा की योजनाओं को एक दूसरे से खटाट होना चाहिए। सफलता के लिए चाहिए कि उनको अलग-अलग चलाया ही न जाय यहाँ तक कि एकको एक दूसरे से जोड़कर अर्थात् यौनिक रूप से उचित परिणाम कारक सिद्ध नहीं होता, यद्यपि इस स्थिति में भी कार्यक्रमों में व्यर्थ का दोहराव बनाता रहता है, उदाहरणार्थ यदि किसी दूसरे के पास में तीस प्रोड के एक केन्द्र की देखने के लिए एक पर्यवेक्षक जाय, २-१४ वय वर्ग के लिये प्रस्ता, बालकों के प्राथमिक विद्यालय के लिए तीसरा तथा क्षानिनाओं के प्राथमिक विद्यालय के लिए चौथा नियुक्त होता है तो क्या इसे हास्यास्पद अप्राम्य नहीं कहेंगे? वास्तव में चाहिए कि इन योजनाओं की सार्थक और मितम्बयी नियन्त्रण के लिए एक अवलम्ब संगठित अथवा समन्वित नियोजन। यह कंठ हो, यह सम्पूर्ण और स्पष्ट चिन्तन का विषय है।

आइये अब अनौपचारिक शिक्षा पर विशिष्ट रूप से विचार करें।

अनौपचारिक शिक्षा का स्वल्प— अनौपचारिक शिक्षा का केन्द्र

ऐसा कि ऊपर सकेत कर चुके हैं, अनौपचारिक शिक्षा एक प्रवृत्ति है, जो अनेक रूपों में व्यक्त होती है। इसके कुछ ज्ञाने माने रूप अथवा नाम अकादमिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, प्रादेशिक शिक्षा, आजीवन शिक्षा, सतत शिक्षा, सेवाशैलिक शिक्षा, अवकाश कालिक शिक्षा, पुनर्जीवन प्रशिक्षण एपरेण्डिसिप, प्रसार शिक्षा आदि हैं। बस्तर की जनजातियों के और पृथिवी के रोम लोग आदि विभिन्न व्यवस्थाओं और नवयुवतियाँ सह-वास और आचारकी शिक्षा पाते हैं, इसमें ही एक कहे जा सकते हैं। उपर्युक्त सत्ताओं में स्पष्ट हो जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा प्रयोजन सिद्ध होती है, और इसके लिए उद्देश्य सामाजिक महत्त्व की बात है, व्यवस्था तथा प्रयासन केवल साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। कुछ विद्व-विश्लेषण तथा 'सूचना स्कूल' जिसकी देश और विदेश में काफी चर्चा है इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। स्पष्ट है कि अनौपचारिक शिक्षा के नियोजन तथा नियन्त्रण

का एक मुख्य सिद्धान्त नमनशीलता है। इस प्रकार की नमनशीलता सम्भावित अर्थात् अनौपचारिक शिक्षा में भी परिलक्षित होनी चाहिए। स्कूल बानेको के कार्यक्रम में भी अनौपचारिकता के सिद्धान्त को यथासम्भव मुख्य मिला चाहिए। स्कूल में बाहर जाकर विद्यार्थियों को स्वानुभव तथा सामाजिक प्रतिभाषी के रूप में सीखन का अवसर इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। पाठ्यपत्र का कार्यक्रम भी इस प्रभाव को परिलक्षित करते हैं। वह दिन अत्यन्त गुप्त होगा, जब हमारी सरकारी भी अनौपचारिकता को अधिक न अधिक ग्रहण करेंगे और साथ ही गरीब जनित श्रमकुशलता को भी अङ्गीकार करेंगे। यहाँ वह स्पष्ट करना भी उचित है कि अनौपचारिक शिक्षा में भी एक सुनियोजित व्यवस्था होती है, किन्तु वह ग्यमासिन्धुन कार्य कुशलता में बाधक नहीं।

अनौपचारिक शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता

एक प्रवृत्ति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अनौपचारिकता के बहुत प्रयोग हैं, और अनेक अनवर हैं, किन्तु उमरती हुई परिस्थितियों में निम्नलिखित प्रयोग विचारणीय हैं।

१. निर्यस्त अवस्था पवित्र धर्म की प्रमाणी शिक्षा, के लोग पूरा कालिक शिक्षण के लिए समय नहीं दे सकते। इनको, इनकी दुनिया तथा काम के बन्धे हुए समय में शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्री में प्रौढ शिक्षा तथा विद्यालय की अपूर्ण शिक्षा प्राप्त बातको की शिक्षा जाती है।

२. आगे की शिक्षा—बहुत से लोग रोजी रोटी कमाने की चोट में अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते किन्तु अपने अभियन्त की रुचिकर बनने के लिए समय निकाल कर आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। यही नहीं अधिक पढ़े लिखे लोग भी अपनी अभिवृद्धि अपना आनन्दन के लिए आगे की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हो सकते हैं।

३. नये रोजगार की शिक्षा—बहुधा तकनीकी परिवर्तन तथा वैज्ञानिकी की समस्या को हल करने के लिए यह जरूरी है कि आवश्यकतानुसार विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा आयोजित की जाय, ताकि एक

रोजगार को सल होने पर जारीगर दूसरे रोजगार में जाने के योग्य अपन को बना सके। यह हमारे बढ़ते हुए औद्योगिककरण के सम्पर्क में आवश्यक है।

४. पुनर्वसन प्रशिक्षण कार्यक्रम—इनकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। -

५. आवागमन के सहयोग हेतु शिक्षा—

६. सामाजिक शिक्षा—सामाज में परिवर्तन मान हेतु उचित मानसिकता, नैतिकता तथा सामाज्य मान, परिवार नियोजन से सम्बन्धित शिक्षा को देने की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा और उनके अन्य प्रयोग के समय में हम राष्ट्रीय क्षेत्री और स्थानिक स्तर पर सीपने की आवश्यकता है और साथ ही इन आवश्यकताओं में प्रापनिकता निश्चित करने की भी। इस हेतु विशेषतः सहयोग अपेक्षित है, जो सर्वोपलब्ध और सीप के आधार पर कार्यवाही करें।

अनौपचारिक शिक्षा की कार्यविधि

अनौपचारिक शिक्षा में अनेक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है जैसे अल्प कालीन प्रशिक्षण विधिर सावकानिक शिक्षण बसाधार, दूर दर्शन, विचार शौचिया, कार्य शौचिया आदि आदि। किन्तु परिस्थिति में विश्व विधि का प्रयोग समर है इसके लिए उचित योजना तथा कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्थापरक न होते हुए भी इसके लिए पूरी तैयारी और विस्तारपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठशाला लक्ष्य बरेलू दवाइयो के मुख्य के रूप में घाटक अपनाना सबसे प्रति सम्पाद करता है। इस प्रकाश में निम्नलिखित तथ्य विशेष रूप में विचारणीय है—इन्के प्रकार करने की आवश्यकता है। साधारण अभिधान के सम्पर्क में तो विशेष रूप से उत्तरेतर सम्बन्धित प्रकार कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सम्पूर्ण निम्न की आवश्यकता है।

२—सामाजिक आवश्यकताएँ प्रमुख आधार अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों को सामाजिकयोगी होने की आवश्यकता है। यदि सामाजिक आवश्यकताओं

को राजनैतिक जागरूकता से सम्बन्धित कर दें तो यह और आवश्यक बन जाती है और राजनैतिक शिक्षा का एक उपयोगी माध्यम बन जाती है। गौनोस्तेरे के शासकों में ऐसी प्रयोग बड़े सफल सिद्ध हुए हैं। यह एक अत्यन्त मातृका प्रयोग है। इसकी क्या सम्भावना हमारे लिए हो सकती है ?

३—शिक्षण के साथ मुलाकात का कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा के बहुत स कामकाज में होता है जिसमें पहले सीसी हुई बातों में सुधार लाने की बहुत जरूरत होती है। व्यक्ति वर्गों की शिक्षा के तत्काल में उनकी मान्यताओं अविश्वसनीय तथा भ्रमों के परिग्रहण में शिक्षा के साथ अत्यन्त सुन्दर कार्य हो जाता है। इन परिस्थितियों का सामना किस काम यह एक सुनिश्चित विधान का विषय है।

४ लक्ष्मीनारायण पाठ्यक्रम जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है अनौपचारिक शिक्षा में रचनीय आवश्यकताओं में तथा सामाजिक परिस्थिति को देखकर शिक्षाक्रम बनाने की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा की इकाईयाँ तबका की दृष्टि में अपनी छोटी होती हैं कि पाठ्यक्रम रचना का विशेष काम इनके स्तर पर कैसे हो ? कहा जाता है कि कुछ कोरा पाठ्यक्रम बनाना या संभव है और कुछ रचनीय समस्याओं को लेकर सामाजिक करने के लिए छोड़ा जा सकता है। कहना माहिर है करना कठिन है। वास्तविकता की दृष्टि से इस पर सीखने की जरूरत है।

५—सामान्यताओं के प्रति जागरूकता तथा विचारों के निर्माण यदि वास्तव में अनौपचारिक शिक्षा की सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनना है इसे विचारों के प्रचार और प्रसार और उन पर जनसाधारण को समीक्षात्मक रूप से मनसर देना आवश्यक है। उन्हें सोचने में तरीकों की रचना होना। लेकिन इस बात की जागरूकता है कि यह प्रोग्राम बड़े पैमाने और लक्ष्य से सजाये जाय। इन सम्बन्ध में उचित विधियों का ज्ञान करना है, और उनमें शिक्षा देने वाले को प्रतिष्ठित भी करना है।

६—कार्यभारित शिक्षा अविनाश योग जो शिक्षा छोड़ देते हैं उनके छोड़ने में एक प्रमुख कारण शिक्षा की निरसता भी होती है। शिक्षा की कार्यकलाप से जोड़ कर निरसता को दूर किया जा सकता है।

७—समस्या आधारित शिक्षाक्रम इसकी उपयोगिता रखता है।

८—व्यक्तिपरक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत हम बहुतों ऐसे लोगों को पाते हैं जो पढ़ाई से एक बार मुक्त हो चुके होते हैं। अब इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्नों के प्रश्न में यह तो और भी आवश्यक हो जाता है।

९ स्व शिक्षा तथा सह शिक्षण का प्रयोग आगे की शिक्षा में अनौपचारिक कार्यक्रम के प्रसार में सर्वोत्तम का विशेष महत्व है।

१०—अनौपचारिक शिक्षा के विशेष प्रत्याशी यह होते हैं अनौपचारिक शिक्षा के प्रत्याशी अनेकानेक वर्गों के लोग हो सकते हैं जिनके बारे में ऊपर संकेत किया जा चुका है। किन्तु वर्तमान परिस्थिति में एक मान्यता के रूप में शिक्षाक्रम बनाने की बात है। उन लोगों के लिए प्रोग्रामों की तीन वर्गों में बाँट सकते हैं —

(क) साक्षरता अभियान तथा शिक्षा का साक्षरनीकरण।

(ख) उत्पादनपरक शिक्षा।

(ग) सामाजिक शिक्षा।

इस कार्यक्रम में १९४४ वर्ष के विधानमंडल छोड़ने वाले लक्ष्य विचारतब से न जाने वाले सालक तथा १९५५ या इसके अधिक माथु जाने अनिश्चित प्रोग्राम विशेषकर से जाते हैं। इसके लिए (१) साक्षरता तथा (२) उपयोगी शिक्षा, जिसमें उत्पादन प्रेरित तथा सामाजिक शिक्षा भी सम्मिलित है दोनों ही प्रकार के कार्यक्रम निहित हैं। इस समय साक्षरता पर ही विशेष धन तथा प्रायः धन्यता दी जा रही है। १९४४ वर्ष के सालक साल-

काओं के लिए यह भी सोचने की आवश्यकता है इनको किस तरह द्रुतवर्तिन शिक्षण देकर औद्योगिक शिक्षा की धारा में डालकर बसा ८ लाख की योग्यता प्रदान कराई जाय। इसमें जो छात्र प्रतिभा सम्पन्न हैं उन्हें और आगे की शिक्षा देकर बड़ों का अवसर दिया जाय। इस प्रयत्न में द्रुतवर्तिन शिक्षण के लिए १ पाठ्यक्रम की सहजा तथा २ अधिगम के मूल्यांकन के स्वरूप के बारे में विशेष रूप से सोचने की जरूरत है। यह भी आवश्यक है कि इस औद्योगिक शिक्षा केन्द्रों को उचित प्रतिष्ठा दी जाय। जिससे इनके शिक्षितों तथा शिक्षक दोनों ही हीन भावना ग्रस्त नहीं हो। साथ ही इन केन्द्रों का साहस भी बढे।

श्रीलंका की साक्षरता के बारे में उनको अभिरुचि थी तथा उनको साम्यवादों एवं परिवर्तन मानस के अनुरूप शिक्षाक्रम बनाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माया शिक्षा पूरी पढाई की कुन्नी नहीं जा सकती है किन्तु इस सम्बन्ध में जो पाठ्यक्रम और साहित्य मिलता है, साकार्यक नहीं है, क्या उसकी विषय वस्तु सम्प्राप्त मर्याद के भक्तिष्क की ही उपज मान ली नहीं है?

उत्पादन परक शिक्षा

देश के आर्थिक विकास के सन्दर्भ में यह काम वात करी जाती है कि हमारे किसान और कारीगरों की उत्पादन क्षमता अन्तराष्ट्रीय स्तर से अति ग़ुप्त है। इसमें कुछ हदु ग़ुप्त में आगत के सिद्धांत पर उचित तकनीक के प्रसार की आवश्यकता है। किसानों और कारीगरों को उसके सीखने और प्रयोग करने के लिए समय देना है। इस सम्बन्ध में औद्योगिक शिक्षा की उद्घाटन में विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत जरूरी है।

इस प्रश्न में महिलाओं की भूमिका अत्यन्त महत्व पूर्ण होनी चाहिए क्योंकि वे अधिकोन्नत घर के चूल्हे बननी तथा ही सीमित रह जायी है। महिलाओं के हस्तशिल्प की दायता का प्रयोग करके अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रसार किया जा सकता है। क्या इससे लिए हमारे सामने कोई प्रोत्साहन है?

सामाजिक शिक्षा

सामाजिक शिक्षा की चर्चा बड़ी पुरानी है। इसमें सम्बन्धित विभाग और उपविभाग भी बम्हरी दे। रायद फंजन व रूप व भावे और उसी के अनुरूप लुप्त भी हो गये। इसने प्रोत्साहन इसर उधर बिखर गये। आवश्यकता है कि सामाजिक शिक्षा में व्यापक वायव्यन बसाए जाय जो साक्षरता अभियान और उत्पादन कार्यक्रमों से जुड़े हों। इस प्रयत्न में निम्नलिखित उद्देश्य विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है।

- (१) बच्चों की देखभाल
- (२) घरों की साज सज्जा
- (३) स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेस क्लब
- (४) सांस्कृतिक तथा मनोरंजन कार्यक्रम
- (५) अन्धों नागरिकता की शिक्षा जिसमें नेतृत्व की शिक्षा भी सम्मिलित है।

नागरिकता की शिक्षा के साथ राजनैतिक शिक्षा का जोड़ना समीचीन प्रतीत होता है। अथवा तीन हजार वर्ष पूर्व पेरिक्लीज ने कहा था कि एथेनसवासी अन्य लोगों से इस बात में भ्रष्ट हैं कि उनका प्रत्येक नागरिक राजनीति में सक्रिय भाग लेता है। यदि यह आदर्श आजकल के सदर्भ में हमें भाग्य हो तो हमें क्या करना चाहिए? विशेष रूप से भविष्य और प्रायोगिकों की शिक्षा के सन्दर्भ में?

बच्चों की देखभाल के सम्बन्ध में क्या यह उपयुक्त होमा कि बड़ी बस्तियों और ग्रामों में निम्न वेग्न लोते जाय। आनन्दबायी और आनन्दबायी के कार्यक्रम कुछ राज्यों में फाँड़ी सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के सदर्भ में इसके बारे में सोचा जाय?

व्यवस्था तथा क्रियायन

जैसा कि ऊपर सकेत कर चुके हैं औद्योगिक शिक्षा को भी एक तरह की व्यवस्था चाहिए और सफलता के लिए एक उत्कृष्ट नियोजन। राष्ट्र की और विशेषरूप से हमारे राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि औद्योगिक शिक्षा (रोप पृष्ठ ४६ पर)

शिक्षा पर राष्ट्रीय-नीति का प्रारूप

छात्र आत्मसम्मान आन्दोलन

सुप्रसिद्ध शिक्षा सारणी एवं संसद-सदस्य

इस निबन्ध में विद्वान् नेमके ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन प्रारूप के एक-एक अंश का समीक्षा परम्परा तत्परकर विवेचन प्रस्तुत कर, समाज के सभी वर्गों के लोगों को इसका सही भाति सम्यपन करने की तरफ सहाह दी है। लेख ने अन्तिम भाग में इसने कतिपय इसकी कमियों की ओर भी मनेत दिया है। वर्तमान सरकार का यह पुनीत कर्तव्य हो जाना है कि इस नवीन प्रारूप को अन्तिम रूप में स्वीकार करने में पहले यह इन कमियों का निपटकरण करें ताकि नवीन नीति के समर्थ में यह शिक्षा-वर्द्धति निती प्रकार की कठिनाओं से मुक्त रह कर राष्ट्र की युवा पीढ़ी को, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति उत प्रतिपन्न उपादेय बनाने में सफल हो सके।

—संपादक

सरकार ने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप, 1९०६ में प्रस्तुत किया है। सबसे मोझू पृष्ठों के इस विवरण-पत्र में कतिपय अंशों को आरम्भ में ही एक प्रकार के प्रस्तावना के रूप में स्थान देकर देना आवश्यक है।

प्रथम यह सरकार की नीति का विवरण पत्र है, जिसमें एक मंत्री अथवा मन्त्रालय के किसी अधिकारी का बक्तव्य गयी। यह एक नीति-विवरण-पत्र है जो केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित है।

दूसरे, यह प्रारूप है; जैसा कि विवरण-पत्र के प्रारूप में कहा गया है, इसका उद्देश्य कोई हस्तोपन अथवा परिवर्तन कर सकती है।

तीसरे, जन्ता सरकार के उत्तराधिक होने के समय से ही तैयार की गयीं वे बड़े विस्तृत विचार-विमर्श का फल है। प्रस्तुत पहले ही दिन प्रमाणमयी और शिक्षा मंत्री ने विचार विमर्श शुरू कर दिया था, जिसके लिए 1९१६ की संसद द्वारा स्वीकृत शिक्षा की प्रथम राष्ट्रीय नीति में व्यवस्था भी है कि हर पाँच वर्षों पर नीति विवरण पुनरीक्षित होता चाहिए। इसका पुनरीक्षण हमें 1९०४ में ही कर लेना चाहिए था। पर हम चुन गये। इस प्रकार इस प्रथम विवरण-पत्र में स्वीकृत हुए बाव 1० वर्षों हो चुके और पिछले दो वर्षों में कई बार विचार

विमर्श होचें रहे हैं। शिक्षा मन्त्रालय ने, और स्वयं प्रधान मंत्री ने भी विचार-विमर्श, शिक्षाविदों तथा राज्यों के शिक्षा अधिकारियों से कई बार विचार विमर्श किए, बल्कि हर राज्य के शिक्षा मंत्री से विचार-विमर्श करने के लिए भी शर उनके सम्मेलन आयोजित किए गए। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सम्मेलन, विरल-विशालय अनुदान आयोग इत्यादि के साथ नीति के प्रारूप की जाँच करने और उस पर टीका टिप्पणी करने का अवसर मिला था।

यह विवरण पत्र ऐतिहासिक निरन्तरता और साथ ही नवी उद्भावनाओं - कतिपय नयी बातों का परि-पक्व सम्मिश्रण है। यह विस्तृत नहीं बोल ही, ऐसी बात नहीं। ऐसा हो भी नहीं सकता। शिक्षा अपना यह रूप नहीं भूल सकती कि वह एक स्थायी क्रिया है, जीवन चरन्त है, एक निरन्तर प्रक्रिया है, परीक्षण करती है। इसलिए ऐतिहासिक निरन्तरता का तत्पर इसमें है और हममें से कोई जबर् इसमें देवता नयी बातें हो देखा चाहें तो यह बलत होगा। इसमें नयी उद्भावनाएँ भी हैं, किन्तु भारत की वास्तव्य ऐतिहासिक प्रणाली के विस्तृत चौखटे के भीतर हम नीति विवरण का व्यापक प्रारूप है और इसमें जिसने सभी अर्थ, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्राथमिक, उच्च, नवस्क शिक्षा स्तर, माध्यमिक

शिक्षा स्तर, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा स्तर तथा तकनीकी, कृषि विषयक और चित्रितकारी शिक्षा सबका समावेश है। इस विवरण-पत्र में इस बात की निम्नलिखित व्यवस्था है कि प्रत्येक स्तर पर संश्लेष प्रणाली का सेप समान से घनिष्ठ सम्बन्ध बने रहना चाहिए।

इस नीति विवरण के प्रारूप के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पक्षों पर मैं विशेष बल देना चाहूँगा।

प्रथम, इस विवरण-पत्र के दो आदर्शपरक भाग मुझे बहुत पसन्द आये हैं। कहा गया है कि शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति का विकास और व्यक्ति के विकास से ही सामाजिक विकास सम्भव है। इस लक्ष्य में वस्तुतः साथ यानी स्वयं नैतिकता पर अधिक जोर है। उदाहरण के लिए उक्त कहा गया है कि सत्यपूर्ण जीवन के द्वारा व्यक्ति का विकास ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए और यही मौख व्यापक धीर्गम्य के शिक्षा के प्रयोजन की धर्मा है। कहा इन बातों पर जोर है कि वह प्रयोजन शिक्षण से हटकर ज्ञानार्जन होना चाहिए। विस्तृत शीक। समस्त शिक्षा ज्ञानार्जन हो तो है, शिक्षण तो मात्र एक साधन है।

द्वितीय, इस प्रयोजन में गांधीवादी शिक्षाप्रदान के तीन मूल तथ्यों का समावेश किया गया है। एक-समस्त ज्ञानार्जन के प्रति गंभीरता और आत्म निरीक्षणमय दृष्टिकोण, इसका तात्पर्य यह कि ज्ञानार्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो आपके ही भीतर होती है, वह ऊपर से योनी नहीं जाती। दूसरा—हाथ और हृदय के परस्पर सम्बन्ध पर उनका शिक्षा के प्रभावित रूप—बौद्धिक कार्य और शारीरिक कार्य में समन्वय स्थापित करता है, और तीसरा है शिक्षा के सामाजिक दायित्वों में गंभीरता जो भी आता।

इस प्रकार शिक्षा के प्रयोजन का तीसरा भाग है समुदाय-सेवा तथा रचनात्मक और सामाजिक उपयोग के कार्यों में भाग लेना, और जहाँ न नैतिक शिक्षा पर पुन जोर दिया गया है जिसकी, मेरी दृष्टि में, हमारे जीवन के इस चरण में बहुत जरूरत है। नैतिक शिक्षा सभी विषयों में अन्तर्सम्बन्धित पाठ्यक्रमों और सह-

पाठ्यक्रमों कायंक्रमों के द्वारा पाठ्यक्रम का एक अंग हो जाना चाहिए, और वह सभी अध्यापकों और समस्त संस्थाओं का दायित्व होना चाहिए।

तब मैं उस उपाय पर जोर दूंगा जिससे शिक्षा एक और तो जीवन पर्यन्त जारी बनी रहे, धूल तथा वास्तव प्रपञ्च बदरक साधारणता के ज्ञान, ज्ञान, छह वर्ष, आठ वर्ष बारह वर्ष के लिए न रहे, और दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो या बरकर, अपने ज्ञानार्जन का रास्ता चुनने के लिए स्वतन्त्र है। उस पर पाठ्यक्रम की कोई खास पद्धतियों, शिक्षा प्रणालियों और इस तरह की चीजें लागू नहीं करनी चाहिए।

तीसरे में, प्राथमिकताएँ स्पष्ट कर दी गयी हैं। इसमें एक नयी उद्घाटना है। एक तो प्रारम्भिक शिक्षा की निम्नलिखित प्राथमिकता दी गयी है अर्थात् विवरण-पत्र में कहा गया है कि सविधान की व्यवस्था में अनुसूचित, १४ वर्ष तक की शिक्षा की अपने बस प्रथम निश्चित व्यवस्था हो जायेगी और दूसरे, बदरक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता है। जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा की बात है, कहा गया है कि उसका बहुत प्रचार नहीं, बल्कि सुचारु होगा और व्यवसायीकरण की व्यवस्था होगी। समस्त माध्यमिक शिक्षा के और भी अधिक अन्तिम दो वर्षों के व्यवसायीकरण की नयी दृष्टि को अपनाया गया है, और साथ ही उच्च शिक्षा में एक और तो सत्यावत-स्थायित्व की व्यवस्था होगी और दूसरी और शिक्षा की विभिन्न और औपचारिक प्रणालियों के द्वारा शिक्षा के इच्छुक व्यक्तियों के लिए उनमें अधिकतर उपलब्ध रहेगे।

पाचवा, प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा ही रहेगी। यह एक नयी उद्घाटना है, क्योंकि साथ यह समझें कि पाठ्यप्राप्तिक स्तर से लेकर पी० एच० डी०, वाकटो शिक्षा, दैनिकीयों को शिक्षा और कृषि शिक्षा के लिए सीमित निश्चित है कि हमें क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को और बढ़ाना चाहिए। अविष्म के लिए यह बड़े महत्व की बात है। इसमें हम उन सभी देखते समन्वय हैं जहाँ समस्त वास्तविक शिक्षा स्वयं अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में दी जाती है।

किन्तु हमारे देश में एक समस्या है जो अन्य देशों में उस हद तक नहीं है। हमारे देश में कई भाषाएँ—१५ प्रमुख भाषाएँ हैं। एक बहुत रोचक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि प्राइमरी स्कूलों में भाषा के पच्चे घंटे का अनुपात कर देने चाहिए जो तीन पच्चे प्रतिदिन से अधिक न हो। कोई क्या बर्बाद खर्च नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि ६ मास, १२ मास का न हो। वह प्राइमरी स्कूल हो जिसका समय स्थानीय भाषा परकताओं के अनुसार निर्धारित हो। अगर वह बाबाँ नित हुआ तो प्राइमरी स्कूल की विस्तृत व्यापकता हो जायेगी। हमारे बच्चों के लिए तीन पच्चे प्रतिदिन काम में दिनों की सप्ताह पहले से ही नहीं बल्कि उनके छुट्टी के काम और जिम्मेदारी के अनुसार निर्धारित होनी।

उपर ब्यक्त शिक्षा के इस बात पर जोर है कि वह मात्र साक्षरता ही प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि एक और तो कार्यनीति प्राप्त करना और दूसरी ओर सामाजिक जागरूकता का होना है। मुझे यकीन है कि नीति विवरण में यह बात गहरी की गयी है कि हमने एक अवधि में है क्योंकि जैसे ही बयस्क शिक्षा द्वारा गरीब, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की जमात को अपनी स्थिति और योग्यता का एहसास होने लगेगा, सामाजिक शक्ति सरचना इस कार्यक्रम की रीढ़ और सत्य करने में कुछ उठा न लेगी।

माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की मैं वर्षों कर चुका हूँ, जिसमें सामाजिक उद्देश्य के रक्षणार्थक कार्य और निम्नलिखित विशेषताएँ व्यावसायिक कार्यक्रमों के द्वारा माध्यमिक विद्यालय के सभी छात्रों को किसी न किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल जायगा और कुछ को तो विस्तृत पूरी अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। यहाँ तक उच्च शिक्षा की बात है, इसमें और औपचारिक पद्धतियों पर जोर दिया गया है।

यैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यह नीति विवरण अभी प्राथमिक की स्थिति में है और आप में से हर किसी

को इसे पढ़ लेना चाहिए, माता-पिताओं को, छात्रों को अध्यापकों को, उद्योगपतियों को, मजदूर लोगों को और सबसे बढ़कर छद्म के सदस्यों को, जिनके समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है इसकी जाँच परत करनी चाहिए। सुद मेरे सामने भी छद्म या सत्य प्रत्यक्ष है, जिसकी व्यवस्था कर देना आवश्यक है। पहला, प्राथमिक शिक्षा में जो खर्चा दी होती है उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह छव गरीबी के कारण है। यह खर्चा रोचक में स्कूल भवन का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जब गरीबी का उन्मूलन कर देंगे तभी गरीबों के सभी बच्चे स्कूल में पढ़ सकेंगे। दूसरा मैं वह उक्ति बसत नहीं करता कि माध्यमिक शिक्षा आवश्यकता की दृष्टि से है। कोई भी शिक्षा अनिवार्य नहीं है। स्वयं नीति विवरण में ही कहा गया है कि शिक्षा एक जीवन पर्यन्त किया है, इसलिए दैनिक पढ़ाई को हटा देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर जीविकोपार्जन करते रहता चाहते हैं उन्हें फिर शुरुआत अपनी इच्छा के अनुसार उच्च अथवा व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की स्वतन्त्रता रहनी ही चाहिए तीसरा, मेरा स्वात यह है कि उच्च शिक्षा का लक्ष्य कमबोरो है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा में नहीं है, माध्यमिक शिक्षा में नहीं है, बसत शिक्षा में नहीं है हमारे विश्वविद्यालयों और कालेजों में है। किन्तु इस बात की पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। पाठ्यपुस्तक शिक्षा का लक्ष्य भी अचूक है वह एक ऐसे आदर्श की तरह है जो मुझे मैं जानो तो सा से पर बात नहीं खत्म हो जाए। सांस्कृतिक लक्ष्य तो बड़ा दायित्व है। क्या निभायायी पाठ्यपुस्तक की बात सुझायी गई है पर हब अच्छी तरह जानते हैं कि तमिल नाडू जैसे कुछ राज्यों में हि मायायी पाठ्यपुस्तक है और यहाँ उत्तर भारत में ही कुछ राज्य हैं जहाँ एक मायायी पाठ्यपुस्तक है। इसलिए यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिये यह कि मायायी पाठ्यपुस्तक किस प्रकार एक राज नीतिक पद के अलावा और भी कुछ है। तब समस्या है पन्थिन स्कूलों की, और उन्हें सामान्य प्रणाली के अधीन करने के लिए पन्थिन स्कूल के माध्यामिक शिक्षा

वही सावधानी से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता होगी।

और अन्त में अच्चाएक विषयक खण्ड, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है, बिल्कुल दकियानुसी है और उस और जो कुछ करना आवश्यक है। अपनी यह वार्ता मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त कहूँगा कि यह एक अच्छा विवरण-पत्र है जिस पर हमें विचार, चिन्तन-मनन करना

चाहिए, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति और प्रधान मंत्री के भी प्रयास की स्पष्ट छाप है। वस्तु प्रधान मंत्री ने बनेक अवसरों पर कहा कि वाश "वे निश्चय मंत्री होते।" इस कथन से निहित उनका भाव मैं समझ सकता हूँ।

(पृष्ठ ४२ का अंश)

मे उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर आन्दोलन के रूप में चलाया जाय। बड़े पैमाने पर चलाने से इकाई-व्यय भार कम होगा और बहुत सी कठिनाइयों को तो आन्दोलन की आधी अपने भाव उठा ले जायेगी। ऐसे आन्दोलन की गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए वर्तमान डग का प्रयासन सम्भवतः कारगर सिद्ध न हो। प्रयासन कैसा हो और उसकी क्या संरचना हो? यह एक खुले भिवाव का विषय है।

शोध तथा मूल्यांकन

अनीतवारिध शिक्षा की जो तस्वीर हमारे सामने उमर कर आती है उससे यही सगुता है कि उसके किया-

गमन के लिए स्कूली शिक्षा की अपेक्षा कहीं अधिक पहल, समझदारी तथा उत्पन्न शक्ति की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति का समानरूप से सामना करने के लिए अधिक जानकारी चाहिए। यह जानकारी सर्वोद्योग-प्रयोग तथा शोध द्वारा ही मिल सकती है। यह कैसे और कहाँ सम्पन्न हो? यह एक मूल्यांकन आवश्यकता है। इसी से सम्बन्धित निरन्तर कार्यक्रम मूल्यांकन का आयोजन भी होगा जरूरी है। आज कल ऐसे मूल्यांकन से हम खी कतराते हैं। जब करोड़ों रुपये स्वाहा हो जाते हैं तब पूछ-ताछ होती है कि क्या कोई काम हुआ है। इस परिस्थिति से कैसे बचे ?

किसी काम में लगा देते थे। इस बारे में उनकी सेवा नेपाव के रूप में सुनसी मेहर की कोटि की थी। प्रभाकर जी के द्वारा इस प्रकार की पारिवारिकता का दायरा बढ़ता गया, बढ़ता गया। इसका कारण था उनकी स्फुटिकृत व्यक्तित्व धरिय और अगाध प्रेम।

मैंने उनसे अस्पताल नाम में देखा कि वे दूसरे व्यापक रचनात्मक कामों में नहीं पड़े थे। अपने दायरे में रहकर जो बन रहा, कर रहे थे। उसमें भी व्यक्ति-मतरूप से जो भी व्यक्ति की सहायता हो सके, उस पर उनका पत था। उनसे मैं नहीं स्नेह कार्य से हर्ष दुनिया जीते, ऐसा उनका मान था। जब तक नूदान आन्दोलन शुरू नहीं हुआ, वे सेवाश्रम कार्य के बाहर के व्यापक क्षेत्र से काम ही सम्पन्न रखते थे। गिनोबा की आज्ञा से नूदान कार्य निमित्त आश्रम प्रदेश का सर्वोदय कार्य उनका क्षेत्र बना और उनके एक पैर सेवाश्रम और दूसरा आश्रम रखते थे। उनका कहना रहता कि, रात को मैं जब भी, जहाँ भी सोता हूँ अनुभव करता हूँ कि बापू के आश्रम में, सेवाश्रम में ही हूँ और सुबह उठ कर उन्हीं के कामों में लग जाता हूँ। उनका वादा रहता कि रात की उपस्थिति सेवाश्रम में गिनी जागी चाहिए। वे सेवाश्रम आश्रम प्रतिष्ठान बनाने जाने पर उतने बड़ी बने और हाल तक उस पद की निमित्त रहे।

आश्रमप्रदेश में सभी रचनात्मक कार्यकारिणों से प्रेम का स्वयं रखकर उन्हें परस्पर जोड़ने का कार्य तो वे करते ही रहे पर उनकी दूसरी बड़ी विशेषता रही राजस्व के साथ वैयक्तिक प्राप्त करने की। दिल्ली में ही या प्रदेश में वे कभी जल्दी अमीनियों से भिन्नकर उनका सहयोग प्राप्त कर लेते थे। बापू, राजेन्द्र प्रसाद, रसिक मेहर, इन्दिरा जी सभी के पास उनका आना-जाना रहता था। मुझे कभी कभी शक होता है उनकी सेवाश्रम बापू की अनुपार भी और उनका गहुर तथा निश्चिन्त स्वभाव और निश्चिन्त श्रद्धा यह सब सामने वाले को बापू की सहज मात्र दिव्य और अपने दिल की बात प्रभावशाली की वहाँ की उसकी इच्छा हो-ने। जो हो बड़ी-बड़ी में उनका सम्बन्ध रहता था और उसके द्वारा वे अनन्त सेवा शर्म कराने में सफल होते थे। किसी का

जैसा भी शर्म हो, उससे प्रति प्रवित होकर वे उनके काम को उठा लेते और वहाँ भी जाना-आना हो, दोष धूप कर के धुल्लाते थे। उनसे इस गुण से बहुतों को सहारा मिलता। मरुपि सामाजिक कार्य और व्यक्तिगत कार्य के बीच की तीव्ररेखा में इससे स्पष्टपण आता, पर उनका मित्र का मानना था कि उनकी वृत्ति सामाजिक हित की दृष्टि से ही, सब नामों को देखने की है।

जिन सेवा-सत्याग्रहों से उनका घनिष्ठ सम्पर्क था उनमें प्राकृतिक निर्विस्तार का स्वभाव था। उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया और अनेक उपचारानुभवों की सहायता पहुँचायी। उनके अपने जीवन में भी वे प्राकृतिक सिद्धान्तों का अंगत करते थे और उनकी अतिम बीमारी में भी जब तक उनकी हालत रहा बर्बाद सेवे से इन्कार किया। शरीर से वे पूर्णतः और पलीते थे। बड़ छोटा और इनहारा था, पर शर्म करने को उनकी क्षमता किसी से कम नहीं थी। उनका प्रवास तो इतना अधिक था कि कभी कभी तो आधा सहीता देश में ही प्रवास रहता। अपने लिए, बाँट सहन करने की उनकी क्षमता थी, पर दूसरे का कुछ ऐसा नहीं जाता था।

१९७७ में आश्रम में लूकान जी गैरेंट में कृष्णा जिले का दिवाी तालुका [तहसील] सबसे अधिक प्रभावित हुआ। उते उन्होंने अपना क्षेत्र मानकर बहुत काम किया। अभी एक माह पूर्व दूसरा लूकान ओगोल तट पर आया। वे उसी के निरीक्षण के लिए गये थे तब बीमार पड़ गये। मस्तिष्क के बाहरी भाग में रोग का असर हो गया 'मेनिन्जाइटिस'। सात दिन बेहोश रहे। पुटूर ने सर्वे अस्पताल में डॉक्टरों ने जी तोड़ कोशिश की, पर वे उनके शरीर को बचा नहीं सके। पुटूर, विजयवाड़ा और हैदराबाद में हजारों में उनका अतिम दर्शन दिया। उनका अतिम संस्कार हैदराबाद में शिव-रामपल्ली आश्रम में किया गया, जहाँ वे अपना आश्रम का हैडक्वार्टर बना कर रहते थे। पर वे तो सतत प्रवासी थे, अनिवेष्ट वृत्ति थे। अन्त की उनकी यात्रा थी, अन्तपुत्र नाम ने स्थात थे गुरु हर्ष इस जन्म में और अन्त तक चली रहने वाली है।

३१ सात पूर्व व्यक्त की सभी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें बलि दी गयी, यो बचना देखिये के हाथों आज की असेम्बली ने उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की और मनोरंजन तथा विधायकों ने उनका अंतिम दर्शन किया ।

गोमेवा के साथ वे सहज ही जुड़ गये । जंगली माह से उन्होंने बेटल की सीमा में बाहर के गांव-बैल करने में जाने हमारे मुहिम में वे रुके थे । सभी रास्ता का सम्पूर्ण कर के उनकी रोडवे में प्रस्थित लगा रहे थे । अर्धदेतन अवस्था में वे मरने के कुछ दिन पूर्व बीच-बीच में बहरी बोलते थे, देखो-देखो गांव बटने जा रही है । उसे रोको बेटल सीमा पर ।

इस प्रकार सेवा के आनन्द द्वारा अपने को पहुँचावें का उनका रास्ता था । अनेकों की अनेकों प्रकार से उन्होंने सेवा की । सेवा सेवा उनकी सम्पदा नहीं लगी । जन्म से ईसाई थे पर बापू के पास आ कर सभी धर्मों के

साथ इतने सराबोर हो गये थे कि भूल गये कि धर्म का संबंध क्या था । भजन, गीतो में डूब जाते थे । सात-पति श्री, आदमी-आदमी के बीच भेद-भाव बनने वाली दीवारों उन्हें नष्ट हो गई । उन्होंने वे दीवारें तोड़ने वाली को हमेशा सहारा दिया । स्त्री-पुरुष विकास उनके बागों में प्रभुत्व स्थान पाता रहा । अविवाहित रहे पर अपना परिवार छोटा नहीं बनने दिया । सभी के परिवारों को वे अपना बना लेते थे । सबसे सुख-दुख में शामिल होते थे । आज जब वे नहीं रहे, इन सभी परिवारों में उनके बिछोह का गहरा दुःख है और दुःख है उन समस्त सत्पात्रों और भाग्यी में जिनको उन्होंने बचाया दिया । पर अत्यन्त दुःख तो अनेकों को है ही ।

बदल मत असंजम पछता,
दुःखदुःख उभय बीच बाटू बरना ।
बिस्मृत एक प्राण हरि लेही,
मिलत एक दुःख साधन देही ।



जिम सांस्कृतिक शक्ति के बिना भारत का एक भारतीयता का बचना दुष्कर प्रतीत हो रहा है, वह मानवीय शक्ति होगी, आन्तरिक शक्ति होगी—ऐसी शक्ति होगी, जिससे भारत का सम्पूर्ण व्यक्तित्व-शक्ति के जीवन में उत्तर जायेगा । तब व्यक्ति अपने हितों का धर्म समूह के हितों में करने लगेगा और ईसा ही जीवन जीने लगेगा । इस शक्ति के बिना न समाजवाद बन सकेगा न साम्यवाद । सर्वोदय तो उसी शक्ति का दूसरा नाम ही है । व्यक्ति समूह के लिए जीए और समूह व्यक्ति के लिए । यह हमारी सांस्कृतिक शक्ति आरोहण की एक प्रक्रिया है ।

— व्यपप्रकाश नारायण

हम यह नहीं चाहते हैं कि सुख बढ़ते चले जाएँ। वह पारव
धमरीका के लोग करते हैं। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि
दुःख मिटे। यदि दुःख नहीं रहेगा, संसार की चिन्ता नहीं
रहेगी, तो हम प्रेम से भगवान का नाम लेते रहेंगे। यह अपने
देश का हृदय है। यह बात दूसरे राष्ट्रों को सोखनी होगी।
सुख को बढ़ाते रहने से सुख बढ़ता नहीं, उसे मर्यादा में रखने
से ही बढ़ता है। यह बात सारी दुनिया को भारत से सीखनी
होगी। दुनिया यह बात ठन सीखेगी, जब हम हिन्दुस्तान में
किस को दुखी नहीं रहने देंगे। फिर भारत की सम्भ्रता में
ये शांति और प्रेम है, उसका मूल्यवान् दुनियां परेगी।

—विनोद

वर्षाद भारत नयी तालीम समिति के लिए श्री अजय कुमार वरुण अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति
आग प्रकाशित एवं विना शुल्क नयी तालीम समिति से प्रकाशित